पंचदश माला, खंड 29, अंक 9

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012
14 अग्रहायण, 1934 (शक)

5 दिसम्बर 2012

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G' 87
Acc. No.
Dated 7 Feb. 2016

सत्यमेव जयते

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

हंस राज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 29, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 9, बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012/14 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 164	1-42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 165 से 180	46-170
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	170-919
सभा पटल पर रखे गए पत्र	919-931
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	932-933
विवरण	932-933
शहरी विकस संबंधी स्थायी समिति	
21वां और 22वां प्रतिवेदन	933
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) मुम्बई में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में एक भव्य स्मारक का निर्माण	
श्री आनन्द शर्मा	933-934
(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री एस. जयपाल रेड्डी	934-937

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती दीपा दासमुंशी 937

(चार) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग, से संबंधित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को डाकघरों द्वारा पारिश्रमिक का संवितरण'' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. क्रुपारानी किल्ली 938

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वर्तमान में सप्ताह में दो दिन उज्जैन-भोपाल-कानपुर होकर चलने वाली इंदौर-पटना एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 19313/19314) को सप्ताह के अन्य पांच दिन वाराणसी उज्जैन-भोपाल-झांसी-खजुराहो-महोवा-चित्रकूट-मानिकपुर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा 939

(दो) राजस्थान में बाघ अभयारण्यों को बेहतर बनाने हेतु उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन सिंह 939-940

(तीन) उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत महाराजगंज रेल लाइन के ऊपर आनंद नगर-घुघली बाईपास को शीघ्र पूरा किए जाने आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन 940-941

(चार) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बालू के अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय 941-942

विषय	कॉलम
(पाँच) उत्तराखण्ड के रामनगर में गन्ना किसानों को निजी चीनी मिलों द्वारा भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सतपाल महाराज	942
(छह) दिल्ली की सभी मलिन/अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने और दिनांक के 24.03.2008 भारत सरकार की राजपत्र की अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	942-943
(सात) गरीब लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पाइप द्वारा जलापूर्ति के कवरेज में विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मौसम नूर	943-944
(आठ) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मकरोनिया-बहेरिया खण्ड पर रेल समपार संख्या 30 रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री भूपेन्द्र सिंह	944-945
(नौ) राजस्थान के चुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रतनगढ़ सरदारशहर तथा सादुलपुर-हनुमानगढ़ खण्डों पर रेल अंडर-पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	945
(दस) सतना नगर निगम की जलापूर्ति परियोजना को यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	945-946
(ग्यारह) विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन की धनराशि में वृद्धि किए जाने तथा इन योजनाओं के अंतर्गत बिहार के वंचित लोगों को पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रमा देवी	946-947

विषय कॉलम

(बारह) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाबागंज, कुंडा, सिरातु चायल और मंझनपुर विधान सभा क्षेत्रों के शेष रह गए गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 947

(तेरह) पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदनीपुर के नंदीग्राम में एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुवेन्दु अधिकारी 947-948

(चौदह) तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के अम्बुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 को चार लेन से छह लेन वाला बनाए जाने के बजाए कृष्णागिरी-वालाजपेट (एम.सी.रोड) सड़क पर या तो बाईपास रोड या फ्लाईओवर रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रहमान 948

(पन्द्रह) देश में 44 शैक्षणिक संस्थाओं को दिए गए मानित विश्वविद्यालय के दर्जे को बहाल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 949

(सोलह) महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनगार समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 949-950

(सत्रह) महाराष्ट्र के कोपरा-पनवेल क्षेत्र में प्रस्तावित नवी मुंबई विमानपत्तन के लिए आवश्यक स्वीकृति दिए जाने तथा वहां पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजीव गणेश नाईक 950-951

(अठारह) तमिलनाडु के चेन्नई मंडल में पवूर चतरम में रेलवे आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री पी. लिंगम 951

विषय कॉलम

(उन्नीस) बिहार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संबंधित सूचं में तेली, कानु, लोहार, कुम्हार, मल्लाह, नोनिया, कहार, धानुक ततवा, तांती, केन्वट, केवट, गोदी, गन्गोट, गड़ेरिया, बेलदार, पल्दार, चौपाल, खटवे और दधी जातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 952

(बीस) पश्चिम घाट के संरक्षण के बारे में माधव गाडगिल समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा केवल 500 मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रों को ही केरल के संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के मणि 952-953

(एक) मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को वापस लेने संबंधी सिफारिश के बारे में प्रस्ताव

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उपाबंध (क) और उपाबंध (ख) में उपांतरण के संबंध में प्रस्ताव

और

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के उपाबंध (ख) में उपांतरण के बारे में प्रस्ताव 953

श्री बसुदेव आचार्य 954-960

श्री शरद यादव 960-968

श्री भर्तृहरि महताब 968-974

श्री अनंत गंगाराम गीते 974-978

श्री प्रफुल पटेल 978-985

श्री एम. तम्बिदुरई 985-991

श्री नामा नागेश्वर राव 991-994

विषय	कॉलम
श्री जयंत चौधरी	994-999
श्री गुरूदास दासगुप्त	999-1006
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1006-1021
श्री लालू प्रसाद	1021-1025
डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1026-1047
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	1047-1054
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1054-1056
श्री पी. करूणाकरन	1056-1058
श्री खगेन दास	1058-1062
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1062-1066
श्री सुखदेव सिंह	1066-1068
श्री बलीराम जाधव	1068-1069
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	1069-1072
श्री नलिन कुमार कटील	1072-1073
श्री जे.एस. आरून रशीद	1074-1076
श्री ए. गणेशमूर्ति	1077-1079
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	1079-1081
श्री राजू शेट्टी	1081-
श्री जोसेफ टोप्पो	1081-1083
श्री पन्ना लाल पुनिया	1083-1086
श्री देवजी एम. पटेल	1086-1089
शेख सैदुल हक	1089-1092

विषय	कॉलम
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1092-1093
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1093-1095
श्री एम. राजामोहन रेड्डी	1095-1097
श्री कल्याण बनर्जी	1097-1098
श्री सुदीप बंदोपाध्याय	1099-
श्री एन. पीताम्बर कुरूप	1099-1101
श्री जोस के. मणि	1101-1103
श्री एस. सेम्मलई	1103-1105
श्री बदरूद्दीन अजमल	1105-1115
श्री अजय कुमार	1115-1118
श्रीमती जयाप्रदा	1118-1119
श्री नरहरि महतो	1119-1121
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	1121-1124
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	1124-1130
श्री ए. सम्पत	1130-1132
श्री अर्जुन राम मेघवाल	1132
श्री राम सिंह कस्वां	1132-1134
श्री एस.एस. रामासुब्बू	1134-1135
श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1135-1136
श्री प्रेम दास राय	1136-1137
श्री सी. शिवासामी	1137
श्री मनोहर तिरकी	1137-1138

विषय	कॉलम
श्री रमेन डेका	1138-1139
श्रीमती ज्योति धुर्वे	1139
श्री राजाराम पाल	1139-1140
श्री के. सुगुमार	1140
श्री शिवराम गौडा	1140-1142
श्री सतपाल महाराज	1142-1146
श्री घनश्याम अनुरागी	1146-
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	1146-1155
श्री हरिभाऊ जावले	1155-1157
श्री अशोक अर्गल	1157
श्री धनंजय सिंह	1157-1160
श्री हंसराज गं. अहीर	1160-1161
श्री ए.टी. नाना पाटील	1161-1162
श्री वीरेन्द्र कुमार	1162-1163
डॉ. मिर्जा महबूब बेग	1163-1164
श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	1164-1165
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1165-1167
डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	1167-1168
श्री थोल तिरूमावलावन	1168-1169
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	1169-1171
डॉ. तरूण मंडल	1171-1174
श्री पी.सी. मोहन	1174-1175

विषय	कॉलम
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	1175-1176
श्री जगदम्बिका पाल	1176-1179
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1179-1180
श्री आनन्द शर्मा	1180-1196
प्रो. सौगत राय	1206-1214
श्री हसन खान	1214-1238
प्रस्ताव-*अस्वीकृत*	1238
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के उपांतरण संबंधी प्रस्ताव-*अस्वीकृत*	1261

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	1263-1264
अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	1264-1278

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1279
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1280-1282

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के विश्वनाथन

लोक सभा

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012/14अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल

[हिन्दी]

भारतीय विश्वविद्यालयों का स्थान

†

*161. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्री नीरज शेखर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक अध्ययन के अनुसार विश्व के शीर्षस्थ दो सौ विश्वविद्यालयों में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा क्या कार्य विधि अपनाई गई; और

(ङ) देश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। एक अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा नियत की गई वर्ष 2012-13 की विश्व रैंकिंग के अनुसार विश्व के शीर्षस्थ 200 विश्वविद्यालयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम नहीं है।

(ख) अनेक संस्थाएं अपने स्वयं के मानदण्डों के अनुसार विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तथा करती हैं। विश्व की कुछ जानी-मानी रैंकिंग प्रणालियां हैं- क्वाकुरेली सायमंड्स (क्यू. एस.) प्रणाली, टाइम्स हायर एजुकेशन (टी.एच.ई.) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग एवं शंघाई जिआओ टोंग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विश्व के विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग (ए.आर. डब्ल्यू.यू.)।

ये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग एवं प्रणालियां उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को रैंक प्रदान करने के लिए विभिन्न मूल्यों, सूचकांकों एवं पैरामीटरों का प्रयोग करती हैं। ये मापदण्ड न तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं न ही इन्हें मान्यता प्रदान की जाती है और इसलिए कई बार इनकी आलोचना की जाती है। इनमें से कुछ पैरामीटर भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रासंगिक नहीं होते हैं और इसलिए ये रैंकिंग भारतीय संस्थाओं के मानकीकरण के लिए आधार नहीं हो सकती।

यद्यपि देश की कुछ संस्थाएं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) इत्यादि की तुलना, गुणवत्ता एवं स्तरों के मामले में विश्व के किसी भी शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय से की जा सकती है, केवल सीमित कार्यक्रमों एवं विषयों पर उनके संकेन्द्रण की वजह से विश्व की शीर्ष रैंक वाली संस्थाओं में उन्हें स्थान नहीं दिया जाता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग के लिए दिशानिर्देश एवं पैरामीटर तैयार करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया स्वैच्छिक है। अब तक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने निम्नलिखित ग्रेड के साथ 172 विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन किया है:

ग्रेड श्रेणी	क	ख	ग
विश्वविद्यालयों की संख्या	67	99	6

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित ग्रेड के साथ 4797 कॉलेजों का प्रत्यायन किया है:

ग्रेड श्रेणी	क	ख	ग
कॉलेजों की संख्या	537	3292	968

(ङ) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार विधायी पहलों के साथ-साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत रूप से प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाना है, दिनांक 03 मई, 2010 को संसद में पेश किया गया है।

शिक्षा एवं शोध नवाचार को क्लस्टर के रूप में विकसित करने एवं अधिगम और डिजाइन में नवाचार को प्रोत्साहित करने, साधनों के विकास एवं उनके वितरण के लिए समर्पित विश्वविद्यालयों को अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए, दिनांक 21 मई, 2012 को अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया है। अन्तर-विषयक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में क्लस्टर नवाचार केन्द्र तथा डिजाईन नवाचार केन्द्रों को प्रारंभ किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने सूचित किया है कि वह उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं, जैसे उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.), उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज (सी.पी.ई.), विशेष सहायता "मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता" (ए.एस.आई.एच.एस.एस.) और मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान (बी.एस. आर.) इत्यादि की कार्यान्वित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपने कार्यक्रम "विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता प्रोत्साहन" (पी.यू.आर.एस.ई.), अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान अध्ययन में नवाचार (इन्सपायर), उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में एस. एंड टी. अवसंरचना के सुधार हेतु निधि (एफ.आई.एस. टी.) इत्यादि के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अनिवार्य तौर पर शोध जनशक्ति लागत, उपकरणों एवं अभिकलन संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने, शोध उपभोज्यों तथा सुविधाओं इत्यादि के अनुरक्षण हेतु सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न-काल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने इसमें जो जवाब दिया है, मैं आपकी अनुमति से पहले उस जवाब के भाग सैकिंड के पैरा दो को पढ़ना चाहता हूं:- "ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणालियां उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को रैंक प्रदान करने के लिए विभिन्न मूल्यों, सूचकांकों एवं पैरामीटरों का प्रयोग करती हैं। ये मापदंड न तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, न ही इन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। इसलिए कई बार इनकी आलोचना की जाती है। इनमें से कुछ पैरामीटर भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रासंगिक नहीं होते हैं, इसलिए ये रैंकिंग भारतीय संस्थाओं के मानकीकरण के लिए आधार नहीं हो सकते।"

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने इस बार जो रैंकिंग की है, उसमें विश्व के दौ सौ श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का चयन किया गया। उनमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आया, इसलिए जो भारतीयता की भावना लिए हुए भारत के नागरिक हैं, उनको बहुत चिन्ता हुई, लेकिन मंत्री जी को उत्तर देते समय कोई चिन्ता नहीं हुई। मंत्री जी ने ये किस तरह का उत्तर दिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपको तो चिन्ता नहीं हुई होगी, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति जी जब आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में भाषण देने गए थे तो उन्होंने जो कोट किया था, उसे मैं कोट कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था - "मेरे लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति होने के बावजूद अपने मानकों को इतना बढ़ाने में सक्षम क्यों नहीं हैं कि शीर्ष दस या शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों में हमारे देश के किसी संस्थान का नाम आ सके।" जब राष्ट्रपति जी भी चिन्ता कर रहे हैं तो हमारे मंत्री जी चिन्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, यह मेरा पहला प्रश्न है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको दूसरे प्रश्न के लिए भी मौका मिलेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमारे तीन लाख से अधिक छात्र ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया आदि देशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, क्या सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वस्तर का ढांचागत विकास करने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिंतित हैं और अपने विश्वविद्यालयों की रेटिंग सुधारने के लिए हम वो समस्त प्रयास कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम शीर्ष 100 में स्थान पाना चाहते हैं; हम शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में जगह पाना चाहते हैं और हमारा यही प्रयत्न होगा और हमारे संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने के प्रति हमारी यही वचनबद्धता है।

साथ ही, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन अंतरराष्ट्रीय रेटिंग के लिए प्रयोग किए गए मानदंड अनिवार्य रूप से हमारी भारतीय स्थिति पर लागू नहीं होते। लेकिन इससे न तो हमारी शिक्षा और न ही हमारे अनुसंधान की गुणवत्ता का अतिक्रमण होता है। फिर भी, जहां तक उच्चतर शिक्षा संबंध है, हमारे विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार का वातावरण है हम उसे सुधारने के प्रति वचनबद्ध हैं। हम असंख्य उपाय कर रहे है और मैं आश्वस्त हूं कि हम इन सभी प्रयासों से अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही प्रश्न पूछिएगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा। मुझे एक प्रश्न तो पूरा पूछने दें, बड़ी मुश्किल से तो कभी प्रश्न-काल में प्रश्न पूछने का नम्बर आता है। मेरा पहले नम्बर पर प्रश्न आया। ...*(व्यवधान)* कई बार आप भी प्रश्न-काल नहीं चलने देते हो। ...*(व्यवधान)* तेलंगाना इश्यू पर हमने नहीं, आपने नहीं चलने दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्षा जी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मूल्यांकन परिषद ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 68 परसेंट विश्वविद्यालय और 90 परसेंट कॉलेजों में उच्च शिक्षा दोषपूर्ण है। इन संस्थाओं के 75 प्रतिशत डिग्रीधारी छात्र बेरोजगार हैं तो इस देश में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? हायर एजुकेशन की दिशा क्या है, GER का स्तर भी जो वर्ल्ड का औसत है, उसके नज़दीक नहीं है, अभी 12 परसेंट ही है। उसको भी ये कह रहे हैं कि हम 2020 तक 30 परसेंट तक ले जाएंगे। मेरा दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि यू.जी.सी. का जो सिस्टम है, जैसे मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, मेरे यहां एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको 12बी की मान्यता देने के लिए भी इनको बहुत तकलीफ आ रही है। 12बी की मान्यता अगर नहीं देंगे तो उनको अनुदान भी नहीं मिलेगा तो मेरा आपके माध्यम से यही प्रश्न है कि सरकार शोध की गुणवत्ता व स्नातक स्तर पर ही रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुलभ कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है और उनको पूरा करने के लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है, क्या रोड मैप है? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया, मैं आपका ध्यान मान्यता प्रदान करने में अधिकारिक अनुपालन को दिए जा रहे प्रोत्साहन की ओर दिलाना चाहता हूं दुर्भाग्यवश, मान्यता प्रदान किए गए विश्वविद्यालयों की संख्या विद्यमान विश्वविद्यालयों की एक तिहाई ही है। अभी यह अनिवार्य नहीं है, परंतु एक विधेयक के माध्यम से, जो कि आज संसद में लंबित है, हम आशा करते हैं कि समस्त विश्वविद्यालय प्रत्यायन प्रक्रिया के अधीन होंगे, जिससे इनकी विश्वसनीयता सुधरेगी और बढ़ेगी। फिलहाल सभी कॉलेजों का केवल पांचवां हिस्सा को ही मान्यता प्राप्त है। इसलिए हम मान्यता प्रदान हेतु अनुपालन को प्रोत्साहन देंगे। मैं आशा करता हूं कि अधिकाधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज मान्यता प्राप्त करेंगे कराएंगे।

जहां तक बीकानेर का संबंध है यदि ये केन्द्र वित्त पोषित विश्वविद्यालय है, तो उसे समग्र सहायता दी जाएगी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किए गए कुछ प्रयासों में विदेश से संकाय, जो विषयों के विशेषज्ञ हैं उन को यहां बुलाने और यहां पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। उन्होंने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

साथ ही साथ, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिक्तियां हैं; उनके संबंध में यथाशीघ्र रिक्तियों को भरने के लिए निदेश दिए गए है। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता दी है, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और इनके वित्तपोषण को बढ़ाया गया है ताकि ये अपने विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हो रहे अनुसंधान की गुणवत्तपरक और मात्रा संबंधी गुणवत्ता को बढ़ा सकें।

[हिन्दी]

श्री नीरज शेखर: अध्यक्षा जी, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि, हमको लगता था कि उच्च शिक्षा या शिक्षा की तरफ इस सरकार का जो रवैया था, वह गम्भीर नहीं था। पहले एक ऐसे मंत्री थे, जिनके पास दो विभागों का भार था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इतना बड़ा मंत्रालय है, पर अब मुझे लगता है कि नये मंत्री आये हैं, इनको हम लोगों की, पूरे सदन की शुभकामनाएं हैं कि ये अच्छा काम करेंगे।

शिक्षा का बहुत गंभीर विषय है, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में 12.5 लाख शिक्षक कम हैं और उससे भी ज्यादा गम्भीर समस्या उच्चतर शिक्षा में है, जहां कि हम लोग गुणगान करते हैं कि आई.आई.टी., आई.आई.एम. और पता नहीं कौन-कौन से विद्यालय हैं, जिनका दुनिया में नाम है, लेकिन वहां पर भी शिक्षकों की कमी है। वहां भी एक तिहाई शिक्षकों की कमी है। अभी मैं पढ़ रहा था कि किसी आई.आई.टी.ज़ में करीब 1500 वेकेंसीज़ हैं, आई.आई.एम. में हैं, यूनिवर्सिटी विश्व केन्द्र में हैं और शिक्षकों का जो स्तर है, वह कहां पर है, वह सब जानते हैं।

मेरा मंत्री जी से बस यही प्रश्न है कि शिक्षकों का स्तर बढ़ाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, इस सरकार की क्या सोच है और आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं, मैं यह भी जानना चाहूंगा? यह नहीं कहें कि क्या होने वाला है, यह बतायें कि क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : अध्यक्ष महोदया, जहां तक उच्चतर शिक्षा की क्षमता का संबंध है, मेरे विचार से हमने बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से ग्यारहवीं योजना में 40 केन्द्र-वित्तपोषित विश्वविद्यालय, सात नए आई.आई.एम., आठ नए आई.आई.टीज, दस नए एन.आई.टीज. और पांच नए आई.आई.एस.ई.आर.जे. स्थापित किए हैं। परंतु जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उच्चतर शिक्षा में लगभग 30 प्रतिशत की सीमा तक संकाय की कमी है। हम इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रयासरत हैं। हम आशा करते हैं कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने के साथ-साथ हम यथाशीघ्र इन रिक्तियों को भर पाएंगे। इसी प्रकार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, इन संस्थानों में लाए जाने वाले संकाय सदस्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज: महोदया, मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराख.ड देवभूमि है और वहां पर वेदनीबोग्याल में वेदों की रचना की गयी, व्यास महाराज ने वहां महाभारत को लिखा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के अन्दर शिक्षा का बहुत प्रचार-प्रसार है। अगर राज्य सरकार कुमायूं के अन्दर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजेगी तो क्या मंत्री जी उस पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कई केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और ये निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ मामलों में, अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसलिए, हमारी पहली प्राथमिकता अपने प्रयासों को समेकित करने की होगी। निस्संदेह, हमारा उद्देश्य उन क्षेत्रों को शामिल करना है जो इसमें सम्मिलित नहीं है और निश्चित तौर पर हम भावी योजना में उत्तराखंड पर विचार करेंगे।

श्री सी. राजेन्द्रन : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम सभी समझते हैं, गत एक दशक या लगभग इसी अवधि में संपूर्ण भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इसका एक मुख्य कारण धन का महत्व है। इन संस्थानों में पढ़ने के बाद विद्यार्थी धन कमाने के लिए चले जाते हैं और नवोन्मेष तथा अनुसंधान के प्रति रूझान नहीं दिखाते। यही कारण है जिसकी वजह से नई अंक प्रणाली अंतर्गत शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में हमारे आई.आई.टीज और आई. आई.एम.ज विफल होते हैं यहा तक कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों में भी लोग शिक्षण कार्य नहीं करना चाहते है। कालेज स्तर पर विद्यार्थी नवोन्मेष और अनुसंधान कार्य करे हमारी सरकार क्या प्रयास कर रही हैं यह सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को और प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण कार्य करें ताकि हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को विश्व स्तर तक लाया जा सके?

श्री एम.एम. पल्लम राजू : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि संकाय की कमी है और शिक्षण व्यवसाय में रूचि कम हो रही है। सुनिश्चित करने के लिए हमें गुणवत्तापरक संकाय मिले और अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जाए। समग्र उपाय करने होंगे। निसंदेह, उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्पन्न वातावरण का प्रभाव पड़ता है अगर आर.आई.आई.टीज और आई.आई.एमज के क्लस्टर वातावरण के देखेंगे जहा उद्योग को अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इन क्लस्टरों में नवोन्मेष अनुसंधान होने जा रहे है। निसन्देह उद्योग के साथ और अधिक सुदृढ़ सम्पर्क की आवश्यकता जिससे कि इस अनुसंधान का वित्तपोषण हो। एक बार विश्वविद्यालय द्वारा मौलिक अनुसंधान का वित्तपोषण किए जाए

तो उस उद्योग विशेष द्वारा अनुसंधान का अनुप्रयोग जारी रखा जा सकता है जिसने इस अनुसंधान का वित्तपोषण किया है। हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे विश्वविद्यालयों में होने वाले अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

मैं समझता हूं कि एक बार ऐसा वातावरण तैयार हो जाएगा तो नए संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए काफी आकर्षक वातावरण तैयार हो जाएगा।

डा. रत्ना डे : 1947 में हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति, से अब तक 65 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। मैं अपने विश्वविद्यालयों की तुलना विदेशी विश्वविद्यालयों से नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा विश्वास है कि अपवादस्वरूप मुट्ठी भर विश्वविद्यालयों के अलावा, ज्यादातर विश्वविद्यालयों का वांदित स्तर और गुणवत्ता नहीं है। हम अपने विश्वविद्यालयों के उच्चस्तरीय होने की डींग नहीं हांक सकते अथवा उनकी तुलना पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से नहीं कर सकते। दूसरी ओर, 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 8 अक्तूबर, 2012 को छपे एक समाचार के अनुसार, गत दो वर्षों में 225 बिजनेस स्कूल और 52 इंजीनियरी महाविद्यालय बंद हो चुके हैं।

विश्वविद्यालयों के मामले में भी स्थिति ऐसी ही खराब है। ऐसी परिस्थितियों में, क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि हम दुनिया के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों की तुलना में कहां ठहरते हैं? गत दो वर्ष में देश में विश्वविद्यालयों के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्री एम.एम. पल्लम राजू : यद्यपि विश्वविद्यालयी अनुसंधान का रैंक अच्छा नहीं है, तथापि यदि आप आई.आई.टी. जैसी संस्थाओं को देखें तो पाएंगे कि 'क्यू एस' रैंकिंग में हमारी चार आई. आई.टी. शीर्ष साठ विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, खर्च की जाने वाली राशि से विश्वविद्यालयी अनुसंधान की गुणवत्ता पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। वर्तमान में, यह हमारे जी.डी.पी. का केवल लगभग 0.8 प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि सरकार को आगामी वर्षों में ज्यादा व्यय होने की उम्मीद है। लेकिन यदि आप पुन: शोध पत्रों की संख्या देखें तो हमारा रैंक काफी अच्छा है। स्पष्टत: गुणवत्तापूर्ण शोधपत्रों की कमी है। मुझे विश्वास है कि अनुसंधान पर होने वाले व्यय में वृद्धि से शोधपत्रों की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा।

श्री एम.बी. राजेश : माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने हमें आश्वस्त किया था कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल को एक आई.आई.टी. दी जाएगी। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बारहवीं योजना के प्रस्तावों में, यह आश्वासन कहीं नजर नहीं आता। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमें आश्वस्त करेगी कि केरल में एक आई.आई.टी., जो केरल की एक दीर्घावधि से लंबित मांग है, स्थापित की जाएगी और क्या इसे बारहवीं योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाएगा। क्या मंत्री महोदय हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि केरल को बारहवीं योजनावधि के दौरान ही आई.आई.टी. दे दी जाएगी?

श्री एम.एम. पल्लम राजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केरल के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। पुन:, कुल मिलाकर, देशभर में उच्च शिक्षा की क्षमता सृजन विशेषत: आई. आई.टी. स्थापित करने की बात है। ग्यारहवीं योजना में हमने आठ नई आई.आई.टी. स्थापित की थीं। अब हमारा प्रयास इस सृजित क्षमता को समेकित करने का होना चाहिए। हमारा प्रयास नए संकाय प्राप्त करने, विषयों को चलाने, नई स्थापित आई.आई.टी.एस. में अनुसंधान में सुधार करने के बारे में है। परन्तु मैं केरल को नजर अंदाज नहीं करुंगा। हम निश्चित रूप से विचार करेंगे लेकिन हमारी प्राथमिकता इसे समेकित करना ही है।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास: अध्यक्ष महोदया, यह सौभाग्य की बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी सदन में मौजूद हैं और उन्होंने भी फाइनैंस मिनिस्टर के रूप में हायर एजुकेशन को जिस तरह महत्व दिया था उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। मैडम, प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया गया है कि किस तरह से क्वालिटी में फर्क आया है। यह सौभाग्य की बात है कि हम आईआईएम और आईआईटीज में तो आगे हैं लेकिन यह दुर्भाग्य है कि चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो या यूनिवर्सिटी के क्वालिटी की बात हो, हम काफी पिछड़े हैं। सब से बड़ी बात यह है कि इसमें राजनीतिकरण भी एक कारण है। वाइस चांसलर से ले कर फैकल्टी मेम्बर्स तक के चयन की प्रक्रिया हो, इसको पारदर्शी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

जो थर्टी परसेंट वेकेन्सिज हैं जिसको माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के हायर ऑफ द डिपार्टमेंट्स के पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा? यूजीसी का यहां पर जिक्र किया गया है। जब यूजीसी के चेयरमैन का भी पद अभी तक रिक्त हो तो हम क्या आशा कर सकते हैं? क्या इस दिशा में कुछ प्रयास होंगे?

विशेषकर मेरा प्रश्न राजनीतिकरण से भी है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज में राजनीतिकरण के पदार्पण को रोका जा सकता है?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य

ने कुछ टिप्पणियां की हैं जिन पर मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन हमारे संस्थानों, विशेषत: विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है और मैंने उन उपायों की रूपरेखा बता दी थी जो हमने किए है। रिक्तियों को भरने के लिए यू.जी.सी. ने दिशा निर्देश और निदेश दिए हैं और विश्वविद्यालयों में ज्यादा अनुसंधान उन्मुखी संकाय लाने के लिए यू.जी.सी. सजगतापूर्व प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि केन्द्र और राज्यों के सहयोग से हम देशभर में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे और इस अवसर पर मै। सभा से कुछ विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूं जो लोक सभा में लंबित है, जिनसे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा।

दूरसंचार प्रयोक्ताओं में कमी

†

*162. **श्री के. सुगुमार :**
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं का वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले तीन वर्षों में नए टेलीफोन कनेक्शनों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तथा इस पर कितना खर्च होगा;

(ग) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान दूरसंचार प्रयोक्ता आधार में काफी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और आपरेटर-वार ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप राजस्व की कितनी हानि हुई; और

(ङ) मोबाइल टेलीफोन प्रयोक्ता आधार में गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का वर्ष-वार और सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दूरसंचार अवसंरचना में 6.5 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 500 मिलियन लाइनों की वृद्धि होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) वर्ष 2012-13 की प्रथम तिमाही के दौरान, टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 951.35 मिलियन से बढ़कर 965.52 मिलियन हो गई है। दूसरी तिमाही में, टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 965.52 मिलियन से घटकर 937.70 मिलियन रह गई है। दिनांक 30.06.2012 और दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों का सेवा क्षेत्र-वार और प्रचालक-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। जून, 2012 के बाद दूरसंचार प्रयोक्ताओं की संख्या में कमी, अन्य बातों के साथ-साथ निष्क्रिय मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों को हटाने और शहरी क्षेत्रों में उच्च टेली-घनत्व के कारण हुई है। दूरसंचार प्रचालकों का राजस्व, टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या सहित अनेक कारकों पर आधारित होता है। अनंतिम आंकडों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष (2012-13) की दूसरी तिमाही के दौरान अभिगम सेवा प्रदाताओं के समेकित सकल राजस्व में वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की तुलना में कोई कमी नहीं आई है।

(ङ) मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस मोबाइल नेटवर्क की क्षमता विस्तार करना।

(ii) बी.एस.एन.एल. ने छितरे हुए और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, जहां लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, में वायरलैस इन लॉकल लूप नेटवर्क संस्थापित किया है।

(iii) बी.एस.एन.एल. ने राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों और राज्य राजमार्गों पर अपना मोबाइल नेटवर्क संस्थापित किया है।

(iv) देश में ऐसे विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्स्ड वायरलैस अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों (टॉवरों) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से राजसहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाताओं द्वारा लगभग 7310 स्थल और 15895 बेस ट्रांसीवर स्टेशन चालू किए गए हैं।

अनुबंध-I

मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	मार्च के अंत में मोबाइल टेलीफोन उपभोगक्ताओं की संख्या			दिनांक 30.09.2012 की के अनुसार कुल मोबाइल फोन
		2010	2011	2012	
1.	आन्ध्र प्रदेश	45624764	60676836	66827458	67592326
2.	असम	8756053	11670711	14208075	14991563
3.	बिहार (झारखंड सहित)	36973251	53541241	63481021	61075669
4.	गुजरात	32349149	46957643	53321886	52946920
5.	हरियाणा	14134799	20389507	22558305	20724685
6.	हिमाचल प्रदेश	4985373	7215932	7971334	7000754
7.	जम्मू और कश्मीर	5547277	5754286	6306835	6789483
8.	कर्नाटक	37132731	49449711	55713994	55976300
9.	केरल	24194621	31361008	34016112	33331336
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	31979765	45825174	51622367	53136781
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	43515981	61716246	70469385	68026038
12.	पूर्वोत्तर	5309850	7184577	8518317	9175549
13.	ओडिशा	15271727	22415369	26618935	25430051
14.	पंजाब	20096890	28761275	31953577	30176437
15.	राजस्थान	33740879	43100379	49159964	49429415
16.	तमिलनाडु (चेन्नै सहित)	53682712	69632613	77678330	77813371
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	44031988	63679385	75074369	74584908
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड संहित)	30646855	45767008	53637361	51461270
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर और और अंडमान निकोबार और सिक्किम सहित)	25165389	39661517	46272843	46039006
20.	कोलकाता	16401874	23213389	24990125	24871370
21.	दिल्ली	28299590	38824604	42489287	41971202
22.	मुंबई	26481884	34799906	36284655	34073566
	अखिल भारत - जोड़	584323402	811598317	919174535	906618000

अनुबंध-II

दिनांक 30.06.2012 और दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
(सेवा क्षेत्र-वार और प्रचालक-वार)

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	भारती		टाटा		क्यूरडेंट	
		30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012
1.	आन्ध्र प्रदेश	18967369	18819223	8081616	8059901	0	0
2.	असम	3877114	3875298	133709	131079	0	0
3.	बिहार (झारखंड सहित)	18296280	18047516	4812084	4332598	0	0
4.	गुजरात	7391407	7251826	3728265	3530452	0	0
5.	हरियाणा	2525217	2362209	2924249	2831489	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	1902855	1907002	316526	261189	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	2193528	2269768	109445	113547	0	0
8.	कर्नाटक	16343194	16653569	7116050	7520971	0	0
9.	केरल	3737463	3561953	2414542	2269886	0	0
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	10318034	10170263	4899619	4477145	0	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	10390379	10077691	8407136	7324354	0	0
12.	पूर्वोत्तर	2504849	2519084	79304	80348	0	0
13.	ओडिशा	6605276	6622129	2524606	2488710	0	0
14.	पंजाब	7094419	6999997	2826257	2771388	1708410	1795013
15.	राजस्थान	14800481	14778584	3747077	3592148	0	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नै सहित)	14171103	14180446	5179380	6320877	0	0
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	15304668	15132404	4631128	4643014	0	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	6760153	6701463	4665792	4632824	0	0
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर और अंडमान निकोबार और सिक्किम सहित)	9265276	9313894	2943184	2612630	0	0
20.	कोलकाता	3995116	3847958	3210879	3083424	0	0
21.	दिल्ली	10032545	10186407	4175033	4136954	0	0
22.	मुंबई	4097461	3918417	4759383	4613671	0	0
	जोड़	190674187	189197101	81685264	79828599	1708410	1795013

लूप मोबाइल		एयरसेल		रिलायंस		वोडाफोन	
30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012
0	0	1820961	1975021	8284649	8134155	6276567	6402233
0	0	3838600	3778274	3064741	3247231	2353212	2319970
0	0	5147125	5288139	9492672	8763607	6476332	6502289
0	0	769189	791597	8573162	7679404	16047223	16242042
0	0	628661	652062	4365198	2597502	4551481	4492681
0	0	753575	720753	1946706	1563891	485278	483741
0	0	1766692	1770577	576149	597315	719029	685776
0	0	1261944	1485942	8465937	7440903	6904322	6863076
0	0	1873532	1777913	4432805	3505841	6012026	6062344
0	0	999014	986875	12952186	12972542	4248431	4498540
0	0	1079177	1191470	11444543	8677024	13265810	13291015
0	0	2453678	2495094	994562	1110159	1003492	980574
0	0	2782969	2894773	4828996	4381184	2703241	2814933
0	0	996674	1117329	4207744	3320347	4574540	4459835
0	ए 0	2192300	2625234	7558807	6476544	9246863	9236300
0	0	22358680	22235152	9039641	8175661	12564127	12341081
0	0	3029969	3398510	12786496	10983840	15400233	14821222
0	0	2200315	2153133	10402228	7814072	9826547	9352384
0	0	2916474	3042615	8110135	7173009	12005875	11709129
0	0	1870717	1884904	5853204	5304368	4272356	4305030
0	0	2781763	2928704	9406372	8674170	8894335	8756181
3150650	3028539	1354795	1413290	9082252	7514257	5897077	6067521
3150650	3028539	64876804	66607361	155869185	136107126	153728397	152687897

दिनांक 30.06.2012 और 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
(सेवा क्षेत्र-वार और प्रचालक-वार)

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	आइडिया		यूनिनोर		वीडियोकॉन	
		30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012
1.	आन्ध्र प्रदेश	10545813	10728762	4056918	3996512	9878	9763
2.	असम	359132	372559	521	673	0	0
3.	बिहार (झारखंड सहित)	5964298	5494988	4852738	4942685	18867	18726
4.	गुजरात	8606504	8216677	4059900	4054136	1157060	950766
5.	हरियाणा	3876555	3687543	649	461	1007896	849452
6.	हिमाचल प्रदेश	489163	482365	166	150	77037	44589
7.	जम्मू और कश्मीर	195572	201974	302	314	0	0
8.	कर्नाटक	5959122	6225658	2203556	1098040	8365	8189
9.	केरल	7695590	7712256	738427	404750	148370	49756
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	14499964	14429519	1320	1289	1064985	941265
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	15425757	15219023	5134325	5399721	8820	8814
12.	पूर्वोत्तर	232322	250036	89	94	0	0
13.	ओडिशा	1052624	1011626	1588820	745951	10673	10673
14.	पंजाब	5645347	5599541	1210	434	0	0
15.	राजस्थान	4469297	4521563	1079	1037	8392	7619
16.	तमिलनाडु (चेन्नै सहित)	2231538	2284356	2221039	1112982	1269726	876259
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7925598	7237189	7774581	7527122	14876	14865
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	10631230	10265870	5242602	4888479	8067	5581
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर और अंडमान निकोबार और सिक्किम सहित)	2253211	2411507	4163771	4119373	17194	16506
20.	कोलकाता	1304676	1355899	1981179	2056696	4096	4096
21.	दिल्ली	4853688	4801988	0	0	0	0
22.	मुंबई	2947341	2953838	1554571	1795446	746786	634284
	जोड़	117164342	115464737	45577763	42146345	5579086	4451203

एस.एस.टी.एल.		बी.एस.एन.एल.		एम.टी.एन.एल.		सभी प्रचालक	
30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012	30.06.2012	30.09.2012
682434	700753	11058999	11054600	–	–	69785202	69880923
1247	1286	1470909	1463831	–	–	15099185	15190201
1688266	1633546	6576403	6614042	–	–	63325065	61638136
198096	238828	5778440	5775511	–	–	56309246	54731239
234403	231421	3566109	3598247	–	–	23680418	21303067
76	69	1778300	1834724	–	–	7749682	7298473
22	19	1314555	1351697	–	–	6875294	6990987
2322809	2392347	8728995	8748656	–	–	59314294	58437351
623707	614243	10350821	10509818	–	–	38027283	36468760
2704	2978	5680673	5777110	–	–	54666930	54257526
724899	710690	8314966	8698848	–	–	74195812	70598650
176	176	1924963	1989915	–	–	9193435	9425480
734	814	4847091	4855936	–	–	26945030	25826729
1016	1120	5432925	5517618	–	–	32488542	31582622
2626619	2522667	6720262	6776754	–	–	51371177	50538450
1643605	1506155	12020548	11941731	–	–	82699387	80974700
611580	672831	11140142	11235401	–	–	78619271	75666498
637976	698580	5671280	5729647	–	–	56044190	52242033
1948057	2005219	4243513	4247340	–	–	47866690	46651222
883589	910611	3367605	3274830	–	–	26743397	26027818
1194507	1261197	–	–	4389461	4161701	45727704	44907302
571841	537860	–	–	4634454	4586035	38796611	37063158
16598343	16643410	119987499	120996256	9023915	8747736	965523845	937701323

श्री के. सुगुमार : महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए पूरे उत्तर के दौरान कहीं भी लैंडलाइन टेलीफोन कनैक्शन की उल्लेख नहीं था। इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि टेलीफोन कनैक्शन का अर्थ मोबाइल कनैक्शन है। यह ठीक है कि हमें किसी भी प्रणाली से दूरसंचार के घनत्व को भेदना चाहिए। पर साथ ही लैंडलाइन टेलीफोन कनैक्शन को एक बीत पूर्व निष्कर्ष मानकर छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ समय पहले विद्युत ग्रिड फेल होने के उदाहरण पर विचार कीजिए। पूरा देश अंधकार में डूब गया था। इसी प्रकार यदि मोबाइल नेटवर्क को कुछ हो जाता है तो संचार के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। अत: हमें लैडलाइन टेलीफोन कनैक्शन को भी समान महत्व देना चाहिए और लैंडलाइन सुविधा को समाप्त नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले एक उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बताया था कि केवल इस वर्ष के दौरान ही अप्रैल से अक्तूबर के बीच भारत संचार निगम लिमिटेड के 17.9 लाख उपभोक्ता और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 2,03,000 ग्राहक लैंडलाइन कनैक्शन वापस कर चुके हैं। क्या सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर लैंडलाइन कनैक्शनों की वापसी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है? अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार लैंडलाइन टेलीफोन कनैक्शनों की वापसी को रोकने के साथ ही देश में मोबाइल फोन के धावा बोलने से पहले व्याप्त दूरभाष की लोकप्रियता को वापस लाने के लिए कार्ययोजना पर विचार कर रही है।

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदया जो प्रश्न पूछा गया वह पिछले तीन सालों और चालू वर्ष के दौरान देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के वर्ष वार और राज्य वार आंकड़ों से संबंधित था। इसीलिए हमने लैंडलाइन कनैक्शनों का कोई उल्लेख नहीं किया। पर मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने में अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक लैंडलाइन टेलीफोन का संबंध हैं स्पष्ट: कि यह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है क्योंकि उपभोक्ता निर्धारित करता है कि क्या वह लैंडलाइन की बजाय मोबाइल फोन को प्राथमिकता देगा। हम उपभोक्ता पर न तो लैंडलाइन रखने का दबाव डाल सकते हैं और न ही लैंडलाइन वापस न करने के लिए आग्रह कर सकते हैं यह पूर्णत: उपभोक्ता की इच्छा है। पर काफी हद तक मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में लैंडलाइन की लहर तेज हो जाएगी इसका साधारण कारण यह है कि कुछेक वर्षों में हम लैंडलाइन पर ब्रॉडबैंड की सुविधा देने जा रहे हैं। लैंडलाइन पर ब्रॉडबैंड का अर्थ होगा लैंडलाइन पर डेटा डिलिवरी। मुझे लगता है कि वह उपभोक्ताओं की अधिक लैंडलाइन लेने की इच्छा को बढ़ाएगा क्योंकि यह बहुत सस्ता होगा चूंकि इसे फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से भेजा जाएगा। आपके पास एक दूरभाष उपकरण होगा जिसमें एक वीडियो लगा होगा, जो फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से भेजा जाएगा, इस प्रकार आने वाले वर्षों में लैंडलाइन का प्रयोग बढ़ेगा। बी.एस.एफ.एल. उस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अध्यक्ष महोदया: दूसरा प्रश्न। यह मूल प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। उसकी परिधि से बाहर न जाएं

श्री के. सुगुमार : महोदया, एक और बात जो मैं माननीय मंत्री के संज्ञान लाना चाहता हूं, वह है तंग करने वाली कालों और एस.एम.एस. के बारे में। भारतीय दूरभाष विनियामक प्राधिकरण ने इस विघ्न को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं पर निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाता राजस्व कमाने के लिए अभी भी इसे जारी रखे हुए हैं। मेरा मानना है कि मोबाइल घनत्व में कमी के कारणों में से यह भी एक है कि कई उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध नियम पारित करने अथवा कठोर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदया, फिर से माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका किसी प्रकार पटल पर रखे प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : हां, यह सही है। श्री पी. विश्नाथन

श्री पी. विश्वनाथन : प्रश्न संख्या 162.

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 162 चल रहा है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी. विश्वनाथन : अध्यक्ष महोदया, स्पैक्ट्रम का आवंटन प्रचालकों के नेटवर्क पर उपभोक्ताओं की संख्या से संबंधित था। किन्तु हाल ही की सरकार नीति के अनुसार भावी आवंटन बाजार द्वारा निर्धारित नीलामी कीमत द्वारा किया जाएगा। स्पैक्ट्रम की उपलब्धता का उपयोग करने के लिए प्रचालक अपने लाभ को अधिकतम करने हेतु अपने नेटवर्क पर उपभोक्ताओं द्वारा अधिकाधिक उपयोग प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करने की योजना बनाऐंगे। प्रचालक उपभोक्ता नंबरों को जोड़ने और नेटवर्क योजना पर कार्य नहीं करेंगे। अत: मैं जानना चाहता हूं कि की क्या उस स्थिति में सरकार अपनी नीति बाजार आधारित नीलमी पर परिवर्तित करेगी अथवा पहले की पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाएगी।

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, मैं यह आंकड़े इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि पहली बार मोबाइल फोन क्षेत्र में जुलाई से सितम्बर 2012 के बीच उपभोक्ताओं की संख्या में 27.82 मिलियन की कमी आई है। मैं समझता हूं कि यह कमी और बढ़ेगी तथा अनेक उपभोक्ता इसे छोड़ देगे। इसका विस्तार 208 मिलियन का होगा। इसका अर्थ है कि आपका वर्तमान उपभोक्ता आधार जो कि लगभग 900 मिलियन से अधिक है वह 700 मिलियन तक आ जाएगा। इसका कारण है कि पुरानी नीति के अंतर्गत यदि आपके पास अधिक उपभोक्ता हो तो आपको अधिक स्पैक्ट्रम मिल सकता था; और दूसरी बात यदि आपके पास उपभोक्ताओं की अधिक संख्या है तो आप डी. ओ.टी. के द्वारा विशिष्ट नम्बर पा सकते थे।

अब नीति बदल चुकी है। इनमें से कई टेलीफोन संचालित नहीं किए गए। शहरी क्षेत्रों में अनेक लोगों जिनकी टेलीडेन्सिटी 160 प्रतिशत है, उनके पास दो या तीन से अधिक टेलीफोन थे। हालांकि संचालकों ने उन टेलीफोनों को काटा नहीं है क्योंकि पुरानी नीति के अंतर्गत उन्हें लाभ होगा। अब चूंकि नीति बदल चुकी है और जहां तक 2जी का संबंध है हमने नीलामी का रास्ता अपनाया है, स्वभाविक रूप से इससे संचालक को कोई लाभ नहीं हैं। अत: वे सभी कनैक्शन काट रहे हैं जो उपयोग में नहीं हैं। अत: वास्तविकता यह है कि हमारे टेलीफोन 937 मिलियन नहीं बल्कि 650 से 700 मिलियन के बीच हैं। इसलिए अभी भी 500 मिलियन लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पस कोई मोबाइल फोन नहीं है। यह स्थिति है मुझे विश्वास है कि निजी क्षेत्र और बी.एस.एन.एल. दोनों सुनिश्चित करेंगे कि बाकी 500 लाख के पास भी एक मोबाइल फोन की पहुंच हो। हम नीति बदलने का विचार नहीं रखते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदया, इस सदन में बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं के बारे में बराबर चिंता व्यक्त होती रही है। पूरे देश में एक जैसी दुर्व्यवस्था है। जब भी बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं का कोई प्रयोग करता है, तो उसमें या तो सेवा नहीं रहती या फिर बिजी दिखाता है। यही कारण है कि पिछली तिमाही में काफी बड़ी संख्या में बीएसएनएल के मोबाइल फोन की संख्याओं में कमी आयी है।

मैं आपका ध्यान केवल गोरखपुर से सोनोली, जो राजमार्ग 29 है, की तरफ ले जाना चाहता हूं। पिछले तीन वर्षों से मैं बीएसएनएल के अधिकारियों को लिखते हुए थक गया हूं। मैंने कई बार उनसे बातचीत भी की है कि इस राजमार्ग पर यह मोबाइल सेवा काम नहीं करती, जबकि अन्य प्राइवेट मोबाइल आपरेटर्स की सेवाएं काम करती हैं। अंत में मेरे से बीएसएनएल का एक अधिकारी बोला कि आप बीएसएनएल का मतलब जानते हैं? मैंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाईसाहब नहीं लगेगा। यह बीएसएनएल का मतलब है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी इस मंत्रालय को वहीं ले जाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपना प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता अन्य प्राइवेट आपरेटर्स की तुलना में अत्यंत ही खराब है। आप उसमें सुधार करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आप पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये सेवाएं और कम होंगी, तो इसे बढ़ाने के लिए मंत्रालय क्या करने जा रहा है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब मंत्री जी का जवाब सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बलः अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का कहना सही है कि बीएसएनएल की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, जितनी प्राइवेट सैक्टर ही है। यह बात सही है। *...(व्यवधान)* खासतौर पर नार्थ ईस्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः यह क्या हो रहा है। मंत्री जी को जवाब पूरा करने दीजिए। पूरा जवाब सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः ऐसे कैसे खड़े हो गए? बैसीमुथियारी जी, आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए। जवाब सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बलः उसकी मूल वजह यह है।*...(व्यवधान)* उसकी मूल वजह यह है कि पिछले तीन साल से बीएसएनएल कोशिश कर रहा है कि उसके टेंडर्स कंप्लीट हो जाएं ताकि हम कोर नेटवर्क लगा सकें। लेकिन पिछले तीन साल से कोई टेंडर सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी 15 मिलियन का एक टेंडर सक्सेसफुल होने जा रहा है, उसके बाद जब कोर नेटवर्क लगेगा, तो पूरी तरीके से बीएसएनएल की सर्विस बेटर हो जाएगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न किसान समुदाय के लिए संयोजकता से संबंधित है, जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जब भी वे अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो वे अपनी फसल मध्यस्थों के द्वारा बेचते हैं और इसीलिए उनकी आय कम होती जा रही है। अतः मैं अपने मित्र श्री कपिल सिब्बल जो कि भारत में विकासात्मक गतिविधियाँ लाने में सदा प्रगतिशील और सक्रिय रहे है; से पूछना चाहता हूं कि क्या वे छोटे और मझोले किसानों को मुफ्त कनैक्शन देंगे ताकि वे पूरे दिन बाजार तक पहुँच बना सकें।

श्री कपिल सिब्बल : महोदया मैं वचन तो नहीं दे सकता कि मुफ्त पहुँच हो जाएगी, पर मैं केवल अपने विशिष्ट सहयोगी को विश्वास दिला सकता हूँ कि अगले एक से डेढ़ साल में हम 2,50,000 ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से जोड़ देंगे। जैसे ही फाइबर ऑप्टिक्स सयोजकता हो जाएगी तो सेवाएं बहुत ही सस्ती हो जाएंगी क्योंकि वह ऐसा हाईवे होगा जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना और डाटा, जिसमें 'वायस' भी शामिल है, प्रवाहित हो सकता है। अंतिम मील की संयोजकता तारारहित ब्रॉडबैंड के माध्यम से की जाएगी।

अगले दस वर्षो या इसके आसपास की अवधि से 'वायस' पर कोई अधिमार नहीं होना चाहिए, न केवल किसानों बल्कि सबके लिए ऐसा होना चाहिए। टेलीफोन संचालक (ऑपरेटर) की डाटा पर कार्य करना चाहिए और डाटा पर अपना पैसा कमाना चाहिए न कि वायस पर क्योंकि अंततः संचार के लिए वायस पर क्योंकि अंततः संचार के लिए 'वायस' (ध्वनि) पर कोई कर नहीं होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे और टेलीफोन ऑपरेटरों को इससे अलग रहने के लिए समझाएगे कि लोगों को वायस के लिए प्रभार न लगाए अपितु डाटा पर प्रभार लें और इस प्रकार उन्हें अपना राजस्व कमाना चाहिए। हम इस प्रकार से करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में सुविधाहीन, छोटे लोग और छोटे किसान पहले आगे आएंगे।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादवः अध्यक्ष महोदया, पहले जब बेसिक फोन था और नई टेक्नोलॉजी - मोबाईल आई, तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आज उसमें भारी दिक्कत है, जिसके बारे में आदरणीय स्वामी जी ने प्रश्न पूछा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी जिलों में टीडीएम कार्यालय के स्तर पर एक टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। जब सांसद अपने क्षेत्र में घूमते हैं, वहां जो टेलीफोन की समस्या होती

है, उसके लिए बैठक होती है, उसमें सांसद मेंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है कि एक सांसद के क्षेत्र में कई जिले हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में हमारा क्षेत्र खगड़िया है, उसमें तीन जिले खगड़िया, सहरसा और समस्तीपुर हैं और तीन टीडीएम कार्यालय हैं। टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी में सांसद को रखा गया है, लेकिन उसमें एक जिले की कमेटी में ही हम सदस्य होते हैं। एक पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा था। इन्होंने एक पत्र के जवाब में लिखा है कि सांसद एक ही जगह सदस्य हो सकते हैं। अगर एक ही जगह सदस्य रहेंगे, तो फिर जो जगह की जो समस्याएं होंगी, उनको सांसद कहां रखेंगे?

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह एक संसदीय क्षेत्र में जितने भी टीडीएम कार्यालय हैं और जहां-जहां भी टेलीफोन एडवाइजरी कमेटीज हैं, सभी में सांसद को रखने में क्या दिक्कत है और क्या आप ऐसा निर्देश देंगे कि सांसद के संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों की सभी टेलीफोन एडवाइजरी कमेटीज में सांसद सदस्या हो?

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, सदस्य ने जो सवाल पूछा है, हालांकि वह मूल प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता, फिर भी मैं उसका जवाब देता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शांत हो जाएं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: मैं बता रहा हूं कि इस पर हम चर्चा करके फैसला करेंगे कि यह हो सकता है या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो।

[अनुवाद]

श्री बैजयंत पांडा : अध्यक्ष महोदया, भारत में मोबाइल फोन कनैक्शनों की अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ यह सेवा बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कलकानगिरी, ओडिशा के ग्रामीण जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी पिछले हफ्ते मैंने यात्रा की थी। वहाँ एस.पी. कार्यालय, कलैक्टर कार्यालय और यहाँ तक कि सीमा सुरक्षा बल ब्रिगेड के पास भी पर्याप्त फोन कनैक्शन नहीं हैं और उन्हें तो सार्वजनिक क्षेत्र और न ही निजी क्षेत्र के संचालकों से उचित सेवा मिल रही है। इसी प्रकार मेरे अपने संसदीय क्षेत्र केन्द्रपाड़ा, जो कि वास्तव नहीं आते। यह स्वभाविक है क्योंकि अधिकतर दूरसंचार संचालक अपनी सेवाएं लाभप्रद बाजारों में देना अधिक पसंद करते हैं, न कि अलाप्रद बाजारों में। इस उद्देश्य के लिए कई वर्षों से सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) नामक एक (उपस्कर) लगाया गया है। टेलीकॉम संचालकों से उनके लाभप्रद सर्किलों में एक उपकर लिया जाता है और यह उन ग्रामीण क्षेत्रों, हेतु होता है जहां ये सेवाएं कम हैं में प्रचालनों को सहायता देने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

हमने कई बार इस सदन में चर्चा की है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें बताएं कि क्या अब इसका समुचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है और यदि नहीं तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित सेवाएं देने के लिए यू.एस.ओ. का प्रयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने पार विचार किया जा रहा है?

श्री कपिल सिब्बल : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं। वास्तव में भारत में ग्रामीण टेलीघनत्व लगभग 40 प्रतिशत और शहरी टेलीघनत्व 100 प्रतिशत है। अत: स्वभाविक है कि इनमें से अधिकांश क्षेत्र, न केवल ओडिशा अपितु संपूर्ण पूर्वोत्तर, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग और बिहार के कुछ हिस्सों में सेवाएं नहीं है। कारण बहुत ही साधारण है। जहाँ तक निजी क्षेत्र का संबंध है, वे उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते है, जहाँ अधिक राजस्व और मुनाफे की संभावना हो ताकि वे वास्तव में उसे आगे निवेश कर सकें।

जहाँ तक यू.एस.ओ. निधि का संबंध है, हां, हमारे पास ऐसी निधि है और सम्पूर्ण निधि 20,000 करोड़ रूपए से कुछ अधिक है। हम एन.ओ.एफ.एन. स्कीम के साथ बढ़ रहे हैं जहाँ हम जोड़ना चाहते हैं जैसाकि मैंने कहा 2,50,000 गांवों को फाइबर ऑप्टिक्स के साथ जोड़ा जाना है और यू.एस.ओ. निधि को 20,000 करोड़ रूपए इसी के लिए आवंटित हैं। जब यह हो जाएगा तो बोईजकता की प्रकृति और गुणवत्ता भी बदल जाएगी। इसी बीच मैं निजी संचालकों से उन दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की आशा नहीं करता। हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष योजना बना रहे हैं कि बी.एस.एन.एल. स्वयं उन क्षेत्रों में निवेश करे और वहाँ सेवाओं में कुशलता तथा गुणवत्ता लाने के लिए कुछ टावर स्थापित करें।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित: अध्यक्ष महोदया, बीएसएनएल के मोबाइल टावर जो हमारे महाराष्ट्र राज्य में लगाए गए हैं, दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में काम नहीं कर रहे हैं। वहां टावर तो लगा दिए हैं, लेकिन रेंज ज्यादा नहीं होने के कारण सिग्नल नहीं आता, यहां तक कि नेशनल हाईवे की सड़कों पर भी मोबाइल फोन काम नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में वह क्या व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि हम उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं।

एयर इंडिया को घाटा

†

*163. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री सी. शिवासामी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का, इंडियन एयरलाइंस में विलय के बाद घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके विलय के समय से लेकर अब तक हुए घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अप्रैल से जून, 2012 की अवधि के दौरान एयर इंडिया के 184 रूटों में से केवल 16 रूटों ने ही अपनी कुल लागत पूरी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान उन रूटों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी ईंधन की लागत भी पूरी नहीं की है;

(घ) क्या सरकार ने रूट मितव्ययिता की जांच करने और रूटों को युक्तिसंगत बनाने के लिए अर्थोपायों का पता लगाने के लिए कोई कार्यबल गठित किया है, ताकि प्रचालनों को अत्यंत लागत प्रभावी बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) एयर इंडिया के घाटे को कम/समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया को वर्ष 2007-08 में 2226.16 करोड़ रुपये मे 5548.26 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 5552.44 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 6865.17 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 में 7853 करोड़ रुपये (अनंतिम) का घाटा हुआ है। इन घाटों के मुख्य कारण हैं: (i) विमानन टर्बाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) की लागत में असमान्य वृद्धि, इसकी प्रतिकूल तथा गैर पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीति और इस पर उच्च वैट; (ii) विमानन अधिग्रहण के कारण मूल्य ह्रास प्रावधान में वृद्धि; (iii) नए विमान बेड़े को शामिल किए जाने के कारण विमान ऋणों पर ब्याज की मात्रा में वृद्धि; (iv) हवाईअड्डों पर उपलब्ध अवसंरचना सहित उच्च अवसंरचनात्मक लागत; (v) ब्याज दरों में तथा भारी कार्य पूंजी ऋणों के कारण वित्त पोषण लागत में वृद्धि; (vi) ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व में कमी; (vii) अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये का अवमूल्यन; (viii) घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर निम्न लागत वाहकों का प्रवेश जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता पर दबाव; तथा (ix) वैश्विक मंदी तथा प्रीमियम यातायात में कमी।

(ग) जी, हां। अप्रैल-जून, 2012 के लिए अनंतिम मार्ग अर्थशास्त्र के अनुसार 184 सेवाओं में से केवल 16 सेवाओं ने कुल लागत को प्राप्त किया, 99 सेवाएं रोकड़ लागत को भी पूरा नहीं कर पाईं तथा 69 सेवाएं रोकड़ लागत को प्राप्त कर पाईं किन्तु कुल लागत को प्राप्त नही कर पाईं।

(घ) मार्ग अर्थशास्त्र की जांच करने तथा मोर्गों के युक्तिकरण के उपायों एवं साधनों का पता लगाने के लिए मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है ताकि प्रचालनों को अधिक लागत कुशल बनाया जा सके।

(ङ) लागतों को कम करने तथा प्रचालनिक निष्पादन में सुधार करने के लिए एयर इंडिया ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं, जिनमें शामिल (i) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के मार्गों का पूर्ण मार्ग युक्तिकरण और समानांतर प्रचालन वाले मार्ग नेटवर्क को समाप्त करना; (ii) कतिपय घाटा करने वाले मार्गों का युक्तिकरण; (iii) यात्री आकर्षण में वृद्धि करने के लिए अनेक घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर नए विमानों को शामिल किया जाना; (iv) पुराने विमानों को बेड़े से अलग करना और इसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण लागत में कमी; (v) पट्टे के विमानों को उनकी पट्टा अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले ही वापस करना; (vi) गैर प्रचालनिक क्षेत्रों में राजगारों को बंद करना; (vii) अनावश्यक व्यय में कमी करने के लिए कर्मचारियों की पुनर्तैनाती; (viii) उच्च प्रचालनिक लागत वाले बी. 747-400 विमान सहित पुराने विमानों को निकालना; (ix) कार्यपालक निदेशकों/भारत आधारित अधिकारियों को विदेशों से भारत में स्थानांतरित करना; (x) कतिपय स्थलों पर विदेशी ऑफलाइन कार्यालयों को बंद किया जाना; (xi) फ्रैंकफर्ट हब को बंद करना और दिल्ली में एक हब की स्थापना जिसके परिणामस्वरूप मार्गों की पुनर्संरचना के कारण व्यापक बचत हुई; (xii) एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना; (xiii) ऋणदाताओं के साथ वित्तीय पुनर्संरचना योजना पर हस्ताक्षर करना जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागतों में बचत और ऋणों के पुनर्भुगतान पर ऋणस्थगन; (xiv) सरकार द्वारा एयर इंडिया के लिए एक टर्नअराउंड योजना तथा एक वित्तीय पुनर्संरचना योजना को स्वीकृति प्रदान किया जाना जिसमें सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी सहायता, लागत में कमी तथा उन्नत प्रचालनिक निष्पादन पर बल दिया गया है; तथा (xv) सरकार द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा कंपनी के कार्यनिष्पादन की गहन मॉनीटरिंग।

श्री भर्तृहरि महताब : अध्यक्ष महोदया, मंत्रीमंडल द्वारा एयर इंडिया की 30,000 करोड़ रूपए की वित्तीय पुनर्गठन योजना का अनुमोदन करने के लगभग छह माह पश्चात, क्या यह सही है कि इस पैकेज ने एक एयर पॉकेट को नुकसान पहुंचाया है, क्या वित्त मंत्रालय ने संप्रभुता गारंटी के रोक कर रखा है? क्या एयर इंडिया को अब अपने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर इश्यू का विस्तार करने की आवश्यकता होगी और वर्ष के आरंभ में की गई कुछ गणनाओं का पुनः आकलन करना होगा? जब एयर इंडिया 20,000 करोड़ रुपए की समेकित हानि झेल रही है और 43,000 करोड़ रुपए के ऋण से ग्रस्त है, जिसका पुनर्निर्मित किया जाना है, इसमें नॉर्थ ब्लॉक द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण विलंब हो रहा है। मंत्री जी के विचार से कब तक लालफीताशाही से ऊपर उठ पाएंगे?

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदया, एयर इंडिया में परिवर्तन का प्लान,

[हिन्दी]

बन चुका है। जो केबिनेट ने एप्रूव की है, उसमें करीब 30,000 करोड़ रुपये उन्होंने दिया है। आप जो 7400 करोड़ रुपए की बात मेंशन कर रहे हैं, वह एनएसडी इश्यू किया है, जो सरकार ने गारंटी दी है। वे एनएसडी इश्यू हो चुके हैं। उनमें से करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम बैंक्स को लौटा चुके हैं, बाकी पैसा जो सरकार ने दिया है, उसमें लिमिट्स रखी है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया को प्रत्येक छह माह के निगरानी समिति इसकी निगरानी करती है और तत्पश्चात् ही धनराशि की अगली किस्त जारी की जाती है। तब से, एयर इंडिया ने कार्यनिष्पादन समय सीमा में सुधार किया है और इनमें से अधिकांश में यह आगे रही है। हमें विश्वास है कि हम इन कार्यनिष्पादन मानकों को पूरा कर लेंगे। एक निगरानी समिति इसकी निगरानी करती है और जब हम इन कार्यनिष्पादन मानकों को पूरा करते हैं केवल तभी हमें धनराशि मिलती है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, ऐसी विमान सेवाएं भी हैं जो दो या इससे अधिक प्रकार के विमानों के साथ सफलतापूर्वक चल रही हैं। एयर इंडिया बोइंग और एयर बस दोनों द्वारा निर्मित विमानों के साथ चल रही है। उदाहरणार्थ, इंडिगो, भारत की एकमात्र लाभार्जन करने वाली विमान सेवा है, जो एयरबस द्वारा निर्मित 56 जेटों का प्रयोग करती है, ये भुवनेश्वर लेकर बैंकाक जैस विभिन्न स्थनों तक उड़ान भरते हैं। जब पूरे विश्व में विमान सेवाओं के विलय की अथाह सफलता दर है, तो क्या सरकार विलय को समाप्त करने की सोच रही है?

जब न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा

स्वीकार कर लिया गया है और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कार्यान्वयन-सह-असंगति परिशोधन समिति के संबंध में क्या प्रगति हुई है। इसके परिणामी लाभ कब तक मिलेंगे?

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदया, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन कर दिया गया है। इसमें जितने भी मामले उठाए गए हैं उन सभी का समाधान कर दिया गया है। केवल पदोन्नतियां जिनको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, पदोननति के लिए इन बोर्डों का गठन कर दिया गया है और आगामी माह में हम पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कदम-दर-कदम क्या किया गया है, तो मैं यहां बता सकता हूं अथवा माननीय सदस्य के साथ इसकी चर्चा कर सकता हूं।

सबसे पहले पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के विभिन्न पदों के स्तर को मिलाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। पूर्ववर्ती इंडियन एयर लाइंस की संयुक्त वरिष्ठता निर्धारित कर ली गई है। 1 जुलाई, 2012 से पी.एल.आई. को समाप्त कर दिया गया है। डी.पी. मार्ग निर्देशों के अनुसार, वेतन निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पायलटों, केबिन क्रू के लिए उड़ान भत्ता और इंजीनियरों के लिए लाइसेंस भत्ते जैसे विभिन्न भत्तों के संवितरण हेतु मंत्रीमंडल टिप्पण अनुमोदन हेतु मंत्रीमंडल को भेज दिया गया है। पदोन्नति के शेष मामलों पर विचार करने के लिए पदोन्नति समिति का गठन किया गया है। विभिन्न असंगतियों के संबंध में कर्मारियों से प्राप्त याचिकाओं को श्रेणीबद्ध किया गया है और इनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए कार्यान्वियन/असंगति परिशोधन समिति वर्तमान में विभिन्न संघों और व्यक्तियों से विचार विमर्श कर रही है।

श्री सी. शिवासामी : महोदया, रिपोर्टें मिली हैं कि कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू रूटों पर एयर इंडिया की ईंधन लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है परंतु फिर भी एयर इंडिया ने इन गंतव्यों तक अपनी उड़ाने जारी रखी हैं। तिरूपुर मुख्य वस्त्र निर्यात क्षेत्र है जो 10 करोड़ रूपए से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। केरल में इरोड, करूर, नमाक्कल, ऊटी और पालाक्काड के लोग अधिकांशत: कोयंबटूर स्थित नज़दीकी विमानपत्तन का प्रयोग करते हैं।

वर्तमान में, कुछ निजी विमान सेवाएं कोयंबटूर से दिल्ली तथा की सीधी उड़ानों का परिचालन करती हैं जिसमें केवल तीन घंटे लगते हैं। परंतु एयर इंडिया की कालीकट से दिल्ली की उड़ान जो बारास्ता कोयंबटूर और मुंबई से आती है, इसको दिल्ली पहुंचने में पांच घंटे से अधिक का समय लगता है। चूंकि निजी विमान-सेवाओं में केवल तीन घंटे का समय लगता है, इसलिए यात्रीगण केवल निजी विमान सेवाओं को वरीयता दे रहे हैं और एयर इंडिया की उपेक्षा कर रहे है।

इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोयंबटूर से दिल्ली और दिल्ली से कोयंबटूर साथ ही चेन्नई से कायंबटूर तथा कोयंबटूर से चेन्नई तक एयर इंडिया की सीधी अविराम सेवा प्रचालित करने के लिए आगे आएगी ताकि अच्छा राजस्व अर्जित किया जा सके।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि एयर इंडिया की बहुत सी उड़ानें लाभार्जन नहीं कर रही है, इनमें से कुछ तो ईंधन लागत भी पूरी नहीं कर पा रही हैं। परंतु हमने समस्त नियमों पर ध्यान देने और यह देखने के लिए कि कहां लागत में कटौती की जा सकती है एक समिति का गठन किया है। कई बार समस्या इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि जब केवल माननीय सदस्यों को उड़ान की आवश्यकता होती है, और जब वाणिज्यिक सरोकारों के कारण वो उड़ान देना संभव नहीं होता, परंतु चूंकि माननीय सदस्यों की मांग होती है, इसलिए एयर इंडिया इनको आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करता है और उन मार्गों पर भी उड़ानें देता है जो गैर-लाभप्रद हैं। परंतु, जैसा कि मैंने कहा है, लागत में कटौती करने के लिए समिति बड़ी तत्परता से ध्यान दे रही है और हम उन कतिपय मार्गों को भी हटा रहे हैं, जो वाणिज्यिक सरोकारों को देखते हुए व्यवहार्य नहीं हैं।

श्री मानिक टैगोर : महोदया, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि वो मार्ग जो पहले लाभप्रद थे, एयर इंडिया ने ऐसे बहुत से मार्ग निजी प्रचालकों को दे दिए हैं। अब, केवल पांच मिनट की अवधि में मदुरै, चेन्नई आदि जैसे गंतव्य स्थलों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। ऐसे कई मार्ग निजी विमान प्रचालकों को दे दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने सब सही करने

के लिए जिस समिति का उल्लेख किया है उसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदया, जहां तक समय सीमा का संबंध है, मैं बताना चाहता हूं कि यह एक सतत् प्रक्रिया है, समिति लागत में कटौती करने के उपाय, इन मार्गों पर एयर इंडिया का कार्य निष्पादन कैसे सुधारा जाए इस प्रकार के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। इसलिए, इसकी कोई समय-सीमा नहीं है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

जहां तक मार्गों को देने और उस प्रकार के मुद्दों का संबंध है, मैं बताना चाहता हूं कि अब एयर इंडिया एकमात्र विमानसेवा नहीं है। काफी पहले कोई विमान सेवाओं को प्रचालन करने की अनुमति थी। हाल ही में हमने एक प्रणाली शुरू की है, विमानपत्तन प्राधिकरण के पास अब स्थल और लैंडिंग का समय निर्धारित करने तथा इन सब प्रकार के कार्यों का विशेषधिकार नहीं रह गया है। इसलिए, किसी अन्य विमानसेवा को मार्ग देने का प्रश्न ही नहीं है। सभी विमान सेवाएं वाणिज्यिक स्थिति और बाजार के आयामों के अनुसार निर्णय लेती हैं कि कौन सी उड़ान तथा किस समय पर प्रचालन करेगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एयर-इंडिया विश्व में महाराजा के नाम से जाना जाता था लेकिन आज महाराजा की हालत भिखारी जैसी हो गयी है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, आप इसमें फिजूलखर्चों को रोकने के लिए और इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे?

श्री अजित सिंह: मैडम स्पीकर, महाराजाओं की हालत सभी जगह ऐसी हो ही गयी है, केवल एयर-इंडिया की नहीं है। आपने जो समस्या उठाई है उसके लिए सरकार ने टर्न-अराऊंड प्लान बनाया है और उसका पालन करने के लिए और जो मर्जर हुआ था उसके लिए एक धर्माधिकारी कमेटी बनाई थी। सरकार टर्न-अराऊंड प्लान के अनुसार काम कर रही है जिससे धीरे-धीरे एयर-इंडिया की स्थिति सुधर रही है।

श्री धनंजय सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से इनके द्वारा जो मूल प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसमें ए. बी. के पार्ट-8 में दिया है कि "घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निम्न लागत वाहकों का प्रवेश जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता पर दबाव" और साथ ही आपने "डी" में उत्तर दिया है कि मार्गों के लिए आपने किसी कमेटी का गठन किया है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जो लो-फेयर कैरियर्स आये हैं उनके कम्प्टीशन में आप एयर-इंडिया में कितना सुधार ला रहे हैं तथा आपने जो कमेटी बनाई है तो आगरा में हमारे यहां एयर-फोर्स का एयर-पोर्ट है, वहां पर कमर्शियल एयर-पोर्ट क्यों नहीं बना सकते जबकि वहां इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं? मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदया, जहां तक इम्प्रूवमेंट का सवाल है, एयर इंडिया का पांच महीने पहले मार्केट शेयर 16.3 प्रतिशत था। पिछले महीने अक्टूबर में एयर इंडिया का मार्केट शेयर 20.8 प्रतिशत हो गया है। उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जहां तक आगरा का सवाल है, हमने प्रदेश सरकार को लिखा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए वह हमें एक प्रस्ताव भेजें लेकिन अभी तक इस बारे में वहां से कोई प्रस्ता हमारे पास नहीं आया है। *...(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: आप साफ साफ लिखें कि प्रस्ताव भेजें।

श्री अजित सिंह: हम उनको लिख चुके हैं।

श्री दारा सिंह चौहान: फिर दोबारा आप लिखें।

श्री अजित सिंह: आगरा में एयरफोर्स का एयरपोर्ट है और एयरफोर्स के लोग डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले और उनका कहना है कि अगर थोड़ी जमीन प्रदेश सरकार दे दे तो वहां पर हम एक डाइरेक्ट एक्सैस एयर स्ट्रिप पर दे देंगे जिससे एयरफोर्स के थ्रू जाने पर जो समस्या होती है, वह समाप्त हो जाएगी। उसके लिए हम निरन्तर प्रदेश सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं लेकिन उनको इस बारे में कोई जवाब भी नहीं मिला है। उसके लिए करीब 50-60 एकड़ जमीन की जरूरत है जो जिला ऑथोरिटीज ने आइडेंटिफाई भी कर ली हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी हमें

कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे कि वह जमीन प्रदेश सरकार दे देगी, वैसे ही वहां एयरफोर्स का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम वहां सिविल एन्क्लेव बना लेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : अध्यक्ष महोदाया, एयर इंडिया में नुकसान की स्थिति भयावह कर देने वाली है। पिछले चार वर्षों में कुल 22,492.59 करोड़ रुपये की हानि हुई है। मुझे याद है कि बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा में जब मैं सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति में सदस्य था, सभी वर्गों के सदस्य एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विलयन के पक्ष में थे क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में, एयरलाइंस में इस प्रकार का विभावन नहीं होता है कि वह दो विभिन्न तरीके से कार्य करे। इसलिए, एयर इंडिया का विलयन एक उत्साहवर्धक निर्णय हैं तथा यह इस सोच के साथ किया गया था कि जहाँ तक इसके प्रचालन क्षेत्र का संबंध है, एयर इंडिया एक चमत्कार करेगा। परंतु अब यह लगता है कि इस प्रकार के भारी घाटे के साथ, सुरक्षा का प्रश्न भी स्वतः उठ खड़ा होता है। हम सब यहाँ बैठे हैं। एयरलाइंस में यात्रा करने वाले लोग इस बात से भयभीत हैं कि इस प्रकार के भारी घाटे के पश्चात, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी अथवा नहीं। दूसरी ओर, कर्मचारियों को समुचित रूप से एवं समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। जब भी हम हवाई अड्डे के पास से गुजरते हैं, वे हमारे पास आकर हमें घेर लेते हैं और वे यह जानना चाहते हैं कि हम एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन के समुचित भुगतान के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित तौर पर दिया जा रहा है अथवा नहीं। दूसरा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तथा एयर इंडिया में हुई भारी हानि के कारण यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विचार किया जा रहा है अथवा नहीं।

श्री अजित सिंह : महोदया, पिछले लगभग छह महीने से, एयर इंडिया के कर्मचारियों को नियमित तौर पर वेतन दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उनका पिछला बकाया है। परंतु हर महीने उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा हम इस अंतर को कम कर रहे हैं हम पिछली बकाया राशि भी चुका रहे हैं।

जहां तक सुरक्षा का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में एयर इंडिया का रिकार्ड किसी से कम नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अक्सर हम लोग प्लेन मे आते-जाते हैं। हमारे साथी ने सैलरी के मामले में पूछ लिया लेकिन जब मर्जर हुआ और बहुत सारे एयर बस खरीदे गए तो जो पेइंग रूट्स हैं, उसमें प्राइवेट लोगों को एलाउ किया गया, लेकिन जो नॉन-पेइंग रूट्स हैं, उसमें एयर इंडिया को भेजा जाता है। आपने कहा कि इसकी एक कमेटी हम बना रहे हैं। आप एक कमेटी बना रहे हैं, ठीक है। आप देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। कुछ काम आपने किया है। लेकिन हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि तनख्वाह आपको समय पर देनी चाहिए। पायलट, एयर होस्टेस को तनख्वाह टाइम से दीजिए। आप समय से पेयमेंट नहीं करते हैं, जैसे ही हम प्लेन में अंदर आते हैं, वहां जो बहनें काम करती हैं वे कहती हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली है। हम इससे डिमोरेलाइज हो जाते हैं। यह प्रियारिटी रखिए कि कम से कम तनख्वाह तो उन्हें टाइम से मिले।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पटना एयरपोर्ट को कब और कहां शिफ्ट करने जा रहे हैं? बिहटा हवाई अड्डा पर इसे ले चलिए। वहां पेड़ कटवा दिए गए हैं, कटिंग हो गई है। हो सकता है कि किसी दिन वहां हादसा हो जाए, पहले भी हुआ है। वहां कोई प्लेन नहीं आ रहा है। आपने कह दिया कि एमपी जहां तय करेंगे वहां ले जाएंगे। आप बिहार के एमपीज़ को बुलाकर फैसला लीजिए। पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर है, वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जबकि यह डोमेस्टिक बना हुआ है। आप कम से कम बिहार के हवाई अड्डे को ठीक कीजिए। पेइंग रूट पर प्लेन भेजिए, एयर इंडिया के लिए वही तय कीजिए और प्राइवेट को नॉन पेइंग में डालिए, तभी जाकर सुधार होगा। इसके अलावा हम बाकी सुधार का लक्षण नहीं देख

रहे हैं।

श्री अजित सिंह: महोदया, मैं तनख्वाह के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि वह पिछले छह-सात महीने से निरंतर समय पर मिल रही है। कुछ बैकलॉग हैं जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा।

जहां तक पटना एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की बात है, यहां जगह नहीं है। हम प्रदेश सरकार से कह रहे हैं कि जगह बताइए क्योंकि बिहार में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है। प्रदेश सरकार को ही प्रस्ताव भेजना पड़ेगा और जमीन देनी पड़ेगी। मैं लालू जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी से बात कर रहा हूं, वे भी बात करें जिससे जल्दी से जल्दी प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि एयर इंडिया को इसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिलवाई जानी चाहिए तथा एयर इंडिया के कर्मचारियों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री अजित सिंह : महोदया, हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चीन द्वारा घुसपैठ

*164. **श्री लालजी टन्डन: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार लद्दाख के डेमचोक क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानती; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में कोई साझी अंकित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) नहीं है। साझी अंकित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) को लेकर भारत और चीन की धारणाओं में मतभेद होने के कारण इस आधार पर समय समय पर ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं, जिनसे बचा जा सकता था, यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) की दोनों देशों की धारणा एक समान होती। सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के आस-पास किसी भी अतिक्रमण के मामले को चीनी पक्ष के साथ सीमा कार्मिक बैठकों, फ्लैग बैठकों, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्यतंत्र की बैठकों तथा राजनयिक माध्यमों सहित स्थापित तंत्रों के माध्यम से लगातार उठाती रहती है। दोनों पक्षों ने अनेक अवसरों पर सीमा के पश्न के अंतिम निपटारे को लंबित रखते हुए, भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास शांति बनाए रखने की अपनी-अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार भारत की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखत है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

[हिन्दी]

श्री लालजी टन्डन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने जो प्रश्न किया है उसका कहीं उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा पर घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं? मैं सरकार से जानना चाहता हूं लेकिन उत्तर में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने पूछा कि विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में कितनी घटनाएं हुई हैं? इसकी सूचना क्या है? इसका कोई जवाब नहीं है। यह एक ऐसा नोट है जिसका अर्थ माननीय विदेश मंत्री समझ

सकते हैं, मैं तो नहीं समझ पाया हूं। मेरे प्रश्न का इसमें कोई जवाब नहीं है। अगर देश की सीमाओं के बारे में प्रश्न हो और संसद में सरकार का ऐसा रवैया हो कि वह उत्तर भी नहीं दे सकती है तो हम समझ सकते हैं कि देश की हालत क्या है।

श्री सलमान खुर्शीदः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद की चिंता का सम्मान करता हूं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस विषय को लेकर प्रश्न पूछा गया है पहले उसका आधार स्पष्ट हो जाए। चीन और भारतवर्ष के बीच में अभी ऐसी कोई सहमति इस बात पर नहीं हुई है। लाइन ऑफ एक्चयुल कंट्रोल या एलएसी है। *...(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अब समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीद : अध्यक्ष जी, यह पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद : अध्यक्ष जी, समय पूरा हो जायेगा, ये मेरी बात सुन लें, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : पहले ही मध्याहन में 12 बज चुके हैं। 12 बज गये हैं। अब समय नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीदः अध्यक्ष जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो हमारी *...(व्यवधान)* मेरी पूरी बात समझ लें। जो हमारी समझ है कि एल.ए.सी. कहां पर है और जो उनकी समझ है, जब तक *...(व्यवधान)* अध्यक्षा जी, जब ये समझना नहीं चाह रहे हैं, यह बात समझने की है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बारह बजकर एक मिनट हो चुका है। प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। मेरा मानना है कि अब इस पर चर्चा करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं रिकॉर्ड देखूँगी। प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब हम अगला मद लेंगे, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अजीत सिंह

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, प्राइम मिनिस्टर यहां बैठे हैं, इस पर चर्चा करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: महोदया, कल छह दिसम्बर को बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): आपकी बात मान ली। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: इनका जवाब एक्सपंज होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं रिकार्ड मंगवाकर देख लूंगी। दूसरी बात यह बात है *[अनुवाद]* वैसे भी उत्तर देने के लिए बहुत थोड़ा समय बाकी बचा है। मुझे लगता है सदन इस विषय पर उत्तेजित है। यदि आप मुझे एक नोटिस भेजेगें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदया : आपका जो भी नोटिस आएगा, हम उसे देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : सरकार चीन पर नियम 193 के तहत चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इस पर नियम 193 में चर्चा कराई जाए।

श्री कमल नाथ : आपकी बात मान ली, मैंने सदन में कह दिया।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का निर्माण/विकास

***165. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में विमानपत्तनों का विकास/निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किए जाने का विचार है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में उन्नत विमानन सुविधाओं हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विकास के लिए अनुमोदित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर उपलब्ध है।

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित 15 नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से 06 परियोजनाओं यथा नवी मुंबई तथा शिरडी (महाराष्ट्र), मोपा (गोवा), कन्नूर (केरल), कराईकल (पुदुचेरी) तथा कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए विचार किया जा रहा है। बशर्ते उनके पास सभी अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों तथा वे ऐसे प्रचालनों के लिए निर्धारित विनियामक स्वीकृतियां प्राप्त करें।

(घ) और (ङ) उन हवाई अड्डों, जिनके संबंध में राज्यों ने स्तरोन्नयन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए अनुरोध किया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर उपलब्ध है।

विवरण-I

(क) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान की गई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	स्थान	राज्य	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	मोपा	गोवा	अंतरराष्ट्रीय
2.	गुलबर्ग	कर्नाटक	
3.	बीजापुर		
4.	हासन		
5.	शिमोगा		
6.	अरानमुला (पथनामथिट्टा)	केरल	
7.	कन्नूर		अंतर्राष्ट्रीय
8.	सिन्धुदुर्ग	महाराष्ट्र	
9.	नवी मुंबई		अंतरराष्ट्रीय
10.	शिरडी		अंतरराष्ट्रीय
11.	डाबरा	मध्य प्रदेश	कार्गो हवाईअड्डा
12.	कराइकल	पुदुचेरी	अंतरराष्ट्रीय
13.	पेक्योंग	सिक्किम	
14.	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	अंतरराष्ट्रीय
15.	अंडल-फरीदपुर	पश्चिम बंगाल	

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्माण के लिए प्रस्तावित नए हवाईअड्डे

(i) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे

1. पेक्योंग (गंगटोक) सिक्किम-कार्य प्रगति पर है
2. इटानगर-अरुणाचल प्रदेश-नियोजन स्तर
3. चेथु (कोहिमा)-नागालैंड-नियोजन स्तर

(ii) मौजूदा हवाईअड्डों का विकास

1. किशनगढ़ (अजमेर)-राजस्थान-नियोजन स्तर

2. देवघर-झारखंड-नियोजन स्तर

3. तेजु-अरुणाचल प्रदेश-कार्य प्रगति पर

विवरण-II

राज्य सरकार से जिन हवाईअड्डों के विकास, विस्तार, स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, उनका ब्यौरा

क्र. स.	राज्य का नाम	हवाईअड्डों की संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1. वारंगल	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है।
		2. विजयवाड़ा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है।
		3. कडप्पा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि सुपुर्द की गई है। परियोजना का कार्य पूरा होने वाला है।
		4. तिरुपति	आंशिक रूप से भूमि सुपुर्द की गई है। शेष भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
2.	जम्मू और कश्मीर	5. जम्मू (सीई)	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
3.	झारखंड	6. देवघर	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
4.	कर्नाटक	7. बेलगांव	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
		8. हुबली	राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सुपुर्द की है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है।
5.	केरल	9. त्रिवेंद्रम	भूमि अधिग्रहरण का कार्य प्रगति पर है।
6.	ओडिशा	10. झारसुगुडा	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
7.	पंजाब	11. भटिंडा	नए सिविल एन्क्लेव का कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4
		12. लुधियाना	विस्तार तथा स्तरोन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जानी है।
		13. चंडीगढ़ (सीई) (मोहाली साइड)	कार्य प्रगति पर है!
8.	राजस्थान	14. किशनगढ़	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
		15. जोधपुर (सीई)	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
9.	तमिलनाडु	16. कोयम्बटूर	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
		17. तूतीकोरिन	राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण कर रही है।
10.	संघ राज्य क्षेत्र	18. अगाती	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण तथा सीआरजेड क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का औपचारिक अनुमोदन प्रतीक्षित है। 10 एकड़ भूमि के अधिग्रहण तथा लगुन क्षेत्र (20.84 एकड़) में निर्माण कार्य की अनुमति का अनुरोध लक्षद्वीप प्रशासन को भेजा गया है।
		19. पुदुचेरी	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आंशिक रूप से भूमि सुपुर्द की गई है। शेष भूमि अभी सुपुर्द की जानी है। चरण-I का कार्य पूरा होने वाला है।

[अनुवाद]

ग्राउंड हैंडलिंग पॉलिसी का कार्यान्वयन

***166. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न विमान कंपनियों द्वारा 2007 में प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग पॉलिसी के कार्यान्वयन के बारे में व्यक्त की गई चिन्ताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त नीति के कार्यान्वयन से ग्राउंड हैंडलिंग की लागत बढ़ेगी और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मुद्दों पर विभिन्न विमान कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इन मुद्दों का अविलंब समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.एस.) ने वर्ष 2007 में सुरक्षा, विमानन संरक्षा, विश्वस्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को प्राप्त करने, आदि से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग पर विचार किया था और नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति को अनुमोदन प्रदान किया था। एयरलाइन प्रचालकों के साथ परामर्श करने के पश्चात वर्ष 2010 में इस नीति में संशोधन किया गया था।

एयरलाइनों ने चिंता व्यक्त की है उन्हें ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों से अलग करने के कारण उनके द्वारा अपने ग्राहकों को वैयक्तिक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और इसलिए उन्हें टर्मिनल साईड पर ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति प्रदान की जाए। एयरलाइनों के अनुरोध पर विचार किया गया और उन्हें टर्मिनल साईड पर स्व-हैंडलिंग की अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, नवम्बर, 2010 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस तथा अन्यों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में ग्राउंड हैंडलिंग नीति को चुनौती दी गई थी। अदालत ने दिनांक 04.03.2011 को इस रिट याचिका को खारिज कर दिया और इस नीति को बहाल रखा। तत्पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. सिविल 7764-2011 दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि संभव हो तो सभी पक्षों को एक साथ वार्ता करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। तदनुसार, एयरलाइन प्रचालकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 25 अक्तूबर, 2012 को एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें उन्हें स्थिति से अवगत कराया गया था। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) से (ङ) विभिन्न एयरलाइनों के प्रतिनिधियों के साथ लागत के मुद्दों पर चर्चा की गई थी और उन्हें स्थिति स्पष्ट की गई थी कि एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए तथा स्टेकधारकों से परामर्श करके भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग के प्रभारों का निर्धारण किया जाएगा। एयरलाइनों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि एयरलाइन प्रचालक अलग से अपनी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां/अनुषंगी कंपनियां निगमित कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां/अनुषंगी कंपनियां ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता (जी. एच.एस.पी.) की नियुक्ति/चयन की बोली में भाग ले सकती हैं।

शहरों और कस्बों का विकास

*167. **डॉ. रत्ना डे :**
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **शहरी विकास** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों, शहरों और कस्बों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या अवसंरचना और मूलभूत सुविधाएं जनसंख्या के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे है

(ग) क्या झारखंड और बिहार सहित विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में शहरों और कस्बों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य और वर्ष-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई; और

(ङ) कितने प्रस्ताव अभी भी लम्बित हैं तथा इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और इन लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएंगी?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ङ) जनगणना, 2001 और 2011 के आधार पर संलग्न विवरण-I में दिए राज्य-वार आंकडे दर्शाते हैं के 2001-2011 के दशक में शहरीकरण में वृद्धि हुई है। जनगणना के अनुसार, शहरों और कस्बों की ओर प्रवास कारकों जिनमें अन्यों के साथ-साथ शिक्षा, विवाह और रोजगार शामिल है, से प्रभावित होता है।

(ख) जी, नहीं। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि से बुनियादी शहरी सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। शहरी विकास राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को शहरों पर दबाव को कम करने के लिए कार्रवाई करनी है। भारत सरकार स्कीमों के जरिए राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) आरम्भ किया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए शहरी अवस्थापना और शासन घटक का उद्देश्य चयनित 65 शहरों में शहरी अवस्थापना और परिवहन में सुधार करना है। छोटे और मझौले कस्बों की आवश्यकताओं की पूर्ति छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) कार्यक्रम द्वारा की जाती है। इसके अलावा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, चिन्हित मेट्रो और अन्य परियोजनाओं के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु एकमुश्त 10% स्कीम एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम और सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट

कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास संबंधी प्रायोगिक स्कीम, के अंतर्गत शहरी अवस्थापना हेतु वित्तीय सहायता भी मुहैया की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत और जारी राशियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II (क) से संलग्न विवरण-II (च) में दिया गया है।

(ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन.एन.यू.आर.एम.) की अवधि वर्ष 2005 से 2012 तक थी जिसे चालू परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए दो वर्ष बढ़ा दिया गया है। अत: कोई नई परियोजना यू.आई.जी. और यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृति हेतु पात्र नहीं है। सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कसबों में शहरी अवस्थापना विकास संबंधी प्रायोगिक स्कीम की अवधि ग्यारहवीं योजना के साथ नहीं समाप्त होनी थी और पूरे आबंटन के लिए वचनबद्धता की जा चुकी है इसलिए कोई नई परियोजना आरम्भ नहीं की जा सकती। एन.ई.आर. यू.डी.पी. के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक सहायता की दो अनुमोदित ट्रांचों के लिए निर्धारित परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। एकमुश्त 10% के अंतर्गत, पात्र परियोजनाएं राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता सूचियों तथा धनराशियों की उपलब्धता के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष स्वीकृत की जाती है। इन्हें आगे के वर्षों में नहीं ले जा सकते। मेट्रो रेल से संबंधित तीन परियोजनाएं अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में है।

विवरण-I

क्र. .सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना-2001			जनगणना-2011 (अनंतिम आंकड़े)		
		कुल आबादी	शहरी आबादी	शहरी आबादी का प्रतिशत	कुल आबादी	शहरी आबादी	शहरी आबादी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	1028737436	286119689	27.8	1210193422	377105760	31.2
1.	जम्मू और कश्मीर	10143700	2516638	24.8	12548926	3414106	27.2
2.	हिमाचल प्रदेश	6077900	595531	9.8	6856509	683704	10.0
3.	पंजाब	24358999	8262511	33.9	27704236	10387436	37.5
4.	चण्डीगढ़	900635	808515	89.8	1054686	1025682	97.2
5.	उत्तराखण्ड	8489349	2179074	25.7	10116752	3091169	30.6
6.	हरियाणा	21144564	6115304	28.9	25353081	8821588	34.8
7.	दिल्ली	13350507	12905780	93.2	16753235	16333916	97.5
8.	राजस्थान	56507188	13214375	23.4	68621012	17080776	24.9
9.	उत्तर प्रदेश	166197921	34539582	20.8	199581477	44470455	22.3
10.	बिहार	82998509	8681800	10.5	103804637	11729609	11.3

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सिक्किम	540851	59870	11.1	107688	151726	25.0
12.	अरूणाचल प्रदेश	1097958	227881	20.8	1382611	313446	22.7
13.	नागालैंड	1990036	342787	17.2	1980602	573741	29.0
14.	मणिपुर	2293896	575968	25.1	2721756	822132	30.2
15.	मिजोरम	388573	441006	49.6	1091014	561977	51.5
16.	त्रिपुरा	3199233	545750	17.1	3671032	960981	26.2
17.	मेघालय	2318822	454111	19.6	2964007	595036	201
18.	असम	26655528	3439240	12.9	31169272	4388756	14.1
19.	पश्चिम बंगाल	80176197	22427251	28.0	91347136	29134060	31.9
20.	झारखंड	26945829	5993741	22.2	32966238	7929292	24 1
21.	ओडिशा	36804660	5517238	15.0	41947358	6996124	16.7
22.	छत्तीसगढ़	20833803	4185747	20.1	25540196	5936538	23.2
23.	मध्य प्रदेश	60348023	15967145	26.5	72597565	20059666	27.6
24.	गुजरात	50671017	18930250	37.4	60383628	25712811	42.6
25.	दमण और दीव	158204	57348	36.2	242911	182580	75.2
26.	दादरा और नगर हवेली	220490	50463	22.9	342853	159829	46.6
27.	महाराष्ट्र	96878627	41100980	42.4	112372972	50827531	45.2
28.	आन्ध्र प्रदेश	76210007	20808940	27.3	84665533	28353745	33.5
29.	कर्णाटक	52850562	17961529	34.0	61130704	23578175	38.6
30.	गोवा	1347668	670577	49.8	1457723	906309	62.2
31.	लक्षद्वीप	60650	26967	44.5	64429	50308	781
32.	केरल	31841374	8266925	26.0	33387677	15932171	47.7
33.	तमिलनाडु	62406679	27483998	44.0	72138958	34949729	48.4

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	पुदुचेरी	974345	648619	66.6	1244464	850123	68.3
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	356152	116198	32.6	379944	135533	35.7

स्रोत: (1) सामान्य आबादी टेबल, भारत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (टेबल ए-1 से ए-3) भाग-1, भारत की जनगणना-2001

(2) अनंतिम जनसंख्या योग, पेपर-2, 2011 का ख.ड-1, ग्रामीण-शहरी वितरण, भारत, सीरीज-1, भारत की जनगणना-2001

नोट : (1) भारत की जनगणना-2001 एवं 2011 के लिए आंकड़ों में मणिपुर राज्य के सेनापति जिले के पावमाता, माउमारः और पूरूल उप-डिवीजन की अनुमानित जनसंख्या शामिल है।

विवरण-II (क)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उप-मिशन के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं और जारी ए.सी.ए. की स्थिति

क्र .सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
		अनुमोदित परियोजनाओं कि संख्या	**उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.	अनुमोदित परियोजनाओं कि संख्या	**उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.	अनुमोदित परियोजनाओं कि संख्या	**उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.	अनुमोदित परियोजनाओं कि संख्या	**उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	27,385.07	0	15,569.86	2	32,500.10	0	8,227.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2,006.94	0	-	0	4,759.16	0	1,738.20
3.	असम	0	7,112.41	0	3,792.54	0	6,795.91	0	-
4.	बिहार	0	7,441.39	0	-	0	-	0	-
5.	चंडीगढ़	1	-	0	734.52	0	-	0	-
6.	छत्तीसगढ़	0	12,145.60	0	3,643.68	0	-	0	-
7.	दिल्ली	20	17,248.00	1	43,509.00	0	6,938.27	0	18,829.88
8.	गोवा	0	-	0	-	2	72.45	0	1,424.37
9.	गुजरात	4	47,788.21	1	7,297.21	1	39,612.00	0	5,304.23
10.	हरियाणा	0	-	0	5,283.80	0	6,888.13	0	1,333.31
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2,619.01	0	-	1	121.09	0	210.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	जम्मू और कश्मीर	0	–	0	–	1	10,032.72	0	6,295.53
13.	झारखंड	0	5,384.66	1	417.03	0	6,204.58	0	–
14.	कर्नाटक	2	21,578.53	0	7,659.85	1	24,234.18	0	3,924.36
15.	केरल	1	2,439.45	0	–	0	6,516.15	0	–
16.	मध्य प्रदेश	2	12,343.27	1	4,828 66	0	14,280.93	0	12,743.68
17.	महाराष्ट्र	2	88,649.86	0	42,004.49	1	76,471.17	0	18,083.46
18.	मणिपुर	1	2,883.37	0	–	0	2,078.42	0	–
19.	मेघालय	0	–	0	–	0	7,296.11	0	550.35
20.	मिजोरम	0	756.82	0	–	3	–	0	2,722.39
21.	नागालैंड	1	1,702.81	0	–	1	1,246.83	0	543.52
22.	ओडिशा	1	2,491 60	0	–	0	6,999.34	0	120.26
23.	पंजाब	1	3,346.62	0	–	0	–	0	1,810.43
24.	पुदुचेरी	0	–	0	–	0	2,189.00	0	252.00
25.	राजस्थान	0	2,826.10	0	–	0	4,584.94	0	768,36
26.	सिक्किम	1	1,663.87	0	–	0	1,273.24	0	2,172.07
27.	तमिलनाडु	1	37,723.44	1	2,635.84	0	47,132.47	0	1,015.88
28.	त्रिपुरा	1	2,250.00	0	–	0	2,406.51	0	–
29.	उत्तर प्रदेश	4	47,632.21	0	25,479.16	0	65,351.90	0	1,456.44
30.	उत्तराखंड	1	7,546.69	3	981.06	1	6,741.55	0	1,549.00
31.	पश्चिम बंगाल	12	27,717.88	8	17,412.81	13	27,043.89	0	14,471.04
	कुल	60	392,683.81	16	181,249.51	27	409,771.04	0	105,546.41

** जारी ए.सी.ए. उन परियोजनाओं को भी दर्शाता है जो पहले अनुमोदित हो चुकी हैं।

* मिशन ने 31 मार्च, 2012 को अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है और सरकार ने केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए यानि 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाई है। इसके तहत नई परियोजनाओं पर विचार और स्वीकृति संबंधी कोई अधिदेश नहीं है।

विवरण-II (ख)

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (21.11.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया आबंटन तथा वचनबद्ध/जारी ए.सी.ए. की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिशन के लिए आबंटन	कस्बों/शहरी की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	पात्र केन्द्रीय अंश (अनुमोदित लागत का 80%/90%) (वचनबद्ध ए.सी.ए.)	पात्र केन्द्रीय अंश की पहली किस्त की राशि (ए.सी.ए. 50%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	49031.00	69	84	245995.50	196796.40	98398.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	746 00	9	9	3935.98	3542.38	1771.19
3.	असम	10129.00	28	30	20783.28	18704.95	9352.48
4.	बिहार	25478.00	11	11	26113.91	20891.13	10445.56
5.	छत्तीसगढ़	13478.00	3	4	25143.65	13472.92	6736.46
6.	गोवा	2211.00	3	3	2875.00	2211.00	1105.50
7.	गुजरात	35182.00	52	52	43814.36	35051.49	17525.74
8.	हरियाणा	19559.00	7	9	20135.81	16108.65	6563.14
9.	हिमाचल प्रदेश	1744.00	4	8	12653.68	10122.94	5061.47
10.	जम्मू और कश्मीर	3545.00	13	47	42441.50	38197.35	19098.68
11.	झारखंड	11452.00	5	6	12864.35	10291.48	5145.74
12.	कर्णाटक	44314.00	30	38	68248.57	54598.86	27299.43
13.	केरल	23282.00	22	25	42778.55	34222.84	17111.42
14.	मध्य प्रदेश	43843.00	49	68	123099 43	98479.54	49239.77
15.	महाराष्ट्र	66476.00	84	95	282677.57	226142.06	113071.03

(लाख रू. में)

संस्तुत ए.सी.ए.		डी.पी.आर. तैयार करने के लिए 1.5% की	2009-10 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2010-11 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2011-12 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2012-13 के दौरान जारी ए.सी.ए.	वित्त मंत्रालय/ गृह मंत्रालय द्वारा जारी कुल ए.सी.ए. (प्रोत्साहन सहित)	अब तक की गई कुल वचनबद्धता (कालम 7+11)
9	10	11	16	17	18		19	21
98398.20	97307.21	2360.92	476.88	43079.00	22017.66	2897.54	198091.21	199157.32
1771.19	1771.19	0.00			1771.19		3542.38	3542.38
9235.79	4450.15	5.00			2408.73	1569.46	13934.13	18709.95
10445.57	0.00	228.81					10674.38	21119.94
6736.46	6736.46	0.00		2447.46	4289.00		13472.92	13472.92
1105.50	337.20	0.00		337.20	768.30	337 20	1442.70	2211.00
17525.744	15196.68	144.09		4651.09	4919.97		32866.52	35195.58
8054.32	4326.09	151.44			2913.22	2904.07	12531.87	16260.09
5061.62	807.94	27.09		345.82	2098.37	2594.08	5873.30	10150.03
19098.70	15304.28	413.68		4020.85		16462.60	34816.64	38611.03
5145.74	0.00	144.70				1287.12	5290.44	10436.18
27299.42	25032.13	517.15		17662.95	2069.43	3917.28	52848.70	55116.01
17111.42	7539.63	309.30				7539.63	24880.35	34532.14
49821.92	21780.96	624.64		3871.53	13330.16	23633.06	72227.51	99104.18
113071ए43	81320.20	854.96	14072.30	22781.21	35455.01	12415.06	194935.08	226997.01

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	1260.00	5	5	6277.00	5649.30	2824.65
17.	मेघालय	719.00	2	2	1433.26	1289.93	644.97
18.	मिजोरम	824.00	2	2	1555 04	1399.54	699.77
19.	नागालैंड	1028.00	2	2	2325.82	2093.24	1046.62
20.	ओडिशा	18179.00	14	18	25699.59	20559.67	10279.84
21.	पंजाब	22660.00	14	17	39577.45	31661.96	15830.98
22.	राजस्थान	40143.00	35	37	60988.52	48790.82	24395.41
23.	सिक्किम	120.00	5	5	3992.82	3593.54	1796.77
24.	तमिलनाडु	70597.00	115	122	88272.98	70618.38	35309.19
25.	त्रिपुरा	1376.00	4	4	7816.81	7035.13	3517.56
26.	उत्तर प्रदेश	94792.00	46	64	115805.15	92644.12	46322.06
27.	उत्तराखंड	4670.00	1	1	6173.25	4938.60	2469.30
28.	पश्चिम बंगाल	31525.00	34	35	61333.67	49066.94	22772.98
29..	दिल्ली	112.00	0	0	0.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	557.00	1	1	3918.00	3134.40	1567.20
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	448.00	1	1	558.13	446.50	223.25
32.	चंडीगढ़	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	193.00	1	1	1864.73	1491.78	745.89
34.	लक्षद्वीप	104.00	0	0	0.00	0.00	0.00
35.	दमन और द्वीव	220.00	1	1	942.37	753.90	376.95
	कुल	639997.00	672	807	1402095.73	1124001.74	558749.19

9	10	11	16	17	18		19	21
2824.65	2824.65	20.79				2824.65	5670.09	5670.09
644.97	0.00	0.00					644.97	1289.93
699.77	699.77	0.00				699.77	1399.54	1399.54
1046.62	190.55	0.00	190.75			1046.42	1237.17	2093.24
10279.84	0.00	168.77		90.37		1278.44	10448.66	20728.44
15830.98	3686 17	123.27		1982.00		1704.17	19640.41	31785.23
24395.41	3752.44	272.26					28421.99	49063.07
1796.77	1796.76	23.71			1796.77		3617.25	3617.25
35309.19	21380.32	0.00	1935.35	2135.61	724.88		56689.52	70618.38
3517.56	3337.30	.65.00			2759.76	577.54	6919.68	7100.13
46322.05	36951.33	877.00	10918.80	16933.84	8789.60	231.38	84613.59	93521.12
2469.30	0.00	0.00					2469.30	4938 60
24532.98	14925.50	347ए26		2005.51	7346.82	9675.65	39805.75	49414.20
0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
1567.20	1567.20	0.00	1567.20		1567.20		3134.40	3134.40
223.25	0.00	0.00				223.25	223.25	446.50
0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
745.89	0.00	0.00	719.89				745.89	1491.78
0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
376.95	0.00	0.00					31.00	753.90
562466.40	373022.11	7679.83	29881.17	122344.44	115026.07	93818.37	943140.59	1131681.57

विवरण-II (ग)

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उप-मिशन के अंतर्गत शहरी परिवहन प्रणाली हेतु बसें खरीदने के लिए स्वीकृत/जारी राज्य-वार और वर्ष-वार ए.सी.ए. (27.11.2012 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रु. में)

क्र .सं.	राज्य	स्वीकार्य केन्द्रीय अंश (ए.सी.ए.)	वर्ष-वार जारी धनराशि				
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष श्रेणी राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.74	1.95	0	0	0.9913	–
2.	असम	47.29	7.11	0	13.49		11.57
3..	हिमाचल प्रदेश	6.08	3.04	0	2.43		–
4.	जम्मू और कश्मीर	23.76	0	5.94	0	13.04	–
5.	मणिपुर	6.08	3.04	0	0		–
6.	मेघालय	14.76	0	3.69	3.69		2.48
7.	मिज़ोरम	2.93	1.46	0	0		–
8.	नागालैंड	2.7	0	0.68	0		1.24
9.	सिक्किम	2.70	0	0.68	1.12		0.22
10.	त्रिपुरा	14.65	7.65	0	0	2.71	2.07
11.	उत्तराखंड	21.74	10.87	0	2.65		–
	कुल (क)	146.43	35.12	10.99	23.38	16.7413	–
गैर विशेष श्रेणी राज्य							
1.	आन्ध्र प्रदेश	176.5	90.88	0	19.1	1.06	20.94
2.	बिहार	25 35	12.68	0	0		–
3.	छत्तीसगढ़	11.88	5.94	0	0		–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	6.16	3.08	0	1.96		-
5.	गुजरात	88.2	39.08	0	0		2.02
6.	हरियाणा	27.3	13.65	0	0		-
7.	झारखंड	23.9	11.95	0	0		-
8.	कर्नाटक	159.04	72.12	12.04	26.52	12.14	5.47
9.	केरल	78.22	39.11	0	0		23.21
10.	मध्य प्रदेश	101.12	50.56	0	0	3.98	0.74
11.	महाराष्ट्र	299.6	142.67	0	16.29	17.38	6.94
12.	ओड़िशा	15.84	7.92	3.68	2.59		-
13.	पंजाब	49.15	24.63	0	0		-
14.	राजस्थान	77.57	38.63	0	0	17.08	3.67
15.	तमिलनाडु	192.35	96.18	0	13.09	13.08	8.36
16.	उत्तर प्रदेश	142.92	130.3	0	0		-
17.	पश्चिम बंगाल	145.4	68.5	0	0		-
	कुल (ख)	1620.50	847.93	15.72	79.55	64.72	-
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	274.75	115.52	1.75	0	106.88	-
2.	पुदुचेरी	12.92	0	3.23	0		4.73
3.	चंडीगढ़	34.20	17.1	0	8.28		-
	कुल (ग)	321.87	132.62	4.98	8.28	106.88	
	कुल (क+ख+ग)	2088.8	1015.67	31.69	111.21	188.341 3	98.65

कुल 1445.5613 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

विवरण-II (घ)

7 मेगा शहरों आस-पास के सेटेलाइट कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश			2	4099				
2.	गुजरात			3	1875.62				
3.	हरियाणा			2	1890.80				
4.	कर्नाटक					1	649.10		
5.	महाराष्ट्र			1	634.53	1	1324.52		
6.	तमिलनाडु					3	1017.35		
7.	उत्तर प्रदेश	1	1322.70	2	2027.38	1	7.32		

विवरण-II (ङ)

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान संबंधी स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009.10		2010.11		2011.12		2012.13	
		स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	1294.06	3	1092.77	5	308.73		
2.	असम	2	953.06	2	72.27	1	145.20		
3.	मणिपुर	1	768.28	1	208.73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	मेघालय	3	219.78	1	7.33	2	436.50		
5.	मिजोरम	2	2948.23	2	904.02	1	224.73		
6.	नागालैंड	2	2266.62	1	336.50	2	127.27		
7.	सिक्किम	3	1511.76	1	87458	1	242.97		

विवरण-II (च)

एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.)

राज्य	2009-10		2012-13	
	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आज तक जारी कुल धनराशि (करोड़ रू. में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी कुल धनराशि (करोड़ रू. में)
नागालैंड	2	23.85	1	छप्प
मिज़ोरम	1	26.93	2	छप्प
मेघालय	1	14.41	1	छप्प
सिक्किम	1	14.43	2	छप्प
त्रिपुरा	1	14.52	1	छप्प

नोट : 1. वर्ष 2010-11 और 2011-12, में कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

2. धनराशि जारी करना प्रतिपूर्ति अनुरोधों पर आधारित है।

[हिन्दी]

सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

***168. श्री वीरेन्द्र कश्यप :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन से लेकर अब तक वर्ष-वार केंद्रीय सूचना आयोग को कितने मामले प्राप्त हुए और उसने कितने मामलों का निपटान किया;

(ख) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कतिपय मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के कथित दुरुपयोग की

शिकायतों की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार केंद्रीय सूचना आयोग में न्यायिक सेवा के प्रतिनिधि को शमिल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) केंद्रीय सूचना आयोग ने यह सूचित किया है कि दिनांक 31 मार्च, 2012 को उनके पास 27856* अपील/शिकायतें लंबित हैं। लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि, केंद्रीय लोक प्राधिकरणों के पास 2006-07 से 2009-10 तक आरटी आवेदनों की संख्या में कई गुणा वृद्धि एवं आयोग के पास दायर अपीलों/शिकायतों की संख्या में परिणामी वृद्धि तथा सितम्बर, 2010 को तीन केंद्रीय सूचना आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई है। इस तथ्य के बावजूद की सूचना आयुक्त द्वारा अपीलों/शिकायतों के निपटान में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिया गया है, लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि केंद्रीय सूचना आयोग के पास दायर की जा रही भारी मात्रा में अपीलों/शिकायतों के कारण भी है :

वर्ष	प्राप्ति	निपटान	प्रथम अप्रैल को लंबित	प्रतिशत (निपटान/प्राप्ति)	सूचना आयुक्त/ केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा औसत वार्षिक निपटान
2005-06	703	682	21	97.00:	136
2006-07	6839	4075	2785	59.58:	815
2007-08	11621	7722	6820 (2008)	68.57:	1544
2008-09	15426	13322	8924 (2009)	86.36:	1665
2009-10	22800	19482	12242 (2010)	85.44:	2165
2010-11	28875	24071	17046 (2011)	83.36:	2675
2011-12	33922	23122	27856*	68.16:	2890

*इसमें अपील/शिकायत के 9500 मामले शामिल हैं जो कि 29.02.2012 को अंतरिम रूप से पंजीकृत हैं।

सरकार ने, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने जैसे बहुत से कदम उठाए हैं ताकि वे सचूना प्रदान कर सकें और प्रथम अपील को प्रभावी ढंग से निपटा सके जिसके परिणामस्वरूप आयोग के पास अपीलों की संख्या में कमी आई है। आयोग ने अपनी तरफ से अपीलों/शिकायतों की लंबित संख्या के निपटान के लिए विशेष अभियान आरंभ किए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1 मार्च, 2012 से तीन और सूचना आयुक्तों की नियुक्त की जा चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयुक्त के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग को कर्मचारियों की भर्ती करने में स्वायत्ता दी जानी चाहिए। पदों की 14 श्रेणियों में से 11 श्रेणियों, जिनमें 130 कर्मचारी हैं, के लिए भर्ती निगम (आरआर) अधिसूचित किए जा चुके हैं। रजिस्ट्रार, हिंदी अनुवादक एवं लाईब्रेरियन के 4 पदों वाली 3 श्रेणियों के भर्ती

नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग में 6 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है एवं एक पद को संवर्ग में शामिल किया गया है। शेष पद अवधि विशेष के लिए/संविदा/आउटसोर्स आधार पर भरे जाते हैं। आयोग ने उन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है जिनके लिए भर्ती नियम अधिसूचित किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगते समय कोई कारण देने या अधिकारिक स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, सूचना तक पहुंच, सूचना का दुरूपयोग नहीं है एवं उसके बाद इसके दुरूपयोग से संगत विधानों के अंतर्गत दांडिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई होगी।

श्री नमित शर्मा द्वारा भारत संघ के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12(5), 12(6), 15(5) एवं 15(6) की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका सं. 210/2012 जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.09.2012 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया है कि सूचना आयोग न्यायिक अधिकरण हैं एवं इन्हें दो सदस्यों वाली पीठ, जिसमें एक न्यायिक पृष्ठभूमि वाला एवं दूसरा विशेषज्ञ सदस्य हो, द्वारा अपीलों/शिकायतों का निपटान करना चाहिए। इसके दिनांक 13.09.2012 के आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में दिनांक 11.10.2012 को एक समीक्षा याचिका सं. 2309/2012 दायर की गई है। उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही है।

[अनुवाद]

परमाणु केन्द्रों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा

***169. श्री अशोक तंवर :**
श्री एस. आर. जेयदुरई :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजस्थान **में रावतभाटा** सहित अन्य परमाणु विद्युत केन्द्रों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी अथवा एजेंसियों द्वारा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समीक्षाओं में व्यक्त की गई चिन्ताओं का समाधान करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी परमाणु विद्युत केन्द्रों की सुरक्षा संबंधी आवधिक समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हाँ। रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आर.ए.पी.एस.) यूनिट 3 तथा 4 की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा का काम, भारत सरकार के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के 'प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल' (ओ.एस.ए.आर.टी.) द्वारा 29 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2012 के बीच किया गया।

(ख) 'प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल' (ओ.एस.आर.टी.) ने, बिजलीघर में कई अच्छी पद्धतियों का पता लगाया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक नाभिकीय उद्योग के साथ मिलकर लागू कर रही है, और उसके साथ-साथ ऐसे सुझाव दिए जिनसे यूनिटों के प्रचालन को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल की सिफारिशों/सुझावों की पुनरीक्षा व्यवस्थित स्वरूप के परिवर्तनों को लागू करने की दृष्टि से की जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा, नियामक प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त, विश्व नाभिकीय प्रचालक संघ (वानो) के विशेषज्ञों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पीयर पुनरीक्षा का काम भी किया जाता है। फुकुशिमा की घटना के बाद, सरकार ने, राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट 3 तथा 4 की सुरक्षा की पुनरीक्षा का काम, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल द्वारा भी कराने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन प्रभार

***170. श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री ए. के. एस. विजयन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रयोक्ता बेहतर सेवा प्रदाताओं

की तुलना में कम प्रभार वसूल करने वाले नेटवर्कों को वरीयता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का विचार इस उद्योग में मूल्य को कम करने की होड़ को रोकने के लिए मोबाइल फोन प्रभारों की न्यूनतम सीमा नियत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का विचार सरलीकृत दूरसंचार प्रभार को लागू करने तथा इसमें पारदर्शिता लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) मौजूदा प्रशुल्क ढांचे के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग सेवा, जिसके अंतर्गत प्रशुल्क की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की गई है, को छोड़कर अन्य मोबाइल सेवाओं के संदर्भ में प्रशुल्क का निर्धारण करना सेवा प्रदाताओं के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मोबाइल प्रचालकों को बाजार दशाओं एवं अन्य वाणिज्यिक स्थितियों के मद्देनजर विभिन्न प्रकार के प्रशुल्कों का प्रस्ताव करने की छूट प्रदान की गई है। उपभोक्ता किसी प्रस्ताव से संबंधित प्रशुल्क प्लान/स्कीम तथा सेवा की गुणवत्ता के साथ:साथ सेवा प्रदाता के सेवा-निष्पादन से संबंधित ऐसे विभिन्न कारकों के बारे में अपनी अवधारणा के आधार पर किसी सेवा प्रदाता की सेवा का चयन करते हैं।

(ख) फिलहाल, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मोबाइल फोन प्रशुल्कों की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रशुल्कों को सरल बनाना तथा प्रशुल्क संबंधी प्रस्तावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक सतत प्रक्रिया है तथा ट्राई द्वारा इस संबंध में काफी प्रयास किए गए हैं। प्रशुल्क संबंधी प्रस्तावों को सरल बनाने तथा इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में वर्ष 2012 में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित हैं :

(i) दिनांक 06.01.2012 को जारी दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 के तहत प्रशुल्क से संबंधित प्रस्तावों को सरल बनाने तथा सेवाओं की उपलब्धता में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्री-पेड उपभोक्ताओं को प्रस्तावित विभिन्न श्रेणियों के वाउचरों को प्रत्येक श्रेणी के वाउचरों की सुगम पहचान हेतु निर्धारित रंगी बैंडों के साथ तर्कसंगत बनाया गया है। वाउचरों पर मुद्रित सामग्री का न्यूनतम फोंट आकार अनिवार्यत: 8 प्वाइंट से कम नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे प्री-पेड उपभोक्ताओं को प्रत्येक कॉल/डॉटा सेवा के बाद उपयोग संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराएं।

(ii) दिनांक 16.01.2012 और दिनांक 03.04.2012 को जारी दिशानिर्देशों के तहत सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे अधिकतम छह महीने की अवधि के अंतराल पर क्षेत्रीय तथा अंग्रेजी समाचार-पत्रों में विशिष्ट प्रारूप में सभी प्रशुल्क प्लानों के बारे में जानकारी प्रकाशित करें। सुगम एवं पारदर्शी तुलना के मद्देनजर, विहित प्रपत्रों में सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट, बिक्री केंद्र तथा ग्राहक सुविधा केंद्र पर संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान भी अनिवार्य बना दिए गए हैं।

(iii) प्रशुल्क संबंधी भ्रामक जानकारी देने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए दिनांक 26.03.2012 को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

(iv) ट्राई के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (51वां संशोधन) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वह लोकर एवं राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के लिए 1 सेकेंड की पल्स अवधि वाले कम से कम एक-एक प्री-पेड तथा पोस्ट पेड प्लान का प्रस्ताव करे।

(v) दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (53वां संशोधन) के तहत प्रोसेसिंग शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस शुल्क की राशि तीन रुपये या "टॉप अप वाउचर" के अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह प्रशुल्क की अधिकतम सीमा

निर्धारित करके विशेषकर कम मूल्य वाले ''टॉप अप वाउचरों'' के साथ रिचार्ज करने से प्री-पेड उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की गई है।

(अप) दिनांक 14.09.2012 को जारी दिशा-निर्देश में ब्लैक आउट दिवसों (जिन दिवसों को मुफ्त/रियायती उपयोग प्रभार की सुविधा प्रापत नहीं होती है) को प्रभार लगाने के बारे में अतिरिक्त पारदर्शी उपया किए गए हैं। अब, प्रचालकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है क वे ब्लैक आउट दिवसों के संबंध में तथा उन दिवसों के प्रभारों को लागू करने के बारे में उपभोक्ताओं को पहले से ही सूचित करें।

संकाय में अध्यापकों की कमी

*171. **श्री कामेश्वर बैठा :**
श्री जयंत चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों सहित देश की उच्च शिक्षा संस्थाओं में संकाय में अध्यापकों की अत्यंत कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन महाविद्यालयों में राज्य-वार कितने पद रिक्त हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन संस्थानों में संकाय में अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों सहित बहुत सी शैक्षिक संस्थाएं योग्य और अनुभवी स्थायी संकाय की कमी से जूझ रही हैं। योग्य संकाय की कमी दूर करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए प्रो. संजय जी. ढांडे की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया। कार्यबल द्वारा जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में योग्य संकाय की क्रमशः लगभग 40 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत की कमी है।

(ख) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत पदों, मौजूदा पदों और रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं में संस्वीकृत पदों, मौजूदा पदों और रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्नन विवरण-II में दिया है। हालांकि ऐसे आंकड़े केंद्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं, जैसे कि कार्यबल द्वारा सूचित किया गया है राज्य विश्वविद्यालयों का मई, 2007 तक का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। संकाय की कमी से जूझ रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। संकाय की कमी के मुख्य कारणों में 11वीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा का विस्तार, न्यूनतम अर्हता मानकों में संशोधन, उपयुक्त अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना, पेंशन योजना की गैर-सुबाह्यता और मुकदमेबाजी शामिल है।

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज यह सुनिश्चित करने हेतु कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, संकाय की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न तरीके/प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। इनमें तदर्थ संकाय नियुक्त करना, अस्थाई संकाय नियुक्त करना, सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेना और अतिथि संकाय की सेवाएं लेना इत्यादि शामिल हैं।

(घ) कार्यबल की सिफारिशों को लागू करने और उनकी निगरानी के लिए 23 जनवरी, 2012 को सरकार द्वारा एक कार्यान्वयन निगरानी समिति का गठन किया गया। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापकों की कमी के कारण पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही बढ़ा कर पैंसठ वर्ष कर दी गई है। यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अध्यापकों के पद यथाशीघ्र भरने की सलाह दी है। पैंसठ वर्ष की आयु के पश्चात् सत्तर वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर अध्यापकों को पुनः रोजगार देना, रिक्त पदों की उपलब्धता और उनके स्वास्थ्य के अध्यधीन अनुमत होगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं पर यूजीसी विनियमों के पैरा 12.2 और उच्चतर शिक्षा के मानदंडों के अनुरक्षण हेतु उपाय 2010 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी संस्वीकृत/अनुमोदित पदों को तात्कालिक आधार पर भरा जाएगा।

यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रणाली में संकाय की कमी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और शिक्षण संसाधनों के संवर्धन हेतु आप्रेशन फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम नामक एक योजना भी आरंभ की है।

तकनीकी संस्थाओं में संस्वीकृत पदों, मौजूदा पदों और रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्नन विवरण-II में दिया है। हालांकि ऐसे आंकड़े केंद्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं, जैसे कि कार्यबल द्वारा सूचित किया गया है राज्य विश्वविद्यालयों का मई, 2007 तक का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। संकाय की कमी से जूझ रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। संकाय की कमी के मुख्य कारणों में 11वीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा का विस्तार, न्यूनतम अर्हता मानकों में संशोधन, उपयुक्त अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना, पेंशन योजना की गैर-सुबाह्यता और मुकदमेबाजी शामिल है।

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज यह सुनिश्चित करने हेतु कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, संकाय की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न तरीके/प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। इनमें तदर्थ संकाय नियुक्त करना, अस्थाई संकाय नियुक्त करना, सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेना और अतिथि संकाय की सेवाएं लेना इत्यादि शामिल हैं।

(घ) कार्यबल की सिफारिशों को लागू करने और उनकी निगरानी के लिए 23 जनवरी, 2012 को सरकार द्वारा एक कार्यान्वयन निगरानी समिति का गठन किया गया। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापकों की कमी के कारण पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही बढ़ा कर पैंसठ वर्ष कर दी गई है। यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अध्यापकों के पद यथाशीघ्र भरने की सलाह दी है। पैंसठ वर्ष की आयु के पश्चात् सत्तर वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर अध्यापकों को पुनः रोजगार देना, रिक्त पदों की उपलब्धता और उनके स्वास्थ्य के अध्यधीन अनुमत होगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं पर यूजीसी विनियमों के पैरा 12.2 और उच्चतर शिक्षा के मानदंडों के अनुरक्षण हेतु उपाय 2010 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी संस्वीकृत/अनुमोदित पदों को तात्कालिक आधार पर भरा जाएगा।

यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रणाली में संकाय की कमी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और शिक्षण संसाधनों के संवर्धन हेतु आप्रेशन फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम नामक एक योजना भी आरंभ की है।

विवरण-I

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्टाफ संख्या (मौजूदा और रिक्त पद) का विवरण

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	संस्वीकृत संकाय पद	मौजूदा पद	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय	284	169	115
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	556	406	150
3.	दि इंग्लिश एंड फोरन लेंग्वेज विश्वविद्यालय	236	200	36
4.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	329	219	110

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1704	761	943
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	824	711	113
7.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	727	459	268
8.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	329	155	174
9.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	79	66	13
10.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	460	377	83
11.	हेमवीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	468	258	210
12.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1887	1509	378
13.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	2416	1520	96
14.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	130	108	22
15.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	852	315	537
16.	विश्व भारतीय	714	622	92
17.	असम विश्वविद्यालय	325	309	16
18.	तेजपुर विश्वविद्यालय	243	194	49
19.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	157	88	69
20	मणिपुर विश्वविद्यालय	266	179	87
21	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	406	301	105
22	मिजोरम विश्वविद्यालय	337	272	65
23	नागालैंड विश्वविद्यालय	249	179	70
24	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	216	147	69
25	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	810	558	252
	कुल	15004	10082	4922

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्टाफ संख्या (मौजूदा और रिक्त पद) का विवरण

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	संस्वीकृत पद	मौजूदा संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार	140	26	114
2	केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात	140	42	98
3	केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा	140	17	123
4	केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	140	36	104
5	केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	21	8	13
6	केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर	140	34	106
7	केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड	140	75	65
8	केंद्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक	140	44	96
9	केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल	140	32	108
10	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय	228	56	172
11	केंद्रीय विश्वविद्यालय, उड़ीसा	140	21	119
12	केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब	140	27	113
13	केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	140	54	86
14	सिक्किम विश्वविद्यालय	201	56	145
15	केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	140	18	122
	कुल	2130	546	1584
	कुल योग (पुराने+नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)	17134	10628	6506

विवरण-II

संकाय स्थिति

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्तियां
1	2	3	4	5
आईआईटी				
1.	आईआईटी बाम्बे	778	528	250
2.	आईआईटी दिल्ली	578	440	138
3.	आईआईटी कानपुर	429	347	82
4.	आईआईटी खड़गपुर	986	541	445
5.	आईआईटी मद्रास	688	491	197
6.	आईआईटी गुवाहाटी	338	282	56
7.	आईआईटी रूड़की	575	378	197
नए आईआईटी				
8.	आईआईटी गांधीनगर	90	50	40
9.	आईआईटी रोपड़	90	46	44
10.	आईआईटी जोधपुर	90	46	34
11.	आईआईटी भुवनेश्वर	90	55	35
12.	आईआईटी हैदराबाद	90	90	12
13.	आईआईटी पटना	90	54	36
14.	आईआईटी म.डी	90	42	48
15.	आईआईटी इंदौर	90	57	33
आईआईआईटी				
16.	आईआईआईटी इलाहाबाद	110	56	54
17.	आईआईआईटीटीएम ग्वालियर	47	27	20

1	2	3	4	5
18.	आईआईआईटीएंडएम जबलपुर	55	37	18
19.	आईआईआईटीडीए.डएम कांचीपुरम	25	18	7
एनआईटी				
20.	एनआईटी अगरतला	219	84	135
21.	एनआईटी इलाहाबाद	462	152	310
22.	एनआईटी भोपाल	315	205	110
23.	एनआईटी कालीकट	279	210	69
24.	एनआईटी दुर्गापुर	320	181	139
25.	एनआईटी हमीरपुर	198	100	98
26.	एनआईटी जयपुर	316	149	167
27.	एनआईटी जालंधर	207	113	94
28.	एनआईटी जमशेदपुर	246	97	146
29.	एनआईटी कुरूक्षेत्र	223	115	118
30.	वीएनआईटी-नागपुर	335	183	152
31.	एनआईटी पटना	142	81	61
32.	एनआईटी रायपुर	–	–	–
33.	एनआईटी राउरकेला	281	218	63
34.	एनआईटी सिल्चर	153	85	68
35.	एनआईटी-श्रीनगर	145	84	61
36.	एसवीएनआईटी-सूरत	396	180	216
37.	एनआईटीके-सूरतकल	375	171	204
38.	एनआईटी तिरूचिरापल्ली	393	264	1
39.	एनआईटी वारंगल	420	188	232
40.	एनआईटी भोपाल	355	202	153

1	2	3	4	5
नए एनआईटी				
41.	एनआईटी गोवा	22	-	22
42.	एनआईटी पुदुचेरी	22	-	22
43.	एनआईटी दिल्ली	25	-	25
44.	एनआईटी उत्तराखंड	25	-	25
45.	एनआईटी मिजोरम	22	-	22
46.	एनआईटी मेघालय	22	-	22
47.	एनआईटी मणिपुर	22	-	22
48.	एनआईटी नागालैंड	22	-	22
49.	एनआईटी अरूणाचल प्रदेश	22	-	22
50.	एनआईटी सिक्किम	22	-	22
आईआईएम				
51.	अहमदाबाद	120	89	31
52.	बंगलौर	120	95	25
53.	कलकत्ता	104	90	14
54.	लखनऊ	90	77	13
55.	इंदौर	56	51 (42 नियमित 9 विजिटिंग)	05
नए आईआईएम				
56.	कोझिकोड	77	60 (40-नियमित 20-विजिटिंग)	17
57.	शिलांग	21	20	1
58.	रोहतक	11	11	-
59.	रायपुर	11	07	04
60.	रांची	12	12	00

1	2	3	4	5
61.	त्रिची	11	13 (8-नियमित 5 विजिटिंग)	-
62.	उदयपुर	11	11	
63.	काशीपुर	11	1	10
आईआईएसईआर				
64.	आईआईएसईआर, कोलकाता	60	83 संविदा आधार पर (15)	-
65.	आईआईएसईआर, पुणे	60	60 संविदा आधार पर (03)	-
66.	आईआईएसईआर, मोहाली	60	46 संविदा आधार पर (12)	14
67.	आईआईएसईआर, भोपाल	60	45 संविदा आधार पर (07)	15
68.	आईआईएसईआर, तिरूवनंतपुरम	60	45	15
एसपीए				
69.	एसपीए भोपाल	49	44	05
70.	एसपीए विजयवाड़ा	18	09	09
71.	एसपीए नई दिल्ली	105	51	54
एनआईटीटीटीआर				
72.	एनआईटीटीटीआर, भोपाल	61	45	16
73.	एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़	64	45	19
74.	एनआईटीटीटीआर, चेन्नई	46	24	22
75.	एनआईटीटीटीआर, कोलकाता	33	25	8
अन्य				
76.	आईआईएससी, बंगलौर	522	392	130
77.	आईएसएम धनबाद	321	210	111
78.	एसएलआईईटी, लोंगवाल	181	126	55*
79.	एनआईटीआईई, मुंबई	84	44	40
80.	एनआईएफएफटी रांची	42	28	14

विवरण-III

राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नियमित/अस्थायी/रिक्त पदों की स्थिति

(01.05.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	संस्वीकृत संख्या			भरे गए पद			रिक्त पद			संस्वीकृत संख्या	भरे गए पद	भरे गए पदों का प्रतिशत
		पी	आर	एल	पी	आर	एल	पी	आर	एल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	आंध्र प्रदेश												
1.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	144	498	478	45	222	560	99	27	18	1220	827	67.8
2.	एसपीएम विश्वविद्यालय, तिरूपति	17	34	76	11	21	69	13	7	127	101		
3.	जेएनटीयू, हैदराबाद	92	97	256	75	71	182	17	26	74	445	328	73.7
4.	नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद	7	7	15	6	5	4	1	3	10	29	15	51.7
5.	द्रविडियन विश्वविद्यालय, कुप्पम	10	20	40	6	6	37	4	14	4	70	149	70
	अरूणाचल प्रदेश												
6.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	13	27	84	2	17	53	11	10	31	124	72	58
	असम												
7.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	115	120	141	103	106	116	12	14	25	376	325	86
8.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ	24	64	111	11	43	102	13	14	16	199	147	73.8
9.	टी. एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	40	155	1294	153	346	460	40	154	336	1489	959	64.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	छत्तीसगढ़												
10.	इंदिरा कलासंगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ	5	16	35	1	5	19	4	11	16	56	25	44.6
11.	पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	23	49	82	14	32	59	9	18	25	154	105	58.1
	दिल्ली												
12.	गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	38	51	87	15	18	73	23	33	9	176	106	60.2
	गोवा												
13.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	31	66	91	21	53	94	19	34	30	188	150	79.7
	गुजरात												
14.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	13	24	36	6	14	30	7	10	6	73	50	58.4
15.	गुजरात विश्वविश्द्यालय, अहमदाबाद	35	76	94	12	43	71	23	33	23	205	51	24.9
16.	एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदा, वडोदरा	86	140	526	44	110	334	41	12	197	752	488	64.8
17.	सरदार पटैल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	37	73	129	27	52	99	10	21	30	239	180	75.3
18.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	23	41	73	12	31	58	11	10	15	137	101	73.7
19.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	23	44	64	13	25	48	10	19	16	131	86	55.6
	हरियाणा												
20.	एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक	35	61	208	20	33	139	15	36	71	304	194	53.8
21.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	106	98	57	87	70	113	19	28	44	361	270	74.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	35	74	60	14	39	118	21	47	34	269	171	53.9
	हिमाचल प्रदेश												
23.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	34	63	26	16	35	101	18	28	26	223	152	68.1
	जम्मू और कश्मीर												
24.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी	59	83	167	47	71	154	11	10	13	309	272	88
	झारखंड												
25.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	43	90	1302	--	11	910	4379	400	1435	921	64.2	
	कर्नाटक												
26.	बंगलौर विश्वविद्यालय	80	156	321	21	75	220	61	76	103	557	316	56.7
27.	कुवेम्प विश्वविद्यालय, शकरघटा	26	40	89	1330	79	14	10	11	155	121	55.6	
28.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	8	22	40	5	19	40	4	3	-	70	64	91
29.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौरगंगोत्री	29	42	94	12	30	81	17	12	15	165	123	74.5
30.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	7	2	11	7	2	11	-	-	-	20	20	100
	केरल												
31.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	32	66	136	22	45	116	10	2	23	234	183	78.2
32.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि	69	88	107	61	55	48	8	23	59	264	174	65.9
33.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायाम	15	23	80	11	18	18	69	4	5	118	47	38.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	कन्नूर विश्वविद्यालय, मंगातुपारम्बा	5	18	27	5	18	26	-	-	1	50	49	99
35.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालाडी	8	35	159	8	26	159	1	22	12	198	193	99
	मध्य प्रदेश												
36.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा	17	21	35	2	7	20	15	14	15	73	29	39.7
37.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय,	15	26	53	4	17	34	12	7	18	94	55	58.5
38.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	33	53	79	16	29	53	12	24	26	165	98	59.39
39.	डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	50	92	174	12	45	22	38	48	72	316	99	25
40.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	21	33	88	5	23	38	3	16	58	142	66	46.4
41.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	4	8	13	-	2	7	4	6	6	25	9	36
	महाराष्ट्र												
42.	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	14	24	47	6	13	46	8	11	1	85	65	76.4
43.	डॉ. बी. ए मराठवाडा	35	80	131	24	42	88	11	38	43	246	155	53
44.	मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर	105	140	177	56	72	120	44	65	52	422	260	61.6
45.	आर टी एम नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	54	91	207	54	10	36	44	55	84	352	100	28.4
46.	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	13	26	76	8	11	32	12	15	36	115	51	44.3
47.	पुणे विश्वविद्यालय, पूना	68	113	190	42	55	127	26	58	63	371	224	50.3
48.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	40	46	124	17	27	95	23	19	29	210	139	66.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.	एस आर टी मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नानदेड़	7	15	32	5	13	28	2	2	4	54	46	35.1
	ओडिशा												
50.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	63	95	182	63	95	182	34	36	72	340	184	54.1
51.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, भंजा बिहार	98	54	100	11	38	69	21	16	31	166	118	71
52.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	7	13	21	5	3	14	2	10	7	41	22	53.6
53.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालसोर	5	10	15	4	10	12	1	–	1	30	26	86.6
54.	नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाड़ा	5	10	15	4	10	13	1	0	2	30	27	90
	पंजाब												
55.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	78	95	98	44	62	66	34	33	32	271	172	53.4
56.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	190	239	424	112	136	229	69	90	116	853	578	57.7
57.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	146	156	255	113	91	207	32	56	198	557	411	73.7
	राजस्थान												
58.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	61	135	703	1	27	244	60	108	459	899	272	30.2
59.	जे एन व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	52	125	503	1	27	298	51	98	205	680	326	47.9
60.	एम एल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	268	–	–	100	–	–	162	–	–	262	100	38.1
61.	एम डी एस विश्वविद्यालय, अजमेर	13	26	19	5	9	14	8	17	5	58	28	48.3
	तमिलनाडु												
62.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुड़ी	15	34	85	10	26	81	5	8	4	134	117	87.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर	250	237	1571	250	237	1571				2058	2058	1.00
64.	भातरीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	21	32	139	14	27	98	7	5		192	139	72.4
65.	भारथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	6	6	65	3	3	30	3	30	35	77	36	46.7
66.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	70	147	177	121	35	35	203	394	192	487		
67.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल	22	25	56	1	5	31	21	19	25	103	37	35.9
	त्रिपुरा												
68.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	15	28	55	9	15	45	6	13	10	98	69	70.4
	उत्तर प्रदेश												
69.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	8	17	31	3	10	29	2	8	3	56	42	75
70.	एम जी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	21	36	126	14	27	114	7	9	13	183	154	34.1
	उत्तरांचल												
71.	कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल	30	48	240	5	30	193	24	18	46	318	228	71.6
	पश्चिम बंगाल												
72.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	147	253	447	89	194	285	44	62	111	847	619	73
73.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	153	257	414	150	225	269	3	32	145	824	664	78.1
74.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बुर्दवान	38	91	140	30	81	118	8	10	22	269	229	85
75.	नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जलिंग	28	56	123	1	2	8	27	54	115	207	11	5.3
76.	रविन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय, कोलकाता	16	33	111	14	29	107	2	4	4	160	150	93.7

विवरण-IV

दिल्ली विश्वविद्यालय

31.8.2012 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षण पदों का विवरण

क्रम सं.	कॉलेज का नाम	अध्यापकों की वस्तुस्थिति	रिक्त पदों के समक्ष तदर्थ/ अस्थायी आधार पर नियुक्त अध्यापक
1	2	3	4
1.	शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनिस स्टडीज	16	14
2.	गार्गी कॉलेज	132	50
3.	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज	112	50
4.	आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज	75	48
5.	अदिति महाविद्यालय	63	35
6.	भगिनी निवेदिता कॉलेज	40	15
7.	भारतीय कॉलेज	56	40
8.	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाईड साइंसिज	47	20
9.	कालेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	56	13
10.	दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज	77	41
11.	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स	61	19
12.	देशबन्धु कॉलेज	138	82
13.	रामानुजम कॉलेज	44	0
14.	दयाल सिंह कॉलेज (एम)	136	94
15.	दयाल सिंह कॉलेज (ईवनिंग)	39	27
16.	इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज	108	27
17.	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज	93	33

1	2	3	4
18.	कालिन्दी कॉलेज	64	56
19.	केशव महाविद्यालय	50	40
20.	लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमन	94	29
21.	लक्ष्मीबाई कॉलेज	96	54
22.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज	62	37
23.	पीजीडीएवी कॉलेज	95	52
24.	मैत्री कॉलेज	108	52
25.	माता सुंदरी कॉलेज	113	47
26.	मोती लाल नेहरू कॉलेज	97	322
27.	पीजीडीएवी कॉलेज (ईवनिंग)	48	25
28.	रामलाल आनंद कॉलेज	43	34
29.	रामलाल आनंद कॉलेज (ईवनिंग)	43	16
30.	सत्यवती कॉलेज (ईवनिंग)	63	34
31.	कमला नेहरू कॉलेज	101	39
32.	श्री अरबिन्दो कॉलेज	76	18
33.	श्री अरबिन्दो कॉलेज (ईवनिंग)	46	5
34.	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज	121	62
35.	स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज	107	62
36.	विवेकानंद कॉलेज	63	30
37.	जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज	147	46
38.	महर्षि बाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजूकेशन	15	1
39.	भीमराव अम्बेडकर कॉलेज	83	19
40.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वूमेन	96	30

1	2	3	4
41.	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स	46	20
42.	आत्मा राम सनातम धर्म कॉलेज	95	80
43.	जीसस एंड मेरी कॉलेज	80	33
44.	राजधानी कॉलेज	101	64
45.	मिरांडा हाऊस	149	55
46.	किरोड़ीमल कॉलेज	141	66
47.	श्याम लाल कॉलेज	74	16
48.	शिवाजी कॉलेज	105	67
49.	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इक्नोमिक्स	54	24
50.	स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग	34	1
51.	शहीद भगतसिंह (ईवनिंग) कॉलेज	55	27
52.	शहीद भगतसिंह कॉलेज	99	41
53.	श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स	69	52
54.	सत्यवती कॉलेज	115	26
55.	रामजस कॉलेज	127	75
56.	श्री गुरूनानक देव	65	17
57.	श्याम लाल कॉलेज (ईवनिंग)	55	17
58.	हंसराज कॉलेज	136	40
59.	हिंदू कॉलेज	122	25
60.	सेंट स्टीफन कॉलेज	सूचना प्राप्त नहीं हुई	सूचना प्राप्त नहीं हुई
61.	मोती लाल नेहरू कॉलेज (ईवनिंग)	सूचना प्राप्त नहीं हुई	सूचना प्राप्त नहीं हुई
62.	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकशन एंड स्पोटर्स साइंसिज	सूचना प्राप्त नहीं हुई	सूचना प्राप्त नहीं हुई

1	2	3	4
63.	शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ एप्लाईड साइंसिज फॉर वूमन	सूचना प्राप्त नहीं हुई	सूचना प्राप्त नहीं हुई
64.	लेडी इरविन कॉलेज	62	39
65.	कॉलेज ऑफ आर्ट	17	15
66.	जाकिर हुसैर पोस्ट ग्रेजुएट ईवनिंग कॉलेज	59	16
67.	दौलत राम कॉलेज	79	81

पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में अवसंरचना संबंधी विकास

*172 **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :**
श्री एस. अलागिरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विकास/कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन द्वारा क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन समाप्त करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों के अवसंरचना संबंधी विकास हेतु नई योजनाएं बनाई हैं अथवा बनाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) जी हां। केंद्र सरकार क्षेत्रीय एवं सामाजिक असंतुलनों को ठीक करने के लिए विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं केंद्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। ये स्कीमें है: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जनजातीय उप योजना (टीएसपी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) आदि। क्षेत्रीय असंतुलनों में कमी से संबंधित मुद्दों का समग्र रूप से समाधान करने के लिए विशिष्ट रूप से कार्यान्वित किया जाने वाला कार्यक्रम है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) तथा इसके दो घटक हैं, नामत: (प) 272 जिलों को कवर करते हुए जिला घटक तथा (पप) राज्य घटक जिसमें बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के केबीके जिलों के लिए विशेषज्ञ योजना, 82 जिलों को कवर करते हुए चयनित पिछड़े एवं जनजातीय जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना तथा बुंदेलखंड पैकेज शामिल है।

(ग) और (घ) चयनित पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु दिनांक 25.11.2010 को चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकत्रत कार्य योजना (आईएपी) शुरू की गई थी। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के विवेक पर छोड़ दी जाती हैं जिसमें जिला के पुलिस अधीक्षक एवं जिला वन अधिकारी शामिल हैं। जिला स्तर की इस समिति को इसके आकलन एवं आवश्यकतानुसार विकास स्कीमों पर राशि खर्च करने की छूट है। राज्य सरकारों एवं जिला अधिकारियों को आईएपी के अंतर्गत स्कीमें शुरू करने के संबंध में पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों सहित स्थानीय संसद एवं अन्य चयनित प्रतिनिधियों के साथ उपयुक्त विचार-विमर्श सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई थी। जिला स्तर समिति स्कूल भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, पीएचसीज और स्कूलों आदि जैसी सार्वजनिक स्थानों में बिजली प्रदान करने

जैसी सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाओं के लिए ठोस प्रस्ताव सहित योजना बनाती है। इस प्रकार से चयनित स्कीमों से अल्प अवधि में अच्छे परिणाम आने की अपेक्षा है।

आईएपी का अनुमोदन प्रारंभ में 60 जिलों को कवर करने के लिए किया गया था जिसका बाद में विस्तार कर 82 जिलों तक कर दिया गया। वर्ष 2010:11 में प्रत्येक जिले को 25.00 करोड़ रु. तथा वर्ष 2011-12 और 2012-13 में प्रति जिला 30.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी। अब तक 5260.00 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है जिसमें से 3341.04 करोड़ रु. अर्थात् लगभग 63 प्रतिशत (30.11.2012 की स्थिति के अनुसार) की राशि व्यय होने की सूचना है। शुरू किए गए 93875 कार्यों में से 66196 कार्य अर्थात् लगभग 70.52 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए गए हैं। राज्य-वार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आईएपी : राज्य-वार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	आबंटन	कुल जारी निधि	व्यय	शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	530.00	410.00	199.41 (48.64)	4949	2287 (46.21)
2.	बिहार	775.00	525.00	278.30 (53.01)	14800	11999 (81.07)
3.	छत्तीसगढ़	850.00	750.00	497.21 (66.29)	17769	12850 (72.32)
4.	झारखंड	1370.00	1200.00	801.88 (66.82)	15276	10714 (70.14)
5.	मध्य प्रदेश	740.00	640.00	389.48 (60.86)	7875	5015 (63.68)
6.	महाराष्ट्र	170.00	150.00	103.03 (68.68)	4882	4278 (87.63)
7.	ओडिशा	1455.00	1275.00	893.13 (70.05)	22774	14668 (64.41)

1	2	3	4	5	6	7
8.	उत्तर प्रदेश	205.00	135.00	79.03 (58.54)	2427	1889 (77.83)
9.	पश्चिम बंगाल	205.00	175.00	99.56 (56.89)	3123	2496 (79.92)
	कुल	6300.00	5260.00	3341.04 (63.52)	993875	66196 (70.52)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

कुडनकुलम विद्युत परियोजना को चालू किया जाना

*173. **श्री भूदेव चौधरी :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट-1 को चालू करने हेतु तकनीकी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट को चालू किए जाने की अनंतिम तारीख क्या है तथा उक्त यूनिट पर अब तक हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ स्थानीय लोग अभी भी इस संयंत्र का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में इन लोगों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) यूनिट-1 में ईंधन का भरण किया गया है, और यूनिट को पहली बार क्रांतिकता (नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को पहली बार शुरू करना) के लिए तैयार किया गया है। यूनिट-1 में क्रांतिकता की प्रक्रिया, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) से चरणवार अनुमति प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी।

(ख) यूनिट-1 के दिसंबर, 2012 के अंत तक कमीशन किए जाने की संभावना है। अक्तूबर, 2012 तक परियोजना (कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र यूनिट 1 तथा 2) पर किया गया व्यय 15,161 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) जी, हां। इदिनठकराई गांव के कुछ वर्गों के, और आस-पास के कुछ हिस्सों के लोग, सुरक्षा और आजीविका के मुद्दे उठाकर संयंत्र को चालू करने का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा और आजीविका संबंधी शंकाओं का समाधान, केंद्रीय सरकार द्वारा गठित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विशेषज्ञ दल द्वारा, और बहु-विषयक दृष्टिकोण को काम में लाकर पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

*174. **श्री एस. पक्कीरप्पा :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में सरकार को कोई निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में ऐसे विद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है जहां सुरक्षित पेयजल और शौचालय सुविधा सहित मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है; और

(ङ) इस मुद्दे का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009 समुचित सरकारों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए आर.टी.ई. अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल अवसंरचना उपलब्ध कराने का अधिदेश देता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशित समय सीमा के अनुसार सभी स्कूलों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का अधिदेश दिया गया है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण प्रतिष्ठान बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य के मामले में 2004 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 631 में दिनांक 3.10.2012 के अपने आदेश में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधाएं, पेयजल की सुविधाएं, पर्याप्त कमरों आदि की सुविधाएं, यदि पहले प्रदान नहीं की गई है, तो छह महीने के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(घ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के 2011-12 के आंकड़ों (अनंतिम) के अनुसार देश के 87.7 प्रतिश प्रारंभिक स्कूलों में शौचालय की सुविधाएं हैं और 94.6 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की सुविधाएं हैं। पेयजल और शौचालय की सुविधाओं वाले प्रारंभिक स्कूलों की प्रतिशतता दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न में दिया गया है।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान आर.टी.ई. की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्कूल अवसंरचना का विस्तार करने का प्रयास करता है जिसके लिए अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3.04 लाख स्कूल भवनों, 17.92 लाख अतिरिक्त कमरों, 8.53 लाख शौचालयों और 2.29 लाख पेयजल सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।

विवरण

डी.ई.एस.ई 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार पेयजल और शौचालय की सुविधा वाले प्रारंभिक स्कूलों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालय की सुविधा वाले स्कूलों की प्रतिशतता	पेयजल की सुविधा वाले स्कूलों की प्रतिशतता
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	88.6	97.0
आन्ध्र प्रदेश	80.6	89.0
अरुणाचल प्रदेश	55.0	78.0
असम	68.6	78.0
बिहार	73.5	93.4

1	2	3
चण्डीगढ़	100.0	100.0
छत्तीसगढ़	68.9	93.7
दादरा और नगर हवेली	75.9	98.7
दमण और दीव	99.1	100.0
दिल्ली	100.0	100.0
गोवा	93.6	99.5
गुजरात	99.9	100.0
हरियाणा	98.0	99.6
हिमाचल प्रदेश	97.5	98.8
झारखंड	78.2	90.0
कर्णाटक	98.8	99.5
केरल	92.8	97.5
लक्षद्वीप	89.1	100.0
मध्य प्रदेश	95.4	98.0
महाराष्ट्र	95.1	94.4
मणिपुर	93.8	95.0
मेघालय	60.4	59.9
मिज़ोरम	87.7	90.3
नागालैण्ड	90.7	75.4
ओडिशा	80.8	94.4
पुदुचेरी	99.9	100.0
पंजाब	99.5	100.0
राजस्थान	95.6	95.1

1	2	3
सिक्किम	98.5	96.8
तमिलनाडु	93.0	100.0
त्रिपुरा	82.3	75.3
उत्तर प्रदेश	91.3	98.5
उत्तराखंड	95.6	95.7
पश्चिम बंगाल	89.6	97.2
कुल	87.7	94.6

[हिन्दी]

साक्षरता दर

*175. **श्री प्रेमदास :***
श्री मंगनी लाल मंडल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/लिंग-वार वर्तमान साक्षरता दर क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हेतु स्वीकृत धनराशि और इस पर हुए व्यय का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने का है जो इस संबंध में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में साक्षरता के स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में राज्य/लिंग-वार वर्तमान साक्षरता दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नए स्वरूप साक्षर भारत के अंतर्गत वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र के हिस्से के रूप में राज्य/वर्ष-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एक संघ राज्य क्षेत्र और 25 राज्यों के 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। 30 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार, 1,00,524 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं; 94,483 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है; 6,69,84,443 शिक्षार्थियों की पहचान की जा चुकी है; 11,38,088 साक्षरता केंद्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से 144 लाख शिक्षार्थियों को साक्षर होने का प्रमाणपत्र दिया गया है!

(घ) जी, नहीं। तथापि, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (जिनमें तत्कालीन जिलों में से बनाए गए वे नए जिले शामिल हैं जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार, प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत अथवा उससे कम थी) के अलावावामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों, चाहे उनकी साक्षरता दर कितनी भी हो, के केवल ग्रामीण क्षेत्र ही साक्षर भारत के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं।

(ङ) सरकार के नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया है और साक्षर भारत की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है ताकि देश में क्रमश: 6-14 वर्ष और 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग में साक्षर के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके।

विवरण-I

2011 की जनगणना के अनुसार देश में राज्य/लिंग-वार वर्तमान साक्षरता दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर (व्यक्ति)	साक्षरता दर (पुरूष)	साक्षरता दर (महिलाएं)
1	2	3	4	5
	भारत	74.04	82.14	65.46
1.	आंध्र प्रदेश	67.66	75.56	59.74
2.	अरूणाचल प्रदेश	66.95	73.69	59.57
3.	असम	73.18	78.81	67.27
4.	बिहार	63.82	73.39	53.33
5.	छत्तीसगढ़	71.04	81.45	60.59
6.	गोवा	87.40	92.81	81.84
7.	गुजरात	79.31	87.23	70.73
8.	हरियाणा	76.64	85.38	66.77
9.	हिमाचल प्रदेश	83.78	90.83	76.60
10.	जम्मू और कश्मीर	68.74	78.26	58.01
11.	झारखंड	67.63	78.45	56.21
12.	कर्नाटक	75.60	82.85	68.13
13.	केरल	93.91	96.02	91.98
14.	मध्य प्रदेश	70.63	80.53	60.02
15.	महाराष्ट्र	82.91	89.82	75.48
16.	मणिपुर	79.85	86.49	73.17
17.	मेघालय	75.48	77.17	73.78
18.	मिजोरम	91.58	93.72	89.40
19.	नागालैंड	80.11	83.29	76.69

1	2	3	4	5
20.	ओडिशा	73.45	82.40	64.36
21.	पंजाब	76.68	81.48	71.34
22.	राजस्थान	67.06	80.51	52.66
23.	सिक्किम	82.20	87.29	76.43
24.	तमिलनाडु	80.33	86.81	73.86
25.	त्रिपुरा	87.75	92.18	83.15
26.	उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26
27.	उत्तराखंड	79.63	88.33	70.70
28.	पश्चिम बंगाल	77.08	82.67	71.16
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.27	90.11	81.84
30.	चंडीगढ़	86.43	90.54	81.38
31.	दादरा और नगर हवेली	77.65	86.46	65.93
32.	दमन और दीव	87.07	91.48	79.59
33.	दिल्ली	86.34	91.03	80.93
34.	लक्षद्वीप	92.28	96.11	88.25
35.	पुदुचेरी	86.55	92.12	81.22

विवरण–II

साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र के हिस्से के रूप में जारी निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्र का जारी हिस्सा			
		2009–10	2010–11	2011–12	2012–12 (16.11.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6899.55	8466.69	6454.92	11605.81

1	2	3	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	403.68	487.03	2260.53	–
3.	असम	1447.59	858.08	0.00	–
4.	बिहार	449.40	8518.94	37.63	–
5.	छत्तीसगढ़	1902.78	1961.53	2867.51	4770.29
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	17.95	0.00	–
7.	गुजरात	2399.11	0.00	1440.12	–0
8.	हरियाणा	120.11	727.56	511.12	–
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	146.34	71.62	269.84
10.	झारखंड	546.67	2576.09	46.41	–
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	887.24	–
12.	कर्नाटक	1844.41	4562.92	0.00	4011.44
13.	मध्य प्रदेश	0.00	2070.01	2817.61	–
14.	महाराष्ट्र	1782.27	479.55	0.00	–
15.	मणिपुर	262.25	0.00	474.84	–
16.	मेघालय	0.00	362.02	0.00	–
17.	नागालैंड	0.00	196.26	119.81	–
18.	ओडिशा	349.89	0.00	9664.37	667.68
19.	पंजाब	0.00	1561.33	0.00	–
20.	राजस्थान	4410.59	0.00	8111.11	–
21.	सिक्किम	62.62	0.00	0.00	–
22.	तमिलनाडु	936.32	1139.63	155.74	1375.04
23.	त्रिपुरा	82.68	0.00	0.00	–
24.	उत्तर प्रदेश	6488.37	0.00	15542.09	–

1	2	3	4	5	6
25.	उत्तराखंड	794.11	190.93	2841.73	-
26.	पश्चिम बंगाल	1415.69	0.00	0.00	2952.05
	कुल	32598.10	34322.86	45604.40	25652.15

अस्पतालों को जमीन

*176. श्री रतन सिंह :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवंटियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें दिल्ली में अस्पतालों और नर्सिंग होमों के निर्माण हेतु रियायती दरों पर जमीन दी गई है;

(ख) क्या पट्टा विलेख के निबंधन और शर्तों के अनुसार अस्पतालों और नर्सिंग होमों के कार्यकरण की निगरानी करने हेतु क्या तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन विभिन्न अस्पतालों और नर्सिंग होमों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हों जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों का मुफ्त उपचार नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) उन आबंटियों का ब्यौरा जिन्हें दिल्ली में अस्पतालों और नर्सिंग होमों के निर्माण हेतु रियायती दरों पर आबंटित भूमि दी गई थी संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। पट्टा विलेख के निबंध एवं शर्तों के अनुसार अस्पतालों और नर्सिंग होमों के कार्यों की निगरानी प्रक्रिया का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। विभिन्न अस्पतालों और नर्सिंग होमों जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई है, लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को नि:शुल्क इलाज मुहैया नहीं करा रहे हैं, के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। अस्पताल जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई है, को गरीब व्यक्तियों को 25 प्रतिशत ओपीडी और 10 प्रतिशत आईपीडी में सभी प्रकार से पूर्णत: नि:शुल्क इलाज मुहैया कराना पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार गरीब और कमजोर वर्गों को नि:शुल्क चिकित्सीय इलाज की मॉनीटरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा एक निगरानी समिति गठित की गई है और यह समिति इन अस्पतालों द्वारा मुहैया कराए जा रहे नि:शुल्क इलाज के प्रावधान की निगरानी के लिए प्रत्येक महीने 4 से 5 चिह्नित निजी अस्पतालों का निरीक्षण करती है।

ऐसे निरीक्षणों के दौरान पाई गई विसंगतियों को तत्काल दूर करने के निर्देश देते हुए संबंधित अस्पतालों को सूचित किया जाता है और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि एवं विकास कार्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अस्पतालों के पट्टा विलेख के निर्धारण/ निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई शुरू करते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मरीजों के नि:शुल्क इजाज पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिल्ली में रियायती दरों पर आबंटित भूमि प्राप्त करने वाले अस्पतालों नर्सिंग होमों के ब्यौरे

क्र.सं.	सोसायटी/हॉस्पिटल का नाम	स्थल	क्षेत्र
1	2	3	4
	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि		
1.	आरबी. जस्सा राम अस्पताल	करोल बाग	4840.50 वर्गमीटर
2.	डा. बी. एल. कपूर मैमोरियल अस्पताल	पूसा रोड	5 एकड़
3.	दिल्ली चशायर होम (विकलांगों के लिए अस्पताल)	ओखला	3.52 एकड़
4.	सुंदर लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट	अशोक विहार	3.14 एकड़
5.	अस्थमा और ब्रानकाईटिस फाउंडेशन (दिल्ली विश्वविद्यालय)	गौतम नगर	1.38 एकड़
6.	आशी राम बत्रा पब्लिक चैरेटेबल ट्रस्ट	तुगलकाबाद	10.50 एकड़
7.	गुजरमल मोदी हास्पिटल और रिसर्च सेंटर	साकेत	15 एकड़
8.	मैडम चानन देवी आई अस्पताल	जनकपुरी	2.075 एकड़
9.	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट	कड़कड़डूमा	4840 वर्ग गज
10.	फ्लाई लैप्टि. राजन ढाल चैरेटिबल ट्रस्ट	मसूदपुर	1.84 एकड़
11.	महासती मोहन देवी जैन शिक्षण समिति (भगवान महावीर अस्पताल)	रोहिणी	4048 वर्ग मीटर
12.	खोसला मेडिकल इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर	शालीमार बाग	9680 वर्ग गज
13.	बिरला सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च	वसंत विहार	3.5 एकड़
14.	जयपुर गोल्डन हास्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट	रोहिणी	3.6295 एकड़
15.	दीपक गुप्ता मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट	कड़कड़डूमा	4840 वर्गमीटर
16.	आल इंडिया सोसायटी फार हेल्थ एंड एजूकेशन रिसर्च	द्वारका फेज-I	2 एकड़
17.	गणेश दास चावला चैरेटिबल ट्रस्ट	रोहिणी	4048 वर्गमीटर
18.	माई कमली वाली जल कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट	राजौरी गार्डन	434.50 वर्गमीटर
19.	परमार्थ मिशन अस्पताल	पीतमपुरा	2420 वर्गमीटर

1	2	3	4
20.	मुकंद लाल मेमौरियल फाउंडेशन	-	6852 वर्गमीटर
21.	लाला गेला राम मैमोरियल मेडिकल रिसर्च सेंटर (डेंटल अस्पताल)	पीतमपुरा	528 वर्गमीटर
22.	वी. एन. गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट	पीतमपुरा	0.2 हेक्टेयर
23.	इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर	वसंत कुंज	11.84 एकड़
24.	फाउंडेशन आफ एपलाइड रिसर्च इन कैंसर	साउथ आफ आईआईटी	4013.66 वर्गमीटर
25.	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एवं रिसर्च सेंटर	धल्लू	13175 वर्गमीटर
26.	नेशनल सोसायटी फॉर प्रिवेनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस (छोटा हॉस्पिटल)	कडकडडूमा	800 वर्गमीटर
27.	राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	रोहिणी	3.5 एकड़
28.	एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	ओखला	6.9 एकड़
29.	लक्ष्मीपत सिंघानिया मेडिकल फाउंडेशन	साकेत	2 एकड़
30.	वेणु चैरिटेबल सोसायटी (आंखों का अस्पताल)	साकेत	2.5 एकड़
31.	सोंढी चैरिटेबल ट्रस्ट	ओखला	1.162 एकड़
32.	विवेकानंद प्रतिष्ठानम	खुरेजी	8000 वर्गमीटर
33.	मानव सेवार्थ ट्रस्ट	पश्चिम पुरी	1 हेक्टेयर
34.	आर्य वैद्य शाला कोटालय	कडकडडूमा	9240 वर्गमीटर
35.	हयूमन केयर मेडिकल ट्रस्ट	द्वारका	1 हेक्टयर
36.	देवकी देवी फाउंडेशन	साकेत	1.123 एकड़
37.	डा. नारायण दत्त श्रीमाली फाउंडेशन	पीतमपुरा	3.0 हेक्टेयर
38.	विक्रांत चिल्ड्रन मेडिकल फाउंडेशन	साकेत	1.4 हेक्टेयर
39.	बालाजी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर	मंडावली	12000 वर्गमीटर
40.	बी.आर. धवन मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट	द्वारका	0.9 हेक्टेयर
41.	निरोगी चैरेटिबल मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट	मंडावली फजलपुर	0.85 हैक्टेयर
42.	लाला मुन्नी लाल मांगे राम चैरिटेबल ट्रस्ट	पश्चिम विहार	2.34 हेक्टेयर

1	2	3	4
43.	मुल्तान सेवा समिति	पीतमपुरा	1590 वर्गमीटर
44.	वालिया चैरिटेबल ट्रस्ट	मयूर विहार-III	795 वर्गमीटर
45.	परम शक्ति पीठ मंडावली	0.26 एकड़	
46.	यूनिक अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट	द्वारका	3.16 हेक्टेयर
47.	सर्वोदय हेल्थ फाउंडेशन	रोहणी	1000 वर्गमीटर
48.	शांती मेमोरियल सोसायटी	लाडो सराय	1 हेक्टेयर
49.	दिल्ली ईएनटी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (ईएनटी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर)	जसोला एफसी-33	768 वर्गमीटर
50.	संत निरंकारी मंडल	धीरपुर	10 एकड़
51.	मधुकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल	गीतांजली	5500 वर्गमीटर
52.	नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	ईस्ट आफ कैलाश	743.80 वर्गमीटर
53.	सीताराम भारतीया इंस्टीट्यूट	बी-16, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया	1.46 एकड़
54.	बाला साहिब गुरूद्वारा	किलोकरी	46274 वर्गमीटर
55.	महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट	मॉडल टाउन	8000 वर्गमीटर
56.	जिवोदय अस्पताल	अशोक विहार	0.84 एकड़ + 37.9 वर्ग गज
	भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा आबंटित भूमि		
1.	मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट	लाजपत नगर	9 एकड़
2.	श्री गंगा राम ट्रस्ट सोसायटी	करोल बाग	11.965 एकड़
3.	सेंट, स्टीफन सोसायटी	तीस हजारी कोर्ट के पास	3.15 एकड़
4.	दिल्ली हास्पिटल सोसायटी	चाणक्य पुरी	2 एकड़
5.	डा. विद्यासागर कौशल्या देवी मेमोरियल ट्रस्ट	नेहरू नगर	3.5 एकड़
6.	आर.बी. सेठ एंड जस्साराम एंड ब्रदर चैरिटेबल ट्रस्ट	करोल बाग	710.50 वर्ग गज

1	2	3	4
दिल्ली नगर निगम द्वारा आबंटित भूमि			
1.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल	पंजाबी बाग	उपलब्ध नहीं
2.	एमजीएस अस्पताल	पंजाबी बाग	उपलब्ध नहीं

विवरण-II

(क) डीडीए द्वारा निजी अस्पताल को भूमि का आबंटन करने संबंधी मानक शर्तें और निबंधन

1. सोसायटी/अस्पताल, ... मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे भारत सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा निर्णीत अनुसार संशोधित दरों पर भूमि की लागत के अंतर की राशि का भुगतान करेंगे।

2. अस्पताल, सार्वजनिक जन अस्पताल के रूप में सेवा प्रदान करेगा जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत बिस्तर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उपचार करने के लिए आरक्षित रखेगा।

3. अस्पताल का ओ.पी.डी. दरिद्र श्रेणी में आने वाले रोगियों को निशुल्क सेवा प्रदान करेगा।

4. अस्पताल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेगा जिसके लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय/स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उसकी सेवाएं प्राप्त की जाएंगी।

5. अस्पताल प्रसूति और बाल स्वास्थ्य केंद्र के लिए पृथक क्षेत्र निर्धारित करेगा जो कि समुदाय के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगा।

6. सर्जिकल यूनिट के मामले में अस्पताल, दिल्ली सरकार/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित भुगतान किए जाने पर स्ट्रलाइजेशन के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा।

7. सोसायटी भूमि का उपयोग, अस्पताल और अत्यावश्यक नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण करने के लिए करेगी और ना किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ।

8. सोसायटी किसी भी प्रयोजनार्थ अन्य किसी भी संगठन को दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना भूमि अंतरित नहीं करेगी/पट्टे पर नहीं देगी।

9. लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दिल्ली सरकार/भारत सरकार भूमि की हकदारी दुबारा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. अस्पताल और अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टस का निर्माण, प्लाट का अधिग्रहण सौंपे जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।

11. सोसायटी निदेशालय (आयोजना)/मुख्य वास्तुशिल्प, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित वास्तुशिल्पीय नियंत्रण के अंतर्गत आबद्ध होगी।

12. अस्पताल को जब कभी भी कहा जाएगा वह अपने खर्चे पर पट्टा विलेख कार्यान्वित करेगा।

13. प्लाट पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय निकाय/दिल्ली विकास प्राधिकरण से निर्माण प्लाट अनुमोदित करवाना होगा।

(ख) भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को आबंटित भूमि के लिए मानक शर्तें और अनुबंधन

(i) पट्टाधारी दिल्ली की नई राजधानी में मान्य समय-समय के बिल्डिंग, ड्रेनेज और अन्य बाई लाजों का सभी प्रकार से पालन करेगा।

(ii) पट्टाधारी भूमि और विहास अधिकारी या ऐसे अधिकारी या निकाय जैसा कि पट्टा प्रदाता है कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के या इस संबंध में प्राधिकृत भूमि और विकास करना जिससे उसकी बदलाव याव उक्त संबंधित परिसरों पर बनी बिल्डिंग में निर्माण करना जिससे उसकी किसी वास्तुविद या ढांचागत विशेषताओं को प्रभावित करती हो या उक्त संबंधित बिल्डिंगों के किसी भाग पर निर्माण, उनकी तारीख पर बनी बिल्डिंगों को छोड़कर, नहीं करेगा।

(iii) पट्टाधारी उक्त परिसरों पर उक्त परिसरों पर किसी व्यापार, व्यापार या उत्पादन जो कि भूमि और विकास अधिकारी की दृष्टि में नोयजी, बुरी या अपराध मुल्क है को चलाने की अनुमति नहीं देगा या उक्त परिसरों के अस्पताल बिल्डिंग के निर्माण या आवश्यक नर्सिंग और चिकित्सा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की अनुमति नहीं देगा तथा या कोई ऐसी गतिविधि जो भी हो जो कि भूमि और विकास अधिकारी की दृष्टि में अनुचित या भारत के राष्ट्रपति के लिए परेशानी का कारण हो या दिल्ली की नई राजधानी में उनके किराएदारों के लिए परेशानी हो, नहीं करेगा तथा भूमि और विकास अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना उक्त परिसर का उपयोग नहीं करेगा या उक्त परिसरों को अनाजों या किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की बिक्री या किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। पट्टाधारी प्रिमियम और आधारभूत किराए (लाइसेंस फीस) के अंतर जब भी 1.4.2000 से भूमि दरें परिशोधित होगी, का भुगतान करेगा।

(iv) पट्टाधारी भूमि और विकास अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी या निकाय की लिखित स्वीकृति के बिना एतद्द्वारा संबंधित परिसरों में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगा तथा इस पट्टे के बने रहने के दौरान हमेशा परिसर की देखरेख करेगा तथा उक्त भूमि और विकास अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी या उक्त निकाय के संतुष्टि के स्तर तक साफ-सफाई रखेगा।

(v) इस पट्टे के बने रहने के समय के दौरान पट्टाधारी उक्त भूमि पर स्थित बिल्डिंगों को अच्छी स्थिति और मरम्मत द्वारा उपयुक्त रूप से रखेगा।

(vi) पट्टाधारी, पट्टाप्रदाता की संतुष्टि के स्तर तक संबंधित परिसरों की उक्त बिल्डिंगों की देखरेख करेगा तथा उक्त संबंधित परिसरों की देखरेख के लिए निरीक्षण के उद्देश्य से तथा उसकी सामान्य स्कीम और उसके प्रबंधनों के लिए ऐसी अधिकारियों जैसा कि पट्टा प्रदाता नियुक्त करे, को संबंधित परिसरों को सभी उपयुक्त समय पर देखने/निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

(vii) प्रथमतया पट्टाकार की लिखित स्वीकृति और उसकी प्राप्ति के बिना पट्टेदार उक्त भवन को उप किराएदारी हस्तांतरण या समाप्त हो चुके स्वामित्व या उसके भाग के रूप में नहीं देगा और ऐसी किसी स्वीकृति के दौरान पट्टाकार ऐसे अनुबंध एवं शर्तें रख सकता है जो उसके विवेकानुसार ऐसे उपलीज हस्तातंरण या प्रदाय के लिए शर्तों के रूप में उचित है। ऐसी शर्तों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि पट्टेदार या हस्तांतरित या प्रदाता यथा परिस्थितिनुसार, पट्टाकार को बढ़ा हुआ भू-किराया देगा जो ऐसा किसी स्वीकृति में विनिर्दिष्ट होगा बशर्ते पट्टाकार हस्तांतरण के समय (चाहे ऐसा हस्तांतरण संपूर्ण साईट या केवल उसके एक भाग का) भूमि के मूल्य में अनर्जित बढ़ोतरी (अर्थात पूर्व प्रदत्त प्रीमियम और वर्तमान बाजार मूल्य का अंतर) कां दावा करने और उसका भाग वसूल करने का पात्र होगा।

वसूल की जाने वाली राशि अनर्जित बढ़ोतरी का 50 प्रतिशत होगी बशर्ते इसके अतिरिक्त उस मामले में जहां हस्तातंरण एक ऐसे व्यक्तियों या संस्थान के पक्ष में किया गया हो जो पट्टेदार के समान आबंटन का पात्र नहीं हो तब पट्टेकार अनर्जित बढ़ोतरी के शत प्रतिशत का दावा करने का पात्र होगा।

यह प्रावधान भी किया जाता है कि पट्टेकार को यथा उपरोक्तानुसार अनर्जित बढ़ोतरी की राशि घटाने के पश्चात समाप्त उक्त भवन के अग्रक्रय अधिकार होंगे।

यह प्रावधान भी किया जाता है कि पट्टेकार को यथा उपरोक्तानुसार अनर्जित बढ़ोतरी की राशि घटाने के पश्चात समाप्त उक्त भवन के अग्रक्रय अधिकार होंगे उक्त सम्पत्ति अधिकार होंगे।

(viii) उक्त पट्टेदार को किसी प्रस्तावित बदलाव संशोधन या रूपांतरण की स्थिति में प्रथमतया पट्टेकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना पंजीकृत अनुच्छेदों और करारज्ञापन या व्यापार के नियमों आदि (फिर चाहे जिस नास से संस्थान का संविधान जाना जाता हो) या उसके संविधान के गठन में बदलाव संशोधन या किसी अन्य प्रकार का रूपांतरण नहीं करेगा।

(ix) किसी समय पट्टेदार या भूमि विकास अधिकारी की राय में, जिसका निर्णय अंतिम हो, उक्त पट्टेदार या दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन किसी शपथबद्ध व्यक्ति द्वारा या विभिन्न उप-धाराओं में वर्णित शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है और यदि उक्त अभिप्रेत पट्टेदार भूमि एवं विकास अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की प्राप्ति जिसमें ऐसे उल्लंघन का प्रतिकार करना अपेक्षित हो, के सात दिवस की अवधि में हुए उल्लंघन को नजर अंदाज करता है या प्रतिकार करने में भूमि तथा विकास अधिकारी की दृष्टि में असफल होता है तो भूमि तथा विकास अधिकारी के प्राधिकार और निदेश में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह कानून सम्मत होगा कि ऐसे समाप्त भवन में दाखिल हो जाए और (क) उक्त भवन में स्थापित निर्माण को हटा दे या परिवर्तनों को ढहा दे (ख) उक्त भूमि और विकास अधिकारी या विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना उक्त भवन में स्थापित निर्माण को हटा या ढहा दे। (ग) आवश्यकतानुसार किसी खुदाई को भरे या मरम्मत कार्य करे और उक्त कार्य में भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा होने वाली समस्त खर्च या उसके आदेश से पट्टेदार द्वारा वहन किया जाएगा, और यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि विभिन्न धाराओं द्वारा वे पूर्वप्रदत्त स्वतंत्रताएं जो भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त हैं किसी भी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगी।

(x) यदि एतद् द्वारा आरक्षित वार्षिक किराया अथवा इसका कुछ भाग किसी भी समय उक्त दिनों में से किसी दिन के बाद अगले एक कैले.डर महीने के लिए बकाया और भुगतान नहीं किया हो जिस पर यह देय हो चुका होगा, इस किराए की मांग की गई है अथवा नहीं अथवा यदि पट्टाकर्ता अथवा भूमि एवं विकास अधिकारी विचार से ऐसा होता हो तो उनका निर्णय अंतिम होगा, पट्टेदार द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन करने अथवा विभिन्न उप-खंडों में निहित शर्तों के अलावा इसमें निहित प्रतिज्ञा पत्र अथवा शर्तों के अनुसार अथवा इसके जरिए दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने और उसके द्वारा निष्पादित अथवा उसकी तरफ से निकाले गए निष्कर्ष अथवा यह पट्टेदार की संतुष्टि के अनुसार होगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा जिससे कि हस्तांतरित परिसरों का अस्पताल भवन के प्रयोजन हेतु अथवा अनिवार्य नर्सिंग और मेडिकल स्टॉफ क्वार्टरों का अनुचित अथवा गैर सक्षम प्रबंधन होने के कारण उपयोग करना बंद हो चुका है, तो ऐसे मामले में पट्टेदार के अनुसार कानून वैद्य होगा अथवा किसी पूर्व कारण अथवा एतद् द्वारा हस्तांतरित परिसरों के किसी भी भाग पर पुनः प्रवेश करने अथवा सभी के नाम से ऐसे भवनों में उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को पुनः प्रवेश करने के अधिकार का त्याग करने के बाद भी और इस हस्तांतरित भूमि पर और इसमें निहित प्रत्येक वस्तु समाप्त होगी और निर्धारित होगी और पट्टेदार हस्तांतरित परिसरों के लिए किसी क्षति पूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा लेकिन ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि उस समय की कीमत अथवा लागत सहित इन वर्तमान परिसरों के निष्पादन से पहले भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि, इनमें से जो भी होगी, उससे अधिक नहीं होगी, पट्टेदार द्वारा भूमि पर निर्मित भवन की कीमत विवादित होने के मामले में उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ग) दि.न.नि. द्वारा निजी अस्पतालों को भूमि के आबंटन हेतु मानक शर्तें और निबंधन

(i) पट्टेदार दिल्ली मास्टर प्लान और जोनल विकास योजनाओं से किसी प्रकार विचलन नहीं करेगा न ही उक्त भूमि के आकार में हेर-फेर करेगा चाहे वह उप-विभाजन, एकीकरण अथवा अन्यथा किसी तरह हो,

(ii) पट्टेदार, पट्टादाता की लिखित में पूर्वसहमति, जिसे नकारने के लिए वह पूर्ण विवेकाधिकार का पात्र होगा, के

बिना कब्जे वाली उक्त भूमि को समग्र रूप से अथवा उसके किसी भाग अथवा उस पर बने किसी भवन की बिक्री, अन्तरण अभ्यर्पण अथवा अन्यथा नहीं करेगा।

(iii) उक्त भूमि में से जब भी किसी प्रकार से पट्टेदार का शीर्ष/नाम कुछ भी अन्तरित होता है, अन्तरणकर्त्ता इसमें निहित सभी प्रसंविदाओं और शर्तों द्वारा बाध्य होगा और उनके संबंध में सभी प्रकार से जवाबदेह होगा।

(iv) उक्त भूमि में से जब भी किसी प्रकार से पट्टेदार का नाम/शीर्ष कुछ भी अंतरित होता है, अन्तरणकर्त्ता और अंतरिती तीन महीने के भीतर पट्टादाता को लिखित में ऐसे अंतरण का अंतरण नोटिस देंगे।

(v) पट्टेदार समय-समय पर और हमेशा ही सभी दरों करों, प्रभारों का भुगतान और प्रत्येक विवरण के निर्धारणों, जो इसके बाद इस पट्टे के जारी रहने के दौरान कभी भी हो सकते हैं, उक्त भूमि के एतद्वारा हस्तांतरण/वसीयत पर तथा ऐसे निर्धारण पर और उस संबंध में भू स्वामी अथवा किराएदार द्वारा ऊपर कोई भवन बनाया गया हो तो उस पर लगने वाले प्रभारों को चुकता करेगा।

(vi) पट्टेदार उक्त भूमि पर अथवा उस पर बने किसी भवन में पट्टादाता की लिखित सहमति के बिना न तो कोई व्यापार करेगा अथवा नहीं उसे जारी रखने के लिए अनुमेय ही होगा अथवा अस्पताल एवं डिस्पेंसरी से भिन्न किसी प्रयोजनार्थ न तो उसका उपयोग ही करेगा अथवा उपयोग करने हेतु अनुमेय होगा जिसे पट्टादाता की राय में उस पर हो रहे किसी कृत्य द्वारा हानि अथवा पट्टादाता तथा पड़ोस में रह रहे लोगों के लिए कष्ट परेशानी अथवा अशांति होती हो, नहीं कर सकेगा।

(vii) न्यास द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल सह-डिस्पेंसरी में 40 प्रतिशत रोगियों का मुफ्त इजाज होगा और दिल्ली नगर निगम को ऐसे रोगियों को भेजने का प्रथम अधिकार होगा।

(viii) पट्टेदार को उक्त भूमि की जांच हेतु सभी उपयुक्त समय पर आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को वहां प्रवेश की अनुमति देनी होगी, इसलिए कि इसमें निहित प्रसंविदाओं और शर्तों का अनुपालन किया गया है और वह इससे संतुष्ट है।

(ix) पट्टेदार इस पट्टे के निर्धारण पर उक्त भूमि और उस पर बने भवन को शांतिमय ढंग से पट्टादाता से प्राप्त करेगा।

(x) इस लीज के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी नोटिस, आदेश, निदेश, सहमति अथवा अनुमोदन लिखित में होंगे तथा इन पर ऐसे अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन्हें आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तथा यदि इन्हें पट्टेधारी को पंजीकृत कार्यालय पर सौंपा जाता हो अथवा उस व्यक्ति को सौंपा गया हो जो उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार का दावा करता हो अथवा इनको किसी भवन जो अस्थाई रूप से बना हो अथवा अन्यथा उक्त भूमि पर बने भवन पर चिपकाया गया हो, इनको पट्टेदार अथवा ऐसे व्यक्ति के पुराने आवास, कार्यालय अथवा व्यापार स्थल पर अथवा सामान्य रूप से अंतिम पहचान वाले निवास, कार्यालय अथवा व्यापार स्थल पर सौंपे जाने पर इसे विधिवत रूप से सौंपा गया माना जाएगा।

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष 2010 से आज तक नि:शुल्क उपचार करने से मना करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	:	134
निपटान और बंद की गई शिकायतों की संख्या	:	51
प्रक्रियाधीन शिकायतों की संख्या	:	83

तीन नामचीन निजी अस्पताल नि:शुल्क उपचार मुहैया नहीं कर रहे हैं तथा उनका मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(i) मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट एवं हास्पिटल, रिंग रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

(ii) सेंट स्टीफन्स हास्पिटल सोसाइटी, तीस हजारी, दिल्ली।

(iii) राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, डी-18, सेक्टर-V रोहिणी दिल्ली।

विवरण-IV

सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के मुफ्त उपचार की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जीएमसीटीडी द्वारा निगरानी समिति का गठन किया गया है तथा यह समिति इन अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए मुफ्त उपचार के प्रावधान की निगरानी के प्रत्येक माह 4 से 5 चयनित प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण करती है। निगरानी समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं अध्यक्ष
* प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नर्सिंग होम सैल सदस्य
* पीआईएल पिटिशनर सदस्य
* सैंट स्टीफन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सदस्य
* संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सदस्य

(ii) ऐसे निरीक्षणों के दौरान प्रकाश में आई कमियों को संबंधित पहचाने गए निजी अस्पतालों के प्रशासन को उसे तत्काल सुधारने तथा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, जीएनसीटीडी को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए भी निदेश के साथ सूचित किया जाता है।

(iii) संबंधित सरकारी नोडल अधिकारी संबंधित पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अपने से भर्ती मरीजों की गरीबी की सत्यता की जांच करने तथा उनके द्वारा भेजे गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे मुफ्त उपचार के लिए पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करते हैं।

(iv) माननीय उच्च न्यायायल, दिल्ली द्वारा गठित विशेष समिति ने मुफ्त उपचार प्राप्त करने के लिए आय की सीमा को संशोधित किया था तथा उसे 5000/- प्रति परिवार प्रति माह से 7254/- प्रति परिवार माह तक बढ़ाया गया था। आय सीमा को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी जिसे कि वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है से जोड़ा गया है।

(v) पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों दोनों में ईडब्ल्यूएस मरीजों के मुफ्त उपचार की सुविधा के लिए विशेष रेफरर डैस्कों/केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों की देखरेख संबंधित अस्पतालों के नोडल अधिकारी कर रहे हैं।

(vi) ईडब्ल्यूएस मरीजों, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, को छोड़कर मुफ्त उपचार की सुविधा देश में कहीं भी निवास करने वाले ईडब्ल्यूएस मरीजों को दी गई थी।

(vii) मुफ्त उपचार के प्रावधान के संबंध में विज्ञापन, नियमित रूप से मुख्य दैनिक समाचार पत्रों (हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी) में प्रकाशित होते हैं तथा इलेक्ट्रोनिक मिडिया (टेलीविजन और एफएम चैनलों) में ब्रोडकास्ट किया जाता है। अंतिम विज्ञापन माह जनवरी-फरवरी, 2012 में 10 समाचार पत्रों, 04 एफएम चैनलों, 02 टेलिवीजन चैनलों और एमटीएनएल और सफल आऊटलेटों की एलसीडी स्क्रीनों में दिया गया था।

अवैध मोबाइल टावर्स

***177. श्री विजय बहादुर सिंह :**
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन (बीटीएस) स्थापित करने और बीटीएस और मोबाइल हैंडसेटों के लिए रेडिएशन उत्सर्जन मानकों हेतु जारी किए गए विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी टॉवर कंपनियों ने इन विनियमों का पालन नहीं किया है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध बीटीएस की सूची तैयार की है तथा इन टॉवरों को सार्वजनिक स्थलों यथा विद्यालयों, अस्पतालों आदि से हटाने/अन्यत्र ले जाने के लिए मोबाइल कंपनियों को निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली सहित राज्य-वार अब तक ऐसे कितने टॉवर हटाए/अन्यत्र ले जाए गए हैं; और

(ङ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी रेडिएशन उत्सर्जन मानकों और बीटीएस स्थापित करने के संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित करने के संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार प्रत्येक स्थल के लिए मोबाइल टॉवरों की संस्थापना हेतु दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) स्कंध द्वारा स्थल संबंधी अनुमोदन अन्य बेतार प्रयोक्ताओं के साथ व्यतिकरण, विमानन खतरों तथा किसी अन्य मौजूदा माइक्रोवेव लिंक के लिए उत्पन्न होने वाले व्यवधान को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। स्थल संबंधी अनुमोदन राज्य सरकार/नगर निगम/ग्राम पंचायत आदि जैसे स्थानीय निकायों द्वारा लागू उपविधियों, नियमों तथा विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है। तदनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाता को टावर की संस्थापना करने से पूर्व नगर निगम/ग्राम पंचायत आदि जैसे संबंधित स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होती है।

बीटीएस के संबंध में रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड (बेस स्टेशन उत्सर्जन) के लए प्रभावन सीमा से संबंधित मानदंड को दिनांक 01.09.2012 से घटाकर इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) द्वासरा निर्धारित वर्तमान सीमा का 1/10 कर दिया गया है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा विकिरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन करने से संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दूरसंचार विभाग के संबंधित दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा निगरानी (टीईआरएम) प्रकोष्ठों को प्रस्तुत किया जाता है। सभी नए बीटीएस स्थल संगत टीईआरएम प्रकोष्ठों को स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात ही विकिरण आरंभ करते हैं। टीईआरएम प्रकोष्ठ अपने विवेक के अनुसार यादृच्छया 10: तक बीटीएस स्थलों का निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन बीटीएस स्थलों के विरुद्ध जनता से शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी भी टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जा रही

यदि कोई स्थल विकिरण संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो प्रति सेवा प्रदाता प्रति बीटीएस 5 लाख रुपए का दंड वसूल करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सेवा प्रदाताओं द्वारा टीईआरम प्रकोष्ठ की रिपोर्ट जारी होने से एक महीने के भीतर मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है जिस अवधि के बीत जाने पर स्थल के कार्य पर रोक लगा दी जाएगी।

मोबाइल हैंडसेटों के संबंध में विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) मान के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं :

(i) मोबाइल हैंडसेटों के लिए एसएआर स्तर को मानव ऊतक की 1 ग्राम मात्रा पर औसतन 1.6 वाट प्रति किलोग्राम तक सीमित किया गया है।

(ii) मोबाइल हैंडसेटों के सभी डिजाइन 1 सितंबर, 2012 से मानव ऊतक की 1 ग्राम मात्रा पर औसतन 1.6 वाट प्रति किलोग्राम के एसएआर मान का अनुपालन करेंगे।

(iii) तथापि, मौजूदा डिजाइनों वाले मोबाइल हैंडसेट जो मानव ऊतक की 10 ग्राम मात्रा पर औसतन 2.0 वाट प्रति किलोग्राम के अनुपालन में हैं, वे 31 अगस्त, 2013 तक बने रह सकते हैं।

(iv) 1 सितम्बर, 2013 से, घरेलू बाजार के लिए केवल 1.6 वाट प्रति किलोग्राम के संशोधित एसएआर मान वाले हैंडसेटों के ही भारत में विनिर्माण या आयात की अनुमति होगी।

(ख) विकिरण संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करने के लिए टीईआरएम प्रकोष्ठ बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की यादृच्छिक जांच करते हैं। दिनांक 30.11.2012 तक विभिन्न प्रचालकों के कुल 83 बीटीएस निर्धारित विकिरण मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हुए पाए गए हैं। संबंधित दूरसंचार प्रदाताओं को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों और अस्पतालों के निकट मोबाइल टावरों की संस्थापना पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षित है कि वे निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन करें।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों ने मोबाइल टावरों के संस्थापन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने मोबाइल टावरों के संस्थापन पर विशेष प्रतिबंध तथा निषेध आरोपित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और तत्संबंधी निगरानी रखी जाती है।

(ङ) दूरसंचार विभाग में दिल्ली उच्च न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वाले बीटीएस की कंपनी-वार सूची

क्र. सं.	दूरसंचार सेवा प्रदाता	मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वाले बीटीएस की संख्या
1.	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	13
2.	यूनिटेक वायरलेस	5
3.	वीडियोकोन टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	1
4.	वोडाफोन लिमिटेड	13
5.	एयरसेल लिमिटेड	10
6.	भारती एयरटेल लिमिटेड	14
7.	आइडिया मोबाइल लिमिटेड	6
8.	लूप मोबाइल लिमिटेड	6
9.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1
10.	सिस्टेमा श्याम लिमिटेड	2
11.	एस टेल लिमिटेड	1
12.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	11
	कुल	83

[अनुवाद]

डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

*178. **श्री हरिभाऊ जावले :***
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितने डाकघर और स्पीड पोस्ट काउंटर कार्यरत हैं तथा कितने नए डाकघर और स्पीड पोस्ट काउंटर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यमान डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उप डाकघर और उप डाकघरों को मुख्य/प्रधान डाकघर करने का है;

(ग) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को देश में नव सृजित जिलों के लिए डाकघर खोलने तथा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने हेतु राज्यों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्य-वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) देश में 1,54,822 डाकघर (31.3.2012 की स्थिति के अनुसार) और 27,022 स्पीड पोस्ट काउंटर (अद्यतन स्थिति के अनुसार) कार्यरत हैं। इन डाकघरों ओर स्पीड पोस्ट काउंटरों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। डाकघर खोलना एक सतत प्रक्रिया है। नए डाकघर, निर्धारित मानदंडों के अनुसार तथा योजनागत निधियों व कर्मचारी बल की उपलब्धता के अध्यधीन खोले जाते हैं। महाराष्ट्र सहित देश में चालू वित्तीय वर्ष (2012-13) के दौरान डाकघरों की पुनर्स्थापना/कर्मचारियों की पुन तैनाती के माध्यम से 80 शाखा डाकघर और 50 उप डाकघर खोलने तथा 300 स्पीड पोस्ट काउंटर की शुरुआत करने का प्रस्ताव है। इन डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) औचित्य के अनुसार मानदंडों के पूरा होने तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मौजूदा शाखा डाकघरों और उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्रमशः उप डाकघर और प्रधान डाकघर बनाया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार को नव सृजित जिलों में नए डाकघर खोलने के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार से 12 तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नए डाकघरों के स्थानों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देशभर में कार्यरत डाकघरों तथा स्पीड पोस्ट काउंटरों की सर्किलवार संख्या
(31.3.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र .सं.	सर्किल	कार्यरत डाकघरों की संख्या (31.3.2012 की स्थिति के अनुसार)	कार्यरत स्पीड पोस्ट काउंटरों की संख्या (अद्यतन स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16141	2469
2.	असम	4007	625
3.	बिहार	9057	997
4.	छत्तीसगढ़	3127	328
5.	दिल्ली	576	276
6.	गुजरात	8979	1256
7.	हरियाणा	2664	518
8.	हिमाचल प्रदेश	2778	459
9.	जम्मू और कश्मीर	1695	224
10.	झारखंड	3095	479
11.	कर्नाटक	9703	2637
12.	केरल	5068	3845
13.	मध्य प्रदेश	8314	1072
14.	महाराष्ट्र	12858	2218

1	2	3	4
15.	उत्तर पूर्व	2912	326
16.	ओडिशा	8163	1193
17.	पंजाब	3849	772
18.	राजस्थान	10324	1225
19.	तमिलनाडु	12; 064	2629
20.	उत्तर प्रदेश	17668	2532
21.	उत्तराखंड	2718	402
22.	पश्चिम बंगाल	9062	540
	योग	154822	27022

विवरण-II

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखा डाकघरों और उप डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्र .सं.	सर्किल	शाखा डाकघर	उप डाकघर	स्पीड पोस्ट कांउटर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	3	0
2.	असम	4	2	0
3.	बिहार	3	1	48
4.	छत्तीसगढ़	4	2	0
5.	दिल्ली	0	4	151
6.	गुजरात	4	3	0
7.	हरियाणा	4	4	0
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1	0

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	1	1	31
10.	झारखंड	4	1	0
11.	कर्णाटक	4	3	0
12.	केरल	3	2	0
13.	मध्य प्रदेश	4	2	0
14.	महाराष्ट्र	5	4	4
15.	उत्तर पूर्व	6	3	0
16.	ओडिशा	4	2	2
17.	पंजाब	4	1	1
18.	राजस्थान	4	2	29
19.	तमिलनाडु	4	3	5
20.	उत्तर प्रदेश	4	4	23
21.	उत्तराखंड	3	1	4
22.	पश्चिम बंगाल	3	1	2
	योग	80	50	300

विवरण-III

डाकघर खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने हेतु प्राप्त अनुरोधों का विवरण और उन पर की गई कार्रवाई

क्र .सं.	सर्किल का नाम	डाकघर का स्थान	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	मढ शाखा डाकघर का दर्जा बढ़कार उसे उप डाकघर बनाना	जांच की जा रही है।
		गोराल, मुंबई शहर, उत्तर पश्चिम डिवीजन में उप डाकघर खोलना	अनुमोदित, परंतु परिसर के अभाव में लंबित

1	2	3	4
		कुरार गांव, मुंबई शहर, उत्तर पश्चिम डिवीजन में उप डाकघर खोलना	-वही-
		दहिसर (पश्चिम), मुंबई शहर, उत्तर पश्चिम डिवीजन में उप डाकघर खोलना	जांच की जा रहीं है।
		खड़कपाड़ा, ठाणे, मध्य डिविजन में उप डाकघर खोलना	-वही-
		कोन शाखा डाकघर की दर्जा बढ़ाकर उसे उप डाकघर बनाना	-वही-
		कुलगांव शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे उप डाकघर बनाना	-वही-
		वेली, धूले डिवीजन में शाखा डाकघर खोलना	-वही-
		औंधगांव, पुणे शहर पूर्व डिवीजन में शाखा डाकघर खोलना	-वही-
		शोलापुर विद्यपीठ शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे उप डाकघर बनाना	-वही-
		नई जिंदगी, शोलापुर में शाखा डाकघर खोलना	-वही-
		उमेदपुर, शोलापुर में शाखा डाकघर खोलना	-वही-
2	मध्य प्रदेश	शहडोल डिवीजन के अंतर्गत वैधान उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे मुख्य डाकघर बनाना	-वही-
		रतलाम डिवीजन के अंतर्गत अलीराजपुर उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे मुख्य डाकघर बनाना।	-वही-

आकाश-2 टेबलेट

***179. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम लागत वाले आकाश-2 नामक टेबलेट का उन्नत संस्करण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आकाश-2 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार छात्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के ग्रामीण और निर्धन छात्रों को आकाश-2 मुफ्त प्रदान करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यविधि/मानदंड बनाए गए हैं; और

(ङ) ये टेबलेट छात्रों में कब तक वितरित कर दिए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) जी, हां। कम लागत के शुलभ उपकरण (एल. ए.सी.डी.) जिसे आकाश-2 टेबलेट के नाम से जाना जाता है, के उन्नत संस्करण का प्रमोचन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

'आकाश-2' टेबलेट की मुख्य विशेषता में कम से कम 800X480 रिजोल्यूशन्स के साथ'' मल्टी-टच कैपेसिटिव प्रोजेक्टिव डिसप्ले शामिल है। यह एंड्रायड 4.0 (आईस-क्रीम सैन्डविल) ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, जिसे 1 जी.एच.जेड प्रोफेसर द्वारा बल और एच.डी. वीडियो प्लेबैक सपोर्ट मिलता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसमें अंतर्निमित वाई-फाई सपोर्ट है। इस उपकरण में 4जी.बी. की आंतरिक स्टोरेज मेमोरी तथा 32 जी.बी. तक एस. डी. कार्डों को ऑपरेट करने वाला एक एस.डी. कार्ड स्लॉट होता है। इसमें 512 एम.बी. रैम तथा 3000 एम.ए.एच. की बैटरी होती है। आकाश-2 टेबलेट के उन्नत संस्करण में, कई लाभकारी एप्लीकेशन तथा कंटेंट शामिल किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन इस प्रकार है:-

(i) इंडर एक्टिव लैसन बिल्डिंग टूल 'प्रोक्सीमिटी'।

(ii) 'क्लिकर' एप्लीकेशन जिसकी सहायता से कक्षा-कक्षों में वास्तविक समय में 'क्विज' का संचालन किया जा सकता है।

(iii) पी.डी.एफ. तथा एच.टी.एम.एल. में मानक शिक्षा विषयों का अब आसानी से संग्रह किया जा सकता है तथा आकाश-2 में पढ़ा जा सकता है। बतौर प्रदर्शन, एन. सी.ई.आर.टी., तथा स्कूली विद्यार्थियों के लिए एक राज्य बोर्ड से डिजिटल फार्मेट में उपलब्ध कुछ पुस्तकों को इसमें डाला गया है।

(iv) इंजीनियरिंग कंट्रोल एप्लीकेशनों के प्रदर्शन के लिए 'रोबोट-कंट्रोलर'।

(v) स्पोकन ट्यूटोरियल्स का प्रयोग आकाश-2 टेबलेट में किया जा सकता है।

(vi) कुछ शैक्षिक एनिमेशन तैयार किए गए हैं, तथा आकाश-2 टेबलेट पर संचालित करने के लिए इंटरएक्टिव एनिमेशन तैयार किए गए हैं, तथा आकाश-2 टेबलेट पर संचालित करने के लिए इंटरएक्टिव एनिमेशन सृजन हेतु ओपन सोर्स साफ्टवेयर टूल्स तैयार किए जा रहे हैं तथा उन्हें अपनाया जा रहा है।

(vii) प्रोग्रामिंग एनावायरमेंट जिसकी सहायता से विद्यर्थी सी. सी.++ एवं पायथन में कार्यक्रम तैयार करने के लिए इन टेबलेट्स का उपयोग नियमित कम्प्यूटर के तौर पर कर सकते हैं।

(viii) स्किलैब पैकेज को पूर्ण रूप से आकाश-2 टेबलेट में डाला गया है।

(ix) आधार बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन को आकाश-2 टेबलेट के साथ समेकित किया गया है।

(x) लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आकाश-2 टेबलेट में डाला गया है जिसे और आगे इष्टतम स्तर तक बढ़ाया जा रहा है।

(xi) विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक ए-व्यू वीडियो कांफ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर से आकाश के माध्यम से देश व्यापी कक्षाओं में शामिल होना।

(ग) से (ङ) वर्तमान में इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्यापक सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.एम.ई.आई.सी.टी.) के अंतर्गत एल.सी.ए.डी. (आकाश-2) प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित डिलिवरेबल्स प्राप्त करने हेतु आई.आई.टी. बाम्बे द्वारा एक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है:-

(i) लो कॉस्ट एक्सेस कम-कम्पयूटिंग डिवाइसिस की अधिप्राप्ति तथा परीक्षण; और

(ii) लो कॉस्ट एक्सेस कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसिस के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन।

प्रथम चरण में, पूरे भारत में 1,00,000 टेबलेट्स विभिन्न जलवायुगत तथा उपयोग दशाओं में परीक्षण के प्रयोजनार्थ हैं। चूंकि ये टेबलेट्स परीक्षण तथा अध्यापक सशक्तिकरण के प्रयोजनार्थ हैं, इसलिए इन्हें प्रथम चरण में विद्यार्थियों को वितरित नहीं किया जाएगा।

स्पैक्ट्रम की नीलामी

*180. श्री एन. कृष्टप्प :
श्री खगेन दास :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी.एस.एम. स्पैक्ट्रम नीलामी में केवल पांच ही कंपनियों ने भाग लिया तथा सी.डी.एम.ए. के लिए कोई बोलीदाता नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा होने का अनुमान है;

(ग) सरकार द्वारा सी.डी.एम.ए. स्पैक्ट्रम की कीमत किस तरह निर्धारित की जाती है; और

(घ) सरकार का उपलब्ध 800 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम का भविष्य में किस प्रकार उपयोग करने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में पांच कंपनियों ने भाग लिया था। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कोई भी बोलीदाता सामने नहीं आया।

(ख) 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने वाली पांच कंपनियों के नाम हैं:-

(i) भारती एयरटेल लिमिटेड

(ii) आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड

(iii) वोडाफोन साउथ लिमिटेड

(iv) वीडियोकोन टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड

(v) टेलीविंग्स कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(ग) नीलामी द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं होने के कारण सी.डी.एम.ए. स्पेक्ट्रम के मूल्य के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) उपलब्ध 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करने की पद्धति की समीक्षा हेतु नया पैनल

1841. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में गरीबों को चिह्नित करने की पद्धति की समीक्षा करने हेतु डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक नए पैनल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पैनल/समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) गरीब के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, देश में 2009-10 में, कुल 1189.9 मिलियन जनसंख्या में से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 354.7 मिलियन अनुमानित की गई है।

(ग) और (घ) "गरीबी के माप हेतु कार्यप्रणाली की समीक्षा" करने के लिए योजना आयोग ने जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। समूह के विचारार्थ-विषय निम्नानुसार हैं:-

(i) गरीबी का अनुमान लगाने हेतु वर्तमान कार्यप्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करना तथा यह जांच करना कि क्या गरीबी रेखा केवल उपभोग बास्केट के अर्थों में निर्धारित की जानी चाहिए अथवा क्या अन्य मानदण्ड भी संगत हैं, और यदि हैं तो, क्या ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुमान लगाने हेतु आधार तैयार करने में दोनों को प्रभावी रूप से संयुक्त किया जा सकता है।

(ii) एन.एस.एस.ओ. कार्यप्रणाली पर आधारित उपभोग अनुमानों तथा राष्ट्रीय लेखा समूहों से प्राप्त अनुमानों में भिन्नता के मुद्दे की जांच करना तथा सी.एस.ओ. द्वारा शुरू किए गए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की राज्य वार उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने हेतु कार्य प्रणाली का सुझाव देना।

(iii) गरीबी अनुमान हेतु वैकल्पिक विधियों, जो अन्य देशों में प्रयोग में हैं, की समीक्षा करना, जिसमें उनके प्रक्रियात्मक पहलू शामिल हों; तथा यह दर्शाना कि क्या इस आधार पर हर समय तथा सभी राज्यों में इसे अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया सहित भारत में गरीबी के आनुभाविक अनुमान के लिए कोई विशेष विधि विकसित की जा सकती है।

(iv) यह सिफारिश करना कि उपरोक्तानुसार विकसित किए गए गरीबी अनुमानों को भारत सरकार की स्कीमों व कार्यक्रमों हेतु पात्रता व हकदारी से कैसे जोड़ा जाना चाहिए।

(ङ) विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ-विषय के अनुसार, समिति को अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

पदों को भरे जाने हेतु पूर्वानुमति

1842. **श्रीमती सुशीला सरोज :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्तियों को किए जाने से पूर्व उनके मंत्रालय की पूर्वानुमति का लिया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या काफी लंबे समय तक पदों के रिक्त रहने के कारण विभिन्न मंत्रालयों का कार्यकलाप बुरी तरह प्रभावित नहीं होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय के कारण देश में बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह ऐसे बेरोजगार युवाओं के मूल अधिकारों का हनन नहीं है जो कि सरकारी नौकरियों के लिए विहित आयु सीमा के अंतिम वर्ष में हैं क्योंकि उक्त निर्णय के कारण वे विहित आयु सीमा को पार कर जाने के पश्चात् किसी सरकारी पद के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य हो जाएंगे;

(ङ) यदि हां, तो क्या विहित आयु सीमा को पार करने के पश्चात 5-6 वर्ष तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु आवेदन करने की अनुमति दिए जाने पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) बहुत कम शीर्षस्थ पद प्रधानमंत्री के अनुमोदन से भरे जाते हैं। अन्य पद, पद के लिए लागू भर्ती नियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भरे जाते हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 36.6 लाख स्वीकृत पदों की कुल संख्या में से दिनांक 01.03.2011 तक लगभग 5.8 लाख पद रिक्त हैं। यह सरकार की कार्य प्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (च) निर्धारित आयु सीमा पार करने के पश्चात रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए बेरोजगारों को 5 से 6 वर्ष की छूट की अनुमति देने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर इस विभाग में विचार नहीं किया जा रहा है।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

1843. **श्रीमती सीमा उपाध्याय :**
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, 2012 विकास लक्ष्यों संबंधी रिपोर्ट के अनुसार 125 देशों की सूची में भारत 89वें स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनीसेफ द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार देश की 32.7 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन एक डॉलर से कम पर जीवन का निर्वाह करती है;

(घ) यदि हां, तो अन्य देशों की तुलना में भारत में जीवन स्तर में ऐसी बड़ी असमानता के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बारे में ऐसे किसी स्थान का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में लक्ष्यों/सूचकों के आधार पर विभिन्न देशों के निष्पादन के बारे में कहा गया है जिसमें विभिन्न सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) विश्व बैंक के डाटाबेस के अनुसार, एक डालर प्रतिदिन से कम पर जीवित रहने वाली भारत की आबादी का प्रतिशत वर्ष 2009-10 में 32.7 प्रतिशत है। विभिन्न देशों के जीवन स्तर में असमानता मात्र आय/उपभोग की निर्धारित स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत पर ही निर्भर नहीं करती है। इसका कारण उनकी विभेदक संसाधन संपन्नता, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक, अवसंरचना उपलब्धता आदि है।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानरव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे प्रशासनिक मंयत्रालय एमडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कई स्कीमें एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

1844. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **विदेश मंत्री** अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 दिनांक 17.8.2012 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में यह बताया गया है कि चीन ने कैलास मानसरोवर के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने में कठिनाइयां बताई हैं;

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा व्यक्त चिंताओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकिला से होकर कैलास मानसरोवर के वैकल्पिक मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कब तक दूर कर लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी हां। चीनी पक्ष ने कैलास-मानसरोवर के लिए किसी वैकल्पिक मार्गों, जिसमें शिपकी ला मार्ग भी शामिल है, को खोलने में कठिनाइयां दर्शाई हैं।

(ख) भारत सरकार वर्ष्ज 1992 से ही कैलास-मानसरोवर के लिए अतिरिक्त मार्ग खोलने के मुद्दे पर चीन की सरकार के साथ चर्चा करती रहती है। चीन के राष्ट्रपति हूं जिंताओं की नवंबर, 2006 में भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने मानसरोवर यात्रा के लिए किसी अतिरिक्त मार्ग खोलने की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि चीनी पक्ष इस आधार पर वैकल्पिक मार्गों को खोलने में कठिनाइयां दर्शाता रहा है कि ऐसा करने से उनके इलाके में दुर्गम रास्तों से होते हुए लंबी दूरी तक यात्रा करनी पड़ेगी जहां पर सड़कों की दशा अच्छी नहीं है और आवास एवं संचार की समुचित सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वैकल्पिक मार्गों पर यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(ग) चीन की सरकार ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों को खोलने के बावत कोई समय-सीमा नहीं बताई है।

[अनुवाद]

एन.सी.आर. के लिए हाईस्पीड कॉरिडोर

1845. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने सूचित किया है कि उसने एन.सी.आर.-2032 के लिए परिवहन संबंधी एक कार्यात्मक योजना तैयार की है। इस योजना में हाई स्पीड रेल आधारित प्रणाली के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न कस्बों/क्षेत्रों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाी कॉरीडोरों 'की अनुशंसा की गई है:-

1. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ
2. दिल्ली-गुडगांव-रिवाड़ी-अलवर
3. दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लबगढ़-पलवल
4. गाजियाबाद-खुर्जा
5. दिल्ली-सोनीपत-पानीपत
6. दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक
7. दिल्ली-गाजियाबाद-हापुड़
8. दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए कार्यदल ने व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर कार्यान्यन हेतु निम्नलिखित तीन कॉरीडोरों को प्राथमिकता दी गई है:

(i) दिल्ली-गुडगांव-रिवाड़ी-अलवर : 180 कि.मी.

(ii) दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ : 90 कि.मी.

(iii) दिल्ली-सोनीपत-पानीपत : 111 कि.मी.

डाक घाटा

1846. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग की वित्तीय स्थिति में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का डाक घाटे को कम करने के लिए विभिन्न डाक सेवाओं की प्र:शुल्क दरों में वृद्धि का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभाग की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) जी नहीं। विभाग की वित्तीय स्थिति में गिरावट नहीं आ रही है। यह सही है कि विभाग घाटे में चल रहा है परंतु पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग का घाटा का रूझान दर्शा रहा है। इसके साथ ही उपरोक्त अवधि के दौरान विभाग के राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है।

(ख)

(करोड़ रुपए में)

अवधि	राजस्व (प्रोग्रेसिव)	व्यय (प्रोग्रेसिव)	घाटा (प्रोग्रेसिव)
2009-10	6266.70	13346.94	6641.30
2010-11	6962.33	13793.67	6345.62
2011-12	7910.52	14163.70	5794.89

(ग) टैरिफ संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है जिस पर विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) विदेश पार्सल (ए.आई.आर./एस.ए.एल.) के डाक टैरिफ को पहले ही 1 सितम्बर 2012 से संशोधित किया जा चुका है और स्पीड पोस्ट की डाक शुल्क दरों को 1 अक्तूबर, 2012 से संशोधित किया गया है।

(ङ) डाक विभाग के अंतर्गत व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय द्वारा विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने हेतु स्पीड पोस्ट, एक्स्प्रेस पार्सल पोस्ट और लॉजिस्टिक पोस्ट आदि जैसी कई प्रीमियम सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बदलते

हुए बाजार परिवेश, ग्राहकों की अपेक्षाओं, औद्योगिक बैंचमार्क आदि को ध्यान में रखते हुए, डाक विभाग समय-समय पर अपनी सेवाओं और उत्पादों की पुनरीक्षा करता है तथा राजस्व अर्जन और अविलंब सेवाएं प्रदान करने के लिए तदनुसार सेवा विशेषताओं में संशोधन करने के लिए उपाय/कार्रवाई करता है।

विभाग ने दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना की है जिससे अधिक व्यापार अर्जित करने और परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी।

विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आवक धन अंतरण सेवा से राजस्व में वृद्धि के लिए 29 सितम्बर, 2011 को मनीग्राम अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा के साथ एक समझौता भी किया है।

पहचान प्रमाण के रूप में आधार

1847. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेश मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी एजेन्सियों से पासपोर्ट जारी करने सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए आधार को स्वीकार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पहचाने गए ऐसे कार्य-कलाप क्या हैं जिनमें आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है;

(ग) इस पर विभिन्न एजेन्सियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को, जिनके आंकड़े दो वर्ष पूर्व संग्रहीत किए गए थे और जिन्हें रसीद जारी की गई थीं, आधार कार्ड वितरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) आधार का उद्देश्य एक ऐसी पहचान उपलब्ध कराना है जिसका उपयोग लोक सेवाएं हासिल करने के लिए किया जा सके ताकि लोगों को कुशल और बेहतर सेवाएं मिल सकें। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को सेवा प्रदानकारी विभिन्न स्कीमों की समीक्षा करने तथा सेवा प्रदान करने हेतु आधार के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे विभिन्न लोकोन्मुख स्कीमों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर मान्यता देने पर विचार करें। आधार को बैंक खाते खोलने और मोबाइल कनेक्शन हासिल करने तथा एल.पी.जी. कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर मान्यता दी गई है। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने तथा वाहनों के पंजीकरण हेतु पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर मान्यता देने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भी गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे लोगों को किसी अतिविशिष्ट चिकित्सा वाले अस्पतालों/संस्थानों अथवा किसी अन्य सरकारी अस्पताल में इलाज़ के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से आर्थिक सहायता देने हेतु आधार को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है जो बड़े जानलेवा रोगों से जूझ रहे हैं। रेल मंत्रालय ने भी रेल यात्रा के लिए आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में, विदेश मंत्रालय, भारत के निर्वाचन आयोग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वे क्रमशः पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र तथा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए "आधार" को पहचान/पते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के रूप में मान्यता दें। भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय मतदाता पहचान-पत्र न होने की स्थिति में, आधार को पहचान तथा पते वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे- सिक्किम, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ नागालैंड, हरियाणा, मणिपुर तथा राजस्थान ने भी विभिन्न लोकोन्मुख स्कीमों के लिए आधार को पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर मान्यता दी है।

(घ) यू.आई.डी.ए.आई. ने निवासियों तक आधार पत्र को पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। 21.11.2012 तक 18.63 करोड़ आधार पत्र भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से मुद्रित तथा प्रेषित किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी का अंतरण

1848. **श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य न होने के बावजूद प्रयोगशालाओं के वाणिज्यिक निष्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रयोगशालाओं में प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी नहीं। जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में सम्मिलित अनेक भारतीय प्रयोगशाला बेहतर वाणिज्यिक प्रदर्शन कर रहे हैं। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधि प्रदत्त परियोजनाओं में विकसित अनेक प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिकरण हेतु भारतीय उद्योगों को पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है। डी.बी.टी. की निधि प्रदत्त परियोजनाओं में से उन्नत तालाब प्रबंधन हेतु एम्बेडेड ऑटोफिश फीडर सिस्टम, नाइसिरिया गोनोरिया, कायमिडिया ट्रैकोमेटिस, फाहलेरिया एंटीबॉडी, फिश नोडा वायरस की पहचान हेतु नैदानिकी किट्स का विकास आदि कुछ महत्वपर्ण प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित की गई हैं। डी बी टी के निधि प्रदत्त परियोजनाओं में विकसित अन्य प्रौद्योगिकियों और वाणिज्यिकरण हेतु भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित विवरण पब्लिक डोमेन पर ेजजचरूध्ककइजपदकपं.दपब.पद में उपलब्ध है।

(ग) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रौद्यागिकियों को हस्तांतरित कर वाणिज्यिकरण करने हेतु तकनीकी, वैज्ञानिक और वित्तीय सहायता प्रदान करक रहा है।

सीबीआई द्वारा सचूना न देना

1849. श्री राकेश सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई को ऐसी जानकारी प्रदान करने संबंधी अनुदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सूचना की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कर दिया गया है और यह अधिनियम की धारा 24 (1) के प्रावधान के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करता है।

(ग) से (च) श्री सी.जे. करीरा बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में दिनांक 31.10.2012 के आदेश सीआईसी/एस.एम./2012/000374 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग ने निदेश दिया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को, सभी सूचना का अधिकार अनुरोधों, जो उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसे आरोप लगाए गए हैं का ध्यान दिए बिना, भ्रष्टाचार के किसी भी प्रकार के आरोपों और मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित हैं, पर विचार करना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को दिनांक 29.11.2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को लागू करने पर दिनांक 30.11.2012 को रोक लगा दी है। यह मामला वर्तमान में न्यायानिर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

एम.डी.एम.एस. के अंतर्गत निधि

1850. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधि आबंटित और उपयोग की गयी;

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य सरकार को

धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का है जिसने योजना के अंतर्गत अपने हिस्से से अधिक धनराशि का व्यय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। मध्याह्न भोजन योजना में सरकारी, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कूलों और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायताप्राप्त मदरसों/मकतबों सहित शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों के अंतर्गत संचालित केन्दों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान 12.13 लाख संस्थाओं में पढ़ने वाले 10.54 करोड़ बच्चों ने मध्याह्न भोजन प्राप्त किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आबंटित तथा प्रयुक्त निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की पात्रता के अनुसार गुजरात को केन्द्रीय सहायता जारी की है।

विवरण

2009-10 से 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 के दौरान आबंटित निधियां तथा किया गया व्यय

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009.10		2010.11		2011-12		2012-13	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	30.11.2012 के अनुसार जारी केन्द्रीय सहायता	30.09.2012 के अनुसार व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	26105.6	20981.3	48302.4	45775.1	85191.5	58518	33579.94	23730.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	1616.82	1073.71	2043.18	1663.96	2091.75	1068.18	1878.30	774.91
3.	असम	28555.8	25167.5	34408.2	39322.3	53220.9	43999.1	25928.57	18398.43
4.	बिहार	52100.1	31936.1	80506.4	78795.9	81820.3	74035.6	49980.15	35064.67
5.	छत्तीसगढ़	17578.6	15661.6	36187.7	36938.9	47463	37890.1	31259.17	19838.15
6.	गोवा	794.34	578.81	1168.27	1049.35	825.41	1158.12	1076.47	576.15
7.	गुजरात	24603.1	21163.8	28851.6	30167.6	35301.6	33068.4	20053.24	11096.45
8.	हरियाणा	19094.9	17651.9	15325.1	15325.1	16713.4	20302.2	9550.14	7497.35
9.	हिमाचल प्रदेश	4835.78	5932.09	6487.67	7002.68	7351.6	7652.29	4180.49	3989.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	5607.67	2982.36	7990.6	8234.22	13430.6	7329.56	2535.06	4656.71
11.	झारखंड	22777.9	18335.1	32595.5	28691	52252.2	29951.4	17406.60	12148.92
12.	कर्नाटक	26902.3	25847.7	45368.3	42599.7	56525.8	46357	47218.80	21676.70
13.	केरल	13845.1	10198.6	18511.3	18112.9	14277.1	18083.2	11191.97	7828.72
14.	मध्य प्रदेश	53311.2	35598.2	65781.8	69417.1	76704.4	74684.5	44591.11	32449.17
15.	महाराष्ट्र	57771.5	46105.6	107492	85622.2	69255.8	90962	69198.02	53972.88
16.	मणिपुर	1478.66	1056.59	5658.11	5575.57	1894.19	1655.46	904.31	0.00
17.	मेघालय	5635.93	5360.22	13831.8	12275.5	3528.12	5303.84	3425.10	1563.24
18.	मिजोरम	821.34	769.19	1902.29	1668.96	3306.57	2800.32	1212.76	297.20
19.	नागालैंड	1062.01	1023.36	4026.97	4079.66	2464.37	2464.37	1660.94	506.91
20.	ओडिशा	32108.2	28046.1	38959.1	28403.4	37124.4	36798.5	25225.32	22186.06
21.	पंजाब	11139.4	10267.4	16605.1	16310.8	17561.5	16268.2	9230.01	7977.00
22.	राजस्थान	40639.5	36328.6	46225.8	46428.6	52901.2	49415.3	24704.74	19668.83
23.	सिक्किम	444.55	423.78	899.59	920.36	1035.65	1225.39	634.12	533.08
24.	तमिलनाडु	40189.2	40012.7	44250.6	42407.5	40333.7	40879.3	51284.21	19117.80
25.	त्रिपुरा	3801.36	4462.79	4856.76	4661.2	8408.41	4902.96	3026.53	2344.23
26.	उत्तराखंड	5169.29	3916.02	10963.3	12478.4	14255.5	11839.5	15357.99	4662.04
27.	उत्तर प्रदेश	89054.4	83949.7	102715	114634	107639	105879	67917.28	48513.82
28.	पश्चिम बंगाल	74165.5	60920.7	79480	79578.4	77251	88572.8	43351.48	42739.98
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	216.48	154.48	247.06	207.31	509.14	238.44	1248.79	54.94
30.	चंडीगढ़	343.12	343.12	525.54	492.83	680.77	680.77	301.00	243.27
31.	दादरा और नागर हवेली	152.62	144.46	290.45	288.83	342.71	342.71	211.25	72.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दमण और दीव	89.96	89.96	147.78	142.1	136.58	136.34	116.08	35.90
33.	दिल्ली	7074.43	3817.07	9072.32	7944.17	6562.19	8429.61	5792.26	4995.86
34.	लक्षद्वीप	46.48	38.5	80.54	48.87	76.32	54.47	45.87	27.56
35.	पुदुचेरी	429.7	366.34	693.24	651.84	635.99	635.99	201.47	310.94
	कुल	669560	560705	912452	887916	989072	923582	625480	429550

[हिन्दी]

अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाएं

1851. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**
श्री एन. पीताम्बर कुरूप :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन परियोजनाओं की आज की तिथि के अनुसार और लंबित होने की तिथि सहित अनुमोदन हेतु केरल सहित योजना आयोग के पास परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को अनुमोदन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) उन परियोजनाओं/प्रस्तावों की राज्य-वार सूची, जिनकी जांच की जा रही है और जो योजना आयोग में अनुमोदन के लिए लंबित हैं, ब्यौरा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) निवेश संबंधी मंजूरी के लिए लंबित सिंचाई परियोजनाएं

क्रमांक	राज्य का नाम	क्षेत्रक/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	कब से लंबित है
1.	हिमाचल प्रदेश	नादुआं क्षेत्र मझोली सिंचाई परियोजना	97.59	14.08.2012
2.	मध्य प्रदेश	बिलगांव मझोली सिंचाई परियोजना	182.22	14.08.2012
3.	उत्तराखंड	तुमारिया-बाहाल्ला और नकटिया फीडर मझोली परियोजना	11.20	14.08.20012
4.	बिहार	पश्चिमी गंडक नहर प्रमुख सिंचाई प्रणाली का पुनरुद्धार	2169.51	14.08.2012

(ख) वार्षिक योजना 2012-13 के दौरान एक-बारगी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता/ विशेष योजना सहायता से वित्तपोषित की जाने वाली लंबित परियोजनाएं

क्रमांक	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	राज्य सरकार से प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	बिहार	पटना में चिरैयाटांड फ्लाइओवर का एग्जीबिशन रोड पर गांधी मैदान तक विस्तार तथा मीठापुर फ्लाईओवर का स्टेशन रोड पर चिरैयाटांड फ्लाइओवर तक विस्तार	167.86	25.10.2012
2.	गुजरात	तटीय पर्यटन का विकास	120.00	10.10.2012
3.	झारखंड	ग्रामीण सड़क, पुलों और पुलियाओं का निर्माण	372.08	30.10.2012
	पश्चिम बंगाल	"मॉडलिंग ऑफ थर्मल ट्रांसपोर्ट इन सब-मर्जड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस" संबंधी अनुसंधान परियोजना	0.80	09.10.2012
5.	उत्तराखंड	(i) नैनिन-सैनी विमानपत्तन, पिथौरागढ़ में रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा सम्बद्ध अवसंरचना और टर्मिनल सुविधाओं का क्रमोन्नयन	48.20	22.11.2012
		(ii) खारशाली (उत्तरकाशी), औली (कमोली), केदारनाथ (रुद्रप्रयाग), घनघरिया (चमोली), बद्रीनाथ (चमोली) और मसूरी (देहरादून) में 6 हेलीपैड का निर्माण	9.77	22.11.2012
		(iii) देहरादून, यूएस नगर, पौड़ी चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, हरिद्वार जिले में 43.075 कि.मी. बाढ़ नियंत्रण एवं 255 स्टैंड का निर्माण किया गया	79.31	15.11.2012
		(iv) कोसी (अल्मोड़ा) में बांध, लिफ्टिंग चैनल, जलाशय और वितरण तंत्र का निर्माण	52.67	15.11.2012
		(v) कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का निर्माण	32.06	15.11.2012
		(vi) जीपीएस और जीजेएस का निर्माण	14.62	15.11.2012
		(vii) देहरादून में निदेशालय भवन का निर्माण	7.81	15.11.2012
		(viii) 21 उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण	28.82	15.11.2012

1	2	3	4	5
	(ix)	माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण	48.07	15.11.2012
	(x)	टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल और चम्पावत, प्रत्येक जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, 1 विद्यालय का निर्माण	45.36	15.11.2012
	(xi)	रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल जिलों में जल आपूर्ति स्कीम	287.62	15.11.2012
	(xii)	भंडारीबाग में आरओबी, बुल्लीवाला में फ्लाइओवर, और आईएसबीटी (देहरादून) का निर्माण	70.00	15.11.2012
		काशीपुर-ठाकुडवाडा रोड (उधम सिंह नगर) का निर्माण	18.14	15.11.2012
		किच्छा-नगला रोड (यूएसएन) का निर्माण	76.30	15.11.2012
		दुगरीपंत-छटीखल रोड (पौड़ी गढ़वाल)	16.90	15.11.2012
		दाबरा-चटी में भारी मोटर वाहनों के लिए हैंगिंग ब्रिज तथा टिहरी झील (टिहरी) पर घोंटी पर हल्के वाहनों हेतु पुल	128.53	15.11.2012
		देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र	24.12	15.11.2012
		देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में शौचालयों का निर्माण	5.62	15.11.2012
		मसूरी में व्यापक पार्किंग	136.00	15.11.2012
		पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण (जैसे कि यू.के. के सभी 13 जिलों में ग्राम-वार/प्रत्येक दुकान/गोदाम एवं कायालय)	51.54	15.11.2012
		चिनीयालसीसौर (उत्तरकाशी) में विमानपत्तन संबंधी निर्माण कार्य	41.04	22.11.2012
		इंजीनियरिंग कॉलेज, गोपेश्वर की स्थापना और पॉलीटेक्नीक्स का सुदृढ़ीकरण	76.40	15.11.2012

1	2	3	4	5
		सड़कों एवं पुलों–क्रास बैरियर, घाटी पुलों का निर्माण	50.00	15.11.2012
		जौलीग्रांट, देहरादून वैकल्पिक सड़क	11.01	15.11.2012
		श्रीनगर (पौड़ी) में चौरस पुल का निर्माण	18.16	15.11.2012
		कोर्ट मचनजी, रोड, देहरादून का निर्माण	15.00	15.11.2012
		शिमला बाइपास सड़क देहरादून का निर्माण	57.81	15.11.2012
		अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण	295.55	15.11.2012
		दून मेडिकल कॉलेज	293.81	15.11.2012
		नर्सिंग कॉलेज	67.14	15.11.2012
		मानेरी भाली हाइड्रे परियोजना चरण-I (उत्तरकाशी) का निर्माण	28.56	15.11.2012
		मानेरी भाली हाइड्रो परियोजना चरण-II (उत्तरकाशी) का निर्माण	94.81	15.11.2012
		राज्य डेटा केन्द्र एवं आईटी भवन का निर्माण	8.95	22.11.2012
		देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में बेघर बच्चों के लिए घर का निर्माण	6.00	22.11.2012
		हज गृह का निर्माण	4.00	15.11.2012
		भारसर-रानीचौरी बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय	20.92	15.11.2012
		हरिद्वार और रूद्रप्रयाग में विश्रमा गृह निर्माण	15.00	22.11.2012
		कामकाजी महिला हॉस्टल	10.00	22.11.2012
		30 गोदामों का निर्माण	18.00	15.11.2012
		देहरादून शहर में परिवहन सुविधाएं	15.00	15.11.2012
		देहरादून शहर में परिवहन सुविधाएं–प्रदूषणकारी वाहनों का प्रतिस्थापन	10.32	15.11.2012

1	2	3	4	5
		फॉरेस्ट फायर लाइन का निर्माण	60.00	15.11.2012
		मानव-पशु संघर्ष का उपशमन	40.50	15.11.2012
		डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण	15.57	15.11.2012
		क्लेक्ट्रेट एवं तहसील भवनों का निर्माण	35.74	15.11.2012
		कारावास भवनों का निर्माण	35.39	15.11.2012
		उत्तरकाशी में अग्निशमन भवनों का निर्माण	9.50	15.11.2012
		योजना भवन का निर्माण	21.04	15.11.2012
		मानव संसाधन विकास सूचकांक का अध्ययन	2.00	22.11.2012
		हरिद्वार में राज्य लोक आयोग के परीक्षा भवन का निर्माण	24.78	22.11.2012
		निदेशालय परिसर (देहरादून) में आउटडोर फील्ड, मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल का निर्माण	3.32	15.11.2012
		व्यापार कर कार्यालय भवन का निर्माण	28.98	22.11.2012
		स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून में बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण तथा मैदान की बाड़ लगाना	12.66	15.11.2012
		स्पोर्टस कॉलेज, रायपुर और स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून में कृत्रिम ट्रेक एवं अन्य कार्य	7.99	15.11.2012
		नहर एवं ट्यूबवैल का निर्माण	210.90	15.11.2012
6.	मणिपुर	अवसंरचना संबंधी 131 परियोजनाएं	386.15	14.09.2012
7.	मेघालय	अवसंरचना संबंधी 15 परियोजनाएं	1416.96	19.10.2012
8.	त्रिपुरा	अवसंरचना संबंधी 21 परियोजनाएं	141.95	26.10.2012

[अनुवाद]

राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति कार्यक्रम का कियान्वयन

1852. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट कार्यक्रम का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा कक्षा VII तक पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर रोकने तथा माध्यमिक स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। इसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु छात्रवृत्तियों का कोटा है। वर्ष 2008-09 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। 28 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य शिक्षा सचिव सम्मेलन में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इस बैठक में उपस्थित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने जैसे पर्याप्त कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि चयन प्रक्रिया में अधिकतम पात्र छात्रों द्वारा भाग लिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। तदनंतर, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है।

विवरण

क्र .सं.	राज्य के नाम	राज्यों को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या	वर्ष 2008-09 में संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	वर्ष 2009-10 में संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	वर्ष 2010-11 में संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	वर्ष 2011-12 में संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42	42	21	6	18
2.	आन्ध्र प्रदेश	7008	6828	6347	6462	6655
3.	अरुणाचल प्रदेश	122	122	86	103	90
4.	असम	2411	15	171	459	364
5.	बिहार	5433	1104	766	2069	2273
6.	चंडीगढ़	85	85	52	85	18
7.	छत्तीसगढ़	2246	210	67	204	103
8.	दादरा और नगर हवेली	22	22	22	22	13
9.	दमण और दीव	16	16	16	16	16
10.	दिल्ली	1576	629	212	334	468
11.	गोवा	144	135	0	113	124
12.	गुजरात	5097	857	857	1854	2636
13.	हरियाणा	2337	1364	102	158	821

1	2	3	4	5	6	7
14.	हिमाचल प्रदेश	832	437	77	99	328
15.	जम्मू और कश्मीर	1091	81	7	62	131
16.	झारखंड	1959	902	493	565	0
17.	कर्नाटक	5534	1632	1347	2444	3170
18.	केरल	3473	3473	3473	3473	3473
19.	लक्षद्वीप	10	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	6446	2700	1003	920	843
21.	महाराष्ट्र	11682	9579	6547	9989	9769
22.	मणिपुर	255	203	109	170	133
23.	मेघालय	231	113	130	154	124
24.	मिजोरम	103	103	103	103	100
25.	नागालैण्ड	180	2	0	55	12
26.	ओडिशा	3314	2151	1906	2452	0
27.	पुदुचेरी	125	125	125	125	125
28.	पंजाब	2210	1911	442	690	876
29.	राजस्थान	5471	1777	306	124	87
30.	सिक्किम	58	57	58	53	58
31.	तमिलनाडु	6695	6069	1119	4386	0
32.	त्रिपुरा	351	136	38	91	52
33.	उत्तर प्रदेश	15143	9206	1520	1725	1351
34.	उत्तराखंड	1048	857	655	678	762
35.	पश्चिम बंगाल	7250	2601	409	1197	2543
	कुल	100000	55544	28586	41440	37536

[हिन्दी]

पेटेंट सरलीकरण निधि

1853. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पेटेंट सरलीकरण केंद्र/प्रकोष्ठ सहित प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित, संस्वीकृत और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पेटेंट सरलीकरण निधि स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे केंद्रों/निधि की स्थापना के परिणामस्वरूप स्वदेशी व्यापार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) महोदय, मंत्रालय द्वारा पेटेंट सरलीकरण निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर), पेटेंट खोज सेवाओं, पेटेंट दर्ज करने आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) में पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ के लिए वित्तपोषण सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पीएफसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य स्तर पर पेटेंट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत आदि सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 24 पेटेंट सूचना केंद्रों (पीआईसी) को भी सहायता प्रदान की जाती है। ये पीआईसी अपने संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालयों में बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ (आईपीसीयू) भी सृजित कर रहे हैं। अब तक राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 84 आईपीसीयू का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश में विभिन्न राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों में 24 पीआईसी को सहायता प्रदान करने के लिए भी पीएफसी के बजट का उपयोग किया जाता है। विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पीएफसी द्वारा आबंटित, संस्वीकृत और उपयोग की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(रु. लाख में)

वर्ष	आबंटन	संस्वीकृत	उपयोग की गई
2010-11	200.00	180.62	175.38
2011-12	250.00	186.49	131.16
2012-13 नवम्बर, 2012 तक	298.00#	197.19	55.33
कुल	748.00	564.30	361.77

#इसमें एससी और एसटी प्रत्येक घटक के लिए 20.00 लाख रुपये का बजट शामिल है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास

1854. श्री मुरारी लाल सिंह :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं पुर्नवास पैकेज हेतु विचार किया है और प्रभावित राज्यों की वित्तीय मांगों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास हेतु एक व्यापक योजना बनाने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) सरकार ने चुनिंदा 60 जनजातीय तथा पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्य योजना को 25.11.2010 को मंजूरी दी जिसमें 2010-11 तथा 2011-12 के लिए प्रति जिला 25 करोड़ रूपए तथा 30 करोड़ रूपए का ब्लॉक अनुदान शामिल है। फिलहाल, इस योजना के दायरे में 82 जिले हैं। एकीकृत कार्य योजना अपने मौजूदा स्वरूप में ही 2012-13 के लिए 30 करोड़ रूपए प्रति जिला के आवंटन के साथ विस्तारित की गई है। 30 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, 9 राज्यों को 5260.00 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं जिसमें से जिलों द्वारा 63.52 प्रतिशत राशि अर्थात् 3341.03 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। प्रारंभ किए गए कुल 93875 कार्यों में से 70.52 प्रतिशत अर्थात् 66196 कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्यों के पास अपनी समर्पण तथा पुनर्वास नीतियां हैं। संघ सरकार ने वामपंथी उग्रवादियों के लिए एक आदर्श समर्पण-सह-पुनर्वास नीति बनाई है जिसमें अन्य के साथ 1.5 लाख रूपए का अनुदान तत्काल लेने, तीन वर्षों तक 2000 रूपए प्रतिमाह का वजीफा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा हथियार समर्पण करने पर प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) एकीकृत कार्य योजना में छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं और इन जिलों ने 750.00 करोड़ रूपए की आवंटित राशि में से 66.29 प्रतिशत अर्थात् 497.20 करोड़ रूपए की राशि खर्च किए जाने की रिपोर्ट दी है। जहां तक वित्तीय उपलब्धियों का संबंध है, शुरू किए गए कुल 17769 कार्यों में से 72.32 प्रतिशत अर्थात् 12850 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं

1855. श्री निलेश नारायण राणे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि सरकार ने, नागरिकों को सामान एवं सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दिगी एवं उनकी शिकायतों के निपटान का अधिकार विधेयक, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया है जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर नागरिक चार्टर प्रकाशित करने की बाध्यता करता है जिसमें वह समय-सीमा दी गई हो, जिसमें विनिर्दिष्ट सामान की आपूर्ति की जाएगी एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी और यह नागरिक चार्टर का अनुपालन न करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था भी करता है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संसद में निम्नलिखित विधेयक प्रस्तुत किए हैं:

(i) न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010

(ii) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;

(iii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011

(iv) विदेशी लोक पदधारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011; तथा

(v) लोक प्रापण विधेयक, 2012।

इस विधान के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों और प्रक्रियाओं का आवश्यक आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। सरकार 'भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं' की अपनी नीति कार्यान्वित करने हेतु पूरी तरह से सचेत और वचनबद्ध है और इसने भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकार के कार्यकरण का सुधार करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियम;

(ii) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) संगठनों के मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता

आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है;

(iv) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(v) नागरिक चार्टर जारी करना।

(vi) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन करना

(vii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी को जनव्यापी बनाना;

(viii) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन (66 न्यायालयों ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है)।

निजी क्षेत्र के और राज्य विश्वविद्यालयों के विरुद्ध शिकायतें

1856. श्री पी.के. बिजू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में संचालित निजी और राज्य विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष स्थापित निजी/राज्य विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा इन विश्वविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) वर्तमान में, भारत में 145 निजी विश्वविद्यालय और 293 राज्य विश्वविद्यालय हैं दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2012 की अवधि के दौरान, 28 निजी विश्वविद्यालय और 12 राज्य विश्वविद्यालय, विभिन्न राज्य विधानमण्डलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए थे। निजी और राज्य विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इन निजी और राज्य विश्वविद्यालयों के खिलाफ शुल्क-वापसी, सुविधाओं की कमी, मूल प्रमाणपत्रों की गैर-वापसी, अंक-तालिकाओं में विसंगतियों, दाखिले में गैर-कानूनी प्रक्रिया, डिग्रियों की अनियमित प्रदानगी आदि से संबंधित शिकायतें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजी जाती हैं ताकि समय-समय पर जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों का समाधान/त्रुटियों का सुधार किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2003 में यू. जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों में स्थापना और रखरखाव के मानक) विनियम भी जारी किए हैं ताकि निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

विदेशी विमान सेवाओं द्वारा भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1857. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय विमानन क्षेत्रक में विदेशी विमान सेवा कंपनियों को 49 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के प्रस्ताव में भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति आदि जैसी कोई पूर्व-शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सरकार ने विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित विमान सेवाओं का प्रचालन करने वाली भारतीय कंपनियों में उनके प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने

की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार के निवेश में निम्नलिखित शर्तें होंगी:

(i) यह सरकार द्वारा अनुमोदित होगा।

(ii) 49 प्रतिशत सीमा में एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. निवेश शामिल होगा।

(iii) इस प्रकार किए जाने वाले निवेशों के लिए सेबी के संबंधित नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा।

(iv) अनुसूचित प्रचालक परमिट केवल उसी कंपनी को प्रदान किया जा सकता है:

(क) जो रजिस्टर्ड हो तथा जिसके कारोबार का प्रमुख स्थान भारत के भीतर ही हो।

(ख) अध्यक्ष तथा कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हो तथा

(ग) जिस पर अधिकांश स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों का हो।

अध्यापकों के रिक्त पद

1858. श्री नवीन जिन्दल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के राज्य-वार कुल रिक्त पदों और इन पर की गई नियुक्तियों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और इस संबंध में कई महीनों से राशि बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अध्यापकों, जिनके वेतन की राशि बकाया रह गई है, का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में बकाया कुल वेतन राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एस.एस.ए. के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन-प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तक 19.82 लाख शिक्षक पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से राज्यों द्वारा 12.48 लाख शिक्षक पदों को भर लिए जाने की सूचना दी गई है। संस्वीकृत और भरे गए शिक्षक पदों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (च) शिक्षकों की भर्ती और वेतन का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सृजित शिक्षक पदों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार वेतन की लागत को 65:35 के अनुपात में बांटते हैं। केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 25,555 करोड़ रूपये के अपने वार्षिक बजट में से 20,548.43 करोड़ रूपये अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए हैं। राज्य सरकारें, वेतन का भुगतान करती हैं और उसका रिकार्ड रखती हैं, न कि भारत सरकार।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012-13 तक संस्वीकृत शिक्षक 2012-13	वर्ष 2012-13 (30.09.2012) तक भर्ती शिक्षक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	39189	38319
2.	अरूणाचल प्रदेश	7262	5226
3.	असम	48808	38364
4.	बिहार	403413	191983
5.	छत्तीसगढ़	67507	54985
6.	गोवा	169	149
7.	गुजरात	58688	31336

1	2	3	4
8.	हरियाणा	13435	6345
9.	हिमाचल प्रदेश	5856	3553
10.	जम्मू और कश्मीर	43471	39739
11.	झारखंड	120396	84672
12.	कर्नाटक	29055	24278
13.	केरल	2925	0
14.	मध्य प्रदेश	173855	98287
15.	महाराष्ट्र	42091	8522
16.	मणिपुर	2871	1544
17.	मेघालय	13262	14020
18.	मिज़ोरम	2485	1303
19.	नागालैंड	3147	590
20.	ओडिशा	89901	88442
21.	पंजाब	14090	7432
22.	राजस्थान	114132	94201
23.	सिक्किम	724	223
24.	तमिलनाडु	33214	22497
25.	त्रिपुरा	6980	5694
25.	उत्तर प्रदेश	423553	258924
27.	उत्तराखंड	14316	5998
28.	पश्चिम बंगाल	198253	115797
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	210	162
30.	चंडीगढ़	1390	785
31.	दादरा और नगर हवेली	937	526
32.	दमण और दीव	119	95
33.	दिल्ली	7104	4342
34.	लक्षद्वीप	38	16
35.	पुदुचेरी	48	36
	कुल	1982894	1248385

[हिन्दी]

मान्यता प्राप्त विद्यालय

1859. श्री यशवंत लागुरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में के.मा.शि.बो. और आई.सी.एस. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या कितनी है और उन विद्यालयों के नाम क्या हैं जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा का कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विद्यालयों ने दाखिला के लिए उपर्युक्त आरक्षण कोटा का कार्यान्वयन नहीं किया है; और

(ग) इन विद्यालयों के विरूद्ध सरकार द्वारा किन नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) स्कूलों को मान्यता संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा लेने वाला निकाय है और स्कूलों को संबंधन की मंजूरी देता है। तथापि, सीबीएसई के संबंधन उप-नियमों में यह निर्धारित है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षण उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर लागू शिक्षा अधिनियम/नियमों द्वारा अभिशासित किया जाएगा जहां स्कूल

स्थित होता है। भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) जो कि एक निजी बोर्ड है, ने भी सूचित किया है कि इसके साथ संबंधन किए गए स्कूल, अनुसूचित जनजातियों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के छात्रों को दाखिला देते हैं। दोषी स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी कंपनी के साथ एयर इंडिया का समझौता ज्ञापन

1860. श्री रूद्रमाधव राय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2008 से एयर इंडिया द्वारा अधिकृत साझेदारों के नामों सहित उनके साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या कितनी है;

(ख) समझौते की समझौता-ज्ञापन-वार, मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में एयर इंडिया को क्या लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा

1861. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और और स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के नक्सल प्रभावित जिलों में इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि नक्सल प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ाई छोड़ देने की दर अत्यधिक है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पढ़ाई छोड़ देने की दर का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के लिए बजट निर्धारित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लिए क्या विशेष प्रोत्साहन है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ शशी थरूर): (क) और (ख) वामपंथ अतिवाद प्रभावित क्षेत्र जनजातीय तथा वन्य क्षेत्रों के साथ ओवरलैप करते हैं जहां दूरी तथा क्षेत्र मुद्दे होते हैं। स्कूलों को क्षति पहुंचाने/बंद करने की घटनाएं सूचित की गई हैं। तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और आन्ध्र प्रदेश ने भी स्थायी ढाचें के निर्माण में कठिनाइयों की सूचना दी है।

(ग) वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों में 6-14 वर्ष आयु वर्ग में बच्चों की पहुंच और उन्हें बनाए रखने के मामले को हल करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन जिलों में 10,551 प्राथमिक स्कूलों, 13,715 उच्च प्राथमिक स्कूलों, 1,04,959 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, 51,600 बालिका शौचालयों तथा 8,121 शौचालयों को संस्वीकृत किया गया है।

वर्ष 2012-13 में 6,59,668 स्कूल-बाह्य बच्चों को नियमित स्कूलों की मुख्यधारा में लाने के लिए वाम चरमपंथ प्रभावित जिलों में विशेष प्रशिक्षण की मंजूरी दी गयी है और इन जिलों में 889 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालनरत हैं जहां कुल प्रवेश का 36.61 प्रतिशत अनुसूचित जाति की बालिकाएं हैं।

इन कार्रवाइयों से अन्य बातों के साथ-साथ वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों में नामांकन में 2005-06 में 2,16,98,119 से 2012 में 2,53,85,043 की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा सांख्यिकी के अनुसार, वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों

वाले राज्यों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दरों में सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत से ही कई क्षेत्रों में कमी का रूख देखा जा रहा है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। वामपंथ अतिवाद प्रभावित राज्यों में वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को दर्शाने वाला तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) वर्ष 2011-12 में 10,02,901 लाख रूपए, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत कुल निधियों का 17 प्रतिशत, वामपंथ अतिवाद प्रभावित 82 जिलों को प्रदान किए गए जबकि वर्ष 2012-13 के लिए इन जिलों को 11,50,503.60 लाख रूपए, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत कुल निधियों का 16 प्रतिशत, प्रदान किए गए। इन दोनों वर्षों के दौरान मूल घटकों में किए गए प्रावधान के सारांश के साथ-साथ संबंधित घटक के लिए राष्ट्रीय अनुमोदनों का तुलनात्मक प्रतिशत नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

मद	2011-12		2012-13	
	संख्या	कुल का %	संख्या	कुल का %
नए प्राथमिक स्कूल खोलना (ई.जी.एस. का प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नयन सहित)	386	10%	412	40%
नये उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना	354	21%	381	24%
कुल शिक्षक	38682	26%	27829	23%
प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण	90	31%	379	27%
उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण	323	44%	383	18%
अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण	43364	19%	46938	27%
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	659	18%	887	23%
एस.एस.ए. (वित्तीय, रूपए लाख में)	970645	17%	1093660.26	16%
के.जी.बी.वी. (वित्तीय, रूपए लाख में)	रु. 24071	11%	51102.17	28%
एन.पी.जी.ई.एल. (वित्तीय, रूपए लाख में)	रु. 8186	21%	5741.17	24%
कुल निधियां (वित्तीय, रूपए लाख में)	1002901	17%	1150503.60	16%

विवरण

नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर

राज्य का नाम	2010-11		2009-10		2008-09	
	प्राथमिक	प्रारंभिक	प्राथमिक	प्रारंभिक	प्राथमिक	प्रारंभिक
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	28.4	49.1	20.52	50.46	27.84	59.33

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	31.0	48.3	34.12	40.67	26.52	37.54
झारखंड	28.4	45.1	27.05	61.87	20.70	60.14
ओडिशा	7.0	55.0	26.45	54.30	33.12	56.92
आन्ध्र प्रदेश	17.4	32.9	15.80	41.29	15.55	40.65

*आंकड़े मूल राज्य के साथ संयोजित. ** स्रोत-स्कूल शिक्षा सांख्यिकी

डाकघरों में विकलांगों के लिए सुविधाएं

1862. **श्री पी. कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत सारे डाकघर ऐसे हैं जहां विकलांग व्यक्ति पहुंच नहीं सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की डाक सुविधाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए और सुगम बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ कृपारानी किल्ली): (क) जी, नहीं। कुछ डाकघरों को छोड़कर, देश भर के अधिकांश डाकघरों में विक्लांग व्यक्ति पहुंच सकते हैं।

(ख) विभागीय/किराए के भवनों में कार्यरत 2924 डाकघर ऐसे हैं जहां विक्लांग व्यक्ति नहीं पहुंच सकते।

(ग) जी, हां।

(घ) जहां कहीं भी डाकघरों में लिफ्ट के द्वारा पहुंचा जा सकता है, उन डाकघरों की लिफ्टों में ब्रेल पैनल उपलब्ध कराने तथा व्हील चेयर के प्रयोक्ताओं के लिए डाकघरों में कम ऊँचाई के काउंटरों की व्यवस्था करने के अलावा, चरणबद्ध तरीके से रैंप का निर्माण करने हेतु डाक सर्किलों को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

न्यूट्रीनो अब्जरवेटरी प्रोजेक्ट

1863. **श्री अब्दुल रहमान :**
प्रो. सौगत राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित इंडिया बेस्ड न्यूट्रीनो अब्जरवेटरी (आई.एन.ओ.) प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का आई.एन.ओ. के निर्माण के लिए 50,000 टन विशेष इस्पात की आपूर्ति करने प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारत आधारित न्यूट्रीनो वेधशाला (आई.एन.ओ.) परियोजना को तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में बोडी पश्चिमी पहाड़ियों में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य न्यूट्रीनो के गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्य करना है, जोकि भू-मंडल में पाए जाने वाले दूसरे अधिकतम प्रचुर कण हैं। न्यूट्रीनो अनावेशी कण हैं और वे कमजोर पारस्परिक क्रिया वाले ऐसे कण हैं जिनका पता लगाया जाना बहुत ही कठिन है। अत: उनके लिए एक विशाल संसूचक की आवश्यकता है। भारत आधारित न्यूट्रीनो वेधशाला के संसूचक का निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में ऐसी प्लेटों की आवश्यकता होगी और उनमें इलेक्ट्रानिकी का बैक-अप होगा, इन संसुचकों से इनमें से गुजरने वाले न्युट्रीनों का पता लगाने

में मदद मिलने की आशा है। भारत आधारित न्यूट्रीनों वेधशाला की सहायता से भू-मंडल के विकास को समझने में अंततः मदद मिलेगी। भारत आधारित न्यूट्रीनो वेधशाला परियोजना के लिए विकसित किए गए संसूचकों का उपयोग चिकित्सीय प्रतिबिम्बन जैसे सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाएगा।

(ख) जी, हाँ। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) से भारत आधारित न्यूट्रीनो वेधशाला के संसूचक का निर्माण करने के लिए विशेष इस्पात की आपूर्ति हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अथवा अन्य किसी एजेंसी को इस्पात की आपूर्ति करने के लिए कोई क्रयादेश नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

मिड-डे मील स्कीम में भेद-भाव

1864. श्री अशोक कुमार रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाति घटक के कारण कुछ स्थानों पर छात्रों द्वारा मध्याह्न भोजन न लिए जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011 और 2012 के दौरान अब तक पता चली ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) दिनांक 1.1.2011 से अब तक इस विभाग को कुल दो शिकायतें, एक मध्य प्रदेश से तथा एक उत्तर प्रदेश से, प्राप्त हुई हैं। दोनों राज्यों को इनकी जांच करने तथा इन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि शिकायत को निराधार पाया गया था, चूंकि अनुसूचित जाति समुदाय से संबद्ध महिला रसोइयाओं द्वारा तैयार किए गए भोजन का स्कूल में सभी बच्चों द्वारा उपभोग किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि मध्याह्न भोजन न पकाने तथा जातिगत भेदभाव के बारे में संबद्ध स्कूल, लखीमपुर के प्राचार्य की शिकायत निराधार पाई गई। चूंकि वह शिकायत उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के कारण की गई थी, प्राचार्य द्वारा अपना कार्य सही प्रकार से न करने के कारण उनका वेतन रोक दिया गया था।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्यान्न को तैयार करने तथा उसका वितरण करने के कार्य के निरीक्षण हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ समितियों का गठन किया है। इसी प्रकार, रसोइया-सह-सहायकों की भर्ती में इन समुदायों को वरीयता दी जाती है।

मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि जिला, उप-खंड, तसील/तालुक, ब्लॉक तथा अन्य समुचित स्तरों पर विभिन्न विभागों से संबद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तिमाही में औसतन 25 प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस कमी का पता लगाने में संयुक्त समीक्षा आयोग, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनीसेफ तथा उच्चतम न्यायालय आयोग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, भी सहायता करता है। इसी प्रकार, आईआईटी चेन्नई और विश्व भारती जैसी 41 स्वतंत्र मानिटरिंग संस्थाएं भी इस पहलू की मानिटरिंग करती हैं।

बीपीएल के लिए आय की सीमा

1865. श्री अंजन कुमार एम. यादव :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रति माह 5000/- रूपये कमाने वाले व्यक्तियों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बढ़ती मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए बीपीएल श्रेणी में शामिल करने हेतु आय की सीमा को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। योजना प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय

संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रू. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रू. के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के रूप में कियागया है जो पांच सदस्यों की पारिवारिक इकाई के लिए, 2009-10 के मूल्यों पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,365 रू. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 4,300 रू. के मासिक उपभोग व्यय के बराबर है। इन गरीबी रेखाओं की मुद्रास्फीति सूचकांकों का उपयोग कर बाद के वर्षों के लिए अद्यतन किया जाता है।

योजना आयोग ने ''गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा'' के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। गरीबी रेखा की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने तथा मौजूदा जमीनी हकीकतों के अनुरूप, गरीबी रेखा की परिगणना में विभिन्न मानदंडों को समुचिम महत्व देना सुनिश्चित करने हेतु, डॉ. रंगराजन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को व्यापक रूप में विचारार्थ विषय दिए गए हैं जिनमें सीएसओ द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्यवार शुरू किए गए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हुए, उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने हेतु कार्यप्रणाली का सुझाव देना शामिल है।

[अनुवाद]

नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क

1866. **श्रीमती अन्नू टन्डन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एन.वी.ई.क्यू.एफ. प्रमाणन प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और उद्योग को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 03.09.2012 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा (एन.वी.क्यू.एफ.) अधिसूचित किया है। एन.वी.ई.क्यू.एफ. के मुख्य सिद्धान्त; व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच तथा रोजगार बाजार में बहुस्तरीय प्रवेश और निर्गमन; व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति; व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच अन्तरण तथा उद्योग/नियोक्ताओं के साथ भागीदारी।

(ग) और (घ) एन.वी.ई.क्यू.एफ. में व्यावसायिक शिक्षा के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय पेशा मानक निर्धारित करने और अर्जित कौशल दक्षताओं के मूल्यांकन में क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एस.एस.सी.) के माध्यम से उद्योग को शामिल करने की व्यवस्था है। क्षेत्रीय कौशल परिषदों की मूल्यांकन रिपोर्टों में प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली एजेंसियों का भी उल्लेख होगा।

[हिन्दी]

मॉडल डिग्री कॉलेज

1867. **श्री देवजी एम. पटेल :**
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश में पता लगाए गए शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले में मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने हेतु केंद्रीय सहायता की नई योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कॉलेजों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है और इनके लिए कितनी धनराशि का उपयोग किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े अभिचिह्नित 374 जिलों में प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने की एक केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2010 में आरंभ की गई थी। शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच पूंजीगत व्यय की सहभागिता 1:2 के अनुपात में है, जो प्रत्येक

कॉलेज की स्थापना के लिए 2.67 करोड़ रू. के केंद्रीय भाग तक सीमित है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 1:1 का है, जो प्रत्येक कॉलेज के लिए 4.00 करोड़ रू. के केंद्रीय भाग तक सीमित है। राज्य सरकारों द्वारा भूमि निःशुल्क प्रदान की जाती है। पूंजीगत लागत की शेष राशि, और इन नए कॉलेजों को चलाने की आवर्ती लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी है। प्रत्येक कॉलेज के लिए कुल पूंजीगत लागत 4 से 8 करोड़ रू. के बीच में है। इन शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 01 जनवरी, 2008 को या उसके बाद स्थापित कए गए कॉलेज भी इस योजना के अंतर्गत कवर कए जाने के लिए पात्र हैं। निधियां जारी होने से पहले प्रत्येक राज्य सरकार के साथ एक स्पष्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 153 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 86 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और 33 प्रस्तावों को अपात्रता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है। अब तक, 50 माडल डिग्री कार्यात्मक हो गए हैं और यूजीसी ने 52.06 करोड़ रू. जारी किए हैं।

विवरण

उच्चतर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए 374 अभिचिह्नित जिलों की सूची।

1. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**

अंडमान

निकोबार

2. **आंध्र प्रदेश**

अदिलाबाद

अनन्तपुर

पूर्वी गोदावरी

कुरनूल

महबूब नगर

मेडक

निजामाबाद

प्रकासम

श्रीकाकुलम

विजनरगम

पश्चिमी गोदावरी

3. **अरूणाचल प्रदेश**

चांगलांग

दीवंगवेली

पूर्वी कामेंग

लोहित

लोअर सुबनसिरी

तवांग

तीराप

अपर सियांग

अपर सुबनसिरी

पश्चिम कामेंग

पश्चिम सियांग

4. **असम**

बोंगाईगांव

कछार

दारांग

धुब्री

गोलपाड़ा

हैलाकांडी

कार्बी आंगलांग

करीमगंज

नौगांव

सोनितपुर

तिनसुकिया

5. बिहार

अरेरिया

औरंगाबाद

बंका

बेगूसराय

दरभंगा

गोपालगंज

जमुई

कैमूर (भभुआ)

कटिहार

खगड़िया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

नवादा

पश्चिमी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण

पूर्णिया

सहरसा

समस्तीपुर

शिवहर

सीतामढ़ी

सीवान

सुपौल

वैशाली

6. छत्तीसगढ़

बस्तर

बिलासपुर

दांतेवाड़ा

धामतरी

दुर्ग

जांजगीर-चम्पा

जसपुर

कांदोर

कवर्धा

कोरिया

महासमुंद

रायगढ़

रायपुर

राजनंदगांव

सरगुजा

7. **दादरा और नगर हवेली**

दादरा और नगर हवेली

8. **दमन और दीव**

दमन

दीव

9. **गुजरात**

अमरेली

बानासकंठा

भरूच

भावनगर

जूनागढ़

कच्छ

खेड़ा

मेहसाना

नर्मदा

पंचमहल

पाटन

पोरबंदर

राजकोट

साबरकांठा

सूरत

सुरेंद्रनगर

दाडांग

वलसाड

10. **हरियाणा**

फतेहबाद

गुड़गांव

जींद

कैथल

करनाल

पानीपत

सिरसा

11. **हिमाचल प्रदेश**

चम्बा

थक्नौर (पू.)

लाहौल तथा स्पीति

सिरमौर

12. **जम्मू और कश्मीर**

अनन्तनाग

बडगाम

बारामूला

डोडा

कारगिल

कथुआ

कुपवाड़ा

लेह (लद्दाख)

पुंछ

राजौरी

ऊधमपुर

13. **झारखंड**

छतरा

देवघर

दुमका

गरहवा

गिरडीह

गोड्डा

गुमला

कोडरमा

पाकुर

पलामू

पश्चिमी सिंहभूम

साहिबगंज

14. **कर्नाटक**

बगलकोट

बंगलौर ग्रामीण

बेलगाम

बेल्लारी

बीजापुर

चामराजनगर

चिकमंगलूर

चित्रदुर्ग

दक्षिण कन्नड़

गडग

गुलबर्गा

हसन

हवेरी

कोडागु

कोलार

कोप्पल

मंध्या

रायचूर

तुमकुर

उदुपी (उडुपी)

उत्तर कन्नड

15. **केरल**

कासरगोड

मालापुरम

पलाक्कड

वेनाड

16. **लक्षद्वीप**

लक्षद्वीप

17. **मध्य प्रदेश**

बालाघाट

बरवानी

बेतुल

भिंड

छतरपुर

छिंदवाडा

दमोह

दतिया

देवास

धार

डिंडोरी

ईस्ट नीमर

गुना

हरदा

झाबुआ

कटनी

मांडला

मंदसौर

मोरेना

नरसिंहपुर

नीमच

पन्ना

रायसेन

राजगढ़

रतलाम

सागर

सतना

सिहोर

सिओनी

शहडोल

शाजापुर

शिओपुर

शिवपुरी

सिंधी

टीकमगढ़

उज्जैन

उमरिया

विदिशा

वेस्ट नीमर

18. महाराष्ट्र

बुल्दाना

गडचिरोली

हिंगोली

जालना

रायगढ़

रत्नागिरी

सिद्धदुर्ग

19. मेघालय

ईस्ट गारो हिल्स

जैनतिया हिल्स

रीभोई साउथ गारो हिल्स

वेस्ट खासी हिल्स

20. मिजोरम

चम्फाई

कोलासिब

लॉंगतलाई

लंगलई

मामित

सेहा

सरचिप

21. नागालैंड

मोन

22. ओडिशा

अंगुल

बोलंगीर

बारगढ़

बौद्ध

देवगढ़

धेनकनाल

गजपति

गंजम

कालाहांडी

कंधामाल

क्योंझर

कोरापुट

मल्कानगिरी

नवरंगपुर

नयागढ़

नूपाड़ा

रायगाड़ा

सोनपुर

23. पुदुचेरी

यनम

24. पंजाब

अमृतसर

भटिंडा

फरीदकोट

फतेहगढ़ साहिब

फिरोजपुर

गुरूदासपुर

कपूरथला

मांसा

मोगा

मुक्तसर

नवाशहर

पटियाला

संगरूर

25. राजस्थान

अजमेर

अलवर

बांसवाड़ा

बारन

बाड़मेर

भरतपुर

भीलवाड़ा

बीकानेर

बुन्दी

चित्तौड़गढ़

चुरू

दोसा

धौलपुर

डुंगरपुर

गंगानगर

हनुमानगढ़

जैसलमेर

जालौर

झालावाड़

झुनझुनु

जोधपुर

करौली

नागौर

पाली

राजसमन्द

सवाई माधोपुर

सीकर

सिरोही

टॉक

उदयपुर

26. **सिक्किम**

पूर्व

उत्तर

दक्षिण

पश्चिम

27. **तमिलनाडु**

अरियालुर

कोयम्बटूर

कुड्डालूर

धर्मपुरी

डिंडीगुल

इरोड

कांचीपुरम

कन्याकुमारी

करूर

मदुरै

नागापट्टीनम

पैरमबल्लूर

पुडुकोट्टई

रामानाथपुरम

सलेम

शिवगंगा

तंजावुर

दॉ नीलगिरीस

थणी

थिरूवल्लूर

थूवरूर

थूथुकुकडी

तिरूनेलवली

तिरूवन्नामलाई

व्लोर

वेलुपुरम

विरूद्धनगर

28. **त्रिपुरा**

धलाइ

उत्तर त्रिपुरा

दक्षिण त्रिपुरा

पश्चिम त्रिपुरा

29. **उत्तर प्रदेश**

बहराइंच

बलरामपुर

बंदा

बराबंकी

बरेली

बस्ती

बिजनौर

बदायूं

बुलन्दशहर

चित्रकूट

एटा

फरूखाबाद

फतेहपुर

गोंडा

हमीरपुर

हरदोई

हाथरस

ज्योतिबा फूले नगर

कन्नौज

कानपुर देहात

कौशाम्बी

खीरी

कुशीनगर

ललितपुर

महाराजगंज

महोवा

मथुरा

मुरादाबाद

मुजफ्फरनगर

पीलीभीत

रायबरेली

रामपुर

सहारनपुर

संत कबीर नगर

शाहजहांपुर

श्रावस्ती

सिद्धार्थ नगर

सीतापुर

सोनभद्र

सुल्तानपुर

उन्नाव

30. उत्तरांचल

बागेश्वर

चम्पावत

31. पश्चिम बंगाल

बांकुरा

बर्धमान

बीरभूम

दक्षिण दिनाजपुर

दार्जिलिंग

हावड़ा

हुगली

जलपाइगुड़ी

कुच बिहार

मालदा

मिदनापुर

मुर्शीदाबाद

नाडिया

उत्तरी 24 परगना

पुरूलिया

दक्षिणी 24 परगना

उत्तर दिनाजपुर

कुल जिला 374

[अनुवाद]

वार्षिक विकास लक्ष्य को कम करना

1868. **श्रीमती श्रुति चौधरी :**
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग वार्षिक विकास लक्ष्य को घटाकर 8.2 प्रतिशत करने का समर्थन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतिपय राष्ट्रों से पीछे है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास

परिषद् (एन.डी.सी.) द्वारा अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में अनुमान किया गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत की औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रख सकती है। तथापि, एन.डी.सी. द्वारा दृष्टिकोण-पत्र को मंजूर किए जाने बाद, वैश्विक अर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और घरेलू अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के कारण ही 2011-12 में विकास दर 6.5 प्रतिशत रही और 2011-12 की आखिरी तिमाही में तो यह दर केवल 5.3 प्रतिशत रही। वैश्विक आर्थिक परिस्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है। अत: बारहवीं योजनावधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत विकास दर के 9 प्रतिशत के पूर्व के लक्ष्य को बनाए रखना कठिन होगा। इसलिए, 15 सितम्बर, 2012 को आयोजित पूर्ण योजना आयोग की बैठक में, 12वीं योजना के विकास लक्ष्य को संशोधित कर 8.2 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है जिसे मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है ताकि राष्ट्रीय विकास परिषद् उस पर विचार कर सके।

(ग) से (च) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अक्टूबर, 2012 में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक डेटाबेस के अनुसार, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय डॉलर में क्रय शक्ति समानता (पी.पी.पी.) आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था अमरीका, चीन और जापान के बाद चौथे स्थान पर है। वर्ष 2011 के लिए, पी.पी.पी. आधार पर 15,075.68 बिलियन अमरीकी डॉलर की जी. डी.पी. के साथ अमरीका अब भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसके बाद चीन (11,299.79 बिलियन अमरीकी डॉलर), जापान (4,444. 14 बिलियन अमरीकी डॉलर) तथा भारत (4,420.56 बिलियन अमरीकी डॉलर) का स्थान है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक डेटाबेस में क्रयशक्ति समानता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का उल्लेख भी है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 के लिए, पी.पी.पी. आधार पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का उल्लेख भी है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 के लिए, पी.पी.पी. आधार पर अमरीका के लिए प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. 48,327.86 अमरीकी डॉलर, जापान के लिए 34,748.15 अमरीकी डॉलर तथा चीन के लिए 8,386.68 करोड़ डॉलर था। भारत के लिए यह 3,662.69 अमरीकी डॉलर रहने का अनुमान है। भारत अब भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता होने का कारण यह है कि वहां विकास का स्तर तथा प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक नीतियां, राजनीतिक स्थिरता, कौशलों तथा प्रौद्योगिकीयों, जनसंख्या का स्तर जैसे अन्य कारक भिन्न-भिन्न हैं।

बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय चर्चा

1869. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत द्वारा बंगलादेश के साथ की गई द्विपक्षीय चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बैठकों के दौरान चर्चा हेतु उभर कर आए मुख्य मुद्दे कौन से थे;

(ग) क्या सरकार की बंगलादेश के साथ विभिन्न लंबित मुद्दों पर और अधिक दौरों में चर्चा करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं जिनमें उच्चतम पर हुई चर्चाएं भी शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2010 में भारत की राजकीय यात्रा की और तदुपरांत जनवरी, 2012 में उन्होंने त्रिपुरा की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2011 में बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की।

हाल ही में की गई अन्य मंत्री स्तरीय यात्राओं में जुलाई, 2011 में विदेश मंत्री द्वारा जुलाई, 2011 में गृह मंत्री द्वारा, मई, 2012 में वित्त मंत्री, मई, 2012 में विधि एवं न्याय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा, ग्रामीण विकास, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्री द्वारा अगस्त, 2012 में और नवंबर, 2012 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की गई बांग्लादेश यात्राएं शामिल हैं। बांग्लादेश से भारत की मंत्री स्तरीय यात्राओं में विदेश मंत्री द्वारा मई, 2012 में, वित्त मंत्री द्वारा जुलाई, 2012 में, स्थानीय सरकार, ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा वर्ष 2012 में, सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री द्वारा सितंबर, 2012 में और कृषि मंत्री द्वारा नवंबर, 2012 में की गई भारत यात्राएं शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने नियमित रूप से आधिकारिक स्तर की बैठकें भी की हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ विदेश कार्यालय परामर्श, गृह सचिव स्तरीय वार्ताएं, कारोबार, विद्युत, सुरक्षा अंतर्देशीय जलमार्ग पर संयुक्त कार्य समूह की बैठकें शामिल हैं।

भवन योजना का उल्लंघन

1870. **श्री समीर भुजबल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन विभिन्न संस्थाओं/सोसायटियों/ट्रस्टों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने डी.डी.ए./एम.सी.डी./एल.एंडडी.ओ. द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन किया है;

(ख) उन भवनों की सूची क्या है जो भूकंप जोन विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है;

(ग) लोक संस्थानों/ट्रस्टों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने परिसरों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए किराये पर दिया है; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा किन नीतियों पर विचार किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि जनवरी, 2011 से स्वीकृत भवन नक्शों के उल्लंघन के लिए सोसाइटियो/संस्थानों/न्यासों को 29 सीलिंग एवं डिमोलिशन आदेश तथा 143 कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 31(1) और 31 क के अंतर्गत कार्रवाई की गई। साउथ दिल्ली, नार्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली नगर निगमों के अनुसार, 39 सोसाइटियों/संस्थाओं/न्यासों ने स्वीकृत भवन नक्शों का उल्लंघन किया है।

(ख) डी.डी.ए. और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि भवन नक्शे की स्वीकृति देते समय तथा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करते समय भवन स्वामी, वास्तुकार और संरचना इंजीनियर को संरचनात्मक सुरक्षा तथा भवन उप-नियमों एवं सरकारी अधिसूचनाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने संबंधी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि नीति के अनुसार किसी संस्थान द्वारा निर्मित क्षेत्र 25% बैंक, वित्तीय संस्थान, इसी प्रकार की गतिविधि चलाने वाले संगठन तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आधारित संगठनों को उप-किरायेदारी पर दिया जा सकता है बशर्ते कि इसके लिए डी.डी.ए. से पूर्व अनुमति ली जाए। गत एक वर्ष के दौरान अब तक 6 सोसाइटियों को ऐसी अनुमति दी गई हैं।

(घ) जब कभी ऐसा उल्लंघन नोटिस में आता है, तो आबंटन/लीज डीड की शर्तों और निबंधनों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विमानपत्तनों पर ठेका मजदूर

1871. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न विमानपत्तनों द्वारा ठेकागत मजदूर काम पर लगाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने ठेकागत मजदूरों की सेवाओं के संबंध में कोई निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्राधिकरणों द्वारा ऐसे निदेशों का अनुपालन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने हवाईअड्डों पर सीधे श्रमिकों का नियोजन नहीं करता है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करता है। संयुक्त उद्यम हवाईअड्डों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्यारहवां लोक आयुक्त सम्मेलन

1872. **श्री उदय सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में ग्यारहवां लोक आयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोक आयुक्त के पद को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का लोक आयुक्तों को किस हद तक अधिक शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां।

दिल्ली लोकायुक्त ने दिनांक 02 नवंबर, 2012 से 04 नवंबर, 2012 तक दिल्ली में 11वां अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन, 2012 आयोजित किया।

(ख) इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार उपर्युक्त सम्मेलन में चर्चा के बिंदु, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित थे:

(i) भ्रष्टाचार के निवारण के लिए संस्थाओं को मजबूत बनाना, शासन तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों की भूमिका में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता लाना।

(ii) लोकायुक्त की भूमिका।

(iii) सतर्कता एवं जांच एजेंसियों की भूमिका।

(iv) आर.टी.आई. कार्यतंत्र एवं भण्डाफोड़कर्ताओं की भूमिका।

(v) न्यायपालिका एवं विधिक बंधुत्व की भूमिका।

(vi) लोकायुक्त की संस्था, अनुशासनिक तथा सतर्कता एजेंसियों के लिए सार्वजनिक राय के निर्माण में मीडिया की भूमिका एवं महत्ता।

(vii) लोक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं नियंत्रण।

(viii) सांविधिक निगम के प्रमुख सहित लोक अधिकारियों तथा लोक सेवकों पर लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार को युक्तियुक्त बनाना।

(ix) भ्रष्टाचार पर नए परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल की संख्या तथा सभी राज्यों में लोकायुक्तों की एकरूप संस्था स्थापित करने के लिए सरकार ने दिनांक 22.12.2011 को लोक सभा में "लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011" पुरःस्थापित किया है। लोक सभा द्वारा दिनांक 27.12.2011 को "लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011" पारित कर दिया गया है तथा यह अभी राज्य सभा में लंबित है।

[हिन्दी]

आरटीआई अधिनियम का क्षेत्राधिकार

1873. डॉ. संजय सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में कार्यरत निजी बिजली वितरण कंपनियां आरटीआई अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे जन उपयोगी संस्थानों/संगठनों को आरटीआई अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम लोक प्राधिकरण पर लागू हैं। एक लोक प्राधिकरण का अर्थ है कोई प्राधिकरण, या निकाय या स्वःशासित संस्थान जो (क) संविधान द्वारा या इसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा (ग) राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अथवा आदेश द्वारा स्थापित या गठित हो और इसमें शामिल हैं–(प) स्वामित्व वाले, नियंत्राणाधीन या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय (पप) समुचित सरकार द्वारा दी गई निधि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप में वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार, किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी, जिसकी पहुंच उस समय पर लागू किसी अन्य कानून के अधीन लोक प्राधिकरण को हो सकती है, पहले से ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्षेत्राधिकार में आती है।

[अनुवाद]

शिक्षा पर खर्च

1874. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी के लिए शिक्षा के अनुपात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमों/प्रस्तावों का ब्यौरा है;

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या वर्ष 2011-12 के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों का समुचित उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के समग्र नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। बारहवीं योजना, ग्यारहवीं योजना के दौरान जीनत संवेग के आधार पर आगे बढ़ेगी और यह "तीन ई एस"- विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता पर फोकस देना जारी रखेगी।

(ख) से (घ) वर्ष 2011-12 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए कुल योजना आबंटन 52060.00 करोड़ रुपये है (उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 13103.00 करोड़ रु. और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 38957.00 करोड़ रु.) राज्य सरकारों/संस्थाओं को अनुदान, प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक योजना के अंतर्गत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की गई विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/गैर सरकारी संगठन योजनाओं के तहत राज्यवार जारी निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्व शिक्षा अभियान	महिला समाख्या	अध्यापक शिक्षा	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास का नियुक्ति	पहुंच तथा साम्यता	माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन	प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसी को सहायता	आई.सी.टी. के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	183551-72	736.14	749.96	-	6454.92	-	-	-	-
अरूणाचल प्रदेश	23880.10	-	263.03	-	2260.53	-	-	-	-
असम	106921.15	42752	2979.03	-	-	-	-	-	-
बिहार	185108.20	599.45	-	-	37.53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	69870.22	73.63	589.95	–	2867.51	–	945.03	–	–
गोवा	1079.14	–	123.09	–	–	–	22.29	–	–
गुजरात	88027.79	368.25	3796.51	–	1440.13	–	1912.31	–	80.13
हरियाणा	40461.41	–	1262.68	–	511.12	–	–	–	15.00
हिमाचल प्रदेश	14192.78		401.12	–	71.62	–	460.02	–	10.00
जम्मू और कश्मीर	30070.50	–	251.52	–	887.24	–	275.55	–	–
झारखण्ड	57903.46	519.68	–	–	46.41	–	806.76	–	10.00
कर्नाटक	62788.35	762.05	2112.14	–	–	–	2358.87	–	–
केरल	17021.85	317.11	1334.61	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	190427.12	–	1464.36	–	2817.61	–	1655.31	–	17.00
महाराष्ट्र	117962.58	–	1988.61	–	–	–	–	–	3486.90
मणिपुर	3940.55	–	375.34	–	474.84	–	–	–	5.00
मेघालय	14410.60	–	625.71	–	–	–	194.34	–	–
मिजोरम	10814.05	–	929.81	1774.00	–	–	–	–	–
नागालैण्ड	9798.33	–	434.90	–	119.81	–	125.28	–	–
ओडिशा	92719.88	–	1227.68	–	964.37	–	1783.17	–	–
पंजाब	48112.44	–	1176.91	–	–	–	1359.03	–	10.00
राजस्थान	148580.86	–	2556.90	–	8111.11	–	434.73	–	100.00
सिक्किम	4022.84	–	193.21	–	–	–	11.91	–	–
तमिलनाडु	68141.95	–	3109.48	–	155.74	–	1846.77	–	2481.55
त्रिपुरा	17493.76	–	33.38	–	–	–	137.29	–	5.00
उत्तर प्रदेश	263682.61	735.19	6245.31	–	15542.09	–	769.02	–	802.00
उत्तराखण्ड	20892.49	433.98	772.25	–	2841.73	–	296.10	–	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	177652.74	–	53.92	–	–	–	–	–	260.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	907.36	–	–	–	–	–	4.41	–	–
चंडीगढ़	1611.21	–	–	–	–	–	12.03	–	–
दादरा और नगर हवेली	564.35	–	–	–	–	–	36.09	–	–
दमण और दीव	257.06	–	–	–	–	–	5.46	–	–
दिल्ली	3783.29	–	1310.90	–	–	–	740.13	–	–
लक्षद्वीप	127.86	–	26.34	–	–	–	14.82	–	30711.26
पुडुचेरी	757.62	–	130.83	–	–	–	99.21	–	–
एन.जी.ओ./सोसाइटियां /अन्य एजेंसियों/ राष्ट्रीय घटक	–	–	–	–	–	15.00	–	9581.59	–

संकेत : आई.सी.टी. : सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर.एम. एस.ए.	मॉडल स्कूल	छात्रा हॉस्टल	आई.ई.डी. एस.एस.	आई.ई. सी.टी. स्कूल	वी.ई.	एम.डी. एम	आई.डी. एम.आई.	एस.पी. क्यू.ई. एम	पोलिटेक्निकों की स्थापना	राष्ट्रीय साधन-सह-छात्रवृत्ति योजना
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
आन्ध्र प्रदेश	32832.00	41209.00	9699.00	227.50	6923.50	–	85191.45	–	–	6.00	2032.8
अरूणाचल प्रदेश	2024.00		100.00	–	584.37	–	2091.75	–	–	35.00	29.46
असम	8346.00	6345.00	1712.00	–	2182.40	30.71	53220.90	94.22	459.23		85.56
बिहार	2350.00		4176.00	–	–	–	81820.31	–	–	80.00	487.92

1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
छत्तीसगढ़	34469.00	859ए00	2656.00	–	–	–	47462.95	–	229.7	–	41.58
गोवा	312.00		–	–	–	–	825.41	–	–	–	7.44
गुजरात	1525.00	30.00	–	1235.57	5107.64	–	35301.58	124.30	–	5.00	586.32
हरियाणा	17556.00		–	161.64	–	1165.19	16713.43	145.36	–	7.00	47.64
हिमाचल प्रदेश	5766.00		–	162.33	2205.68	–	7351.60	–	–	25.00	25.98
जम्मू और कश्मीर	9636.00		–	–	–	–	13430.59	–	538.60	36.00	21.72
झारखण्ड	1794.00	4891.00	–	–	–	–	52252.17	–	–	85.00	–
कर्णाटक	4890.00		–	–	6229.48	–	56525.78	357.26	210.58	–	370.86
केरल	1910.00		–	2290.21	5562.00	–	14277.09	2588.56	–	–	1099.08
मध्य प्रदेश	24239.00	20274.00	879.00	898.62	–	–	76704.43	–	1085.53	40.00	140.58
महाराष्ट्र	7399.00	2927.00	–	–	–	–	69255.77	754.59	147.52	8.00	–
मणिपुर	3813.00		–	–	–	–	1894.19	–	–	–	–
मेघालय	1239.00	1503.00	–	–	20.00	–	3528ए12	–	–	–	7.98
मिजोरम	3623.00		20.00	141.78	672.84	–	3306.57	25.00	–	24.00	24.54
नागालैण्ड	2826.00		–	731.04	542.67	–	2464.37	–	–	–	4.08
ओडिशा	12887.00	12885.00	–	1128.11	400.00	–	37124.38	–	–	16.00	471.36
पंजाब	8940.00	190.00	–	–	2890.00	–	17561.54	–	–	21 00	121.8
राजस्थान	14689.00	4992.00	199.00	39.43	–	–	52901.22	–	71.95	45.00	95.82
सिक्किम	692.00		–	–	–	–	1035.65	345.60	–	28.00	13.56
तमिलनाडु	19719.00	1167.00	–	128.12	4360.00	–	40333.68	–	–	–	139.68
त्रिपुरा	723.00	–	–	127.18	927.72	–	8408.41	–	–	13.00	7.8

1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
उत्तर प्रदेश	20448.00	11567.00	–	–	6268.17	–	107638.85	200.39	11175.37	60.00	198.18
उत्तराखंड	3407.00	–	28.00	–	–	–	14255.51	208.32	34.62	–	25.14
पश्चिम बंगाल	274.00	–	–	903.94	3646.83	453.76	77251.02	–	–	15.00	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	105.00	–	–	–	67.20	–	509.14	–	–	–	2.28
चंडीगढ़	235.00	–	–	–	–	–	680.77	–	–	–	10.56
दादरा और नगर हवेली	126.00	–	–	–	31.20	–	342.71	–	–	–	5.52
दमण और दीव	129.00	–	–	–	18.75	–	136.58	–		–	3.54
दिल्ली	397.00	–	–	140.68	639.98	–	6562.19	–	–	–	52.2
लक्षद्वीव	74.00	–	–	–	–	–	76.32	–	–	–	–
पुदुचेरी	196.00	–	–	–	–	–	635.99	–	–	–	20.94

एन.जी.ओ./सोसाइटियां/अन्य एजेंसियों/राष्ट्रीय घटक

संकेत: **आर.एम.एस.ए.** : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग : **आई.सी.टी.** : सूचना संचार प्रौद्योगिकी एम.डी.एम: मध्याह्न भोजन : **आई.डी. एम.आई** : अल्पसंख्यक संस्थानों के विकास के लिए अवसंरचना **एस.पी.क्यू.ई.एम** : मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम : **वी.ई:** उच्चतर माध्यमिक शिक्षाका व्यावसायिकरण

आई.ई.डी.एस.एस. : माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों के लिए समावेशी शिक्षा

शहरी परिवहन

1875. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो ने शहरी परिवहन पर काक्रर्यम आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डी.एम.आर. सी.) ने सूचित किया है कि डी.एम.आर.सी. प्रशिक्षण संस्थान ने दिनांक 15 से 19.10.2012 तक रेल आधारित शहरी परिवहन पर

प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र सहित शहरी परिवहन से जुड़े मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के लिए विशेषरूप से तैयार किय गया था। कार्यक्रम की विषय-वस्तु में रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों से संबंधित सर्वाधिक संगत विषयों जैसे शहरी परिवहन की आवश्यकता, शहरी परिवहन के साधन जन द्रुत परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) के लाभ, परिवहन अर्थव्यवस्था, डी.एम.आर.सी. की प्रबंधन, शहरी परिवहन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, सम्पत्ति विकास आदि शामिल है। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के 18 सहभागी ने भाग लिया। कार्यक्रम के बारे में सहीभागियों का फीडबैक बहुत संतोषजनक है।

[हिन्दी]

स्वतंत्र विनियामक निकाय की स्थापना करना

1876. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अभियांत्रिकी, प्रबंधन और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों को स्वतंत्र विनियामक निकाय के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2009 में प्रो. यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उक्त निकाय का गठन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यशपाल समिति ने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट में उच्चतर शिक्षा के नवीकरण और कायाकल्पन पर सलाह देते हुए विद्यमान विनियामक निकायों के स्थान पर संवैधानिक निकाय के रूप में एक सर्वव्यापी उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के सृजन की सिफारिश की थी। बाद में, उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 2011 दिनांक 28.12.2011 को संसद में पेश किया गया है।

उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 2011 में ज्ञान और नवाचार के निःशुल्क अनुसरण के लिए शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बढ़ाने; शैक्षिक और अनुसंधान प्रथाओं के लिए वैश्विक मानकों को देखते हुए उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना करने जिससे कृषि शिक्षा को छोड़कर विश्वविद्यालयीय शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी, कारोबारी और चिकित्सा शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान के मानकों का निर्धारण, समन्वय, अनुरक्षण और निरंतर वृद्धि को सुकर करने की व्यवस्था है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.जी.एन.टी.यू. के क्षेत्रीय केन्द्र/परिसर

1877. श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री हरिचंद्र चव्हाण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्थल की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ङ) देश में गुजरात सहित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आई.जी.एन.टी.यू.) के क्षेत्रीय केन्द्रों/परिसरों का ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो पहले से ही स्थापित हैं के अलावा और कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आई.जी. एन.टी.यू.) का एक क्षेत्रीय परिसर है जो इम्फाल, मणिपुर में अवस्थित है। आई.जी.एन.टी.यू. ने गुजरात राज्य में कोई परिसर स्थापित नहीं किया है।

(च) और (छ) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार उन्होंने गुजरात सरकार को राज्य में विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना करने के लिए पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना सहित 300 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के प्रत्युत्तर के बिना, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं है।

भारत में विदेशी राजनयिक

1878. **श्री मानिक टैगोर : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तैनात राजनयिक केन्द्र सरकार की सहमति/जानकारी के बगैर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकें कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या रवैया है;

(ग) क्या विगत में ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं।

(ख) विहित मानदण्डों के अनुसार ऐसी बैठकों से संबंधित अनुरोध बैठक की प्रस्तावित तारीख से 10 कार्यदिवस पहले विदेश मंत्रालय को भेजा जाना होता है। प्रतिबंधित क्षेत्रों, संरक्षित क्षेत्रों/निषिद्ध क्षेत्रों की यात्रा से संबंधित अनुमति विदेश मंत्रालय से लेनी होती है और ऐसी अनुमति से संबंधित अनुरोध यात्रा की तारीख से कम से कम 4 सप्ताह पहले विदेश मंत्रालय में भेजा जाना अपेक्षित होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों की घटती संख्या

1879. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**
श्रीमती रमा देवी :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के पद बढ़ रहे हैं जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद घट रहे हैं जिससे सरकारी कार्यालयों में कार्यकरण प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001 और 2012 में स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन नहीं कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके कारण व्यय में अनावश्यक वृद्धि हुई है और कार्य का समय पर निपटान नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, समूह क, ख, ग और पूर्व समूह घ के नियमित केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) की अनुमानित संख्या है :-

समूह	1 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार	1 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार
1	2	3
क	73174	87410

1	2	3
ख	151727	205523
ग*	2227233	2856347
घ	1034826	–

(*छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात पूर्व समूह घ पदों को समूह ग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वेतन और भत्तों पर व्यय की समूह-वार सूचना व्यय विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यात्मक विचारण के आधार पर रिक्तियों को भरा जाना अपेक्षित है।

गरीबों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु नए मानक

1880. श्री सुरेंद्र सिंह नागर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गरीबों के लिए कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने हेतु नए मानक तैयार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) सरकार गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिससे कि खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि जैसे मुद्दों का समाधान हो सके। सरकार में केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर स्कीमें कई स्तरों पर प्रचालित की जा रही हैं। स्कीमों में प्रयुक्त मानक एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की पहचान के संबंध में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 को दिए गए संयुक्त वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि योजना आयोग के कार्यप्रणाली पर आधारित वर्तमान राज्यवार गरीबी अनुमानों का प्रयोग विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं स्कीमों में शामिल किए जाने वाले परिवारों की संख्या को सीमित करने के लिए नहीं किया जाएगा। चल रहे सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के माध्यम से एकत्र किए जा रहे सूचकों पर आधारित वंचन के बहु आयामों पर विशिष्ट हकदारी निश्चित करते समय विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को प्रभावी एवं तेजी से लाभों का अंतरण करने हेतु जहां तक संभव हो, आधार प्लेटफार्म के प्रयोग पर बल दिया है।

विमान सुरक्षा

1881. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन अधिकारियों ने विमानों में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए नए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी नागर विमानन सुरक्षा परामर्श निकाय का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्यों के चयन के मानदंड सहित इसे कब तक गठित कर दिया जाएगा;

(ङ) क्या संसद सदस्यों को भी इस निकाय में नामित किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विमानों में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए विनिर्दिष्ट मार्गों पर विमानों में स्काई मार्शल तैनात किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(ध) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

काउंटर मेगनेट सिटी योजना

1882. श्री प्रवीण सिंह ऐरन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय काउंटर मैगनेट सिटी विकास योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस योजना हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा किए जा रहे कृत्य लक्ष्य के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या काउंटर मैगनेट सिटी विकास योजना अब प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची में नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बजट में कोई कटौती की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) बरेली, उत्तर प्रदेश हेतु इस योजना को कई वर्ष पूर्व अपनाए जाने के बावजूद वहां इसका कार्यान्वयन न होने के क्या कारण हैं; और

(ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने सूचित किया है कि उसके द्वारा कोई राष्ट्रीय काउंटर मैगनेट शहरी विकास स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है तथापि विकास के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 में निम्नलिखित 5 काउंटर मैगनेट क्षेत्रों की पहचान की गई है :

1. हरियाणा में हिसार
2. मध्य प्रदेश में ग्वालियर
3. पंजाब में पटियाला
4. राजस्थान में कोटा
5. उत्तर प्रदेश में बरेली

संबंधित राज्य सरकारों को इन काउंटर मैगनेट क्षेत्रों का विकास करना है। एनसीआरपीबी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण देता है। अब तक बोर्ड ने 16 परियोजनाओं के लिए काउंटर मैगनेट क्षेत्र कस्बों को ऋण सहायता निर्माणधीन दी है जिसमें से 9 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 7 परियोजनाएं हैं। एनसीआरपीबी ने यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बजट में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ज) एनसीआरपीबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार की है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया। क्षेत्रीय योजना 2021 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक नीतिगत दस्तावेज है, जिसमें विभिन्न परस्पर क्षेत्र जैसे आर्थिक गतिविधियां, परिवहन, विद्युत, जल, सीवरेज, ठोस कचरा, प्रबंधन, दूरसंचार, आश्रय, सामाजिक अवसंरचना, धरोहर और पर्यटन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय भू उपयोग, काउंटर मैगनेट क्षेत्र आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर वायुयानों में तकनीकी खराबी

1883. श्री सोमेन मित्रा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के ''ड्रीमलाइनर वायुयान'' में प्रचालन के पहले दिन ही तकनीकी खराबी आ गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार की त्रुटि को दूर किए बिना ही अन्य ड्रीमलाइनर वायुयानों की डिलिवरी लेने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ड्रीमलाइनर वायुयानों को केवल घरेलू क्षेत्रक में ही प्रचालित किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो ड्रीमलाइनर वायुयानों को किन-किन अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों पर प्रचालित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) दिनांक 19.9.2012 को अपने प्रचालन पहले दिन ही ड्रीमलाइनर बाइंग 787 ने तीन सेक्टरों, अर्थात दिल्ली-मद्रास-दिल्ली और

दिल्ली-बंगलौर, पर उड़ान भरी। पहले दो सेक्टरों पर प्रचालन के समय इसने बिना किसी तकनीकी खराबी के उड़ान भरी जबकि तीसरे सेक्टर तथा दिल्ली-बंगलौर, पर पुश बैक तथा दोनों इंजन को चालू करने के पश्चात पावर इक्विपमेंट लिक्विड कूलिंग सिस्टम तथा इलैक्ट्रिकल पावर सिस्टम में खराबी के कारण विमान वापिस आ गया। विमान की खराबी का संतोषप्रद समाधान हो जाने पर विमान को वाणिज्यिक सर्विसेज के लिए दिया गया।

(ख) एयर इंडिया ने पहले ही इस मुद्दों की समीक्षा कर रही है।

(ग) और (घ) विमान में खराबी के बारे में बोइंग को सूचित किया गया है और उनकी सलाह के अनुसार, वर्ष 2013 की पहली तिमाही में उपलब्ध विमान इलैक्ट्रिकल सिस्टम में आशोधन किए जाने तक, एयर इंडिया द्वारा अन्तरिम समाधान कर लिया गया है। चूंकि एयर इंडिया के टी.ए.पी./एफ.आर.पी. को प्रभावी कार्यान्वियन के लिए इस विमान को शामिल करना महत्वपूर्ण है, इसलिए योजना के अनुसार विमान का अर्जन जारी रखा जाएगा और तकनीकी मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं। इस समय एयर इंडिया ने 3 बी 787 ड्रीमलाइनर विमान की सुपुर्दगी प्राप्त कर ली है। इन तीनों विमानों में से प्रत्येक विमान का प्रचालन निम्नानुसार है:-

प्रथम यूनिट- 2 घरेलू सेक्टर अर्थात दिल्ली-कोलकाता एवं वापसी दैनिक और दिल्ली-मद्रास एवं वापसी दैनिक

द्वीतीय यूनिट- 2 घरेलू तथा 1 कम दूरी वाले अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर अर्थात दिल्ली-बंगलौर एव वापसी प्रतिदिन दो बार और दिल्ली-दुबई एवं वापसी प्रतिदिन

तृतीय यूनिट - 1 लम्बी दूरी वाले अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर अर्थात दिल्ली-फ्रैंकफर्ट एवं वापसी-प्रतिदिन

चतुर्थ बी 787 आशा है कि दिसंबर, 2012 के प्रथम सप्ताह में शामिल कर लिया जाएगा। इस यूनिट को दिल्ली-प्रेरिस-दिल्ली सेक्टर पर लगाए जाने की योजना है।

संचार उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों का उत्पादन

1884. श्री आधि शंकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को चंद्रमा और मंगल ग्रह के अभियानों की अपनी तैयारी के मद्देनजर, संचार-उपग्रहों और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानों (पी.एस.एल.वी.) का उत्पादन संबंधित उद्योग को सौंपने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अंतरिक्ष एजेन्सी संचार उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के निर्माण के पुनरावृत्तिपूर्ण कार्य में संलग्न रहने की बजाय विशिष्ट विज्ञान परियोजनाओं पर कार्य करने, दूरसंवेदी उपग्रह विकसित करने तथा और अधिक अनुसंधान और विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारतीय उद्योग की भागीदारी का स्तर बढ़ाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में, विशेषत: पुनरावृत्तिवाली प्रकृति के कुछ संचार उपग्रहों और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट का भारतीय उद्योग के द्वारा चरणबद्ध उत्पादन कार्यों की संभावव्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। भविष्य में उन्नत अंतरिक्ष प्रणालियों और अनूठी अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी परियोजनाओं की संवर्धित मांग के दृष्टिकोण से इसरो उच्च शक्ति उच्च संवेश प्रवाह संचार उपग्रहों, सूक्ष्म तरंग और अति-स्पेक्ट्रमी प्रतिबिंबन सहित उन्नत सुदूर संवेदन उपग्रहों, मंगल कक्षित्र सहित अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहीय अनुसंधान हेतु उपग्रहों और अर्ध-क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी सहित कम लागत वाली अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों के विकास जैसे अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों में स्वनिर्मित सुविधाओं के उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है।

[हिन्दी]

डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की समीक्षा

1885. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा डा. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है जो इसके तहत बनाए गए अधिनियम, सांविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा-8 के तहत, विश्वविद्यालय के कार्य और प्रगति की समीक्षा के लिए विजिटर समय-समय पर एक या अधिक व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जिसमें उनके द्वारा अनुरक्षित कालेज और संस्थान शामिल हैं। विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फ्लैटों की बिक्री

1886. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि और विकास कार्यालय/एलएंडडीओ विभाग ने दिल्ली में अपने आबंटियों को फ्लैटों की बिक्री के संबंध में स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आबंटितियों को उक्त अनुमानित प्रदान करके दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का कार्य आसान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एमसीडी ने भी इस संबंध में सरकार से संपर्क किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मद्रास विश्वविद्यालय के अधीनस्थ संस्थान को बंद किया जाना

1887. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास विश्वविद्यालय के अधीनस्थ आने वाला एक प्रमुख औषधिक आकल्पन संस्थान, अर्थात् सेन्टर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन क्रिस्टॅलोग्राफी एण्ड बायो फिजिक्स बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संस्थान में नए प्राध्यापकों की जल्द भर्ती करके इसे बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। मद्रास विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि सेन्टर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन किस्टॅलोग्राफी एण्ड बायो फिजिक्स, विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है और विश्वविद्यालय द्वारा किसी कारण से कोई विभाग बंद नहीं किया जा सकता।

(ग) मद्रास विश्वविद्यालय ने विभाग के सुचारू कार्यकरण के लिए विभाग में नए संकाय की भर्ती करने हेतु पहले ही पर्याप्त कदम उठाए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां

1888. श्री रामसिंह राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों और सहायक स्टॉफ के पदों की स्वीकृत संख्या क्या है और इसमें से कितने पद भरे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का स्थानीय आधार पर तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति द्वारा विद्यमान रिक्तियों को भरने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) 1089 केन्द्रीय विद्यालय हैं तथा संस्वीकृत एवं भरे हुए शिक्षकों तथा सहायत कर्मचारियों के पदों की संख्या इस प्रकार है:-

	कुल पद	भरे गए पद
शिक्षण कर्मचारी	42506	35642
सहायक कर्मचारी	10767	8202

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन इन रिक्तियों को समय-समय पर नियमित वार्षिक कार्रवाई के माध्यम से सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति द्वारा भरता है। तथापि, नियमित रिक्तियों पर शिक्षकों को संविदा आधार पर नियुक्ति किया जाता है ताकि छात्रों के अध्ययन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

[हिन्दी]

मैट्रो का निर्माण कार्य

1889. श्री हरि मांझी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मैट्रो के तीसरे चरण के अंतर्गत सुभाष पार्क के निकट मैट्रो का निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि जामा मस्जिद मैट्रो स्टेशन के लिए सुभाष पार्क में निर्माण कार्य दिनांक 18.07.2012 से स्थगित करके दिनांक 03.10.2012 कर दिया गया था। अब यह कार्य पुन: शुरू कर दिया गया है तथा यह नियत कार्यक्रम से 3 माह पीछे है।

(ग) डीएमआरसी ने व्यर्थ गए समय की पूर्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने का ठेकेदार को निर्देश दिया है।

[अनुवाद]

'लुक ईस्ट' नीति

1890. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से विश्व के पूर्वी क्षेत्र के देशों की ओर अभिमुखता (लुक ईस्ट) की नीति का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऊर्जा क्षेत्र में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ कोई संधि या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की भी योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) विगत वर्षों के दौरान भारत की ऊर्जा जरूरतों में लगातार वृद्धि होती रही है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों सहित सम्पूर्ण विश्व से ऊर्जा संसाधनों का आयात करती है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों सहित अनेक देशों से विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति/गवेषण के बारे में करार निष्पन्न किया जा सके।

दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों हेतु विनियामक ढांचा

1891. श्री प्रहलाद जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों हेतु कोई विनियामक ढांचा लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे संस्थानों में कदाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में कार्यरत दूरवर्ती शिक्षा विश्वविद्यालयों और इनमें पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के बारे में कोई डाटाबेस है;

(च) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। संसद में पहले से ही पुरःस्थापित किए गए उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान विधेयक, 2011 में दूरस्थ शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा विनियामक निकायों को सम्मिलित करते हुए उच्चतर शिक्षा हेतु एक सर्वोच्च विनियामक निकाय की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, पारदर्शिता सहित जवाबदेही निर्धारित करने, सहभागी शासन और उद्देश्य मूल्यांकन तथा निरीक्षण-अनुमोदित प्रक्रियाओं के स्थान पर सत्यापन एवं अधिप्रमाणन तंत्र को अपनाने को सुकर बनाया जा सके।

(ग) और (घ) दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इसे कुछ विश्वविद्यालयों अर्थात् पेरियार विश्वविद्यालय (तमिलनाडु), मनोनमेनियन सुंदरनार विश्वविद्यालय (तमिलनाडु), ई. आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय (सिक्किम), आई.ए.एस.ई. मानद विश्वविद्यालय (राजस्थान), एम.जी. विश्वविद्यालय (मेघालय), विनायक मिशनस विश्वविद्यालय (तमिलनाडु), जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (राजस्थान), दी ग्लोबल ओपन विश्वविद्यालय (नागालैंड), पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (पंजाब), कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (कर्णाटक) आदि के संबंध में, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर अध्ययन केन्द्र खोलने, बी.ई./बी.टेक कार्यक्रम प्रदान करने और अध्ययन केन्द्रों आदि को अधिकार प्रदान करने आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दुरस्थ शिक्षा परिषद ने शिकायतों की जांच की है और संबंधित संस्थाओं/प्राधिकरणों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए सूचित कर दिया है। दूरस्थ शिक्षा परिषद, नियमित रूप से दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं को दूरस्थ शिक्षा परिषद और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य शीर्ष निकायों को मानकों का अनुपालन करने, अध्ययन-केन्द्रों की अधिकृत करने के साथ ही दूरस्थ पद्धति के जरिए बी.ई./बी. टेक. कार्यक्रम प्रदान नहीं करने के बारे में सूचित करती है।

(ङ) दूरस्थ शिक्षा परिषद के अनुसार यह एक डाटाबेस रखती है लेकिन समय पर डाटा प्रस्तुत करने में संस्थाओं की उदासीनता के कारण इसको अद्यतन करने में कठिनाई का सामना करती है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) में दिए गए उत्तर के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में सांस्कृतिक निधि की अनियमितताएं

1892. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थिति भारतीय मिशनों को अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में निधि प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निधि के प्रयोग में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) लागू नहीं।

कार्गो-केन्द्र

1893. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के कुछ भागों में नए कार्गो-केन्द्र निर्मित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) सरकार के पास विशेष कार्गो केन्द्र निर्मित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

एन.पी.आर. का बायोमीट्रिक डाटा और आधार कार्ड

1894. श्री सी.आर. पाटिल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस व्यक्ति के पास राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एन.पी.आर.) के अंतर्गत बायोमीट्रिक जानकारी वाला कार्ड है उसे आधार-कार्ड के लिए भी पंजीकरण कराना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो कार्य के दोहराव से बचने और राजकोष पर बोझ न डालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जिन सेवाओं को उक्त पहचान-कार्डों से जोड़ने का प्रस्ताव है, उन्हें इन दोनों कार्डों में से कोई एक भी रखने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रत्येक कार्ड पर कितनी लागत आ रही है और बायोमीट्रिक डाटा संग्रहण किए जाने के कितने दिन बाद आवेदक को ये कार्ड दिए जाते हैं; और

(ङ) इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने प्रतिशत लोगों को लाया गया है और सभी राज्यों, विशेषकर गुजरात की समस्त आबादी को इस योजनांतर्गत कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के माध्यम से पंजीकरण और आधार के लिए एक ही प्रकार के आंकड़े लिए जाते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के माध्यम से पंजी के माध्यम से पंजीकरण के समय निवासी का आधार के लिए भी पंजीकरण किया जाता है। अत:, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के माध्यम से पंजीकृत हो चुके व्यक्ति को आधार के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) आधार का उद्देश्य एक ऐसी सॉफ्ट पहचान अवसंरचना उपलब्ध कराना है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा सके। व्यक्ति की पात्रता और अर्हता का निर्धारण करना संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है।

(घ) पंजीकरण एजेंसियों को निवासियों के पंजीकरण के 20 दिनों के भीतर पंजीकरण डेटा पैकेटों को अपलोड करना करना होता है। निवासियों के डेटा पैकेटों की वैधता/गुणवत्ता की कई प्रकार से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राप्त ब्यौरे सही और प्रामाणिक हैं। यदि सत्यापन विफल नहीं होता, तो निवासी को सामान्यत: 90 दिनों के भीतर हमारे डिलीवरी भागीदार भारतीय डाक से आधार-पत्र मिल जाता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निवासियों को कोई कार्ड जारी नहीं करता। यह पत्र के रूप में आधार संख्या से अवगत कराता है। फिलहाल, इस पत्र की मुद्रण लागत 2.16 रूपए है। डिलीवरी का काम भारतीय डाक के माध्यम से किया जाता है जो प्रति आधार पत्र 20/-रूपए लेता है। निवासी पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करने की गृह मंत्रालय की स्कीम को सरकार की मंजूरी मिलना अभी शेष है।

(ङ) 31.10.2012 क स्थिति के अनुसार, देश भर में 21 करोड़ से अधिक आधार संख्याएं सृजित की गई हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को 2014 तक 60 करोड़ निवासियों के पंजीकरण के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसने आधार परियोजना को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय डाक आदि के साथ साझेदारी मॉडल के माध्यम से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया है जिनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। शेष आबादी को भारत के पंजीयक द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी प्रक्रिया के अंतर्गत आधार के दायरे में लाया जाएगा। 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, सृजित आधार का राज्य/संघ राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण-II में दी गई है।

गुजरात में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पंजीकरण और आधार समर्थित अनुप्रयोगों के विकास के लिए पंजीयक के रूप में गुजरात सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के साथ साझेदारी कर रहा है। अपने निवासियों का पंजीकरण पूर्ण करवाने की पहल करना राज्य पंजीयक का उत्तरदायित्व है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य पंजीयकों के साथ लगातार सम्पर्क में है।

विवरण-I

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/सं राज्य क्षेत्र
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमण और द्वीप
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखण्ड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

विवरण-II

क्र .सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या (जनगणना 2011)	अक्तूबर 2012 तक सृजित आधार	आधार संतृप्तता प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	379944	159660	42%
2.	आन्ध्र प्रदेश	84665533	47798541	56%
3.	अरूणाचल प्रदेश	1382611	603	0%
4.	असम	31169272	17960	0%
5.	बिहार	103804637	2102277	2%
6.	चण्डीगढ़	1054686	620994	59%
7.	छत्तीसगढ़	25540196	319915	1%

1	2	3	4	5
8.	दादरा और नगर हवेली	342853	29634	9%
9.	दमण और द्वीव	242911	122120	50%
10.	दिल्ली	16753235	11805342	70%
11.	गोवा	1457723	1056961	73%
12.	गुजरात	60383628	5410346	9%
13.	हरियाणा	25353081	2390327	9%
14.	हिमाचल प्रदेश	6856509	4292254	63%
15.	जम्मू और कश्मीर	12548926	45613	0%
16.	झारखंड	32966238	8772309	27%
17.	कर्नाटक	61130704	15943152	26%
18.	केरल	33387677	13599776	41%
19.	लक्षद्वीप	64429	42828	66%
20.	मध्य प्रदेश	72597565	12409495	17%
21.	महाराष्ट्र	112372972	40041572	36%
22.	मणिपुर	2721756	482912	18%
23.	मेघालय	2964007	850	0%
24.	मिजोरम	1091014	8477	1%
25.	नागालैंड	1980602	59300	3%
26.	ओडिशा	41947358	3897444	9%
27.	पुदुचेरी	1244464	880258	71%
28.	पंजाब	27704236	10639174	38%
29.	राजस्थान	68621012	9484620	14%
30.	सिक्किम	607688	476146	78%
31.	तमिलनाडु	72138958	6679306	9%

1	2	3	4	5
32.	त्रिपुरा	3671032	2949098	80%
33.	उत्तर प्रदेश	199581477	9947931	5%
34.	उत्तराखण्ड	10116752	1016854	10%
35.	पश्चिम बंगाल	91347736	3730743	4%
	कुल योग	1,210,193,422	217,234,792	18%

अल्पसंख्यकों हेतु काक्रर्यम/अध्येतावृत्ति

1895. श्री राजू शेट्टी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के अल्पसंख्यकों को विभिन्न कार्यक्रमों/अध्येतावृत्तियों में वरीयता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो उन उपबंधों और उल्लेखों का ब्यौरा क्या है, जिनके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को ये रियायतें दी गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, पात्र राज्य विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षित सम-विश्वविद्यालयों तथा पात्र कॉलेजों को तीन कोचिंग योजनाओं नामत: () अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी कोचिंग () सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग योजना; और () राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने हेतु कोचिंग की योजना जो अनन्य रूप में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए हैं, के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2009 से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृति की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित चुनिंदा अभ्यर्थियों को भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एम.फिल/पी.एच.डी. करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। प्रत्येक वर्ष 756 स्लॉट होते हैं और अध्येतावृत्ति की अवधि 5 वर्ष है। सहायता की राशि नीचे दी गई है:-

अध्येतावृत्ति (1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी)	@रु16,000/- आरंभिक दो वर्ष के लिए (जे.आर.एफ.) @रु18,000/- शेष अवधि के लिए (एस.आर.एफ.)
मानविकी और सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के लिए आकस्मिकता	@रु10,000/- वार्षिक आरंभिक दो वर्ष के लिए @रु20,500/- वार्षिक शेष 3 वर्ष के लिए
विज्ञान के लिए आकस्मिता	@रु12,000/- वार्षिक आरंभिक दो वर्ष के लिए @रु25,000/- वार्षिक शेष तीन वर्ष के लिए
विभागीय सहायता	मेजबान संस्था को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यार्थी @रु3,000/- वार्षिक
एस्कॉर्ट्स/रीडर सहायता	शारीरिक तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामले में @रु2,000/- प्रतिमाह

शिक्षा-किटें

1896. श्री विष्णु पद राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय संसद-सदस्यों ने आई.डी.ए. की 14वीं बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को शिक्षा-किटें प्रदान करने के संबंध में राशि प्रतिपूर्ति-योजना को लागू करने की मांग की है, जैसा कि यूनिफॉर्मों की आपूर्ति के सिलसिले में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) सरकारी पाठ्यचर्या लागू करने के इच्छुक मदरसों सहित सरकारी/स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करके महत्वपूर्ण शिक्षा निवेश उपलब्ध कराता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्राथमिक स्तर पर 150/- रूपये प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 250/- रुपए प्रति बच्चा है। कक्षा I से VIII तक छात्रों को शिक्षा किट उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अर्हता-संबंधी नए मापदण्ड

1897. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) के नए अर्हता-संबंधी मापदण्डों से राज्य-वार विशेषकर अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के अनेक अभ्यार्थियों की उम्मीदों पर तुषारापात हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जून, 2012 की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए कुल 706994 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया था, जिसमें से 571630 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे और 57550 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। उत्तीर्ण उम्मीदवारों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

यू.जी.सी.-नेट	श्रेणी	पंजीकृत	परीक्षा में बैठने वाले	उत्तीर्ण
जून, 2012	सामान्य	326090	271752	24014
	ओबीसी	211112	169582	19035
	पी.डब्ल्यू.डी.	11673	9046	1506
	एस.सी./एस.टी.	158119	121250	12995
	कुल	706994	571630	57550

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने सूचित किया है कि यू.जी.सी.-नेट, जून, 2012 की परीक्षा के मानदण्डों के संबंध में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसकी दिनांक 22.10.2012 की बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू.जी.सी.-नेट, 2012 के परिणाम से संबंधित अभिवेदनों/शिकायतों की जांच करने और यदि आवश्यक पाया गया तो परिणामों की पुनः जांच करने के लिए एक, चार सदस्यीय समिति गठित की।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू.जी.सी. द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुपूरक परिणाम तैयार कर लिए हैं, जो दिनांक 12.11.2012 को घोषित किए गए थे। यह दिनांक 18.09.2012 को घोषित किए गए मूल परिणामों में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के अतिरिक्त था।

विदेश राजनयिकों का शैक्षिक-पाठ्यक्रमों में शामिल होना

1898. श्री ताराचंद भगोरा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन नियमों में ढील दी है जो भारत में विदेशी राजनयिकों की तैनाती के दौरान उनके शैक्षिक-पाठ्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाते थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारत में अपनी तैनाती के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों मेंशैक्षिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त करने संबंधी विदेशी राजनयिकों के सभी अनुरोधों पर विदेश मंत्रालय द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है।

एयरलाइनों का समयबद्ध कार्य-संचालन

1899. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू क्षेत्र की विभिन्न विमान सेवाओं का समयबद्ध कार्य-संचालन, अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली में निकृष्टतम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानसेवा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य विमानपत्तनों की तुलना में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से वायुयानों के प्रस्थान में कहीं अधिक विलंब होता है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे विलंब हेतु उत्तरदायी कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डी.जी.सी.ए. ने ऐसे विलंब पर त्रुटिकर्त्री विमानसेवाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) जी नहीं, एयरलाइन का समयबद्ध कार्य-संचालन एअरलाइन संबंधी विशिष्ट मुद्दा है न कि शहर विशिष्ट।

अधिकांश विलंब प्रतिक्रियात्मक प्रकृति के होते हैं जिनका कारण दूसरी उड़ान से लोड कनेक्शन, उद्गम स्टेशन पर यात्री/बैगेज चैक-इन में गलती, पूर्ववर्ती सैक्टर से विमान का देरी से आगमन, दूसरी उड़ान से कर्मीदल की उपलब्धता, तकनीकी से विभिन्न री-रूटिंग या विमान का परिवर्तन आदि हैं।

(ङ) और (च) डी.जी.सी.ए. समय-सारणी का सही प्रकार से पालन करने की नियमित निगरानी और समय-समय पर संबंधित एयरलाइनों के समक्ष इस मामले को उठाता है।

[हिन्दी]

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियां

1900. श्री कीर्ति आज़ाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों को अनुरक्षण संबंधी अनुदान, विकास-अनुदान और शिक्षण व शिक्षा-सामग्री संबंधी अनुदान प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस सिलसिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य-वार, वर्ष-वार और अनुदान-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और प्रयुक्त की गई;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ष-वार, राज्य-वार और माह-वार मासिक आधार पर कितनी अनुदान राशि दी गई और इसका कितना उपयोग हुआ;

(घ) क्या वर्ष के दौरान अनुदानों का असमान वितरण किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) स्कूलों को सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुसार स्कूल अनुदान, अनुरक्षण अनुदान तथा शिक्षक अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय हिस्सा अनुमोदित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु दो अथवा अधिक किस्तों में जारी किया जाता है। राज्यों को शैक्षिक वर्ष के आरंभ में स्कूलों को ये अनुदान जारी करने पर बल दिया जाता है। परंतु, पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता, उपयोग प्रमाणपत्र बकाया रहने इत्यादि के कारण कुछ मामलों में विलंब हुए हैं।

विवरण

स्कूल अनुदान, अनुरक्षण अनुदान और शिक्षक अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		स्कूल अनुदान	अनुरक्षण अनुदान	शिक्षक अनुदान	स्कूल अनुदान	अनुरक्षण अनुदान	शिक्षक अनुदान	स्कूल अनुदान	अनुरक्षण अनुदान	शिक्षक अनुदान	स्कूल अनुदान	अनुरक्षण अनुदान	शिक्षक अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	428	424	3382	425	421	3439	422	418	3645	451	447	3038
2.	आंध्र प्रदेश	79996	72261	234853	90445	73324	235485	90126	82903	257948	89549	82370	291106
3.	अरूणाचल प्रदेश	3325	2609	13035	3517	2864	13286	3716	3038	13429	3992	3887	13638
4.	असम	43358	35973	185934	45868	37395	191570	48501	37361	167518	49416	40067	191467
5.	बिहार	96052	71286	326524	98972	52299	317613	101882	58632	351496	103968	59512	353313
6.	चंडीगढ़	204	0	2890	204	0	2890	202	202	3150	206	206	3200
7.	छत्तीसगढ़	46029	41519	134338	46487	42552	144555	47029	34389	157747	47594	45127	166445
8.	दादरा और नगर हवेली	393	252	1196	398	259	1198	367	261	1176	370	262	1156
9.	दमन और दीव	84	84	489	86	86	521	85	85	521	91	85	572
10.	दिल्ली	3475	3088	52939	3502	3125	52290	3507	3138	55404	3523	3154	46017
11.	गोवा	1533	1018	6256	1518	1001	6294	1501	1029	5698	1500	996	6705
12.	गुजरात	56096	54730	194459	56688	54703	194727	58812	55548	219992	57892	51962	235754
13.	हरियाणा	14612	14364	64568	14636	14614	59593	14779	14671	69425	15014	14831	68582
14.	हिमाचल प्रदेश	15046	14436	48475	15086	14840	49346	15103	14938	48243	14974	14923	47034
15.	जम्मू और कश्मीर	29001	20311	78904	31010	21310	83492	31808	21691	85201	32761	22395	86591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	झारखंड	53799	31746	135873	54844	33562	139411	55527	36473	131698	55224	38126	129022
17.	कर्नाटक	72457	67236	228885	73360	67376	227272	73548	67490	234164	73222	67460	228987
18.	केरल	14157	5445	127869	14278	5666	129124	14278	5666	131330	14253	5823	128936
19.	लक्षद्वीप	47	47	667	51	51	669	53	0	673	57	57	690
20.	मध्य प्रदेश	113316	100858	281626	114667	104357	290674	114409	111891	278943	114198	111891	270534
21.	महाराष्ट्र	106402	84482	437853	107811	86592	444331	110194	87801	433318	111780	87024	455591
22.	मणिपुर	3659	2281	13438	3515	2869	11084	3490	2815	15591	3554	2461	16368
23.	मेघालय	9516	6217	26872	11467	6635	36057	10999	7476	34088	11291	7726	34605
24.	मिजोरम	2374	2150	13575	2461	2395	13251	2468	2388	13835	2402	2276	14104
25.	नागालैंड	1938	1938	12927	2014	2014	12060	2144	2144	11720	2672	0	12628
26.	ओडिशा	68465	66698	188266	70419	68297	198010	72043	69209	196982	72467	70478	209254
27.	पुदुचेरी	384	508	2861	588	525	4114	580	433	4459	580	516	4097
28.	पंजाब	19466	18969	76180	20209	19608	74620	20328	19632	78684	20266	19482	98507
29.	राजस्थान	109204	63145	279001	109540	80667	252966	106973	68659	271733	106956	57353	268228
30.	सिक्किम	1143	1143	6099	1157	1157	6531	1210	1210	6780	1207	1207	7451
31.	तमिलनाडु	52842	35236	209918	53808	35255	203485	54220	35782	200317	54185	36098	196287
32.	त्रिपुरा	5977	5847	30306	6327	6133	29813	6487	6270	30250	6383	6246	30255
33.	उत्तर प्रदेश	151217	144128	473115	155340	155356	506719	155732	147680	491573	167855	149925	488040
34.	उत्तराखंड	17953	16375	47915	18088	17283	47530	17883	16949	42869	17789	16679	41976
35.	पश्चिम बंगाल	59421	59421	295820	60351	77159	267733	79608	76250	370128	81606	79697	386584
	कुल	1253369	1046225	4237308	1289137	1081750	4251854	1320014	1103622	4419728	1339248	1100749	4536762

[अनुवाद]

महिला शिक्षण केन्द्र

1901. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निरक्षर महिलाओं हेतु महिला शिक्षण केन्द्र (एम.एस.के.) स्थापित किए है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे केन्द्र आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ शशी थरूर): (क) जी, हां। महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत महिला शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में संचालनरत महिला शिक्षण केन्दों के ब्यौरे तथा राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गयी है:

महिला समाख्या राज्य का नाम	आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	झारखंड	कर्णाटक	केरल	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	कुल
महिला शिक्षण केन्द्रों की संख्या	16	9	12	1	4	14	5	13	16	6	96
लाभार्थियों की संख्या	6014	1445	5873	30	1694	3496	1304	460	5985	949	27250

[हिन्दी]

भारतीय लड़कियों का उत्पीड़न

1902. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि विदेशी नागरिकों से विवाहित भारतीय महिलाओं के साथ धोखाधड़ी/उनके परित्याग की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करने और उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतें सामान्यत: परित्याग करने, शारीरिक उत्पीड़न, शादी से पहले अपने बारे में झूठी सूचना देने, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी उत्पीड़न, बच्चे को गैर-कानूनी रूप से रोकने या बच्चे को गैर-कानूनी रूप से अलग करने, आदि से संबंधित होती हैं।

(ग) ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर, भारतीय मिशन, काउंसिलिंग, मामले का पति-पत्नी या स्थानीय प्राधिकरणों या दोनों के साथ अनुवर्तन करने, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय समुदाय कल्याण कोष से कानूनी सहायता प्रदान करने या आश्रय और/या भारत वापस लौटने के लिए निधियां प्रदान करने जैसी सहायता प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

सेवानिवृति लाभ

1903. श्रीमती अश्वमेध देवी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2014 के बाद भर्ती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारी पेंशन, जी.पी.एफ. और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनवरी, 2004 के पश्चात् भर्ती हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेंशन और जी.पी.एफ. की सुविधा नहीं देना, उनके साथ भेदभाव नहीं है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को यह सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए सरकारी सेवकों को ग्रेच्युटी सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (च) जी.पी.एफ. सहित परिभाषित प्रसुविधा पेंशन प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए, सशस्त्र बलों को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी सेवा में नए प्रवेशकों हेतु एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को अधिसूचित की गई थी। दिनांक 1.1.2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त और नई पेंशन प्रणाली द्वारा शासित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, अपनी सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त रूप में उनकी पेंशन प्रणाली द्वारा शासित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, अपनी सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त रूप में उनकी पेंशन निधि का 60 प्रतिशत निकाल सकते हैं और उनके धन का शेष 40 प्रतिशत उनकी इच्छानुसार किसी जीवन बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी योजना की खरीद हेतु प्रयोग किया जाना है जो उसे उसके शेष जीवन के लिए एक मासिक पेंशन अदा करेंगी। यदि 60 वर्ष की आयु से पूर्व नई पेंशन को कर्मचारी छोड़ते हैं तो अनिवार्य वार्षिकी योजना पेंशन धन का 80 प्रतिशत होगी।

नई पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक वार्षिकी, केवल सेवानिवृत्ति पर पेंशन और सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर कुटुम्ब पेंशन योजना द्वारा आविष्ट केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का का.ज्ञा.सं. 38/41/06 पी.एंडपी. डब्ल्यू.(क) दिनांक 5.5.2009 द्वारा अनंतिम रूप में ऐसे मामलों जहां कोई सरकारी कर्मचारी अवैधता/अशक्तता पर सेवानिवृत्त होता है और सेवा में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, के मामले में पुरानी पेंशन योजना अर्थात् सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत लागू दरों की समान दरों पर लागू हैं। एन.पी.एस. के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय डी.सी.आर.जी. के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(i) सेवानिवृत्ति उपदान सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को देय है। एकबारगी इस एकमुश्त लाभ को पाने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा और उपदान/पेंशन प्राप्त करने की पात्रता सेवा अनिवार्य है। सेवानिवृत्ति उपदान छः माह की प्रत्येक पूर्ण अर्हक सेवा की अवधि हेतु सेवानिवृत्ति के पहले एक माह के मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते की एक चौथाई दर से गिना जाता है। अधिकतम देय सेवानिवृत्ति उपदान, अधिकतम 10 लाख रूपए के अध्यधीन मूल वेतन की 16½ गुणा है।

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी सेवा में मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु उपदान उसके कुटुम्ब को निम्नलिखित तालिका में दी गई दरों पर देय होगा:

क्र.सं.	अर्हक सेवावधि	मृत्यु उत्पादन की दर
1.	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों को दो गुणा
2.	एक वर्ष अथवा अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	परिब्धियों का 6 गुणा
3.	20 वर्ष अथवा अधिक	अधिकतम 33 गुणा परिलब्धियों के अध्यधीन अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छः माह की अवधि हेतु परिलब्धियों का आधा

1.1.2006 से मृत्यु उपदान की अधिकतम स्वीकार्य धनराशि 10 लाख रूपए है।

[हिन्दी]

बालिका शिक्षा

1904. श्री राजेंद्र अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बालिका शिक्षा के लिए उपयोग किए जा रहे कुल शिक्षा बजट का अनुमानित अनुपात क्या है;

(ख) क्या माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के दाखिले में सुधार करने एवं बढ़ावा देने के लिए कक्षा सात उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बालक-बालिकाओं के लिए बजट में से बालिकाओं की शिक्षा के लिए वर्ष 2011-12 के 18781.72 करोड़ रूपये (संशोधित अनुमान) और वर्ष 2012-13 के लिए 22253.54 करोड़ रूपए (बजट अनुमान) के कुल बजट की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में सुधार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए सातवीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना नहीं है। तथापि, स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी लाने और माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने हेतु समर्थकारी वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना नामक केंद्र प्रायोजित योजना मई, 2008 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पात्र बालिका के नाम से 3000/- रू. की राशि सावधि जमा के रूप में जमा कराई जाती है जो इस राशि को इस ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने और 10वीं कक्षा पास करने के बाद निकालने की हकदार है। इस योजना में (प) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सभी बालिकाएं जिन्होंने 8वीं कक्षा पास की है, (पप) वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से 8वीं कक्षा पास की है (चाहे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों या नहीं) और सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में नौवीं कक्षा में नामांकन करवाया है, शामिल हैं।

(घ) वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के तहत जारी की गई और उपयोग की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) बालिका शिक्षा में सुधार करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

* कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा मुस्लिम समुदायों की बालिकाओं को आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्धकराने की मुख्य पहल है।

* उपेक्षित/अलाभान्वित वर्गों की बालिकाओं की गहन समुदाय संघटन, बस्तियों में मॉडल स्कूलों के विकास, अध्यापकों को बालक-बालिकाओं के प्रति सुग्राही बनाना, बालक-बालिकाओं के प्रति संवेदी अध्ययन सामग्री का विकास, छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा सुविधाएं और बालिकाओं के लिए अनुरक्षण, लेखन सामग्री, कार्य पुस्तकों और वर्दियों आदि की व्यवस्था के जरिए प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के संवर्धन हेतु प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराता है।

* वर्ष 2008-09 में आरंभ की गई माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना में देश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लगभग 3500 ब्लाकों में से प्रत्येक ब्लॉक में 100 बालिकाओं की क्षमतायुक्त छात्रावास के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम (एनएसआईजीएसई) के तहत जारी/ प्रयुक्त की गई राशि

क्रम सं.	राज्य का नाम	2009-10 जारी किया गया सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	2010-11 जारी किया गया सहायता अनुदान (करोड़ रु.)	2011-12 जारी किया गया सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	2012-13 जारी किया गया सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.856			
2.	छत्तीसगढ़	0.176	0.42	9.450	
3.	गोवा			0.223	
4.	गुजरात	13.323	12.375	19.123	
5.	हिमाचल प्रदेश		1.870	4.600	
6.	जम्मू और कश्मीर	1.508		2.756	3.704
7.	झारखंड	10.417	0.930	8.068	
8.	कर्नाटक			23.589	
9.	केरल	6.368	0.352		7.881
10.	मध्य प्रदेश		14.407	16.553	34.115
11.	मणिपुर				0.089
12.	मेघालय	0.515		1.943	1.581
13.	मिजोरम	0.981	1.193	1.253	
14.	ओडिशा			17.832	
15.	पंजाब	10.357		13.590	12.586
16.	राजस्थान		4.553	4.347	4.968
17.	सिक्किम			0.119	0.190

1	2	3	4	5	6
18.	तमिलनाडु		32.751	18.468	15.778
19.	त्रिपुरा		0.890	1.373	1.172
20.	उत्तर प्रदेश			7.690	
21.	उत्तराखंड	0.248	2.120	2.961	
22.	पश्चिम बंगाल				5.711
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.025	0.051	0.044	0.056
24.	चंडीगढ़	0.098	0.167	0.120	
25.	दादरा और नगर हवेली			0.361	
26.	दमन और दीव	0.037	0.048	0.055	0.055
27.	लक्षद्वीप			0.148	
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		1.158	7.401	
29.	पुदुचेरी		0.342	0.992	
	कुल	45.798	72.458	163.059	87.256

[अनुवाद]

एयरलाइंसों के वित्तीय विश्लेषण के लिए पृथक-स्कंध

1905. श्री जोस के. मणि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमेरिका में फेडरल एवियेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तर्ज पर एयरलाइंसों की वित्तीय हालत की निगरानी और आकलन करने के लिए एक पृथक् स्कंध बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) की संभावित भूमिका क्या होगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अधिभारित विश्वविद्यालय

1906. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या मानव संसाधन विकास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में

बड़ी संख्या में महाविद्यालयों और छात्रों के होने के कारण अधिभारित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रबंधनों को दो भागों या तीन भागों में बांट कर उन्हें भार में राहत देने के लिए प्रो. एस.पी. त्यागराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिष्ठा/साख का निर्माण करने के लिए समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसने विश्वविद्यालयों पर संबंधन 'अधिभार' संबंधी निर्णय करने हेतु किसी मानक को निर्धारित नहीं किया है। देश में 108 संबद्ध विश्वविद्यालय हैं (कुल 248 में से) जिनमें प्रत्येक के साथ 100 से अधिक कॉलेज संबद्ध हैं। संबद्ध कॉलेजों की अत्यधिक संख्या के कारण, इन विश्वविद्यालयों को इन कॉलेजों के प्रबंधन अत्यधिक समय और श्रम लगाना पड़ता है। सबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या और उनके साथ संबद्ध कॉलेजों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) 'संबंधन प्रणाली के सुधार' संबंधी कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए प्रोफेसर एस.पी. त्यागराजन, पूर्व कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, की अध्यक्षता में एक यू.जी.सी. विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि एक विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध कॉलेजों की संख्या लगभग 100 होनी चाहिए। इन सभी ऊपर उल्लिखित 108 विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभिशासित और नियंत्रित विभिन्न राज्य विधानों द्वारा की गई है। इन विश्वविद्यालयों को उनके संबंधित अधिनियमों और संविधियों द्वारा संबंधन शक्तियां प्रदान की जाती हैं और इन विश्वविद्यालयों को दो भागों या तीन भागों में बांटने का निर्णय राज्य सरकारों में निहित है।

विवरण

राज्य	राज्य में संबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या	ऐसे विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	24	4159
अरूणाचल प्रदेश	1	17
असम	4	447
बिहार	8	449
छत्तीसगढ़	9	653
गोवा	1	59
गुजरात	20	1742
हरियाणा	4	592
हिमाचल प्रदेश	4	335
जम्मू और कश्मीर	4	303
झारखंड	6	219
कर्नाटक	23	3322
केरल	5	1001
मध्य प्रदेश	11	1987
महाराष्ट्र	20	3696
मणिपुर	1	77
मेघालय	1	67
मिजोरम	1	28
नागालैण्ड	1	58
ओडिशा	9	1034

1	2	3
पंजाब	6	810
राजस्थान	12	2482
सिक्किम	2	15
तमिलनाडु	25	1577
त्रिपुरा	2	40
उत्तर प्रदेश	21	4339
उत्तराखण्ड	6	397
पश्चिम बंगाल	11	674
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4	207
चण्डीगढ़ संघ राज्य प्रदेश	1	26
पुदुचेरी	1	82
कुल	248	30894

सरकारी आवासों को किराए पर देना

1907. श्री एन. पीताम्बर कुरूप : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आवास किराए पर दे रहे लोगों की पहचान करने के लिए क्या तंत्र है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संपदा निदेशालय के तहत दिल्ली और अन्य स्थानों पर किराए पर देने के ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें जुर्माने लगाए गए थे;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधि की सूचना देने के लिए किसी संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्राधिकृत करने का कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) सामान्य पूल रिहायशी आवासें में उप-किराएदारी का पता लगाने के लिए शिकायतें प्राप्त होने पर तथा स्वयं भी नियमित रूप में औचक निरीक्षण किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय स्थानों, जहां उप किराएदारी के मामलों में शास्तियां लगाई गई, उनकी संख्या निम्नवत है:

वर्ष	दिल्ली	अन्य क्षेत्रीय कार्यालय
2009	213	73
2010	308	62
2011	527	64
2012 (01.01.2012 से 30.11.2012 तक)	284	82

(ग) और (घ) रेजिडेंशियल वैलफेयर एसोसिएशन सहित कोई भी व्यक्ति सामान्य पूल रिहायशी आवासों में उप-किराएदारी के मामले में संपदा निदेशालय को सूचित कर सकता है।

मंगलौर हवाई अड्डे पर घातक तरीके से उतरना

1908. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर हवाई अड्डे पर हाल ही में वर्ष 2010 की तरह की दुर्घटना को रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घातक लैंडिंग का प्रयास करने की जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या यह घटना उसी रनवे, उसी हवाई अड्डे, उसी वायु मार्ग और उड़ान संख्या पर हुई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (च) दुबई-मंगलौर सेक्टर पर IX-814 उड़ान का प्रचालन करते समय मंगलौर हवाईअड्डे पर दिनांक 14 अगस्त, 2012 को मैसर्स एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के बी-737-800 विमान वी.टी. -ए एक्स ई की अण्डरशूट लैंडिंग की घटना हुई। उड़ान संख्या, वायुमार्ग और अवतरण के लिए प्रयुक्त रनवे वर्ष 2010 में हुई मंगलौर विमान दुर्घटना के समान था।

सरकार ने इस घटना को गंभीर घटना के रूप में वर्गीकृत किया है और इसकी जांच के लिए समिति का गठन किया है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

सरकार ने उद्योग तथा स्टेकधारकों से विशेषज्ञ सदस्यों के साथ नागर विमानन संरक्षा परामर्श परिषद (सी.ए.एस.ए.सी.) का गठन किया है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

सरकार ने उद्योग तथा स्टेकधारकों से विशेषज्ञ सदस्यों के साथ नागर विमानन संरक्षा परामर्श परिषद (सी.ए.एस.ए.सी.) का गठन किया है। एप्रोच तथा लैंडिंग की मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के सख्ती से अनुपालन पर बल देते हुए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 01.06.2010 को 2010 का प्रचालन परिपत्र-12 जारी किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विमान की स्थिर और सुरक्षित लैंडिंग होगी।

[हिन्दी]

जयपुर में मैट्रो रेल के लिए सहायता

1909. **श्री राम सिंह कस्वां :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर में प्रस्तावित मैट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता देने का अनुरोध किया गया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ऐसी मैट्रो रेल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई नीति/दिशानिर्देश बनाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) मांगी गई अपेक्षित सहायता की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

करोड़ रूपए में

स्त्रोत	अपेक्षित प्रस्तावित राशि
जे आई सी ए/ ए डी बी ऋण/ मार्किट से उधार	1781.00
भारत सरकार अंशदान	630.00

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा यह प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति-2006 में मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए परियोजना की पूंजी लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक इक्विटी अथवा व्यवहार्यता अंतराल कोष के रूप में वित्तीय सहायता हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

महाविद्यालयों की स्थापना

1910. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में महाविद्यालयों की स्थापना करने संबंधी आधे से अधिक आवेदनों को अस्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के निर्णय का आन्ध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों के महाविद्यालयों के छात्रों पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश राज्य में कॉलेज स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन और पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/अस्वीकृत आवेदन का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त हुए आवेदनों की कुल संख्या	अनुमोदित संस्थानों की कुल संख्या	अस्वीकृत संस्थानों की कुल संख्या
2010-11	248	104	144
2011-12	76	32	44
2012-13	42	27	15

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित संस्थान अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2012-13 पर और उसमें निर्धारित क्रियाविधियों पर आधारित हैं। यदि स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित कोई संस्थान अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) नए संस्थानों का अनुमोदन करने का प्रभाव यह है कि इंजीनियरी शिक्षा में छात्रों की पहुंच बढ़ी है।

एयर इंडिया के अधिकारियों की मांग

1911. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के वरिष्ठ, मध्यम दर्जे के प्रबंधन और तकनीकी कर्मचारियों की विदेशी एयरलाइनों में काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशी एयरलाइनों सहित इंडिया से त्यागपत्र देकर अन्य एयरलाइनों में नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसे निष्क्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एयर इंडिया के पास यह सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) एयर इंडिया के जिन कर्मचारियों ने 2009 और 2012 के दौरान त्याग पत्र दिया है, उनका श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, त्याग पत्र के पश्चात, उनके रोजगार की स्थिति के बारे में एयर इंडिया के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

एयर इंडिया के जिन कर्मचारियों ने 2009 और 2012 के दौरान त्याग पत्र दिया है, उनका श्रेणी-वार ब्यौरा

क्र.सं.	श्रेणी	2009	2010	2011	2012	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार्यपालक पायलट	2	1	7	1	11

1	2	3	4	5	6	7
2.	साधारण श्रेणी के अधिकारी (उप महाप्रबंधक तथा इससे ऊपर)	–	–	1	1	2
3.	तकनीकी अधिकारी	2	1	–	4	7
4.	साधारण श्रेणी के अधिकारी (सहायक महाप्रबंधक तक)	5	10	13	7	35
5.	लाईन पायलट	1	–	20	2	23
6.	वायुयान इंजीनियर	2	1	–	–	3
7.	केबिन कर्मीदल	28	15	34	34	111
8.	तकनीशियन	7	13	11	17	48
9.	स्टाफ (ग्रेड 3 से 9)	9	8	9	7	33
10.	स्टाफ (ग्रेड तथा 2)	4	10	8	6	28
	कुल	60	59	103	79	301

दोहरी डिग्री कार्यक्रम

1912. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) बारहवीं पंचवर्षीय योनजा में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में संयुक्त कार्यक्रम तथा दोहरे डिग्री कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित भारतीय प्रबंध संस्थानों ने नीचे सारणी में उनके नामों के सामने सूचित किए गए संस्थानों के साथ दोहरे डिग्री कार्यक्रम सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखा है:

क्र.सं.	आई.आई.एम.	सहयोग
1	2	3
1.	अहमदाबाद	(i) ई.एस.एस.ई.सी. बिजनेस स्कूल, फ्रांस (ii) यूनिवर्सिटी ऑफ बोकोनि, इटली

1	2	3
		(iii) एच.ई.सी. स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस
2.	कलकत्ता	ई.एस.सी.पी.-यूरोप
3.	लखनऊ	ई.एस.सी.पी.-ई.ए.पी. यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस
4.	शिलांग	ओसियन यूनिवर्सिटी, चीन
5.	उदयपुर	क्रेनर्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पुरदयू यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए.

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट निधियां आवंटित नहीं की है।

उच्च शिक्षा के लिए नामांकन

1913. श्री शिवराम गौडा : क्या **मानव संसाधन विकास** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उच्च शिक्षा के लिए किए गए बजटीय आवंटन का राज्य-वार ब्यौर क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान आवंटित निधि इस उद्देश्य के लिए पूर्णत: उपयोग में लायी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 (अस्थायी) और 2010-11 (अस्थायी) के दौरान, 18-23 आयु वर्ग में जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में देश में उच्चतर शिक्षा में नामांकित छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) नीचे दिया गया है:-

2008-09	2009-10 (अस्थायी)	2010-11 (अस्थायी)
13.7	15.0	18.8

दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित आंकड़ों पर आधारित उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात 18.8 होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) संशोधित अनुमान (आर.ई.) और वास्तविक खर्च नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

2009-10			2010-11			2011-12		
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
96000.00	7952.00	7794.58	11000.00	9796.58	9356.77	13103.00	12812.00	12641.98

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान, संशोधित अनुमान का उपयोग क्रमशः 98%, 95% और 99% तथा बजट अनुमान का उपयोग क्रमशः 81%, 85% और 96% है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन

1914. **श्री सी. राजेन्द्रन :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए कुल कितना आवंटन किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए निर्धारित इन परिव्ययों के व्यय के पैटर्न में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निधियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) केन्द्रीय क्षेत्रक, केन्द्र प्रायोजित तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीमों के रूप में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सामाजिक क्षेत्रक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए सामाजिक क्षेत्रक में कार्य करने वाले मंत्रालयों के योजना आवंटन तथा व्यय संबंधी और ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों से जड़े मंत्रालय के कुल योजना खर्च मे वर्ष 2009-10 में 1,47,938.33 करोड़ रुपये से वर्ष 2010-11 में 1,76,768.37 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई है। ऐसे मंत्रालयों के आवंटन को वर्ष 2011-12 (बी.ई) में 1,94,321.01 करोड़ रुपये से वर्ष 2012-13 (बी.ई.) में 2,23,053.39 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के निष्पादन की लगातार मानीटरिंग कर रहे है।

विवरण

सामाजिक क्षेत्रक से जुडे मंत्रालयों के योजना आवंटन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	230.95	111.16	207.96	129.41	197.70	230.71	303.86
2.	स्वास्थ्य	19534.00	17646.48	22300.00	20726.44	26760.00	24315.26	30477.00
3.	शिक्षा	36400.00	29640.26	42036.00	43513.62	52060.00	51772.00	61427.00
4.	श्रम व रोजगार मंत्रालय	900.00	791.77	1000.00	1080.44	1300.00	1254.41	2470.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	1740.00	1709.41	2600.00	2008.17	2850.00	2750.00	3135.00
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	80770.00	74309.07	89340.00	74672.63	76800.00	69563.54	76376.00
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2500.00	2448.91	4500.00	4170.56	5375.00	5123.00	5915
8.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	7579.83	4555.15	9421.60	10279.12	7954.78	12826.56	13331.33
9.	जनजातीय मामले मंत्रालय	805.00	616.41	1200.00	1204.87	1430.00	1596.72	1573.00
10.	शहरी विभाग मंत्रालय	5284.15	7627.39	7605.75	8365.81	8054.00	8788.81	9545.20
11.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	7350.00	8482.32	11000.00	10617.30	12650ए00	16100.00	18500.00
	कुल (1 से 11)	163093.93	147938.33	191211.31	176768.37	195431.5	194321.01	223053.39

टिप्पणी: सामाजिक क्षेत्रक के आवंटन एवं व्यय में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के आवंटन एवं व्यय शामिल है--खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, श्रम व रोजगार, अल्पसंख्यक मामले, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, जनजातीय मामले, शहरी विकास और महिला एवं बाल विकास आंकड़ों में आई.ई.बी.आर. शामिल है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

1915. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) प्रधान पीठ के अध्यक्ष ने हाल ही में अधिकरणों के आदेश की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकारों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि वर्ष 1997 के एल. चन्द्र कुमार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वह इस उद्देश्य में विफल हो गया है जिसके लिए प्रशासनिक अधिनियम को लागू किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का कैट के आदेश की समीक्षा करने के उच्च न्यायालयों की शक्तियों को समाप्त करने के लिए संसद में एक उपयुक्त विधेयक लाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दिनांक 07.03.2012 के अपने पत्र द्वारा भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट सं. 215 के मत की पुष्टि की है कि उचित कदम उठाए जाएं ताकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेशों में मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही अपील की जा सके।

(ग) से (च) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जांच-पड़ताल यह देखने के लिए की गई थी कि क्या एल. चन्द्र कुमार के मामले में निर्णय से पूर्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए किसी पुनरीक्षा को दायर किया जा सकता है अथवा संविधान में कोई संशोधन किया जा सकता है। तथापि, इसे कानूनी तौर पर तर्कसंगत नहीं पाया गया था।

एयरपोर्ट मेट्रो

1916. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रैस की छोटी प्रचालन अवधि के दौरान कई हजार टेंशन क्लैम्प्स क्षतिग्रस्त पाए गए और बदले गए थे, जिसके कारण मेट्रो की गति कम की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रैस क्षतिग्रस्त क्लैम्प्स वाले त्रुटिपूर्ण ट्रैक पर चल रही थी और हजारों लोगों का जीवन खतरे में था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर टेंशन क्लैम्पों के प्रयोग की स्वीकृति देने वाले विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने क्षतिग्रस्त क्लैम्पों को बदलने में अतिरिक्त व्यय किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गई है और इस लाइन का प्रचालन कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डी.एम.आर.सी.) ने सूचित किया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर लगभग 11000 टेंशन क्लैम्पे टूटी हुई पाई गई तथा उन्हें जनवरी से फरवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान बदला गया।

(ग) और (घ) जी नहीं। डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि मैट्रो खराब क्लैम्पों वाले खराब ट्रैक पर नही चल रही थी। जैसे ही दैनिक रात्रि पैट्रोलिंग के दौरान कुछ टूटे हुए टैंशन क्लैप्पों को देखा गया, ग्राही कंसेशनर द्वारा अतिरिक्त व्यक्तियों की तैनाती कर सभी टैंशन क्लैम्पों के निरीक्षण के साथ-साथ गहन पैट्रोलिंग शुरू की गई तथा कैक टैंशन क्लेम्पों को तत्काल बदला गया। अतः यात्रियों के जीवन को कोई खतरा नहीं था। इसके अतिरिक्त ट्रेन की गति को भी 105 कि.मी. प्रति घंटे से घटाकर 80 कि.मी. प्रति घंटा किया गया, जिससे टैंशन क्लैम्पों के टूटने कीं घटनाओं में कमी हई।

(ङ) रेल मंत्रालय ने ट्रैक ढ़ांचे को अंतिम अनुमोदन रेल डिज़ायन मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) द्वारा डी.एम.आर.सी. के जरिए ट्रेक फार्म प्रस्ताव की जांच करने के बाद दिया था।

(च) और (छ) डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि उन्होंने खराब क्लैम्पों को बदलने पर कोई व्यय नहीं किया हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था और स्थापना मैसर्स डी.ए.एम.ई.पी.एल. द्वारा की गई तथा उनका प्रतिस्थापन भी उन्होंने अपने स्पलायरों के माध्यम से ही किया। लाइन को पुनः खोलने का आवेदन मैट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सी.एम.आर.सी.) को दिनांक 19.11.2012 प्रस्तुत किया जा चुका है।

पी.आर.आई.एस. का कार्यान्वयन

1917. **श्री वैजयंत पांडा :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अपने/कार्मिकों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पी.आर.आई.एस.) को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय मंत्रालयों ने पी.आर.आई.एस. को लागू करने के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक एक्सेस कन्ट्रोल प्रणाली को लगा दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इन प्रणालियों को लगाने में कितना खर्च आया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां।

(ख) कार्य निष्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना (पी.आर.आई.एस.), केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लक्षित कार्यनिष्पादन के आधार पर नियमित वेतन के अतिरिक्त गैर योजना बजटीय बचतों में से धन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) कुछ मंत्रालयों/विभागों ने अपने कार्यालयों में बायोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण प्रणाली शुरू की है। समयबद्धता को लागू करने के लिए आवश्यक मानदंड विकसित किए जाएं।

वी.आई.पी. संदर्भ की स्वीकृति

1918. श्रीमती रमा देवी :
श्री रतन सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों सहित वी.आई.पी. संदर्भों के मंत्रियों के विभिन्न अधिकारियों/मंत्रालयों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विद्यमान दिशानिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार से संबंधित प्राप्त ऐसे पत्रों की संख्या कितनी है;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) इसके क्या परिणाम रहे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (छ) केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका का पैरा सं. 63 और 66 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के शीघ्रातिशीघ्र उत्तर देने से संबंधित है। केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा सं. 63(1) में यह उल्लेख है कि 'संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए' तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा सं. 66(1) में यह उल्लेख है कि 'अन्य बातों के साथ-साथ संसद सदस्य से प्राप्त प्रत्येक पत्र की पावती 15 दिनों के भीतर दी जाए और पावती भेजने के अगले 15 दिनों के भीतर पत्र का उत्तर दिया जाए।

प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (क) सभी मंत्रालयों में संसद सदस्यों से प्राप्त वी.आई.पी. पत्रों के आंकड़े/सूचना और संबंधित मंत्रालयों द्वारा चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई; (ख) मंत्रालयों-विभागों के भ्रष्टाचार के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के आंकडें/सूचना तथा ऐसे पत्रों पर संबंधित मंत्रालयों/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी का केंद्रीयकृत रूप से रख-रखाव नहीं करता है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विशेषकर संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती देने और उनका शीघ्रातिशीघ्र उत्तर देने के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करने की आवश्यकता के बारे में मंत्रालयों/विभागों को जानकारी देने के लिए समय-समय पर उन्हें पत्र लिखता रहता है। विशेष रूप से केन्द्रीय मंत्रियों से संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान की प्रगति को आवधिक रूप से मॉनीटर करने के लिए अपने संबंधित मंत्रालयों में तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मंत्रालय में दिनांक 1.12.2010 को कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/4/2011 स्था. (ए) भी जारी किया गया था जिसमें केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया था कि अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में वर्णित अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए। विधिवत जांच के बाद इन अनुदेशों के किसी प्रकार का उल्लंघन सिद्ध होने पर संबंधित सरकारी सेवक नियमानुसार उपयुक्त दंड का भागी होगा।

उल्लेखनीय है कि सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को पुनः दिनांक 9.10.2012 को अ.शा. पत्र सं. 11013/4/2011 स्था. (ए) लिखा था जिसमें उनसे अनुरोध किय गया था कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1.12.2011 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अनुदेशों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए वे आवधिक रूप से इन अनुदेशों को दोहराएं तथा अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर और अधीक्षकों के सम्मेलन में इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करें।

भारी दुर्लभ मृदा खनिजों का निर्यात

1919. **श्री धनंजय सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोनाज़ाइट और इल्मेनाइट जैसी भारी धातुओं के खनन के लिए लाइसेंस धारक खनन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान इल्मेनाइट और मोनाज़ाइट तत्व वाले थोरियम सहित भारी दुर्लभ मृदा खनिजों का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत थोरियम अथवा इल्मेनाइट और मोनाज़ाइट तत्व वाले थोरियम के निर्यात का निषेध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तमिलनाडु और केरल के तटों से थोरियम व अन्य भारी दुर्लभ खनिजों के गैर-कानूनी खनन और निर्यात की सूचना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) मोनाज़ाइट और इल्मेनाइट जैसे भारी खनिजों के खनन के लिए लाइसेंसधारी खनन कंपनियों के ब्यौरे खान मंत्रालय के भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा रखे जाते हैं। इस संबंध में खान विभाग से प्राप्त की गई सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) ''थोरियम युक्त इल्मेनाइट'' के नाम, विवरण अथवा संदर्भ वाली ऐसी कोई भी सामग्री वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इल्मेनाइट एक ऐसा खनिज है जो प्राकृतिक रूप में पुलिन बालू खनिजों के साथ संयुक्त रूप से और उनके एक भाग के रूप में पाया जाता है। मोनाज़ाइट भी उसी पुलिन बालू खनिज कच्ची सामग्री के एक भाग के रूप में विद्यमान होता है। थोरियम प्राकृतिक रूप में विद्यमान नहीं होता है और यह एक ऐसा उत्पाद है जो मोनाज़ाइट को संसोधित करके प्राप्त किया जाता है। तथापि, संसाधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इल्मेनाइट में मोनाज़ाइट के एक 'संदूषक' के रूप में कुछ प्रतिशत विद्यमान होने की संभावना रहती है, जिसका कारण यह है कि इल्मेनाइट और मोनाज़ाइट दोनों का निष्कर्षण उसी आधार कच्ची सामग्री अर्थात् पुलिन बालू से

किया जाता है, अर्थात् देश से बाहर किसी उत्पाद जिसमें इल्मेनाइट जैसे भारी खनिज ओर मोनाज़ाइट जैसे विरल मृदा खनिज आदि शामिल हैं, के कुल निर्यात के संबंध में पुलिन बालू सूचना वाणिज्य विभाग द्वारा रखी जाती है। वाणिज्य विभाग से प्राप्त की गई सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, ''थोरियम युक्त इल्मेनाइट'' के नाम, विवरण अथवा संदर्भ वाली कोई भी सामग्री वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इल्मेनाइट एक ऐसा खनिज है जो प्राकृतिक रूप में विद्यमान होता है। भारी खनिजों युक्त पुलिन बालू से इल्मेनाइट जोकि वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादित किया जाने वाला मुख्य उत्पाद है, की पृथक्करण की प्रक्रिया के दौरान, ऐसी संभावना होती है कि मोनाज़ाइट की कुछ प्रतिशतता इल्मेनाइट में रह जाए। इल्मेनाइट का उत्पादन ऐसी मोनाज़ाइट अशुद्धता के पूर्णतः (100%) बिना करना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा विकिरण संरक्षण नियम, 2000 के नियम 3,5 और 6 के अंतर्गत ''ठोस सामग्री में रेडियोन्यूक्लाइड का अपवर्जन, छूट और अनुमति'' के संबंध में जारी किए गए निर्देश संख्या 01/2010 के अनुसार, इल्मेनाइट में मोनाज़ाइट की मात्रा अधिक से अधिक 0.25% हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मोनाज़ाइट प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक भारी खनिज है जो पुलिन बालू में मौजूद होता है। मोनाज़ाइट को संसोधित करने से थोरियम नामक एक उत्पाद उत्पादित होता है। मोनाज़ाइट और थोरियम को धातु, मिश्र धातु, रासायनिक यौगिन अथवा सांद्र अथवा किसी भी पदार्थ के रूप में, परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत विहित पदार्थों की अनुसूची में ''विहित पदार्थ'' माना जाता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 14,16 और 30 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के अतिरिक्त किसी विहित पदार्थ का अर्जन, उत्पादन, अधिग्रहण, उपयोग, निपटान, निर्यात अथवा आयात निषेध है।

(ङ) और (च) सरकार को तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों से थोरियम और अन्य भारी खनिजों के अवैध रूप से खनन करने और उनका निर्यात करने के संबंध में कोई सरकारी रिपोर्ट अथवा सूचना नहीं मिली है। तथापि, हाल ही में विगत में, कुछेक प्रेस रिपोर्टें और अन्य पत्र इस मामले में प्राप्त हुए हैं। किसी खनिज और पुलिंग बालू खनिज के लिए खनन पट्टे की अनुमति देने के संबंध में विशेष रूप से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है; तत्संबंधी राज्य सरकारों द्वारा इच्छुक पक्षकारों से पुलिन बालू खनिजों के संबंध में खनन संबंधी पट्टे को लेने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें वे भारत सरकार के खान मंत्रालय को उनकी संस्तुति के लिए प्रेषित करते हैं। यदि खनन संबंधी पट्टे के आवेदन पत्र में इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कन, ल्यूकॉक्सीन, गार्नेट, सिलिमेनाइट और मोनाज़ाइट जैसे परमाणु खनिजों का खनन शामिल होता है, खान मंत्रालय, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग से ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' (एन.ओ.सी.) की मांग करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र करने के बाद, खान मंत्रालय राज्य सरकारों को सिफारिशें जारी करता है, जो आवेदन कों को खनन पट्टे के लिए अनुमति अथवा अस्वीकृति जारी करते हैं। तत्संबंधी राज्य सरकारों के खान और भूविज्ञान निदेशक, प्रत्येक राज्य में खनन संबंधी कार्य कलापों पर नियंत्रण रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन पट्टाधारक द्वारा संगत कानूनों का अनुपालन किया जा रहा है। अतः, किसी राज्य में किसी भी खनिज के अवैध रूप से खनन का पता लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के प्राधिकारियों की है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद पुलिन बालू खनन सुविधाओं का अपेक्षित विनियामक निरीक्षण किया जाता है और परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए.एम.डी.) को पूर्ण रूप से शामिल करते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संबंध में निर्णय लिया गया है। मोनाज़ाइट और थोरियम के अवैध रूप से निर्यात करने के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग किसी भी सामग्री का अवैध रूप से निर्यात करने को रोकने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह पुष्टि की है कि, विकिरण संसूचन उपस्कर जिसका विनिर्माण इस समय इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.एल) द्वारा किया जा रहा है, अगले वर्ष विभिन्न समुद्र पत्तनों पर स्थापित करके, पुलिन बालू खनिज की निर्यात खेपों में मोनाजाइट के अस्वीकार्य स्तरों की मौजूदगी का पता आसानी से लगाया जा सकेगा।

विवरण-I

खनिज बालू/मोनाज़ाइट/इल्मेनाइट/रूटाइल का उत्पादन करने वाले खनन पट्टों की सूची

क.सं.	पट्टा धारक का नाम	गांव	जिला
1	2	3	4
केरल			
1.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	चावरा एवं नींडकरा	कोल्लम
2.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	चवरा, भागम एवं तेक्कुम	कोल्लम
3.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	पानमाना, अलापड एवं अयनिवेलिक्कुलंगरा	कोल्लम
4.	केरल मिनरल्स एंड मैट्लस	पानमाना, चवरा	कोल्लम
ओडिशा			
1.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	माटिखाल	गंजाम
तमिलनाडु			
1.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	कीलमिडालम	कन्याकुमारी
2.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	मणवालकुरिच्चि लक्ष्मीपुरा एवं कुलच्चल	कन्याकुमारी
3.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	मणवालकुरिच्चि	कन्याकुमारी
4.	वी.वी. मिनरल्स	अलगप्पपुरम	कन्याकुमारी
5.	वी.वी. मिनरल्स	अलगप्पुरम	कन्याकुमारी
6.	वी.वी. मिनरल्स	कन्याकुमारी	कन्याकुमारी
7.	वी.वी. मिनरल्स	कीलमिडालम	कन्याकुमारी
8.	वी.वी. मिनरल्स	मिडालम	कन्याकुमारी
9.	वी.वी. मिनरल्स	मिडालम	कन्याकुमारी
10.	वी.वी. मिनरल्स	वायपर	तुत्तुक्कुडि
11.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी लिमिटेड (इंडिया)	मनप्पाडु	तुत्तुक्कुडि
12.	इंडियन गार्नेट सैडस कंपनी	पडुक्कप्पत्तु	तुत्तुक्कुडि
13.	इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंडिया	वेम्बर एवं पेरियसामीपुरम	तुत्तुक्कुडि
14.	वी.वी मिनरल्स	चेट्टिकुलम	तिरूनेल्वेलि

क्षेत्र (हैक्टेयर)	स्वीकृति की तारीख	निष्पादन की तारीख	खनिजों का नाम
5	6	7	8
67	21/10/1998	19/04/1999	मोनाज़ाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल
102.77	15/03/2006	11/5/2006	खनिज बालू
180	8/6/2007	7/6/2011	खनिज बालू
203.8	11-दिसम्बर-72	9-जुलाई-85	खनिज बालू
2464.05	लागू नहीं	27/10/2005	इल्मेनाइट
29.78	21/09/1977	15/10/1979	मोनाज़ाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल
141.23	12/8/1981	27/06/1984	मोनाज़ाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल
7.06	1/11/1968	25/05/2001(नवीनीकरण)	मोनाज़ाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.22	21/01/2004	21/02/2004	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.08	21/01/2004	21/02/2004	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.07	21/01/2004	21/02/2004	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.42	31/01/2006	17/03/2008	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
0.7	31/01/2006	17/03/2008	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.63	10/3/2004	18/03/2004	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.18	18/04/2006	3/5/2006	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
5	1/8/2001	6/2/2002	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
16.93	लागू नहीं	7/2/1994	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
36.66	27/09/2011	4/10/2011	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.19	20-अक्तूबर-05	15-जुलाई-06	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल

1	2	3	4
15.	वी.वी मिनरल्स	चेट्टिकुलम	तिरूनेल्वेलि
16.	वी.वी मिनरल्स	इरूक्कनतुरै	तिरूनेल्वेलि
17.	वी.वी मिनरल्स	इरूक्कनतुरै (पूर्वी)	तिरूनेल्वेलि
18.	वी.वी मिनरल्स	इरूक्कनतुरै (पश्चिम)	तिरूनेल्वेलि
19.	वी.वी मिनरल्स	के. पुदूर	तिरूनेल्वेलि
20.	एम. रमेश, तूतीकोरिन	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
21.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
22.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
23.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
24.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
25.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
26.	के थंगाराज	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
27.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
28.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
29.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
30.	वी.वी मिनरल्स	कराइचितु पुदूर	तिरूनेल्वेलि
31.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
32.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
33.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
34.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
35.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
36.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
37.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
38.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
39.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
40.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
41.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
42.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि

5	6	7	8
4	19-जनवरी-10	10-मई-10	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
9	10-मई-95	22-जून-95	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
5	17-मार्च-04	11-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
5	5-जून-02	11-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
0.82	5-जून-90	30-जुलाई-90	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
1.13	22-जनवरी-90	17-जुलाई-90	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.77	20-अक्तूबर-05	13-जुलाई-06	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.01	14-जनवरी-03	13-जुलाई-06	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.47	15-जून-02	9-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.47	20-अक्तूबर-05	12-दिसम्बर-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.08	19-जनवरी-10	4-मई-10	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
1.91	24-मई-01	11-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.49	5-मई-95	7-जून-95	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.29	5-जून-02	12-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
7.87	5-मई-95	7-जून-95	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
36.34	19-जुलाई-94	12-नवम्बर-94	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
10.11	12-दिसम्बर-96	3-अप्रैल-97	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.38	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.43	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.53	30-सितम्बर-97	22-अक्तूबर-97	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.85	9-जुलाई-01	22-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
1.01	17-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
1.17	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
0.88	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.37	25-सितम्बर-97	22-अक्तूबर-97	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
0.36	9-जुलाई-01	22-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
0.89	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
0.51	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल

1	2	3	4
43.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
44.	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	कराइचितु उवरि	तिरूनेल्वेलि
45.	वी.वी मिनरल्स	कुडनकुलम	तिरूनेल्वेलि
46.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
47.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
48.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
49.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
50.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
51.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
52.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
53.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
54.	तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
55.	बीच मिनरल्स सैंड कंपनी	कुट्टम	तिरूनेल्वेलि
56.	वी.वी मिनरल्स	लिविन्जीपुरम	तिरूनेल्वेलि
57.	वी.वी मिनरल्स	लिविन्जीपुरम	तिरूनेल्वेलि
58.	वी.वी मिनरल्स	लिविन्जीपुरम	तिरूनेल्वेलि
59.	वी.वी मिनरल्स	लिविन्जीपुरम	तिरूनेल्वेलि
60.	वी.वी मिनरल्स	तिरूवम्बलपुरम	तिरूनेल्वेलि
61.	वी.वी मिनरल्स	तिरूवम्बलपुरम	तिरूनेल्वेलि
62.	वी.वी मिनरल्स	तिरूवम्बलपुरम	तिरूनेल्वेलि
63.	वी.वी मिनरल्स	विजयपति	तिरूनेल्वेलि
64.	वी.वी मिनरल्स	विजयपति	तिरूनेल्वेलि
65.	वी.वी मिनरल्स	विजयपति	तिरूनेल्वेलि
66.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	विजयपति	कन्याकुमारी
67.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	विजयपति	कन्याकुमारी
68.	वी.वी. मिनरल्स	गोपालापुरम	मदुरै
69.	वी.वी मिनरल्स	मुरूगनेरि	मदुरै

5	6	7	8
1.6	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
1.03	9-जुलाई-01	23-अक्तूबर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.47	20-अक्तूबर-05	12-दिसम्बर-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.64	12-जुलाई-95	17-मार्च-95	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.87	16-फरवरी-01	12-सितम्बर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.43	1-मार्च-04	5-अगस्त-04	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.76	31-जनवरी-01	11-सितम्बर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.9	31-जनवरी-01	11-सितम्बर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.6	31-जनवरी-01	11-सितम्बर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.73	18-जनवरी-01	19-फरवरी-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.15	18-जनवरी-01	12-सितम्बर-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.36	10-जुलाई-97	20-जुलाई-98	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.47	18-जनवरी-01	19-फरवरी-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
0.96	15-सितम्बर-04	11-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.1	17-मार्च-04	11-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.79	23-अगस्त-04	11-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.36	23-अगस्त-04	11-अप्रैल-05	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.38	9-मार्च-01	17-अगस्त-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
2.03	18-अप्रैल-04	23-मई-06	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.06	18-अप्रैल-06	25-मई-06	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.8	9-मार्च-01	17-अगस्त-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
4.51	9-मार्च-01	17-अगस्त-01	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
5.03	6-सितम्बर-00	28-सितम्बर-00	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
13.24	28-अक्तूबर-78	28-सितम्बर-79	मोनाज़ाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल
67	21-अक्तूबर-98	19-अप्रैल-99	मोनाज़ाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.16	31-जनवरी-06	28-फरवरी-06	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल
3.46	31-जनवरी-06	28-फरवरी-06	गार्नेट, इल्मेनाइट और रूटाइल

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के लिए भारत द्वारा विरल मृदा खनिजों का निर्यात

आई.टी.सी.एच.एस.	मद का विवरण	मात्रा(किलोग्राम)
25085032	सिलीमेनाइट सूक्ष्मक (सिलीमेनाइट बालू सहित)	8835484
25132030	प्राकृतिक गार्नेट	428719479
25132090	अन्य प्राकृतिक अपघर्षक	45891711
25309040	विरल मृदा धातु के अयस्क तथा सांद्र	24000
26122000	थोरियम अयक तथा सांद्र (स्त्रोत आई.आर.ई.एल.)	4000
26140010	असंसाधित इल्मेनाइट	824185630
26140020	इल्मेनाइट, अपग्रेडिड ग्राउंड इल्मेनाइट (इल्मेनाइट सहित सज्जीकृत इल्मेनाइट)	55337211
26140031	रूटाइल बालू सहित विरल मृदा ऑक्साइड	6695931
26140039	अन्य रूटाइल	4012
26140090	अन्य टाइटेनियम अयस्क तथा सांद्र	26757940
26151000	ज़र्कोनियम अयस्क तथा सांद्र	43533383
26159010	वैनेडियम अयस्क तथा सांद्र	1250000
26159020	नायोबियम अथवा टैन्टेलम अयस्क तथा सांद्र	522657

असैनिक परमाणु सहयोग समझौता

1920. श्री वरुण गांधी :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और कनाडा के बीच हुए द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग समझौते के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कनाडा भारत को परमाणु संयंत्र बेचने का इच्छुक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कनाडा और आस्ट्रेलिया यूरेनियम परमाणु ईंधन ऊर्जा निर्यात करने पर सहमत हो गए हैं बशर्ते सरकार उन्हें अपने परमाणु सामग्री के उपयोग की जांच करने की अनुमति प्रदान करे; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) भारत सरकार तथा कनाडा सरकार ने जून, 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कनाडा यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग पर सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये थे।

परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग पर सहयोग संबंधी भारत कनाडा करार, 2010 के प्रावधानों के अनुसार भारत तथा कनाडा के बीच व्यापक सहयोग की परिकल्पना की गई है।

4-9 नवम्बर, 2012 को कनाडा के प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग पर सहयोग संबंधी भारत-कनाडा करार के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त व्यवस्था पर आद्यक्षर किये थे।

15-17 अक्तूबर, 2012 को आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री जूलिया गिलार्ड की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने यह घोषणा की कि भारत तथा आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग करार पर वार्ता प्रारम्भ करेंगे।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति के लिए सीवीसी द्वारा एनओसी

1921. श्री हर्ष वर्धन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के पूर्व सीवीसी द्वारा एनओसी जारी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों, जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान सीवीसी द्वारा एनओसी जारी किया जाना था, की संख्या के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) उन मामलों की कुल संख्या कितनी है जिनमें सीवीसी द्वारा इस संबंध में चयनित अधिकारियों के कार्यग्रहण की तिथि के पश्चात् अनुमति प्रदान की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी सहित) के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के मामले में सतर्कता अनापत्ति सीवीसी से तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के मामले में पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त की जाती है।

(ख) सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशकों की पिछले तीन वर्षों में की गई नियुक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

2009-10	:	92
2010-11	:	96
2011-12	:	142

नियुक्तियों के ऐसे मामलों में, सीवीसी अनापत्ति/पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाता है जो इस पर निर्भर करता है कि क्या अभ्यर्थी को सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भीतर से अथवा गैर-सरकारी स्रोतों से नियुक्त किया जा रहा है।

(ग) नियुक्ति किए जाने के पूर्व सीवीसी अनापत्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाती है, चयनित अधिकारियों के कार्यभार-ग्रहण की तिथि के पश्चात सीवीसी अनापत्ति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों में विद्यालय छोड़ने की दर

1922. श्री के.पी. धनपालन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों में विद्यालय छोड़ने की दर राज्य-वार क्या है;

(ख) इन समुदायों से संबंधित छात्रों में विद्यालय छोड़ने की उच्च दर के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) 2008-09, 2009-10 (अनंतिम) और 2010-11 (अनंतिम) के दौरान कक्षा I-V तथा कक्षा I-X के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रों के अध्ययन बीच में छोड़ने की दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) अध्ययन बीच में छोड़ने की दर अधिक होने के कारण अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना और सुविधाएं, प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात;

गृहकार्यों अथवा अन्य प्रकार के कार्यों में लगे बच्चे, मौसमी प्रवर्जन और अन्य सामाजर्थिक कारक हो सकते हैं।

(ग) सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य पूरा करने हेतु सतत रूप से प्रगति कर रही है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन कार्यढांचे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के समनुरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदण्डों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में नामांकन और बच्चों को स्कूल में रोकने में वृद्धि हो सके।

स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल अवसंरचना और सुविधाओं को सुदृढ़ करना, उन आवासीय स्थानों, जहां पर नियमित स्कूल नहीं हैं, में बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण करना, अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करना, शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना, बच्चों की पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों की व्यवस्था करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय के लिए संगत निर्धारित प्रावधानों की व्यवस्था करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की व्यवस्था है। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि करने की दृष्टि से मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षा की सुलभता में महिला-पुरूष संबंधी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं को अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय को माध्यमिक स्कूल में स्तरोन्नत करने की व्यवस्था है। अध्ययन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया, विशेष कोचिंग/उपचारात्मक शिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम जैसे कई अन्य उपाय किए गए हैं।

विवरण-I

प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V) पर अध्ययन बीच में छोड़ने की दर

क्र .सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति छात्र			अनुसूचित जनजाति छात्र		
		2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.2	18.5	19.6	39.8	37.0	36.8
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	100.0	41.5	41.5	43.7
3.	असम	6.9	26.9	26.2	-19.8	33.0	25.7
4.	बिहार	50.1	50.4	38.8	4.0	10.9	27.1
5.	छत्तीसगढ़	29.1	35.5	44.7	37.8	39.2	40.3

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	-25.6	14.9	15.1	-122.6	-80.6	-
7.	गुजरात	46.9	45.2	45.2	52.6	48.0	48.0
8.	हरियाणा	-5.7	-5.1	2.2	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	15.1	5.2	7.3	3.5	-3.3	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-23.4	-3.2	-	4.7	29.8	29.8
11.	झारखंड	20.1	33.2	40.6	29.9	37.5	37.5
12.	कर्णाटक	7.1	16.3	14.3	5.4	16.7	6.9
13.	केरल	-7.5	-7.2	-	-13.6	-14.8	-
14.	मध्य प्रदेश	18.5	24.0	28.9	17.8	20.3	37.1
15.	महाराष्ट्र	21.8	22.8	22.7	33.2	23.8	21.1
16.	मणिपुर	35.5	37.3	29.3	52.2	57.9	51.3
17.	मेघालय	15.3	12.8	17.7	52.9	52.1	54.6
18.	मिजोरम	95.5	46.9	-	40.1	46.5	38.4
19.	नागालैंड	-	-	-	9.8	39.8	39.8
20.	ओडिशा	25.7	19.1	15.7	35.2	38.9	22.1
21.	पंजाब	23.5	9.4	9.8	-	-	-
22.	राजस्थान	50.7	50.9	50.5	39.5	50.4	49.4
23.	सिक्किम	52.0	27.9	31.9	37.4	21.5	19.1
24.	तमिलनाडु	-29.1	-8.6	-	-57.1	8.2	-
25.	त्रिपुरा	8.9	5.9	15.3	32.5	37.8	41.5
26.	उत्तर प्रदेश	31.9	37.7	26.0	-158.8	-160.9	-
27.	उत्तराखंड	34.4	31.0	27.8	15.9	25.2	16.3
28.	पश्चिम बंगाल	22.6	21.4	25.9	49.9	42.2	28.3

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–		–	22.7	4.76	0.2
30.	चंडीगढ़	-52.7	-50.1	–	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	21.9	12.1	14.6	24.6	20.2	12.0
32.	दमन और दीव	–	0.7	1.8	-68.2	7.8	5.0
33.	दिल्ली	8.9	22.9	16.3	-17.3	19.2	24.1
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	6.1	12.1	9.0
35.	पुदुचेरी	-5.7	-6.3	–	–	–	
	भारत	26.7	29.3	26.7	31.3	34.5	35.6

(-) का अर्थ है कि अध्ययन बीच में छोड़ने की दर की गणना करने के लिए कोई अ.जा./अ.ज.जा. अथवा वांछित डाटा उपलब्ध नहीं है।

नकारात्मक दर स्कूल में लेटरल एंट्री या कक्षा दोहराने वाले छात्रों के कारण है।

विवरण-II

माध्यमिक स्तर (कक्षा I-X) पर अध्ययन बीच में छोड़ने की दर

क्र .सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति छात्र			अनुसूचित जनजाति छात्र		
		2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.2	58.2	49.7	81.8	76.8	72.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	100.0	66.1	65.7	63.5
3.	असम	83.9	82.0	–	83.6	83.1	–
4.	बिहार	88.4	85.4	79.8	98.6	97.7	71.1
5.	छत्तीसगढ़	–	–	59.0	–	–	62.7
6.	गोवा	62.9	71.2	49.8	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	65.0	59.3	64.5	73.9	74.5	77.6
8.	हरियाणा	48.4	18.5	17.0	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	39.6	40.7	32.5	18.0	1.4	2.1
10.	जम्मू और कश्मीर	50.7	49.7	–	65.3	71.9	–
11.	झारखंड[2]	–	–	72.3	–		79.8
12.	कर्नाटक	56.3	56.6	55.6	48.1	50.6	47.0
13.	केरल	-4.2	5.8	6.2	35.2	21.2	29.1
14.	मध्य प्रदेश	63.6	62.3	43.2	82.9	81.7	64.6
15.	महाराष्ट्र	41.8	40.6	38.3	70.2	69.7	69.8
16.	मणिपुर	6.6	10.7	–	71.7	70.0	–
17.	मेघालय	70.6	77.6	78.3	77.5	78.0	79.6
18.	मिजोरम	59.1	62.1	–	68.9	63.4	54.1
19.	नागालैंड	–	–	–	67.3	68.2	68.5
20.	ओडिशा	77.0	75.8	75.1	85.8	85.7	85.6
21.	पंजाब	70.1	58.9	55.7	–	–	–
22.	राजस्थान	75.1	77.2	74.5	70.8	76.1	79.3
23.	सिक्किम	86.9	84.6	75.2	63.7	69.6	52.2
24.	तमिलनाडु	11.2	16.6	10.2	50.4	19.9	31.9
25.	त्रिपुरा	63.7	53.2	47.8	78.7	73.9	71.6
26.	उत्तर प्रदेश	75.7	49.3	57.2	53.9	-41.9	–
27.	उत्तराखंड[3]	–	–	50.2	–	36.0	
28.	पश्चिम बंगाल	77.7	75.5	66.2	87.1	84.9	74.6

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	28.5	45.4	31.9
30.	चंडीगढ़	60.0	56.1	43.3	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	37.4	29.5	28.1	68.6	67.5	63.3
32.	दमन और दीव	–	20.3	–	56.6	58.1	–
33.	दिल्ली	47.6	39.3	0.1	–	2.6	–
34.	लक्षद्वीप	–	.	100.0	29.9	23.6	33.6
35.	पुदुचेरी	11.9	12.9	8.0	–	–	–
	भारत	66.6	59.0	56.0	76.2	75.2	70.9

2008-09 (अनंतिम) और 2009-10 (अनंतिम) के लिए 1. मध्य प्रदेश में शामिल है, 2. बिहार में शामिल है, 3. उत्तर प्रदेश में शामिल है

(-) का अर्थ है कि अध्ययन बीच में छोड़ने की दर की गणना करने के लिए कोई अ.जा./अ.ज.जा. अथवा वांछित डाटा उपलब्ध नहीं है।

नकारात्मक दर स्कूल में लेटरल एंट्री या कक्षा दोहराने वाले छात्रों के कारण है।

[हिन्दी]

बीआरटीएस

1923. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस रैपिड ट्रांजिटपोर्ट सिस्टम के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ख) बीआरटीएस के साथ संबद्ध किए जा रहे संस्थान कौन-से हैं;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया जाना है; और

(घ) इस परियोजना में सम्मिलित एजेंसियां कौन-सी हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) द्रुत जन बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) का उद्देश्य राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) के इस सिद्धांत "लोग चले वाहन नहीं" को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मध्यम घनत्व के समर्पित कोरिडोरों पर सुरक्षित, तीव्र, सस्ता, आरामदायक, विश्वसनीय और सतत जन परिवहन उपलब्ध कराना है।

(ख) केवल बी आर टी एस से संबद्ध कोई विशिष्ट संस्थान नहीं है। तथापि, पर्यावरणीय आयोजना और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी) विश्वविद्यालय; अहमदाबाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी); दिल्ली, शहरी द्रुतजन परिवहन कंपनी लिमिटेड (यू एम टी सी) और शहरी परिवहन संस्थान (आईयूटी) इससे संबंधित संस्थान हैं।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीरकण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत स्वीकृत 21 बीआरटीएस परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 5211.60 करोड़ रू. (अनुमानित) है। जिसमें से, भारत सरकार का अंश अर्थात् अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) 2373.86 करोड़ रू. (अनुमानित) है।

(घ) उपर्युक्त 21 परियोजनाओं में, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार और आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार शामिल हैं। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम्, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, भोपाल, इंदौर, पुणे, पिम्परी, चिंचवाड़, जयपुर, शहरों के संबंधित नगर निगम और कोलकत्ता मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण इनकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

1924. श्री संजय भोई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगाँवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर हाल में भारी कोताही बरती गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या हैं तथा इस घटना के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी कोताहियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं,

(ख) से (ङ) दिनांक 3.10.2012 की छत्रपति शिवाजी अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में तैनात सी.आई.एस.एफ. और सीमा शुल्क कर्मियों से संबंधित एक घटना की सूचना मिली है। सरकार द्वारा इस मामले की प्रारम्भिक जांच की गई है तथा पाया गया है कि पूरी घटना के समय द्वार संख्या-1 और द्वार संख्या-6 बंद थे, अतः सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया।

एकमुश्त एस.एम.एस. एवं एम.एम.एस. पर प्रतिबंध

1925. श्री एम. आनन्दन :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेंगलुरू के लिए पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने देश में एकमुश्त एस.एम.एस. एवं एम. एस.एस. के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार लगाए गए प्रतिबंध की कोई समीक्षा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बगैर समुचित जांच के मोबाइल कनेक्शन जारी करने वाले मोबाइल आपरेटरों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) सरकार ने, उस समय सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.08.2012 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को, तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित कार्रवाई करने का आदेश दिया:-

(i) समूचे देशभर के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अगले 15 दिनों के लिए बड़ी संख्या में (5 से अधिक) संदेशों (एस.एम.एस.) पर रोक लगाना।

(ii) समूचे देशभर के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अगले 15 दिनों के लिए बड़ी संख्या में (5 के.बी. से अधिक की सामग्री वाले) सभी एम.एम.एस. पर रोक लगाना।

(iii) एस.एम.एस./एम.एम.एस. पर यह प्रतिबंध बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों और रेलवे जैसे संस्थानों के संबंधित लेन-देन संबंधी संदेशों पर लागू नहीं होगा।

सरकार ने, इस संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के बाद, दिनांक 23.08.2012 को बड़ी संख्या में एस.एम.एस./एम.एम.एस. की

अनुमत्य सीमा को बढ़ाकर 'पांच' के स्थान पर 'बीस' करने का निर्णय लिया और अंतत: इन प्रतिबंधों को दिनांक 30.08.2012 को हटा लिया गया।

(ङ) दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं निगरानी (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ फोटो, पहचान, पते (पी.आई.ए) आधार पर अनुपालन की पुन: छानबीन हेतु अन्य सहायक सामग्री सहित ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र/ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सी.ए.एफ)/उपभोक्ता अधिग्रहण प्रपत्र की मासिक नमूना जांच करते हैं। गैर अनुपालना संबंधी मामलों में संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता पर दंड लगाया जाता है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय के दिनांक 27.04.2012 के निर्णय और आदेश के निहित निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 09.08.2012 के आदेश संख्या: 800-09/2010-वी.ए.एस. की मार्फत मोबाइल उपभोक्ताओं का सत्यापन करने के बारे में नवीन कड़े अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

मेट्रो रेल टोकनों की चोरी

1926. श्री तूफानी सरोज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो के टोकनों की चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खोए या चोरी हुए मेट्रो रेल टोकनों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे टोकनों की चोरी या खोने के कारण कितनी राशि की हानि हुई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटैड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि उनकी प्रणाली से कुछ टोकन खो रहे हैं।

(ख) और (ग) डीएमआरसी द्वारा यथा सूचित अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खो गए या चोरी हुए मैट्रो रेल टोकनों की संख्या, तथा इसकी वजह से हुए नुकसान की राशि के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

वर्ष	टोकन नुकसान की संख्या	टोकन नुकसान की राशि (रु.)
2009-10	585,545	12,026,077
2010-11	998,708	16,713,963
2011-12	1,298,639	18,734,106
अप्रैल, 12 सितम्बर, 12	709,985	9,520,899
कुल	3,592,877	56,995,045

(घ) टोकन नुकसान को टोकने के लिए डीएनआरसी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) वर्ष 2002 के दौरान जब प्रणाली शुरू हुई, प्रणाली इतनी उपयुक्त थी कि वह भारत की स्थिति के उपयुक्त थी तथा यात्रियों की आसान आवाजाही में मदद करती थी शारीरिक क्षति को रोकने और टेल गेटिंग को रोका जा सकता था। अब 01.03.2012 से स्टेशनों पर टोकनों की गिनती के लिए प्रणाली में एक संशोधित टोकन मूवमेंट प्रक्रिया आदेश कार्यान्वित किया जा रही है जिसके परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। लोगों को टोकनों के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन/शिक्षित करने/जानकारी देने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

(ii) टोकन में प्रवेश की जानकारी रिकार्ड न होने पर भी टोकनों द्वारा बाहर निकालने के लिए ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) प्रणवाली साफ्टवेयर में संशोधन किया गया है। इससे टेल गेटिंग और निकास द्वारों पर टोकन हानि को नियंत्रित करने में मदद मिली है।

(iii) प्रत्येक मंगलवार को "टोकन बचाओं दिवस" के रूप में मनाया जाता है जिसके दौरान प्रत्येक स्टॉफ को सभी स्रोतों से टोकन इकट्ठा करने/वापस लेने/गणना करने पर बल देने के निदेश दिए जाते हैं।

(vi) यात्रियों से टोकन छुपा कर ले जाने पर निगरानी रखने और टोकनों को जब्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उपभोक्ता सुविधा एजेंट (सीएफए) नियुक्त किए गए हैं।

(v) स्टेशन प्रबंधक/नियंत्रकों को टोकनों की चोरी/हानि को रोकने के विशेषरूप से व्यस्त समय के दौरान एएफसी गेटों की निगरानी के लिए अधिक समय देने के निदेश दिए गए हैं।

(vi) स्टेशनों पर नियमित रूप से घोषणाएं की जाती हैं कि प्रणाली से टोकन ले जाना 'डीएमआरसी नियम' के तहत अपराध हैं''। यह चेतावनी, उपभोक्ताओं की सूचना के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर भी प्रदर्शित की जाती है।

(vii) स्टेशनों पर नियमित अभियान चलाया जाता है तथा रिवेन्यू सैल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें स्टेशनों पर टोकनों की चोरी और उसे रोकने के संबंध में जानकारी दी जाती है।

(viii) यात्रियों द्वारा गलती से ले जाए गए टोकनों को जमा करने के लिए एएफसी गेटों पर एक पारदर्शी बाक्स रखा गया है।

(ix) यात्री जो गेट पर टोकनों को बिना जमा करे ले जा रहे होते हैं, से 200/- रु. का जुर्माना लिया जाता है। टोकन ले जाने वाले 1410 मामलों में अक्टूबर, 2011 से मार्च, 2012 तक जुर्माना के रूप में 2,82,000/ रु. एकत्रित किए गए हैं।

(x) स्मार्ट कार्ड के उपयोग को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना ताकि टोकनों के उपयोग को कम किया जा सके जिससे टोकनों की हानि कम हो। इसके परिणामस्वरूप स्मार्ट कार्ड का उपयोग बढ़कर 64क्र हो गया है।

दिल्ली किराया अधिनियम, 1995

1927. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री रामकिशुन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कब तक लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों के हितों का संरक्षण करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का है जिन्हें ब्रिटिश शासन के पूर्व संपत्तियों का भूस्वामी/मालिक के रूप में परिभाषित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होना था। वर्ष 1995 के अधिनियम के अधिनियमन के तत्काल बाद अधिसूचना जारी नहीं की गई क्योंकि मुख्य रूप से मानित किराया, किराएदारी का पंजीकरण, किरायेदारी की उत्तराधिकारिता, किराए में वृद्धि और किराएदार की बेदखली से संबंधित प्रावधानों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। चूंकि कानूनी प्रक्रिया अभी शुरू की जानी है इसलिए इस स्तर पर किसी नियत समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार की नीति के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्कूलों में शारीरिक दंड

1928. **श्री अवतार सिंह भडाना :**
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ किए गए शारीरिक दुर्व्यवहार के मामलों की संख्या का अनुमान लगाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौर क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से स्कूल के पदाधिकारियों के विरुद्ध बाल दुर्व्यवहार के मामलों से निपटने के लिए कठोर कानून बनाने का है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने स्कूलों ने शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया है; और

(घ) सभी स्कूलों में शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठों का गठन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, राज्य/संघ शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति एवं केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2010-11 के बाद केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के संदर्भ में शारीरिक दण्ड की घटनाओं के पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) इन स्कूलों में शारीरिक दण्ड देने पर कड़ाई से रोक है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा समिति द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधानाचार्यों को पहले ही आवश्यक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधानाचार्यों को यह मॉनीटर करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि इन दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। जहां तक सी.टी.एस.ए. का संबंध है, स्कूल प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापक द्वारा अध्यक्षता वाली स्कूल अनुशासन समिति विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शारीरिक दण्ड के मामलों को मॉनीटर कर रही है।

विवरण

राज्य का नाम	2009-2010			2010-2011			2011-12			2012-13 आज तक		
	केवी	जेएनवी	सीटीएसए	केवी	जेएनवी	सीटीएसए	केवी	जेएनवी	सीटीएसए	केवी	जेएनवी	सीटीएसए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
छत्तीसगढ़		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
दिल्ली		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात		4	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश		–	1	–	–	–		2	–	–	1	–
हरियाणा		–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
झारखण्ड		–	–	–	1	–		–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कर्नाटक		–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–
केरल		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
पुदुचेरी		–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
पंजाब		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
तमिलनाडु		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
त्रिपुरा		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश		–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–
उत्तराखण्ड		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
पश्चिम बंगाल		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
सकल योग		4	2	4	7	1	6	5	1	2	4	–

अरूणाचल प्रदेश में धनराशि का उपयोग

1929. श्री तकाम संजय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य द्वारा केन्द्रीय सहायता के उपयोग के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अरूणाचल प्रदेश में केन्द्रीय सहायता के प्रभावशाली इस्तेमाल की राह में मुख्य बाधकों की पहचान करने के लिए कोई ऐसा आकलन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) योजना आयोग मत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन करता है। 11वीं योजना के दौरान अरूणाचल प्रदेश के राज्य योजना परिव्यय, केन्द्रीय सहायता और वास्तविक व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड रू. में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	केन्द्रीय सहायता (अनुमोदित अनुदान)	अनुमोदित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सहायता	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय/ योजनागत परिव्यय (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007-08	1320	1033.31	78.28	1459.92	110.60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008-09	2265	1886.92	83.32	1801.33	79.53
2009-10	2100	2168.96	103.28	2016.00	96.00
2010-11	2500	2255.60	90.22	2555.11	102.20
2011-12	3200	2421.05	75.66	2942.59	91.96
कुल 11वीं योजना	11385	9765.84	85.78	10774.95	94.64

स्रोत: योजना आयोग और राज्य सरकार।

केन्द्रीय सहायता के तहत निधियां जारी करने से पहले, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा, स्कीम, विशेष दिशानिदेशों के अनुसार, पिछली किश्तों में जारी की गई निधियों के उपयोग का आकलन किया जाता है।

चूंकि अरूणाचल प्रदेश विशेष श्रेणी राज्य है, इसलिए राज्य को विभिन्न शर्तों के तहत परियोजनाओं के लिए विशेष योजनागत सहायता (एस.पी.ए.) भी प्रदान की जाती है। संबंधित विभागों को आवंटित निधियां जारी करने से पहले राज्य सरकार के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, नियमित अंतरालों पर उपयोगिता की प्रगति की जांच करने हेतु निगरानी तंत्र स्थापित करना; तीसरे पक्ष द्वारा मॉनीटरण सुनिश्चित करना, अनिवार्य निविदाएं संचालित करना तथा प्रत्येक परियोजना से संबंधित निगरानी-योग्य लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना अपेक्षित है। योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना पर चर्चाओं के दौरान केन्द्रीय सहायता के उपयोग सहित राज्य योजना स्कीमों के तहत उपलब्धियों की भी समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति

1930. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री पी. सी. गद्दीगौदर :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित समिति ने लोकपाल और लोकायुक्त की तत्काल नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए लोकपाल की नियुक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

काले धन की बुराई से निपटने के लिए वर्तमान कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की जांच-पड़ताल करने के क्रम में अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सरकार को दिनांक 29.03.2012 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि लोकपाल और लोकायुक्त संस्था क्रमशः केंद्र और राज्यों में शीघ्रातिशीघ्र बनाई जाए जिससे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल शीघ्र हो सके और अपराधी को दंड दिया जा सके।

(ख) और (ग) केंद्र में लोकपाल संस्था स्थापित करने और सभी राज्यों में एक समान लोकायुक्त संस्था स्थापित करने के लिए सरकार ने पहले ही लोक सभा में दिनांक 22.12.2011 को "लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011" पुरःस्थापित कर दिया है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 दिनांक 27.12.2011 को लोक सभा

द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में पुर:स्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पदोन्नति में आरक्षण

1931. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महान्यायवादी ने सरकार को सुझाव दिया है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में एस.सी./एस.टी. को आरक्षण संबंधी प्रस्तावित विधेयक में खामियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या संसद में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के बाद हाल में मिले कुछ सुझावों के मद्देनजर प्रस्तावित विधेयक में पदोन्नति में मुसलमानों सहित ओ.बी.सी. एवं गरीब अल्पसंख्यकों को शामिल करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने, एम. नागराज केस के मामले में, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के संबंध में संविधान संशोधनों की वैधता को बनाए रखते हुए, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ पूर्वापेक्षित शर्तें निर्धारित की हैं, नामत: राज्य को प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, वर्ग के पिछड़ेपन तथा प्रशासन की कार्यकुशलता का निरीक्षण करना है। इन पूर्वापेक्षित शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन का विधेयक पुर:स्थापित करना प्रस्तावित किया। प्रस्तावित विधेयक पर भारत के महान्यायावादी की राय मांगी गई थी तथा उन्होंने यह राय नहीं दी थी कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण हेतु संविधान संशोधन विधेयक गलत था।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इस विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 16(4ए) में संशोधन करना है ताकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति में आरक्षण के वर्तमान प्रावधानों को, बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सके।

प्राथमिक स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव

1932. श्री पी. करूणाकरन :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में जाति आधारित भेदभाव बरते जाने, जिसमें कथित रूप से दलित बच्चों को उच्च जाति के बच्चों से अलग बैठने के लिए कहा गया है, के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में 6 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान) में स्कूलों में बच्चों को शामिल करने और बाहर करने के संबंध में एक अध्ययन आरंभ किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में शिक्षण कक्षों में अलग बैठने की व्यवस्था करने की घटनाएं हुई हैं।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भेदमूलक प्रथाओं को काफी गंभीरता से लिया है और भेदभाव को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा 26 अक्टूबर 2012 का वृहत प्रचार और अनुपालन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

शैक्षिक संस्थानों में आत्महत्या के मामले

1933. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री आधि शंकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य शीर्ष संस्थानों में आत्महत्या के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या सरकार विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या रोकने के लिए ऐसे संस्थानों में काउंसिलिंग सत्र प्रारंभ करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी आत्महत्याओं तक पहुंचाने वाली परिस्थितियों के अध्ययन के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कृतक बल गठित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समिति द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(च) स्वीकार एवं अस्वीकार की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ शशी थरूर): (क) देश के विभिन्न अग्रणी संस्थानों में छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आत्महत्याओं के 15 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों की व्यक्तिगत, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए सलाहकार उपलब्ध होते हैं इसके अलावा विभिन्न विभागों में छात्र-परामर्शदाता हैं जो उचित दिशा-निर्देश प्रदान करके उनकी शैक्षिक और अन्य समस्याओं का समाधान करते हैं और उनकी समस्याओं को समय पर निवारण के लिए उनकी संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में लाते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्र-प्रशिक्षण भी हैं और उनकी शैक्षिक समस्याओं से निपटने में उनकी सहायता करते हैं।

(घ) से (च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की 42वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आई.आई.टी. कानपुर के शासी बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. एम. आनंदकृष्णन की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया गया था ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य केन्द्रीय निधियन प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में आत्महत्याओं के कारणों का अध्ययन किया जा सके और उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकें। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसने अन्य बातों के साथ-साथ संस्थाओं में व्यवस्थाओं और संरचना का सृजन करने की सिफारिश की है जिनमें उन व्यवस्थाओं के कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ-साथ संस्थागत तैयारी का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारप्राप्त समिति की स्थापना की भी सुझाव दिया है कि इन सिफारिशों का अनुसरण किया जाए तथा केन्द्रीय निधियनप्राप्त तकनीकी संस्थाओं में परामर्श एवं अन्य सहायता सेवाओं की उपलब्धता संबंधी एक सामान्य डाटाबेस मुहैया कराया जाए, साथ ही आंतरिक परामर्शदाताओं, संकाय तथा परामर्श सेवाओं से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। अधिकार प्राप्त समिति ऐसी वित्तीय सहायता का भी प्राक्कलन कर सकती है जो इस संबंध में किसी केन्द्रीय निधियन प्राप्त तकनीकी संस्था के लिए आवश्यक हो।

कार्यबल की सिफरिशों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के समक्ष इसकी आगामी बैठक में विचार और सिफारिशों के लिए रखा जा रहा है।

सी.डब्ल्यू.जी. फ्लैटों का आवंटन

1934. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल खेल गांव में फ्लैटों के आवंटन में देरी के क्या कारण हैं; और

(ख) उपर्युक्त फ्लैटों को कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि राष्ट्रमण्डल खेल गांव परिसर में निर्मित कुल 1168 फ्लैटों में से, दिल्ली विकास प्राधिकरण के हिस्से के 711 फ्लैट हैं। इन 711 फ्लैटों में से, 110 फ्लैटों की निविदाएं आमन्त्रित की गईं जिनमें से 74 फ्लैटों की बिक्री हो चुकी है। शेष फ्लैटों की बिक्री सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को की जानी है। निजी बिल्डर के भाग में से 28 फ्लैटों की अभी बिक्री

की जानी है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 3703/2011 में "सी.डब्ल्यू.जी. अलॉटी वेल्फेयर एसोसियेशन बनाम डी.डी.ए." नामक मामले में स्थगन आदेश जारी किया गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन हटा लिये जाने के बाद ही इन फ्लैटों की बिक्री की जानी है।

नयी गरीबी रेखा बनाना

1935. श्री अजय कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी भारत के लिए उपभोग पर खर्च की गयी राशि को लेकर नयी गरीबी रेखा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गरीबी परिभाषित करने के लिए वैश्विक रूप से स्वीकार्य एफ.ए.ओ. (खाद्य और कृषि संगठन) के मानदंडों का पालन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एम.पी.सी.ई.) के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। योजना आयोग की गरीबी आकलन प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की गई है। प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अखिल भारतीय स्तर पर 2004-05 के मूल्य पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रूपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रूपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय पर गरीबी रेखा की परिगणना की।

योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है। ये सर्वेक्षण हर 5 वर्ष पर किये जाते हैं। 2004-05 के बाद, 2009-10 में किए गए सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हैं। योजना आयोग ने तेंदुलकर पद्धति का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 66वें दौर (2009-10) के परिवार उपभोग व्यय संबंधी सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग कर वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन किया है। अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रू. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रू. के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के रूप में किया गया है जो पांच सदस्यों की पारिवारिक इकाई के लिए, 2009-10 के मूल्यों पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,365 रू तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 4,300 रू. के मासिक उपभोग व्यय के बराबर है।

(ग) और (घ) तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रस्तावित गरीबी रेखाएं गरीबी रेखाओं के पास खाद्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के मद में प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की जांच, लिए इन व्ययों की तुलना पोषणगत, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य परिणामों के साथ मानदंडात्मक व्ययों की निरन्तरता से करते हुए मान्य की गई हैं। तेंदुलकर समिति ने यह भी कहा है कि:

"यह उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी के मूल मानक को वहन करना जारी रखे हुए हैं, परन्तु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर से पता चलता हैं कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वास्तविक अंतर्ग्रहरण 1776 कैलोरी ही है। यह वास्तविक अंतर्ग्रहण खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत के लिए हाल ही में संस्तुत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1770 कैलोरी के संशोधित मानक के बहुत निकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई गरीबी रेखा के आसपास प्रति व्यक्ति वास्तविक अंतर्ग्रहण 1999 कैलोरी है जो खाद्य तथा कृषि संगठन के मानक से अधिक है।"

[हिन्दी]

सीवीसी एवं सीबीआई को सांविधिक दर्जा

1936. श्री राधे मोहन सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीवीसी एवं सीबीआई को सांविधिक दर्जा एवं स्वायत्तता देने के लिए कोई प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) सरकार के पास केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सीवीसी एक सांविधिक निकाय है तथा यह अपने अधिकार केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, 2003 से प्राप्त करता है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। दोनों संगठनों के पास पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्तों को सूचना

1937. **श्री तथागत सत्पथी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ग्रामीण क्षेत्रों, जहां इंटरनेट उपयोग क्षमता बहुत कम है, में निःशक्त लोगों के लिए सरकारी सूचना उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं कि लाइसेंस देने, न्यूनतम खाद्य का न्यूनतम मजदूरी कार्ड देने वाले कतिपय मंत्रालयों की वेबसाइटों को नियमित रूप से अद्यतम किया जए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(ङ) सरकारी वेबसाइटों के अद्यतनीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) विकलांग लोगों के लाभार्थ सरकारी वेबसाइटों को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस संदर्भ में सरकार ने भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जी.आई.जी.डब्ल्यू.) तैयार किए, जिन्हें फरवरी, 2009 में जारी किया गया और उन्हें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.पी.जी.) द्वारा कार्यालय प्रक्रिया के केन्द्रीय सचिवालय मेनुअल के भाग के रूप में शामिल किया गया। भारतीय पोर्टल (http://www.india.gov.in) को इन दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए दृश्यहीनता वाला कोई व्यक्ति सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे स्क्रीन रीडर्स और मैग्निफायर्स का उपयोग करके इस पोर्टल का लाभ उठा सकता है। इस पोर्टल का हिन्दी रूपान्तरण भी उपलब्ध करा दिया गया है। स्थानीय भाषा का प्रयोग करके विषयवस्तु उपलब्ध कराने हेतु सरकारी वेबसाइटों को विकसित किया गया है। दिशानिर्देशों द्वारा भी सभी बैंडविड्थ और उपकरणों पर वेबसाइटों की सुगम्यता का हल किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कई मंत्रालयों द्वारा वेबसाइटों की विषयवस्तु को नियमित रूप से अद्यतन किया गया है। कई वेबसाइटों में विभिन्न आवेदन-पत्रों पर अद्यतन ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए गतिशील विषयवस्तु उपलब्ध है। उदाहरण के लिए मनरेगा की वेबसाइट (http://nrega.nic.in) में जॉब कार्ड है और अन्य विवरण नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइटों के मामले में आवेदन-पत्रों की स्थिति का विवरण नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों में विभागों के लिए एक वेब सूचना प्रबंधन का होना अनिवार्य है जिसके दायित्व में विषयवस्तु की निगरानी करना और उसकी गुणवत्ता और करेंसी शामिल है। विभागों को वेबसाइटों की विषयवस्तु की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'विषयवस्तु समीक्षा नीति तैयार करने की भी सलाह दी गई है। निदेशों के अनुसार, पूरे देश में मंत्रालय/विभाग/राज्यों/जिलों की वेबसाइट डिजायन, विकसित और अनुरक्षण करते समय इस दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। इस बारे में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने सभी मुख्य सचिवों को अपने राज्यों में भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों अनुपालन के लिए पत्र लिखा है। मंत्रिमंडल सचिव ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों अनुपालन के लिए पत्र लिखा है। मंत्रीमंडल सचिव ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को वेबसाइटों द्वारा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए

जरूरी कदम उठाने के लिए पत्र लिखा है। दिशा-निर्देशों का विवरण वेबसाइट *http://guidelines.gov.in* पर उपलब्ध है।

एयर इंडिया द्वारा नए सी.एम.एस.

1938. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने नयी क्रू प्रबंधन प्रणाली (सी.एम. एस.) प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) स्टाफ की तैनाती एवं प्रबंधन में विषयनिष्ठता तथा पक्षपात की संभावना खत्म करने में नयी प्रणाली किस हद तक मददगार होगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां। एयर इंडिया ने बड़े आकार (वाइड बॉडी) और छोटे आकर (नैरो बॉडी) वाले दोनों प्रकार के विमानों में तैनात केबिन कर्मीदल के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (सी.एम.एस.) लांच करनी आरम्भ कर दी है। उक्त प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) सी.एम.एस. में केबिन क्रू वेब पोर्टल है, जिसमें केबिन कर्मीदल दैनिक रूप से ए.आर.एम.एस. पर कार्यक्रम देख सकते हैं।

(ii) कर्मीदल केबिन कर्मीदल का निजी ब्यौरा देख सकते हैं और इसमें बदलाव कर सकते हैं, जिन्हें नामित क्रू वेब पोर्टल प्रशासकों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(iii) ए.आर.एम.एस. में मुम्बई स्थित केबिन कर्मीदल के लिए रोस्टर अपलोट किया गया ताकि दिसंबर के नियोजित रोस्टर को सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके।

(ग) इस प्रणाली से व्यक्तिपरकता और पक्षपात की गुजांइश कम होगी क्योंकि यह कर्मीदल प्रबंधन प्रणाली का अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी पद्धति होगी।

म्यांमार में लोकतंत्र

1939. प्रो. सौगत राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार की नेता आंग सांग सू की ने हाल में अपने देश में लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन के प्रति भारत के रुख पर निराशा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) म्यांमार में वर्तमान शासन के प्रति सरकार की क्या नीति है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) म्यांमार लोकतंत्र की राष्ट्रीय लीग की अध्यक्ष आंग सांग सू की ने 13 से 17 नवंबर 2012 को नेहरू स्मारक व्याख्यान देने के लिए भारत की यात्रा की। डा आंग सांग सू की ने अपनी सार्वजनिक टिप्पणी में कथित रूप से यह कहा था कि "उन्हें इस बात पर खेद है कि हम अपनी कठिनाई के दिनों में भारत से दूर होते चले गए तथा भारत उनसे दूर होता चला गया परंतु उन्हें दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता में विश्वास है।" "उन्होंने यह भी कहा कि वे यह चाहती हैं कि भारत लोकतंत्र के पथ पर म्यांमार की सहायता करे।"

डा आंग सांग सूकी ने अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की। उनकी यात्रा म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए भारत के सतत समर्थन सहित आपसी हित के मामलों पर विचारों के आदान-प्रदान में सहायक थी। डा आंग सांग सूकी को लोकतांत्रिक संस्थानों, क्षमता निर्माण प्रयासों तथा लोगों के आपसी संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्थन सहित म्यांमार में बहुदलीय राजनीति भारत के संबंध के बारे में सूचित किया गया था।

मई 2012 में प्रधानमंत्री की म्यांमार यात्रा तथा अक्तूबर 2011 में म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा सहित पिछले वर्ष के दौरान भारत तथा म्यांमार के बीच उच्चस्तरीय आदान-प्रदान से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध और सशक्त हुए हैं। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र के विकास, व्यापार व निवेश, संपर्क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, अवस्थापना विकास, सीमा प्रबंधन, संस्कृति,

क्षमता निमार्ण तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में कई प्रकार से नई पहल पर सहमति व्यक्त की थी।

प्रधामंत्री ने मई 2012 में अपनी म्यांमार यात्रा के दौरान लोकतांत्रिक संस्थानों की क्षमता का विकास करने के लिए हर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारत की तत्परता को दोहराया था। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने म्यांमार सांसदों तथा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत की तत्परता के बारे में सूचित किया। जुलाई तथा अक्तूबर 2012 में म्यांमार सांसदों के लिए भारत में संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा प्रयासोन्मुखी पाठ्क्रम आयोजित किए गए थे।

[हिन्दी]

कन्या शिक्षा परिसर स्कीम

1940. **श्री गोविंद प्रसाद मिश्र:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चलायी जा रही कन्या शिक्षा परिसर स्कीम के लिए वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 हेतु 60.18 लाख रुपये राशि के अनुदान को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दिया जाना अभी भी बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लंबित अनुदानों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में मध्य प्रदेश में चल रही कन्या शिक्षा परिसर नाम की कोई स्कीम नहीं है। इसलिए उक्त स्कीम के लिए लम्बित अनुदान का प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक स्तर पर स्कूल शिक्षा छोड़ देना

1941. **श्री जगदानन्द सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में विद्यार्थी माध्यमिक स्कूल स्तर तक जाने के पूर्व पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माध्यमिक स्कूल स्तर पर दाखिले में कमी का प्रमुख कारण स्कूलों की अपर्याप्त संख्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) देश में वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के दौरान कक्षा I-V, कक्षा I-VII तथा कक्षा I-X के लिए अध्ययन बीच में छोड़ने की दर क्रमश: 27.0, 40.6 तथा 49.3 है।

(ख) 2009-10 (अनंतिम) तथा 2010-11 (अनंतिम) के दौरान अध्ययन बीच में छोड़ने का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न पर दिया गया है।

(ग) से (ङ) देश में 2009-10 (अनंतिम) तथा 2010-11 (अनंतिम) के दौरान कक्षा IX-X में नामांकित छात्रों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)
नामांकन	30598519	31779027

सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य पूरा करने हेतु सतत रूप से प्रगति कर रही है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन कार्यढांचे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के समनुरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में नामांकन और बच्चों को स्कूल में रोकने में वृद्धि हो सके।

स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल

अवसंरचना और सुविधाओं को सुदृढ़ करना, उन आवासीय स्थानों, जहां पर नियमित स्कूल नहीं हैं, में बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण करना, अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करना, शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना, बच्चों की पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों की व्यवस्था करना शामिल है। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि करने की दृष्टि से मध्याह्न शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षा की सुलभता में महिला-पुरुष संबंधी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं को अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को माध्यमिक स्कूल में स्तरोन्नत करने की व्यवस्था है। अध्ययन बीच में छोड़ने की दर में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नामांकन प्रक्रिया, विशेष कोचिंग/उपचारात्मक शिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम जैसे कई अन्य उपाय किए गए हैं।

विवरण

अध्ययन छोड़ने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा I-V		कक्षा I-VIII		कक्षा I-X	
		2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	15.8	17.4	41.3	32.9	53.4	46.2
2	अरूणाचल प्रदेश	41.3	43.0	47.0	50.5	64.9	61.7
3	असम	35.9	29.9	61.2	54.0	77.6	77.4
4	बिहार	42.5	35.7	66.0	58.3	77.6	62.2
5	छत्तीसगढ़[1]	34.1	31.0	40.7	48.3	-	58.0
6	गोवा	-8.5	-	-17.9	-	34.3	28.1
7	गुजरात	25.7	25.7	39.7	46.7	62.1	57.9
8	हरियाणा	-1.6	9.4	14.4	4.6	19.8	18.9
9	हिमाचल प्रदेश	0.7	3.8	2.4	-	20.6	16.0
10	जम्मू और कश्मीर	8.4	8.4	21.9	6.1	44.3	43.6
11	झारखंड[2]	27.0	28.4	61.9	45.1	-	69.5
12	कर्नाटक	11.1	8.9	25.9	20.8	46.6	43.3

1	2	3	4	5	6	7	8
13	केरल	-12.5	-	14.1	-	-4.1	-
14	मध्य प्रदेश	21.2	29.5	21.4	30.7	65.7	51.1
15	महाराष्ट्र	21.3	20.3	25.9	25.9	40.5	38.2
16	मणिपुर	36.5	45.7	57.1	52.8	56.8	45.3
17	मेघालय	57.6	58.4	72.3	70.4	77.9	77.4
18	मिजोरम	46.0	37.9	55.1	36.7	62.9	53.7
19	नागालैंड	39.9	7.0	54.3	55.0	68.2	64.0
20	ओडिशा	26.5	7.0	54.3	55.0	68.2	64.0
21	पंजाब	-18.0	-	-19.1	-	40.4	30.5
22	राजस्थान	50.5	50.6	50.3	53.3	71.6	68.5
23	सिक्किम	18.6	18.4	44.7	42.8	80.7	69.9
24	तमिलनाडु	0.3	-	8.7	48.2	62.9	58.4
25	त्रिपुरा	25.5	31.1	43.7	48.2	62.9	58.4
26	उत्तर प्रदेश	42.1	34.11	52.8	49.7	23.8	24.0
27	उत्तराखंड[3]	42.13	4.15	2.8	49.7	23.8	24.0
28	पश्चिम बंगाल	20.5	28.4	50.5	49.1	71.8	64.2
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.0	7.8	11.6	15.1	30.1	21.1
30	चंडीगढ़	-22.8	-	-23.8	-	3.8	-
31	दादरा और नगर हवेली	17.5	12.7	43.3	33.7	58.8	54.7
32	दमन और दीव	2.8	8.3	10.7	10.8	35.9	28.3
33	दिल्ली	13.3	5.9	-27.1	-	2.0	22.9

1	2	3	4	5	6	7	8
34	लक्षद्वीप	11.1	7.1	9.0	12.7	25.1	31.3
35	पुदुचेरी	-3.6	-	-14.9	-	7.3	6.4
	भारत	28.9	27.0	42.4	40.6	52.8	49.3

2008-09 (अनंतिम) और 2009-10 (अनंतिम) के लिए 1. मध्य प्रदेश में शामिल है, 2. बिहार में शामिल है, 3. उत्तर प्रदेश में शामिल है।

नकारात्मक दर स्कूल में लेटरल एंट्री या कक्षा दोहराने वाले छात्रों के कारण हैं।

[अनुवाद]

एकसमान पाठ्क्रयम

1942. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एकसमान पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 'एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम, एक परीक्षा' की अवधारणा और 'कोर-पाठ्यचर्या' और अपनाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य हितधारियों से परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) देश में एक समान पाठ्यक्रम प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) में अनुशंसा की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली साथ-एक साझा कोर शामिल है। अगस्त, 2009 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 के आधार पर अपनी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने देश में सभी शैक्षिक बोर्डों में माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान तथा गणित में एक कोर पाठ्यचर्या की आवश्यकता का समर्थन किया है, ताकि सभी छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। दिनांक 16 फरवरी, 2010, को आयोजित माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परिषद (सी.ओ.बी.एस.ई.) की बैठक में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा गणित में एक कोर पाठ्यचर्या अपनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पाठ्यक्रम तैयार किया है तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु विज्ञान, गणित, वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र में कोर पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया है। इसे राज्य बोर्डों द्वारा अपनाया/अनुकूलित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नियुक्तिकर्ता एर्जेसियों के खिलाफ शिकायतें

1943. श्री इज्यराज सिंह :
श्री पी. के. बिजू :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विदेश में नौकरी दिलाने वाली नियुक्तिकर्ता एर्जेसियों के विरूद्ध उनकी धोखेबाज हरकतों के लिए कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) अभी भी लंबित शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसे एजेंटों की हरकतों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) विचाराधीनता के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों और अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई हैं।

भर्ती एजेंटों (आरएज) के विरूद्ध कार्रवाई, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। किसी निर्णय पर पहुंचने में कुछ समय लगता है, क्योंकि शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रदान करने के लिए एक अवसर और एजेंट को मामलों को हल करने/अपने आप का बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

अवैध/अप्राधिकृत एजेंटों के विरूद्ध दायर की गई शिकायतों को, कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को संदर्भित कर दिया जाता है।

(घ) पंजीकृत भर्ती एजेंटों जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और भर्ती एजेंटों को पहले तो शिकायत को हल करने/निपटाने का निर्देश दिया जाता है। यदि भर्ती एजेंट कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने में असफल रहता है या उसका उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, तो उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया जाता है। यदि फिर भी शिकायत का निपटान नहीं होता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र को अनिश्चित अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने और बैंक गारंटी को जब्त करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। भर्ती एजेंटों के विरूद्ध मामलों को, शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत को निपटा दिए जाने की पुष्टि हो जाने और जहां कहीं लागू हो, तो मिशन और संबंधित पीओई से विचार-विमर्श करने के बाद ही समाप्त किया जाता है।

आरएज के रूप में काम करने के लिए केवल गंभीर और सच्चे लोगों को रखने के उद्देश्य से, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने उत्प्रवास नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियम 09 जुलाई, 2009 से लागू हुए हैं। महत्वपूर्ण बदलाव नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

(i) भर्ती एजेंट (आरए) द्वारा बैंक गारंटी के रूप में दी जाने वाली सिक्यूरिटी की राशि को बढ़ाकर बीस लाख रूपए कर दिया गया है।

(ii) पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन शुल्क को पांच हजार रूपए से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपए कर दिया गया है।

(iii) पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वालों के लिए, न्यूनतम योग्यता "स्नातक" है। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट, या आवेदक की संपत्तियों और देयताओं को दिखाने वाले खातों का ब्यौरा, पिछले क्रमिक तीन वर्षों की आयकर विवरणी, और वित्तीय स्थिति और विश्वस्तता दिखाने वाला एक शपथपत्र, अनिवार्य है।

(iv) भर्ती एजेंटों को निश्चित आधारभूत सुविधाएं रखनी होंगी, जैसे कार्यालय क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए, वहां एक प्रतीक्षा हॉल होना चाहिए, पर्याप्त व विधिवत रूप से प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, ट्रेड हेतु जिसके लिए वह भावी उत्प्रवासियों की भर्ती करता है, के लिए कौशल टेस्टिंग का प्रबंध होना चाहिए और पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सुविधाओं के साथ, एक आधुनिक व अच्छे उपकरणों वाला कार्यालय होना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, उत्प्रवास संरक्षियों को, उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करते समय मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशों पर ध्यान देते समय, समुचित जांच और पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गया है। महिला संवेदनशील श्रेणियों के संबंध में उत्प्रवास, केवल दूतावास सत्यापित दस्तावेजों पर ही प्रदान किया जाता है। कुवैत, जार्डन, सीरिया, लीबिया, लेबनान और यमन के लिए उत्प्रवास, श्रेणी पर ध्यान दिए बिना केवल भारतीय दूतावास सत्यापित दस्तावेजों पर ही प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

विवरण-I

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरूद्ध की गई कार्रवाई

वर्ष	कुल	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	निलंबित	निरस्त	समाप्त/निपटा दिया गया + रद्द कर दिया गया	शेष
2009	158	158	20	35	82	21
2010	145	145	10	29	82	24
2011	212	212	20	44	94	54
2012 (31.10.2012 तक)	234	234	37	15	36	146

विवरण-II

अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरूद्ध की गई कार्रवाई

वर्ष	शिकायतों की संख्या	कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को संदर्भित मामले	अभियोजन स्वीकृतियां मांगी गईं	जारी की गई अभियोजन स्वीकृतियां
2009	136	136	14	14
2010	166	166	10	10
2011	225	225	9	9
2012 (31.10.2012 तक)	254	240	14	14

*ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्ता उत्प्रवासी/भावी उत्प्रवासी या उनके संबंधी होते हैं वहां केंद्र सरकार से अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

[अनुवाद]

संयुक्त प्रवेश परीक्षा

1944. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) के प्रारूप में जरूरी बदलाव किए गए हैं;

(ख) क्या कुछेक राज्यों एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) ने नये प्रारूप के प्रति अपना विरोध/आपत्तियां दर्ज की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी आपत्तियों/आशंकाओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह तथ्य है कि देश में बहुतेरे शिक्षा बोर्ड हैं जिनमें अंकों के मानकीकरण की जरूरत है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आई.आई.टी. के परामर्श से कोई ऐसा मानकीकरण सूत्र तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई के कार्यक्रम, 1992 में देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। अनेक प्रवेश परीक्षाएं छात्रों का कक्षा की पढ़ाई से ध्यान भंग करती हैं जिससे स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रभावकारिता कम होती है। रामासामी समिति, जिसने इस मामले की जांच की थी, ने अन्य बातों के साथ-साथ कक्षा 12 की परीक्षाओं में निष्पादन को अधिमान देते हुए एक सामान्य राष्ट्रीय परीक्षा का प्रस्ताव दिया था।

(ख) और (ग) आई.आई.टी. की सीनेटों, आई.आई.टी. के संयुक्त प्रवेश बोर्डों के बीच तथा साथ ही आई.आई.टी. की परिषदों के साथ-साथ एन.आई.टी. परिषदों की विभिन्न बैठकों में हुए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति हुई थी कि 12वीं कक्षा को बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के निष्पादन को समुचित अधिमान देकर व्यापक परीक्षाओं की बहुतलता को कम किया जाए और साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश की विश्वसनीयत एवं सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जाए। इसे राज्य शिक्षा मंत्रियों के दो सम्मेलनों में इस सुझाव के साथ 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदित कर दिया गया है कि राज्य, राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश की यही पद्धति अपना सकते हैं, यदि वे ऐसा करना उपयुक्त समझते हैं। सम विश्वविद्यालय संस्थाओं ने भी आम तौर पर इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

(घ) से (च) आई.आई.टी. में प्रवेश के लिए अंतिम योग्यता सूची आई.आई.टी. प्रणाली द्वारा स्वयं आयोजित की जानी वाली जे.ई.ई.-एडवांस्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर तैयार की जाएगी। परंतु प्रवेश केवल जे.ई.ई.-एडवांस्ड परीक्षा में सफल होने वाले ऐसे उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा जो अपने संबंधित बोर्डों के उच्चतम 20 पर्सेंटाइल में आते हैं। अलग-अगल बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए अंकों को बराबर के अनुसार ली जा रही है जो उसी परीक्षा में बैठे हैं तथा जिनके निष्पादन का मूल्यांकन उसी ढंग से किया गया है।

दूरसंचार में हुआई प्रौद्योगिकी

1945. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूरसंचार बाजार में हुआई प्रौद्योगिकियों का क्या स्थान है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया ने हुआई प्रौद्योगिकियों के विरुद्ध चिंताएं व्यक्त की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को हुआई प्रौद्योगिकीयों के संभावित सुरक्षा खतरे के बारे में ऐसी कोई चेतावनी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) दूरसंचार सेवाप्रदाता, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन अपने तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर हुआई प्रोद्योगिकियों सहित विभिन्न दूरसंचार उपस्कर संस्थापित कर सकता है। चूंकि लाइसेंस संबंधी निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अतिरिक्त किसी भी विक्रेता से उपस्कर को संस्थापित करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कुछ हुआई प्रौद्योगिकी उपस्कर दूरसंचार नेटवर्क में भी उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) सरकार को "चीन की दूरसंचार कंपनी हुआई और जेड.टी.ई. के संबंध में उठाए गए अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों से संबंधित जांच रिपोर्ट" शीर्षक से संबंधित अमरीकी सरकार की इंटेलीजेंस संबंधी स्थायी चयन समिति की रिपोर्ट की जानकारी है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि आधुनिक युग में, दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए दूरसंचार उपस्कर से अथवा इनमें निहित सन्निहित साफ्टवेयर अथवा असमाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों अथवा एजेंसियों से उत्पन्न स्पाइवेयर/मालवेयर इत्यादि से असुरक्षा का खतरा होता है। ऐसे संभावित खतरे, चीन में निर्मित दूरसंचार उपस्कर अथवा किसी अन्य विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए संसाधनों के संबंध में ध्यान दिए बिना, नेटवर्क में मौजूद हैं।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई विशिष्ट घटना ध्यान में नहीं आई है। तथापि, दूरसंचार और दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के निवारण हेतु, गृह मंत्रालय के परामर्श और उद्योग क्षेत्र के साथ यथोचित विचार-विमर्श के बाद दिनांक 31.05.2011 को अभिगम सेवा लाइसेंसों के लिए और 3 जून, 2011 को अन्य लाइसेंसों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस संशोधन के रूप में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इन संशोधनों के द्वारा यह अधिदेशित किया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यह भी अधिदेशित किया गया है कि केवल वे ही नेटवर्क घटक उनके दूरसंचार नेटवर्क में शामिल होंगे जिनकी 31 मार्च, 2013 तक संबंधित सामयिक भारतीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के अनुसार जांच की गई है अर्थात आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 15408 मानदंडों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित घटक, आई.एस.ओ. 27000 श्रेणी मानदंडों के आधार पर दूरसंचार से संबंधित घटकों के लिए, मानदंडों की किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी/प्रयोगशाला अर्थात आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 15408 मानदंडों के मामले में समान मानदंड प्रयोगशालाओं से जांच की गई हो। दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से भारत में प्रमाणन का कार्य केवल प्राधिकृत और प्रमाणित एजेंसियों/प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा उपस्कर की प्राप्ति की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए जांच परिणामों और जांच-प्रमाण पत्रों की प्रतियां अपने पास रखनी होंगी और इस समयावधि के दौरान किसी भी लाइसेंसदाता द्वारा इनकी जांच/मांग की जा सकती है।

इस प्रकार, चीन के दूरसंचार उपस्कर के प्रवेश अथवा अन्य किसी संसाधन के द्वारा संभावित खतरों के निवारण के मद्देनजर एक ढांचे को पहले ही अधिदेशित कर दिया गया है। अभी तक, किसी भी विशिष्ट देश के उपस्कर के कारण कोई विशिष्ट मुद्दा उत्पन्न नहीं हुआ है। तथापि, जब भी कोई विशिष्ट मुद्दा उत्पन्न होता है तथा रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उस विशिष्ट देश अथवा संसाधन अथवा देशों के समूह से आने वाले उपस्करों के संबंध में व्यवस्था को और सख्त किया जा सकता है।

सरकार दूरसंचार सुरक्षा से संबंधित सभी नए घटनाक्रमों की सतत रूप से जांच करती है तथा इन घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में सुरक्षा प्रबंधन की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. विभाग की दिनांक 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 8(78)/2010-आई.पी.एच.डब्ल्यू. के आधार पर देश में विनिर्मित दूरसंचार उपस्कर के शेयर को बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा सरकारी प्रापण और सरकारी परियोजनाओं के लिए घरेलू दूरसंचार उपस्कर से संबंधित दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 की सं. 18-0712010 के द्वारा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

स्कूलों के लिए शुल्क ढांचा

1946. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों की शुल्क ढांचा के विनियमन के संबंध में कोई केंद्रीय कानून या विधिक रूपरेखा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पब्लिक स्कूलों की शुल्क संरचना पर कोई नियंत्रण लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर) : (क) और (ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है। सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूल सीबीएसई सम्बद्धता उपनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं, जिनमें यह बताया गया है कि :

* स्कूलों द्वारा लिया गया शुल्क उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के अनुरूप होना चाहिए।
* स्कूल में दाखिला लेने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्कूल के नाम से कोई कैपिटेशन शुल्क या स्वैच्छिक दान नहीं लेना चाहिए।
* सामान्यत: विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभागों द्वारा निर्धारित शीर्षों के तहत ही शुल्क लेना चाहिए।

सीबीएसई स्कूलों की शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए वैधानिक कार्यढांचे वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

खाड़ी क्षेत्र के लिए एअर इंडिया की उड़ानें

1947. **श्री पी.टी. थॉमस :**
श्री एंटो एंटोनी :
श्री एम.के. राघवन :
श्री के.पी. धनपालन :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों में प्रत्येक माह के दौरान केरल से संचालित होने वाली रद्द की गई/विलंबित एअर इंडिया उड़ानों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त अवधि के दौरान राजस्व की कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार/एअर इंडिया ने खाड़ी देशों के साथ साप्ताहिक सीट बंटवारे संबंधी कोई करार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस क्षेत्र में वास्तविक मांग और सीटों की कमी के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक सेवाएं शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जून-नवम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, प्रचालित की गई 5984 उड़ान में से 91 उड़ाने रद्द की गई थी और 1131 उड़ानें 15 मिनट से अधिक विलंबित थीं।

(ख) और (ग) जी हां। केरल से खाड़ी तक उड़ानों को बार-बार रद्द करने/उड़ानों को बहाल करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय/संसद सदस्यों/अनिवासी केरल वासियों से पत्र प्राप्त हुए हैं। 7 मई से 3 जुलाई, 2012 तक इसके पायलटों के एक वर्ग द्वारा आंदोलन किए जाने के कारण ये उड़ानें प्रभावित हुईं/वापस ली गईं। पायलटों की हड़ताल का असर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर भी पड़ा।

केरल-खाड़ी मार्ग पर, एयर इंडिया ने ग्रीष्म कालीन समयावली के लिए 45 अनुसूचित उड़ानों में से 42 उड़ानें प्रचालित कीं। बी 747 विमान से प्रचालित कालीकट-रियाध मार्ग पर 3 साप्ताहिक सेवाएं वापस ली गईं। तथापि, कोच्चि में से प्रचालित सेवाओं पर यात्रियों को समायोजित किया गया। रियाध-कोच्चि-रियाध मार्ग पर उड़ानें प्रचालित करने के लिए रियाद-त्रिवेन्द्रम-कोच्चि -रियाद मार्ग पर बी 747 विमान से दो साप्ताहिक सेवाएं पुनः संरचित की गईं और यात्रियों को कोच्चि में से प्रचालित सेवाओं में समायोजित किया गया। उक्त आंदोलन 3 जुलाई, 2012 को बंद हो गया। तथापि, पायलट चरणों में प्रचालनिक ड्यूटी के लिए उपलब्ध थे। कालीकट-रियाध तथा वापसी मार्ग पर सेवाएं 9 अगस्त, 2012 से बहाल हो गईं।

हज प्रचालन के लिए विमान की अपेक्षा के कारण इंडिया को 19.9.2012 से 26.10.2012 तक कोच्चि-रियाध तथा वापसी मार्ग पर उड़ानों की वापसी के लिए विवश होना पड़ा। यात्रियों को अन्य शहरों में से प्रचालित होने वाली सेवाओं के समायोजित किया गया। पायलटों के आंदोलन के कारण, एअर इंडिया एक्सप्रेस को भी केरल-खाड़ी मार्ग पर प्रति सप्ताह 77 उड़ानें थीं, जो हड़ताल के कारण घट कर 20 प्रतिशत हो गई। तथापि, 1.8.2012 से 16.09.2012 तक एअर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रमुख सीजन में 81 अतिरिक्त उड़ाने प्रचालित की इसके पश्चात, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पूर्ण ग्रीष्म कालीन समयावली बहाल की। हज प्रचालन की आवश्यकता के कारण, एअर इंडिया एक्सप्रेस को दो विमान छोड़ना पड़ा जो 17.9.2012 तथा 28.9.2012 के बीच केरल से खाड़ी तक 15 उड़ानों को रद्द करना आवश्यक हो गया। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 29.9.2012 से केवल से खाड़ी तक अपनी अपनी सभी समयावली बहाल कर दी। रद्द की गई उड़ानों के सभी मामलों में रद्द की गई उड़ानों के यात्रियों को अन्य एअर इंडिया/एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में समायोजित किया गया या उनकी विकल्प के अनुसार पूर्ण धन वापस की गई।

विमान प्रबंधन ने अपने कार्यपालक पायलटों तथा छोटे आकार वाले विमानों की मदद से संयोजित गंतव्यों के लिए संपर्कता कायम करने हेतु विभिन्न कदम उठाए ताकि यात्रियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

चालू शीतकालीन समयावली में एअर इंडिया एक्सप्रेस ने केरल-खाड़ी प्रचालन पर 88 उड़ाने प्रति सप्ताह बढ़ा दी है। केरल-खाड़ी एअर इंडिया तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस के लिए एक अनुकूल बाजार है। परिणामतः राष्ट्रीय वाहक होने के नाते, यात्रियों के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उड़ान समयावलियों को अंतिम रूप दिया जाता है।

पायलटों की हड़ताल के कारण एअर इंडिया को 600 करोड़ रूपए का घाटा उठाना पड़ा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं खाड़ी बाजार में सीटों की कोई कमी नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्कूलों/महाविद्यालयों में यौन उत्पीड़न

1948. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इससे संबंधित कानूनों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्यमान कानूनों में आवश्यक संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण रखने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली, 2009 में भी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न पर नियंत्रण रखने के लिए कतिपय उपबंध निहित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परिपत्र जारी करता रहा है जिनमें उनसे यौन उत्पीड़न और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मुद्दे के समाधान के लिए स्थायी प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुरोध किया जाता रहा है।

सरकार ने 'दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफेन्सेज एक्ट, 2012'' अधिनियमित किया है जो स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों सहित सभी स्थानों पर यौन आक्षेप, यौन उत्पीड़न इत्यादि अपराधों से बच्चों के संरक्षण की मांग करता है। कानून के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पासपोर्ट मेला

1949. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री दत्ता मेघे :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी करने का आवेदन करने वाले आवेदकों को पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में मिलने तथा अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों ने हाल ही में पासपोर्ट मेले आयोजित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मेलों में कितनी शिकायतें मिलीं तथा कितनी शिकायतों को निपटाया गया;

(घ) क्या निकट भविष्य में देश के विभिन्न भागों में ऐसे और अधिक मेले आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) ग्रीष्म काल के दौरान पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और मिलने का समय प्राप्त करने में नागरिकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से 24 पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 23 जून, 2012 से पासपोर्ट मेला आयोजित किए गए हैं। दिनांक 23 जून, 2012 से 20 नवम्बर, 2012 तक आयोजित हुए मेलों में 33,584 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें से 25,408 के मामले में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान कर दी गई हैं। शेष 8176 आवेदन पासपोर्ट जारी करने के लिए कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं। पासपोर्ट मेलों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) पासपोर्ट सेवाओं की मांग के आधार पर पासपोर्ट मेले भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे।

विवरण

23.6.2012 से 20.11.2012 तक आयोजित पासपोर्ट मेलों का ब्यौरा

क्षे.पा.का./ पा.का.	पी.एस.के.	23 जून- प्राप्त आवेदनों की संख्या	24 जून- प्राप्त आवेदनों की संख्या	30 जून- प्राप्त आवेदनों की संख्या	1 जुलाई- प्राप्त आवेदनों की संख्या	7 जुलाई- प्राप्त आवेदनों की संख्या	14 जुलाई- प्राप्त आवेदनों की संख्या	4अगस्त- प्राप्त आवेदनों की संख्या	7-20 नवंबर प्राप्त आवेदनों की संख्या	10नवंबर- प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अमृतसर	अमृतसर पी.एस.के.	135	266	–	–	–	–	–	–	–	401
	उप योग										401
बैंगलोर	बैंगलोर-आर.पी.ओ.	414	435	450	477	–	–	–	–	–	1776
	बैंगलोर-लाल बाग	260	630	598	743	–	–	–	–	–	2231
	बैंगलोर-साई आर्केड	190	272	280	330	–	–	–	–	–	1072
	मंगलोर	95	273	86	177	–	–	–	–	–	631
	हुबली	57	155	107	236	–	–	–	–	–	555
	उप योग										6265
चेन्नई	चेन्नई-आर.पी.ओ.	49	155	0	–	–	–	–	–	–	204
	चेन्नई-1 (वडापलानी)	84	174	65	–	–	–	–	–	–	323
	चेन्नई-2 (नवीन)	100	277	77	–	–	–	–	–	–	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	चेन्नई-3 (थमबरम)	101	129	43	–	–	–	–	–	–	273
	उप योग										1254
दिल्ली	आई.टी.ओ. दिल्ली	140	311	319	404	–	–	–	–	–	1174
	गुडगांव पी.एस.के.	105	220	205	203	–	–	–	–	–	733
	शालीमार बाग, दिल्ली	208	403	358	450	–	–	–	–	–	1419
	भीखाजी, आर.के. पुरम	206	400	497	525	–	–	–	–	–	1628
	उप योग										4954
गाजियाबाद	गाजियाबाद पी.एस.के.	40	92	–	–	–	–	–	–	–	132
	गाजियाबाद आर.पी.ओ.	12	0	–	–	–	–	–	–	–	12
	उप योग										144
हैदराबाद	हैदराबाद-आर.पी.ओ.	92	499	–	–	–	–	–	–	–	591
	हैदराबाद 1 -बेगमपेट	52	227	–	–	–	–	–	–	–	279
	हैदराबाद 2 -अमीरपेट	125	280	–	–	–	–	–	–	–	405
	हैदराबाद 3 -टोलीचौकी	50	282	–	–	–	–	–	–	–	3321
	विजयवाड़ा	30	105	–	–	–	–	–	–	–	135
	निजामाबाद	31	65	–	–	–	–	–	–	–	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	तिरुपति	35	173	–	408	–	–	–	–	–	616
	उप योग										2454
लखनऊ	कानपुर	2	45	–	–	–	–	–	–	–	47
	गोरखपुर	.6	6	–	–	–	–	–	–	–	12
	उप योग										59
कोयम्बतूर	कोयम्बतूर–आर.पी.ओ.	–	–	571	–	–	–	–	–	–	571
	उप योग										571
गोवा	पणजी	–	–	83	–	–	–	41	–	–	124
	उप योग										124
मल्लाप्पुरम	मल्लप्पुरम	–	–	491	–	–	–	563	–	646	1700
	उप योग										1700
नागपुर	नागपुर	–	–	10	–	–	–	–	–	–	10
	उप योग										10
पुणे	पुणे	–	–	21	–	–	–	–	–	–	21
	पुणे – आर.पी.ओ.	–	–	35	–	–	–	–	–	–	35
	उप योग										56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	–	–	496	–	–	–	–	–	–	496
	विशाखापत्तनम–आर.पी.ओ.	–	–	329	–	–	–	–	10123		11918
	उप योग										11918
अहमदाबाद	अहमदाबाद–1	–	–	–	226	–	–	–	–	–	226
	बडोदरा	–	–	–	136	–	–	–	–	–	136
	उप योग										362
मदुरै	मदुरै	–	–	–	72	–	–	–	–	–	72
	मदुरै आर.पी.ओ.	–	–	–	48	–	–	–	–	–	48
	उप योग										120
सूरत	सूरत	–	–	–	242	–	–	–	–	–	242
	उप योग										242
कोलकाता	बहरामपुर	–	–	–	–	167	–	–	–	–	167
	कोलकाता	–	–	–	–	791	–	–	–	–	791
	कोलकाता आर.पी.ओ.	–	–	–	–	631	–	–	–	–	631
	उप योग										1589
पटना	पटना	–	–	–	–	70	–	–	–	–	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	पटना आर.पी.ओ.	–	–	–	–	143	–	–	–	–	145
	उप योग										213
चण्डीगढ़	अम्बाला	–	–	–	–	84	–	–	–	–	84
	उप योग										84
जयपुर	जयपुर	–	–	–	–	409	–	–	–	–	409
	जोधपुर	–	–	–	–	176	–	–	–	–	176
	सीकर	–	–	–	–	242	–	–	–	–	242
	उप योग										827
कोचीन	थ्रिसूर	–	–	–	–	56	–	–	–	–	56
	अल्प्पूझा	–	–	–	–	13	–	–	–	–	13
	कोट्टायम	–	–	–	–	23	–	–	–	–	23
	कोचीन	–	–	–	–	51	–	–	–	–	51
	अलूवा	–	–	–	–	113	–	–	–	–	113
	कोचीन आर.पी.ओ.	–	–	–	–	96	–	–	–	–	96
	उप योग										352
त्रिवेन्द्रम	कोल्लम	–	–	–	–	19	–	–	–	–	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	वाजूथाकौड	–	–	–	–	26	–	–	–	–	26
	नेयातिनकारा	–	–	–	–	3	–	–	–	–	3
	उप योग										48
कोझीकोड	कोझीकोड 1	–	–	–	–	60	–	–	–	–	60
	वडाकरा	–	–	–	–	39	–	–	–	–	39
	पयानूर	–	–	–	–	46	–	–	–	–	46
	कन्नूर 1	–	–	–	–	62	–	–	–	–	62
	उप योग										207
त्रिची	त्रिची						250	–	–	–	250
	तंजावुर						350	–	–	–	350
	उप योग										600
	कुल	2619	5874	5121	4677	3320	600	604	10123	646	33584

* पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापत्तनम द्वारा पासपोर्ट मेला दिनांक 7,8,9,12,14,15,16,19 तथा 20 नवंबर, 2012 को आयोजित किए गए थे।

सी.एस.एस. हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम

1950. **श्री जयंत चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री—यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित कल्याण योजनाओं हेतु निधियों के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्रणाली के अंतर्गत कौन-सी योजनाएं शामिल की जाएंगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसी प्रणाली का व्यवहार्यता संबंधी कोई अध्ययन कराया है और अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संबंध में इसके क्या प्रभाव होंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और निधियों के अंतरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन में बेहतर पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सब्सिडी एवं लाभ हेतु आधार सुलभ प्रत्यक्ष नकद अंतरण प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली के तहत कवर की जाने वाली स्कीमें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

प्रत्यक्ष नकद अंतरण के लिए उत्तरदायी केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्र प्रयोजित स्कीमों की सूची

1. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
2. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
3. अस्वच्छ व्यवसाय में शामिल लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
4. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैरिट का उन्नयन
5. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी (ओवरसीज) छात्रवृत्ति स्कीम
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय प्रवासी (ओवरसीज) छात्रवृत्ति
8. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
9. विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
10. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी (ओवरसीज) छात्रवृत्ति
11. विकलांग छात्रों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
12. उच्च स्तरीय शिक्षा स्कीम
13. विश्वविद्यालय/कालेज के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
14. यू.जी.सी. की फैलोशिप स्कीम
15. ए.आई.सी.टी.ई. की फैलोशिप स्कीम
16. छात्रों को शुल्क पर सब्सिडी
17. राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति
18. माध्यमिक शिक्षा के बालिकाओं को प्रोत्याहन हेतु राष्ट्रीय स्कीम
19. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी (ओवरसीज) छात्रवृत्ति
20. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम
21. मैरिट स्कीम का उन्नयन
22. उच्च स्तर की शिक्षा हेतु स्कीम
23. राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप
24. मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
25. मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप
26. साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम
27. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)
28. धनलक्ष्मी स्कीम

29. जननी सुरक्षा योजना

30. बीड़ी कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

31. बीड़ी कामगारों को आवास सब्सिडी

32. बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों में बच्चों को वजीफा

33. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को स्थायी विकलांगता लाभ, आश्रित लाभ, बीमारी लाभ

34. भविष्य निधि से पेंशन निकासी, समय से पहले पेंशन निकासी, कर्मचारी जमा बीमा से संबंधित भुगतान

सब्सिडी से संबंधित प्रत्यक्ष नकद अंतरण के लिए उत्तरदायी स्कीमों की सूची

1. घरेलू एल.पी.जी. सब्सिडी स्कीम

2. पी.डी.एस. कैरोसिन

3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (संघ राज्य क्षेत्रों में)

[हिन्दी]

पीएसयू में नियुक्ति की प्रक्रिया

1951. श्री के. डी. देशमुख : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठतम पदों पर नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है तथा नियुक्ति के समय किन-किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठतम पदों पर नियुक्ति अधिकारियों का पीएसयू-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठतम पदों पर नियुक्ति से पूर्व क्या इन अधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) लोक उद्यम चयन बोर्ड, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श करके नौकरी विवरण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उच्च पदों का विज्ञापन प्रकाशित करता है/परिपत्र जारी करता है। उचित माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, विभिन्न श्रेणियों में से बंटवारे के निर्धारित मानदंड के अनुसार आवेदनकर्ताओं की छंटाई लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा की जाती है। सामान्य तौर से प्रत्येक पद के लिए 15 उम्मीदवारों की छंटाई की जाती है और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता हैं उनकी प्रबंधकीय क्षमता के गुणों, नेतृत्व, व्यापक दृष्टिकोण, ट्रैक रिकार्ड, उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक सचिव द्वारा की गई विशेष टिप्पणियों के संदर्भ में साक्षात्कार लिए गए उम्मीदवारों के कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति के नाम की सिफारिश करता है।

लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के मामले में, संबंधित प्राधिकरणों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सतर्कता निकासी प्राप्त करते हैं और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुसूची 'क' और 'ख' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति और अनुसूची 'ग' और 'घ' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में प्रभावी मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूची 'क' और 'ख' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों अर्थात् अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों (सीएमडीज) तथा प्रबंध निदेशकों के पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के उपक्रम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां, सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत, व्यक्तियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा और गैर सरकारी उम्मीदवारों के मामले में पुलिस प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, से सतर्कता निकासी प्राप्त होने के बाद ही की जाती है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारी

वर्ष 2009-10

क्रम सं.	मंत्रालय और विभाग	पीएसयू	पदाधिकारी का नाम सर्व/श्री/सुश्री	पद	एसीसी आदेश की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	पी और एन.जी.	गेल	बी.सी. त्रिपाठी	सीएमडी	1.4.2009
2.	इस्पात	एमएसटीसी	एस.के. त्रिपाठी	सीएमडी	9.4.2009
3.	परमाणु ऊर्जा	ईसीआईएल	वाई.एस. मैया	सीएमडी	13.4.2009
4.	नागर विमानन	एआईएल	अरविन्द जाधव	सीएमडी	1.5.2009
5.	रक्षा उत्पाद	एचएएल	आर. श्री निवासन	एमडी (हैलीकॉपटर कॉम्पलेक्स)	19.6.2009
6.	भारी उद्योग	एचएनएल	एम.वी. नरसिम्हा राव	एमडी	
7.	खनन	नालको	(प) सी.आर. प्रधान (पप) ए.के. श्रीवास्तव	सीएमडी	31.7.2009
8.	इस्पात	सेल-(डीएसपी)	पी.के. बजाज	एमडी	19.8.2009
9.	इस्पात	एचएससीएल	मलय चटर्जी	सीएमडी	21.8.2009
10.	खाद	एनएफसीएल	वी.के. शर्मा	सीएमडी	27.8.2009
11.	पी और एन.जी.	गेल	ऐ.के. पुर्वाहा	सीएमडी	30.9.2009
12.	भारी उद्योग	बीएचईएल	बी.पी.रॉय	सीएमडी	30.9.2009
13.	खनन	एचसीएल	शकील अहमद	सीएमडी	1.10.2009
14.	पी और एन.जी.	सीपीसीएल	के. बालचन्द्रन	एमडी	1.10.2009
15.	पोत परिवहन	एचएसएल	कमोडोर. नरेश कुमार	सीएमडी	16.11.2009
16.	पोत परिवहन	एचडीपीईएल	रंजीत लोहरी	सीएमडी	19.11.2009
17.	रासायन एवं खाद	बीसीपीएल	जे.के. सिंह तेबतिया	एमडी	20.11.2009

1	2	3	4	5	6
18.	रेलवे	कनकोर	ए.के. गुप्ता	एमडी	23.11.2009
19.	परमाणु ऊर्जा	आईआरईए	आर एल पत्रा	सीएमडी	11.12.2009
20.	रक्षा उत्पाद	जीएसएल	रीअर एडमिन. विनीत बक्शी	सीएमडी	19.1.2010
21.	रेलवे	आरवीएनएल	एस.सी. अग्निहोत्री	एमडी	19.1.2010
22.	रक्षा उत्पाद	एचएएल	डी. बालसुन्दरन	एमडी (बैंगलूर कॉप्लेक्स)	12.3.2010
23.	खाद्य और (पीडी)	एफसीआई	सिराज हुसैन	सीएमडी	16.3.2010
24.	पी और एन.जी.	एचवपीसीएल	एस. रॉय चौधरी	सीएमडी	22.3.2010

वर्ष 2010-11

क्रम सं.	मंत्रालय और विभाग	पीएसयू	पदाधिकारी का नाम सर्व/श्री/सुश्री	पद	एसीसी आदेश की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	दूरसंचार	आईटीआइ	के.एल. धींगरा	सीएमडी	1.4.2010
2.	पर्यटन	आईटीडीसी	ललित के. पंवार	सीएमडी	15.4.2010
3.	जल संसाधन	डब्ल्यूएपीसीओएस	आर.के. गुप्ता	सीएमडी	27.4.2010
4.	इस्पात	सेल	सी.एस. वर्मा	अध्यक्ष	4.6.2010
5.	खाद	बीवीएफसीएल	रामेश्वरी सिंह	सीएमडी	22.6.2010
6.	वस्त्र	एचएचईसी	निर्मल सिन्हा	सीएमडी	9.7.2010
7.	भारी उद्योग	टीसीआईएल	ब्रि.एस.के. मुत्रेजा	सीएमडी	16.7.2010
8.	इस्पात	सेल	एस.एस. मोहती	एमडी (सीएसएल)	23.7.2010
9.	विद्युत	एनटीपीसी	ए.आर. चौधरी	सीएमडी	27.7.2010
10.	वाणिज्य	एसटीसीआईएल	एच.पी. गिरीश	एमडी	14.9.2010
11.	खाद	आरसीएफएल	आर.जी. राजन	सीएमडी	30.9.2010
12.	रेलवे	केआरसीएल	बी.पी. तयाल	एमडी	26.10.2010

1	2	3	4	5	6
13.	भारी उद्योग	सीसीआईएल	आर.पी. टक	सीएमडी	22.11.2010
14.	पी एंड एनजी	बीपीसीएल	आर.के. सिंह	सीएमडी	8.12.2010
15.	भारी उद्योग	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	गिरीश कुमार	एमडी	9.12.2010
16.	कोयला	ईसीएल	राकेश सिन्हा	सीएमडी	21.12.2010
17.	पोत परिवहन	सीएसएल	कमोडोर. के. सुब्रह्मण्यम	सीएमडी	30.12.2010
18.	रसायन और पेट्रोलियम	एचएएल	के.के. वियजकुमार	एमडी	25.1.2011
19.	कोयला	एमसीएल	ए.एन. सहाय	सीएमडी	7.2.2011
20.	पी एंड एनजी	आईओसीएल	आर.एसत्रबुटोला	अध्यक्ष	26.12.2011
21.	वस्त्र	सीसीआई	बी.के. मिश्रा	सीएमडी	3.3.2011
22.	हाउसिंग एवं यूपीए	एचयूडीसीओ	वी.पी. बालीगर	सीएमडी	15.3.2011
23.	भारी उद्योग	एचसीएल	ब्रिग. शेखर विश्वनाथन	सीएमडी	25.3.2011
24.	वस्त्र	बीआईसी	हीरक उपाध्याय	सीएमडी	31.3.2011

वर्ष 2011-12

क्रम सं.	मंत्रालय और विभाग	पीएसयू	पदाधिकारी का नाम सर्व/श्री/सुश्री	पद	एसीसी आदेश की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	शहरी विकास	एनबीसीसी	वी.पी. दास	सीएमडी	4.4.2011
2.	पेट्रोलियम और एनजी	एनआरएल	दीपक चक्रवर्ती	एमडी	1.4.2011
3.	दूर संचार	बीएसएनएल	आर.के. उपाध्याय	सीएमडी	29.4.2011
4.	रेलवे	डीएफसीसीआईएल	आर.के. गुप्ता	एमडी	3.5.2011
5.	रेलवे	सीआरआईएस	वी.ए. चोपड़ा	एमडी	26.5.2011
6.	रक्षा उत्पाद	एचएसएल	रिअर एडमिरल निजुंज किशोर मिश्रा	सीएमडी	25.5.2011

1	2	3	4	5	6
7.	विद्युत	एनईईपीसीओ	पी.सी. पंकज	सीएमडी	2.6.2011
8.	रसायन और पेट्रोलियम	एचओसीएल	आर.एनत्र मदनगिरी	सीएमडी	7.6.2011
9.	परमाणु ऊर्जा	यूसीआईएल	दिवाकर आचार्य	सीएमडी	4.7.2011
10.	वस्त्र	एनजेएमसी	अरूंधती पांडा	सीएमडी	4.7.2011
11.	इस्पात	आरआईएनएल	ए.पी. चौधरी	सीएमडी	25.7.2011
12.	खाद	पीडीआईएल	एम. रवि कांत	सीएमडी	28.7.2011
13.	विद्युत	पीजीसीआईएल	आर.एन. नायक	सीएमडी	20.7.2011
14.	नागर विमानन	एआईएल	रोहित नन्दन	सीएमडी	12.8.2011
15.	फार्मास्यूटिकल्स	आईडीपीएल	प्रवीन कुमार	सीएमडी	17.8.2011
16.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	एसईसी	अनिल काकोडकर	अध्यक्ष	26.8.2011
17.	रक्षा उत्पाद	बीईएल	अनिल कुमार	सीएमडी	25.8.2011
18.	रक्षा उत्पाद	जीआरएसईएल	रिअर एडमिरल ए.के. वर्मा	सीएमडी	30.8.2011
19.	रक्षा उत्पाद	एचएएल	के. नरेश बाबू	एमडी (बंगलौर कॉम्पलैक्स)	2.9.2011
20.	रेलवे	आरसीआईएल	आर.के. बहुगुणा		2.9.2011
21.	पेट्रोलियम और एनजी	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल)	डी.के. सर्राफ	एमडी	13.9.2011
22.	रेलवे	एमआरवीसी	राकेश सक्सेना	एमडी	13.9.2011
23.	भारी उद्योग	एचएमटी लिमिटेड	एस.जी. श्रीधर		15.9.2011
24.	पेट्रोलियम और एनजी	ओएनजीसी	एस. वसुदेव	सीएमडी	3.10.2011
25.	पेट्रोलियम और एनजी	बी एंड एल को. लिमिटेड	वीरेंद्र सिन्हा	सीएमडी	5.10.2011
26.	रेलवे	आईआरएफसी	राजीव दत्त	एमडी	7.10.2011
27.	वाणिज्य	ईसीजीसी	एन. शंकर	सीएमडी	10.10.2011
28.	पोत परिवहन	डीसीआई	डी.के. मोहंती	सीएमडी	11.11.2011

1	2	3	4	5	6
29.	रेलवे	सीआरडबल्यूसी	विनोद अस्थाना	एमडी	21.11.2011
30.	विद्युत	आरईसी	राजीव शर्मा	सीएमडी	29.11.2011
31.	दूर संचार	एमटीएनलएल	अशोक कुमार गर्ग	सीएमडी	30.11.2011
32.	दूर संचार	टीओआईएल	विमन वाखलू	सीएमडी	15.12.2011
33.	भारी उद्योग	एचपीसी	एम.वी. नरसिम्हाराव	सीएमडी	16.12.2011
34.	रसायन और पेट्रोकेमिकल	बीसीपीएल	पी.एन. प्रसाद	प्रबंधक निदेशक	22.12.2011
35.	विद्युत	एसजेवीएनएल	आर.पी. सिंह	सीएमडी	30.1.2012
36.	रक्षा	एमडीएल	आर.के. श्रावत	सीएमडी	7.2.2012
37.	इस्पात	एमीईसीओएन लिमिटेड	के.के. महरोत्रा	सीएमडी	10.2.2012
38.	रक्षा	सीसीएल	गोपाल सिंह	सीएमडी	10.2.2012
39.	रक्षा	एनएलसी	ए. सुंदर मोहन	सीएमडी	24.2.2012
40.	रक्षा उत्पाद	एचएएल	आर.के. त्यागी	अध्यक्ष	29.2.2012
41.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ओआईएल	एस.के. श्रीवास्तव	सीएमडी	20.3.2012
42.	भारी उद्योग	एचएमटी-एमटी	एम.डी. श्रीकुमार	सीएमडी	21.3.2012
43.	रक्षा	बीडीएल	एस.एन. मंथा	सीएमडी	28.3.2012

2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी

1952. **श्री दिनेश चंद्र यादव :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री नीरज़ शेखर :
श्री पी. लिंगम :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :
श्री यशवीर सिंह :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुई 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल बोली लगाने वालों के नाम क्या हैं तथा सरकार द्वारा इससे प्राप्त ब्लॉक-वार/सर्किल-वार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ख) क्या नीलामी से प्राप्त राजस्व सरकार द्वारा अनुमानित लक्ष्य से बहुत कम है और यहां तक कि कुछ टेलीकॉम सर्किलों के लिए कोई बोली लगाने वाला नहीं था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) टेलीकॉम सर्किल के शेष क्षेत्रों के स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सरकार द्वारा क्या भावी योजना बनाई गई है;

(ङ) क्या सरकार ने कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम में से स्पेक्ट्रम के केवल एक भाग की नीलामी को शामिल किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) उन बोलीदाताओं के नाम निम्नवत हैं जिन्होंने हाल ही में आयोजित की गई स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया :-

(i) मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड।

(ii) मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड।

(iii) मैसर्स वोडाफोन साउथ लिमिटेड।

(iv) मैसर्स वीडियोकॉन टैलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड।

(v) मैसर्स टेलीविंग्स कम्युनिकेशंस सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड।

1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त सर्किल-वार बोली मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) नीलामी के लिए पेश 1800 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज दोनों बैंड्स के लिए आरक्षित मूल्य के आधार पर 40,000 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व थे। 1800 मेगाहर्ट्ज की नीलामी से प्राप्त बोली मूल्य 9407.64 करोड़ रुपए था। 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान दूरसंचार सेवा क्षेत्रों के लिए और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में सभी सेवा क्षेत्रों के लिए कोई भी बोलीदाता नहीं था।

(घ) शेष दूरसंचार सर्किलों के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था, 800 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज के 2जी बैंड्स में स्पेक्ट्रम को सभी 22 दूरसंचार सर्किलों में नीलामी हेतु पेश किया गया। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कुल 95 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (सीडीएमए) की नीलामी की गई और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कुल 295 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (जीएसएम) की नीलामी की गई जिससे (122 लाइसेंसधारकों को आवंटित 473.6 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 413.6 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 60 मेगाहर्ट्ज) की मात्रा के मद्देनजर) कुल 390 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। आयोजित की गई नीलामी प्रक्रिया में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए कोई भी बोली नहीं की गई। 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड हेतु नीलामी प्रक्रिया जोकि 12.11.2012 को प्रारंभ हुई वह प्रक्रिया दिनांक 14.11.2012 को समाप्त हो चुकी है। इसमें प्रत्येक भागीदार ने समान मात्रा में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। प्रत्येक 1.25 मेगाहर्ट्ज के कुल 102 ब्लॉकों यानि नीलामी में प्रस्तुत 295 मेगाहर्ट्ज के मद्देनजर दिनांक 14.11.2012 को समाप्त 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड को नीलामी में 127.7 मेगाहर्ट्ज के लिए बोलीदाताओं को अनुमोदित किया गया है।

विवरण

1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी

नीलामी प्रारंभ होने की तारीख एवं समय	12.11.2012 प्रात:	09.00 बजे
नीलामी समाप्त होने की तारीख एवं समय	14.11.2012	18.00 बजे
संचालित किए गए कुल चक्र	14	

सेवा क्षेत्र	आवंटित ब्लाकों की संख्या	आवंटित ब्लॉकों का कुल मूल्य (करोड़ रुपए में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4	1147.64
असम	7	60.69
बिहार	11	510.73
दिल्ली	0	0.00
गुजरात	8	1798.72
हरियाणा	6	279.12
हिमाचल प्रदेश	1	7.78
जम्मू और कश्मीर	6	37.98
कर्नाटक	0	0.00
केरल	1	65.30

1	2	3
कोलकाता	4	454.88
मध्य प्रदेश	6	323.94
महाराष्ट्र	5	1314.05
मुंबई	0	0.00
पूर्वोत्तर	6	53.04
ओडिशा	6	121.62
पंजाब	1	67.28
राजस्थान	0	0.00
तमिलनाडु	4	1224.36
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9	685.53
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	10	1074.10
पश्चिम बंगाल	7	180.88
कुल	102	9407.64

[अनुवाद]

शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन

1953. **श्री सुरेश कलमाडी :**
डॉ. मन्दा जगनाथ :
श्री अनंत कुमार :
श्री उदयन राजे भोंसले :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री प्रदीप माझी :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 देश के सभी स्कूलों पर लागू है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उन्हें आवंटित धनराशि के अलावा अतिरिक्त निधि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कुछ राज्य अधिनियम के क्रियान्वयन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(छ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी/उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 आर.टी.ई. अधिनियम की धारा (2) के खंड (ढ) में उल्लिखित सभी स्कूलों पर लागू होता है। परंतु यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), जो आर.टी.ई. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, के अंतर्गत निधियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर प्रदान की जाती हैं। आर.टी.ई. अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा, राज्यों के संबंध में एस.एस.ए. के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच निधीयन की पद्धति संशोधित करके 65:35 कर दी गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए निधीयन की पद्धति 90:10 के अनुपात में है। वित्त आयोग ने भी आर.टी.ई. अधिनियम के फलस्वरूप पड़ने वाले राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए राज्यों के लिए अतिरिक्त उद्दिष्ट निधियां प्रदान की हैं।

(ङ) से (ज) सभी राज्यों ने आर.टी.ई. नियम अधिसूचित कर दिए हैं तथा अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों और स्तरों को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। एस.एस.ए. निधियों का जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा और राज्य में किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रूपए में)

क्र .सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		जारी#	व्यय*	जारी#	व्यय*	जारी#	व्यय*	जारी# (22.11.2012 तक)	व्यय* (30.06.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	38569.90	72257.36	81000.00	144044.00	183551.72	337247.68	111049.46	18723.05
2.	अरूणाचल प्रदेश	11427.95	12427.83	20401.77	20993.09	23880.10	26705.67	17984.73	3821.34
3.	असम	47480.00	50780.61	76854.35	85575.16	106921.15	124930.52	90881.60	8343.14
4.	बिहार	121739.06	224870.24	204789.63	349506.91	185108.20	408963.04	272462.25	61369.24
5.	छत्तीसगढ़	55592.82	96340.63	87863.00	123107.25	69870.22	133902.11	85015.73	23821.26
6.	गोवा	550.58	1212.60	671.27	1459.10	1079.14	1934.35	513.04	112.16
7.	गुजरात	20031.73	40058.48	44065.01	82624.00	88027.79	141781.07	83918.08	62555.53
8.	हरियाणा	27600.00	45620.98	32786.11	64378.71	40461.41	77193.80	29910.35	12928.43
9.	हिमाचल प्रदेश	8608.00	14610.06	13786.66	21756.06	14192.78	25196.78	7052.93	2865.36
10.	जम्मू और कश्मीर	37363.27	22257.61	40348.79	64000.64	30070.50	104733.46	40805.85	9466.29
11.	झारखंड	70940.22	119946.99	89562.26	159246.86	57903.46	117232.77	56183.87	11477.37
12.	कर्नाटक	44220.60	83028.85	66903.00	114457.93	62788.35	124995.76	39936.69	23142.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	11989.50	19233.00	19660.73	26071.88	17021.85	26046.45	13449.14	12114.25
14.	मध्य प्रदेश	113249.00	194011.77	176783.00	293543.00	190427.12	342831.85	80343.30	104441.26
15.	महाराष्ट्र	56432.00	107883.64	85537.00	143200.00	117962.58	181066.45	99574.73	12229.73
16.	मणिपुर	1500.00	1443.14	13253.77	10659.22	3940.55	8389.53	15862.44	3007.79
17.	मेघालय	9383.00	12093.67	18540.90	20050.00	14410.60	19782.59	13670.78	4698.76
18.	मिजोरम	6617.75	8254.45	10115.31	9073.47	10814.05	14084.57	7820.60	3249.53
19.	नागालैंड	4913.00	5439.51	8636.83	10349.83	9798.33	10315.05	7791.12	483.79
20.	ओडिशा	63061.60	112011.89	73177.85	146508.08	92719.98	162570.06	100807.62	25121.83
21.	पंजाब	20044.00	36772.00	39612.74	55943.00	48112.44	64703.06	41972.68	3111.80
22.	राजस्थान	127124.00	199893.55	146182.29	270368.00	148580.86	313064.40	143520.11	75338.71
23.	सिक्किम	1736.00	2040.90	4469.19	3915.93	4022.84	4453.04	1493.85	552.71
24.	तमिलनाडु	48366.00	78267.24	69068.57	119480.84	68141.96	116817.50	38672.47	14201.40
25.	त्रिपुरा	7473.00	9196.44	17121.48	14283.80	17493.76	24263.63	8010.11	470.00
26.	उत्तर प्रदेश	196011.90	335048.80	310462.88	511096.00	263682.61	515804.16	362476.26	73330.27
27.	उत्तराखंड	16006.29	27187.03	25793.94	36831.60	20892.49	39936.44	17941.10	7728.56
28.	पश्चिम बंगाल	104142.00	162540.01	174703.17	305333.13	177652.74	298627.19	258056.58	62008.52
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	412.44	724.18	357.78	885.55	907.36	1606.37	589.28	172.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	1100.72	2063.43	2155.89	2566.09	1611.21	3301.27	972.64	575.28
31.	दादरा और नगर हवेली	350.18	631.10	413.78	692.07	564.35	796.36	152.76	117.99
32.	दमण और दीव	169.00	324.15	162.99	374.81	257.06	485.42	233.12	19.95
33.	दिल्ली	3088.62	3684.61	3552.71	4657.72	3783.29	8008.74	3251.90	1261.16
34.	लक्षद्वीप	143.80	245.51	127.39	292.95	127.86	363.28	57.62	0.00
35.	पुदुचेरी	669.96	1124.64	485.38	1296.00	757.62	1275.50	518.91	151.77
	कुल	1278107.89	2103526.90	1959407.42	3218622.68	2077538.33	3783409.92	2052953.70	643012.95

भारत सरकार द्वारा जारी निधियां

* व्यय में भारत सरकार और राज्य के हिस्से की जारी गई निधियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

स्वदेशी अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करना

1954. **श्री विश्व मोहन कुमार :**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार, गुजरात और राजस्थान सहित राज्य सरकारों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा स्वदेशी अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्वसंबंधी वर्ष-वार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कोई प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित नहीं करते और इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) के विकास तथा स्वदेशी अनुसंधान परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु राज्य-वार आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि ये मंत्रालय अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) पुरस्कार स्कीम, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एस एस टी पी) तथा पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पी एफ सी) कार्यक्रम जैसी कुछ केंद्रीय स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ कार्य करते हैं और इ नसे प्रस्ताव मंगाते हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-13 और 2012-13 (वर्तमान वर्ष) के लिए इंस्पायर पुरस्कार, एस एस टी पी और पी एफ सी कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) की इंस्पायर पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत, पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 6 से 10वीं कक्षा वाले देश के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर स्कूलों से विज्ञान प्रोजेक्ट/मॉडल तैयार करने के लिए 5,000/- रु. प्रत्येक के इंस्पायर पुरस्कार के लिए दो छात्रों को चुना जाता है। स्कूलों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य को शामिल करते हुए राज्य सरकार के कार्यतंत्र द्वारा विद्यार्थियों का प्रतिभा आधारित चयन किया जाता है। पुरस्कार की राशि को बैंक द्वारा जारी इंस्पायर पुरस्कार अधिपत्र के रूप में चयनित विद्यार्थी को सीधे भेजा जाता है। ये पुरस्कार विजेता जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताओं (डी एल ई पी सी) में भाग लेते हैं और जिले की 5% से 10% सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताओं (एस एल ई पी सी) में भाग लेने के लिए चुना जाता है। कम से कम 5 प्रविष्टियों के अध्यधीन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ 5% प्रविष्टियों को राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता (एन एल ई पी सी) में भाग लेने के लिए चुना जाता है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सभी 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के संचालन की संपूर्ण लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिला और राज्य स्तरों पर प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए राशि को इंस्पायर के प्रभारी राज्य नोडल अधिकारी को जारी किया जाता है।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डी एस टी) के राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एस एस टी पी) के अंतर्गत बिहार, गुजरात और राजस्थान राज्यों सहित राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को वार्षिक मुख्य अनुदान सहायता प्रदान की गई है। राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों की आयोजना, अनुवीक्षण और कार्यान्वयन में इन परिषदों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को यह मुख्य सहायता दी जाती हैं इस मुख्य अनुदान सहायता में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक मानव शक्ति, यातायात, कार्यालयी खर्चों तथा आधुनिक कार्यालय संबंधी उपकरणों आदि के लिए आंशिक रूप से सहायता शामिल होती है।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) के पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पी एफ सी) कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य स्तर पर पेटेंट, कापीराइट, भौगोलिक संकेत आदि सहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर) के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने और सहायता प्रदान करने के लिए गुजरात और राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्यों में 24 पेटेंट सूचना केंद्रों (पी आई सी) को सहायता प्रदान की जाती है। ये पी आई सी अपने संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालय बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ (आई पी सी यू) भी सृजित कर रहे हैं। अब तक राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 84 आई पी सी यू का सृजन किया गया है। पी आई सी स्थापित करने के लिए बिहार राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विगत तीन वर्षों (2009-10, 2010-11, 2011-12) और चालू वर्ष (2012-13, नवम्बर तक) के दौरान उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदानों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान राज्यों को दिए गए कार्यक्रम-वार और वर्ष-वार अनुदानों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(कुल रू. में)

कार्यक्रम का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-12 (नवम्बर तक)	कुल
इंस्पायर पुरस्कार*	8283.40 (1.27 लाख)	15125.05 (2.05 लाख)	15095.07 (2.43 लाख)	4335.06 (0.65 लाख)	42838.58 (6.85 लाख)
एस एस टी पी	935.20	1317.64	1480.14	761.75	4494.73
पी एफसी	45.83	78.00	51.62	42.04	217.49
कुल	9264.43	16520.69	16626.83	5138.85	47550.80

*कोष्ठक में दी गई संख्या सभी राज्यों के लिए इंस्पायर पुरस्कार की संख्या को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त, इन दो मंत्रालयों ने राज्य सरकारों से स्वप्रेरणा से सीमित संख्या में प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। राज्य सरकारें इन प्रस्तावों के माध्यम से नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार (क) विज्ञान सिटी/संग्रहालय/केंद्र (ख) नए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संस्थानों और प्रयोगशालाओं (ग) केंद्र सरकार द्वारा कुछ राज्य सहायित आर एंड डी संस्थानों के अधिग्रहण (घ) राज्य स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना आदि जैसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचनाओं की स्थापना की मांग करती है :

प्रस्तावों की प्रकृति	राज्य	विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में संबद्ध विभाग	स्थिति
1	2	3	4
(क) विज्ञान सिटी/संग्रहालय/केंद्र	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात	-	संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया
(ख) नए आर एंड डी संस्थान और प्रयोगशालाएं			
1. श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र	वयनाड, केरल	डी एस टी	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4
2. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन केंद्र	रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यलय, छत्तीसगढ़	डी एस टी	स्थापित
3. राष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान	मोहाली, पंजाब	डी बी टी	स्थापित
4. नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	मोहाली, पंजाब	डी एस टी	प्रक्रियाधीन
5. उष्कणटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान	पलोड, केरल	डी एस टी	प्रक्रियाधीन
6. राजीव गांधी सृजनात्मकता संस्थान	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	डी एस आई आर	प्रक्रियाधीन
7. उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (एन ई सी टी ए आर)	अन्य पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रीय केंद्रों के साथ शिलांग, मेघालय	डी एस टी	अनुमोदित
(ग) केंद्र सरकार द्वारा कुछ राज्य सहायित आर एंड डी संस्थानों का अधिग्रहण			
1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान	गुवाहाटी, असम	डी एस टी	अधिग्रहित
2. राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र	तिरूअन्तपुरम, केरल	डी बी टी	अधिग्रहित
3. पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी ई एस एस)	तिरूअन्तपुरम, केरल	एम ओ ई एस	प्रक्रियाधीन
(घ) राज्य स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना का सृजन आदि	कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहले से स्थापित	डी एस टी	भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत-सभी राज्यों को चरणवार रूप से शामिल किया जाएगा।

(ग) और (घ) इंस्पायर पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारों यथा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी के वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्ताव लंबित हैं, चूंकि ये अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। वर्तमान विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता के कारण गुजरात राज्य के लिए प्रस्ताव लंबित हैं। इसी तरह, एस एस टी पी में भी, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, करेल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 2012-13 हेतु मुख्य अनुदान को जारी करने के लिए राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के कुछ प्रस्ताव लंबित है, चूंकि ये अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। अंडमान और निकोबार, बिहार और राजस्थान से वर्ष 2012-13 के लिए मुख्य अनुदान को जारी करने हेतु प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा है। वर्ष 2012-13 के लिए पी आई सी वार्षिक अनुदान हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) लंबित प्रस्तावों के दिसम्बर, 2012-13 तक पूरा होने की आशा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (2009-10, 2010-11, 2011-12) और चालू वर्ष (2012-13 नवम्बर तक) के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता के वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

(रू. लाख में)

राज्य	अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) इंस्पायर पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किए गए पुरस्कारों एवं राशि की संख्या और जिला/राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताएं (डी एल ई पी सी)					राज्य विज्ञान औरप्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एसव एस टी पी) विभिन्न राज्य परिषदों को प्रदान की गई मुख्य सहायता					पेटेन्ट सुगमीकरण प्रकोष्ठ कार्यक्रम पेटेंट सूचना केंद्र तथा विश्वविद्यालयों में बौद्धिक सम्पदा प्रकोष्ठ को प्रदान किया गया अनुदान				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2009-10	2010-11	2010-12	2010-13	कुल	2009-10	2010-11	2011-12	2912-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	–	2053.06 (29282)	844.65 (16893)	563.74 (8950)	3461.45 (55125)	35.00	51.00	58.00	62.74	206.74	–	7.37	–	–	7.37
अरुणाचल प्रदेश	–	2.35 (47)	26.15 (303)	4.96 (88)	33.46 (438)	43.50	53.00	73.50	–	170.00	–	7.37	–	–	7.37
असम	–	80.51 (1093)	102.74 (2045)	87.74 (991)	270.99 (4129)	41.00	53.00	59.00	–	153.00	4.29	4.67	4.67	4.67	18.30
बिहार	432.25 (6645)	412.95 (8439)	219.65 (4393)	429.87 (8456)	1503.72 (27933)	19.46	18.68	36.26	–	74.40	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	1019.95 (20399)	1195.24 (14942)	90.33 (259)	2305.52 (35600)	31.00	55.45	6203	74.32	222.80	–	–	–	–	–
गोवा	2.50 (50)	3.55 (71)	15.01 (277)	4.45	25.51 (398)	43.00	61.50	52.31		156.81	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
गुजरात	962.45 (16249)	270.25 (5405)	1086.14 (21670)	766.36 (15267)	3085.20 (58591)	49.00	53.00	66.09	56.00	224.09		4.50	4.66	–	9.10
हरियाणा	113.65 (2273)	490.80 (9816)	397.07 (2748)	1.35	1002.87 (14837)	19.64	19.04	23.00	–	61.68	–	5.23	–	–	5.23
हिमाचल प्रदेश	47.15 (943)	57.10 (1142)	404.31 (7143)	150.83 (137)	659.39 (9365)	50.00	65.00	73.00	–	188.00	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	324.04 (4994)	221.13 (3712)	9.85	555.02 (8706)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड	–	–	438.24 (6728)	254.59 (5061)	692.83 (11789)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	4.45 (89)	1931.98 (27084)	1972.88 (39412)	420.35 (4847)	4329.66 (71432)	48.42	72.50	79.50	–	200.42	–	–	2.89	6.75	9.64
केरल	117.10 (2342)	113.04 (877)	164.78 (3286)	214.31 (4261)	609.23 (10766)	39.00	61.00	69.00		169.00	9.31	4.62	4.39	3.78	22.10
मध्य प्रदेश	1905.95 (31379)	1345.00 (26900)	1552.75 (21201)	178.97	4982.67 (79480)	64.50	81.00	93.00	105.38	343.88	–	6.74	–	–	6.74
महाराष्ट्र	–	3463.52 (48834)	841.94 (13906)	232.81 (4596)	4538.27 (67336)	14.00	14.00	14.00	–	42.00	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	16.45 (329)	44.65 (521)	0.72	61.82 (850)	51.05	59.30	74.00	–	184.35	–	–	–	–	–
मेघालय	5.30 (106)	23.55 (471)	71.93 (1334)	16.34	117.12 (1911)	10.54	11.25	14.50	–	36.39	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मिजोरम	–	115.23 (1589)	41.46 (818)	10.23	166.92 (2407)	26.00	34.00	41.00	52.00	153.00	7.37	–	–	4.67	12.04
नागालैंड	–	–	14.60 (292)	7.52	22.12 (292)	–	30.40	44.00	46.00	120.40	–	–	7.37	–	7.37
ओडिशा	–	281.31 (3922)	541.90 (10838)	231.18	1055.02 (14760)	–	–	–	–	–	–	–	7.37	–	7.37
पंजाब	458.65 (6173)	233.25 (4665)	55.83 (836)	335.33 (6684)	1083 (18358)	85.50	95.50	110.00	125.50	416.50	5.72	9.05	9.05	9.05	32.87
राजस्थान	2100.85 (35217)	1354.50 (27090)	568.26 (11318)	13.85 (277)	4037.46 (73902)	63.04	77.90	84.50	–	225.44	–	–	–	–	–
सिक्किम	1.10 (22)	6.30 (126)	31.93 (483)	5.93	45.26 (631)	48.16	92.63	68.00		208.79	3.72	2.00	1.72	3.52	10.96
तमिलनाडु	663.35 (10267)	715.55 (14311)	722.07 (8847)	9.03	2110 (33425)	50.15	65.87	66.52	51.34	233.88	–	7.62	–	4.87	12.49
त्रिपुरा	5.35 (47)	8.50 (170)	78.96 (1500)	34.62	127.434 (1717)	20.00	27.00	33.00	–	80.00	4.73	4.83	4.63	4.73	18.92
उत्तर प्रदेश	1228.75 (9975)	424.60 (8492)	2940.63 (38663)	84.45 (1689)	4678.43 (58819)	70.50	86.50	96.50	110.50	364.00	3.37	2.65	–	–	6.02
उत्तराखंड	–	18.65 (373)	63.61 (743)	130.01 (2592)	212.27 (3708)	37.50	55.00	61.50	77.97	231.97	–	7.37	4.87	–	12.24
पश्चिम बंगाल	186.80 (3736)	291.76 (2922)	271.00 (5384)	19.55 (349)	769.11 (12391)	16.15	14.77	18.83	–	49.75	7.32	3.98	–	–	11.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.05 (21)	6.05 (121)	8.16 (60)	3.82 (62)	19.08 (264)	6.34	9.35	9.10	–	24.79	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	4.25 (85)	2.80 (56)	16.53 (200)	8.01 (152)	31.59 (493)	2.90	–	–	–	2.90	–	–	–	–	–
दादर और नागर हवेली	–	–	8.96 (128)	6.55 (117)	15.51 (245)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	2.25 (45)	–	6.90 (96)	5.19 (94)	14.34 (235)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	0.45 (9)	–	0.87 (8)	0.52	1.84 (17)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	33.65 (673)	31.50 (630)	110.41 (1687)	–	175.56 (2990)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुदुचेरी	6.10 (122)	17.95 (359)	13.73 (246)	1.07	38.85 (727)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	8283.4 (126468)	15125.05 (250009)	15095.07 (242661)	4335.06 (64929)	42838.58 (684067)	935.20	1317.64	1480.14	761.75	4494.73	45.83	78.00	51.62	42.04	217.49

कोष्ठक में दी गई संख्या इन राज्यों में विद्यार्थियों को दिए गए इन्सपायर पुरस्कार की संख्या दर्शाती है।

[अनुवाद]

मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का प्रक्षेपण

1955 **श्री एंटो एंटोनी** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जलवायु की स्थिति की निगरानी के लिए इनसैट थ्री-डी नामक मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह के प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसैन थ्री-डी उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस परियोजना पर कब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक अत्याधुनिक मौसमविज्ञानी उपग्रह, इन्सैट-3डी के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। भू-आधारित पर्यवेक्षणें सहित इस उपग्रह से प्राप्त आंकड़े जलवाई की स्थितियों के बारे में सूचना व्युत्पन्न करने में मदद करेंगे।

(ख) इन्सैट-3डी अपने साथ जिन दो उपकरणों को ले जाएगा वे हैं-(I) एक दृश्य और पांच अवरक्त चैनलों सहित छः चैनल वाला प्रतिबिंबक; और (II) एक दृश्य और अठारह अवरक्त चैनलों सहित उन्नीस चैनलवाला परिज्ञापी। प्रतिबिंबक पृथ्वी के बिंब उत्पन्न करेगा और बहिर्गामी दीर्घ-तरंग विकिरण, परिमाणात्मक अवक्षेपण आकलन, समुद्री सतह तापमान, हिम आवरण, मेघ गति पवन, इत्यादि जैसे विविध प्राचलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। परिज्ञापी आर्द्रता और तापमान के ऊर्ध्वाधर पार्श्वदृश्य, कुल अवक्षेपणीय जल इत्यादि जैसे विविध मौसमविज्ञानी प्राचलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उपग्रह का द्रव्यमान लगभग 2100 कि.ग्राम. होगा। उपग्रह को प्रारंभिक रूप में 82° पूर्व देशांतर की भूस्थिर कक्षा से प्रचालित किया जाएगा।

(ग) इन्सैट-3डी उपग्रह के निर्माण के लिए अब तक (लगभग) रु. 225 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है। इन्सैट-3डी के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्राप्त करने हेतु 50 की अग्रिम अदायगी के रूप में अब तक 221 करोड़ की कुल धनराशि खर्च की गई है। सभी उपप्रणाली पैकेजों और नीतभार अवयवों (प्रतिबिंबक एवं परिज्ञापी तथा संबंधित इलेक्ट्रानिकी) का समुच्चयन किया गया है। समेकित उपग्रह की विद्युतीय और तापीय जांच पूरी कर ली गई है। इस समय उपग्रह तैयारी के अग्रिम चरण में है।

(घ) उपग्रह को प्राप्त प्रक्षेपक द्वारा 2013 की तीसरी तिमाही के दौरान प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई है।

एन.ए.एम. शिखर सम्मेलन

1956. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने तेहराहन में 16वें एन.ए.एम. शिखर सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अन्य देशों के नेताओं के साथ बैठकें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) तेहरान, ईरान में 30-31 अगस्त, 2012 तक आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े राष्ट्रध्यक्षों एवं सरकारों के 16वें शिखर सम्मेलन में सम्मलित होने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इस शिखर सम्मेलन में अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था व वित्तीय प्रबंधन, स्थायी खाद्य एवं ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, गरीबी उन्मूलन, भूख एवं लाभवंचन मुक्ति, रोग-व्याधियों, साक्षरता स्तरों से लड़ने, चिरस्थायी विकास सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से लड़ने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।

(ग) और (घ) गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से पूर्व ईरान की अपनी द्विपक्षीय यात्रा के भाग के रूप में, प्रधानमंत्री ने महान नेता अयातुल्लाह सैय्यद अली खुमेनी और राष्ट्रपति महमूद अहमदनिजाद से 29 अगस्त, 2012 को मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान दोनों पक्षों ने हमारे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का स्मरण किया और हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधी की स्थिति

की समीक्षा की। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश तथा सीरिया के प्रधानमंत्रीयों से मुलाकात की थी, जहां द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गयी।

आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी

1957. श्री एम. के. राघवन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की राज्य-वार विद्यमान कुल संख्या कितनी है तथा केन्द्र के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या इन दो संवर्गों में अधिकारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कमी किस स्तर पर है;

(घ) राज्य सेवाओं से पदोन्नति सहित इन पदों को भरने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सी.एस.एस. अधिकारियों को आई.ए.एस. में शामिल करने का है जैसा कि राज्य सेवा से किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) एवं भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के पदस्थ अधिकारियों की राज्य-वार कुल प्राधिकृत संख्या, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सी.डी. आर.); एवं अधिकारियों की कमी संबंधी ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में विभिन्न स्तर पर कमी संबंधी ब्यौरों को केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) सरकार ने सीधी भर्ती कोटा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की वार्षिक भर्ती में बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुलिस सेवा की भर्ती में भर्ती की तीसरी विधि नामत: समीति प्रतिस्पर्धी परीक्षा की शुरुआत की गई है। पदोन्नति कोटा में, राज्य सेवा के अधिकारियों का पदोन्नति/चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित करने के क्रम में तुरंत कार्रवाई की गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नतियों द्वारा नियुक्ति) .विनियमन 1955 एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1997 जो इस विषय को अधिशासित करते हैं, में केवल राज्य विविल सेवा के अधिकारियों/गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के नाम पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश देने के लिए विचार करने की व्यवस्था है।

विवरण-I

1.1.2012 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) में संवर्ग में पदों की कमी और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व

क्र .सं.	संवर्ग	कुल प्राधिकृत संख्या	1.1.2012 तक की स्थिति के अनुसार कुल पदस्थ अधिकारी	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	कमी (3-4)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	376	284	81	92
2.	ए.जी.एम.यू.टी.	337	221	73	116

1	2	3	4	5	6
3.	असम-मेघालय	248	205	54	43
4.	बिहार	326	198	70	128
5.	छत्तीसगढ़	178	124	38	54
6.	गुजरात	260	208	56	52
7.	हरियाणा	205	178	44	27
8.	हिमाचल प्रदेश	129	101	28	28
9.	जम्मू और कश्मीर	137	91	30	46
10.	झारखण्ड	208	108	45	100
11.	कर्नाटक	299	219	65	80
12.	केरल	214	158	46	56
13.	मध्य प्रदेश	417	299	90	118
14.	महाराष्ट्र	350	295	76	55
15.	मणिपुर-त्रिपुरा	207	137	45	70
16.	नागालैण्ड	91	52	20	39
17.	ओडिशा	226	148	49	78
18.	पंजाब	221	161	48	60
19.	राजस्थान	296	184	64	112
20.	सिक्किम	48	33	10	15
21.	तमिलनाडु	355	286	77	69
22.	उत्तराखण्ड	120	84	26	36
23.	उत्तर प्रदेश	592	376	128	216
24.	पश्चिम बंगाल	314	227	68	87
	कुल	6154	4377	1331	1777

विवरण-II

1.1.2012 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में संवर्ग में कमी और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व

क्र .सं.	संवर्ग	कुल प्राधिकृत संख्या	1.1.2012 तक की स्थिति के अनुसार कुल पदस्थ अधिकारी	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	कमी (3-4)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	258	211	56	47
2.	ए.जी.एम.यू.टी.	295	200	64	95
3.	असम-मेघालय	188	127	41	61
4.	बिहार	231	164	50	67
5.	छत्तीसगढ़	103	77	22	26
6.	गुजरात	195	143	42	52
7.	हरियाणा	137	100	30	37
8.	हिमाचल प्रदेश	89	69	19	20
9.	जम्मू और कश्मीर	147	120	32	27
10.	झारखण्ड	135	95	29	40
11.	कर्णाटक	205	136	44	69
12.	केरल	163	112	35	51
13.	मध्य प्रदेश	291	235	63	56
14.	महाराष्ट्र	302	200	65	102
15.	मणिपुर-त्रिपुरा	156	99	34	57
16.	नागालैण्ड	70	31	15	39
17.	ओडिशा	188	107	41	81
18.	पंजाब	172	109	37	63

1	2	3	4	5	6
19.	राजस्थान	205	162	44	43
20.	सिक्किम	32	30	7	02
21.	तमिलनाडु	263	198	57	65
22.	उत्तराखण्ड	69	56	15	13
23.	उत्तर प्रदेश	489	317	106	172
24.	पश्चिम बंगाल	347	227	75	120
	आई.पी.एस. परिविक्षुओं का 2011 बैच		150		
	कुल	4730	3475	1023	1255

द्विपक्षीय विमान सेवा करार

1958. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके साथ द्विपक्षीय विमान सेवाएं करार विद्यमान हैं;

(ख) उक्त करार के अंतर्गत एयरलाइनों को क्या लाभ मिलते हैं;

(ग) क्या भारतीय विमान कंपनियां उक्त लाभों का उपयोग करने में समर्थ रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय विमान कंपनियों को उनका हक मिले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) भारत ने 109 देशों के साथ द्विपीक्षीय विमान सेवाएं करार (बी.ए.एस.ए.) किया है। देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस प्रकार के करार देशों के बीच विमान संपर्कता के लिए द्विपक्षीय अधिकार प्रदान करते हैं।

(ग) से (ङ) अनुसूचित एयरलाइने यथा एअर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट तथा इंडिगो 2009 के ए.आई.सी. 8 के अनुरूप अपने यातायात अधिकारों का उपयोग कर रही हैं। नागर विमानन मंत्रालय सभी भारतीय वाहकों को विभिन्न देशों में अधिकतम यातायात अधिकार का उपयोग करने हेतु अधिकाधिक द्विपक्षीय यातायात अधिकार प्रदान कर रहे है।

विवरण

उन देशों की सूची जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय विमान सेवा करार किया है

क्र .सं.	देश का नाम	हस्ताक्षर की तिथि/ए.एस.ए. का आरंभ
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	26.01.1952

1	2	3
2.	अल्जीरिया	26.06.2000
3.	आर्मेनिया	05.12.2000
4.	ऑस्ट्रेलिया	06.03.2006
5.	ऑस्ट्रिया	26.10.1989
6.	*अज़रबैजान	28.09.2009
7.	बहरीन	05.04.2000
8.	बांग्लादेश	05.05.1978
9.	*बारबाडोस	01.07.2010
10.	बेलारूस	27.09.1997
11.	बेल्जियम	06.04.1967
12.	भूटान	22.12.2009
13.	बोस्निया और हर्जेगोविना	21.05.2010
14.	ब्राजील	08.03.2011
15.	ब्रुनेई	06.11.1995
16.	बुल्गानिया	16.06.1992
17.	कंबोडिया	09.04.2002
18.	कनाडा	20.07.1982
19.	चीन	22.12.1988
20.	चिली	21.04.2008
21.	क्रोएशिया	12.09.2000
22.	साइप्रस	18.12.2000
23.	चेक गणराज्य	16.10.1997
24.	डेनमार्क	19.12.1995
25.	जिबूती	1.9.05.2003
26.	मिस्र	09.04.1997
27.	इथियोपिया	03.08.1967
28.	फिजी	28.01.1974
29.	फिनलैंड	18.07.1995
30.	फ्रांस	16.07.1947
31.	*जॉर्जिया	04.11.1997
32.	जर्मनी	31.05.1963
33.	घाना	25.01.1978
34.	*ग्रीस	23.10.1997
35.	हांगकांग	10.10.1996
36.	हंगरी	23.02.1966
37.	आइसलैंड	14.01.2010
38.	इंडोनेशिया	25.01.2011
39.	ईरान	09.07.2010
40.	इराक	27.07.1955
41.	आयरलैंड	20.02.1991
42.	इसराइल	04.04.1994
43.	इटली	16.07.1959
44.	जापान	26.11.1955
45.	जॉर्डन	16.10.1989
46.	कजाखस्ता	10.09.1993
47.	केन्या	30.09.2009

1	2	3
48.	कुवैत	04.01.1989
49.	किर्गिस्तान	08.09.1993
50.	लातविया	20.10.1997
51.	लेबनान	19.09.1964
52.	लेसोथो	16.09.1992
53.	लिथुआनिया	20.02.2001
54.	लक्समबर्ग	08.01.2001
55.	मकाओ	11.02.1998
56.	*मेडागास्कर	23.07.1998
57.	मलेशिया	22.05.1974
58.	मालदीव	24.12.2008
59.	माल्टा	05.10.1998
60.	मॉरीशस	28.01.1972
61.	मंगोलिया	30.11.1998
62.	मेक्सिको	17.04.2008
63.	*मोरक्को	11.12.1996
64.	म्यांमार	23.01.1979
65.	नेपाल	16.02.2010
66.	नीदरलैंड	24.05.1951
67.	न्यूजीलैंड	26.08.1997
68.	नाइजीरिया	31.01.1978
69.	नॉर्वे	19.12.1995
70.	ओमान	31.05.1995
71.	पाकिस्तान	16.07.1976
72.	फिलीपींस	20.10.1949
73.	पोलैंड	25.01.1977
74.	पुर्तगाल	06.02.1997
75.	कतर	14.04.2005
76.	*रवांडा	01.07.2010
77.	कोरिया गणराज्य	16.03.1992
78.	रूस	21.12.1998
79.	रोमानिया	04.12.1993
80.	सऊदी अरब	26.04.1973
81.	*सेनेगल	02.07.2010
82.	सेशेल्स	30.10.1978
83.	सिंगापुर	23.01.1968
84.	स्लोवाकिया	09ए10.1996
85.	स्लोवेनिया	16.02.2004
86.	दक्षिण अफ्रीका	04.06.2010
87.	स्पेन	10.04.1987
88.	श्रीलंका	21.12.1948
89.	स्वीडन	19.12.1995
90.	स्विट्जरलैंड	02.05.2001
91.	सीरिया	23.04.1979
92.	ताजिकिस्तान	10.05.2001
93.	तंजानिया	29.09.1982

1	2	3
94.	थाईलैंड	19.12.1969
95.	*ट्यूनीशिया	14.02.2004
96.	तुर्की	10.04.1986
97.	तुर्कमेनिस्तान	14.09.1993
98.	त्रिनिदाद और टोबैगो.	29.11.2011
99.	*संयुक्त अरब अमीरात	05.02.2008
100.	ब्रिटेन	08.09.2005
101.	युगांडा	05.10.1997
102.	यूक्रेन	07.07.1995
103.	संयुक्त राज्य अमेरिका	14.04.2005
104.	उजबेकिस्तान	24.05.1993
105.	वियतनाम	20.05.1993
106.	यमन	20.07.1999
107.	*यूगोस्लाविया	31.01.2003
108.	जाम्बिया	15.11.1993
109.	*जिम्बाब्वे	20.05.2010

[हिन्दी]

छात्र-शिक्षक अनुपात

1959. श्री ए. टी. नाना पाटील :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री गोरखनाथ पाण्डेय :
श्री लालजी टंडन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान के छात्र-शिक्षक अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार शिक्षक-छात्र अनुपात के मामले में राज्य सरकारों के साथ समन्वय करती है या हस्तक्षेप करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ और सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधकार अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप बनाने क लिए संशोधित किया गया है। संशोधित मानदंड निम्नानुसार हैं :-

क. कक्षा I से V के लिए :

(i) प्रवेश दिए गए साठ बच्चों तक दो अध्यापक

(ii) 61 से 90 बच्चों के लिए तीन अध्यापक

(iii) 91-120 बच्चों के लिए चार अध्यापक

(iv) 121-200 बच्चों तक पांच अध्यापक

(v) यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो जाती है तो पांच अध्यापकों के अतिरिक्त एक मुख्य अध्यापक; और छात्र शिक्षक अनुपात (मुख्य अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा, यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है।

ख. कक्षा VI से VIII के लिए

(i) प्रति कक्षा न्यूनतम एक अध्यापक ताकि (क) विज्ञान तथा गणित; (ख) सामाजिक अध्ययन; और (ग) भाषाओं के लिए न्यूनतम एक अध्यापक होगा।

(ii) प्रत्येक 35 बच्चों के लिए न्यूनतम एक अध्यापक;

(iii) जहां प्रवेश दिए गए बच्चे 100 से अधिक हैं, वहां (क) एक पूर्ण-कालीन मुख्य अध्यापक तथा (ख) कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा के लिए अंशकालीन अनुदेशक होगा।

(ग) देश में वर्तमान राज्य-वार छात्र शिक्षक अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार करने के लिए 2012-13 तक 19.82 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30.9.2012 तक 12.48 लाख अध्यापकों की भर्ती की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य क्षेत्र के तहत अध्यापक रिक्तियों के साथ-साथ इन अध्यापक पदों को भरने की सलाह दी गई है। उन्हें स्कूलों को शिक्षा का अधिकार घटक के अनुरूप बनाने के लिए अध्यापकों की तैनाती को सुसंगत बनाने की भी सलाह दी गई है।

विवरण

छात्र-शिक्षक अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर 2011-12	उच्च प्राथमिक स्तर 2011-12
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	10
आंध्र प्रदेश	22	17
अरुणाचल प्रदेश	19	18
असम	30	17
बिहार	59	63
चंडीगढ़	29	29
छत्तीसगढ़	24	24
दादरा और नगर हवेली	40	43
दमन और दीव	33	33
दिल्ली	33	31
गोवा	23	23
गुजरात	31	31
हरियाणा	29	22
हिमाचल प्रदेश	16	16
जम्मू और कश्मीर	14	14
झारखंड	41	42
कर्नाटक	26	23
केरल	21	22
लक्षद्वीप	13	11
मध्य प्रदेश	33	34
महाराष्ट्र	29	32
मणिपुर	19	22
मेघालय	20	15
मिजोरम	17	13
नागालैंड	20	20
ओडिशा	29	24
पुदुचेरी	18	16
पंजाब	22	17
राजस्थान	27	26
सिक्किम	11	12
तमिलनाडु	27	33

1	2	3
त्रिपुरा	19	20
उत्तर प्रदेश	46	44
उत्तराखंड	25	22
पश्चिम बंगाल	27	28
सभी राज्य	31	29

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2011-12।

महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा

1960. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवश्यक व्यवसायिक कौशल हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण" की केंद्रीय प्रायोजित योजना में उच्च रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों में बालिकाओं की सहभागिता और अच्छे प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत विशेष फोकस समूहों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे समूहों से आने वाली बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी व्यवस्था है।

(ग) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के प्रावधानों में नए व्यावसायिक विद्यालय स्थापित करना, मौजूदा व्यावसायिक विद्यालयों को सुदृढ़ बनाना, व्यावसायिक शिक्षा के अध्यापकों का क्षमता निर्माण, दक्षता आधारित पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री का विकास करना शामिल है।

स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा

1961. श्री महेश जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी स्कूलों में पूर्ण विषय के रूप में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए स्कूलों के चयन संबंधी क्या मानदंड हैं; और

(घ) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना" नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत उद्योग/नियोक्ताओं के साथ सहयोग से मांग आधारित माड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान तथा उनका विकास किया जाता है और उन्हें उच्चतर माध्यमिक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूलों के माध्यम से एक वैकल्पिक विषय के रूप में उनकी पेशकश की जाती हैं। योजना में नए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना, मौजूदा व्यावसायिक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक शिक्षा शिक्षकों की क्षमता का निर्माण, योग्यता आधारित पाठ्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री का विकास आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/निजी-गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्कूलों का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना" नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा पैदा करना

1962. डॉ. थोकचोम मैन्या :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री प्रेम दास राय :

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूकंपीय क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की अवस्थिति का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न परमाणु विद्युत संयंत्रों को आबंटित/व्यय निधि का संयंत्र और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पैदा की गई परमाणु विद्युत की संयंत्र-वार और वर्ष-वार मात्रा कितनी है;

(घ) एशियाई विकासशील और विकसित देशों के बीच परमाणु ऊर्जा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में देश का क्या स्थान है;

(ङ) क्या सरकार का विचार परमाणु विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) राजस्थान में रावतभाटा तथा तमिलनाडु में कलपाक्कम और कुडनकुलम भूकंपीय क्षेत्र-II में अवस्थित हैं। महाराष्ट्र में तारापुर, गुजरात में काकरापार और कर्नाटक में कैगा भूकंपीय क्षेत्र-III में अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में नरोरा भूकंपीय क्षेत्र-IV के अंतर्गत आता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और योजनाओं के संबंध में आबंटित/व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (अक्तूबर 2012 तक)	
आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय
2912.70	2710.86	3675	2470.32	4901	3406.33	5756	2313.93

(ग) ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवस्थिति तथा राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	मिलियन यूनिट (एम.यूज) में सकल उत्पादन			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
		साधारण जल रिएक्टर (एलडब्ल्युआर्)				
तारापुर, महाराष्ट्र	टी.ए.पी.एस-1	160	1199	1142	1371	392

1	2	3	4	5	6	7
	टी.ए.पी.एस-2	160	1251	1273	1337	794
	दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्युआर्)					
तारापुर, महाराष्ट्र	टी.ए.पी.एस-3	540	2787	3582	4325	2441
	टी.ए.पी.एस-4	540	2754	3124	2781	2214
रावतभाटा, राजस्थान	आर.ए.पी.एस.-1	100	0	0	0	0
	आर.ए.पी.एस.-2	200	950	1720	1821	802
	आर.ए.पी.एस.-3	220	1277	1564	1938	1123
	आर.ए.पी.एस.-4	220	1143	1807	1645	1081
	आर.ए.पी.एस.-5	220	301	1753	1974	908
	आर.ए.पी.एस.-6	220	3	1060	1764	1088
कलपाक्कम, तमिलनाडु	एम.ए.पी.एस.-1	220	938	1260	1240	864
	एम.ए.पी.एस.-2	220	1108	980	1276	776
नरोरा, उत्तर प्रदेश	एन.ए.पी.एस.-1	220	818	1228	1047	753
	एन.ए.पी.एस.-2	220	0	658	937	726
काकरापार, गुजरात	के.ए.पी.एस.-1	220	0	370	1919	1104
	के.ए.पी.एस.-2	220	1068	1077	1868	875
कैगा, कर्नाटक	कैगा-1	220	1011	1259	1270	859
	कैगा-2	220	1111	988	1381	690
	कैगा-3	220	1112	1334	1231	866
	कैगा-4	220	छपस	295	1330	804

संकेत-शब्द

टी.ए.पी.एस.- तारापुर परमाणु बिजलीघर

आर.ए.पी.एस.- राजस्थान परमाणु बिजलीघर

एम.ए.पी.एस.- मद्रास परमाणु बिजलीघर

एन.ए.पी.एस.- नरोरा परमाणु बिजलीघर

के.ए.पी.एस.- काकरापार परमाणु बिजलीघर

कैगा- कैगा परमाणु बिजलीघर

(घ) नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करने के क्षेत्र में, भारत का स्थान एशिया के देशों में यानि जापान, कोरिया, चीन और ताइवान के बाद पांचवें नम्बर पर आता है। नाभिकीय विद्युत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले विकसित देशों में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में भारत का स्थान पंद्रहवें नम्बर पर है।

(ङ) और (च) निजी उद्योग नाभिकीय संघटकों और उपस्करों की आपूर्ति करने, कार्य संबंधी संविदाओं को निष्पादित करने और सेवाओं का प्रावधान करने के लिए भागीदारी कर रहे हैं। तथापि, नाभिकीय विद्युत के उत्पादन में निजी भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

निजी एयर लाइनों के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें

1963. **श्री संजय निरूपम :**
श्री प्रतापराव गणतराव जाधव :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री राजू शेट्टी :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी एयर लाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के गिरते स्तर को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विमानपत्तनों पर ऐसी शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, निजी एयर लाइनों के विरुद्ध ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक एयर लाइन द्वारा कितनी शिकायतों का निवारण किया गया तथा पीडित व्यक्तियों को कितनी राहत प्रदान की गई;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी शिकायतों पर जांच करने के बाद कितनी सरकारी/निजी एयर लाइनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई; और

(छ) इसके क्या परिणाम हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) सरकार यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देती है मंत्रालय यात्रियों की किसी भी प्रकार की असुविधा/परेशानी का ख्याल रखता है तथा उन्हें दूर करने के लिए नीति निदेश जारी करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) विमान द्वारा यात्रा यात्रियों तथा वाहकों के बीच एक अनुबंध है। शिकायतें यात्रियों द्वारा एयरलाइनों को दायर की जाती है। तथापि, कुछ यात्री मामले के समाधान हेतु नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) के समक्ष भी उठाते हैं। इस तरह की शिकायतें समाधान के लिए संबंधित एयरलाइनों के समक्ष उठाई जाती है।

(ङ) से (छ) मंत्रालय में इसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भवन का निर्माण

1964. **श्री इन्दर सिंह नामधारी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर नक्सल प्रभावित राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत स्कूल भवनों के निर्माण से समस्याएं पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वामपंथी उग्रवादी उन शिक्षकों से भारी उगाही की मांग रखते हैं जो स्कूल भवन का निर्माण करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार किसी विकल्प पर विचार कर रही है ताकि स्कूलों के भवनों का कार्य निविदा आधार पर किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों में सर्व

शिक्षा अभियान के तहत स्कूल भवनों का निर्माण आमतौर पर कोई समस्या नहीं है। तथापि, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और झारखंड में कुछ कठिनाइयां बताई गई हैं, जहां नक्सलियों द्वारा स्थायी संरचनाओं का विरोध किया जा रहा है।

(ग) और (घ) स्कूल भवनों के निर्माण हेतु शिक्षकों से उगाही की किसी प्रामाणिक घटना की रिपोर्ट संबंधित राज्य से प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) छत्तीसगढ़ सरकार ने वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्री-फैब्रीकेटेड स्कूल भवनों का निर्माण किया है और झारखंड ने भी ऐसे जिलों में प्री-फैब्रीकेटेड संरचनाओं को मंजूरी दी है।

सर्व शिक्षा अभियान

1965. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री भक्त चरण दास :
श्री नरहरि महतो :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) की कोई समीक्षा/मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या परिणाम रहे हैं तथा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें एस.एस.ए. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को उक्त योजना के दौरान वित्तीय और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी अनियमितताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) एस.एस.ए. के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने जून, 2010 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम की एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है।

(ख) से (घ) इस अध्ययन से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चला है कि 98 प्रतिशत से भी अधिक नमूना ग्रामीण बस्तियों की पहुंच 3 कि.मी. के भीतर के प्राथमिक स्कूलों तक है जबकि 93 प्रतिशत तक के नमूना मलिन बस्ती के बच्चों की पहुंच पड़ोस के 1 कि.मी. के भीतर के स्कूलों तक है। अध्ययन, में स्कूल अवसंरचना के सशक्तीकरण, नि:शुल्क यूनिफार्म प्रदान करने, शिक्षकों पर पड़ने वाले शिक्षणेतर भार को घटाने, 'नो-डिटेंशन' नीति, अभिभावकों के प्रतिनिधित्व में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन आदि की भी सिफारिश की गई है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) क्रियान्वयन ढांचे और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत ये सिफारिशें अनिवार्य मानदंड बन चुकी हैं जो पड़ोस के स्कूलों को स्कूल अवसंरचना के लिए मानक और मानदंड प्रदान करना बालिकाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. बालकों को नि:शुल्क वर्दियां बांटना, दशकीय जनगणना, आपदा राहत ड्यूटी अथवा स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानमंडल या संसद के चुनावों से संबंधित ड्यूटी के अलावा अनय शिक्षणेतर प्रयोजनों में शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध, निजी ट्यूशन अथवा निजी शिक्षण कार्यकलापों पर प्रतिबंध, कक्षा VIII पास करने से पूर्व बालकों का 'नॉन-डिटेंशन', निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन और सभी सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल प्रबंधन समिति का गठन जिनके तीन चौथाई सदस्य अभिभावक होंगे, आदि जैसे कार्य करते हैं। राज्य-वार प्रगति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) और (च) एस.एस.ए. के अंतर्गत वित्त तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त राज्य-वार शिकायतें ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(छ) सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय प्रबंध एवं प्रापण मैन्युअल, वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा, दो वर्ष के चक में सभी राज्य सर्व शिक्षा अभियान सोसायटियों की समवर्ती लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की व्यवस्था है। इसके अलावा, 41 स्वतंत्र अनुवीक्षण संस्थान तथा अर्धवार्षिक समीक्षा मिशन भी मौजूद हैं।

विवरण-I

क्र .सं.	राज्य	स्कूल खोलना		स्कूल भवन		अतिरिक्त कक्षा-कक्ष		अध्यापक		वर्दी(*)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	8308	8006	10083	9744	103337	91313	39189	38319	6386323
2.	अरूणाचल प्रदेश	2079	1126	2173	2038	4862	4565	7262	5226	0.00
3.	असम	5054	5017	12149	12149	66909	64451	48808	38364	0.00
4.	बिहार	39398	32388	18010	14692	272455	263583	403413	191983	2212411
5.	छत्तीसगढ़	17206	17206	19429	19028	48252	46171	67507	54985	1536203
6.	गोवा	8	5	0	0	227	177	169	149	0.00
7.	गुजरात	0	0	835	797	59751	58421	58688	31336	0.00
8.	हरियाणा	2598	2558	2414	2267	29292	28742	13435	6345	33192
9.	हिमाचल प्रदेश	1413	1158	115	16	11421	10956	5856	3553	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	16566	13398	11743	9806	23159	10914	43471	39739	0.00
11.	झारखंड	29386	28193	29463	28825	108038	92482	120396	84672	0.00
12.	कर्नाटक	11323	11091	3751	3736	56672	51063	29055	24278	0.00
13.	केरल	144	0	529	240	8270	8270	2925	0	752880
14.	मध्य प्रदेश	54321	54289	45183	44741	127309	125778	173855	98287	17514881
15.	महाराष्ट्र	8662	8397	18775	17256	76207	70198	42091	8522	4077890
16.	मणिपुर	406	0	1158	460	3664	2511	2871	1544	389156
17.	मेघालय	5131	5131	5031	4508	7248	7193	13262	14020	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	522	314	1453	1285	2010	1909	2485	1303	147406
19.	नागालैंड	732	236	931	931	4709	4737	3147	590	311913
20.	ओडिशा	20119	17290	17818	17883	77157	61487	89901	88442	17634249
21.	पंजाब	2053	1901	1507	1396	25875	24297	14090	7432	0.00
22.	राजस्थान	50590	47890	8466	8340	90297	85981	114132	94201	0.00
23.	सिक्किम	112	84	108	95	586	670	724	223	0.00
24.	तमिलनाडु	7995	7259	8322	8322	36903	34291	33214	22497	0.00
25.	त्रिपुरा	2257	1697	2007	1987	4482	3784	6980	5694	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	45422	44773	62925	60215	306728	291803	423553	258924	29787171
27.	उत्तराखंड	2573	2440	4430	4038	8765	8018	14316	5998	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	31785	21762	15117	9099	232296	185691	198253	115797	4640060
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	10	41	4	251	208	210	162	6306
30.	चंडीगढ़	44	18	36	32	290	213	1390	785	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	112	92	61	61	654	452	937	526	0.00
32.	दमण और दीव	12	8	15	12	109	96	119	95	5982
33.	दिल्ली	12	6	13	13	2242	1942	7104	4342	0.00
34.	लक्षद्वीप	13	11	9	8	25	30	38	16	0.00
35.	पुदुचेरी	28	10	12	8	534	470	48	36	0.00
	कुल एस.एस.ए.	366399	333764	304112	284032	1800986	1642867	1982894	1248385	85436023

(30.09.2012 तक)

टिप्पणी: सिविल कार्यों की उपलब्धियों में जो कार्य प्रगति पर हैं वे भी शामिल हैं।

(*) यदि राज्य अपने स्वयं के बजट से वर्दियों उपलब्ध नहीं करा रहा और यदि वह राज्य आर.टी.ई. नियमों में पात्रता के रूप में शामिल हैं तो एस.एस.ए. के अंतर्गत बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बी.पी.एल. बालकों को वर्दियां दी जाती हैं।

विवरण–II

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय अनियमितताओं की प्रकृति
1.	आन्ध्र प्रदेश	2006-07 में डी.पी.ई.पी./एस.एस.ए. के अंतर्गत 14.98 करोड़ रूपए का गबन।
2.	बिहार	अररिया के तीन जिलों में (80.38 लाख रूपए), औरंगाबाद (17 लाख रूपए) और पूर्वी चंपारण (8.28 लाख रूपए) में एस.एस.ए. की निधियों की कपटपूर्ण निकासी।
3.	छत्तीसगढ़	जसपुर जिले के पाथलगांव ब्लॉक (11.60 लाख रूपए) और कुंकरी ब्लॉक (7.97 लाख रूपए) के सहकारी बैंकों के दिवालिया होने पर उनमें जमा राशि को बट्टे खाते में डालने पर हानि।
4.	गुजरात	डी.पी.ओ., सुरेन्द्रनगर में चार्ट, पुस्तिकाएं, सी.डी. आदि की कपटपूर्ण खरीद।
5.	हरियाणा	आंतरिक जांच न होने तथा मैन्युअल के प्रावधानों का पालन न किए जाने के कारण राज्य परियोजना कार्यालय में 22.25 लाख रूपए का गबन।
6.	हिमाचल प्रदेश	सर्व शिक्षा अभियान की निधियों दुरूपयोग।
7.	कर्नाटक	सरकारी प्राथमिक स्कूल, हन्नीकेरी, बैथुंगल तालुक, जिला बेलगाम में प्रधान अध्यापक द्वारा दो अतिरिक्त कमरों के सिविल निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई एस.एस.ए. निधियों का दुर्विनियोजन।
8.	मध्य प्रदेश	जिला शिक्षा केन्द्र, विदिशा के वर्ष 2009-10 के संपरीक्षित लेखों में लातेरी ब्लॉक से संबंधित 31 मार्च, 2002 को नकद शेष में 'एफ.डी.आर. उचंत' के रूप में एस.एस.ए. निधियों का दुर्विनियोजन।
9.	महाराष्ट्र	शिक्षा अधिकारी करवीर, जिला कोल्हापुर के कार्यालय में एस.एस.ए. निधियों की 71.87 लाख रूपए की राशि को व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित करके दुर्विनियोजन किया गया।
10.	ओडिशा	जिला परियोजना अधिकारी, जगतसिंहपुर द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन और प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक स्कूल, गंजाम द्वारा निधियों का गबन।
11.	राजस्थान	एस.एस.ए. निधियों का दुरूपयोग और अन्य अनियमितताएं।
12.	उत्तर प्रदेश	वर्दियों की खरीद सहित वित्तीय अनियमितताएं।
13.	तमिलनाडु	कुड्डालूर जिले के ब्लॉक पर्यवेक्षकों बी.आर.टी.ई. और सी.आर.टी.ई. को छठे वेतन आयोग की बकाया राशियों के वेतन भुगतान में अनियमितता तथा इसे सरकारी अध्यापकों के वेतन खाते के अंतर्गत प्रभारित किया गया।
14.	पश्चिम बंगाल	517.80 लाख रूपए की निधियों की कपटपूर्ण निकासी।

शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1966. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा डिप्लोमा कोर्स हेतु भारत में आए तथा ये किन-किन देशों से आए;

(ग) क्या सरकार का अधिक विविधता और बेहतर प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह इस प्रकार है:-

क्र .सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	करोड़ रु.	यू.एस. मिलियन$
1.	2009-10	300.50	63.35
2.	2010-11	173.24	37.94
3.	2011-12	510.95	105.62
4.	2012-13 (अप्रैल-अगस्त)	784.90	146.23
	कुल योग	1769.59	353.14

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत में विभिन्न संस्थाओं में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के संबंध में विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में एन.आर.आई./पी.आई.ओ. सहित विदेशी छात्रों के लिए 15% अधिसंख्य सीटों की अनुमति प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारतीय संस्थाओं में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं जिनमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'विदेशी छात्रों को सीधा प्रवेश' (डी.ए.एस.ए.); प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवासी बच्चों हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम और 'नो इंडिया' कार्यक्रम; भारतीय सांस्कृतिक संबंधी परिषद द्वारा फेलोशिप तथा विजिटर कार्यक्रम; भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अध्येतावृति कार्यक्रम शामिल हैं। अच्छी संख्या में विदेशी छात्रों वाली विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

दिल्ली विमानपत्तन पर विकास शुल्क

1967. श्री एस. सेम्मलई :
श्री रमेश राठौड़ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) और जी.एम.आर. द्वारा हस्ताक्षरित संचालन, प्रबंध और विकास समझौते (ओ.एम.डी.ए.) में विकास शुल्क वसूलने का प्रावधान नहीं है और संयुक्त उद्यम को ऋण और इक्विटी अंशदानों के जरिए वित्त की व्यवस्था करनी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लि. (डायल) को किन परिस्थितियों में यात्रियों से विकास शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या जी.एम.आर. को विकास शुल्क एकत्र करने की अनुमति देना बोली प्रक्रिया का उल्लंघन है क्योंकि सभी बोलीदाताओं को, जिन्होंने बोली प्रक्रिया और बोली मानदंड के मूल्यांकन में हिस्सा लिया था, इस बारे में कभी जानकारी नहीं दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार (ओ.एम.डी.ए.) के खंड

13.1 (क) के अनुसार: ''यह स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि संयुक्त उद्यम कंपनी मास्टर प्लान तथा प्रमुख विकास योजनाओं के अनुसरण में हवाईअड्डे के विकास सहित अपने दायित्वों का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त ऋण तथा इक्विटी अंशदानों के माध्यम से वित्त पोषण और या सभी वित्त पोषण की अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करेगी।'' तथापि, प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार के 20.3.7 के अनुसार शासी कानून शीर्षक में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ''यह करार भारतीय विधि के अनुसार नियंत्रित और व्याख्यायित होगा।''

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अधीन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर हवाईअड्डा परियोजना के वित्त पोषण के लिए अन्तिम विकल्प के रूप में वित्त पोषण अंतर को कम करने के लिए विकास शुल्क निर्धारित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम में उक्त धारा विशेष रूप से तब शामिल की गई जब वर्ष 2003 में सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से हवाईअड्डों को विकसित करने का निर्णय लिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में किए गए संशोधन की जानकारी उन सभी अफ्रंट बोलीदाताओं को थी, जिन्होंने दिल्ली तथा मुंबई के हवाईअड्डों की पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों के चयन के समय बोली प्रक्रिया में भाग लिया।

दूरसंचार का विकास

1968. **श्री अनंत कुमार:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री गणेश सिंह :
श्री देवजी एम. पटेल :
कुमारी मौसम नूर :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में से दूरसंचार उपभोक्ताओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्यूलर टेलीफोन की संख्या और प्रतिशत की दृष्टि से वर्ष-वार और राज्य-वार अलग-अलग कितनी बढ़ोतरी हुई;

(ग) विभिन्न राज्यों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सेवाओं की वृद्धि में अन्तर के, यदि कोई हैं, क्या कारण हैं;

(घ) बारहवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास हेतु अलग-अलग क्या लक्ष्य नियत किए गए थे;

(ङ) जिन ग्राम पंचायतों को दूरभाष सुविधाएं दी गईं और जिन ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधाएं अभी दी जानी हैं, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष के विकास हेतु बल देने के लिए क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार देश में सेवा क्षेत्र-वार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार उपभोक्ताओं का पृथक-पृथक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोनों की संख्या और प्रतिशत के आधार पर सेवा क्षेत्र-वार और वर्ष-वार वृद्धि का अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा में वृद्धि में अंतर के लिए आय-स्तर, साक्षरता दर, अवसंरचना की उपलब्धता और क्षेत्र की दूरस्थता में अंतर जैसे कारण जिम्मेदार हैं।

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अभी अनुमोदित की जानी है।

(ङ) जिन ग्रामों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

(वी.पी.टी.) की सुविधा दी गई है और जिन ग्रामों में यह सुविधा प्रदान की जानी है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिय गया है।

(च) सरकार ने देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने हेतु निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

(i) सरकार ने दिनांक 31 मई, 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 (एन.टी.पी.-2012) को अनुमोदित किया जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में संबंधित दृष्टिकोण, कार्यनीतिक निर्देश और अनेक माध्यम अवधि और दीर्घ अवधि मुद्दों का समाधान किया गया है। एन.टी.पी.-2012 का मुख्य उद्देश्य देशभर में वहनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित दूरसंचार और ब्राडबैण्ड सेवा उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना है।

(ii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा अपने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स, (जी. एस.एम) मोबाइल नेटवर्क के लिए क्षमता का विस्तार करना।

(iii) देश के ऐसे विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं है, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों (टावरों) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए राजसहायता प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से एक स्कीम शुरू की गई है। दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा लगभग 7310 स्थल और 15895 बेस ट्रांसीवर स्टेशन चालू किए गए हैं।

(iv) सरकार ने देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए एक राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) के सृजन हेतु 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना को अनुमोदित किया है।

विवरण-I

दिनांक 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार ग्रामीण और शहरी टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र. सं.	राज्य क्षेत्र का नाम	टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25948661	43932262	69880923
2.	असम	7959595	7230606	15190201
3.	बिहार (झारखंड सहित)	29798492	31839644	61638136
4.	गुजरात	19109242	35621997	54731239
5.	हरियाणा	9819007	11484060	21303067

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	4506804	2791669	7298473
7.	जम्मू और कश्मीर	3208523	3782464	6990987
8.	कर्नाटक	16991934	41445417	58437351
9.	केरल	16632253	19836507	36468760
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	21702977	32554549	54257526
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	32209064	38389586	70598650
12.	पूर्वोत्तर	4326880	5098600	9425480
13.	ओडिशा	12772907	13053822	25826729
14.	पंजाब	11567624	20014998	31582622
15.	राजस्थान	23667860	26870590	50538450
16.	तमिलनाडु (चेन्नै सहित)	16857368	64117332	80974700
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	34170177	41496321	75666498
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	20283267	31958766	52242033
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कार) (अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित)	27702837	18948385	46651222
20.	कोलकाता	–	–	26027816
21.	दिल्ली	–	–	44907302
22.	मुंबई	–	–	37063158

विवरण-II

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों में सेवा क्षेत्र-वार और वर्ष-वार वृद्धि

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (30.09.2012 तक)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	5697673	9522424	15220097	5950334	9101738	15052072	3606584	2544038	6150622	1744300	-979432	764868
2.	असम	2385861	559234	2945095	1493343	1421315	2914658	1230937	13064267	2537364	524624	258864	783488
3.	बिहार (झारखंड संहित)	8008439	7986620	15995059	8310122	8257868	16567990	4799612	51401681	9939780	865133	-3270485	-2405352
4.	गुजरात	3047710	5191090	8238800	4858085	9750409	14608494	2785755	3578488	6364243	-226243	-148723	-374966
5.	हरियाणा	1970204	2262235	4232439	2166882	4087826	6254708	892113	1276685	2168798	297435	-2131055	-1833620
6.	हिमाचल प्रदेश	762316	902369	1664685	1114646	1115913	2230559	456747	298655	755402	-161596	-808984	-970580
7.	जम्मू और कश्मीर	881114	1162179	2043293	289049	-82040	207009	100756	451793	552549	537284	-54636	482648
8.	कर्नाटक	3693921	9895087	13589008	4206342	8110638	12315980	3484872	2779411	6264283	529872	-2675656	262306
9.	केरल	2523984	5270504	7794488	2431955	4734432	7166387	2467224	187880	2655104	566963	-1251739	-684776
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	4877276	6503479	11380755	5533571	8311838	13845409	2413982	3383211	5797193	3095237	-1580823	1514414
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	6691373	5479285	12170658	8693606	9506659	18200265	3966579	4786560	8753139	142785	-2586132	-2443347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	पूर्वोत्तर	1564768	395281	1960049	741787	1132940	1874727	540375	793365	1333740	553053	104179	657232
13.	ओडिशा	2762708	3821729	6584437	2724171	4419471	7143642	2388573	1814993	4203566	822281	-2011165	-1188884
14.	पंजाब	1663597	3551709	5215306	2582723	6081662	8664385	1423405	1768897	3192302	413782	-2190922	-1777140
15.	राजस्थान	7640020	3344117	10984137	4171581	5187919	9359500	3025241	3034344	6059585	698161	-428710	269451
16.	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	3876720	12798151	16674871	3135939	12813962	15949901	2054641	5991076	8045717	-341356	476397	135041
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9104149	7778306	16882455	8996925	10650472	19647397	6204051	5190933	11394984	-21544	-467917	-489461
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	4366932	6785904	11152836	5263260	9856893	16120153	3548639	4321714	7870353	1261857	-3437948	-2176091
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर) (अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित)	6468361	3039143	9507504	9011739	5484389	14496128	3627256	2984070	6611326	237264	-471101	-233837
20.	कोलकाता	-	-	4758862	-	-	6811515	-	-	1776736	-	-	-118755
21.	दिल्ली	-	-	6319517	-	-	10525014	-	-	3664683	-	-	-518085
22.	मुंबई	-	-	7248482	-	-	8318022	-	-	1484749	-	-	2211089

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों में सेवा क्षेत्र-वार और वर्ष-वार वृद्धि

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (30.09.2012 तक)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	68.64%	43.08%	50.06%	42.51%	28.78%	32.99%	18.08%	6.25%	10.14%	7.41%	-2.26%	1.14%
2.	असम	104.36%	15.87%	50.68%	31.96%	34.80%	33.29%	19.97%	23.73%	21.74%	7.09%	3.80%	5.51%
3.	बिहार (झारखंड सहित)	104.67%	59.93%	76.25%	53.07%	38.74%	44.81%	20.02%	17.38%	18.56%	3.01%	-9.42%	-3.79%
4.	गुजरात	36.78%	32.80%	34.17%	42.86%	46.40%	45.16%	17.20%	11.63%	13.55%	-1.19%	-0.43%	-0.70%
5.	हरियाणा	45.64%	40.50%	42.74%	34.47%	52.09%	44.25%	10.55%	10.70%	10.64%	3.18%	-16.13%	-8.13%
6.	हिमाचल प्रदेश	36.23%	74.17%	50.13%	38.89%	52.66%	44.74%	11.47%	9.23%	10.47%	-3.64%	-22.89%	-12.18%
7.	जम्मू और कश्मीर	64.66%	54.27%	58.31%	12.88%	-2.48%	3.73%	3.98%	14.02%	9.60%	20.40%	-1.49%	7.65%
8.	कर्नाटक	79.01%	52.44%	57.72%	50.26%	28.20%	33.17%	27.71%	7.54%	12.67%	3.30%	-0.67%	0.47%
9.	केरल	38.45%	53.59%	47.53%	26.76%	31.34%	29.62%	21.42%	0.95%	8.47%	4.05%	-6.25%	-2.01%
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	86.73%	43.43%	55.25%	52.70%	38.70%	43.29%	15.05%	11.36%	12.65%	16.78%	-4.77%	2.93%
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	55.47%	28.42%	38.83%	46.35%	38.39%	41.82%	14.45%	13.97%	14.18%	0.45%	-6.62%	-3.47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	पूर्वोत्तर	180.86%	15.91%	58.51%	30.53%	39.34%	35.31%	17.04%	19.77%	18.56%	14.90%	2.17%	7.72%
13.	ओडिशा	69.86%	80.75%	75.79%	40.56%	51.66%	46.78%	25.30%	13.99%	18.75%	6.95%	-13.60%	-4.47%
14.	पंजाब	33.21%	35.98%	35.05%	38.71%	45.30%	43.11%	15.38%	9.07%	11.10%	3.87%	-10.30%	-5.58%
15.	राजस्थान	97.71%	22.39%	48.27%	26.98%	28.38%	27.74%	15.41%	12.93%	14.06%	3.08%	-1.62%	0.55%
16.	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	51.22%	43.47%	45.06%	27.40%	30.34%	29.71%	14.09%	10.88%	11.55%	-2.05%	0.78%	0.17%
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	94.58%	44.39%	62.18%	48.03%	42.09%	44.62%	22.38%	14.44%	17.89%	-0.06%	-1.14%	-0.65%
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) (उत्तराखंड सहित)	76.43%	49.24%	57.21%	52.21%	47.93%	49.34%	23.13%	14.21%	17.20%	6.68%	-9.89%	-4.06%
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर) (अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित)	80.01%	40.13%	60.72%	61.93%	51.68%	57.60%	15.39%	18.54%	16.67%	0.87%	-2.47%	-0.51%
20.	कोलकाता	-	-	40.87%	-	-	41.53%	-	-	7.65%	-	-	-0.48%
21.	दिल्ली	-	-	28.75%	-	-	37.19%	-	-	9.44%	-	-	-1.22%
22.	मुंबई	-	-	37.69%	-	-	31.41%	-	-	4.27%	-	-	-6.09%

विवरण-III

दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रदान किए गए वी.पी.टी. की संख्या

राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले राजस्व गांवों की संख्या	प्रदान किए गए वी.पी.टी. की संख्या	लंबित वी.पी.टी.
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	352	149
आन्ध्र प्रदेश	26613	25078	1535
असम	25124	24502	622
बिहार	39032	38932	100
झारखंड	29354	28807	547
गुजरात	18159	17137	1022
हरियाणा	6764	6678	86
हिमाचल प्रदेश	17495	17407	88
जम्मू और कश्मीर	6417	6383	34
कर्णाटक	27481	27449	32
केरल	1372	1372	0
मध्य प्रदेश	52117	51986	131
छत्तीसगढ़	19744	18192	1552
महाराष्ट्र	41442	40643	799
मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	5782	5109	673
मिजोरम (पूर्वोत्तर-I)	707	704	3
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	858	858	0
अरूणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II)	3863	2763	1100

1	2	3	4
मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	2315	2170	145
नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	1278	1263	15
ओडिशा	47529	44904	2625
पंजाब	12301	12065	236
राजस्थान	39753	39410	343
तमिलनाडु (तमिलनाडु सर्किल)	13837	13837	0
चेन्नै महानगर	1655	1655	0
उत्तर प्रदेश	97942	97774	168
उत्तराखंड	15761	15366	395
पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल संर्किल)	37062	36474	588
कोलकाता महानगर	893	613	280
सिक्किम (पश्चिम बंगाल सर्किल)	450	429	21
जोड़	5,93,601	5,80,312	13,289

व्यक्तिगत डेटा निजता

1969. श्री प्रेम दास राय :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोखेबाजी से लोगों से पासवार्ड, क्रेडिट कार्ड के ब्यौरे इत्यादि जैसी निजी सूचनाओं की चोरी के मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अंकुश लगाने के लिए कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया (सी.ई.आर.टी.-इन) ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का निजी सूचना का अनधिकृत आदान-प्रदान और इसे किसी को बताने को एक संज्ञेय अपराध का दर्जा देने के लिए कोई संगत कानून/नियम बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में अभी तक क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) गत कुछ वर्षों में फिशिंग हमलों के जरिए पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के ब्यौरे आदि जैसी निजी सूचना चोरी होने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) के अनुसार वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 (अक्टूबर तक) उन्हें क्रमशः कुल 1618, 2124 और 2853 फिशिंग घटनाओं की सूचना की गई।

(ग) सर्ट-इन फिशिंग संबंधी मामलों से निपटने के लिए कोई कदम उठा रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) देश में बैंकों और अन्य संस्थाओं को प्रभावित करने वाले फिशिंग हमलों से निपटने के लिए 24x7 आधार पर घटना प्रतिक्रिया सेवा प्रदान करना।

(ii) फिशिंग हमलों के उपशमन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंकों और अन्य संस्थाओं के लिए सर्ट-इन द्वारा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(iii) फिशिंग प्रयासों और अनधिकृत सूचना प्रकटन से कम्प्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए नियमित आधार पर अद्यतन साइबर खतरों और प्रतिउपायों के बारे में सर्ट-इन चेतावनी और परामर्श जारी करता है।

फिशिंग हमलों को रोकने, मल्टि फैक्टर अधिप्रमाणन अपनाने, पूर्ण पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान और फिशिंग हमलों से निपटने के लिए फिशिंग प्रयासों का विवरण रखने और प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए सर्ट-इन इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन अधिसूचित नियमों की धारा 43क में भारत में आंकड़ों की निजता की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने की व्यवस्था है। इसमें निगमित निकायों के लिए अनिवार्य है कि संग्रहण पद्धति, संवेदी निजी आंकड़ों या सूचना के हस्तांतरण तथा प्रकटन के लिए यथोचित पद्धतियां, फ्रेमवार्क कार्यान्वित करें। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ग तथा 72क में पहचान चोरी तथा गोपनीयता और निजता के लिए क्रमशः दण्ड और शास्ति का प्रावधान है।

[हिन्दी]

यूआईडीएसएसएमटी

1970. श्री गणेश सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिए क्या प्राथमिकताएं तय की गई हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की अनदेखी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सतना नगर निगम में प्राथमिकता के आधार पर जलापूर्ति करने के बारे में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव की अनदेखी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उपेक्षित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) छोटे एवं मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के उद्देश्य निम्न हैं : (प) शहरों एवं कस्बों में अवस्थापना विकास सुविधाओं (जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज औरठोस कचरा प्रबंधन, सड़क आदि समेत) में सुधार लाना और स्थायी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों और गुणवत्ता उन्मुखी सेवाओं की व्यवस्था करना (पप) अवस्थापना विकास में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी को बढ़ावा देना और (पपप) कस्बों एवं शहरों के योजनागत एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना।

(ख) से (ङ) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति निधियों की उपलब्धता, तकनीकी मूल्यांकन और राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा सिफारिश पर निर्भर करती है। सतना जलापूर्ति स्कीम दिनांक 13 जून, 2011 को मध्य प्रदेश की एसएलएससी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में से एक थी जिसमें 64.14 करोड़ रू. की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता शामिल थी और इस पर स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि स्वीकृति और धनराशि जारी करने के बाद इसकी पूर्णता की अवधि तीन वर्षों से अधिक है।

(च) और (छ) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत मिशन पहले ही पूर्ण हो चुकी है। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत दिनांक 31.03.2012 को इसकी पूर्णता के पश्चात् नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय में कोई अधिदेश नहीं है।

सब्सिडी हेतु निधियां

1971. **श्री आर.के. सिंह पटेल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा भारी राशि व्यय की जाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सब्सिडी के रूप में जिन सैक्टरों को निधियां दी गईं उनका ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का अगले कुछ वर्षों में सब्सिडी बंद करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सब्सिडियों पर बहुत बड़ी राशि व्यय की जाती है। कुल गैर-योजनागत व्यय में सब्सिडियों का पंचमांश (1/5) से अधिक हिस्सा रहता है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रकों को प्रदान की गई सब्सिडियों का ब्यौरा निम्नानुसार है

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	क्षेत्रक	2009-10	2010-11	2011-12 संशोधित अनुमान
1.	खाद्य	58443	63844	72823
2.	उर्वरक	61264	62301	67199
3.	पेट्रोलियम जिसमें से	14951	38371	68481
	(क) एलपीजी एवं पीडीएस के लिए मिट्टी के तेल पर सब्सिडी	2770	2904	3000
	(ख) एनईआर के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तेल कंपनियों को सब्सिडी	159	445	458
4.	ब्याज सब्सिडी	2687	4680	5791
5.	अन्य	4006	4224	2003
6.	कुल सब्सिडी	141351	173420	216297
	गैर-योजनागत व्यय के : के रूप में सब्सिडी	19.60	21.19	24.25

सरकार ने बारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न उपायों, जैसे कि मूल्यों के बेहतर तालमेल और दुरुपयोगों को समाप्त करने, के माध्यम से सब्सिडियों को कम करने का प्रस्ताव किया है।

गांवों में डाकघर

1972. **श्री नारनभाई कछाड़िया :**
श्री मधु कोड़ा :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क होने के बावजूद देश में अभी भी अनेक गांवों में डाकघर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी गांवों में कब तक डाकघर खोले जाने की संभावना है और बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कितने गांवों में डाकघर खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या सभी मौजूदा डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करके उनमें इलेक्ट्रानिक मनी आर्डर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार सभी डाकघरों में इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व में सर्वाधिक संख्या में डाकघर भारत में हैं। तथापि, देश में 5,00,327 गांवों में डाकघर नहीं हैं। ऐसे गांव जहां डाकघर नहीं हैं, उनकी सर्किलवार संख्या (31.03.2012 के अनुसार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। डाकघर खोलना एक सतत प्रक्रिया है। योजना निधि और मानव संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्धारित मानकों के अनुसार नए डाकघर खोले जाते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) के दौरान देश में 80 शाखा डाकघर तथा 50 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। 12वीं योजना के शेष वर्षों के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। 24,969 विभागीय डाकघरों को कम्प्यूटरीकरण किया गया है जिन में से 21,606 डाकघरों में इलेक्ट्रानिक मनीआर्डर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी डाकघरों के जरिए चरणबद्ध तरीके से इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की विभाग की योजना है तथा चालू योजना के दौरान इसके पूर्ण हो जाने की आशा है।

विवरण

डाकघरों से रिहत गांवों की सर्किलवार संख्या (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार) का ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों से रिहत गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24152
2.	असम	21282
3.	बिहार	30679
4.	छत्तीसगढ़	17496
5.	दिल्ली	95
6.	गुजरात	9742
7.	हरियाणा	4441
8.	हिमाचल प्रदेश	14833
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5148
10.	झारखंड	26035
11.	कर्नाटक	19918
12.	केरल	0
13.	मध्य प्रदेश	44969
14.	महाराष्ट्र	29434
15.	पूर्वोत्तर	12551
16.	ओडिसा	43377
17.	पंजाब	9201
18.	राजस्थान	29762
19.	तमिलनाडु	26579
20.	उत्तर प्रदेश	86435
21.	उत्तराखंड	13248
22.	पश्चिम बंगाल	30950
	कुल	500327

केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का कार्यान्वयन

1973. डॉ. बलीराम :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश बाध्यकारी हैं और मंत्रालय तथा इसके तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उन्हें लागू करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय तथा इसके तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषरूप से भारत संचार निगम द्वारा सीआईसी आदेश संख्या 3297/आईसी/(ए)/2008 एफ सं. सीआईसी/एमए/सी/2008/00374 दिनांक 18.09.2008 लागू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रालय ने अपने अधीन विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीआईसी के आदेशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(घ) इन आदेशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) मंत्रालय ने इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, हां। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय ट के तहत खंड 19(7) के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय बाध्यकारी हैं।

(ख) केंद्रीय सूचना आयोग ने दिनांक 18 सितंबर, 2008 के अपने निर्णय संख्या : 3297/आईसी (क)/2008 के द्वारा शिकायतकर्ता को मूल मंत्रालय में संपर्क करने की सलाह दी लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) केंद्रीय सूचना आयोग के आदेशों/निर्णयों को, यदि केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश/निर्णय में ही कोई समय-सीमा निर्धारित की है तो उन्हें नियत समय-सीमा में क्रियान्वित किया जाता है। यदि किसी लोक प्राधिकारी का विचार है कि सूचना आयोग का कोई निर्णय आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है।

[अनुवाद]

नकद अन्तरण योजना

1974. श्री मधु गौड़ यास्खी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद अन्तरण लागू करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस योजना की कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) जी हां। सरकारी सब्सिडियों को सीधे नकद अंतरित करने हेतु आधार समर्थित व्यवस्था को अपनाने का प्रस्ताव है ताकि सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) और (घ) जी हां। सब्सिडियों को सीधे नकद अंतरित करने की व्यवहार्यता तथा वांछनीयता का आकलन करने के लिए, कुछेक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारें ने प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं, यथा-

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मैसूर, कर्नाटक में तरलीकृत पेट्रोलियम गैर (एल.पी.जी.) के और राजस्थान के अलवर जिले की कोटकासिम तहसील के कैरोसिन सब्सिडी के सीधे अंतरण की प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। आन्ध्र प्रदेश के उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूर्वी गोदावरी जिले में खाद्य

सब्सिडी का सीधा अंतरण शुरू किया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिसाव पर रोक लगाई जा सके।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्ति की आयु

1975. **श्री महाबल मिश्रा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के विभिन्न विभागों ने सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु नियत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) मूल नियम 56 के अनुसार, नियमावली में दिए गए अपवादों के अलावा, सभी सरकारी कर्मचारी, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

1976. **श्री सज्जन वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंदौर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं। तथापि, निर्दिष्ट भारतीय वाहक अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार भारत में किसी भी स्थान से अपनी सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया का भुगतान

1977. **श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :**
श्री भरत राम मेघवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्यरत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अध्यापकों तथा समकक्ष संवर्गों को छठे वेतन आयोग के बकाया के भुगतान में अभी भी गतिरोध बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने वाले इस अतिरिक्त व्यय की 80 प्रतिशत राशि देने पर सहमत है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने हिस्से की कुछ राशि राजस्थान सहित अन्य राज्य सरकारों को दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त राशि राज्य सरकारों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर) : (क) और (ख) इस गतिरोध को दूर कर दिया गया है तथा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने संबंधी शर्त को बकाया के भुगतान से वियोजित कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 14.08.2012 को एक पत्र सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है, जो मंत्रालय की वेबसाइट ूणमकनबंजपवदण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।

(ग) केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दिनांक 1.12006 से 31.3.2010 तक की अवधि के लिए

संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन हेतु अध्यापकों को भुगतान किए जाने वाले बकायों के कारण अतिरिक्त राशि का 80: भाग वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, इस राशि को राज्य सरकारों को अध्यापकों को बकाया का भुगतान किए जाने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी किया जाएगा।

(घ) से (च) आज की तारीख तक किसी राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है। निधियां जारी करना सभी शर्तों को पूरा किए जाने तथा राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं हलफनामा प्रदान किए जाने के अध्यधीन है।

केंद्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालयों के भवनों का निर्माण

1978. **श्री जफर अली नकवी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की गई;

(ख) इनमें से कितने विद्यालयों को अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है और जो किराए के भवनों अथवा किराए की भूमि पर चलाए जा रहे हैं और इन विद्यालयों को भूमि तथा भवन उपलब्ध नहीं करवाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार ने इन विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई भूमि पर विद्यालय हेतु भवन बनाने के लिए कोई मार्ग निदेश जारी करते हुए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2006-07 से 2011-12 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय और एक जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) माटी अकबपुर स्थित एक केंद्रीय विद्यालय का भवन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्मित किया गया है जबकि 09 केंद्रीय विद्यालय प्रायोजित प्राधिकरणों द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए अस्थाई भवनों से कार्य कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार द्वारा भूमि का शीर्षक केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में अंतरित नहीं किया गया है। बांदा, जिला बांदा में स्थित एक केंद्रीय विद्यालय कार्यात्मक नहीं किया जा सका क्योंकि जिला प्रशासन न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सका है। जिला रामपुर में संस्वीकृत एक जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यात्मक नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय को उपलब्ध कराई गई स्थाई भूमि विवादित हो गई है जिसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल में निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

(ग) और (घ) सामान्यत: केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और निधियों की उपलब्धता की संस्वीकृति के बाद 18-24 महीने के अंदर पूरा किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण कार्य दो चरणों में संस्वीकृत किया जाता है। पहले चरण के लिए 21 महीने और दूसरे चरण के लिए 15 महीने दिए जाते हैं इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल नहीं हैं जिसके पहले चरण को पूरा करने के लिए 27 महीने और दूसरे चरण को पूरा करने के लिए 21 महीने की समय सीमा है।

[अनुवाद]

रिक्त पद

1979. **श्री पी. लिंगम :**
श्री गुरूदास दासगुप्ता :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री जोस के. मणि :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री सुदर्शन भगत :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभागों में आरक्षित श्रेणी के 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और इसमें अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रह हैं;

(घ) क्या अनेक मंत्रालयों ने आरक्षण संबंधी विनियमों के अनुपात के उल्लंघन में कर्मचारियों/कर्मकारों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपाए किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) आरक्षित पदों और रिक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 1.1.2011 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पदों और सेवाओं में अनु.जा., अनु.ज.जा. और अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

समूह	कुल कर्मचारी	अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि.व.	
		अनु.जा. की संख्या	प्रतिशत	अनु.ज.जा. की संख्या	प्रतिशत	अ.पि.व. की संख्या	प्रतिशत
क	77455	8922	11.5	3732	4.8	5357	6.9
ख	190134	28403	14.9	11357	6.0	13897	7.3
ग	2264795	370557	16.4	174562	7.7	346433	15.3
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	396478	77704	19.6	27595	7.0	71801	18.1
घ (सफाई कर्मचारियों सहित)	479834	110515	23.0	32791	6.8	81468	17.0

नोट:- इसमें दो मंत्रालयों के संबंध में सूचना शामिल नहीं है।

(ग)इस तरह के अनुदेश हैं कि यदि भर्ती के प्रथम प्रयास में अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो उसी भर्ती वर्ष में अथवा शीघ्रतिशीघ्र इन रिक्तियों को भरे जाने हेतु अगले भर्ती वर्ष से पूर्व संबंधित श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु एक दूसरा प्रयास किया जाए ताकि बकाया आरक्षित रिक्तियां हों ही नहीं। यदि, ऐसे प्रयास करने के बावजूद भी, आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरा जाता है और बकाया आरक्षित रिक्तियों को बाद के भर्ती वर्ष में आगे ले जाया जाता है तो शीघ्रातिशीघ्र बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने हेतु ठोस प्रयास किए जाएं।

इसके अलावा, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं और पदों में समय-समय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाती आ रही है। अनु.जा., अनु.ज.जा. और अ. पि.व. की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसा पिछला अभियान नवम्बर, 19,2008 को शुरू किया गया था। इसमें कुल 77520 बकाया आरक्षित रिक्तियां (अन.जा. 24744, अनु.ज.जा. 29955 और अ.पि.व. 22821) थीं। इसमें से 45438 रिक्तियां (अनु.जा. 16690, अनु.ज.जा. 15802 और अ.पि.व. 12946) अब तक भरी जा चुकी हैं।

(घ) और (ङ) इस तरह के अनुदेश हैं कि आरक्षण 45 दिन अथवा अधिक के लिए की गई सभी अस्थायी नियुक्तियों, जिसमें सीधी भर्ती के सभी घटक हों, पर भी लागू है चाहे नियुक्ति "संविदा आधार" पर की जानी हो।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से पिछड़े लोग

1980. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का पता लगाने के उद्देश्य से एक लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा तय की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उक्त मानदंड का आधार क्या है;

(ग) क्या उक्त मानदंडों को संशोधित करने और अधिकतम सीमा को बढ़ाकर दो लाख करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का पता लगाने के उद्देश्य से रुपयों में वार्षिक आय की दृष्टि से किसी प्रकार की सीमा तय करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम

1981. श्री गोपाल सिंह शेखावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त स्कीम के तहत कार्यनिष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर) : (क) राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना जिसे योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जा रहा था, 31 मार्च, 2007 को बंद कर दी गई है। इसके स्थान पर दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं, नामत: कक्षा IXवीं से कक्षा XIIवीं तक के छात्रों के लिए "राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना" तथा कक्षा XIIवीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उच्चतर अध्ययन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इंजीनियरी तथा चिकित्सा अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए "कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों हेतु केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना"

(ख) कक्षा IXवीं से कक्षा XIIवीं तक के छात्रों के लिए "राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना" तथा "कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों हेतु केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना" में छात्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से छात्रों के बैंक खातों में संवितरित की जाती है। "राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना" में कक्षा IX-XII में अध्ययन कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिमाह 500/- रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्र छात्रों का चयन "राष्ट्रीय प्रतिभा खोज-चरण । परीक्षा" के साथ आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस स्कीम के तहत प्रति वर्ष एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

"कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना" में स्नातक स्तर पर पहले तीन वर्ष 1000/- रुपये प्रतिमाह तत्पश्चात् 2000/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऐसे छात्र जो किसी विशिष्ट परीक्षा बोर्ड की 10+2 पैटर्न की कक्षा-XII या समकक्ष परीक्षा में संबंधित स्ट्रीम में सफल छात्रों के 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर होते हैं तथा 'नॉन-क्रीमी लेयर' से आते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना जाता है। इस स्कीम के तहत प्रतिवर्ष 82,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनमें से 41,000 बालकों के लिए तथा 41,000 बालिकाओं के लिए होती हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्यालयों के लिए उपग्रह मानचित्रण

1982. श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा का अधिकार, 2009 के उपबंधों के अनुसार देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता के आकलन हेतु उपग्रह मानचित्रण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में किए जा रहे उपग्रह मानचित्रण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के परिणाम कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.), 2009 के अंतर्गत राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को राज्य शिक्षा का अधिकार नियमावली में उनके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निकटवर्ती क्षेत्र अथवा सीमाओं के भीतर स्कूल स्थापित करना अपेक्षित है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों की स्थापना के लिए बस्तियों का भौतिक मानचित्रण अथवा/और उपग्रह मानचित्रण, जैसी भी आवश्यकता हो, कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्यों ने स्कूलों से वंचित बस्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए भू-स्थानिक मानचित्रण किया है। हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी कुछ सीमा तक ऐसे मानचित्रण का प्रयोग किया है।

इस कार्य के परिणामस्वरूप, राज्यों ने असेवित बस्तियों में नए स्कूल खोले हैं।

[हिन्दी]

जन शिक्षण संस्थान की समीक्षा

1983. श्री बलीराम जाधव :
श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जन शिक्षण संस्थान के कामकाज की समीक्षा की है जो निर्धनों, अशिक्षितों इत्यादि के लाभार्थ कौशल विकसित करने और साक्षरता को व्यावसायिक योजनाओं से जोड़ने के लिए स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा का परिणाम क्या रहा;

(ग) क्या उक्त समीक्षा के दौरान किन्हीं कमियों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो वंचित वर्गों और अन्य लक्षित समूहों के लाभार्थ इस योजना को पुनरभिमुखित करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) उन शिक्षण संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा एक मानक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो आंतरिक रूप से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा तथा तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से नियमित आधार पर आवधिक रूप से की जाती है। इन समीक्षाओं के दौरान यह पाया गया है कि जन शिक्षण संस्थानों की मॉनीटरिंग में और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है; पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को मानकीकृत बनाए जाने की आवश्यकता है; वह कौशल जिसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, की मांग की जानी चाहिए; वित्तीय मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए; प्रशिक्षण को संचालित करने के लिए जेएसएस के पास पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध होने की जरूरत है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना के प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए सुसंगत होने चाहिए।

(घ) योजना के कार्यान्वयन में और सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण उपचारात्मक सुझावों में ये शामिल हैं (i) वेब-आधारित मॉनीटरिंग तथा सूचना प्रणाली का विकास; (ii) उनकी क्षमताओं का

मूल्यांकन तथा उनका समुचित निर्माण करने हेतु तकनीकी ऑडिट; (iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का मानकीकरण तथा प्रमाणन; (iv) मानकीकृत तथा नियमित निष्पादन लेखापरीक्षा की संस्थागत प्रणाली आरंभ करना; और ऐसे व्यवसायों को शामिल करना जो योजना के लाभग्राहियों, अर्थात विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों जैसे लक्षित समूह के प्रौढ़ों, जिनकी शिक्षा का स्तर शून्य अथवा आरंभिक चरण में है, के लिए संगत हों।

[अनुवाद]

एन.आर.एस.सी.एस. हेतु अग्रिम

1984. श्री बालकुमार पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दूर-संवेदी केन्द्र को इसके पास अत्यधिक मात्रा में अप्रयुक्त निधियों के होने के बावजूद अभी भी अग्रिम राशि प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निधियों का कुप्रबंधन हुआ है और परियोजनाओं की बिल्कुल निगरानी नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं। चूंकि राष्ट्रीय सुदुर संवेदन केन्द्र (एन. आर.एस.सी.) 01.09.2008 से एक सरकारी अस्तित्व बन गया है, इसे केवल अंतरिक्ष विभाग की विशेष परियोजनाओं हेतु बजटीय अनुमोदन प्राप्त होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

विदेशों में श्रमिक

1985. श्री पूर्णमासी राम :
श्री जितेंद्र सिंह बुंदेला :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि विदेशों विशेषकर खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं की मिली जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी घटनाओं में किसी श्रमिक की मृत्यु हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशों में हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) समय-समय पर, वेतन का भुगतान न करने/विलंब से भुगतान करने अथवा कम भुगतान करने, समय पर वीजा और श्रमिक कार्ड का नवीकरण न करने, कैंप स्थल पर घटिया भोजन सहित, असंतोषजनक रहने की स्थितियों, कामगार के चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करने से मना करने, दो वर्ष की संविदात्मक अवधि के पूरा होने पर होमटाउन के लिए एयर टिकट और छुट्टी देने से मना करने, शारीरिक मारपीट/यौन उत्पीड़न, आदि की शिकायतों के साथ, नियोक्ता-कर्मचारी विवादों के मामले, प्राप्त होते हैं।

इस संबंध में गत तीन वर्षों में भारतीय दूतावास, रियाद, कुवैत, मस्कत (ओमान) और भारत के महाकान्सुलावास, जेद्दाह से प्राप्त सूचना नीचे दिए गए अनुसार है :

देश	2010	2011	2012
भारतीय दूतावास, रियाद	3,139	2,330	2,359
सीजीआई, जेद्दाह	2,111	1,326	1,243
कुवैत	4,373	2,854	2,978
ओमान	2,262	2,789	2,183

(ग) और (घ) किसी भारतीय श्रमिक की उसके प्रायोजक के साथ विवाद की वजह से, मृत्यु की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। तथापि, कुवैत में एक घटना नोटिस में आई है, जहां एक कुवैती नागरिक द्वारा 01,08,2011 को चार भारतीय घरेलू कामगारों को गोली से मार दिया गया, क्योंकि अभियुक्त मानसिक रोग से पीड़ित रिपोर्ट किया गया था।

(ङ) भारतीय उत्प्रवासियों के मामलों के समाधान के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं :-

(i) मंत्रालय ने भर्ती एजेंटों (आरएज) के पात्रता मानदंडों को संशोधित करते हुए, उनकी भर्ती करने की क्षमता को बढ़ाते हुए तथा सुरक्षा राशि और सेवा प्रभारों को बढ़ाते हुए, दिनांक 09 जुलाई, 2009 को उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2009 अधिसूचित किया है।

(ii) आम जनता और विशेष रूप से सम्भावित उत्प्रवासियों में अवैध उत्प्रवास के जोखिमों और अप्राधिकृत बिचौलियों और धोखेबाज भर्ती एजेंसिवयों द्वारा अपनाई जाने वाली अवैध प्रक्रियाओं से सावधान रहने के बारे में व्यापक जागरूकता सृजन करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता-सह-प्रचार अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं।

(iii) मंत्रालय ने विपदाग्रस्त भारतीय कामगारों को, मौके पर राहत और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सभी देशों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की है।

(iv) उत्प्रवासियों/उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) 17 अधिसूचित देशों में रोजगार के लिए जाने की इच्छुक उत्प्रवासियों की, आठ क्षेत्रीय भाषाओं में समर्थित, एक प्रवासी कामगार स्रोत केंद्र (ओडब्ल्यूआरसी) नामक एक 24ग7 हेल्पलाइन सहायता करती है।

(v) भारत ने हाल ही के वर्षों में, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, ओमान, मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कत्तर के साथ मौजूदा करार पर एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया।

ये समझौता ज्ञापन उत्प्रवास के प्रबंधन और श्रम कल्याण के संरक्षण में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हैं। इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत, एक संयुक्त कार्यकारी दल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है, जो द्विपक्षीय श्रम विवादों को निपटाने के उद्देश्य से नियमित रूप से बैठकें करता है।

नेपाल में चीन की गतिविधियां

1986. श्री सुदर्शन भगत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल में चीन की बढ़ती गतिविधियों को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल द्वारा भारत में अवैध रूप से घुसने की घटनाओं को सरकार ने संज्ञान में लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) भौगोलिक समीपता एवं चीन के आर्थिक विकास के कारण हाल के वर्षों में नेपाल में चीनी पूंजीनिवेश एवं उसके साथ चीन की अंत:क्रिया में वृद्धि हुई है। सरकार नेपाल सहित अन्य विकासशील देशों में परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में चीन की वर्धित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमता से अवगत है। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं के संबंध में गंभीर रहती है तथा इसकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

(ग) और (घ) भारत-नेपाल की सीमा खुली हुई है और दोनों देशों के नागरिकों के निर्बाध आवागमन की स्वीकृति है। भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों के मामले में भारत एवं नेपाल की सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वयन है।

गुणवत्ता शिक्षा की सुविधा

1987. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार वर्ष 2015 तक बंगलादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान और भारत के सभी वंचित शहरों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने पर सहमति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मार्च, 2013 तक भारत में कुल कितने प्रतिशत लोगों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) विकासशील विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नौ देश बंगलादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान 'सभी के लिए शिक्षा' हेतु ई-9 पहल का हिस्सा हैं। वर्ष 2000 में उन्होंने डकार में 'वर्ल्ड एजूकेशन फोरम' में भाग लिया तथा अन्य देशों के साथ 'सभी के लिए शिक्षा' के छह लक्ष्यों को प्राप्त करने की शपथ ली थी जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार करने और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने का लक्ष्य शामिल है ताकि सभी को विशेष रूप से साक्षरता, अंकज्ञान और आवश्यक जीवन कौशलों में मान्यताप्राप्त और मापनीय अधिगम परिणाम प्राप्त हो सकें। द्विवार्षिक सम्मेलन 2012-14 के दौरान ई-9 देश 'सभी के लिए समावेशी संगत गुणवत्तापरक शिक्षा' की विषयवस्तु पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तथापि, इस शब्द का अर्थ विधिक संदर्भ में 'अंतरराष्ट्रीय अभिसमय' नहीं है।

(ग) से (ङ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ था, में प्रावधान हे कि 6 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक और समतुल्य गुणवत्ता की निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है और वर्तमान में इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कार्यकलापों का प्रावधान करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, आवधिक सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों का प्रावधान, शिक्षकों की अधिगम अभिवृद्धि के लिए नियमित अकादमिक सहायता शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रत्येक स्कूल के लिए बनाए रखे जाने वाले छात्र-शिक्षक अनुपात का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत शिक्षक अर्हताएं निर्धारित की हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। इस अधिनियम में किसी स्कूल में स्कूल अवसंरचना एवं शिक्षकों तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के संबंध में मानदंडों और मानकों के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमाएं तय की गई हैं।

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अनुदान

1988. डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात चौथा अत्यधिक शहरीकृत और देश के सर्वाधिक तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते राज्यों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुल अनुदान का केवल 10 प्रतिशत ही आवंटित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात निधियों के उपयोग और परियोजनाओं को पूरा करने वाले उत्कृष्ट राज्यों में एक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत गुजरात को आवंटित की जाने वाली निधियों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात का अत्याधिक शहरीकृत राज्य के रूप में 6वां (42.58%) स्थान है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) के तहत गुजरात राज्य के लिए कुल आबंटन 2578.81 करोड़ रु. है जोकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन यू.आई.जी. के तहत कुल आबंटन (31500 करोड़ रू.) के 8% से अधिक है।

(ग) गुजरात राज्य में विभिन्न मिशन शहरों के लिए 5604.70 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत और 2475.01 करोड रू. की अतिरिक्त केन्द्रीय (ए.सी.ए.) वचनबद्धता, जो राज्य के आबंटन का लगभग 96% है, से 72 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अब तक, गुजरात राज्य में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उप-मिशन के तहत पूर्ण कुल 163 परियोजनाओं में से 41 परियोजनाओं के वास्तविक रूप से पूर्ण होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ) मिशन ने अपना सामान्य कार्यकाल मार्च, 2012 में पूरा कर लिया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए मार्च, 2014 तक दो वष्र के लिए अवधि बढ़ाई गई है। नई परियोजनाओं पर विचार करने के लिए कोई अधिदेश नहीं है।

[हिन्दी]

त्वरित अनुसंधान और विकास

1989. श्री सतपाल महाराज : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रक्षा और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में त्वरित (फास्ट ट्रैक) अनुसंधान और विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है अथवा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने टॉप-डाउन और बॉटम-अप उपागमों दोनों का उपयोग करके रक्षा के क्षेत्र में त्वरित (फास्टट्रैक) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा ''डीआरडीओ द्वारा एमएकेई'' और ''उद्योग द्वारा एमएकेई'' के माध्यम से स्वदेशी प्रणालियों के विकास हेतु तीन सेवाओं के साथ निकट रूप से कार्य करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ऊर्जा, पर्यावरण जैवप्रौद्योगिकी, नेनो प्रौद्योगिकी आदि जैसे बहुत से अन्य गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में त्वरित अनुसंधान और विकास के लिए कई कार्यक्रमों को शुरू किया है।

विद्यालय विकास निधि

1990. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों से वसूले जाने वाली विद्यालय विकास निधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक केंद्रीय विद्यालय द्वारा वर्ष-वार विद्यालय विकास निधि किन कार्यों पर खर्च की गई;

(ग) क्या केंद्र सरकार को विद्यालय विकास निधि के कथित दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विद्यालय विकास निधि की निगरानी के लिए कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 1999 में 01 अप्रैल, 1999 से र 25/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह लगाकर एक अनुरक्षण और विकास निधि बनाने का निर्णय लिया था। 01 अप्रैल, 2000 से छात्र निधि, अनुरक्षण विकास निधि और विज्ञान निधि का आपस में विलय करके इसका 'विद्यालय विकास निधि' के रूप में पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया गया था। विद्यार्थियों से विद्यालय विकास निधि शुल्क इकट्ठा करने के मानदंड निम्नलिखित हैं:-

(i)	कक्षा-I से X	रु 240/- प्रतिमाह
(ii)	कक्षा XI-XII (गैर विज्ञान)	रु 240/- प्रतिमाह
(iii)	कक्षा XI-XII (विज्ञान)	रु 300/- प्रतिमाह

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विद्यार्थियों और एकल बालिका (कक्षा-VI से आगे) के माता-पिता के अधिकारियों के बच्चे और युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियान में मारे जाने वाले/विकलांग

सशस्त्र सेनाओं और अर्द्ध-सैनिक बलों के कर्मचारियों को विद्यालय विकास निधि के भुगतान से छूट दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्यालय विकास निधि अंशकालिक/संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों, छोटे निर्माण कार्य, स्कूल भवन की मरम्मत और रखरखाव, फर्नीचर एवं जुड़नार, खेल के सामान, स्कूल पर्यटन, सौंदर्यीकरण और बागवानी, पुस्तकालय की पुस्तकों, बिजली और पानी प्रभार, परीक्षा, स्कूल की सुरक्षा, कम्प्यूटर/उपकरणों आदि के भुगतान जैसे कार्यकलापों पर व्यय की गई थी।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अभी तक 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	शिकायतों की संख्या
1.	2009	06
2.	2010	02
3.	2011	07
4.	2012 (अभी तक)	04

(ङ) और (च) विद्यालय विकास निधि से किया गया व्यय, केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मासिक लेखा विवरणों, आंतरिक लेखा परीक्षा और महालेखापरीक्षा के जरिये मानीटर किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) भी विशेष लेखा परीक्षा द्वारा आवश्यकता अनुसार विद्यालय विकास निधि पर होने वाले व्यय को मानीटर करता है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा धोखाधड़ी

1991. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा विशेषकर दूल्हों के द्वारा भारतीय महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक तीन वर्षों में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को भारत में 19 राज्यों से 102 महिलाओं की सूचना दी गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय महिलाएं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय या विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के पास पहुंच सकती हैं। पात्र मामलों में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा, उनके प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता की इसकी योजना के अंतर्गत, सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, विदेशी न्यायालयों में ऐसी शिकायतकर्ताओं के मामले उठाने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यदि आवश्यक हो, तो मामले पर उचित कार्रवाई करने के लिए, शिकायतों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों, पुलिस प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महिला आयोग, आदि को अग्रेषित किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	एमओआईए में प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2009-10	56
2	2010-11	15
3	2011-12	31
	कुल	102

इन 102 शिकायतों का राज्यवार ब्रेकअप निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10 के दौरान शिकायतों की संख्या	2010-11 के दौरान शिकायतों की संख्या	2011-12 के दौरान शिकायतों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	1	13
2.	असम	0	1	1	2
3.	बिहार	2	0	0	2
4.	दिल्ली	6	7	3	16
5.	गुजरात	4	0	3	7
6.	हरियाणा	4	0	1	5
7.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1
8.	जम्मू और कश्मीर	5	0	0	5
9.	कर्नाटक	1	1	1	3
10.	केरल	3	1	5	9
11.	महाराष्ट्र	2	0	3	5
12.	मध्य प्रदेश	2	0	2	4
13.	पंजाब	6	1	6	13
14.	पुदुचेरी (यूटी)	1	0	0	1
15.	राजस्थान	1	0	0	1
16.	तमिलनाडु	3	0	3	6
17.	उत्तर प्रदेश	2	0	1	4
18.	उत्तराखंड	2	0	0	2
19.	पश्चिम बंगाल	0	2	1	3
	कुल	56	15	31	102

के.मा.शि. बोर्ड पाठ्यक्रम में सामाजिक बुराई संबंधी पाठ को शामिल करना

1992. श्री रामकिशुन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाठ्यक्रम में कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक बुराई और लिंग अनुपात पर इसके अत्यधिक प्रभाव को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एन.सी.ई.आर.टी. को पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) कन्या भ्रूणहत्या का संदर्भ तथा लिंग अनुपात पर इसके बुरे प्रभाव का उल्लेख राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा तैयार की गई सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित पुस्तकों अर्थात् समसामयिक भारत-I, कक्षा IX, लोकांत्रिक राजनीति-II, कक्षा ग्ए मानव भूगोल के मूल तत्व, कक्षा XII, भारतीय लोक एवं अर्थव्यवस्था तथा जीव विज्ञान, कक्षा XII में किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फ्लैटों का आवंटन

1993. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण 2010 आवास योजना के आवंटियों जिन्हें फ्लैट का कब्जा दे दिया गया है उन्हें बिजली और पानी के कनैक्शन दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां बिजली और पानी के कनैक्शन के बिना आवंटियों ने कब्जा ले लिया है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेवारी तय करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि आवासीय स्कीम 2010 के तहत आबंटित/कब्जा दिए गए अधिकांश फ्लैटों में बिजली और पानी के कैनेक्शन उपलब्ध करा दिये गए हैं। बिजली और पानी के कैनेक्शन उपलब्ध कराने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित बिजली कम्पनी और दिल्ली जल बोर्ड की है। डी.डी.ए. ने संबंधित एजेंसियों को आवश्यक भुगतान कर दिया है तथा इस्टालैशन कार्य को पूरा करने के लिए उच्च स्तर पर मामले उठाया गया है। जहां भी दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) ने अब तक जल का कैनेक्शन, उपलब्ध नहीं कराया है, जल की आपूर्ति गुणवत्ता की जांच के बाद टैंकरो/टयूबवैलों के माध्यम से डी.डी.ए. द्वारा की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में अब तक बिजली का कैनेक्शन नहीं दिया गया है:-

(i) सेक्टर 28 रोहिणी में 1080 एल.आई.जी. आवास

(ii) सेक्टर 28 रोहिणी में 1380 एल.आई.जी. आवास

(iii) सेक्टर 29 रोहिणी में 1800 एल.आई.जी. आवास

(iv) सेक्टर 18 बी एच.आई.एच. फ्लैट द्वारका।

(ग) से (ड.) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि गलत नोटिस के मामले में उत्तरदायी अधिकारियों/एजेंसियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

मौसम की भविष्यवाणी सेवाओं में अनुसंधान

1994. श्री भक्त चरण दास : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मौसम की भविष्यवाणी में उच्च अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फिलहाल ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों में कितने विद्यार्थी शामिल है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान और जलवायु के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आवश्यक समूह बनाने के लिए, 2011 में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान (ई.एस.एस.ओ.-ओई. आई.टी.एम.) की स्थापना की गई जिसका कार्य विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के साथ बराबरी करने के लिए नियमित आधार पर आवश्यक प्रशिक्षित और समर्पित जलवायु और पृथ्वी प्रणाली वैज्ञानिकों का बड़ा समूह तैयार करना है। 18 महीने की अवधि वाले कड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, प्रशिक्षु को मंत्रालय के ई.एस.एस.ओ. की विभिन्न एजेंसियों/संस्थानों में वैज्ञानिक 'बी'/ वैज्ञानिक 'सी' के स्तर पर उपयुक्त संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं (बी. टेक/एम. टेक या एम.एस.सी.) के आधार पर शामिल किया जाएगा।

2011 से शुरू करके, राष्ट्रीय विज्ञापन और इसके बाद विधिवत् अनुबद्ध स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा/ग्रुप डिस्कशन/इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवर्ष-20 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रशिक्षुओं में से कुछ को प्रवेश देने के बाद पी.एच.डी. भी कारवाई जाएगी और उन्हें विदेश के नामी शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों में भी शोध प्रबन्ध के लिए भेजा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार पहले से ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) दिल्ली, आई.आई.टी. चेन्नै, भारतीय विज्ञान संस्थान (आई. आई.एस.सी.) बंगलौर, पुणे विश्वविद्यालय आदि में वायुमंडलीय और समुद्री विज्ञान में चल रहे एम. टेक कार्यक्रमों को पूर्णतः समर्थन देने के साथ-साथ पी.एच.डी. के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां और वैश्विक शैक्षणिक/अनुसंधान एवं कवकास पेशवरों में से पेशवरों को लाने के लिए प्रतिष्ठिता प्रोफेसर पीठ स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवा रही है।

झारखंड के लिए विशेष पैकेज

1995. श्री निशिकांत दुबे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके विपुल प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के दोहन के लिए पर्याप्त अवसंरचना के सृजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झारखंड को यदि कोई विशेष पैकेज दिया गया है तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्य को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य को विपुल प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के दोहन के लिए पर्याप्त अवसंरचना के सृजन हेतु कोई विशेष पैकेज नहीं दिय गया है। तथापि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजा में, झारखंड राज्य को खनिज (खान और भूविज्ञान) उप-क्षेत्रक के लिए 51.63 करोड़ रु. (2006-07 की कीमतों पर) की राशि आवंटित की गई थी। राज्य में खानों और भूविज्ञान के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों हेतु आवंटन के रूप में वार्षिक योजना 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 2.80 करोड़ रु. और 4.00 करोड़ रु. का परिव्यय उद्दिष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य की वार्षिक योजना 2012-13 के दौरान खनिज सर्वेक्षण, गवेषण, खान विकास और अवसंरचना के लिए 4.00 करोड़ रु. का परिव्यय आवंटित किया गया है।

विमानन क्षेत्र के लिए सी.ए.आर.

1996. श्री आनंदराव अडसुल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन आवश्यकता (सी.ए.आर.) एक दिशानिर्देश है जिसमें देश में विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) नागर विमानन आवश्यकता की "एसेस्मेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंसियल स्ट्रेस ऑन सेफअी ऑफ ऑपरेशन" शीर्षक से "फाइनेंसियल" शब्द को हटाने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमान यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। वायुयान नियम, 1937 के नियम 133क के तहत नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की गई हैं। ये अपेक्षाएं नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए विशेष निदेशों के रूप में हैं, जो कि भारत के बाहर या अंदर उड़ान भरने वाले विमान के प्रचालन, प्रयोग पजेशन, अनुरक्षण या दिक्चालन से संबंधित या वायुयान अधिनियम 1934 या वायुयान नियम 1937 के अनुरक्षण या दिक्कचालन से संबंधित या वायुयान अधिनियम 1934 या वायुयान नियम 1937 के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय से नागर विमानन अपेक्षा की "एसेस्मेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंसियल स्ट्रेस ऑन सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस" शीर्षक से 'फाइनेंसियल' शब्द को हटाने का अनुरोध नहीं किया है।

(ङ.) विमान यात्रियों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विमान प्रचालनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- **विमान दुर्घटनाओं तथा जोखिमपूर्ण घटनाओं की जांच से उत्पन्न सिफारिशों का क्रियान्वयन :**

  विभिन्न विमान दुर्घटनाओं तथा घटनाओं की जांचों से उत्पन्न सुरक्षा सिफारिशों का क्रियान्वयन संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाता है ताकि इस प्रकार की दुर्घटना/घटना से बचा जा सके। महानिदेशक, नागर विमानन की अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति विभिन्न न्यायालयों/जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति को आवधिक रूप से मॉनीटर करती है।

- **सुरक्षा सूचना का प्रसारण :**

  प्रचालकों में सुरक्ष जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर पायलटों, इंजीनियरों, ए.टी.सी.ओ. तथा प्रचालकों के साथ आवधिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

- **विमान संरक्षा परिपत्र/नागर विमानन अपेक्षाओं को जारी किया जाना :**

  दुर्घटनाओं का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और इन विश्लेषणों के आधार पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए महत्वपूर्ण अवलोकनों/निष्कर्षों को प्रचालकों के ध्यान में लाने के लिए विमान संरक्षा परिपत्र जारी किए जाते हैं। विमान संरक्षा परिपत्रों के माध्यम स संरक्षा संबंधी एहतियात भी परिचालित किए जाते हैं। जब कभी आवश्यकता महसूस होती है, नागर विमानन अपेक्षाओं को जारी करके विनियामक परिवर्तन किए जाते हैं। वी.आई.पी. कैरेज की आवश्यकता, उड़ान ड्यूटी समय सीमितताओं आदि की समीक्षा की जा रही है। विभिन्न प्रचालकों के लिए हेलीकॉप्टर के प्रशिक्षण तथा प्रचालन संबंधी विस्तृत नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की गई हैं।

- **उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी :**

  नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान निरीक्षक पायलटों द्वारा विभिन्न प्रचालकों के पायलटों की आवधिक कुशलता तथा मानकीकरण की जांच की जाती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रचालनिक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जा रहा है।

- **प्रचालकों का संरक्षा ऑडिट :**

  नागर विमानन महानिदेशालय के सुरक्षा ऑडिट दल द्वारा प्रचालकों तथा अनुरक्षण संगठनों का आवधिक सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टों में बताई गई कमियों को तत्काल आवश्यक उपचारी इनहाउस उपायों के लिए प्रचालकों के ध्यान में लाया जाता है। नागर विमानन महानिदेशालय ने गुणवत्ता नियंत्रण तथा संरक्षा के लिए प्रचालकों को अधिक उत्तरदायी

बनाने के अपने प्रयासों में इस बात पर बल दिया है कि प्रचालक नागर विमानन महानिदेशालय संरक्षा ऑडिट के अतिरिक्त अपना आंतरिक ऑडिट भी करें।

- **आवधिक स्थल जांचें :**

निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानदेशालय के अधिकारियों द्वारा प्रचालनों तथा प्रचालकों की अनुरक्षण गतिविधियों की आवधिक स्थल जांचों में तीव्रता लाई गई है।

- **खराब मौसम स्थितियों में प्रचालन संबंधी विशेष सावधानियां:**

प्रचालकों तथा हवाईअड्डा प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे मॉनसून तथा धुंध की अवधि के दौरान विशिष्ट कार्रवाईयां करें। मॉनसून परिस्थितियों में पायलटों की कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों पायलटों की विशेष जांचें की जाती हैं।

- **पुराने विमानों पर उड़नयोग्यता नियंत्रण :**

अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्धारित करके जेसे 20 वर्ष से अधिक पुराने विमान के लिए उड़नयोग्यता वैधता प्रमाण पत्र 06 महीनों तक के लिए जारी किया जाना और निरीक्षण अनुसूची की आवधिकता को 80% तक कम करना, और प्रचालकों द्वारा विमान के आयात के लिए विमान की अधिकतम आयु को 15 वर्ष/45000 साईकिलों तक प्रतिबंधित करना, जो भी कम हो, द्वारा पुराने विमानों पर प्रभावी उड़नयोग्यता नियंत्रण के लिए उपाय किए गए हैं।

- **पक्षी टकराते की घटनाओं से बचाव :**

पक्षी टकराने की समस्या को कम करने के लिए प्रभावपूर्ण उपायों को अपनाए जाने हेतु हवाईअड्डा प्राधिकारियों तथा स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों के संहयोग से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, पक्षी टकराने की घटनाओं की संख्या में व्यापक कमी हुई है।

- **दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई :**

जब भी यह पता चलता है कि संरक्षा के लिए समझौता किया गया है या कि निर्धारित मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

दूर संवेदी इकाइयां स्थापित करना

1997. कुमारी मीनाक्षी नटराजन : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूकंप आपदा प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए किन-किन क्षेत्रों में दूर संवेदी इकाइयां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन इकाइयों की स्थापना के लिए किस हद तक कार्य पहले पूरा कर लिया गया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कार्य पूरा किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) भूकंप आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए दूर संवेदी इकाइयों की स्थापना करने की योजना नहीं बना रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिला शिक्षक

1998. श्री रमाशंकर राजभर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का प्रतिशत क्या है; और

(ख) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की राज्य-वार संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) वर्ष 2011-12 के लिए जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के अनुसार 46.3 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल शिक्षक महिलाएं थीं। 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों की राज्यवार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्राथमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या (स्रोत : डीआईएसई)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला शिक्षकों की संख्या		
	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	703	605	757
आंध्र प्रदेश	98243	114474	116659
अरुणाचल प्रदेश	2576	2468	2068
असम	39412	40257	38263
बिहार	62664	60914	62337
चंडीगढ़	199	145	120
छत्तीसगढ़	33429	37888	40767
दादरा और नगर हवेली	146	152	213
दमन और दीव	198	246	247
दिल्ली	19769	18678	20009
गोवा	2359	2229	2508
गुजरात	15875	14865	15434
हरियाणा	18235	19526	20573
हिमाचल प्रदेश	13459	13013	12887
जम्मू और कश्मीर	13804	14043	13801
झारखंड	15353	16241	16633
कर्नाटक	28556	30476	31200
केरल	32239	33027	38687
लक्षद्वीप	101	117	122

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	76812	76129	75498
महाराष्ट्र	65851	66647	68946
मणिपुर	3207	4684	5069
मेघालय	11489	12601	12713
मिजोरम	3237	3079	3460
नागालैंड	4072	3701	4056
ओडिशा	32253	35180	38998
पुदुचेरी	1376	1171	1132
पंजाब	29521	34594	33297
राजस्थान	34209	33915	33621
सिक्किम	1786	1761	1727
तमिलनाडु	109226	111701	112385
त्रिपुरा	1997	2211	2150
उत्तर प्रदेश	208259	217774	235157
उत्तराखंड	20939	21561	21988
पश्चिम बंगाल	115817	124844	128716
कुल	1117371	1170917	1212198

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय श्रमिक

1999. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देश कार्य समझौते के अनुसार भारतीय श्रमिकों की कार्य अवधि पूरा होने से पूर्व ही उन्हें भारत वापस भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन देशों ने अभी तक कितने भारतीय श्रमिकों को भारत वापस भेजा है; और

(घ) इन श्रमिकों के संरक्षण/सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सऊदी अरब तथा खाड़ी के अन्य देशों के भारतीय कामगार आम तौर पर घर वापसी से पहले कार्य करारों के अनुरूप अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, यदि स्थानीय कानूनों तथा विनियमों का उल्लंघन न हुआ हो। हमारे मिशन यह सुनिश्चित करते हेतु उपयुक्त कदम उठाते रहते हैं कि उनके ध्यान में लाए गए विशिष्ट मामलों के संबंध में नियोक्ताओं द्वारा भारतीय कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय न हो। वे हमारे प्रवासियों के कल्याण तथा उनकी देख भाल के लिए सातों दिन चौबीसों घंटे हेल्पलाईन के माध्यम से, भारतीय सामुदायिक संगठनों के साथ लगातार बातचीत करके तथा प्रत्येक महीने विशिष्ट दिनों में नियमित ओपन हाउसेज़ के माध्यम से भी उनके साथ निकट सम्पर्क में रहते हैं।

(ग) और (घ) लागू नहीं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत आई.आई.आई.टी. की स्थापना करना

2000. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप मांझी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में "लाभ के लिए नहीं" आधार पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.ऑई.टी.) की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस प्रकार के आई.आई.आई.टी. की स्थापना के लिए निर्धारित निबंधनों और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार के आई.आई.आई.टी. की स्थापना पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें देश में इस प्रकार के आई.आई.आई.टी. की स्थापना किए जाने के लिए अब तक चिन्हित किया गया है;

(च) क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रत्येक आई.आई.आई.टी. का शैक्षिक सत्र आरम्भ करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने कुल 2808.71 करोड़ रूपए के परिव्यय से सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति में 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) स्थापित करने की एक योजना अनुमोदित की है। जहां इस प्रयोजन के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं आई.आई.आई.टी. 128 करोड़ रूपए की पूंजी लागत से स्थापित की जाएंगी। इस राशि का योगदान 50:35:15 (उत्तर पूर्वी राज्यों में 57:5:35:7.5) के अनुपात में क्रमश: केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और औद्योगिक भागीदार द्वारा किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि आई.आई.आई.टी. शुरू में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत की जाएंगी तथा एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा जिसमें सभी साझीदारों के कार्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया जाएगा।

(ङ) अब तक केन्द्र सरकार ने असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में आई.आई.आई.टी. स्थापित करने के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन संसूचित कर दिया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम

2001. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केंद्रीय विद्यालयों में चित्रकला, वास्तुकला और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों की शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में किस कक्षा तक इन विषयों को पढ़ाया जाता है;

(घ) क्या उक्त विषयों को कक्षा एक से पढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त विषयों को कब तक पढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) केंद्रीय विद्यालयों में कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, कक्षा-I से X तक पढ़ाई जाती है। +2 स्तर पर शारीरिक शिक्षा, वैकल्पिक विषयों में से एक है। केंद्रीय विद्यालयों में वास्तुकला नहीं पढ़ाई जाती है। केंद्रीय विद्यालयों में वास्तुकला को छोड़कर उपर्युक्त विषय पहले ही कक्षा-I से पढ़ाए जा रहे हैं।

(ङ) से (च) केंद्रीय विद्यालयों में वास्तुकला को पढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है।

[अनुवाद]

मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना

2002. **श्री कमलेश पासवान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनेक निजी तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थानों ने मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और देश के इन संस्थानों के निवेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) निजी संस्थानों का मूल्यांकन करने में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए रखे गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 17 प्राईवेट उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी.सी.) (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के अनुसार विचार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त, 2012 तक प्राप्त आवेदनों में पाई गई कमियों के बारे में संबंधित संस्थाओं के बारे में सूचित कर दिय गया है। प्राइवेट उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की वर्ष वार एवं राज्य-वार संख्या संलग्न-विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के प्राइवेट उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु मूल्यांकन करने के लिए निष्पक्षता बनाए रखने संबंधी दिशा-निर्देशों का निर्धारण किया गया है। ये दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

विवरण

क्र .सं.	राज्य का नाम	प्राइवेट उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या (वर्ष वार)		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1		
2.	पंजाब	1		
3.	तमिलनाडु	1		

1	2	3	4	5
4.	मध्य प्रदेश		1	
5.	महाराष्ट्र		2	1
6.	ओडिशा		1	1
7.	तमिलनाडु		2	1
8.	उत्तर प्रदेश		3	2
	वर्ष-वार योग	3	9	5

अखिल भारतीय सेवाओं का ग्रेड पे

2003. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (आई.ए.एस.) अधिकारियों की ग्रेड पे को उस पद जिस पर उन्हें उनके वर्तमान केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के आरम्भ में नियुक्त किया गया था, पर समिति करने का अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस.) के वरिष्ठ अधिकारियों को उसी मंत्रालय में उनके कनिष्ठ अधिकारियों और कुछ मामलों में उसी राज्य संवर्ग के कनिष्ठ अधिकारियों की तुलना में कम वेतन अथवा ग्रेड पे मिलने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के भेदभाव से अधिकारियों के मनोबल में गिरावट नहीं आएगी;

(घ) इस प्रकार से प्रभावित अधिकारियों जिन्होंने समय से पूर्व अपने राज्यों में वापसी अथवा इसी आधार पर अथवा अन्य आधार पर स्थानांतरण की मांग की है, की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम (सी.एस.एस.) तथा गैर-केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम (गैर-सी.एस.एस.) के तहत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तथा उनका वेतन प्रत्येक स्कीम के तहत पृथक रूप से विनियमित किया जाता है। सी.एस.एस. के तहत नियुक्ति पर, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का वेतन संबंधित राज्य संवर्गों में उनके द्वारा आहरित वेतन के संदर्भ के साथ-साथ पद के वेतनमान के अनुसार नियत किया जाता है, जबकि गैर-सी.एस.एस. स्कीम के तहत नियुक्ति पर वेतन को उनके द्वारा चुने गए वेतन के विकल्प के आधार पर नियत किया जाता है।

(ख) अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा विनियमित सी.एस.एस. एवं गैर-सी.एस.एस. के तहत कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा का कोई वरिष्ठ अधिकारी उसी राज्य संवर्ग के अपने उस कनिष्ठ से कम वेतन आहरित कर रहा है जो उसी स्कीम के तहत पद के उसी स्तर पर कार्य भी कर रहा हो।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात भवन का विस्तार

2004. श्री हरिन पाठक :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से नई दिल्ली

गुजरात भवन के विस्तार हेतु भूमि के आवंटन हेतु निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा अतिरिक्त भूमि आबंटित करना संभव नहीं है।

आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का भारत दौरा

2005. **श्री प्रबोध पांडा :**
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान आज की तिथि तक भारत का दौरा करने वाले विदेशी शिष्टमंडलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक शिष्टमंडल के साथ किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) क्या उनके द्वारा कोई द्विपक्षीय समझौते किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है;

(च) की गई चर्चा और उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (छ) आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सुश्री जुलिया गिलार्ड ने 15-17 अक्तूबर 2012 को भारत की सरकारी यात्रा की थी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उनके साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बात-चीत की थी। उन्होंने राष्ट्रपति, यू.पी.ए. अध्यक्ष, विदेश मंत्री तथा विपक्ष के नेता से मुलाकात की। रणनीतिक सहभागिता को सशक्त बनाने तथा आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की नई पहलें की गईं। विद्यार्थी आवागमन एवं कल्याण, सिविल अंतरिक्ष विज्ञान, ऊन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग संवर्धित करने के लिए चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया था।

पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के लिए तथा बहुआयामी सहयोग को सशक्त बनाने के लिए सतत उपाय किए हैं। वर्ष 2009 में संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्चस्तरीय यात्राएं हुई हैं। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गिलार्ड की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में नए सिरे से गतिशीलता आई है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यावसायिक

2006. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यावसायिक अमरीका को पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2011 के दौरान भारतीय कंपनियों के एल-वन वीजा के अनेक आवेदन रद्द किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यावसायिकों सहित कई हजार कुशल व्यावसायिक सेवा प्रदायी कंपनियों के लिए कार्य करने हेतु प्रति वर्ष अमेरिका की यात्रा करते हैं। 25 अक्तूबर, 2011 को अमरीकी दूतावास द्वारा जारी

की गई प्रेस प्रकाशनी के अनुसार अमेरिका के राजकोषीय वर्ष 2011 में 67,195 एच-1बी वीजा तथा 25,000 से अधिक एल-। वीजा जारी किए गए थे। भारत में प्रवास करने से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) नेशनल फाउण्डेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी नामक एक स्वतंत्र संगठन द्वारा नवंबर, 2011 में संकलित रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिका द्वारा राजकोषीय वर्ष 2010 में जारी किए गए एल-। वीजा की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2011 में जारी वीजा में 28% की कमी आई है। वर्ष 2011 में अमेरिका 25,898 भारतीय नागरिकों को एल-। वीजा जारी किए थे जबकि वर्ष 2010 में 35,896 एल-। वीजा जारी किए गए थे।

(ङ) सरकार व्यापारिक बैठकों सहित प्रत्येक अवसर का उपयोग भारतीय व्यावसायिकों को वीजा के संबंध में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में अमेरिकी सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त करने हेतु करती रहती है।

[हिन्दी]

स्वचालित डाक छंटाई केंद्र

2007. श्री प्रेमचंद गुड्डू :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खोले गए स्वचालित डाक छंटाई केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऐसे खोले जाने वाले केंद्रों की संख्या का राज्य-वार और मध्य प्रदेश सहित स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के अनेक राज्यों में डाक छंटाई केंद्रों का अधिक दूरी पर होने के कारण डाक की सुपुर्दगी में अत्यधिक विलंब होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे केंद्रों को केंद्रीय स्थलों पर अंतरित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) देश में अब तक चार स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केंद्र (एएमपीसी) खोले गए हैं। राज्यवार रूप से ये केंद्र मुंबई (महाराष्ट्र), चेन्नई (तमिलनाडु), दिल्ली (दिल्ली) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

(ख) निधियों की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन 12वीं योजना के दौरान हैदराबाद और बेंगलूर में दो और एएमपीसी खोलने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश में एएमपीसी खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं। कोई असाधारण विलंब नहीं हुआ है। सेवा की गुणवत्ता की मानीटरिंग कड़ाई से की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर संवितरण में सुधार के उपाय किए जाते हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अध्यापकों को प्रशिक्षण

2008. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी मौसमों में पढ़ाने के लिए उपयुक्त कक्षाओं तथा वर्ष 2013 तक निर्धारित शिष्य-अध्यापक अनुपात को पूरा करने के लिए पर्याप्त अध्यापकों का प्रावधान करने तथा 2015 तक अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तक 304112 नए स्कूल-भवन और 19.82 लाख शिक्षक पदों की संस्वीकृति दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान, अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। दिनांक

30.09.2012 तक संस्वीकृत नए स्कूल भवनों, पूरा किए गए एवं प्रगति पर और दिनांक 30.09.2012 स्थिति के अनुसार संस्वीकृति एवं भर्ती किए गए अध्यापकों के पदों की स्थिति के संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 में अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य-वार संस्वीकृति को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल भवन		अध्यापक	
	संस्वीकृत (30.09.2012 तक)	पूरा कर लिए गए और कार्याधीन (30.09.2012)	संस्वीकृत (30.09.2012 तक)	भर्ती किए गए (30.09.2012 तक)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	10083	9744	39189	38319
अरूणाचल प्रदेश	2173	2038	7262	5226
असम	12149	12149	48808	38364
बिहार	18010	14692	403413	191983
छत्तीसगढ़	19429	19028	67507	54985
गोवा	00	00	169	149
गुजरात	835	797	58688	31336
हरियाणा	2414	2267	13435	6345
हिमाचल प्रदेश	115	16	5856	3553
जम्मू और कश्मीर	11743	9806	43471	39739
झारखंड	29463	28825	120396	84672
कर्नाटक	3751	3736	29055	24278
केरल	529	240	2925	00
मध्य प्रदेश	45183	44741	173855	98287
महाराष्ट्र	18775	17256	42091	8522

1	2	3	4	5
मणिपुर	1158	460	2871	1544
मेघालय	5031	4508	13262	14020
मिजोरम	1453	1285	2485	1303
नागालैंड	931	931	3147	590
ओडिशा	17818	17883	89901	88442
पंजाब	1507	1396	14090	7432
राजस्थान	8466	8340	114132	94201
सिक्किम	108	95	724	223
तमिलनाडु	8322	8322	33214	22497
त्रिपुरा	2007	1987	6980	5694
उत्तर प्रदेश	62925	60215	423553	258924
उत्तराखंड	4430	4038	14316	5998
पश्चिम बंगाल	15117	9099	198253	115797
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	41	4	210	162
चंडीगढ़	36	32	1390	785
दादरा और नगर हवेली	61	61	937	526
दमण और दीव	15	12	119	95
दिल्ली	13	13	7104	4342
लक्षद्वीप	9	8	38	16
पुदुचेरी	12	8	48	36
कुल	304112	284032	1982894	1248385

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012-13 में अप्रशिक्षत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्वीकृति
1.	आन्ध्र प्रदेश	107
2.	अरूणाचल प्रदेश	4360
3.	असम	10000
4.	बिहार	39210
5.	छत्तीसगढ़	10045
6.	हिमाचल प्रदेश	3627
7.	जम्मू और कश्मीर	10000
8.	झारखंड	14022
9.	मध्य प्रदेश	15101
10.	महाराष्ट्र	5337
11.	मणिपुर	5401
12.	मेघालय	7333
13.	मिजोरम	1600
14.	नागालैंड	1000
15.	ओडिशा	20208
16.	सिक्किम	687
17.	त्रिपुरा	3010
18.	उत्तर प्रदेश	61600
19.	पश्चिम बंगाल	25000
	कुल	237648

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना

2009. श्रीमती मौसम नूर :
श्री प्रेमचन्द गुड्डू :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में चल रहे मदरसों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) मदरसों की स्थापना के लिए मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 2008-09 से 'मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना' कार्यान्वित कर रहा है जिसमें इस योजना का विकल्प चुनने वाले मदरसों और मकतबों को अपनी पाठ्यचर्चा में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी विषय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के कार्यान्वयन की शुरूआत से अब तक इस योजना के तहत 10602 मदरसों को सहायता प्रदान की गई है।

(ख) सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) वे मदरसे और मकतब, जो कम-से-कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हैं और मदरसा बोर्डों अथवा वक्फ बोर्डों अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) के तहत पंजीकृत हैं, एस.पी.क्यू.ई.एम. के अंतर्गत सहायतार्थ आवेदन करने के पात्र हैं।

(घ) विगत तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रदत्त राज्य-वार निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एस.पी.क्यू.ई.एम. के अंतर्गत जारी राज्य-वार निधियां दर्शाने वाला विवरण

(रूपए लाख में)

क्र .सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012.13 नच जव 20.11.12012
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	260.00	–	–
2.	असम	–	1039.00	459.53	–
3.	बिहार	–	–	–	55.54
4.	चंडीगढ़	0.36	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	811.67	229.70	592.78
6.	हरियाणा	–	37.50	–	–
7.	जम्मू और कश्मीर	–	347.87	538.60	–
8.	झारखंड	497.18	–	–	–
9.	कर्नाटक	–	490.17	210.58	
10.	केरल	–	1490.09	–	–
11.	मध्य प्रदेश	561.35	1343.24	1085.53	1794.48
12.	महाराष्ट्र	–	36.59	147.52	30.94
13.	राजस्थान	–	547.46	71.95	392.66
14.	त्रिपुरा	374.18	–	–	–
15.	उत्तर प्रदेश	3190.47	3554.55	11175.37	9865.82
16.	उत्तराखंड	–	188.86	34.62	432.34
	कुल	4623.54	10147.00	13953.40	13164.56

साइबर निगरानी एजेन्सी

2010. श्री प्रदीप माझी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री अंजन कुमार एम. यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्रीमती रमा देवी :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खराब विषय वस्तु, जिससे देश में कानून और व्यवस्था इत्यादि पर असर पड़ सकता है, के लिए वेब और सामाजिक नेटवर्कों की निगरानी करने के लिए एक समर्पित साइबर निगरानी एजेन्सी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा साइबर निगरानी एजेंसी के लिए शक्तियां प्रदान करने को अंतिम रूप दिए जाने से पहले विभिन्न पणधारकों के साथ क्या विचार-विमर्श किया गया;

(ग) ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिका (आई.टी.) अधिनियम में कमियों को दूर करने हेतु एक विधिक तंत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गृह मंत्रालय ने आसूचना ब्यूरो को दुर्भावनापूर्ण विषय वस्तु हेतु वेब और सोशल मीडिया सेवाओं की निगरानी के लिए अधिकृत करने का अनुरोध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और निगरानी एजेन्सी के कब तक प्रचालनात्मक होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त उपबंध हैं। इसके अलावा, सरकार ने अधिनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के मुद्दे के हल के लिए सोशल मीडिया सहित सभी पणधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की है। यह सहमति हुई कि गैर-इरादतन परिणामों को न्यूनतम करने और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण और दिशानिर्देशों के जरिए प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए सभी पणधारक साथ मिल मिलकर काम करेंगे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

शिकायत निवारण समिति

2011. **श्री एम.बी. राजेश : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों तथा मुद्दों का निवारण करने हेतु गठित संयुक्त परामर्शदात्री समिति वर्तमान में कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की पिछली बैठक संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परिषद किन विभागों में कार्यरत हैं तथा इनकी पिछली बैठक किस तारीख को हुई थी;

(घ) क्या सेवानिवृत व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद अथवा विभागीय परिषद का एक सदस्य बन सकता है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या विभागीय परिषद में सेवानिवृत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक 15.05.2010 को हुई थी; अन्तर्काल के दौरान, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए, जे. सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों एवं सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों से गठित, राष्ट्रीय विसंगति समिति की बैठक, कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 2009 से 2012 तक पांच बार हुई। इसकी पिछली बैठक 14 जुलाई, 2012 को हुई थी।

(ग) यह जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) से (च) कर्मचारी पक्ष के सदस्यों का जे.सी.एम. की संयुक्त परिषद् में नामांकन, जे.सी.एम. स्कीम के अंतर्गत होता है, जो गैर सांविधिक प्रकृति का है एवं कर्मचारी पक्ष एवं आधिकारिक पक्ष की परस्पर सहमति से होता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि ''कर्मचारी संगठन तीन वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधियों का नामांकन करेंगे; लेकिन पुनः नामांकन पर कोई रोक नहीं होगी'' एवं ''कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारी नहीं हैं या केन्द्रीय सरकार का मानद सेवानिवृत हुआ कर्मचारी परिरषद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता''।

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवसंरचना मानक

2012. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के केवल 5 प्रतिशत राज्यों ने ही आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवसंरचना मानकों को अब तक पूरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च 2013 की निर्धारित समय-सीमा के अंदर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार आवश्यक अवसंरचना के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जिला शिक्षा सांख्यिकी सूचना (डी.आई.एस.ई.) 2011-12 (अनन्तिम) के अनुसार 87.7 प्रतिशत प्रारंभिक स्कूलों में प्रसाधन, 94.6 प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी, 53.6 प्रतिशत स्कूलों में रैंप, 70.1 प्रतिशत स्कूलों में चार दीवारी और 79.1 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान हैं।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ स्कूल अवसंरचना को बढ़ाना है, जिसके लिए अभी तक राज्यों/संघ शासित राज्यों में 3.04 लाख स्कूल भवन, 17.92 लाख अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, 8.53 लाख प्रसाधन, 2.29 लाख पेय जल सुविधाएं, 5.01 लाख रैंप, 1.57 लाख स्कूलों में चार दीवारी संस्वीकृत की गई है।

अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय

2013. श्री एल. राजगोपाल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड.डी) पर सकल घरेलू व्यय 1995 में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 0.72 प्रतिशत से बढ़ कर आज की तारीख तक जी.डी.पी. का 0.88 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर एण्ड डी पर कोई विशेष जोर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। अद्यतन उपलब्ध अनुसंधान और विकास आंकड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) पर सकल घरेलू व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में वर्ष 1995 में 0.6% से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 0.88% हो गया है ऐसा विगत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी की वजह से हुआ है। तत्संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) सरकार 12वीं योजना अवधि के अंत तक जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान और विकास व्यय

को लगभग 0.9% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2% तक करने का लक्ष्य रखती है। यह विगत वर्षों के व्यय के दोगुने से अधिक है और यह देश के समग्र संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का महत्वपूर्ण आबंटन दर्शाता है। सरकार नीतिगत परिवर्तनों, उद्योग एवं कार्यनीतिक क्षेत्रों के निवेश सहित अनुसंधान और विकास निवेश में बढ़ोत्तरी, आधारभूत विज्ञान अवसंरचना के विस्तार, भोजन एवं स्वास्थ्य देखरेख जैसी विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संयोजन, वैज्ञानिक अनुसंधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के नए मॉडलों के विकास, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से 12वीं योजना अवधि के दौरान इस लक्षित लक्ष्य को हासिल करने का इरादा रखती है।

विवरण

जी.डी.पी. से संबंधित अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय व्यय

वर्ष	अनुसंधान और विकास व्यय (करोड़ रू.)	जी.डी.पी. के % के रूप में आर एण्ड डी
1	2	3
1995-96	7483.88	0.69
1996-97	8913.61	0.71
1997-98	10611.34	0.76
1998-99	12473.17	0.77
1999-00	14397.60	0.81
2000-01	16198.80	0.84
2001-02	17038.15	0.81
2002-03	18088.16	0.80
2003-04	20086.34	0.79
2004-05	24117.24	0.84
2005-06	28776.65	0.88
2006-07	*32941.64	0.87
2007-08	*37777.90	0.88

*अनुमानित

स्त्रोत: अनुसंधान और विकास आंकड़े 2009, डी.एस.टी. (भारत सरकार)

टिप्पणी: जी.डी.पी.: सकल घरेलू उत्पाद

निजी विमान कंपनियों के विमान किराए

2014. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने निजी विमान कंपनियों के किराया बैण्ड को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अधिक विमान किराया बैण्ड को स्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियों ने टिकट मुद्रण शुल्क, अकेले किशोर के लिए सर्वोत्तम सीट शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क तथा रद्द करने अथवा रिशेड्यूल शुल्क इत्यादि सहित विभिन्न सेवाओं के लिए हाल ही में किराए बढ़ा दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसे प्रभार बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने किस तारीख को विमान कंपनियों को किराया/प्रभार बढ़ाने की अनुमति दी है; और

(छ) सार्वजनिक तथा निजी विमान कंपनियों द्वारा किराया/प्रभार को अत्यधिक बढ़ाने पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) घरेलू यात्रियों के लिए लागू हवाई किरायों का निर्धारण बाज़ार शक्तियों द्वारा किया जाता है और इन्हें सरकार द्वारा नियत नहीं किया जाता है। हवाई किराए ए.टी.एफ. की कीमतों, हवाईअड्डा विकास प्रभारों, यात्री सेवा शुल्क, विदेशी मुद्रा दरों, सेवा कर आदि पर निर्भर करते हैं। इनमें से किसी भी घटक में घटा-बढ़ी से हवाई किराए प्रभावित होते हैं। अनुसूचित एयरलाइनें प्रत्येक उड़ान के लिए अलग-अलग किराया वर्ग ऑफर करती हैं और एयरलाइनों द्वारा कम किराया वर्ग में ऑफर किए गए हवाई किराए वहनीय होते हैं। सीटों की मांग में वृद्धि के साथ-साथ हवाई किराए बढ़ते जाते हैं क्योंकि निम्न किराया वर्ग तेजी से बिक जाते हैं। घरेलू हवाई किरायों की औचक मॉनीटरिंग से पता चलता है कि हवाई किराए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध किराया बैंड के भीतर बने रहते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। घरेलू यात्रियों के लिए लागू हवाई किरायों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है और इन्हें सरकार द्वारा नियत नहीं किया जाता है।

(छ) टैरिफ प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से, नागर विमानन महानिदेशालय ने निम्न कदम उठाए हैं:

अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों से कहा गया है कि निर्धारित टैरिफ को मासिक आधार पर मार्ग-वार और किराया श्रेणी-वार प्रदर्शित करे तथा यह भी कि उल्लेखनीय परिवर्तनों के बारे में ऐसी परिवर्तन होने के 24 घंटे के भीतर डी.जी.सी.ए. को भी सूचित करें। उपरोक्त निदेशों का उद्देश्य एयरलाइनों की कीमत निर्धारित करने की पद्धति के बारे में यात्रियों को अवगत रखना है।

इसके अतिरिक्त, डी.जी.सी.ए. भी नियमित रूप से विनिर्दिष्ट सेक्टरों पर टैरिफ पर नजर रखता है।

असम में उच्च शिक्षा/तकनीकी संस्थानों की स्थापना

2015. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या मानव संसाधन विकास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बोडोलैण्ड के अंदर तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षण के दायरे में प्रगति एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु असम के कोकराझार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय "बोडोलैण्ड सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी", भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना हेतु कोई विशेष पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) अब तक, असम के बोडोलैंड के क्षेत्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि असम राज्य में पहले से ही दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय नामत: असम विश्वविद्यालय, सिल्चर और तेजपुर विश्वविद्यालय हैं। इस क्षेत्र में किसी भारतीय प्रबंध संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी में पहले से ही एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और शिलांग में भारतीय प्रबंध संस्थान है। जहां तक आई.आई.आई.टी. का संबंध है, राज्य सरकार ने हाल ही में इसके लिए गुवाहाटी में भूमि अभिनिर्धारित की है।

मेट्रो रेल का विस्तार

2016. डॉ. भोला सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद में मोहन नगर तथा वैशाली से इंदिरापुरम तक दिल्ली मेट्रो सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है तथा इसे दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.)/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके लिए डी.एम.आर.सी. ने मृदा परीक्षण हेतु कोई अध्ययन शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो डी.पी.आर. की तैयारी पर कितना व्यय हुआ तथा सरकार द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.एस.आर.सी.) ने सूचित किया है कि उन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जी.डी.ए.) के अनुरोध पर दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे, गाजियाबाद (मोहन नगर से) मेट्रो लाईन के विस्तार के लिए वर्ष 2005 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की थी। जुलाई 2010 में अद्यतन कर जी.डी.ए. को पुनः प्रस्तुत की गई। भारत सरकार को दिलशाद गार्डन से आगे मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के वैशाली से इंदिरा पुरम तक विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उक्त डी.पी.आर. में दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे, गाजियाबाद तक मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए 7 स्टेशनों वाले 9.41 कि.मी. लम्बे मार्ग का उल्लेख है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त विस्तार से संबंधित डी.पी.आर. तैयार करने के लिए डी.एम.आर.सी. ने सेवाकर समेत 75 लाख रू. कन्सलटेंसी शुल्क के रूप में प्राप्त किए। भारत सरकार को दिलशाद गार्डन से आगे मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अंतिम कार्रवाई का ब्यौरा देने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रिश्वतरोधी कानून में संशोधन

2017. **श्री निखिल कुमार चौधरी :**
श्री रूद्रमाधव राय :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में मौजूद भ्रष्टाचार को भारतीय दंड संहिता के दायरे में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को इसके दायरे में लाने के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दिए जाने पर नियंत्रण करने हेतु आचार संहिता शुरू करने हेतु वर्तमान रिश्वत रोधी कानून में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सरकार के पास गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के कोई आंकड़े नहीं हैं

(ग) और (घ) भारतीय दंड संहिता में गैर-सरकारी क्षेत्र में घूसखोरी हेतु दंड का प्रावधान नहीं है। तथापि, चूंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में घूसखोरी के कृत्य को आपराधिक माना जाए, अतः गैर-सरकारी क्षेत्र में घूसखोरी को एक दांडिक अपराध बनाने हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए जाने के संबंध में गृह मंत्रालय में एक प्रस्ताव है। चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में दंड विधि और दंड प्रक्रिया आते हैं। अतः उनके द्वारा सूचित किया यगा है कि इस प्रस्ताव पर राय बनाना, सभी राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों से राय प्राप्त किए जाने के अध्यधीन होगा।

(ङ) और (च) गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल किए जाने के लिए विद्यमान रिश्वत रोधी कानूनों में संशोधन करने हेतु और लोक कर्मचारियों की घूसखोरी रोकने हेतु आचार संहिता शुरू करने का सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

लाइसेंस के प्रावधानों का उल्लंघन

2018. **श्री रमेश राठौड़ :**
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री एन. कृष्टप्प;
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने आपके मंत्रालय को लाइसेंस के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कुछ आपरेटरों पर सख्त कार्रवाई करने तथा अर्थदण्ड लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या आपरेटरों के विरूद्ध अभी भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलम्ब के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) आपरेटरों के विरूद्ध दूरसंचार विभाग द्वारा कब तक कार्रवाई करने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) गृह मंत्रालय तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में नियमित रूप से अंत:संपर्क करते रहते हैं। हाल ही में, गृह मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई.पी.) अड्रेसो का समाधन करने में आने वाली कतिपय तकनीकी कठिनाइयों के बारे में सूचित किया गया था। आई. पी. (संस्करण 4) अड्रेसों की कमी होने की वजह से सेवा प्रदाताओं द्वारा ''नेटवर्क अड्रेस ट्रांसलेटिंग'' तकनीक का उपयोग करने में ऐसी ही कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। सरकार ऐसे तकनीकी मुद्दों के समाधान हेतु सभी स्टेकधारकों के साथ नियमित रूप से संपर्क करती रहती है।

इसके अलावा, विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भेजे गए मामले सहित अन्य मामलों की जांच भी की जाती है तथा लाइसें की शर्तों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. की बाजार में हिस्सेदारी

2019. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री अशोक तंवर :
श्री रतन सिंह :
श्री इज्यराज सिंह :
डॉ. बलीराम :
श्री एस. अलागिरी :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
डॉ. संजय सिंह :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री ताराचंद भगोरा :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) की बाजार में हिस्सेदारी निजी सेवा प्रदाताओं की तुलना में घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन्हें कितना घाटा हुआ है और इसके कंपनी-वार और वर्ष-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त दोनों सरकारी उपक्रमों ने ऋण ले रखा है और अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्तियां बेची हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उक्त ऋण राशि पर इन्होंने कितना ब्याज चुकाया; और

(ङ) उक्त सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या के मद्देनजर उनकी बाजार हिस्सेदारी का ब्यौरा निम्नानुसार है :

दिनांक की स्थिति के अनुसार	टेलीफोन उपभोक्ताओं की बाजार हिस्सेदारी (%)	
	बीएसएनएल	एमटीएनएल
31.03.2010	17.34	14.21
31.03.2011	15.26	11.25
31.03.2012	13.96	11.00
31.09.2012	14.14	10.67

विगत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को हुए निवल लाभ/हानि संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	लाभ/हानि (करोड़ रुपए में)	
2009-10	(-) 1823	(-) 2611
2010-11	(-) 6384	(-) 2802
2011-12	(-) 8851	(-) 4109

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को होने वाली हानि के कारण निम्नलिखित हैं :-

★ फिक्सड फोन की जगह मोबाइल फोन का उपयोग करने तथा मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से राजस्व की हानि हुई है।

★ अन्य प्राइवेट प्रचालकों का तुलना में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल में स्टाफ पर होने वाला व्यय काफी अधिक है। बीएसएनएल में यह राशि कुल राजस्व राशि का लगभग 50% है जबकि एमटीएनएल में 70% से अधिक है।

★ बीएसएनएल तथा एमटीएनएल दोनों ने 3जी तथा ब्रॉडबैंड वायरलेस अधिगम के लिए अपफ्रंट स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में क्रमश: 18500 करोड़ रुपए तथा 11098 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है।

(ग) और (घ) बीएसएनएल तथा एमटीएनएल दोनों कंपनियां अपनी भूमि/भवन परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं की है। तथापि इन दोनों कंपनियों ने ऋण लिया है। विगत तीन वर्षों के दौरान, बीएसएनल तथा एमटीएनल ने पूंजीगत व्यय केलिए 1320 करोड़ रुपए की राशि का ऋण लिया है तथा इस ऋण पर 99 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान ब्याज के रूप में किया है जबकि एमटीएनएल ने अपने कर्मचारियों के वेतन/पेंशन तथा ब्याज सहित प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 11264 करोड़ रुपए का ऋण लिया है तथा इसने अक्तूबर, 2012 तक इस ऋण पर ब्याज के रूप में 2064 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है।

(ङ) दूरसंचार विभाग बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के कार्य-निष्पादन की समीक्षा आवधिक आधार पर करता है। बीएसएनएल तथा एमटीएनएल अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :-

बीएसएनएल

★ परियोजना विजय के माध्यम से मोबाइल की बिक्री तथा वितरण चैनल को सुदृढ़ बनाना।

★ चरण-VI में क्षमता में 15 मिलियन की वृद्धि करना।

★ जिला स्तर पर बीएसएनएल के फ्रेंचाइजियों/खुदरा विक्रेताओं तथा बिक्री दलों के साथ साप्ताहिक बैठक करना।

★ बिक्री दल के लिए लक्ष्य निर्धारित करना तथा सामग्री की डिलीवरी को सुनिश्चित करना।

★ खुदरा बिक्री प्रबंधक-वार लक्ष्य निर्धारित करना तथा इसकी निगरानी करना।

★ अपने नम्बर को बनाए रखते हुए पोर्टआउट करने को इच्छुक उपभोक्ताओं के साथ अत:संपर्क करने के लिए विशेष कैम्प आयोजित करने ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

★ गांवों में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए डाक विभाग के साथ करार करके ग्रामीण क्षेत्रों में नए बिक्री चैनलों को खोलना।

★ 3जी डाटा कार्डों वाले वायरलेस ब्रॉडबैंड तथा 3जी

डाटा प्लानों वाली सुविधा से युक्त स्मार्ट डिवाइसों को प्रभावी रूप से बढ़ावा देना।

★ समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मूल्य वृद्धित सेवाओं पर सतत रूप से ध्यान देना।

★ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित किए गए बैंचमार्कों को अपनाने के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों की निगरानी करना।

एमटीएनएल

★ एमटीएनएल विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अपने प्रशुल्क की समीक्षा कर रहा है ताकि इन्हें ग्राहकोनुकूल बनाया जा सके तथा ये समाज के विभिन्न वर्गों के अनुकूल बन सकें।

★ एमटीएनएल ने समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टेलीफोन बिलों के सरल भुगतान को सुकर बनाने के संबंध में अनेक उपाय किए हैं।

★ लायल्टी स्कीम और कार्पोरेटर उपभोक्ताओं का विशेष ध्यान रखना।

★ एमटीएनएल उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने के लिए काल सेंटर/हेल्प लाइन चला रहा है।

★ विभिन्न सेवाओं तथा लैंडलाइनों और मोबाइलों से संबंधित शिकायतों के लिए अब आनलाइन बुकिंग उपलब्ध है।

★ एमटीएनएल के दिल्ली में संचार हाट और मुंबई में ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) हैं जहां उपभोक्ता विभिन्न सेवा जैसे नई सेवा का पंजीकरण, सेल्यूलर कनेक्शन का डुप्लीकेट बिल, बिल संबंधी भुगतान, वीसीसी कार्ड आदि प्राप्त कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी 2012) में अन्य बातों के साथ-साथ बीएसएनएल की एमटीएनएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए निम्नलिखित भूमिका की परिकल्पना की गई है :-

★ भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित द्विपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामलों में सरकार के उपायों की क्षमताओं को प्रोत्साहन देने/बढ़ावा देने के संबंध में दूरसंचार पीएसयू के कार्यनीतिक महत्व को स्वीकार करना।

★ कार्यनीतिक और प्रचालनात्मक बेहतर आपसी सहयोग की पहचान और उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बढ़ावा देना ताकि वे सेवा प्रदान करने, अवसंरचना के सृजन और विनिर्माण में विशिष्ट भूमिका निभा सकें।

★ राष्ट्र की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त सहायता प्रदान करते हुए दूरसंचार विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक दूरसंचार बाजार में प्रभावी रूप से सफल बनाने की सुनिश्चितता के लिए उनके आपसी लाभ हेतु उनकी वैयक्तिक क्षमता का उपयोग करना।

[अनुवाद]

परेशान करने वाली कॉलों के संबंध में विनियम

2020. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में मोबाइल उपभोक्ताओं/अंशदाताओं को की गई अनचाही/परेशान करने वाली कॉलों/एस.एम.एस. की सरकार/भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'ट्राई' ने परेशान करने वाली कॉलों/एस.एम.एस. को रोकने हेतु विनियमों को सुदृढ़ करने के लिए आम जनता की राय लेने के लिए हाल ही एक परामर्श-पत्र जारी किया;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आईं और इस संबंध में 'ट्राई' द्वारा जारी किए गए विनियम क्या हैं;

(घ) आज की तारीख में देश में पंजीकृत टेलीमार्केटर्स का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई अनचाही/परेशान करने वाली कॉलें/एस.एम.एस. अब निजी/व्यक्तिगत नम्बरों से आ रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार/'ट्राई' द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 को जारी 'दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010' की मार्फत अनचाही/परेशान करने वाली कॉलों/एस.एम.एस. को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा विनियामक प्रणाली निर्धारित की गई है। उक्त विनियम के सभी प्रावधान दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से लागू किए गए हैं। ट्राई ने इस विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इन विनियमों ने अनेक संशोधन भी जारी किए हैं। गत तीन वर्षों में से प्रतयेक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में ट्राई/सरकार के नोटिस में आईं मोबाइल ग्राहकों/उपभोक्ताओं को मिलने वाली अनचाही/परेशान करने वाली कॉलों/एस.एम.एस. की शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	अनचाही/परेशान करने वाली कॉलों/ एस.एम.एस. से संबंधित प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
2009-10	515
2010-11	412
2011-12	465
मौजूदा वर्ष (27.11.2012 तक)	786

(ख) और (ग) जी, हां। ट्राई ने अनचाहे वाणिज्यिक संदेशों (यू.सी.सी.) को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु स्टेकधारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 3.08.2012 को 'दूरसंचार वाणिज्यक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 की समीक्षा' के बारे में परामर्शी दस्तावेज जारी किया है। अनचाही/परेशान करने वाली कॉलों/एस.एम.एस. को नियंत्रित करने के लिए स्टेकधारियों के साथ अपेक्षित उपायों पर चर्चा करने के लिए लिए ट्राई द्वारा दिनांक 10 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली एक ओपन हाउस परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस ओपन हाउस परिचर्चा के दौरान कुछ संभावित समाधानों के बारे में दिनांक 25 अक्तूबर, 2012 तक स्टेकधारियों के पुख्ता विचार मांगे गए। परामर्शी दस्तावेज पर निम्नलिखित से जवाब प्राप्त हुए:-

(i) तीन उद्योग संघ-भारतीय सेलुलर प्रचालक संघ (सी.ओ.ए.एल.), भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता संघ (ए.यू.एस.पी.आई.), भरतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ (आई.ए.एम.ए.आई.)

(ii) आठ सेवा प्रदाता-मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज, मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया, मैसर्स एयरसेल, मैसर्स लूप एवं मैसर्स बी.एस.एन.एल.,

(iii) बारह ग्राहक सलाहकार समूह-ग्राहक मार्गदर्शन सोसायटी (सी.जी.एस.आई.), ग्राहक संरक्षण संघ (सी.पी.ए.), श्रमिक वर्ग एवं निर्मल वर्ग विकास संस्थान, समर्पित, संरक्षण, हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, अखिल भारत ग्राहक चैम्बर, अमेन सोसायटी, ग्रामविकास परिषद, लोक नीति अनुसंधान केन्द्र (सी.पी.पी.आर.), भारतीय टेलीकॉम प्रयोक्ता समूह, ग्राहक शिक्षा के हित में स्वैच्छिक संगठन (वी.ओ.आई.सी.ई.)।

(iv) तीन व्यक्तियों-सुश्री राशि अरोड़ा, श्री एस.के. विरमानी, श्री सुरेन्द्र पी.ए. और नौ अन्य कंपनी।

ट्राई ने स्टेकधारकों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को 'दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (दसवां संशोधन) विनियम, 2012' जारी किए।

(घ) दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, देश में ट्राई के साथ 2830 टेलीमार्केटरों को पंजीकृत किया गया है।

(ङ) और (च) सरकार/ट्राई को अभिज्ञान है कि ऐसी प्राइवेट/व्यक्तिगत नम्बरों से अनेक कॉल एवं एस.एम.एस. भेजे जा

रहे हैं जोकि ट्राई के साथ टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकृत नहीं है। विनियम के अनुसार पहले उल्लंघन के बारे में नोटिस जारी किए जाने के बाद दूसरी बार शिकायत मिलने पर ऐसे 'अपंजीकृत टेलीमार्केटरों' के टेलीफोन कनेक्शनों को समाप्त करने का प्रावधान है। विनियमों के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, 1,48,095 उपभोक्तओं को नोटिस जारी किए गए हैं और 1,37,052 उपभोक्तओं के कनेक्शनों को समापत कर दिया गया है।

इस मुद्दे का समाधान करने और परेशान करने वाली कॉलों/एस.एम.एस. को नियंत्रित करने हेतु इस प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ट्राई द्वारा स्टेकधारियों के साथ पूर्ण परामर्श करने के बाद दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को 'दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (दसवाँ संशोधन) विनियम, 2012' को जारी करके सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। इस विनियम के तहत किए गए उपायों/विशेष कदमों का सार नीचे दिया गया है:-

(i) 100 एस.एम.एस. प्रति दिन से अधिक भेजे जाने वाले संदेशों पर 50 पैसे प्रति एस.एम.एस. की दर से न्यूनतम प्रभार लगाया गया है। सेवा प्रदाताओं को अधिदेश दिया गया है कि वे रियायती दरों पर प्रति दिन प्रति सिम 100 एस.एस.एस. से अधिक संदेश भेजने की अनुमति न दें। ग्राहक प्रति सिम 100 एस.एम.एस. प्रति दिन से अधिक संदेश भेज सकते हैं लेकिन ऐसे भी एस.एम.एस. पर न्यूनतम 50 पैसे प्रति संदेश की दर से प्रभार लगाया जाएगा।

(ii) ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभिगम प्रदाताओं को अधिदेश दिया गया है कि वे आवधिक तौर पर अपने ग्राहकों को एस.एम.एस. भेजकर सलाह दें कि यदि वे ट्राई के साथ टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकृत नहीं हैं तो वे कोई भी वाणिज्यिक संदेश नहीं भेजें तथा प्राइवेट/व्यक्तिगत नम्बरों का प्रयोग करके वाणिज्यिक संदेश भेजने से उनके टेलीफोन कनेक्शन काटे जा सकते हैं।

(iii) अभिगम प्रदाताओं को भी अधिदेश दिया गया है कि वे टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराते समय ग्राहकों से वचन लें कि खरीदे गए सिम को टेलीमार्केटिंग उद्देश्य से प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

(iv) अवांछित वाणिज्यिक एस.एम.एस. के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए ऐसे संदेशों को अग्रेषित करने के लिए बारे में सरल प्रावधान किए गए हैं कि जिस नम्बर (या एस.एम.एस. के हैडर) से ये संदेश प्राप्त हुए हैं, का संदर्भ देते हुए, ऐसे संदेशों और उनके प्राप्त होने के समय को 1909 पर अग्रेषित किया जाए।

[हिन्दी]

गांवों में वी.पी.टी. तथा ब्रॉडबैंड सुविधा

2021. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री लालजी टंडन :
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री मानिक टैगोर :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
कुमारी मौसम नूर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे गांवों की संख्या राज्य-वार कितनी है जहां आज की तारीख तक ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधा दी गई है तथा ऐसे गांवों की संख्या राज्य-वार कितनी है जहां यह सुविधा अभी उपलब्ध कराई जानी शेष है;

(ख) देश के सभी गांवों में वी.पी.टी. सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ग) अब तक कितनी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा कितनी पंचायतों को यह सुविधा दी जानी शेष है;

(घ) क्या सरकार ने ''भारत निर्माण'' योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड-कनेक्शन देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) देश में 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार ऐसे गांवों की संख्या अनुबंध में दी गई है जहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा दी गई है और जहां यह सुविधा अभी दी जानी है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा शेष व्यवहार्य गांवों में वीपीटी सुविधा मार्च, 2013 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) बीएसएनएल द्वारा 157371 पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है और 90493 पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा अभी प्रदान की जानी शेष है।

(घ) और (ङ) भारत निर्माण चरण-III के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ''ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ'' प्रदान किए जाने का प्रावधान है, तथापि सरकार ने कुल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 25 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन हेतु स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करने हुए प्रचायतों तक मौजूदा आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है। इस परियोजना को 2 वर्षों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। एनओएफएन स्कीम के प्रारंभिक चरण की प्रस्तावित लागत लगभग 20,000 करोड़ रु. है।

एनओएफएन परियोजना का क्रियान्वयन विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) अर्थात भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा किया जा रहा है, जो कि सरकार, बीएसएनएल, रेलटेल और पावरग्रिड की इक्विटी भागीदारी के साथ पूर्णत: केंद्र सरकार के स्वामित्व में भारतीय कंपनी अधनियम, 1956 के तहत गठित कंपनी है। इस उद्देश्य के लिए 25.02.2012 को कंपनी का गठन किया गया है।

विवरण

31.10.2012 की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गए वीपीटी की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	जनगणना 2001 के अनुसार आबाद राजस्व गांवों की सं.	प्रदान किए गए वीपीटी की सं.	वीपीटी जो अभी प्रदान किए जाने हैं
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	352	149
आंध्र प्रदेश	26613	25078	1535
असम	25124	24502	622
बिहार	39032	38932	100
झारखंड	29354	28807	547
गुजरात	18159	17137	1022
हरियाणा	6764	6678	86
हिमाचल प्रदेश	17495	17407	88

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	6417	6383	34
कर्नाटक	27481	27449	32
केरल	1372	1372	0
मध्य प्रदेश	52117	51986	131
छत्तीसगढ़	19744	18192	1552
महाराष्ट्र	41442	40642	799
मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	5782	5109	673
मिजोरम (पूर्वोत्तर-I)	707	704	3
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	858	858	0
अरूणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II)	3863	2763	1100
मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	2315	2170	145
नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	1278	1263	15
ओडिशा	47529	44904	2625
पंजाब	12301	12065	236
राजस्थान	39753	39410	343
तमिलनाडु (तमिलनाडु सर्किल)	13837	13837	0
चेन्नै मैट्रो	1655	1655	0
उत्तर प्रदेश	97942	97774	168
उत्तराखंड	15761	15366	395
पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल सर्किल)	37062	36474	588
कोलकाता मेट्रो	893	613	280
सिक्किम (पश्चिम बंगाल सर्किल)	450	429	21
कुल जोड़	5,93,601	5,80312	13,289

नागर विमानन उद्योग का पुनरुद्धार

2022. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :**
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री पी. सी. मोहन :
श्री पी. सी. गद्दीगौदर :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागर विमानन उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए कोई नए उपाय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार, विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों/विदेशी विमान कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में रुचि दिखाने वाली विदेशी विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) सरकार ने विमानन उद्योग के जीर्णोद्धार तथा इस क्षेत्र की दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

(1) नागर विमानन के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों पर चर्चा करने और इनके समाधान सुझाने के लिए सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में सचिव, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सचिव, वित्तीय सेवाएं, डीजीएफटी, वित्त सचिव तथा संयुक्त सचिव, नागर विमानन के एक कार्य समूह का गठन किया गया था।

इस कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) विमानन टर्बाइन ईंधन पर वैट के युक्तिकरण का मुद्दा राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया है।

(ii) विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एयरलाइनों को वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर एयरलाइनों द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रत्यक्ष आयात की अनुमति प्रदान की है।

(iii) मंत्रालय ने विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्य निर्धारण तथा वित्तीय ढांचे का अध्ययन विशेषज्ञों से करवाया है। इसकी रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।

(iv) विदेशी एयरलाइनों को घरेलू वाहकों की इक्विटी में 49% तक निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।

(2) एयरलाइनों को अपनी कार्य पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बिलियन अमरीकी डॉलर तक ईसीबी की अनुमति प्रदान की गई है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध

2023. **श्री आर. ध्रुवनारायण :**
डॉ. रत्ना डे :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों, नामतः पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए इनके साथ विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप क्या लाभ हुआ अथवा होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) इस प्रश्न से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजनयिकों की कमी

2024. **श्री महाबली सिंह :**
श्री अशोक तंवर :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में राजनयिक स्तर के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2018 तक भारतीय विदेश सेवा विस्तार योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस सिलसिले में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विदेश सेवा में सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ प्रतिभाएं आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) इस समय विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में 25 राजनयिकों के पद रिक्त हैं। इनमें से 21 पदों के लिए अधिकारियों का चयन किया जा चुका है तथा उनके कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। शेष रिक्तियों के लिए उचित अधिकारियों के चयन के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत विदेश सेवा विस्तार योजना के अंतर्गत इन पदों के 5 चरणों को, निर्धारित समय सीमा के भीतर पहले से ही पूरा कर लिया गया है।

(घ) भारतीय विदेश सेवा के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है तथा यह सेवा विविध क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने में समर्थ है। विदेश मंत्रालय का लोक राजनय प्रभाग विद्यार्थी समुदाय सहित विभिन्न समुदायों में विदेश नीति मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता तथा गहन रूचि का प्रसार करने के लिए अभिकल्पित हर प्रकार के संकेंद्रित कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों का आयोजन करता है तथा उसमें भाग लेता है।

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत परियोजनाएं

2025. **श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री प्रेमदास :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री धनंजय सिंह :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री बलीराम जाधव :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री हरिन पाठक :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री कादिर राणा :
श्री भरत राम मेघवाल :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

श्री देवजी एम. पटेल :
श्री ए.के.एम. विजयन :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न शहरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का राज्य-वार व शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों और संस्वीकृत/जारी धनराशि का शहर-वार, राज्य-वार, वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के कुछ प्रस्ताव अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) अगले दो वर्षों के दौरान सरकार का शहर-वार, राज्य-वार और परियोजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी करने का विचार है;

(च) क्या सरकार इन परियोजनाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा करती है/समीक्षा करने का उसका प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं समय पर यथोचित रूप से प्रगति कर रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) देश के विभिन्न शहरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) उप-मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्य और शहर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उप-मिशन के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान परियोजनाओं और स्वीकृत/जारी धनराशियों का शहर, राज्य और परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) के अंतर्गत मूल्यांकित लेकिन स्वीकृत नहीं की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन यू.आई.जी. के अंतर्गत परियोजनाओं पर अनुमोदनार्थ विचार उनके यू.आई.जी. के दिशानिर्देशों के अनुरूप होने, तकनीकी मूल्यांकन/पालन और राज्यों के लिए धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है।

(ग) और (घ) मिशन ने 31 मार्च, 2012 को 7 साल का अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है और सरकार ने केवल निर्माणधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए यानी 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाई है। इसके तहत नई परियोजनाओं पर विचार और स्वीकृति संबंधी कोई अधिदेश नहीं है।

(ङ) राज्य/संघ क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर समझौता ज्ञापन में यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति और उपयोगिता प्रामण-पत्र प्राप्त होने के अध्यधीन जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 70% तक (केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) अनुदान जारी किया जाता है।

(च) राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं का निष्पादन और निगरानी की जाती है। परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन स्वतन्त्र समीक्षा एवं निगरानी एजेन्सी (आई.आर.एम.ए.), राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.) और राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के जरिये किया जाता है। अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भारत सरकार द्वारा राज्यों द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के ज़रिये भी की जाती है।

(छ) और (ज) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और

पेरा स्टेटल के जरिए किया जाता है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू. आई.जी. उप-मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कुल परियोजनाओं में से 163 परियोजनाओं के वास्तविक रूप से पूरा होने की सूचना दी गई है और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महसूस की गई कठिनाइयां सह-सुविधाओं के स्थानंतरण, विभिन्न प्राधिकारियों (रेलवे, वन आदि) से अनुमति मिलने में देरी, क्षमता की कमी, भूमि अधिग्रहण, संविदा संबंधी मुद्दें आदि और सुधारों का स्वरूप जटिल और कठिन होना और इन्हें पूर्ण करने की स्थानीय निकायों में क्षमता न होना है।

मिशन निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता निर्माण उपाय यथा शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल के पदाधिकारियों का तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.टी.पी.) आयोजित करना, राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर परियोजना इकाइयां राज्य स्तर पर स्वतन्त्र समीक्षा एवं निगरानी समिति (आई.आर.एम.ए.) की सहायता करना, आदि किए गए हैं।

विवरण-I

यू.आई.जी. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य और शहर वार ब्यौरा

राशि लाख रूपए में

(31.10.2012 की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिशन शहर का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध ए.सी.ए.	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	22	257,213.51	88,026.13	59,782.39
		तिरूपति	3	8,498.00	6,798.20	3,996.70
		विजयवाड़ा	13	77,809.02	38,904.51	32,057.87
		विशाखापट्टनम	14	155,310.48	77,655.24	64,844.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	3	18,048.20	16,243.38	12,565.15
3.	असम	गुवाहाटी	2	31,610.71	28,449.64	24,813.27
4.	बिहार	बोधगया	2	12,950.06	10360.04	2,590.01
		पटना	6	58,231.35	29,115.69	7,268.93
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	3	19,119.60	15,297.68	2,684.64
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1	30,364.00	24,291.20	21,862.08
7.	दिल्ली	दिल्ली	23	689,456.00	241,308.90	88,746.09
8.	गोवा	पणजी	2	7,484.08	5,987.26	1,496.82
9.	गुजरात	अहमदाबाद	26	239,038.01	83,663.64	65,328.62

1	2	3	4	5	6	7
		पोरबन्दर	2	13,811.69	11,049.36	2,762.34
		राजकोट	6	49,646.86	24,225.87	16,800.64
		सूरत	25	181,828.77	90,920.54	74,812.17
		वडोदरा	13	76,144.73	37,647.74	29,317.16
10.	हरियाणा	फरीदाबाद	4	69,909.02	34,954.51	25,290.42
11.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	5	16,373.68	12,599.75	3,472.84
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	2	14,955.03	13,459.53	5,109.49
		श्रीनगर	3	40,229.00	35,316.10	22,955.47
13.	झारखंड	धनबाद	2	42,170.90	21,085.60	8,015.28
		जमशेदपुर	1	3,336.24	1,668.12	417.03
		रांची	2	33,978.58	27,182.86	10,256.42
14.	कर्नाटक	बंगलौर	38	258,411.07	79,750.80	54,930.38
		मैसूर	9	110,802.73	65,594.95	44,582.57
15.	केरल	कोचिन	6	50,922.00	25,461.00	12,105.59
		थिरूवनंतपुरम	5	48,867.00	39,093.60	10,925.44
16.	मध्य प्रदेश	भोपाल	7	104,042.11	51,552.90	36,014.36
		इन्दौर	10	81,264.01	40,632.01	29,222.02
		जबलपुर	4	48,937.00	24,468.50	9,962.91
		उज्जैन	2	11,425.44	9,140.35	4,424.74
17.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	26	537,636.73	188,173.55	154,103.79
		नागपुर	17	149,970.01	74,985.02	38,168.10
		नानदेड	11	71,983.53	57,586.83	52,236.65
		नासिक	6	79,346.56	39,673.28	28,335.64
		पुणे	20	319,277.90	155,378.75	141,119.86
18.	मणिपुर	इम्फाल	3	15,395.66	13,856.10	5,542.45
19.	मेघालय	शिलॉग	2	21,795.72	19,616.15	12,750.50

1	2	3	4	5	6	7
20.	मिजोरम	आईजोल	4	12,772.16	11,494.94	3,857.62
21.	नागालैंड	कोहिमा	3	11,594.13	10,434.72	4,061.42
22.	ओडिशा	भुवनेश्वर	3	57,325.66	45,860.53	18,584.73
		पुरी	2	23,872.00	17,852.00	4,463.00
23.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	2	25,306.00	20,244.80	7,502.20
24.	पंजाब	अमृतसर	5	48,400.00	24,200.00	11,655.51
		लुधियाना	1	24,139.00	12,069.50	4,827.80
25.	राजस्थान	अजमेर-पुश्कर	4	50,564.80	40,450.84	24,942.93
		जयपुर	9	72,208.31	36,104.16	18,318.81
26.	सिक्किम	गंगटोक	2	9,653.67	8,688.30	6,185.58
27.	तमिलनाडु	चेन्नई	35	358,543.57	129,440.63	86,790.88
		कोयम्बटूर	5	87,295.54	41,310.27	26,494.40
		मदुरै	8	84,289.17	41,925.59	32,674.70
28.	त्रिपुरा	अगरतला	2	18,047.00	16,043.40	6,417.36
29.	उत्तर प्रदेश	आगरा	4	33,108.49	15,758.25	14,290.52
		इलाहाबाद	4	61,751.71	30,875.85	24,008.48
		कानपुर	6	120,422.27	59,843.13	47,594.12
		लखनऊ	7	161,612.97	80,807.44	67,413.13
		मथुरा	3	15,747.37	12,269.28	7,048.24
		मेरठ	3	48,149.40	23,779.70	16,619.66
		वाराणसी	6	95,569.73	46,326.87	29,250.22
30.	उत्तराखंड	देहरादून	5	23,968.61	18,776.56	13,113.00
		हरिद्वार	5	11,667.34	9,334.31	6,180.92
		नैनीताल	4	4,620.27	3,698.22	1,726.79
31.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	11	72,949.71	36,474.85	16,881.52
		कोलकाता	58	612,752.65	214,463.49	107,016.97
		कुल	552	6,203,926.52	2,869,702.90	1,829,591.75

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत/जारी धनराशि का ब्यौरा

(लाख रूपए में)

क्र.सं	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजनाओं का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध ए.सी.ए.	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	तिरूपति	तिरूमाला बाईपास सड़क के पूर्वी ओर तिरूपति के लिए भूमिगत जल निकास स्कीम	1613.00	1290.00	323.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	तिरूपति	जी.एच.एम.सी. का व्यापक जलापूर्ति वितरण नेटवर्क तथा राजेन्द्र नगर म्युनिसिपल सर्कल के प्राथमिकता जोन की पहचान करने के लिए सीवरेज सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	31426.00	9000.00	2500.00
3.	आन्ध्र प्रदेश	तिरूपति	तिरूपति नगर निगम के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	4556.00	3645.00	911.00
4.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	जलापूर्ति फेज-5 चंडीगढ़ को बढ़ाना	13421.00	10738.80	0.00
5.	दिल्ली	नई दिल्ली	सीविक सेन्टर, जे.एल.एन. मार्ग, मिन्टों, नई दिल्ली के पास के क्षेत्रों के लिए यातायात प्रबंधन परियोजना	9716.00	3400.60	0.00
6.	दिल्ली	नई दिल्ली	रोड़ न. 56 आई.एस.बी.टी. आनन्द विहार दिल्ली पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	9600.00	3360.00	840.00

1	2	3	4	5	6	7
7.	दिल्ली	नई दिल्ली	नोएडा मोड़ फ्लाईओवर अर्थात सिलिप रोड, ब्रिज, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, और अंडरपास पर तीन अतिरिक्त क्लोवर लीवस का निर्माण	8818.00	3087.00	771.58
8.	दिल्ली	नई दिल्ली	नन्द नगरी के समीप सड़क सं. 68 पर रेलवे लेवर क्रासिंग पर आर.यू.वी. और आर.ओ.वी.	10286.00	3600.00	900.03
9.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में बहुस्तरीय अपरम्परागत पार्किंग का विकास (ए.एल. ब्लाक, शालीमार बाग, शिव मार्किट पीतमपुरा, न्यूयू पीतमपुरा, सेन्ट्रल मार्किट अशोक विहार, मोहम्दपुर गॉव, मालवीय नगर मार्किट, पी.वी.आर. बसंत लोक, पी.वी.आर. साकेत, जी-8 राजोरी गार्डन, ब्लाक-10 सुभाष नगर, सी-4 जनकपुरी, अजमलखॉन पार्क, करोल बाग, कृष्णा मार्किट कालकाजी, हौजरानी, न्यूफ्रैण्ड कालोनी, जंगपुरा, भोगल	46980.00	16443.00	4110.75
10.	दिल्ली	नई दिल्ली	ओखला ओद्योगिक क्षेत्र फेज-I, और -II सेन्ट्रल जोन की सड़क का सुधार और सुदृढ़ीकरण	14861.00	5201.00	1300.34
11.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए अफ्रीका एवेन्यू से रिंग रोड़ तक नारोजी नगर में नल्ला को ढकना	5120.00	1792.00	448.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए पुलिस स्टेशन डिफैन्स कालोनी के पीछे एनड्यूज गंज से रिंग रोड तक शेख सराय, चिराग दिल्ली पंचशील एनक्लेव, ग्रेटर कैलाश-I से होकर गुजरने वाली प्रैम इनक्लेव सड़क से नाल्लो को ढकना	23300.00	8155.00	2038.75
13.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के विभिन्न जोनों में आर.एम.सी. पेवमेन्ट (फेज-I) मुहैया कराकर 60 फुट आर.ओ.डब्ल्यू. और इससे ऊपर की सड़क का सुधार	16510.00	5779.00	1444.63
14.	दिल्ली	नई दिल्ली	शाहदरा (उत्तरी) जोन में एस.एस.बी.एल. (सहारनपुर-शामली ब्रांच लाइन) निकास का पुनर्रूपेण	15226.00	5329.00	1332.28
15.	दिल्ली	नई दिल्ली	ट्रंक सीवर का पुनर्स्थापन	25337.00	8868.00	0.00
16.	दिल्ली	नई दिल्ली	अफ्रीका एवेन्यू और अरुण आसिफ अली रोड पर फ्लाईओवर	12661.00	4431.00	0.00
17.	दिल्ली	नई दिल्ली	विवेकानन्द मार्ग, नेशनल मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग पर फ्लाईओवर	12661.00	4431.00	0.00
18.	दिल्ली	नई दिल्ली	मार्जिनल बन्द रोड, गीता कालोनी, दिल्ली पर राजाराम कोहली मार्ग इंटरसेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	250.00	87.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7
19.	दिल्ली	नई दिल्ली	ईस्ट दिल्ली में शास्त्री नगर के समीप दीसूसर्द कैनाल पर मार्जिनल बन्द रोड और मास्टर प्लान रोड के टी जक्शन पर यातायात के निर्बाद संचालन के लिए ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	250.00	87.50	0.00
20.	दिल्ली	नई दिल्ली	अप्सरा बॉर्डर के समीप जी.टी. रोड और सड़क सं. 56 के जक्शन ग्रड सेपरेटर का निमार्ण	14147.00	4951.00	0.00
21.	दिल्ली	नई दिल्ली	वजीराबाद दिल्ली के मौजूदा ब्रिज के यमुना नदी अनुप्रवाह पर ब्रिज और इसकी एप्रोच सड़कों का निर्माण	108740.00	38059.00	0ए00
22.	दिल्ली	नई दिल्ली	बारापुला नाला पर एलाइमेंट	97000.00	33950.00	0.00
23.	दिल्ली	नई दिल्ली	राजघाट पावर स्टेशन पैकेज-II के पीछे से शालीमगढ़ फोर्ट तक शालीमगढ़ फोर्ट से वैलेड्रम रोड पैकेज-I तक रिंग रोड बाई पास	46900.00	16415.00	0.00
24.	दिल्ली	नई दिल्ली	एन.एच.-24 क्रोसिंग (नोएडा मोड) से चिल्ला रेगुलेटर तक उत्तर प्रदेश रिंग रोड़ का कॉरीडोर सुधार	25400.00	8890.00	0.00
25.	गुजरात	राजकोटा	राजकोट शहर के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-2 भाग-2	19195.12	9000.00	2250.00
26.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में भद्रकिला का पुनर्द्वार	7439.00	2603.65	650.91

1	2	3	4	5	6	7
27.	गुजरात	वडोदरा	बडोदरा शहर में कान्स का पुनर्वास विकसित करने के लिए बुनियादी सेवाएं (क) बरसाती पानी निकासी क्षेत्र (ख) जलआपूर्ति क्षेत्र	16789.88	8394.94	2098.73
28.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर के अजवा क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु अनुपूरक डी.पी.आर.	2059.26	605.50	151.37
29.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला, फेज-I के विभिन्न जोनों में छूटी हुई/ध्वस्त सीवरेज तथा मिशिंग लाइन में सीवरेज नेटवर्क का पुनरूद्धार	5474.00	3880.00	970.00
30.	कर्णाटक	मैसूर	बोमाना हली सिटी नगर पालिका परिषद में भूमिगत निकास सुविधा कराना तथा सड़क सुधार	2270.00	1176.00	294.00
31.	कर्णाटक	मैसूर	मैसूर हेतु बेहतर परिवहन प्रणाली एवं नवीन पर्यावरण परियोजना	3945.00	3156.00	789.00
32.	केरल	कोचिन	ब्राडवे एवं इरनाकुलम मार्किट हेरीटेज एवं शहरी नवीकरण परियोजना	2210.00	1105.00	276.25
33.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	महाकाल एवं गोपाल विरासत क्षेत्र का सुरक्षित संरक्षण एवं विकास	4739.00	3791.20	947.80
34.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बरसाती पानी निकास (ओमती नाला सहित) का डी.पी.आर.	32649.00	16324.50	4081.12
35.	महाराष्ट्र	नासिक	भूमिगत सीवरेज परियोजना पैकेज-II	17182.92	8591.46	2147.87

1	2	3	4	5	6	7
36.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	ग्रेटर मुम्बई के नवी मुम्मई यू.ए. में ठोस कचरा प्रबन्धन	4986.86	1745ए40	436.35
37.	मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल शहर के लिए वर्षा जल निकासी कार्यक्रम	10250.13	9225.12	2306.28
38.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा में एकीकृत सड़क और बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना	5042.43	4538.19	1134.55
39.	ओडिशा	पुरी	पुरी कस्बे के लिए ठोस बरसाती पानी व्यवस्था	7182.00	4500.00	1125.00
40.	पंजाब	अमृतसर	बाल्ड सिटी क्षेत्र, अमृतसर के लिए मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली का पुनर्स्थापन	4578.00	2289.00	572.25
41.	सिक्किम	गंगटोक	वृहत गंगटोक के लिए कच्चे पानी की मुख्य लाइनों और जल शोधन संयंत्र का उन्नयन और आधुनिकीकरण	7261.66	6535.49	1663.87
42.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	शहरी नगर निगम (फेज-I) वर्षा जल निकासी व्यवस्था	22675.00	9000.00	2250.00
43.	त्रिपुरा	अगरतला	सीवरेज और जोन (प्राथमिकता 1 क्षेत्र) के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन स्कीम	10221.00	9000.00	2250.00
44.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा सीवरेज स्कीम पार्ट-I	19592.00	9000.00	2250.00
45.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ शहर के सीवरेज जोन-5 और 7 में सीवरेज कार्य	18589.00	9000.00	2250.00

1	2	3	4	5	6	7
46.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर के वरुण क्षेत्र पार हेतु जलापूर्ति घटक (प्राथमिकता-2)	20916.00	9000.00	2250.00
47.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	मथुरा में एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन	6035.77	4500.00	1125.00
48.	उत्तराखंड	देहरादून	एल जोन के लिए देहरादून सीवरेज स्कीम (फेज-I)	6283.00	4628.00	1157.00
49.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	दुर्गापुर में रघुनाथपुर से धुपचुरिया और अकंदारा से फली ओर तक सड़क का निर्माण, चौडा करना और सुधार	9492.26	4746.13	1186.53
50.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	रानीगंज नगरपालिका के लिए सीवरेज परियोजना	4008.82	2004.41	501.10
51.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	30 एम.जी.डी. धापा जल शोधन संयत्र के कमांड जोन में व्यापक वितरण नेटवर्क	21555.27	7544.34	1886.06
52.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	भटपाडा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम	24970.42	8739.65	2184.91
53.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डलहोजी स्केवयर का पुनरूद्धार	2062.00	721.70	180.43
54.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बीधन नगर कोलकाता में निकास और सीवरेज परियोजना	2358.45	825.46	206.37
55.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में बज नगर पालिका क्षेत्र में वर्षा जल निकास स्कीम	3480.16	1218.05	304.51
56.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दुर्गापुर के लिए 24X7 जलापूर्ति (फेज-3)	12681.40	6340.70	1585.18
57.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कुल्टी नगर पालिका, आसनसोल यू.ए. के लिए 24X7 जलापूर्ति स्कीम	13370.60	6685.30	1671.33

1	2	3	4	5	6	7
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चंदानाघर नगरनिगम के लिए जलापूर्ति प्रणाली की मिटरिंग	1369.41	479.29	119.82
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बेली नगर पालिका कोलकाता के लिए सतही जल आपूर्ति स्कीम	13849.36	4847.28	0.00
60.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	विधाना नगर निगम क्षेत्र के लिए बरसाती जल नालियां	1915.53	670.44	167.61
		कुल		923458.71	387402.60	62341.56
		वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत/जारी धनराशि का ब्यौरा				
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए तीन मुख्य नालों नामत: नजफगढ़, सपलीमेट्री एवं शहादरा के साथ इंटरसेक्टार सीवर बिछाना।	135771.00	47520.00	11880.00
2.	गुजरात	पोरबन्दर	पोरबंदर में जलापूर्ति का संवर्धन	2631.04	2104.84	526.21
3.	झारखंड	जमशेदपुर	जमशेदपुर शहरी समूह के एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन प्रयोजना	3336.24	1668.12	417.03
4.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इंदौर बी.आर.टी.एस. फेज-I का रीवर साईड कोरिडोर 14.30 km	18000.00	9000.00	0.00
5.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में कोयम्बडू फेज-2 में अतिरिक्त 120 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयत्र का निर्माण और उसे चालू करना	11610.00	4063.50	0.00
6.	उत्तराखंड	नैनीताल	नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	931.00	744.80	186.20

1	2	3	4	5	6	7
7.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन सी-2 में सीवरेज प्रणाली	2698.00	2158.40	0.00
8.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन सी-2 में सीवरेज प्रणाली	748.33	598.66	0.00
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कमरहाटी नगर पालिका कोलकाता के लिए बरसाती पानी निकासी स्कीम	6733.87	2356.85	591.24
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मेट्रो पोलीटन क्षेत्र में उल्टादंगा से गोरिया तक बी.आर.टी.एस.-15.50कि.मी.	25291.00	8851.85	2212.96
11.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पनीहटी नगरपालिका कोलकाता के लिए 24X7 जलापूर्ति स्कीम	24602.30	8610.81	2152.70
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एप्रोच रोड चंदाना घर के साथ-साथ ईस्टन रेलवे मुख्य लाइन पर फ्लाई ओवर का निर्माण	3257.00	1139.95	284.95
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	के.एम.ए. में बराकपुर कल्याणी-दमदम एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना	31457.00	11009.95	2752.49
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	काजी नरुल इस्लाम एवेन्यू पर कैस्ट्रोपूट से जोर मंदिर तक भूमोपरि कोरिडोर	20658.85	7230.60	1807.65
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में अपर बगजोला नगर का सुधार	5131.12	1795.89	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में बड़ा नगर पालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास	3587.39	1255.59	0.00
		कुल		296444.14	110109.81	22811.47

1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत/जारी धनराशि का ब्यौरा			
1.	आन्ध्र प्रदेश	तिरूपति	तिरूपति नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन	2329.00	1863.20	0.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम (जी.वी. एम.सी.) के सेंट्रल क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी सेक्टरों के बचे हुए क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति का कार्यान्वयन	8349.00	4174.50	0.00
3.	गुजरात	पोरबन्दर	पोरबन्दर मिशन शहर के लिए भूमिगम जल निकास (सीवरेज) परियोजना	11180.65	8944.52	0.00
4.	गोवा	पणजी	पणजी शहर के लिए विरासत का संरक्षण	362.25	289.80	72.45
5.	गोवा	पणजी	गोवा में पणजी शहर के नगर निगम अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पणजी शहर और आस-पास के क्षेत्र हेतु जल आपूर्ति	7121.83	5697.46	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	गांव भरियाल, तहसील जिला शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनिट्री ढलाव स्थल	1050.62	840.50	0.00
7.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू शहर के डिविजन क के बाकी बचे फेज-II के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	2032.03	1828.83	0.00
8.	कर्नाटक	मैसूर	चामराजेन्द्र जियोलॉजिकल गार्डन में सतही और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल प्रबंधन	330.00	264.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के लिए सीवरेज प्रणाली	10941.57	3829.55	0.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	मिजोरम	आईजोल	शहरी सड़क फेज-I में सुधार और चौड़ा करना	3873.40	3486.06	0.00
11.	मिजोरम	आईजोल	वैवाकौन से मिजोरम विश्वविद्यालय तक चौड़ा और सुधार करना	1907.64	1716.88	0.00
12.	मिजोरम	आईजोल	आइजोल सिटी रिंग रोड से निकले छोटे मार्ग रूप में सिहमुई से मिजोरम विश्वविद्यालय	5309.32	4778.38	0.00
13.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा शहर फेज-I के लिए वर्षा जल निकास विकास स्कीम	4026.10	3623.49	905.87
14.	उत्तराखंड	नैनीताल	राजभवन का पुनरूद्धार और संरक्षण	1182.27	945.82	236.45
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में उलबेरिया नगर पालिका के लिए जल आपूर्ति परियोजना (फेज-II)	12478.23	4367.38	1091.85
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता महानगर के भीतर भटपारा नगरपालिका के वार्ड सं. 5,6,7,8 में घोष पारा रोड, कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए.पी. बैनर्जी रोड पर रेल ओवर ब्रिज-9 (आर.ओ.बी.)	1293.00	452.55	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कल्याण रेलवे स्टेशन के पास बस टर्मिनल	650.69	227.74	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आदी गंगा कोलकाता के शुरू में ई.एम. बाईपास कनेक्टर पर कमलगाजी इंटरसैक्शन पर चार लेन का फ्लाई ओवर	10016.62	3505.81	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दुर्गापुर में माया बाजार से होकर गम्मन ब्रिज से गांधी मोड़ (एन.एच.-2) तक रोड़ का सुधार, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	7781.79	3890.89	0.00

1	2	3	4	5	6	7
20.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम, न्यू बैरकपुर और बरसात के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	44547.77	15591.72	0.00
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	टी.आई.टी. गढ़ और खरदन, के नगर आपूर्ति निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल परियोजना	19484.00	6819.40	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल में जुबली ढाबा से एस.सी.-ओ.बी. गेट तक सड़क का सुधार और 4 लेन तक चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण।	4316.61	2158.30	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बज ट्रंक रोड पर जिनजीरा बाजार और बाटानगर के बीच भूमोपरि रोड़ का निर्माण	25573.00	8950.55	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नबादीगंटा औद्योगिक टाऊनशिप क्षेत्र (एन. डी.आई.टी.ए.) के बाहरी क्षेत्र में कार्यालय बिल्डंग/कैफिटेरिया सहित बस टर्मिनस का निर्माण	624.34	218.52	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोदेपुर से एम.बी. रोड तक बैरकपुर कल्याणी दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना (फेज-II)	4433.49	1551.72	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम नगर पालिका, कोलकाता के लिए वर्षा जल निकास प्रणाली	7204.37	2521.53	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरसातनगर पालिका, कोलकाता के लिए एकीकृत वर्षा जल निकास प्रणाली	8548.33	2991.92	0.00
			कुल	206947.92	95531.02	2306.62

वर्ष 2012-13 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत/जारी धनराशि का ब्यौरा

मिशन ने 31 मार्च, 2012 को अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है और सरकार ने केवल निर्माणधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए यानी 31 मार्च 2014 तक बढ़ाई है। इसके तहत नई परियोजनाओं पर विचार और स्वीकृति संबंधी कोई अधिदेश नहीं है।

विवरण-III

क्र .सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (लाख रूपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम में जलापूर्ति प्रणाली का विस्तार तथा औद्योगिक उपयोग के लिए खराब जल का पुन:चक्रण और पुन:उपयोग (पैकेज-I)	21289.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	साइकिल लेन, फुटपाथ और सार्वजनिक बाईसिकल स्कीम का कार्यान्वयन	1000.00
3.	गुजरात	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत ईस्ट जल निकास जोन के तहत करंज सीवेज शोधन संयंत्र का विस्तार	4158.60
4.	गुजरात	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत नार्थ जल निकास जोन के तहत सिंगापौर सीवेज शोधन संयंत्र का विस्तार	5922.31
5.	गुजरात	सूरत नगर निगम, सूरत के ईस्ट जोन के लिए जल आपूर्ति प्रणाली	5590.51
6.	गुजरात	अहमदाबाद शहर की सीवरेज प्रणाली के आटोमेशन (एस.सी.ए.डी.ए. आधारित) के लिए डी.पी.आर.	2367.35
7.	गुजरात	अहमदाबाद शहर की सीवरेज प्रणाली के आटोमेशन (एस.सी.ए.डी.ए. आधारित) के लिए डी.पी.आर.	3439.14
8.	गुजरात	बंगलौर, कर्णाटक में कित्तूर रानी चेन्नमा सर्किल में ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	3200.00
9.	झारखंड	जमशेदपुर शहर के लिए सीवरेज परियोजना	14698.8
10.	झारखंड	धनबाद की सीवरेज स्कीम	28081.7
11.	महाराष्ट्र	नागपुर के लिए नार्थ सीवरेज जोन परियोजना	27052.00
12.	नागालैंड	एन.एच.-61 से नार्थ पिफल्ड स्कूल तक सड़क के साथ रिटेनिंग वाल का निर्माण	147.26
13.	पश्चिम बंगाल	महेशताला नगर निगम क्षेत्र के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम (फेज-II)	33122.1
14.	पश्चिम बंगाल	रिशरा नगर पालिका के लिए वर्षा जल निकास स्कीम	6304.5
15.	पश्चिम बंगाल	बरूईपुर की जल निकास स्कीम	6086
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के लिए वर्षा जल निकास स्कीम	3364.51
17.	पश्चिम बंगाल	एकीकृत वर्षा जल निकास प्रणाली राजाहट गोपालपुर नगर पालिका	9476.1

[हिन्दी]

असुरक्षित रन-वे

2026. **श्री जगदीश शर्मा :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री ओ. एस. मणियन :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विमानपत्तनों पर कई रन-वे/विमानधावन-पट्टियां आसानी से विमान उतरने और उड़ान भरने की दृष्टि से या तो असुरक्षित हैं या छोटी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार विमान पट्टी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में विभिन्न विमानपत्तनों के रन-वे को सुधारने/आधुनिक बनाने/विस्तारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) मरम्मत/पुनरुद्धार कार्य कब तक शुरू/पूर्ण किए जाने की संभावना है तथा इस पर विमानपत्तन-वार तथा विमानपट्टी-वार कितना व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): (क) कोई भी प्रचालनिक एयरोड्रम असुरक्षित नहीं है। एयरड्रोम पर उपलब्ध सेवाओं से संबंधित सूचना को एयरलाइन प्रचालकों द्वारा उपयोग के लिए वैमानिक सूचना प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। इनमें लागू मानक स्तरों का अनुपालन न किए जाने संबंधी सूचना शामिल है। प्रचालनात्मक मिटीगेशन उपायों समेत विमान की किस्म के लिए सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के पश्चात विमान प्रचालकों द्वारा विमान का प्रचालन किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर रनवे की लंबाई घोषित है जहां पर अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन सुरक्षित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डीजीसीए (विनियामक) तथा एएआई के विमानन संरक्षा निदेशालय द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) रनवे का विस्तार और आधुनिकीकरण, बड़े आकार वाले विमान के प्रचालन हेतु एयरलाइनों द्वारा अनुमानित अपेक्षाओं और राज्य सरकार द्वारा एएआई को भूमि उपलब्ध कराए जाने/हस्तांतरित किए जाने के अध्यधीन किया जाता है। राजस्थान में जयपुर हवाईअड्डे पर बड़े आकार वाले विमान के प्रचालन हेतु 76.47 करोड़ रूपये की लागत से रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और मार्च, 2015 तक कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र में गोंदिया हवाई अड्डे पर रनवे और समानांतर टैक्सी ट्रैक के विस्तार का कार्य 34.49 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है और जून, 2013 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि

2027. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री रतन सिंह :
श्री पी. लिंगम :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में टेलीकॉम आपरेटरों से एकत्र एवं उन्हें वितरित धनराशि वर्ष-वार व कंपनी-वार कितनी है तथा प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा इस अवधि में वर्ष-वार तथा कंपनी-वार क्या-क्या कार्य किए गए;

(ख) क्या कुछ टेलीकॉम कंपनियां यू.एस.ओ.एफ. के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के बावजूद अपने नियत दायित्व पूरे नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान चूककर्ता ऑपरेटरों के विरूद्ध सरकार द्वारा आपरेटर-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) विगत तीन वर्षों तथ चालू वर्ष के दौरान, आज तक, यू.एस.ओ.एफ. के अंतर्गत न की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य द्वारा शेष धनराशि किस प्रकार उपयोग में लाई जा रही है;

(ङ) क्या झारखंड सहित कुछ राज्यों ने शेष/खर्च न की गई यू.एस.ओ.एफ. राशि की उपयोग की स्वीकृति मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) की स्थापना ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जनता को वहनीय तथा उपयुक्त दरों पर विभिन्न दूरसंचार सेवाओं (बुनियादी, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) अवसंरचना आदि की उपलब्धता प्रदान करने के मूलभूत उद्देश्य के साथ की गई थी।

सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एकत्रित की गई और दूरसंचार प्रचालकों को संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान यूएसओएफ द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, कंपनियों द्वारा यूएसओएफ स्कीमों के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है। ऐसे विलंब के लिए इन कंपनियों पर संबंधित कंपनी के साथ हस्ताक्षरित करार (करारों) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नवम्बर, 2010 से फरवरी, 2011 के दौरान मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि. और मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लि. द्वारा यू.एस.ओ.एफ. द्वारा वित्तपोषित अवस्थलों क्रमशः 1191 और 228 पर अपने मोबाइल बेस ट्रांससीवर स्टेशनों (बीटीएस) को स्विच ऑफ कर देने के कारण संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं में निलंबन/व्यवधान हुआ।

इन कंपनियों द्वारा अपनी सेवाएं बदं कर देने के कारण मोबाइल सेवाओं में व्यवधान की अवधि के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि. पर 4,63,22,000 रूपए तथा मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लि. पर 1,07,67,500 रूपए का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है और वसूल किया गया है। ऐसा, यू.एस.ओ.एफ. द्वारा इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित किए गए करार के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

यूएसओएफ स्कीमों के "रॉल आऊट" में विलंब के लिए यूएसओएफ द्वारा लगाए गए औरव सूल किए गए वित्तीय जुर्माने (परिशोधित नुकसानी) का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) (i) यूएसओएफ के अंतर्गत एकत्रित निधियों का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन इन निधियों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। विभिन्न दूरसंचार कंपनियों से यूएसओएफ के अंतर्गत एकत्रित की गई निधियों का उपयोग केंद्रीय सरकार द्वारा देश के ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में किया जा रहा है।

(ii) दिनांक 31.10.2012 तक यूएसओएफ के तहत कुल 47,035.33 करोड़ रुपए की निधियां एकत्र की गई। दिनांक 31.10.2012 तक यूएसओएफ के माध्यम से 15,489.53 करोड़ रुपए की आर्थिक राजसहायता संवितरित की गई है तथा भारत संचार निगम लि. को एलएफ और स्पेक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु 6,948.64 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस प्रकार दिनांक 31.10.2012 तक यूएसओएफ की कुल 22,438.17 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग किया गया है तथा उपलब्ध शेष धनराशि 24,597.16 करोड़ रुपए है।

(iii) 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी" प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क, (एनओएफएन) को यूएसओएफ द्वारा दो वर्षों ने 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर वित्त-पोषण किया जाएगा। शेष निधियों का उपयोग यूएसओएफ की अन्य चल रही और आगामी स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु किया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

यू.एस.ओ.एफ. द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष की दूसरी तिमाही तक के दौरान एकत्रित निधियां।

(रूपए करोड़ में)

प्रचालक का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	की दूसरी तिमाही तक 2012-13
1	2	3	4	5
आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि.	11.55	17.85	0.00	0.00
एयरसेल लि.	74.35	102.78	113.10	58.00
एयरसेल सेलुलर लि.	19.04	21.80	20.56	9.93
एलायंस ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रा. लि.	0.04	0.15	0.34	0.13
एलायंस इन्फ्राटेक प्रा. लि.	0.00	0.01	0.02	0.00
अपना टेलीलिंक प्रा. लि.	0.00	0.01	0.00	0.00
अरविंद मिल्स प्रा. लि.	0.11	0.01	0.00	0.00
आर्या आफॅशोर सर्विसेज	0.01	0.00	0.00	0.00
आर्या आमनीटॉक रेडियो ट्रंकिंग सर्विसेज प्रा. लि.	0.01	0.57	0.61	0.42
आर्यदूत ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	0.06	0.00	0.00	0.00
एशियोनेट सेटलाईट कम्यूनिकेशन्स लि.	0.01	0.13	0.01	0.07
एस्ट्रोनेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.02	0.00	0.01
एटी एंड टी ग्लोबल नेटवर्कस सर्विसेज	20.43	23.09	27.31	17.41
अन्नै कन्वेर्जेन्स टैक्नॉलॉजी प्रा. लि.	0.00	0.01	0.01	0.00
बीम केबल सिस्टम प्रा. लि.	0.02	0.02	0.11	0.05
भारतीय एयरटेल लि.	1518.01	1594.12	1753.51	897.86
भारतीय हेक्साकॉम लि.	90.40	99.51	112.98	56.34
भारतीय टेलीवेन्चरस लि.	2.47	2.38	2.51	1.60

1	2	3	4	5
भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेज प्रा. लि.	0.03	0.03	0.03	0.02
ब्लेजनेट लि0	0.01	0.01	0.00	0.02
बी.पी.एल. मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	23.85	2676	25.58	9.76
ब्रॉडबैंड पेसनेट इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00	0.01	0.00
ब्रॉडलाइन इन्फोसर्विसेज प्रा. लि.	0.00	0.00	0.16	0.00
बीएसएनएल	1390.98	1069.53	1134.77	364.96
बीटी ग्लोबल कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्रा. लि.	21.53	24.62	26.18	16.64
सीजेएम कन्सलटेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	0.00	0.00	0.00	0.01
सीजे ऑनलाइन प्रा. लि.	0.00	0.00	0.00	0.01
केबल एंड बायरलैस नेटवर्क इंडिया प्रा.	8.11	7.32	8.54	5.36
कैप्चर नेटवर्क सिस्टम प्रा. लि.	0.00	0.04	0.00	0.00
केमिकल एंड मेटालरजिकल डिजाइन कंपनी लि.	0.00	0.00	0.00	0.02
सिटी आनलाइन सर्विसेज लि.	0.05	0.03	0.03	0.08
सिटी कॉम	0.40	0.39	0.70	0.42
सिटी कॉम नेटवर्क प्रा. लि.	0.01	0.08	0.08	0.09
कॉमसैट मैक्स लि.	0.16	0.07	0.04	0.02
कोर्डिया एल.टी. कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	0.01	0.10	0.00	0.04
डी वायॅस ब्राडबैंड प्रो. लि.	0.00	0.01	0.01	0.00
डाटा इन्फोसिस लि.	0.01	0.02	0.02	0.02
डेल डीएसएल इंटरनेट प्रा. लि.	0.00	0.01	0.00	0.00
दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.	0.01	0.01	0.03	0.01
डेल डीएसएल इटरनेट प्रा. लि.	0.00	0.01	0.00	0.00
डेन नेटवर्कस लि.	0.00	0.01	0.00	0.00

1	2	3	4	5
डेसकॉन लि.	0.01	0.02	0.07	0.00
देवास मल्टीमीडिया प्रा. लि.	0.01	0.00	0.00	0.00
डिजीटल 2 वर्चुअल आईएसपी प्रा. लि.	0.04	0.02	0.01	0.00
डिशनेट वायरलैस लि.	80.72	103.35	129.37	72.86
इक्वैंट नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	8.63	6.00	6.25	3.96
ईएसएस ईएल श्याम लि.	0.50	0. 46	0.51	0.27
एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा. लि.	6.43	0.31	1.31	0.33
इयूरस नेटवर्क सर्विसेज प्रा. लि.	0.14	0.10	0.03	0.01
एक्सल मीडिया प्रा. लि.	0.00	0.00	0.01	0.00
फाइनेंशियल टेक्नॉलॉजिस कम्प्यू.लि.	0.10	0.20	0.27	0.16
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	0.86	0.21	0.15	0.06
गेटवे सिस्टमस इंडिया लि.	0.01	0.00	0.00	0.00
जर्मन एक्सप्रेस लि.	0.01	0.00	0.00	0.00
जीटीएल लि.	0.01	0.03	0.00	0.00
गुजरात इन्फो पैट्रो लि.	0.03	0.10	0.17	0.06
हाथवे केबल एंड डाटाकॉम प्रा. लि.	0.23	0.15	0.23	0.25
एचसीएल कॉमनेट सिस्टम एंड सर्विसेज लि.	2.10	2.23	2.04	1.51
एचसीएल इन्फ्रोनेट लि.	3.24	0.97	3.62	1.55
एचएफसीएल इन्फ्रोटेल लि.	6.68	7.08	5.50	3.52
ह्यूजस कम्यूनिकेशन्स इंडिया लि.	0.02	0.27	0.16	0.05
ह्यूजस एस्कोर्ट कम्यूनिकेशन्स लि.	4.12	3.37	4.83	2.48
आईसनेट नेट लि.	0.00	0.00	0.01	0.00
आईडिया सेलुलर लि0	383.25	416.42	564.15	346.34

1	2	3	4	5
आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	140.39	128.43	173.96	107.77
आई के एफ टेक्नॉलाजिस लि.	0.03	0.00	0.02	0.01
इन 2 केबल इंडिया लि.	0.03	0.03	0.04	0.00
इनफीनियम इंडिया लि.	0.28	0.13	0.11	0.01
इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रा. लि.	0.01	0.01	0.04	0.01
इन्फोटल सेटकॉम प्रा. लि.	0.10	0.63	0.55	0.32
जेट एआईयू स्काईलाइन टॉक प्रा. लि.	0.02	0.00	0.00	0.00
करूतरी नेटवर्कस लि.	0.03	0.04	0.04	0.02
एल एंड टी फाइनेन्स लि.	0.01	0.01	0.01	0.01
लिमरास एरोनेट ब्रॉडबैंड सेर्विसेज प्रा.लि.	0.00	0.02	0.00	0.00
लूप टेलीकॉम लि.	0.00	0.38	0.13	0.00
मनीपाल ई. कामर्स लि.	0.00	0.01	0.02	0.01
माइक्रोसेंस प्रा. लि.	0.00	0.00	0.00	0.02
मेघबेला केबल एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रा. लि.	0.00	0.01	0.07	0.00
एमटीएनएल	177.99	172.02	112.50	58.83
माई ओन इन्फोटेक प्रा. लि.	0.00	0.00	0.00	0.01
नर्मदा साइबर जोन प्रा. लि.	0.02	0.00	0.00	0.00
नेटलिंक्स लि.	0.01	0.03	0.00	0.00
न्यूजेन कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	0.02	0.00	0.00	0.00
नोएडा साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क लि.	0.00	0.02	0.00	0.00
नोवानेट लि.	0.02	0.03	0.02	0.03
आयल इंडिया लि.	0.00	0.01	0.01	0.00
आनलाइन मीडिया सोल्यूशन्स लि.	0.00	0.02	0.00	0.00

1	2	3	4	5
आप्टो नेटवर्क प्रा. लि0	0.02	0.01	0.02	0.04
आरटेल कम्यूनिकेशन्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.05
ओ.-जोन नेटवर्क प्रा. लि.	0.00	0.00	0.01	0.00
पी 3 टेक्नॉलॉजिस प्रा. लि.	0.04	0.00	0.00	0.00
पेसिफिक इंटरनेट इंडिया लि.	0.10	0.11	0.21	0.13
पीक एयर प्रा. लि.	0.00	0.00	0.01	0.00
पायनीर ई-लैबस लि.	0.00	0.00	0.03	0.00
पाइपटल कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	0.00	0.00	0.43	0.27
पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	8.00	8.76	9.88	6.14
प्रो कॉल प्रा. लि.	0.42	0.45	0.56	0.21
पल्स टेलीसिस्टम प्रा. लि.	0.19	0.35	0.31	0.13
क्विककॉलम प्रा.	0.22	0.27	0.25	0.13
रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	12.75	8.88	11.82	6.19
रीच नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	0.00	0.00	6.08	0.24
रेडी लिंक इंटरनेट सर्विसेज कोविया प्रा. लि.	0.00	0.00	0.00	0.04
रिलायबेल इंटरनेट सर्विसेज लि.	6.87	7.40	6.23	4.20
रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि.	493.44	466.49	447.60	188.84
रिलायंस टेलीकॉम लि.	76.52	65.00	91.60	55.66
आर.आई. नेटवर्क प्रा. लि.	0.11	0.01	0.01	0.00
एस एंड ए इंटरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	0.00	0.02	0.00	0.00
एसटेल प्रा. लि.	0.13	2.68	2.47	0.00
एस.वी. टेलीटेक प्रा.लि.	0.00	0.01	0.01	0.00
एसएबी इन्फोटेक लि.	0.00	0.01	0.00	0.00

1	2	3	4	5
सिफी कम्यूनिकेशन्स लि.	8.32	8.09	9.00	5.88
सिंग टेल ग्लोबल इंडिया प्रा. लि.	0.00	2.08	3.09	1.65
सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	9.10	22.31	51.26	32.61
स्मार्टॉक प्रा. लि.	0.06	0.06	0.05	0.03
साफ्टसेल टेकनॉलाजी लि	0.00	0.01	0.00	0.00
साफ्टवेयर टेक्नॉलाजिस पार्क ऑफ इंडिया	0.00	0.00	0.29	0.08
साऊथर्न आनलाइंस बी.आई.ओ.	0.06	0.00	0.00	0.00
स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	52.16	57.47	64.81	38.13
स्पाइस इनोवेटिव टेक्नॉलाजिस प्रा. लि.	0.01	0.00	0.00	0.00
स्विफट मेल कम्यूनिकेशन्स लि.	0.02	0.01	0.01	0.01
सिन्टल टेलीकॉम लि.	0.00	0.00	0.01	0.00
सिस्कॉन इन्फोवे प्रा. लि.	0.00	0.01	0.00	0.00
टाटा कम्यूनिकेशन्स लि.	60.09	56.52	65.39	35.88
टाटा नेट सर्विसेज लि.	1.44	1.63	1.90	1.10
टाटा पावर ब्रॉडबैंड कंपनी लि.	0.39	0.00	0.00	0.00
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	344.04	352.02	416.62	238.86
टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लि.	83.22	136.07	99.37	53.04
तिकोना डिजीटल नेटवर्क प्रा. लि.	0.15	0.76	0.29	0.24
ट्रेक ऑनलाइन नेट इंडिया प्रा. लि.	0.63	0.74	0.22	0.00
ट्रांस वर्चुयल प्रा. लि.	0.00	0.00	0.02	0.00
त्रिकोन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	0.09	0.13	0.12	0.09
ट्यूलिप आईटी सर्विसेज लि.	13.63	22.64	8.27	3.93
ट्यूलिप टेलीकॉम लि.	0.00	0.09	0.06	0.05

1	2	3	4	5
यूनीटेक लांग डिस्टेंस कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज लि.	0.00	0.00	0.06	0.70
यूनीटेक लांग डिस्टेंस कम्यूनिकेशन्स सर्विसज प्रा. लि.	0.00	0.00	0.00	0.15
यूनीटेक वायरलैस दिल्ली प्रा. लि.	0.20	0.02	0.00	0.16
यूनीटेक वायरलैस ईस्ट प्रा. लि.	1.01	10.86	35.08	23.44
यूनीटेक वायरलैस कोलकाता प्रा. लि.	0.17	1.08	3.60	2.01
यूनीटेक वायरलैस मुंबई प्रा. लि.	0.18	1.45	4.44	3.33
यूनीटेक वायरलैस नार्थ प्रा. लि.	0.70	3.57	10.66	6.77
यूनीटेक वायरलैस साउथ प्रा. लि.	1.10	4.74	12.77	8.10
यूनीटेक वायरलैस तमिलनाडु प्रा. लि.	0.37	1.41	3.71	1.94
यूनीटेक वायरलैस वेस्ट प्रा. लि.	0.38	4.17	18.06	13.96
यूनाइटेड लाइनर एजेन्सिज प्रा. लि.	0.02	0.00	0.00	0.00
अरबन कम्यूनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	0.01	0.00	0.00	0.00
वैनवी इंडस्ट्रीज लि.	0.00	0.00	0.00	0.02
वेल्यू हेल्थकेयर लि.	0.00	0.01	0.00	0.00
वीकेयर कॉल सेंटर इंडिया	0.00	0.01	0.00	0.00
वेरीजॉन कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्रा. लि.	12.97	20.33	30.85	17.81
वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	0.00	5.00	10.40	3.80
विदेश संचार निगम लि.	1.17	2.03	2.72	1.65
वीवा कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	0.04	0.04	0.09	0.04
वोडाफोन एस्सार सेलुलर लि.	111.15	116.61	146.09	76.91
वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक इंडिया लि.	0.13	0.00	0.00	0.00
वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लि.	154.14	195.84	215.17	116.29
वोडाफोन एस्सार ईस्ट लि.	33.53	33.77	37.64	19.26

1	2	3	4	5
वोडाफोन एस्सार गुजरात लि.	98.23	105.57	121.78	60.07
वोडाफोन एस्सार लि.	81.85	86.92	90.38	44.03
वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेज लि.	64.01	73.88	90.47	48.04
वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	356.66	441.60	505.57	286.24
वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल प्रा. लि.	24.18	48.74	72.74	43.76
वीएसएनएल इंटरनेट सर्विसेज लि.	0.30	0.29	0.50	0.36
वायरलैस बिजिनेस सर्विसेज प्रा. लि.	0.00	0.00	0.00	0.23
विशनेट प्रा. लि.	0.00	0.01	0.02	0.01
वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विस प्रा. लि.	0.00	0.05	0.00	0.00
यू टेलीकॉम इंडिया प्रा. लि.	0.06	0.15	0.05	0.00
जाइलॉग सिस्टमस (इंडिया) लि.	0.01	0.01	0.00	0.00

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े एमआईएस रिपोर्टों पर आधारित हैं।

विवरण-II

दूरसंचार प्रचालकों को वितरित की गई निधियों का वर्ष वार ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों और वर्ष 31.10.2012 तक चालू वर्ष के दौरान)

आंकड़े रुपए में

दूरसंचार प्रचालक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.10.2012 तक)
1	2	3	4	5
बीबीएनएल	0	0	0	215.00
बीएएल	0	0	0	0
बीएसएनएल	2009.06	3001.70	1634.62	97.80
डीडब्ल्यूएल	0.99	1.23	2.99	1.07

1	2	3	4	5
जीटीएल	6.01	8.93	7.88	2.98
एचएफसीएल	0	0	0	0
केईसी	6.61	9.20	7.61	5.61
क्यूटीआईएल	0.66	0	0.00	2.42
आरसीआईएल	3.29	4.38	9.55	1.95
आरसीएल	0	0.08	0.05	0.01
आरआईएल	83.20	17.30	16.53	-0.80
आरटीएल	0	0	1.09	0.49
श्याम	0	0	0	0
टाटा	184.57	31.25	2.51	1.19
टीईआरआई	0	0	0.53	2.39
टीटीएमएल	98.98	19.17	2.21	0
वीईसीएल	1.56	2.29	0.46	0
वीईएसएल	5.05	4.47	1.96	0.02

प्रयुक्त संक्षिप्तियां

बीबीएनएल	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि.	बीएएल	भारती एयरटेल लिमिटेड
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड	डीडब्ल्यूएल	डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
जीटीएल	जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	एचएफसीएल	हिमाचल फयूचरस्टिक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
केईसी	केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड	क्यूटीईएल	क्यूप्पो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
आरसीआईएल	रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	आरसीएल	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटैड
आरआईएल	रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड	आरटीएल	रिलायसं टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड
श्याम	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड	टीईआरआई	दि एनर्जी रिसोंस ऑफ इंडिया
टीटीएमएल	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	वीईसीएल	वोडाफोन एस्सार सेलुलर लिमिटेड
वीईएसएल	वोडाफोन एस्सार साऊथ लिमिटेड		

विवरण-III

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीम के तहत आरंभ किए गए कार्य

जारी यूएसओएफ स्कीम

1. सामान्य ओएफसी अवसंरचना का सृजन

(क) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) :

ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार फिलहाल मुख्यत: राज्य की राजधानियों, जिला और ब्लॉक मुख्यालयों तक हो गया है तथा देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात बीएसएनएल, रेलटेल तथा पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच संपर्कता अंतराल को समाप्त करने के लिए संवर्द्धनात्मक फाइबर बिछाने, जहां आवश्यक हो, की योजना है।

संवर्द्धनात्मक नेटवर्क का आकार लगभग 0.5 मिलियन कि. मी. है। इस तरह सृजित डार्क फाइबर नेटवर्क को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क के लिए गैर-भेदभाव आधार पर अभिगम्यता प्रदान की जाएगी। ये अभिगम सेवा प्रदाता जैसे मोबाइल प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता, केबल टीवी प्रचालक, कंटेंट प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आरंभ कर सकते हैं।

ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-शासन इत्यादि जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना के लिए यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा इस परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत 2 वर्षों में 20,000 करोड़ रू. है। यह परियोजना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25.02.2012 को निगमित कंपनी बनी है।

वर्तमान स्थिति :

एनओएफएन परियोजना की परिकल्पना केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयास के तहत निष्पादित की जाने वाली परियोजना के रूप में की गई है। राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे अपना योगदान मार्गाधिकार प्रभारों को आरोपित न करके करें, जिसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा बीबीएनएल के बीच उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उ. प्र., उत्तराखंड तथा 3 संघराज्य क्षेत्रों अर्थात् दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के साथ किए गए हैं। इन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की कुल 1,40,727 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका सारणीबद्ध ब्यौरा नीचे दिया गया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

तीन प्रायोगिक परियोजनाओं की संस्वीकृति प्रदान की गई है ताकि अजमेर जिला (राजस्थान) के अराइन ब्लॉक, उतरी त्रिपुरा जिले (त्रिपुरा) के पाणिसागर ब्लॉक, विशाखापट्टनम जिले (आंध्र प्रदेश) के पारावडा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। दिनांक 15.10.2012 की स्थिति के अनुसार, इन तीन ब्लॉकों में से प्रत्येक ब्लॉक में 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ सुविधा प्राप्त ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 58 है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरा जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का संवर्द्धन, सृजन एवं प्रबंधन

(i) असम के लिए स्कीम

यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों के अभिगम नेटवर्क से वायस और डाटा परियात उनके' मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मेद्दनजर ओएफसी नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए अक्टूबर, 2009 में शुरू की गई। इस स्कीम के तहत आरंभ में जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन पर विचार किया जाता है।

इस स्कीम के माध्यम से यूएसओएफ सब्सिडी सहायता अंतरा

जिला एसडीएचक्यू डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सर्जन और प्रबंधन के लए इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य दूरसंचार प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत प्राप्त की गई राज-सहायता से तैयार की गई बैंडविड्थ क्षमता को कम सें कम 70% तक असम के क्षेत्रों में लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के मौजूदा प्रशुल्कों की 26.22% की अधिकतम मौजूदा दरों पर साझा की जाएगी।

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं

इस स्कीम का निष्पादन बीओओ मोडल अर्थात् निर्माण, प्रचालन और स्वामित्व आधार पर किया जाएगा तथा तदनुसार, बीएसएनएल प्रस्तावित अंतरा-जिला संवर्द्धित/सृजित ओएफसी परिवहन नेटवर्क के लिए सभी उपस्कर/अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन, स्वामित्व तथा प्रबंधन करेगा।

सभी स्थानों को डीएचक्यू नोड से वास्तविक ओएफसी रिंग रूटों के माध्यम से जोड़ा जाएगा तथा असम के सभी जिलों में एकीकृत वॉएस, डाटा तथा वीडियो सिग्नलों के लिए टीडीएम, आईपी, फ्रेम रिले, एटीएम इत्यादि सहित विभिन्न प्रोटोकॉलों का प्रभावी रूप से वाहित करने की क्षमता सहित कम से कम 2.5 जीबीपीएस की रिंग क्षमता और केबल रूट विविधता सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) पूर्वोत्तर-I सर्किल के लिए स्कीम

अंतरा जिला एसडीएचक्यू डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सर्जन और प्रबंधन के लिए इस स्कीम के तहत मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में कार्य आरंभ किए गए हैं।

इस स्कीम के तहत प्राप्त की गई राज-सहायता से तेयार की गई बैंडविड्थ क्षमता को कम से कम 70% लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के मौजूदा प्रशुल्कों की 12% की अधिकतम मौजूदा दरों पर साझा की जाएगी।

(iii) पूर्वोत्तर-II सर्किल के लिए स्कीम

अंतरा जिला एसडीएचक्यू डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सर्जन और प्रबंधन के लिए इस स्कीम के तहत अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड राज्यों में कार्य आरंभ किए गए हैं।

इस स्कीम के तहत प्राप्त की गई राज-सहायता से तैयार की गई बैंडविड्थ क्षमता को कम से कम 70% तक लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के मौजूदा प्रशुल्कों की 27% की अधिकतम मौजूदा दरों पर साझा की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपर्युक्त ओएफसी स्कीमों से संबंधित सारणीबद्ध ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	मद	असम	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)	पूर्वोत्तर-II (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)
1	2	3	4	5
1.	जिलों की संख्या	27	19	30
2.	नोडों की संख्या (अवस्थिति)	354	188 मेघालय (71)+ मिजोरम (62)+ त्रिपुरा (55)	407 अरूणाचल प्रदेश (226) + मणिपुर (62)+ नागालैंड (119)
3.	निर्धारित पद्देशुदा प्रभार	26.22:	ट्राई की दरों का 12:	ट्राई की दरों का 27:
4.	रॉलआउट अवधि	18 महीने	24 महीने	30 महीने

1	2	3	4	5
5.	करार अवधि	7 वर्ष	8 वर्ष	8 वर्ष
6.	परियोजना पूंजीगत लागत		161.38 करोड़ रु.	434.67 करोड़ रु.
7.	राजसहायता चरणबद्ध	40: (ज़िला) + 10: (सर्किल) + 4ग 12ण्5: (ईएएस)	40: (जिला) + 20: (सर्किल) + 4ग 10: (ईएएस)	40: (जिला) + 20: (सर्किल) +4ग 10: (ईएएस)
8.	प्रचालक (कार्यकारी एजेंसी)	बीएसएनएल	रेलटेल	रेलटैल
9.	प्रतिनिधि दर (राजसहायता)	98.89 करोड़ रु.	89.50 करोड़ रु.	298.50 करोड़ रु.
10.	करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि	12 फरवरी, 2012	16 जनवरी 2012	16 जनवरी 2012
11.	बजट प्राकलन 2011:12 के लिए अनुमान	24.75 के लिए अनुभाग	17.9 करोड़ रु.	59.7 करोड़ रु.
12.	प्रगति	354 संस्थापित किए गए नोडों में से लगभग 224 नोड	अभी शुरू हुआ है	अभी शुरू हुआ है।

2. **ग्राम स्तर तक वायरलाइन ब्रॉडबैंड संपर्कता की सुविधा का विस्तार करने के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम**

ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान करने के लिए, यूएसओएफ ने बीएसएनएल के साथ ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत 20 जनवरी, 2009 को करार पर हस्ताक्षर किए ताकि मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना तथा कॉपर वायरलाइन नेटवर्क का स्तरोन्नयन करते हुए ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में वायरलाइन ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान की जा सके। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति हमेशा कम से कम 512 केबीपीएस होगी।

इस स्कीम के तहत, बीएसएनएल द्वारा वैयक्तिक प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थाओं को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे तथा 5 वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2014 तक 28,672 कियोस्को की स्थापना की जाएगी।

राजसहायता का संवितरण–(प) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइसों (पप) ब्रॉडबैंड सुविधाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए कियोस्कों की स्थापना के लिए है। 5 वर्ष की अवधि के दौरान अनुमानित संवितरण 1500 करोड़ रू. की है, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, सीपीई, कंप्यूटरों/कंप्यूटिंग डिवाइसों तथा कियोस्कों के लिए प्रदान की जानेवाली राजसहायता शामिल है।

31.08.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में 3,91,245 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं तथा 10,076 कियोस्कों की स्थापना की गई है।

3. **साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम**

ऐसे विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र, जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं था, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टॉवरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन

करने के लिए राजसहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांव अथवा गांवों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में टावर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया था।

करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टॉवरों की संख्या में परिवर्तन हो सकता था। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इन करारों पर मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किए गए।

अवसंरचना स्थलों की स्थापना करने हेतु स्कीम के भाग-क के निम्नलिखित बोलीदाताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) भारत संचार निगम लिमिटेड

(ii) केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड

(iii) रिलायंस कम्यूनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

(vi) वायमनेटवर्क्स लि.

(v) जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

(vi) वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.

स्कीम के भाग-क के तहत स्थापित अवसंरचना स्थलों का उपयोग करते हुए मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता कराने हेतु स्कीम के भाग-ख के निम्नलिखित बोलीदाताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए

(i) भारत संचार निगम लि.

(ii) रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि.

(iii) रिलायंस टेलीकॉम लि.

(iv) भारती एयरटेल लि.

(v) भारती हेकसाकॉम लि.

(vi) डिशनेट वायरलेस लि. (एयरसेल)

(vii) एयरसेल लि.

(viii) आयडिया सेल्यूलर लि.

(ix) बीटीए सेलकॉम लि.

(x) आयडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.

(xi) वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.

(xii) वोडाफोन एस्सार साउथ लि.

(xiii) वोडाफोन एस्सार गुजरात लि.

दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत 7310 टावर अर्थात् लगभग 99.42% टावर संस्थापित कर दिए गए हैं। इस प्रकार सृजित अवसंरचना को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किया जा रहा है। दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा 15,895 बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) चालू किए गए हैं।

4. सार्वजनिक अभिगम :

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, 5,80,312 गांव अर्थात 2001 की जनगणना के अनुसार 97.76% आबादी वाले कुल राजस्व गांव में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है। बीएसएनएल ने यह बताया है कि 2010 की जनगणना के अनुसार नए चिन्हित सुविधारहित गांवों में वीपीटी से संबंधित चालू यूएसओएफ स्कीम के माध्यम से मार्च, 2013 तक शेष आबादी वाले राजस्व गांवों में वीपीटी की सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

2001 की जनगणना के अनुसार नए चिन्हित सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने संबंधी यूएसओएफ स्कीम :

मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण के तहत प्रदत्त वीपीटी को ध्यान में रखते हुए 2001 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों में चालू वीपीटी का समाधान हाल ही में किया गया

था। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, दूरस्थता, पहुंच और कानून एवं व्यवस्था के मानदंडों पर विचार किए बिना 01.10.2007 को बसे हुए सभी शेष 62443 गांवों को इस स्कीम के तहत यूएसओ फंड की सहायता से वीपीटी के प्रावधान हेतु शामिल किया गया है। इस संबंध में बीएसएनएल के साथ हाल ही में 27.02.2009 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते की शर्तों के अनुरूप 01.10.2007 से 26.02.2009 की अवधि के बीच स्थापित वीपीटी भी वित्तीय सहायता के पात्र हैं। 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत कुल 62,443 वीपीटी में से 53,471 अर्थात 85.63% वीपीटी उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) भारत निर्माण-I के अंतर्गत वीपीटी प्रदान करना

इस स्कीम के तहत ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 100 से कम है, जो घने वन क्षेत्र में स्थित हैं और जो उग्रवाद से प्रभावित हैं को छोड़कर, देश में 62,302 सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए राजसहायता प्रदान करने हेतु नवंबर 2004 में बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इन गांवों में वीपीटी प्रदान करना भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों में शामिल किया गया है। दिनांक 31.08.2012 की रॉल आउट अवधि की समाप्ति तक इस स्कीम के अंतर्गत 62,101 वीपीटी प्रदान किए गए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार नए चिन्हित सुविधारहित गांवों में वीपीटी से संबंधित यूएसओएफ स्कीम के तहत इस स्कीम के शेष गांवों में वीपीटी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ग) एमएआरआर आधारित वीपीटी को बदलना (एमएआरआर-ए और एमएआरआर-बी)

1,85,121 वीपीटी को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी से बदलने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के साथ वर्ष 2003 में करार पर हस्ताक्षर किए गए जोकि पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे थे तथा जिन्हें 01.04.2002 से पहले लगाया गया था। इनमें 30.06.2003 से पहले बदले जा चुके 47075 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-बी) तथा 01.07.2008 से बदले जाने वाले 138046 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-ए) शामिल थे। 30.06.2012 तक कुल 1,84,794 एमएआरआर वीपीटी (99.83%) को बदल दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार नए चिन्हित सुविधारहित गांवों में वीपीटी से संबंधित यूएसओएफ स्कीम के तहत इस स्कीम के शेष गांवों में वीपीटी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

पूरी की गई यूएसओएफ स्कीमें

(i) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) का प्रचालन और संचालन

इस करार के कार्य-क्षेत्र का लक्ष्य सार्वभौमिक सेवा प्रदाता (यूएसपी) द्वारा सभी वीपीटी का प्रचालन और संचालन करना है जिसके लिए करार किया गया है। यह करार 28 मार्च, 2003 को लागू हुआ जो कि प्रभावी तारीख से 7 वर्ष के लिए वैध था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2010 को पहले ही समाप्त हो गई है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

- ★ करार के अंतर्गत राजसहायता, वीपीटी के प्रचालन और संचालन की तारीख से अथवा दिनांक 01.04.2002 जो भी बाद में हो, करार की अवधि तक देय थी।
- ★ इस करार के अंतर्गत मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी को बदलने का कार्य राजसहायता के लिए पात्र नहीं था।
- ★ सार्वभौमिक सेवा प्रदाता उसी गांव के भीतर जनता को बेहतर अधिगम प्रदान करने के लिए वीपीटी के स्थान को बदल सकता है। वीपीटी का स्थान बदलने में हुए व्यय का यूएसओएफ से भुगतान नहीं किया गया था।
- ★ आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों के प्रावधान और प्रचालन, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने, कॉल प्रभारों का संग्रहण और इससे संबंधित प्राप्ति जारी करने और प्रचालनों से संबंधित दावों और क्षतियों के निवारण के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाता को एकमात्र रूप से जिम्मेदार किया जाना था।
- ★ यूएसपी को बुनियादी सेवा लाइसेंस से संबंधित निबंधन और शर्तों के ढांचे के भीतर कार्य करना था।

(ii) **दिनांक 01.04.2002 और 31.03.2005 (आरडीईएल-ख) के बीच संस्थापित - विशिष्ट अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करना**

इस करार के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01.04.2002 और 31.03.2005 के बीच कवर किए गए सेवा क्षेत्रों में विशिष्ट एसडीसीए में सार्वभौमिक सेवा प्रदाता द्वारा संस्थापित आरडीईएल का प्रचालन और संचालन करना था। ग्रामीण डीईएल से तात्पर्य है 2001 की जनगणना के अंतर्गत यथा परिभाषित संस्थापित डीईएल को निवल अव्यवहार्य एसडीसीए में संस्थापित करना। इस करार के उद्देश्यार्थ पीसीओ, आरसीपी और अन्य मोबाइल कनेक्शनों सहित डब्ल्यूएलएल मोबाइल भी ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के रूप में पात्र नहीं है। यह स्कीम दिनांक 31.03.2010 को पहले ही समाप्त हो गई है।

★ अंतिम उपभोक्ता उपस्करों के रूप में फिक्स्ड वायरलैस टर्मिनल (एफडब्ल्यूटी) वाले लैंडलाईन तथा साथ ही किसी भी वायरलैस प्रौद्योगिकी पर आधारित आरडीईएल इस करार के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

★ यह करार दिनांक 01.04.2012 को लागू हुआ जो कि प्रभावी तारीख से 8 वर्ष की अवधि तक वैध था।

★ इस करार के अतर्गत, एक बारगी फ्रंट लोडिड सब्सिडी (एफएलएस) का भुगतान केवल स्थानीय एक्सचेंज क्षेत्र में आरडीईएल की निवल वृद्धि के लिए किया गया था। निवल वृद्धि से तात्पर्य भुगतान न करने के कारण अथवा स्थानीय एक्सचेंज क्षेत्र को बदलने से स्थायी रूप से बंद हुए आरडीईएल को समायोजित करने के बाद जोड़े गए आरडीईएल की संख्या से है।

★ दिनांक 01.04.2002 और 31.03.2005 के बीच संस्थापित आरडीईएल के लिए राजसहायता देय थी। समीकृत वार्षिक राजसहायता, जहां भी देय हो, इन आरडीईएल को संस्थापित करने की तारीख से 5 वर्ष की अधिकतम अवधि तक दी गई थी।

★ यूएसपी को करार की वैधता के दौरान उपभोक्ता की मांग के अनुसार आरडीईएल को शिफ्ट करने की अनुमति थी। आरडीईएल को शिफ्ट करने के लिए यूएसपी को कोई राजसहायता देय नहीं थी।

★ आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों के प्रावधान और प्रचालन, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने, कॉल प्रभारों का संग्रहण और इससे संबंधित प्राप्ति जारी करने और प्रचालनों से संबंधित दावों और क्षतियों के निवारण के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाता को एकमात्र रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना था।

★ यूएसपी को बुनियादी सेवा लाइसेंस से संबंधित निबंधन और शर्तों के ढांचे के भीतर कार्य करना था।

(iii) **दिनांक 01.04.2005 से संस्थापित (आरडीईएल-ए और आरडीईएल-एक्स)-विशिश्टि अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करना**

दिनांक 01.04.2005 और 31.03.2007 के दौरान देश में वैयक्तिक ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) को संस्थापित करने के लिए मार्च, 2005 में मैसर्स बीएसएनएल, रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। (आरडीईएल-क) आरडीईएल को संस्थापित करने की निर्धारित तारीख को दिनांक 31.03.2010 तक बढ़ा दिया गया था (आरडीईएल-X)। हस्ताक्षरित करारों के अनुसार, ये आरडीईएल, किसी वायरलैस प्रौद्योगिकी के मामले में लैंडलाईन अथवा फिक्स्ड वायरलैस टर्मिनलों पर प्रदान किए जाने थे। ये आरडीईएल कुल 2647 एलडीसीए में से पात्र 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए), जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की लागत अर्जित राजस्व से अधिक थी में संस्थापित किए जाने थे। इन कंपनियों के बीच ये संविदात्मक एसडीसीए क्रमश: 1267, 203, 172 और 43 थे। इस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 31.03.2010 को इस स्कीम के समाप्त होने तक लगभग 79.3 लाख आरडीईएल प्रदान किए गए हैं।

(iv) **दिनांक 01.04.2002 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण वायरलाईन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के निरंतर प्रचालन के लिए सहायता (आरडीईएल-पी)**

बीएसएनएल के साथ दिनांक 12.03.2009 को एक समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है जिसके तहत बीएसएनएल को एडीसी को फेज आउट करने के बदले में दिनांक 01.04.2002 से पूर्व संस्थापित अपनी ग्रामीण वायरलाइनों की प्रचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए दिनांक 18.07.2008 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 6000 करोड़ रु. (2000 करोड़ रु. प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

(v) ग्रामीण सामुदायिक फोन का प्रावधान (आरसीपी)

2000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गांवों जहां पीसीओ सुविधा नहीं है वहां 40,694 ग्रामीण सामुदायिक फोनों (आरसीपी) (बीएसएनल 21,958, आरआईएल 18736) का प्रावधान करने के लिए दिनांक 30.09.2004 को करार पर हस्ताक्षर किए गए। ये सभी 40694 आरसीपी प्रदान कर दिए गए हैं।

(vi) प्रायोगिक परियोजनाएं

लाइटिंग ए बिलियन लाईव्स (एलएबीएल) की परियोजना द एनेर्जी रिसर्च इन्सट्टियूट (टेरी) के माध्यम से गांवों में मोबाइल चार्जिंग स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 29.04.2010 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 1900 गांवों में सौर मोबाइल चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं।

विवरण-IV

यूएसओएफ द्वारा अधिरोपित और वसूली गई वित्तीय शास्तियों (परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार) का वर्ष-वार ब्यौरा

दिनांक 31.10.2011 तक परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों से संबंधित दर्ज राशियां

वित्तीय वर्ष	वसूली गई राशि (रुपए)
1	2
2007-08	27728902
2008-09	53538383
2009-10	-20812532*
2010-11	18554019
2011-12 (31.10.2011 तक)	31380505
कुल	11.04 करोड़ रू.

नोट : स्कीम के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए बाद में शास्ति को छोड़ने के कारण इसका समायोजन किया गया।

उपयोग-प्रमाणपत्र

2028. श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री गणेशवराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) के द्वारा वित्तपोषित किसी आवासीय या अन्य परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार कार्य-निष्पादन एजेंसियों द्वारा एन.सी.आर.पी.बी. से लिए गए ऋण के बारे में उपयोग-संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा नियत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इनके लिए उपयोग-प्रमाणपत्र नहीं दिया है और एन.सी.आर.पी.बी. ने इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना बोर्ड (एनसीआरसीबी) ने सूचित किया है कि इसके द्वारा वित्तपोषित किसी आवासीय अथवा अन्य परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार कार्य-निष्पादन एजेंसियों द्वारा उक्त बार्ड से लिए गए ऋण के उपयोग-संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, ऋण की दूसरी और बाद की किश्तें, परियोजना के लिए जारी पूर्व किश्तों के लिए ऋणी से उपयोग प्रमाण-पत्र/प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के साथ-साथ उक्त बोर्ड के अधिकारियों द्वारा वास्तविक और वित्तीय सत्यापन के बाद ही जारी की जाती है। स्वीकृति पत्र के साथ जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण द्वारा परियोजना के पूरा होने की तारीख से तीन महीने के अंदर परियोजना के सफलता

पूर्वक पूरा होने संबंधी समापन रिपोर्ट एनसीआरपीबी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) एनसीआरपीबी ने यह भी सूचित किया है परियोजना की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत ऋण की दूसरी और बाद की किश्तें बोर्ड द्वारा जारी नहीं की जाती है। अभी तक निम्नलिखित एजेंसियों ने समापन प्रमाण-पत्रों के बिना अवस्थापना विकास परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी है :-

1. लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) हरियाणा सरकार
2. हरियाणा स्लम मंजूरी बोर्ड
3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
4. हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लि.
5. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.
6. तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार
7. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
8. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
9. पटियाला शहरी योजना और विकास प्राधिकरण

एनसीआरपीबी ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले की सूचना संबंधित राज्य सरकारों को देने के साथ-साथ बोर्ड की परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह के ध्यान में लाई गई है।

[अनुवाद]

तकनीकी/व्यावसायिक कालेजों को बंद किया जाना

2029. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय भोई :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2011 में एक दशक पहले की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर के काफी अधिक तकनीकी/व्यावसायिक कालेज बंद हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन तकनीकी/व्यावसायिक कॉलेजों की संख्या का ब्यौरा क्या है जो 2011 से बन्द हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके बंद होने के लिए प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार देश में नये व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना को अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (छ) जी, हां। तकनीकी/व्यावसाविक संस्थाओं को बंद किए जाने की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। बंद होना दाखिले की कमी से हो सकता है, जिसका कारण स्थान (ग्रामीण) उद्योगों के साथ कम परस्पर संवाद, कमजोर अवसंरचना आदि हो सकता है। हालांकि, वर्ष 2011-12 में 140 संस्थाएं बंद हुई थीं तथा 540 नई संस्थाएं खोली गई थीं। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में 79 संस्थाएं बंद की गई थीं तथा 10 नई संस्थाएं खोली गई थीं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए भावी योजनाएं तैयार करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को राज्य सरकारों से अभी तक ऐसी कोई भावी योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

राज्य	संस्थानों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	48

1	2
बिहार	1
छत्तीसगढ़	2
दिल्ली	1
गुजरात	2
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	7
केरल	5
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	14
ओडिशा	3
पंजाब	8
राजस्थान	10
तमिलनाडु	5
उत्तर प्रदेश	11
कुल योग	140

एयर इंडिया का निजीकरण

2030. **श्री गुरूदास दास गुप्त :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय भोई :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री पी. लिंगम :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री के. सुधाकरण :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नागर, विमानन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी ढांचा संबंधी अध्ययन रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि एयर इंडिया का आंशिक रूप से निजीकरण किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एयर इंडिया पूरे देश में एवं विदेश में फैली अपनी कुछ परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चिन्हित प्ररिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घाटे में चल रही सरकारी कंपनी को उबारने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) ऐसी कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) जी हां।

(घ) एयर इंडिया ने भारत में तथा विदेशों में अपनी संपत्तियों की जांच करने तथा इसके मौद्रीकरण के लिए रोड मैप का सुझाव देने के लिए वैश्विक रीयल एस्टेट परामर्शदाता की नियुक्त की है। परामर्शदाता परिसंपत्तियों की पहचान कर रहे हैं।

(ङ) सरकार ने एयर इंडिया की टर्नअराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना को दिनांक 12.04.2012 को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्ति पर, सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता निम्नवत है:-

(i) वर्ष 2011-12 के बजट उपलब्ध कराये गए 1200 करोड़

रुपए समेत 6750 करोड़ रुपये की अपफ्रंट इक्विटी का समावेश और जिसे वर्ष 2011-12 से पहले ही जारी किया जा चुका है।

(ii) वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 तक 4552 करोड़ रुपए की नकदी घाटा सहायता के लिए इक्विटी।

(iii) वित्त वर्ष 2021 तक 18929 करोड़ रुपए के विमान ऋण के लिए की गारंटी के लिए इक्विटी।

(iv) एयर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंको, एल.आई.सी, ई.पी.एफ.ओ. आदि के लिए जारी किये प्रस्तावित 7400 करोड़ रुपए वाले अपरिवर्तनीय डिब्बरों पर मूल धन राशि का पुनर्भुगतान तथा ब्याज की अदायगी के लिए भारत सरकार की गारंटी।

विमानन सुरक्षा बल

2031. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री प्रदीप माझी :
श्री संजय भोई :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री जोस के. मणि :
श्री बंस गोपाल चौधरी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री के. सुगुमार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने सिफारिश की है कि विमानपत्तनों की सुरक्षा करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल का गठन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस समय विमानपत्तनों पर सुरक्षा कर रहे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) के स्थान पर उक्त विमानन सुरक्षा बल को लगाए जाने की संभावना है;

(घ) **यदि हां**, तो यह परिवर्तन कब तक प्रभावी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) विमानपत्तन की सुरक्षा में इसके बाद सी.आई.एस.एफ. की क्या भूमिका होगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) देश में नागर विमानन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के विशेषज्ञों की टीम को लगाया गया है जो कि हवाई अड्डों पर मौजूदा सुरक्षा प्रणाली का व्यापक अध्ययन करेगी और इसमें सुधार किए जाने के उपायों का सुझाव देगी। इकाओ के अध्ययन रिपोर्ट, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है, में नागर विमानन मंत्रालय की कमान और नियंत्रण के तहत एक समर्पित विमानन सुरक्षा बल (ए.एस.एफ.) की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है, जो पूरे विश्व की परंपरा की तर्ज पर विमानन उद्योग के साथ पूर्णत: एकीकृत किया जानी है। इस मामले पर आगे की कार्यवाही के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एक उप-समूह का गठन किया गया जो एक समर्पित, विशेषज्ञता प्राप्त ए.एस.एफ. के सृजन पर इकाओ के अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच करेगा। इस उप-समूह ने भी नागर विमानन मंत्रालय की कमान एवं नियंत्रण में एक समर्पित, विशेषज्ञता प्राप्त ए.एस.एफ. के गठन की सिफारिश की है। साथ ही साथ उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति से संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विदेश गए भारतीय अनुसंधान वैज्ञानिक

2031. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एस. नेशनल साइन्स फाउन्डेशन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत अपने अधिकांश अनुसंधान वैज्ञानिक देश से बाहर भेजता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या

कारण हैं तथा उनमें से कितने प्रतिशत वैज्ञानिक भारत में लौटते हैं; और

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों के अपना अनुसंधान कार्य पूरा करने के बाद उन्हें देश के लिए कार्य करने हेतु प्रभावित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) मांगी गई सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने वैज्ञानिकों को देश में रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में संविदा पर अनुसंधान और विकास के लाभों को साझा करना, परामर्श, वैज्ञानिकों के साथ प्रौद्योगिकी के अन्तरण से प्राप्त प्रतिफल और रायल्टी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) शैक्षिक-जीवन और उद्योग के बीच वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधार परिषद (सी.एस.आई.आर.) शैक्षिक-जीवन और उद्योग के बीच वैज्ञानिकों की गतिशीलता, सेवाकाल में रहते हुए ज्ञान उद्यमों की स्थापना, नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियां जैसे कि प्रेरक अनुसंधान के लिए विज्ञान अनुसरण में नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं के व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि, छठे वेतन आयोग के अनुसार वैज्ञानिकों को बेहतर वेतनमान, वैज्ञानिकों के 'एच' ग्रेड में अतिरिक्त पदों का सृजन, अध्येतावृत्ति परिलाभों आदि में वृद्धि शामिल है।

अधिक स्पेक्ट्रम पर प्रभार

2033. श्री प्रभात सिंह पी. चौहान :
श्री एन. कृष्टप्प :
श्री खगेन दास :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री रमेश राठौड़ :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारप्राप्त मंत्री समूह ने दूरसंचार आयोग की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है तथा भूतलक्षी प्रभाव से अधिक स्पेक्ट्रम लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आपरेटर-वार उन आपरेटरों का ब्यौरा क्या है जो 2002 से लेकर अब तक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन से लाभान्वित हुए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व की अनुमानित हानि क्या है;

(घ) क्या संविदागत स्पेक्ट्रम से अलग अधिक स्पेक्ट्रम के प्रभार की संभावनाओं हेतु जी.एस.एम. और सी.डी.एम.ए. हेतु पृथक रूप से सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) अधिकारप्राप्त मंत्री-समूह (ई.जी.ओ.एम.) ने एकबारगी स्पैक्ट्रम प्रभार के मुद्दे पर दूरसंचार आयोग की सिफारिशों, महान्यायवादी की राय इत्यादि सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(i) 4.4 मेगाहर्ट्ज (जी.एस.एम.)/2.5 मेगाहर्ट्ज (सी.डी.एम.ए.) तक स्पैक्ट्रम धारित के लिए कोई एकबारगी प्रभार नहीं लगाया जाए।

(ii) 4.4 मेगाहर्ट्ज (जी.एस.एम.)/2.5 मेगाहर्ट्ज (सी.डी.एम.ए.) से अधिक सभी स्पैक्ट्रम धारिताओं के लिए 2012 की नीलामी में निर्धारित मूल्य पर भावी प्रभाव से एकबारगी प्रभार लगाया जाएगा। प्रभारण की तारीख मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद प्रथम तिमाही के प्रारंभ होने की तारीख होगी।

(iii) 6.2 (जी.एस.एम.)/5.0 मेगाहर्ट्ज (सी.डी.एम.ए.) से अधिक स्पैक्ट्रम के लिए, एकबारगी प्रभार जुलाई 2008 से लगाया जाए। इसके दो मूल्य होंगे। जुलाई, 2008 से लेकर नीलामी में निर्धारित मूल्य के लागू किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए यथानुपातित मूल्य 6.2 द्वारा विभाजित 2001 का प्रवेश शुल्क होगा जिसका भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लैंडिंग रेट (एस.बी.आई. पी.एल.आर.) का प्रयोग करते हुए पूरी तरह से आकलन किया गया है। 6.2 (जी.एस.एम.)/5.0 मेगाहर्ट्ज (सी.डी.एम.ए.) से अधिक के स्पेक्ट्रम पर

नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य लगाया जाएगा और यह मूल्य मंत्रिमंडल के निर्णय की तारीख के बाद की प्रथम तिमाही के आरंभ होने की तारीख से प्रभावी होगा।

(ग) उक्त अवधि के लिए अतिशय स्पैक्ट्रम के प्रभारण पर नीतिगत निर्णय नहीं होने की स्थिति में इसका कोई मात्रा-निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का निर्णय लिया है:

(i) 4.4 मेगाहट्र्ज (जी.एस.एम.) तक की स्पैक्ट्रम धारित के लिए कोई एकबारगी प्रभार नहीं लगाया जाए।

(ii) 4.4 मेगाहट्र्ज (जी.एस.एम.) से अधिक सभी स्पैक्ट्रम धारिताओं के लिए 2012 की नीलामी में निर्धारित मूल्य पर भावी प्रभाव से एकबारगी प्रभार लगाया जाएगा। प्रभार लागू होने की तारीख मंत्रिमंडल के निर्णय की तारीख के बाद प्रथम तिमाही के प्रारंभ होने की तारीख होगी।

(iii) 6.2 (जी.एस.एम.) से अधिक स्पैक्ट्रम के लिए, एकबारगी प्रभार जुलाई 2008 से लगाया जाए। इसके दो मूल्य होंगे। जुलाई, 2008 से लेकर नीलामी में निर्धारित मूल्य के लागू किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए यथानुपातित मूल्य 6.2 द्वारा विभाजित 2001 का प्रवेश शुल्क होगा जिसका भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लैंडिंग रेट (एस.बी.आई. पी.एल.आर.) का प्रयोग करते हुए पूरी तरह से आकलन किया गया है। 6.2 (जी.एस.एम.) से अधिक के स्पेक्ट्रम पर नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य लगाया जाएगा और यह मूल्य मंत्रिमंडल के निर्णय की तारीख के बाद की प्रथम तिमाही के आरंभ होने की तारीख से प्रभावी होगा।

(iv) लाइसेंसधारक यदि इस प्रकार का भुगतान नहीं करना चाहते तो उन्हें 4.4 मेगाहट्र्ज (जी.एस.एम.) से अधिक स्पैक्ट्रम के अभ्यर्पण का विकल्प दिया जाए।

(v) सी.डी.एम.ए. स्पैक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नए आई.आई.टी. हेतु लंबित प्रस्ताव

2034. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
प्रो. सौगत राय :
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
श्री पी. करूणाकरन :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित देश में और अधिक आई.आई.टी. की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों और जन-प्रतिनिधियों से अपने-अपने राज्यों में आई.आई.टी. की स्थापना हेतु अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

(च) क्या कुछ राज्य अपने-अपने राज्यों में नए आई.आई.टी. की स्थापना हेतु भूमि प्रदान करने में असफल रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् (एस.ए.सी.-पी.एम.) की सिफारिशों के आधार पर तथा क्षेत्रीय असंतुलन

को भी ध्यान में रखकर, सरकार ने XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए थे। इन आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए स्थान-निर्धारण का निर्णय लेते समय उपयुक्त कनेक्टिविटी, भौतिक अवसंरचना तथा बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के एि विभिन्न समूहों से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा इस संबंध में किसी प्रस्ताव को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा XIIवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन की प्रतीक्षा करनी होगी।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आयरलैण्ड के साथ द्विपक्षीय स्वास्थ्य देखभाल समझौता

2035. श्री नलिन कुमार कटील :
प्रो. सौगत राय :
श्री शिवराम गौडा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयरलैण्ड और भारत ने आयरलैण्ड में रहने वाले भारतीयों के चिकित्सा उपचार हेतु किसी द्विपक्षीय स्वास्थ्य देखभाल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आयरलैण्ड में अस्पताल के अधिकारियों द्वारा उचित चिकित्सा देखभाल के अभाव में एक भारतीय दंत चिकित्सक की मृत्यु हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और पीड़ित के परिवार को क्या सहायता प्रदान की गई है और इस घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारत और आयरलैंड के बीच कोई द्विपक्षीय स्वास्थ्य देखभाल करार मौजूद नहीं है। आयरलैंड तथा भारत की चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के स्वरूप एवं विषयवस्तु में भिन्नताएं हैं।

(ग) से (ड.) आयरलैंड में रहने वाली एक भारतीय नागरिक श्रीमती सविता हलप्पानावर के दु:खद निधन के बारे में सरकार को जानकारी है। सरकार ने इस मामले को आयरलैंड सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया है और इससे संबंधित जांच के बारे में सूचित करते रहने की अनुरोध किया है। डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने मृतका के परिजनों को सभी अपेक्षित कोंसुली सहायता उपलब्ध कराई है।

विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा भारत सरकार का मुख्य सरोकार है। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशनों के जरिए उनके कल्याण की निरन्तर निगरानी की जाती है। जब कभी भी सरकार को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, वह ऐसे मामलों को संबंधित सरकारों के साथ उठाती है।

एयर इंडिया पर संकट

2036. डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया को वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति घोषित किए जाने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) एयर इंडिया द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों/बैंकों से संस्थान-वार लिए गए/लिए जाने हेतु प्रस्तावित ऋण का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख तक ऋण के पुनर्भुगतान में चूक का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उधार देने वालों को देय राशि का भुगतान करने में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एयर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थाओं/बैंको के लिए गए कुल बकाया ऋणों का ब्यौरा निम्नवत है:

31.03.09 की स्थिति के अनुसार	30931.19 करोड़ रुपए
31.03.10 की स्थिति के अनुसार	38422.78 करोड़ रुपए
31.03.11 की स्थिति के अनुसार	42629.00 करोड़ रुपए
31.03.12 की स्थिति के अनुसार	43441.56 करोड़ रुपए (अन अंकेक्षित)

(घ) आज की तारीख तक पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

(ङ) वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार, एयर इंडिया 31.12.2013 से आरंभ होने वाली तथा 30.09.2026 को समाप्त होने वाली तिमाही किस्तों में 10,448 करोड़ रूपये की राशि का दीर्घ कालिक ऋण, एयर इंडिया द्वारा जारी किए जा रहे अपरिवर्तनीय बंध पत्रों के आगमों से 7,400 करोड़ रुपए की राशि का अल्पकालिक ऋण और 31.12.13 से आरंभ होने वाली तथा 30.09.2026 से समाप्त होने वाली तिमाही किस्तों में निधिगत ब्याज सावधि ऋण से भुगतान करेगी। सरकार ने विमान के अधिग्रहण के लिए गारंटीशुदा ऋणों की योजना बनाई है ताकि सरकार से प्राप्त होने वाली इक्विटी से भुगतान किया जा सके।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का विकास

2037. श्री संजय सिंह चौहान :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में विमापत्तनों के विकास के लिए अधिगृहीत भूमि भातरीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केंद्र सरकार ने परियोजना-वार-भू-स्वामियों को मुआवजे के भुगतान सहित क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) विभिन्न विमानपत्तनों पर विकास कार्य की स्थिति क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जो प्रचालन के लिए तैयार हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश समेत उन हवाई अड्डों, जहां पर भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है, का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न हवाई अड्डों पर पूरे किए जा चुके/किए जा रहे विकास कार्य का ब्यौरा क्रमशः विवरण-VI और विवरण VII पर दिया गया है।

(ङ) भोपाल और इंदौर हवाई अड्डे का कार्य पूरा हो गया है और आधुनिकीकरण कार्यों के पूरा होने के पश्चात् इसे प्रचालनिक कर दिया गया है।

विवरण-I

उन हवाई अड्डों का राज्यवार ब्यौरा जहां भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है

उत्तरी क्षेत्र

क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	(क) और (ख)	(ग)
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	लखनऊ	जून 2000 में 77.69 एकड़ भूमि का सुपुर्द किया गया।	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाई पट्टी के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण लीज पर एक रुपए प्रतिवर्ष के टोकन तथा लाइसेंस शुल्क पर 30 वर्षों के लिए किया गया था।
2.	वाराणसी	नि:शुल्क 64.73	राज्य सरकार द्वारा एएआई को भूमि का सुपुर्द विभागीय कार्य के लिए किया गया। हवाई पट्टी के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण तथा एएआई को नि:शुल्क सुपुर्द। कार्य पूरा हो गया।
पंजाब			
1.	अमृतसर	1.92 एकड़ भूमि 1987 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया।	राज्य सरकार द्वारा एएआई को नि:शुल्क भूमि का सुपुर्द
		14.17 एकड़ भूमि 1997 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया।	राज्य सरकार द्वारा एएआई को नि:शुल्क भूमि का सुपुर्द
		125.3 एकड़ भूमि 1998 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया।	राज्य सरकार द्वारा एएआई को नि:शुल्क भूमि का सुपुर्द
		23 एकड़ भूमि 2000 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया।	राज्य सरकार द्वारा एएआई को नि:शुल्क भूमि का सुपुर्द
		45.37 एकड़ भूमि 2008 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया।	राज्य सरकार द्वारा एएआई को नि:शुल्क भूमि का सुपुर्द
2.	चंडीगढ़/मोहाली	सिविल एयर टर्मिनल चंडीगढ़ ने 1986 से राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क अथवा भुगतान आधार पर किसी भी भूमि का सुपुर्द नहीं गया है। सिवाय पंजाब राज्य सरकार द्वारा अनुसार चंडीगढ़ 305 एकड़ 07 कनाल, 17 मारला समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (मोहाली साइड) एएआई को सुपुर्द कर दिया गया।	

1	2	3		4
3.	लुधियाना	7.5 एकड़ भूमि 2010 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया		आइसोलेसन बे के लिए 5 एकड़ तथा डीवीओआर के लिए 2.5 एकड़
4.	पठानकोट	47 एकड़ भूमि का 2006 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया		हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण
		27.84 एकड़ भूमि का 2006 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया		पंजाब सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण
उत्तराखंड				
1.	देहरादून	326.42 एकड़ भूमि का 2004 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया		2004 में 326.42 एकड़ भूमि का सुपुर्द हवाईअड्डे के विकास के लिए नि:शुल्क किया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्रयोग के लिए रखा गया भूमि शामिल हैं।
2.	पंतनगर	173.81 एकड़ भूमि 2006 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया		173.81 एकड़ संपूर्ण कुल क्षेत्र का सुपुर्द किया जाना है, 2006 में 134.4 एकड़ वास्तविक क्षेत्र का सुपुर्द किया गया 39.41 एकड़ क्षेत्र को सुपुर्द किया जाना बाकी है।
राजस्थान				
1.	जैसलमेर	57.6 एकड़ भूमि जुलाई 2003 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया		—
2.	जयपुर	40 एकड़ भूमि 1986 में सुपुर्द किया गया	सरकार का भूमि पार्सल नि:शुल्क सुपुर्दकर दिया गया। बाकी भूमि भुगतान आधार पर की जाएगी	भूमि का मूल्य 2,66,15,255.00
		0.69 एकड़ भूमि 1987 में सुपुर्द किया गया		भूमि का मूल्य
		4.25 एकड़ भूमि 1989 में सुपुर्द किया गया		भूमि का मूल्य 2,96,550.00
		9 एकड़ भूमि 1995 में सुपुर्द किया गया		भूमि का मूल्य 39,22,400.00

1	2	3		4
		295.7 एकड़ भूमि 1995 में सुपुर्द किया गया		भूमि का मूल्य 13,57,51,997.00
		62.47 एकड़ भूमि 2002 में सुपुर्द किया गया		भूमि का मूल्य 1,14,25,203.00
		147.62 एकड़ भूमि 2010 में सुपुर्द किया गया		भूमि का मूल्य 42,34,29,777.00 (उपकृतों को मुआवजे का आवंटन प्रगति पर है। जल्द ही कब्जा लिया जाएगा।
3.	किसनगढ़	221 एकड़ भूमि 2009 में सुपुर्द किया गया	निशुल्क	नि:शुल्क
		442 एकड़ भूमि 2011 में सुपुर्द किया गया		नि:शुल्क (अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है एएआई की भूमि अभी तक सुपुर्द नहीं की गई)
4.	उदयपुर	1986 से अधिग्रहण की गई भूमि कुल 301.73 एकड़ है। कुल 6.99 एकड़ भूमि 14,22,371.00 रूपए के भुगतान पर एएआई को सुपुर्द की गई। शेष 294.74 एकड़ भूमि नि:शुल्क अधिग्रहीत की गई।		
जम्मू और कश्मीर				
1.	जम्मू	9.06 एकड़ भूमि 1987 में सुपुर्द किया गया।	14.32 लाख के भुगतान पर	14.32 लाख के भुगतान पर वीओआर स्थापित करने कग लिए (कार्य संपन्न)
		14.38 एकड़ भूमि 1997 में सुपुर्द किया गया	258.69 लाख के भुगतान पर	हवाईपट्टी चरण 1 के विस्तार के लिए 258.69 लाख का भुगतान (कार्य संपन्न)
		12.8 एकड़ भूमि 2004-05 में सुपुर्द किया गया	304.98 लाख के भुगतान पर	आईएलएस कैट-1 की स्थापना के लिए (कार्य संपन्न) 304.98 लाख के भुगतान पर
		34.5 एकड़ भूमि 2001 में सुपुर्द किया गया	एक रुपए प्रतिवर्ष पर 40 वर्ष के लिए लीज पर	राज्य सरकार द्वारा एक रुपए प्रतिवर्ष पर 40 वर्ष के लिए भूमि का सुपुर्द
		5.29 एकड़ भूमि 2010 में सुपुर्द किया गया	नि:शुल्क	एप्रन की विस्तार राज्य सरकार से नि:शुल्क किया गया। (कार्य संपन्न)
		17.05 एकड़ भूमि 2012 में सुपुर्द किया गया	नि:शुल्क	हवाई पट्टी के विस्तार के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सेना भूमि सुपुर्द

1	2	3	4
2.	लेह	28.63 एकड़ भूमि में से 20.276 एकड़ भूमि बची हुई भूमि लीज लंबित।	20 रूपया प्रति मारला वार्षिक दर से लीज पर तथा
हिमाचल प्रदेश			
1.	कांगड़ा	116.14 एकड़ भूमि 1992 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गग्गल हवाईअड्डे का एनएए को सुपुर्द
		9.88 एकड़ भूमि 2001 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया	हवाईपट्टी के विस्तार के लिए
2.	कुल्लू मनाली	13.02 एकड़ भूमि 2001 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया	–
3.	शिमला	लगभग 191.82 एकड़ भूमि 1991 में नि:शुल्क सुपुर्द किया गया	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एएआई को नि:शुल्क भूमि का सुपुर्द
मध्य प्रदेश			
1.	खजुराहो	1986 के बाद 387.31 एकड़ भूमि तीन चरणों में सुपुर्द की गई। 14.05 एकड़ भूमि के लिए 964274.00 राशि मुआवजे के रूप में दी गई जिसमें 122.89 एकड़ प्रथम चरण में सम्मिलित थी। शेष भूमि नि:शुल्क प्रदान की गई।	14.05 एकड़ भूमि के लिए 964274.00 राशि मुआवजे के रूप में दी गई।
दिल्ली			
1.	सफदरजंग	1987 में 44 लाख के भुगतान पर 5.5 एकड़ सुपुर्द की गई	एलडीओ, शहरी विकास मंत्रालय से 44 लाख के भुगतान पर अधिग्रहण

विवरण-II

दक्षिणी क्षेत्र

तमिलनाडु

क्रम सं.	हवाईअड्डे का नाम	(क) और (ख)	(ग)
1	2	3	4
1.	मदुरै	580.14 एकड़ प्रस्तावित अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। रिंग रोड (तूतीकोरिन-अरूपकोत्तई रोड) के डायवर्जन

1	2	3	4
			पर होने वाला खर्च एएआई से मांगा गया था। एएआई ने राज्य सरकार से इस संबंध में जारी सरकारी आदेश का अनुपालन करने का अनुरोध किया था, की भूमि नि:शुल्क तथा प्रतिभारों से मुक्त सुपुर्द की जाएगी।
2.	कोयम्बटूर	594 एकड़ प्रस्तावित अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	a. (i) भारतीय नौसेना 6.38 एकड़ भूमि का सुपुर्द करने में अनिच्छुक है। (ii) मामले पर नौसेना से विचार-विमर्श किया जा रहा है। b. 134 एकड़ भूमि वायु सेना की है। वे भूमि सुपुर्द के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें भूमि की अपने उपयोग के लिए जरूरत है।
3.	तूतीकोरिन	586 एकड़ अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।
4.	त्रिची	510.30 एकड़ अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	164.68 एकड़ सेना-डीईओ चेन्नई द्वारा अनापत्ति पत्र नहीं दिया गया। शेष भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
5.	सलेम	563 एकड़ अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।
6.	वेल्लूर	1046 एकड़ अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	राज्य सरकार से पुष्टिकरण नहीं प्राप्त है।
आंध्र प्रदेश			
1.	वारंगल	438 एकड़ अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	भूमि में जल-जीव की उपस्थित/एचटीएलटी पावर लाइन का डायवर्सन; जीएम (सीआईसी) 15.10.2012 को भूमि के अधिग्रहण के लिए राजस्व अथारिटी को फार्म-I जमा किया। राज्य सरकार द्वारा फंड नहीं जारी किया गया।
2.	राजमुंदरी	851 एकड़ अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा 81 करोड़ रुपए जारी किए गए।
3.	विजयवाड़ा	491.82 एकड़ के लिए एलपीएस जमा किया गया। अब तक सुपुर्द नहीं किया गया।	राज्य सरकार से संपर्क किया गया, राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए स्वीकृति किया गया है।

1	2	3	4
4.	तिरूपति	230.73 एकड़ के लिए अग्रिम कब्जा दिया गया। बची हुई भूमि के लिए अनुरोध किया गया।	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।
5.	कुडप्पा	550 एकड़ में 23 एकड़ अब तक सुपुर्द नहीं किया गया। राज्य सरकार से शेष भूमि के लिए निर्माण वर्जित क्षेत्र का अनुरोध किया गया है।	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।
कर्नाटक			
1.	बैंगलोर	भुगतान पर आवासीय निवास के लिए 5 एकड़ के अधिग्रहण का प्रस्ताव।	9 करोड़ भूमि के कुल लागत में से 1.80 करोड़ रुपया एएआई को अग्रिम भुगतान किया गया। जून, 2012 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कार्य प्रगति पर है, तीन महीने में भूमि सुपुर्द कर दिया जाएगा।
2.	मेंगलौर	21.03.2009 को 77.05 एकड़ सुपुर्द किया गया। 3.21 सुपुर्द किया जाना है।	कार्य प्रगति पर है, कर्नाटक सरकार द्वारा 309 लाख प्रदान किया गया है।
3.	मैसूर	735 एकड़ में से 362.46 का सुपुर्द किए गए।	शेष भूमि के सुपुर्द के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया गया है।
4.	हुबली	615 एकड़ में से 600 सुपुर्द किए गए 15 सुपुर्द किए जाने हैं।	शेष भूमि के सुपुर्दगी हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
केरल			
1.	कालीकट	प्रस्तावित 137 एकड़ सुपुर्द नहीं किए गए हैं।	स्थानीय निवासियों का विरोध, दावेदारों द्वारा दो रिट याचिका दायर। सघन आबादी वाले क्षेत्र से बचने के लिए संशोधित एलाइनमेंट विचाराधीन है।
2.	त्रिवेन्द्रम	120 एकड़ में से 81.29 का सुपुर्द किया जाना बाकी 38.71 एकड़ का सुपुर्द किया जा चुका है।	राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	पुदुचेरी	चरण 1; 370 एकड़ प्रस्तावित है। जो अभी पूरा नहीं हुआ है। 50 एकड़ सुपुर्द किया गया।	शेष भूमि का सुपुर्द की जानी है।
2.	अगाती	32.30 एकड़ प्रस्तावित भूमि सुपुर्द नहीं की गई है।	संरचना/तकनीकी बाधाएं हैं।

विवरण-III

पश्चिमी क्षेत्र

क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	(क) तथा (ख)		(ग)
		अनुरोध की गई भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द की गई भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	
1	2	3	4	5
क.	**महाराष्ट्र**			
1.	औरंगाबाद	147.00+182.00	147.00	महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास मांग लंबित है।
2.	अकोला	174.67	0.00	महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास मांग लंबित है।
3.	गोंदिया	19.90	0.00	महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास मांग लंबित है।
4.	पुणे	5.00	0.00	अधिग्रहीत किए जाने के लिए हाल में प्रस्तावित।
ख.	**गुजरात**			
1.	अहमदाबाद	67.289	0.00	सर्वेक्षण पूरा हो गया/राज्य सरकार के पास लंबित है।
2.	जामनगर	17.38	0.00	प्रस्ताव लंबित।
3.	कांडला	282.07	0.00	राज्य सरकार के पास प्रस्ताव लंबित।
4.	पोरबंदर	276.00	0.00	राज्य सरकार के पास प्रस्ताव लंबित।
5.	सूरत	784.05	784.05	2619.43 एकड़ की नई आवश्यकता।
6.	वडोदरा	24.18	0.00	राज्य सरकार के पास लंबित।
ग.	**मध्य प्रदेश**			
1.	इंदौर	137.67+28.00+13.45	137.67	राज्य सरकार के पास लंबित।
2.	जबलपुर	469.52	0.00	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।

1	2	3	4	5
3.	भोपाल	387.85	387.85	–
घ.	**गोवा**			
1.	गोवा	7.50 से 10.00	0.00	राज्य सरकार के पास लंबित।
ङ.	**कर्नाटक**			
1.	बेलगाम	370.00	0.00	चिन्हित प्रक्रिया पूरी हो गई/शीघ्र सुपुर्द की जाएगी।

विवरण-IV

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	(क) तथा (ख)		(ग)
		अनुरोध की गई भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द की गई भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	
1	2	3	4	5
क.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**			
1.	वीएसआई हवाईअड्डा पोर्ट ब्लेयर	ग्लाईड तथा संस्थापन के लिए 2.9 एकड़। हवाईअड्डा विकास के लिए 4.25 हेक्टेयर तथा भाविप्रा कालोनी के लिए 6.42 हेक्टेयर	0.00	प्रगतिरत। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अंडमान और निकोबार राजस्व विभाग को 20 लाख का भुगतान किया गया है। धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है, भूमि अभी आवंटित नहीं की गई है (भूमि निजी स्वामियों की है)।
बिहार				
1.	पटना हवाईअड्डा	(क) रनवे की प्रचालनिक कुशलता में संवर्धन के 5.02 एकड़	5.02	भुगतान आधार पर वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भूमि के स्थाई निपटान के रूप में भूमि हस्तांतरित की गई थी।
		(ख) रनवे की प्रचालनिक कुशलता में संवर्धन करने के लिए 1.4 एकड़ रेलवे भूमि	1.4	भुगतान आधार पर वर्ष 2002-03 के दौरान रेलवे से दीर्घकालीन पट्टा आधार पर

1	2	3	4	5
		(ग) हवाईअड्डे के विकास के लिए 227 एकड़	0.00	प्रगतिरत
2.	गया हवाईअड्डा	ए-310 विमान के प्रचालन के लिए 100 एकड़	0.00	प्रगतिरत
3.	कटिहार एसीएस स्टेशन	एसीएस तथा कार्यालय एमएसएसआर तथा डीवीओआर/डीएमई हेतु 10.52 एकड़ (2.23+8.29)	10.52	भुगतान आधार पर क्रमशः वर्ष 1958 तथा 2006 के दौरान भूमि हस्तांतरित की गई (केवल 8.29 एकड़ के लिए)
छत्तीसगढ़				
1.	स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा रायपुर	2206 एकड़ फेज-1-1158 एकड़ तथा फेज-II-1048 एकड़-हवाईअड्डा विकास हेतु	0.00	प्रगतिरत
झारखंड				
1.	बी.एम. हवाईअड्डा, रांची	वाइड बॉडी विमान के प्रचालन के लिए 582 एकड़	रु0.00	राज्य सरकार के पास लंबित
2.	देवघर	659.41 (53.41 एकड़ + मौजूदा 606 एकड़)	0.00	यह हवाईअड्डा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हवाईअड्डे के विकास के लिए अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु समन्वय का कार्य किया जा रहा है।
ओडिशा				
1.	बी.पी. हवाईअड्डा, भुवनेश्वर	133.631 एकड़	18.964	वर्ष 2011 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा सरकार से 18.964 एकड़ भूमि प्राप्त की गई।
2.	झारसुगुडा	फेज-II के विकास के लिए 191 एकड़ (हवाईअड्डे के प्रचालनीकरण के लिए कुल 684 एकड़)	0.00	सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समन्वय का कार्य किया जा रहा है।
3	बेरहामपुर (एमएसएस आर स्टेशन)	एमएसएसआर स्टेशन के लिए 0.949 एकड़ भूमि ली गई	0.949 एकड़	

1	2	3	4	5
		आवासीय कॉलोनी के लिए 1.005 एकड़	1.005 एकड़	
पश्चिम बंगाल				
1.	बेहला	बेहला हवाईअड्डे के विकास के लिए 38.35	0.00	राज्य सरकार के पास लंबित
2	मालदा	एटीआर-42 विमान के प्रचालन के लिए 61 एकड़	0.00	राज्य सरकार के पास लंबित

विवरण-V

क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	(क)	(ख)	(ग)
1	2	3	4	5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
1.	पेक्योंग (सिक्किम)	हां	200.91 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो गया है	हवाईअड्डे का विकास हो रहा है/ नामांतरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2.	गुवाहाटी	नहीं	–	रडार का स्थान परिवर्तन डीवीओआर की चारदीवारी। क्षेत्र का चिन्हांकन तथा नामांतरण-डी.सी. कामरूप, सचिव, टीपीटी विभाग, असम सरकार के समक्ष मुद्दे उठाए गए।
3.	बारापानी	नहीं	–	चारदीवारी (केवल 39%)। ग्रामीणों द्वारा विरोध-बार-बार जिला प्रशासन तथा मेघालय सरकार (पूर्वोत्तर परिषद सलाहकार सहित) के साथ बैठक।
4.	जोरहट	नहीं	–	असम राइफल के ढांचे के कारण 1.7656 एकड़ के कार पार्किंग क्षेत्र को अभी सौंपा नहीं गया है जिसके लिए वे लागत क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा प्रधान सचिव, परिवहन, असम सरकार के समक्ष उठाया गया (नि:शुल्क तथा सभी दायित्वों से मुक्त)।

1	2	3	4	5
5.	डिब्रूगढ़	नहीं	–	मूल पट्टी मापदंड (32 एकड़)-यह मुद्दा असम सरकार के साथ बैठक में उठाया गया।
6.	बागडोगरा	नहीं	–	कैट-I उपकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करते। प्रकाश आवश्यकता (रनवे के ओ/सी के साथ 600 मीटर लंबाई)-पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष उठाया गया। (निरःशुल्क तथा सभी दायित्वों से मुक्त)।

विवरण-VI

एएआई के हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण
(पूर्ण कार्य)

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	कार्य का नाम	ए/ए एवं ई/एस/ (करोड़ रुपए में)	कार्य पूर्ण की तारीख
1	2	3	4	5
1	चेन्नई	द्वितीयक रनवे 12-30 का 1032 मीटर तक विस्तार, पार्किंग वे, समानांतर टैक्सी वे आदि का निर्माण	1808 (संयुक्त ए/ए एवं ई/एस)	मार्च-11
		अडियार नदी पर आरसीसी/प्री स्ट्रेस्ड पुल का निर्माण		मार्च-11
		कामराज घरेलू टर्मिनल (चरण-IV) का विकास, अन्ना अंतरराष्ट्रीय का विस्तार और मौजूदा टर्मिनल की फेस लिफ्टिंग		अप्रैल-12
		चेन्नई हवाईअड्डे पर कैट-I के लिए नए फायर स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण	14.13	दिसम्बर-11
		एकीकृत कार्गो टर्मिनल (चरण-III)	144.93	अगस्त-12
		नए टर्मिनल भवन से मैच करने के लिए मौजूदा टर्मिनल भवन का स्तरोन्नयन	14.08	अगस्त-12
2	कोलकाता	(पप) 431 मीटर तक द्वितीयक रनवे 01 एल-19 आर का विस्तार	1942.51 (संयुक्त ए/ए एवं ई/एस)	दिसम्बर-10

1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	आगरा	टर्मिनल भवन का जीर्णोद्धार	3.38	दिसम्बर-09
2.	अमृतसर	अमृतसर हवाई अड्डे (चरण-ए) का स्तरोन्नयन एवं विकास	87.50	2006
		4 रिमोट पार्किंग बे का निर्माण	9.56	नवम्बर-07
		रनवे का विस्तार और संबद्ध कार्य	17.04	जून-08
		ओआरपीएस (34) की शिफ्टिंग	9.65	दिसम्बर-08
		एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का मॉड्यूलर विस्तार	149.1	जून-09
		2 कान्टेक्ट पार्किंग बे का निर्माण		
		3 आंतरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	13.19	जुलाई-09
		मेल अनुभाग की शिफ्टिंग	5.76	अगस्त-09
		भूमि अधिग्रहण	2.21	दिसम्बर-10
		एसएच : नई अर्जित की गई भूमि के चारों ओर चार दीवारी का निर्माण		
		सुरक्षा हट समेत पेरामीटर रोड, ड्रेन एवं पुलिया का निर्माण	3.04	जुलाई-11
3.	भटिंडा	लिंक टैक्सी वे समेत एप्रन का निर्माण	6.37	मई-12
		टर्मिनल भवन का निर्माण	2.50	जुलाई-12
4.	चंडीगढ़	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	78.00	मार्च-11
5.	देहरादून	नए टर्मिनल भवन, एसी संयंत्र कक्ष एवं सब स्टेशन, कार पार्क आदि का निर्माण	35.00	सितम्बर-09
		रनवे, एप्रन, लिंक टैक्सी वे का निर्माण	44.50	नवम्बर-07
		तकनीकी खंड सह नियंत्रण टावर, फायर स्टेशन तथा आकस्मिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण	5.99	दिसम्बर-09
6.	जयपुर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	115.77	जुलाई-09

1	2	3	4	5
		नए एप्रन एवं टैक्सी वे का निर्माण	32.00	सितम्बर-09
7.	जैसलमेर	एप्रन एवं टैक्सी ट्रैक का निर्माण	9.94	अप्रैल-10
8.	जम्मू	एप्रन का विस्तार	15.00	सितम्बर-12
9.	कुल्लू	नए टर्मिनल भवन का निर्माण एवं पेवमेंट कार्य	10.00	जून-07
10.	खजुराहो	नए एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	13.47	मार्च-08
11.	लखनऊ	चार बड़े आकार वाले विमान और टैक्सी वे के लिए नए एप्रन का निर्माण	41.30	दिसम्बर-09
		नए एकीकृत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	129.38	अक्तूबर-11
		लखनऊ हवाई अड्डे पर तकनीकी खंड एवं नियंत्रण टावर का निर्माण	3.61	सितम्बर-07
12.	लुधियाना	मौजूदा रनवे, टैक्सी वे एवं एप्रन का पुन: सतहीकरण	9.80	
13.	पंत नगर	रनवे का विस्तार और संबद्ध कार्य	6.00	फरवरी-08
14.	श्रीनगर	एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आशोधन	101.33	अप्रैल-09
		एप्रन चरण-II और कार पार्क का विस्तार	28.00	मार्च-11
15.	उदयपुर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	77.44	अप्रैल-08
		रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण और संबद्ध कार्य	44.31	मई-09
		लिंक टैक्सी वे चरण-I समेत एप्रन का निर्माण	4.56	फरवरी-08
		लिंक टैक्सी वे चरण-II समेत एप्रन का निर्माण	10.32	जून-11
		प्रशासनिक खंड का निर्माण	4.64	जून-10
		फायर स्टेशन तथा आपातकालीन चिकित्सा केंद्र का निर्माण	3.29	जून-09
		तकनीकी ब्लॉक और नियंत्रण टावर का निर्माण	7.37	मार्च-10
16.	वाराणसी	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	139.50	अगस्त-10
		एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण और रनवे का विस्तार	40.00	अप्रैल-10

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
1.	भुवनेश्वर	एप्रन का विस्तार, मौजूदा एप्रन और टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त टैक्सी वे का निर्माण	15.00	जनवरी-07
2.	कूच बिहार	नए टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य	12.46	जनू-09
3.	गया	नए टर्मिनल भवन और सबद्ध संरचना का निर्माण	62.52	अगस्त-06
4.	पोर्ट ब्लेयर	एप्रन और अतिरिक्त टैक्सी वे का विस्तार	34.38	दिसम्बर-09
5.	पटना	जेपीएनआई हवाई अड्डे पर रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन की री-कार्पेटि।ग और संबद्ध कार्य	23.08	अगस्त-11
6.	रायपुर	एप्रन का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	6.85	जनवरी-08
		नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	129.65	अक्तूबर-12
7.	रांची	एप्रन का विस्तार और आइसोलेशन बे का निर्माण	12.52	मई-10
		रनवे की रिसर्फेसिंग	15.07	जनवरी-11
		नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	137.79	अक्तूबर-12
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
1.	अगरतला	मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण	37.00	जुलाई-09
		एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	18.66	अप्रैल-09
		तकनीकी भवन का निर्माण	4.99	मार्च-09
		नियंत्रण टावर का निर्माण	9.67	मई-12
		डॉप्लर राडार भवन का निर्माण	3.24	मई-12
2.	बागडोगरा	प) एप्रन का विस्तार	20.70	सितम्बर-09
		टर्मिनल भवन के सिटी साइड का विस्तार और अन्य संबद्ध कार्य	3.20	मार्च-11
3.	बारापानी (शिलांग)	नए टर्मिनल भवन का निर्माण और एप्रन का विस्तार	29.70	मई-10
4.	डिब्रूगढ़	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	71.71	अगस्त-09

1	2	3	4	5
		मौजूदा रनवे और टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण	17.71	दिसम्बर-10
		एप्रन का विस्तार	21.82	जून-07
		डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर मौसम विभाग के लिए डॉप्लर बेदर राडार का निर्माण	2.18	जुलाई-12
		फायर स्टेशन का निर्माण	3.24	जुलाई-12
5.	दीमापर	एप्रन का विस्तार और लिंक टैक्सी वे का निर्माण	13.25	जुलाई-11
6.	गुवाहाटी	रनवे का विस्तार और लिंक टैक्सी वे के साथ नए एप्रन का निर्माण	60.82	जून-09
		आईसोलेटेड विमान पार्किंग का निर्माण	14.15	मार्च-10
		नई अर्जित की गई भूमि की आंतरिक जल निकास प्रणाली का विकास	29.78	जनवरी-11
		एयरोब्रिज, स्वचालित सीढ़ियां तथा लिफ्ट समेत विमान लिंक कोरिडोर का निर्माण	1.61	मार्च-07
		रनवे विस्तार और नए एप्रन आदि निर्माण के लिए नई अर्जित भूमि में चार दीवारी का निर्माण	8.68	जून-10
7.	इम्फाल	रनवे की रिसर्फेसिंग, आइसोलेशन बे का निर्माण, एप्रन तथा लिंक टैक्सी वे का विस्तार	21.00	दिसम्बर-04
8.	सिल्चर	रनवे का विस्तार, भूमि का अर्जन और चार दीवारी का निर्माण	41.49	फरवरी-09
पश्चिमी क्षेत्र				
1.	अहमदाबाद	नए घरेलू आगमन खंड का निर्माण	56.94	अप्रैल-08
		नए घरेलू प्रस्थान खंड का निर्माण	46.09	अगस्त-05
		अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मौजूदा घरेलू एप्रन का विस्तार	101.32	नवम्बर-08
		नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	328.00	अगस्त-10
2.	औरंगाबाद	नए एकीकृत टर्मिनल भवन, तकनीकी खंड, नियंत्रण टावर, फायर स्टेशन, एमटी पूल आदि का निर्माण	99.70	दिसम्बर-08

1	2	3	4	5
		वैद्युत कार्य सेमत रनवे का विस्तार	25.68	जनवरी-10
		नए एप्रन का निर्माण	7.55	अक्तूबर-07
3.	भोपाल	रनवे का विस्तार	35.00	जुलाई-09
		नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	135.00	दिसम्बर-10
		नए एप्रन का निर्माण और संबद्ध कार्य	63.78	सितम्बर-10
4.	गोंदिया	समानान्तर टैक्सी वे का निर्माण	18.61	मार्च-10
		एनआईएटीएएम का निर्माण	52.33	जनवरी-11
		11 मॉड्यूल यात्री लाउन्ज का निर्माण और संबद्ध कार्य	12.97	फरवरी-12
5.	गोवा	नए एकीकृत टर्मिनल भवन के लिए नए एप्रन का निर्माण	14.86	फरवरी-09
6.	इंदौर	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा आइसोलेटेड वे तथा टैक्सी वे का निर्माण	79.00	जुलाई-09
		नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	135.60	मई-11
7.	जलगांव	जलगांव हवाई अड्डे का विकास	61.00	दिसम्बर-11
8.	नागपुर	एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	79.00	अगस्त-08
9.	पुणे	(i) पुणे हवाई अड्डे पर मौजूद एप्रन तथा टैक्सी-ट्रैक चरण-II का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	15.42	जुलाई-08
		(ii) एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	78.00	सितम्बर-10
		(iii) पुणे हवाई अड्डे पर समानांतर टैसी वे का निर्माण	16.64	अक्तूबर-07
10.	सूरत	एटीआर-72 किस्म के विमान के लिए सूरत हवाई अड्डे का विकास-टर्मिनल भवन कार्य	53.33	जून-08
		सिटी साइड ड्रेनेज	1.18	नवम्बर-08
		सिटी साइड प्रचालनिक कम्पाउंड दीवार का निर्माण	2.02	फरवरी-09

1	2	3	4	5
		एवी 320 किस्म के विमान के लिए 2250 मीटर तक रनवे का विस्तार	21.30	अप्रैल-09
		क्षतिग्रस्त/टूटे हुए प्रचालनिक कम्पाउंड दीवार का निर्माण	2.84	अप्रैल-09
		सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरक टाइप के आवास का निर्माण	0.95	अप्रैल-09
		कार पार्क का विस्तार और सड़क आदि का चौड़ा करना	2.81	मई-09
		आईएलएस के संस्थापन के लिए सिविल तथा विद्युत कार्य	3.16	जुलाई-09
		फायर स्टेशन का स्तरोन्नयन	1.10	जुलाई-11
		टर्मिनल भवन चरण-II प्रथम मंजिल का निर्माण	23.68	दिसम्बर-09
11.	वडोदरा	संबद्ध कार्य समेत अनुरक्षण और रात्रि पार्किंग स्टैंड का निर्माण	17.12	दिसम्बर-08
दक्षिणी क्षेत्र				
1.	अगाती	अगाती पर रन वे का सुदृढ़ीकरण	11.26	नवम्बर-10
2.	कालीकट	रनवे का सुदृढ़ीकरण और संबद्ध कार्य	27.00	मार्च-'09
		एकीकृत प्रचालनों के लिए विद्युत पैकेज समेत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	89.50	फरवरी-08
3.	कोयम्बटूर	रनवे का विस्तार	42.00	अक्तूबर-07
		आंशिक समानांतर टैक्सी वे का निर्माण और एप्रन का विस्तार	41.51	फरवरी-10
		एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	78.00	सितम्बर-11
4.	कुडप्पा	रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन का निर्माण	26.12	जनवरी-10
5.	मदुरै	रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	35.25 27.83	अक्तूबर-08
		नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य	128.76	जुलाई-10
6.	मंगलौर	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	147.00	अक्तूबर-09
		नए एप्रन और टैक्सी वे का निर्माण		सितम्बर-08
		तकनीकी खंड एवं नियंत्रण टावर का निर्माण		

1	2	3	4	5
7.	मैसूर	नए रनवे का निर्माण	85.00	मार्च-08
		नए एप्रन और टैक्सी वे का निर्माण		मार्च-08
		टर्मिनल भवन का निर्माण तथा आवासीय क्वार्टर के संबंध में अन्य सहायक भवनों का निर्माण		सितम्बर-10
8.	पुदुचेरी	पुडुचेरी हवाई अड्डे का विकास	24.34	मार्च-09
		एसएच: रनवे का निर्माण		
9.	राजमुन्द्री	कार पार्क समेत नए टर्मिनल भवन का निर्माण	43.29	अक्तूबर-11
10.	त्रिची	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	74.70	अक्तूबर-08
		रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	25.94	मार्च-08
		एप्रन का सुदृढ़ीकरण, नए टैक्सी वे का निर्माण	17.76	जनवरी-08
11.	तिरूपति	रनवे, टैकसी ट्रैक, एप्रन, आइसोलेशन वे आदि का पुनः सतहीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	17.30	
		एन एप्रन का निर्माण	13.00	जून-12
12.	त्रिवेन्द्रम	अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर एयरोब्रिज का प्रावधान, एप्रन कार्य	12.35	सितम्बर-07
		त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा, तिरूवनन्तपुरम पर रनवे 14 के क्षेत्र पर आरईएसए का निर्माण	3.47	नवम्बर-07
		एसएच : आरईएसए 14 क्षेत्र में खुली नाली के स्थान पर पुर्लिया का निर्माण		
		त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम पर एयरोब्रिज का प्रावधान एसएच भवन कार्य	12.35	दिसम्बर-07
		त्रिवेंद्रम हवाईअड्डे पर एप्रन का विस्तार तथा अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	8.38	मार्च-08
		तिरूवनंतपुरम पर मौजूदा स्टार्म वाटर ड्रेन और क्रास ड्रेनेज के डायवर्जन का कार्य	6.96	मार्च-08
		8 बे, टैक्सी वे जीएसई क्षेत्र तथा शोल्डर्स का निर्माण	30.92	मई-09
		एप्रन तथा कार पार्क आदि समेत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	259.00	अप्रैल-10

1	2	3	4	5
		सब-स्टेशन 66 के वी का निर्माण	59.29	अप्रैल-10
		त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम पर एएआई की भूमि में दोनों तरफ चकईकैनाल और कार पार्क पर कनेक्टिंग आरसीसी रैम्प का निर्माण	14.65	जून-10
		त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम पर बैरक का निर्माण	4.74	सितम्बर-10
		त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरूवन्तपुरम पर चकई कैनाल साइड की ओर समानान्तर टैक्सी ट्रैक (चरण-1) का निर्माण	13.12	सितम्बर-11
		त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा तिरूवनंतपुरम में फायर स्टेशन की साइड तथा एअर इंडिया हैगर के सामने पर न्यू लिंकरोड के निर्माण समेत एनआईपीटीसी, चकई की तरफ मौजूदा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल से पैरामीटर रोड का सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करना।	5.48	मई-12
		त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा, तिरूवनन्तपुरम पर कनेक्टेड सीवरलाइन समेत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना।	1.71	जून-12
13.	विजाग	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	94.95	जून-09
		शोल्डर तथा अन्य संबद्ध कार्यों समेत नए रनवे, एप्रन, टैक्सी ट्रैक, आइसेलेशन बे का निर्माण	147.74	फरवरी-07
14.	विजयवाड़ा	टर्मिनल भवन का विस्तार		
		रनवे का विस्तार	47.87	दिसम्बर-09

विवरण-VII ,

एएआई के हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण
(कार्य प्रगति पर)

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	कार्य का नाम	ए/ए एवं ई/एस/ (करोड़ रुपए में) 30.10.2012	कार्य पूर्ण की तारीख
1	2	3	4	5
असम				
1.	गुवाहाटी	एलजीबीआई हवाई अड्डा, गुवाहाटी पर हैंगर का निर्माण	9.5%	दिसम्बर-2013

1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
2.	पोर्ट ब्लेयर	हैंगर, एनेक्सी भवन,एप्रन तथा लिंक टैकसी वे आदि का निर्माण	90%	मार्च-2013
अरूणाचल प्रदेश				
3.	तेजू	टर्मिनल भवन हवाई पट्टी, रनवे, एप्रन का निर्माण	5.1%	जून-14
आंध्र प्रदेश				
4.	कुडप्पा	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	85%	फरवरी-13
चंडीगढ़				
5.	चंडीगढ़	पएप्रन का विस्तार और संबद्ध कार्य	67%	जून-2013
		चंडीगढ़ हवाई अड्डा (मोहाली की तरफ) नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकास (क) टर्मिनल भवन	11%	फरवरी-2015
गोवा				
6.	गोवा	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	82.50%	मई-2013
गुजरात				
7.	अहमदाबाद	राज्य सरकार के हैंगर का निर्माण99%	99%	दिसम्बर-2012
8.	वडोदरा	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	13%	मार्च-2014
कर्नाटक				
9.	मंगलौर	मंगलौर हवाई अड्डा, पर एटीसी टावर तथा तकनीकी खंड का निर्माण	26%	अगस्त-2013
मध्य प्रदेश				
10.	खजुराहो	नए एकीकृत टर्मिनल भवन (जोखिम और लागत) का निर्माण	49.5%	अगस्त-2013
महाराष्ट्र				
11.	गोंदिया	रनवे तथा समानांतर टैक्सी वे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	77%	जून-2013
12.	पुणे	पुणे हवाई अड्डे पट्टा पर हैंगर तथा सीआईपी लाउंज सह प्रशासनिक भवन का निर्माण	संसाधन जुटा जा रहे हैं	सितम्बर-2013

1	2	3	4	5
मेघालय				
13.	बरापानी	बरापनी हवाई अड्डे पर नई अधिग्रहीत की गई भूमि पर वाल फेंसिंग का प्रावधान करना	39%	अक्तूबर-2013
मणिपुर				
14.	इंफाल	लिंक टैसी वे के साथ एप्रन का विस्तार	52%	मार्च-2013
		इम्फाल हवाईअड्डे पर नई अर्जित भूमि के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण	60%	अगस्त-2013
		अग्निशमन तथा संबद्ध कार्यों का निर्माण	40.25%	जून-2013
		सिक्योरिटी होल्ड एरिया का विस्तार	71%	मई-2013
ओडिशा				
15.	भुवनेश्वर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	92%	जनवरी-2013
पुदुचेरी				
16.	पुदुचेरी	कार पार्क रहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	97%	जनवरी-2013
पंजाब				
17.	अमृतसर	अमृतसर हवाई अड्डे पर रनेव 34 से शुरू करके टैक्सी वे एक तक समानान्तर टैक्सी टैक का निर्माण	23%	अक्तूबर-2013
राजस्थान				
18.	बीकानेर	टर्मिनल भवन, एप्रन तथा कार पार्क का निर्माण	91%	मई-2013
19.	जयपुर	जयपुर हवाई अड्डे पर श्रेणी-प्प प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान सहित ई श्रेणी के चौड़े आकार वाले जेट एयरक्राफ्ट के प्रचालन के लिए रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	7%	मार्च-2015
सिक्किम				
20.	पेक्यांग	पेक्यांग, सिक्किम में नए हवाई अड्डे का निर्माण (एसएच-बाक्स कल्वर्ट, एयरोडॉम पेवमेंट सहित कटिंग, फीलिंग, जियोग्रिड रिइन फोर्स्ड रिटेनिंग वाल, ड्रेनेज में भू संबंधी कार्य आदि)	65%	दिसम्बर-2014

[अनुवाद]

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर भूमि की नीलामी/पट्टा

2038. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री पी. करूणाकरन :
श्री गणेश सिंह :
श्री खगेन दास :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री हरि मांझी :
श्री रमेश बैस :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली पर महत्वपूर्ण भूमि की नीलामी/पट्टा किसी प्राइवेट ऑपरेटर को देने से सरकार को बड़ी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा सरेआम किए जा रहे उल्लंघन और गलत तरीकों से लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप सरकार/ए.ए.आई. को कितनी हानि हुई है;

(घ) उन कंपनियों के नाम और ब्यौरा क्या है जिन्हें भूमि बहुत ही कम धनराशि पर दी गई है तथा किस तारीख से दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई जांच करने और समझौते की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों को उच्च दर पर भूमि का आबंटन करने के क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं। दिल्ली हवाई अड्डे के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संसद के पटल पर रखी गई अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.6 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिमत दिया है कि "दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) द्वारा 681.63 करोड़ रुपये प्रति एकड़ भी संभावित आय के लिए अपने स्वयं के प्रक्षेपण का इस्तेमाल करते हुए, 58 वर्ष तक 240 एकड़ भूमि के लिए यह धन राशि 1,63,557 करोड़ रुपये बनती है। इस धन राशि का 45.99 प्रतिशत, जो 75,220 करोड़ रुपये बनता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का हिस्सा होगा। 10 प्रतिशत की रियायत दर पर इसका निवल वर्तमान मूल्य 3566 करोड़ रुपये बनता है। डायल का हिस्सा 88337 करोड़ रुपये बनेगा जिसका निवल वर्तमान मूल्य 4187 करोड़ रुपये है।"

(घ) दिल्ली हवाई अड्डे की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण का कार्य पी.पी.पी. मॉडल, के तहत मैसर्स डायल नाम एक संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंपा गया है। उक्त हवाई अड्डे को 30 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी को लीज पर दिया गया है जो आगे 30 वर्ष तक विस्तारणीय है। निजी भागीदार का चयन अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। बोली का एकमात्र मापदंड उच्चतम राजस्व हिस्सदारी था, जिसके दायरे में वाणिज्यिक विकास के लिए सौंपी गई भूमि की अर्जन संभाव्यता भी आती है। तथापि, लीज संबंधी विलेख (लीज डीड) 100 रुपये के स्टांप पेपर पर संपादित किया गया था।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) करार के नियमों एवं शर्तो का उल्लघंन नहीं हुआ है।

अध्यापकों की कमी

2039. **श्री संजय दिना पाटील :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जगदीश शर्मा :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री रमाशंकर राजभर :

श्री पी.सी. मोहन :

श्री हमदुल्लाह सईद :

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या मानव संसाधन विकास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के ग्यारह लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्यापकों की अत्यधिक कमी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में एक बाधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (च) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तक शिक्षकों के कुल 19.82 लाख पद संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 12.48 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है, और 7.34 लाख पद रिक्त बचे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मार्च 2012 के अंत तक राज्य बजट के अंतर्गत शिक्षकों के 5,65,905 पद रिक्त होने की सूचना दी है। राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा शिक्षकों की रिक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों पर जोर डाला है कि शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाएं और वर्तमान शिक्षकों का पुनर्नियोजन करें ताकि सभी स्कूलों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2009 में यथा निर्धारित शिष्य-अध्यापक अनुपात सुनिश्चित किया जा सके। अध्यापकों की भर्ती के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजित की है। भारत सरकार ने आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत 13 राज्यों के संबंध में शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता में रियायत को मंजूरी दी है, क्योंकि इन राज्यों में कक्षा-I से VIII तक के अध्यापकों की मांग के मुकाबले अध्यापकों को तैयार करने की क्षमता अपर्याप्त थी।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.एस.ए. के अधीन संस्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्त पद	31 मई, 2012 की स्थिति के अनुसार राज्य बजट के अंतर्गत शिक्षक पदों के मुकाबले सूचित खाली पद
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	870	15379
2.	अरूणाचल प्रदेश	2036	0
3.	असम	10444	13757
4.	बिहार	211430	55464
5.	छत्तीसगढ़	12522	50766
6.	गोवा	20	86
7.	गुजरात	27352	0
8	हरियाणा	7090	13906
9.	हिमाचल प्रदेश	2303	1009
10.	जम्मू और कश्मीर	3732	5438
11.	झारखंड	35724	23656
12.	कर्नाटक	4777	15336
13.	केरल	2925	88
14.	मध्य प्रदेश	75568	16244

1	2	3	4
15.	महाराष्ट्र	33569	6729
16.	मणिपुर	1327	0
17.	मेघालय	.758	0
18.	मिजोरम	1182	0
19.	नागालैंड	2557	7
20.	ओडिशा	1459	23679
21.	पंजाब	6658	19161
22.	राजस्थान	19931	32622
23.	सिक्किम	501	0
24.	तमिलनाडु	10717	14495
25.	त्रिपुरा	1286	0
26.	उत्तर प्रदेश	164629	147593
27.	उत्तराखंड	8318	7746
28.	पश्चिम बंगाल	82456	98473
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48	125
30.	चंडीगढ़	605	109
31.	दादरा और नगर हवेली	411	294
32.	दमन और दीव	24	145
33.	दिल्ली	2762	3006
34.	लक्षद्वीप	22	40
35.	पुदुचेरी	12	552

एयरलाइन के लाइसेंस निलंबित करना

2040. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :

श्री एंटो एंटोनी :

श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसी एयरलाइन का प्रचालन लाइसेंस निलंबित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन यात्रियों जिन्होंने इन एयरलाइनों में अपनी सीटें बुक करायी थीं और इन एयरलाइनों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वैश्विक मानक एवं प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए नागर विमानन क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (घ) जी हां। मैसर्स किंगफिशर एयरलाइन, एक अनुसूचित प्रचालक का सुरक्षित, कार्यक्षम तथा भरोसेमंद विमान परिवहन सेवाएं पुनर्स्थापित न करने के कारण इस कंपनी का प्रचालक परमिट 20.10.2012 से रद्द कर दिया गया।

(ग) और (घ) एयरलाइन को यह कहा गया कि सभी यात्रियों के रद्दीकरण के संबंध में अग्रिम सूचना दी जाए तथा उनके किराये की राशि वापस करने के मामले को तत्काल निपटाया जाए। एयरलाइन को यह भी कहा गया कि एक ठोस तथा भरोसेमंद पुनरूद्धार योजना जो डी.जी.सी.ए. के संतोष के अनुरूप हो, प्रस्तुत की जाए।

(ङ) नागर विमानन एक गतिशील सेक्टर है, जिसमें वैश्विक तथा घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर समायोजन करना अपेक्षित है। सरकार लगातार बदलते परिदृश्य के अनुसार कार्य कर रही है तथा सेक्टर के विकास के लिए सेक्टर संबंधी विशेष उपाय कर रही है।

तकनीकी शिक्षा में कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रवेश

2041. **श्री ए. साई प्रताप :**
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री जोस के. मणि :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कारोबार करने वाली सरकारी/निजी लिमिटेड कंपनियों एवं उद्योगों को अपने कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति देने कां निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.आई.सी.टी.ई. ने इस बारे में आवेदकों द्वारा पालन किए जाने हेतु मानदण्ड एवं प्रक्रिया का ब्यौरा देते हुए कोई अधिसूचना जारी की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन कंपनियों की संख्या क्या है जो इस अवसर का लाभ उठाने एवं अपना कॉलेज शुरू करने हेतु आगे आई हैं;

(ङ) क्या उक्त निर्णय से ऐसे उद्योग रक्षित संस्थानों से स्नातक होने वाले विद्यार्थी उद्योग के लिए तैयार एवं तुरंत रोजगार पर रखने योग्य बन जाएंगे तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने अपने उक्त निर्णय से कार्पोरेट क्षेत्र को अवगत कराया है और उच्च तकनीकी शिक्षा में उनके निवेश करने की उत्सुकता का आकलन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने पिछले तीन वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली सरकारी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/उद्योगों को इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, वास्तुकला, नगर योजना, होटल प्रबन्धन तथा खानपान प्रौद्योगिकी में नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु अनुमति दी है। ऐसी संस्थाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2013-14 के अध्याय-1 में दिए गए अनुसार नियमों द्वारा अभिशासित होंगी। अनुमोदन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2013-14 में दी गई है जो कि वेबसाइट www.aicte-india.org पर उपलब्ध है।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इस योजना के अंतर्गत कॉलेज स्थापित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.12.2012 है।

(ङ) से (छ) विभिन्न कालेजों में तकनीकी शिक्षा, जिस किसी भी विषय में दी जाती है, का उद्देश्य उद्योग में सभी स्तरों पर विभिन्न विधाओं में अर्थपूर्ण रोजगार प्रदान करना होता है। इस प्रकार सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिसे छात्रों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में उनके चार वर्षीय कार्यक्रम के जरिए प्रदान किया जाता है, पाठ्यचर्या की तुलना में समसामयिक होना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि पाठ्यचर्या तैयार करने में उद्योग की अन्त: कार्रवाई केवल उद्योग के कुछेक विशेषज्ञों द्वारा सहयोग देने के दृष्टिकोण और अंतिम वर्ष के स्तर पर उद्योग द्वारा दी गई कुछ परियोजनाओं तक ही सीमित कर दी गई है। इस प्रकार उद्योग आधारित संगठनों से विभिन्न रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनमें छात्रों को प्रदान की जाने वाली तकनीकी शिक्षा में पर्याप्त कौशलों की कमी होने के बारे में टिप्पणियां की गई हैं जिसमें नियोजनीयता में कमी आई है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने पाठ्यचर्या की समीक्षा की है और उद्योग की उत्तम प्रक्रियाओं को शामिल करने हेतु मॉडल पाठ्यचर्या तैयार की है। स्टेक-होल्डरों की सुविधा के लिए मॉडल पाठ्यचर्या ए.आई.सी.टी.ई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एयर इंडिया के पायलटों और अन्य कर्मचारियों को वेतन

2042. **श्री हमदुल्लाह सईद :**
श्री ए. टी. नाना पाटील :
श्रीमती मेनका गांधी :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने कुछ पायलटों, स्टाफ और सब-स्टाफ का वेतन/भुगतान अभी तक रोक रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने इस संबंध में अपनी चिन्ता वक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सभी देयों के साथ भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है और इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(च) सभी कर्मचारियों को उनके देय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने और इस प्रकार के विलंब की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) एयर इंडिया ने अक्तूबर, 2012 तक अपने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया है। लाइसेंसशुदा श्रेणी के कर्मचारियों को जून, 2012 (जो जूलाई, 2012 में देय था) तक पी.एल.आई. का भुगतान कर दिया गया है। लाइसेंसशुदा श्रेणी के कर्मचारियों को जुलाई, 2012 और इसके बाद का उड़ान तथा अन्य भत्तों का भुगतान अभी किया जाना है। गैर-लाइसेंसशुदा श्रेणी के कर्मचारियों को जून 2012 (जो जुलाई, 2012 में देय था) की पी.एल.आई. का भुगतान अभी किया जाना है। सभी श्रेणी के कर्मचारियों की पी.एल.आई. जो जुलाई, 2012 से प्रभावी है, को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, लाइसेंसशुदा श्रेणी के कर्मचारियों को उड़ान भत्ता, इंजीनियरी भत्ता सहित कुछ और भत्तों का भुगतान सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ ने प्रबंधन को पत्र लिखे हैं, जिनमें वेतन तथा भत्तों के भुगतान में हो रही देरी पर चिन्ता जताई गई है। पायलटों के मासिक प्रतिकर में वेतन तथा अन्य उड़ान संबंधी भत्ते शामिल हैं। उक्त कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट के बावजूद, कुछ भुगतान प्रतिमाह जारी करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पायलटों को अक्टूबर माह, 2012 तक के तथा जून, 2012 तक के उड़ान भत्तों का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) कर्मचारियों को समय पर देय राशि का भुगतान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन खाते में कोई बकाया राशि देय नहीं है। एयर इंडिया के पास निधि उपलब्ध होते ही पी.एल.आई./भत्तों का भुगतान कर दिया जाएगा।

(च) सरकार ने एयर इंडिया की टर्न अराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना को दिनांक 12.04.2012 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके भाग के रूप में, एयर इंडिया को समयावधि फ्रेश में इक्विटी इंफ्यूजन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग इसकी उधार राशियों को चुकाने में किया जाएगा। वित्तीय स्थिति सुधारने के साथ, आशा है कि वेतन का भुगतान नियमित रूप से होगा।

[हिन्दी]

विमान सेवाओं का प्रसार

2043. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री घनश्याम अनुरागी :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री यशवंत लागुरी :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह माह के दौरान सरकारी और निजी विमान कंपनियों (एयरलाइनों) द्वारा कितने नए घरेलू विमान मार्ग शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या देश के सभी मुख्य शहर विमान सेवा से जोड़े गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को देश के विभिन्न स्थानों विशेषकर इलाहाबाद से नई उड़ानें शुरू करने के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस उद्देश्य हेतु यदि नए मार्गों को चिन्हित किया गया है तो स्थान-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सेवाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): (क) विगत छह माह के दौरान सार्वजनिक तथा निजी एयरलाइनों द्वारा शुरू किए गए नए घरेलू विमान मार्गों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (छ) जी, हां। सभी राज्यों की राजधानियों (अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम को छोड़कर) तथा इलाहाबाद सहित प्रमुख शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ा गया है। सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं को ध्यान में रखकर विनियमन को बेहतर बनाने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकों को श्रेणी-II (जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं) में श्रेणी-I में मार्गों पर और क्षमता में उनके द्वारा अभिनियोजित क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत अभिनियोजन करना होता है। अत: श्रेणी के मार्गों पर उनकी प्रचालित सेवाओं का सेगमेंट में अनन्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में कम से कम 10 प्रतिशत अभिनियोजित करना होगा। तथापि, यह निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमानसेवाएं उपलब्ध कराएं। अत: एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए देश में कहीं से विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण-I

पिछले 06 महीनों में नए घरेलू विमान मार्ग

एअर इंडिया	चेन्नै-पुणे-चेन्नै
	श्रीनगर-दिल्ली-मुम्बई-गोवा
	दिल्ली-मुम्बई-मंगलौर
एलायंस एयर	कोचीन-मदुरै-कोचीन (28.10.2012 से सेवा वापस ली गई)
इंडिगो	:हैदराबाद-पुणे-हैदराबाद
	मुम्बई-चंडीगढ़-मुम्बई
गो एयर	मुम्बई-चेन्नै-मुंबई
	चेन्नै-पोर्ट ब्लेयर-चेन्नै
	चेन्नै-पुणे-चेन्नै
	बंगलौर-गोवा-बंगलौर
	मुंबई-लखनऊ-मुंबई
	दिल्ली-अहमदाबाद
जेट एयरवेज एवं जेटलाइट	चेन्नै-पुणे-चेन्नै
	भोपाल-लखनऊ-भोपाल
	कोलकाता-वाराणसी-कोलकाता
	बंगलौर-विशाखापत्तनम-बंगलौर
	कोलकाता-विशाखापत्तनम-कोलकाता
	नागपुर-भोपाल
स्पाइस जेट	दिल्ली-अमृतसर-दिल्ली
	दिल्ली-चंडीगढ़-दिल्ली
	दिल्ली-देहरादून-दिल्ली

	बंगलौर-हुबली
	चेन्नै-पोर्ट ब्लेयर-चेन्नै
	कोलकाता-पोर्ट ब्लेयर-कोलकाता
	दिल्ली-जबलपुवर-दिल्ली
	मुंबई-जबलपुर-मुंबई
	बंगलौर-बेलगांव
मंत्रा	अमृतसर-चंडीगढ़-अमृतसर
	अमृतसर-चंडीगढ़-जम्मू-चंडीगढ़-अमृतसर

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

2044. श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" योजना के अंतर्गत कवर किए गए देश में राज्य-वार सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) इस योजना से लाभान्वित हुए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित निर्धन विद्यार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस केंद्र प्रायोजित योजना "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)" के अंतर्गत कितने शहरी/ग्रामीण विद्यार्थी लाभान्वित हुए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर जारी की जाती हैं। मंत्रालया ने आज की तिथि तक इस योजना के अंतर्गत 96007 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कवरेज को अनुमोदित किया है। राज्य-वार स्कूलों का ब्यौरा सूचक विवरण-III में दिया गया है। कम्प्यूटर की सहायता से अध्ययन शीर्षक से एक अलग कार्यक्रम 6-14 वर्ष की आयु समूह के छात्रों के लिए उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यान्वयनाधीन है। आज की तिथि तक कम्प्यूटर की सहायता से अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 99369 उच्च प्राथमिक स्कूल शामिल किए गए हैं (राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।)

(ख) इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों की बहुलता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आवंटन आरंभ किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों की कवरेज के लिए 7000.00 लाख रुपये की राशि और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 3745.00 लाख रुपये की राशि अलग-अलग उद्दिष्ट की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संख्या में छात्र (शहरी और ग्रामीण दोनों) लाभान्वित हुए हैं :-

2009-10	-	2869742
2010-11	-	12617362
2011-12	-	7941933
2012-13 (आज की तिथि तक)	-	416333

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य-वार स्कूलों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	अनुमोदित स्मार्ट स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		-	12	-	14	-	28	-		-
आंध्र प्रदेश	500	-	200	5000	2000	-	4031	-		05
अरूणाचल प्रदेश		154	-	35	-	55	24	-		-
असम		-	-	641	-	-	1240	969		-
बिहार		180	-	1000	-	-	-	-		-
चंडीगढ़		-	20	67	-	-	-	-		-
छत्तीसगढ़		-	100	200	800	1100	-	-		-
दादरा और नगर हवेली		-	06	06	-	-	13	01		02
दमन और दीव		15	-	22	-	-	08	-		02
दिल्ली		-	-	-	-	-	594	1110		-
गोवा		230	-	432	-	-	-	-		-
गुजरात		-	-	1150	2500	2730	-	-		-
हरियाणा		100	-	500	1000	1000	1617	-		-
हिमाचल प्रदेश			-	-	628	-	618	848		05
जम्मू और कश्मीर		140	-	-	-	200	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
झारखंड		–	–	1074	–	–	–	–		–
कर्नाटक	150	480	–	2279	4396	–	–	–		–
केरल		125	–	1016	3055	–	–	–		05
लक्षद्वीप		–	12	–	–	–	–	–		–
मध्य प्रदेश		230	–	320	–	2000	–	2000		–
महाराष्ट्र		–	200	500	2500	–	–	5000		–
मणिपुर		–	–	65	–	–	260	–		04
मेघालय		–	–	75	75	100	241	164		04
मिजोरम		60	–	–	100	–	37	181		04
नागालैंड		53	147	284	–	–	82	–	121	04
ओडिशा		200	–	–	–	–	4000	–	2000	–
पुदुचेरी		–	25	169	–	–	–	182		04
पंजाब		200	–	–	2000	870	494	–	134	05
राजस्थान		100	–	2500	2000	–	2000	–		–
सिक्किम		103	–	02	–	–	46	–		04
तमिलनाडु		125	–	400	400	1880	461	1999		05
त्रिपुरा		–	200	400	282	–	282	–		–
उत्तर प्रदेश		–	200	2500	1500	–	1500	1608		05
उत्तराखंड		25	–	100	–	–	500	–		–
पश्चिम बंगाल		200	–	343	1400	–	2000	–		05
कुल	650	2720	1110	21080	24650	9935	19482	14062	2255	63

विवरण-II

केन्द्र प्रायोजित कम्प्यूटर की सहायता से अध्ययन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शामिल किए गए उच्च प्राथमिक स्कूलों का ब्यौरा

क्र.सं.	ब्लॉक/नगर निगम क्षेत्र	उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2010-11 तक सी.ए.एल. के तहत शामिल किए गए स्कूल	2011-12 के दौरान शामिल किए गए नए स्कूल	आज की तिथि तक कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	161	43	39	82
2.	आंध्र प्रदेश	33871	2487	1680	4167
3.	अरूणाचल प्रदेश	1160	531	425	956
4.	असम	14428	2179	1380	3559
5.	बिहार	23953	620	619	1239
6.	चंडीगढ़	159	77	21	98
7.	छत्तीसगढ़	17397	1880	288	2168
8.	दमन और दीव	124	12	0	12
9.	दादरा और नगर हवेली	59	46	13	59
10.	दिल्ली	2409	970	970	1940
11.	गोवा	436	105	116	221
12.	गुजरात	28876	5188	14856	20044
13.	हरियाणा	8806	1427	5567	6994
14.	हिमाचल प्रदेश	6005	602	797	1399
15.	जम्मू और कश्मीर	11377	470	0	470
16.	झारखंड	15725	575	260	835
17.	कर्नाटक	31982	3280	335	3615
18.	केरल	5736	1215	0	1215

1	2	3	4	5	6
19.	लक्षद्वीप	24	21	3	24
20.	मध्य प्रदेश	43761	3441	3441	6882
21.	महाराष्ट्र	47067	4446	805	5251
22.	मणिपुर	1537	225	0	225
23.	मेघालय	3496	198	0	198
24.	मिजोरम	1387	495	140	635
25.	नागालैंड	1026	345	346	691
26.	ओडिशा	21508	2418	1800	4218
27.	पुडुचेरी	393	125	268	393
28.	पंजाब	9110	4558	0	4558
29.	राजस्थान	55497	6650	2508	9158
30.	सिक्किम	412	108	0	108
31.	तमिलनाडु	20588	5688	810	6498
32.	त्रिपुरा	1913	35	0	35
33.	उत्तर प्रदेश	62764	4844	1550	6394
34.	उत्तराखंड	6783	2020	419	2439
35.	पश्चिम बंगाल	13865	2149	440	2589
	कुल	493795	59473	39896	99369

विवरण–III

विद्यालयों में केन्द्रीय प्रायोजित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17.25	67.2	67.2	67.2

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	0	6600	6923.5	3487.5
अरूणाचल प्रदेश	105.52	645.59	584.37	69.12
असम	0	641	2182.4	2483.44
बिहार	0	0	0	0
चंडीगढ़	182.75	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	31.2	31.2	0
दमन और दीव	0	14.4	18.75	0
दिल्ली	0	399	639.98	0
गोवा	432	432	0	0
गुजरात	1871.78	6915.57	5107.649	0
हरियाणा	1500	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	753.6	2205.68	
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	6229.48755	0
केरल	4071	2600	5562	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0
महाराष्ट्र	2250	0	0	0
मणिपुर	391.95	65.65	0	0
मेघालय	0	386.59	20	0
मिजोरम	301.5	408.06	672.84	0

1	2	3	4	5
नागालैंड	111.21	486.82	542.673	348.48
ओडिशा	0	0	400	4000
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	4305	4603	2890	7291.3595
राजस्थान	2300	4500	0	6000
सिक्किम	0	418.97	0	0
तमिलनाडु	318.72	0	4360	0
त्रिपुरा	0	946.32	927.723	184.977
उत्तर प्रदेश	0	3984.82581	6268.174	4302.7275
उत्तराखंड	151.5	500	0	0
पश्चिम बंगाल	0	3500	3646.83792	0
कुल	18310.18	38899.79581	49280.46447	28234.804

[अनुवाद]

विमानपत्तनों में सुरक्षा चूक

2045. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

श्री अब्दुल रहमान :

श्री ए. साई प्रताप :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न विमानपत्तनों में सुरक्षा चूक के मामलों का विमानपत्तन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राधिकरणों द्वारा इस संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समीक्षाओं के दौरान क्या कमियां पाई गई;

(घ) क्या बी.सी.ए.एस. ने सरकार से विमानपत्तन में प्रवेश अनुमति/वी.आई.पी. नयाचार को पास एवं दूतावास के कार्मिकों द्वारा जारी अंतरणीय पास सहित स्थाई पासों के प्रचलन को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों और दूतावास के पदाधिकारियों को जारी पासों की संख्या क्या है;

(च) क्या इस प्रणाली को बदलने के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विमानन सुरक्षा के लिए बी.सी.ए.एस. के पुनर्गठन और समुचित प्रचालन के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान घुसपैठ तथा अन्य मामलों की श्रेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	हवाई अड्डा क्षेत्रवार	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर तक)
1.	मुंबई क्षेत्र	1	2	–	–
2.	दिल्ली क्षेत्र	–	5	1	3
3.	कोलकाता क्षेत्र	6	6	3	–
4.	चेन्नई क्षेत्र	2	6	5	–

(ख) और (ग) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) की कार्य प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। हाल ही में, भारत में विमानन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर व्यापक अध्ययन करने और बी.सी.ए.एस. की पुनर्संरचना के लिए सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के अध्ययन दल को लगाया गया है। अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ एक समर्पित विमानन सुरक्षा बल के गठन और जन शक्ति की भारी कमी को पूरा करने के लिए बी.सी.ए.एस. की पुनर्संरचना किए जाने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। सरकारी तथा दूतावास के प्राधिकारियों को जारी किए गए कुल पास 1486 है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लेख किए अनुसार।

[हिन्दी]

आर.टी.आई. के अंतर्गत सूचना को प्रस्तुत न करना

2046. **श्रीमती ऊषा वर्मा :**
श्री महेश जोशी :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत समय पर सूचना प्रस्तुत न करने संबंधी शिकायतों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिकॉर्डों की अनुपलब्धता के कारण कितने मामलों में सूचना प्रदान नहीं की जा सकी;

(घ) क्या समय पर सूचना प्रस्तुत न करने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित किया गया;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन मामलों जिनमें रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) किसी व्यक्ति, जिसके, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई हो, उसके संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग की यह ड्यूटी है कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत प्राप्त होने पर जांच करे।

(ग) आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) 2007-08 से केंद्रीय सूचना आयोग ने 20.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार सूचना प्रदान न किए जाने

के 853 मामलों में 160232.75/- रुपए की शास्ति लगाई थी जिसमें से 9767589/- रुपए की धनराशि वसूल की गई है।

(च) लोक सूचना अधिकारी उसके नियंत्रणाधीन धारित सूचना, प्रदान करने के लिए बाध्य है।

नवोदय विद्यालय

2047. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री संजय निरूपम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय (एन.वी.) कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक नवोदय विद्यालय खोलने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये राज्य-वार किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे और इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का नवोदय विद्यालयों में वैसी ही सुविधाएं देने का विचार है, जैसी कि केंद्रीय विद्यालयों मे दी गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) तमिलनाडु राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों में 586 जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.वी.) कार्य कर रहे हैं। राज्यवार कार्यात्मक जवाहर नवोदय विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान पांच नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे, वर्ष 2010-11 में दो नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे और वर्ष 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान कोई नया जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है।

(ग) और (घ) नए जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए बारहवीं योजना के प्रस्तावों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) नवोदय विद्यालय आवासीय स्कूल हैं और उन्हें भोजन व्यवस्था, आवास, पुस्तकें, वर्दी इत्यादि जैसी अपेक्षित सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं। अत: इनकी तुलना केंद्रीय विद्यालयों से नहीं की जा सकती हैं।

विवरण

राज्यवार कार्यात्मक जवाहर नवोदय विद्यालय

क्र.सं.	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	50
2.	छत्तीसगढ़	17
3.	ओडिशा	31
4.	पंजाब	21
5.	हिमाचल प्रदेश	12
6.	जम्मू और कश्मीर	17
7.	चंडीगढ़	1
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
9.	आंध्र प्रदेश	24
10.	कर्नाटक	28
11.	केरल	14
12.	पुदुचेरी	4
13.	लक्षद्वीप	1
14.	हरियाणा	20

1	2	3
15.	दिल्ली	2
16.	राजस्थान	33
17.	उत्तर प्रदेश	68
18.	उत्तराखंड	13
19.	बिहार	39
20.	झारखंड	24
21.	पश्चिम बंगाल	18
22.	महाराष्ट्र	33
23.	गुजरात	23
24.	गोवा	2
25.	दमन और दीव	2
26.	दादरा और नगर हवेली	1
27.	अरूणाचल प्रदेश	16
28.	असम	27
29.	मेघालय	8
30.	मणिपुर	9
31.	मिजोरम	7
32.	नागालैंड	11
33.	सिक्किम	4
34.	त्रिपुरा	4
	कुल	586

[अनुवाद]

नाभिकीय और विकिरण सुरक्षा नीति

2048. श्री ओ.एस. मणियन :
श्री धनंजय सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री यशवीर सिंह :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यरत और बंद पड़े नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से विकिरण के लीक होने के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विकिरण लीकेज को रोकने के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई राष्ट्रीय स्तर की नाभिकीय और विकिरण सुरक्षा नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) नाभिकीय और विकिरण दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों और उल्लंघन के लिए विद्यमान दंडों/जुर्मानों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का दंडों/जुर्मानों जो निवारक के रूप में कार्य करते हैं को बढ़ाने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) देश के नाभिकीय विनियामक को सौंपी गई विधिक शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रचालनरत और शट-डाउन किए गए किसी भी नाभिकीय विद्युत रिएक्टर से न तो पर्यावरण में और न ही सार्वजनिक प्रक्षेत्र में निर्धारित सीमा से अधिक विकिरण के उत्सर्जित होने की कोई घटना हुई है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि विकिरण का उत्सर्जन निर्धारित सीमा के भीतर और अभिकल्पित मार्गों के माध्यम से किया गया है।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर. बी.) द्वारा विनियमित नाभिकीय और विकिरण सुरक्षा से संबंधित नीतियों का उल्लेख परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के उच्च स्तरीय दस्तावेजों नामतः परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004, मिशन विवरण और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की 'संहिता' में किया गया है। इन दस्तावेजों में उन नीतियों, सिद्धांतों और/अथवा सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जोकि संगत कार्यकलाप/क्षेत्र पर लागू होते हैं और विशिष्ट विनियामक अपेक्षाएं जिनका उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसरण किया जाना है, शामिल हैं। उपर्युक्त मिशन, सिद्धांत और उद्देश्य देश में नाभिकीय और विकिरण सुरक्षा का विनियमन करने के लिए अपेक्षित परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की एक अपेक्षाकृत विस्तृत नीति का निर्माण करते हैं।

(ङ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30(3) के अनुसार, "इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम यह उपबंध कर सकते हैं कि नियमों का उल्लंघन, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा"। तथापि, इस अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, धारा 17 (सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध) के अंतर्गत किसी नियम का उल्लंघन करने की स्थिति मे पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कैद अथवा जुर्माने के साथ अथवा दोनों दंड दिए जाएंगे।

(च) और (छ) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 24 और धारा 30 (3) में नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं में अपराध करने और उनका उल्लंघन करने के प्रति शास्ति देने का प्रावधान किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के पास अलग-अलग किस्म की कार्रवाई करने का प्रावधान उपलब्ध है। ये प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयां गैर-अनुपालन की गंभीरता और लिखित चेतावनी से लेकर सहमति को वापिस लेने/निलंबित करने के अनुरूप होंगी। सहमति को वापिस लेना अपने आप में ही एक बहुत गंभीर आर्थिक शास्ति है और इसमें पनधारक की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करने की क्षमता है।

(ज) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के पास परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16,17 और 23 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत परिकल्पित कतिपय विनियामक और सुरक्षा संबंधी कार्यों को निष्पादित करने की विधायी शक्तियां हैं।

- परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यकरण, खनिज और विहित पदार्थ का हस्तन) नियम, 1984
- परमाणु ऊर्जा (विकिरणसक्रिय अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987
- परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम, 1996
- परमाणु ऊर्जा (खाद्य किरणन का नियंत्रण) नियम, 1996
- परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद को पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10(1) (प्रवेश की शक्ति) और 11 (1) (नमूने लेने की शक्ति) और पर्यावरणीय संरक्षण (संशोधन) नियम, 1987 के नियम 12 (जिस एजेंसी को प्रदूषकों की अतिरिक्त मात्रा के उत्सर्जन के बारे में सूचना दी जानी है) के अंतर्गत विकिरणसक्रिय पदार्थों के संबंध में कार्यों को निष्पादित करने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

अलवणीकरण संयंत्र

2049. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री अनंत कुमार :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार द्वारा स्थापित निम्न तापमान वाले तापीय अलवणीकरण संयंत्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक संयंत्र की क्षमता, उनके शुरू होने का वर्ष और परियोजना लागत क्या;

(ख) क्या पेयजल की कमी को दूर करने के लिए कुछ और अलवणीकरण संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सौर-ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री पानी का बड़े पैमाने पर अलवणीकरण कार्य करने का भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) देश में चार निम्न तापमान वाले तापीय विलवणीकरण (एल.टी.टी.डी.) संयंत्र चालू किए जा चुके हैं, जिनमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह के कावराती (2005), मिनीकॉय (2001), अगात्ती (2001), में एक-एक संयंत्र और उत्तरी चेन्नै के तापीय विद्युत स्टेशन (एन.सी.टी.पी.एस.), चेन्नै (2008) में लगाया गया एक संयंत्र शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक एल.टी.टी.डी. संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन एक लाख लीटर स्वच्छ जल तैयार करने की है। कावराती में लगाए गए एल.टी.टी.डी. संयंत्र की पूंजीगत लागत 5 करोड़ रु. मिनीकॉय में लगाए गए एल.टी.टी.डी. संयंत्र की पूंजीगत लागत 13 करोड़ रु. अगाती में लगाए गए एल.टी.टी.डी. संयंत्र की पूंजीगत लागत 21 करोड़ और एन.सी.टी.पी.एस. में लगाए गए संयंत्र की पूंजीगत लागत 5 करोड़ रु. थी।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु के तूतीकोरिन तापीय विद्युत स्टेशन में प्रतिदिन 2 मिलीयन लीटर पेयजल (2 एम.एल.डी.) का उत्पादन करने की क्षमता वाले एक एल.टी.टी.डी. संयंत्र की स्थापना किए जाने और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल का उत्पादन करने की क्षमता वाले छह एल.टी.टी.डी. संयंत्र अर्थात् अमीनी, चेत्लेट, कड़मठ, कल्पेनी, किल्तन और एंड्रोथ में एक-एक संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए निधि लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी।

(घ) और (ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकाय राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) द्वारा तमिलनाडु के रामानाथापुरम में एक प्रायोगिक सोलर-बहु प्रभावी आसवन संयंत्र (एम. ई.डी.) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन पर प्रतिबंध

2050. **श्री के. सुधाकरण :**
श्री पी. लिंगम :
श्री राकेश सिंह :
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें शामिल करने के लिए मांग की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आर.टी.आई. अधिनियम दायरा को सीमित करने या कम करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, गैर-सरकारी बैंकों, गैर-सरकारी निगमों, सार्वजनिक गैर सरकारी साझेदारी परियोजनाओं, जनसंचार माध्यमों, शिक्षा संस्थाओं आदि को लाने के लिए विभिन्न पक्षों और सूचना के अधिकार कार्यकत्ताओं से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2(छ) के अंतर्गत यथा परिभाषित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकारियों पर लागू है जिसमें सरकार के स्वामित्व वाले, इसके द्वारा नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय और समुचित सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पर्याप्त वित्त पोषित और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार, गैर-सरकारी निकाय से संबंधित कोई सूचना जिस पर, फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की पहुंच है, पहले से ही सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्षेत्राधिकार में शामिल है।

(घ) और (ङ) गैर सरकारी संस्थाओं के संबंध में सूचना के अधिकार के दायरे को सीमित अथवा कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रशासन पर भ्रष्टाचार का प्रभाव

2051. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार ने समूचे प्रशासनिक कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप प्रकाश में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भ्रष्टाचार के प्रभाव के कारण देश की छवि को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भ्रष्टाचार प्रजातंत्रा और कानून के नियम को कमजोर बनाता है, मानव अधिकारिों का उल्लंघन करता है, बाजारों को विकृत करता है और जीवन की गुणवत्ता को नष्ट करता है। भ्रष्टाचार विकास के लिए चिह्नित निधियों का पथांतरित करके, मूलभूत सेवाएं प्रदान करने की सरकार की योग्यता को कम करके, असमानता और अन्याय को बढ़ावा देकर निर्धनों को अननुपातिक तौर पर नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार तीव्र विकास में बाधा है, यह हमारे सामाजिक कार्यों में हमारे प्रयास को केवल कमजोर ही नहीं करता बल्कि नकारता भी है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करता है।

(ख) भ्रष्टाचार वहां पनपता है जहां पारदर्शिता में कमी हो, पद्धतियां जटिल हों, उच्च स्तर पर विवेकाधिकार की अनुमति हो तथा जहां मांग-आपूर्ति में अंतर हो। केंद्र सरकार अधिक से अधिक पारदर्शिता लाकर, सरलीकृत पद्धतियों को आरंभ करके तथा विवेकाधिकार दायरे में कमी करके इन स्थितियों को सुलझा रही है।

(ग) और (घ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के रैंक के पदाधिकारियों के विरुद्ध 109 मामले (81 नियमित मामले और 28 प्रारंभिक जांच पड़तालें) दर्ज किए हैं। भ्रष्टाचार/प्रारंभिक जांच पड़ताल मामले, संविदाओं, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले, ट्रैप मामले और आपराधिक कदाचार आदि के संबंध में अनियमितताओं के आरोप दर्ज किए गए हैं। इन मामलों के अतिरिक्त सीबीआई के पास केई महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009 से 2012 (31.10.2012 तक) के दौरान निम्नलिखित प्रकार के उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं :-

(i) 2जी मामले (3 नियमित मामले और 1 जांच पड़ताल)

(ii) सीडब्ल्यू जी मामले (19 नियमित मामले और 10 जांच पड़ताल)

(iii) एनआरएचएम मामले (20 नियमित मामले और 5 जांच पड़ताल)

(iv) टट्रा ट्रक मामले

(v) कोल ब्लॉक मामले (9 नियमित मामले और 3 जांच पड़ताल)

(vi) लौह अयस्क मामले (12 नियमित मामले)

(vii) आदर्श सोसायटी मामले इत्यादि

(ङ) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है और यह सरकार का प्रयास है कि वह समय-समय पर अपना भ्रष्टाचार निरोधी कानून और अन्य तंत्र को सुदृढ़ करे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि भ्रष्ट को उसके दर्जे का ध्यान दिए बिना प्रभावी और शीघ्र दंडित किया जाए। भ्रष्टाचार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में कई विधानों को पुर:स्थापित किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

(i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;,

(ii) सूचनाप्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011

(iii) विदेशी लोक पदधारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011; तथा

(iv) सामान एवं सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी हेतु नागरिक अधिकार तथा शिकायत निपटान विधेयक, 2011

(v) लोक प्रापण विधेयक, 2012।

इस विधान के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों और प्रक्रियाओं का आवश्यक आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। सरकार 'भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं' की अपनी नीति कार्यान्वित करने हेतु पूरी तरह से सचेत और वचनबद्ध है और इसने भ्रष्टाचार

स

लड़ने और सरकार के कार्यकरण का सुधार करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(ii) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है;

(iv) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(v) नागरिक चार्टर जारी करना।

(vi) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन करना

(vii) अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा केंद्र सरकार के अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी को जनव्यापी बनाना;

(viii) न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 को संसद में पुर:स्थापित करना (दिनांक 29.03.2012 को लोक सभा द्वारा पारित)।

(ix) विभिन्न राज्यों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन (66 न्यायालयों ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है।)

डाक बचत योजना

2052. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :

डॉ. संजय सिंह :

डॉ. भोला सिंह :

श्री सुशील कुमार सिंह :

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्यामल गोपीनाथ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने डाक बचत योजना की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) लघु बचत योजनाओं की निष्पादनकारी एजेंसी हेतु सरकार द्वारा डाक विभाग को सिक दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है;

(घ) क्या डाक विभाग ने हाल में पारिश्रमिक की दर में बढ़ोत्तरी की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशें निम्नानुसार थीं :-

1. मासिक आय योजना (एमआईएस) और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) की परिपक्वता अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया जाए।

2. 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाला एक नया एनएससी लिखत प्रारंभ किया जाए।

3. लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) स्कीम के अंतर्गत निवेश की वार्षिक सीलिंग को 70000/- रुपए से बढ़ाकर 100000/- रुपए कर दिया जाए।

4. डाकघर सावधि जमा (पीओटीडी) की–1, 2, 3 एवं 5 वर्ष की लिक्विडिटी–तुलनीय परिपक्वता के सावधि

जमा की तुलना में 1 प्रतिशत कम ब्याज दर पर परिपक्वता-पूर्व आहरण की अनुमति देकर सुधार किया जाएगा। 06-12 माह के निवेश के बीच परिपक्वता-पूर्व निकासी के लिए डाकघर बचत खाता (पीओएसए) ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।

5. लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को दो अपवादों सहित 25 आधार बिंदुओं (बेसिस प्वाइंट) के विस्तार के साथ समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति की दर के तुल्य किया जाना चाहिए। 10 वर्षीय एनएससी (नई लिखत) के संबंध में विस्तार 50 बेसिस प्वाइंट और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के मामले में 100 बेसिस प्वाइंट होना चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष की 1 अप्रैल से पूर्व ब्याज दरों की पुनरीक्षा की जाए और उन्हें अधिसूचित किया जाना चाहिए।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के विचारों/टिप्पणियों तथा विभिन्न एजेंटों के संघों, संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अभयावेदनों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इन सिफारिशों पर विस्तृत रूप से विचार किया है। इसके साथ-साथ सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 01.04.2012 से 2012-13 के लिए नई ब्याज दरों को अधिसूचित किया है जो निम्नानुसार हैं :-

योजना	01.04.2012 से ब्याज दर
बचत जमा	4.0
1 वर्षीय सावधि जमा	8.2
2 वर्षीय सावधि जमा	8.3
3 वर्षीय सावधि जमा	8.4
5 वर्षीय सावधि जमा	8.5
5 वर्षीय आवती जमा	8.4
5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	9.3
5 वर्षीय मासिक आय योजना	8.5
5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र	8.6
10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र	8.9
लोक भविष्य निधि	8.8

(ग) लघु बचत योजनाओं की निष्पादनकारी एजेंसी के तौर पर कार्य करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से डाक विभाग को निम्न दर पर पारिश्रमिक मिलता है :-

वित्तीय वर्ष	पारिश्रमिक की दर (रु. में)			
	प्रति सक्रिय खाता	प्रति जारी बचत पत्र + उन्मोचित	प्रति उन्मोचित आईवीपी	प्रति निष्क्रिय खाता
2012-13	163.22	55.77	14.77	24.75

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

2053. **श्री महेश्वर हजारी :**
श्री हर्षवर्धन :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां भारत-अमरीका समझौता के बाद देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (ए.पी.पी.) की स्थापना करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना किए जाने की योजना प्रस्तावित है;

(ख) प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संयंत्र-वार कितनी विद्युत का उत्पादन होने का अनुमान है और विद्युत का उत्पादन कब से शुरू होने की संभावना है;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं; और

(घ) उनके द्वारा उठाई गई चिंताओं का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद, वर्ष 2010 और 2011 में दो स्वदेशी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं नामत:, गुजरात में ककरापार में ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4 (केएपीपी यूनिट 3 तथा 4-2x700 मेगावाट), और राजस्थान में रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 7 तथा 8 (आरएपीपी यूनिट 7 तथा 8-2x700 मेगावाट) का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इन चार यूनिटों से होने वाला विद्युत उत्पादन, जोकि 2800 मेगावाट तक होगा, के बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शुरू किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, छः स्वदेशी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने की योजना है। इसका विवरण निम्नानुसार है :

स्वदेशी रिएक्टर

परियोजना	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)
गोरखपुर, यूनिट 1 तथा 2	गोरखपुर, हरियाणा	2x700
चुटका, यूनिट 1 तथा 2	चुटका, मध्य प्रदेश	2x700
माही बांसवाड़ा, यूनिट 1 तथा 2	माही बांसवाड़ा, राजस्थान	2x700
कैगा, यूनिट 5 तथा 6	कैगा, कर्नाटक	2x700
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यूनिट 1 तथा 2	कलपाक्कम, तमिलनाडु	2x500
प्रगत भारी पानी रिएक्टर	स्थल का निर्णय अभी किया जाना है	300
विदेशी तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले रिएक्टर		
कुडनकुलम, यूनिट 3 तथा 4	कुडनकुलम, तमिलनाडु	2x1000
जैतापुर, यूनिट 1 तथा 2	जैतापुर, महाराष्ट्र	2x1650
कोव्वाडा, यूनिट 1 तथा 2	कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश	2x1500
छाया मीठी विरदी, यूनिट 1 तथा 2	छाया मीठी विरदी, गुजरात	2x1100

प्रस्तावित परियोजनाओं से होने वाला विद्युत उत्पादन, उनके वास्तविक रूप से प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख के आधार पर, तेरहवीं पंचवर्षीय योजना/चौदहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में शुरू किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ) अधिकांश नए स्थलों पर लोगों के कुछ वर्गों द्वारा, मुख्यत: मुआवजे, पुनर्स्थापना तथा पुर्नवास (आरएंडआर) के मुद्दों पर, और नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा से संबंधित शंकाओं के बारे में विरोध प्रकट किया गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क

2054. श्री रमेश बैस :
श्री हरि मांझी :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों से आने वाले सिगनल विशेषकर नाथुला के निकट चीनी सीमा से मोबाइल सिगनल में अवरोध होने की रिपोर्ट है जिसके परिणामस्वरूप सैनिकों के साथ-साथ मोबाइल उपभोक्ताओं को अपने कॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रभार देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु सरकार का सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क शुरू करने तथा और अधिक सिगनल टावर लगाने करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों को कब तक लगाये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) पड़ोसी देशों से आने वाले मोबाइल सिग्नलों में अवरोध संबंधी मामलों की रिपोर्ट मिली है। तद्नुसार, इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का निर्णय किया गया है। तथापि, इस मंत्रालय को नाथूला के निकट चीन सीमा पर सैनिकों सहित मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रभारों के भुगतान किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जुलाई, 2008 से पूर्व भारतीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ 500 मीटर चौड़ाई में बेतार/मोबाइल सेवा के लिए कोई सेवा क्षेत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, जम्मू तथा कश्मीर के कतिपय क्षेत्रों में 10 कि.मी. चौड़े बफर जोन में सैल साइट (साइटों)/बेस ट्रांससीवर स्टेशनों (बीटीएस) को प्रतिष्ठापित करना भी प्रतिबंधित था। दूरसंचार विभाग के दिनांक 11.07.2008 के पत्र द्वारा 10 कि.मी. के बफर जोन में सैल साइट (साइटों)/बेस ट्रांससीवर स्टेशनों (बीटीएस)/रेडियो ट्रांसमीटरों की संस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है और अब दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके रेडियो सिगनल ऐसी सीमाओं के पार एक उपयुक्त दूरी के भीतर क्षीण हो जाएं अथवा अप्रयोज्य हो जाएं।

चीन सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों को एक अथवा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कवर किया जाता है। तथापि, कुछ ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में दुर्गम भूभाग, खराब सड़कों, और विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने के कारण प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता में कमी रहती है। इसके अलावा, चूंकि अब सीमा के 10 कि.मी. के भीतर टॉवर संस्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषताओं के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में बीटीएस संस्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) भी सीमावर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की अभिगम्यता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करता है। भारत संचार निगम लि. की भी नाथूला के निकट एक बेस ट्रांससीवर स्थापित करने की योजना है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार

2055. श्री राम सुंदर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत के दावे का जोरदार विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे पर अपना विरोध जता दिया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेंबली और इसके मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2010 में अलग-अलग संकल्प पारित किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को अमेरिका द्वारा किया गया समर्थन दक्षिण एशिया की शांति, सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और स्थिरता के लिए खतरा है।

(ग) भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता और इसके कार्यकलापों में दिए जाने वाले अपने व्यापक योगदानों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की योग्यता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष दृढ़तापूर्वक रखती है। अनेक राष्ट्रों ने विस्तारित सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बनने की भारत की योग्यता का खुला समर्थन किया है।

[अनुवाद]

एयर लाइन्स को अन्य देशों के लिए उड़ान भरने हेतु मानदंड

2056. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का घरेलू एयर लाइन्स को विदेशों के लिए उड़ान भरने हेतु पात्रता मानदंडों में छूट देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे घरेलू विमान वाहकों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान सुविधाएं

2057. **श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व-स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाई गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी हां। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले दो दशकों में अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों और संबंधित मंत्रालयों एवं भारत सरकार के विभागों की सहभागिता से विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की हैं। इन सुविधाओं में 14 स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थाएं और विषयक एवं अंतर-विषयक क्षेत्रों को शामिल कर कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास हेतु 50 उत्कृष्टता केंद्र; अनेक उच्च एवं बहुमूल्य स्टेट-ऑफ-आर्ट उपकरणों; जैविक पदार्थों हेतु रेपोसिटरीज; प्रौद्योगिकी मंचों एवं इन्क्यूबेटरों; और शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिकों और निजी क्षेत्रों को सुविधाएं देने हेतु जैव सूचना तंत्र सुविधाएं।

(ख) 12वीं योजना के दौरान जीवन विज्ञान और जैव- प्रौद्योगिकी में प्रस्तावित नई पहलें : उभरते हुए क्षेत्रों में अंतर-संस्थागत और साझेदारी केंद्र; सभी अनुसंधान सुविधाओं की नेटवर्किंग के लिए केंद्रित जीवन विज्ञान अनुसंधान संसाधन केंद्र; स्टेट-ऑफ-आर्ट प्रयोगात्मक पशु रोग मॉडल और नॉकआउट अनुसंधान सुविधाएं; जीएलपी प्रमाणित विनियामक परीक्षण प्रयोगशालाएं; फसलों के आण्विक प्रजनन हेतु जीनोमिक मंच. जैविकियों हेतु ट्रांसलेटेड अनुसंधान सुविधाएं; और उच्च प्रदर्शन की गणना में नई स्टेट-ऑफ-आर्ट में साझेदार उपकरणों हेतु सुविधाएं आण्विक एवं कोशकीय संरचनात्मक जैविक प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी, नॉन-इनवैसिव इमैजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी, गणितीय नमूने और कम्प्यूटर अनुकरण।

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों में दो स्टेट-ऑफ-आर्ट पशु सुविधाएं, 6 अकादमी-इंडस्ट्री इन्क्यूबेटर की स्थापना, सात विश्वविद्यालयों में आधुनिक स्नातोकत्तर प्रयोगशालाओं और केंद्रीय उपकरण सुविधाएं; मूलभूत जीव विज्ञान, रासायनिक जीव विज्ञान और कृत्रिम जीव विज्ञान प्रत्येक के लिए साझेदारी केंद्र; और न्यू जेनरेशन क्रमिक सुविधाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु आवंटन

2058. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का आवंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और विगत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग के पास उपलब्ध निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आवंटित ए. सी.ए. का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ए.सी.ए. के आवंटन हेतु मानदंड क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी हां। योजना आयोग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ विचार-विमर्श से राज्यों की वार्षिक योजना हेतु विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्रदान करता है।

(ख) से (घ) राज्यों को विभिन्न ए.सी.ए. स्कीमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत निधियों का आवंटन संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित स्कीम-विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार शासित की जाती है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के ए.सी.ए. का राज्य-वार एवं वर्ष-वार आवंटन का ब्यौरा, जिसमें पिछले तीन वर्षों नामत: 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की अवधि शामिल है, संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है। निधियां स्कीम-विशिष्ट दिशा-निर्देशों और उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने की शर्त पर जारी की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2007-2008(ए.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन (अनुमोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	ईएपी हेतु एसीए	एआईबीपी	एपीडी आरपी	झूम खेती	बीए डीपी	एचए डीपी	डब्ल्यूजी डीपी	टीएसपी	सड़के व पुल	एनएस एपी	एनपी एजी	सहायता अनुदान (अधि.275-1)	बीआर जीएफ	एनईजी एपी	जेएनएन यूआरएम	एक-बारगी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.)**																
1.	अरूणाचल प्रदेश	8.98	60.00	9.00	3.00	32.98	0.00	0.00	0.00	16.22	7.59	0.08	2.20	15.45	9.75	2.42	38.77
2.	असम	886.42	49.50	90.00	4.00	13.52	74.40	0.00	15.68	25.28	62.36	3.07	12.77	165.00	11.25	50.21	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	4.59	50.00	49.50	0.00	7.43	0.00	0.00	8.90	18.40	15.30	2.57	1.31	39.39	11.28	9.93	0.00
4.	जम्मू और कश्मीर	318.13	50.00	219.90	0.00	105.00	0.00	0.00	11.97	50.36	17.16	1.79	4.70	48.77	6.88	60.50	0.00
5.	मणिपुर	62.11	110.00	10.00	3.50	7.50	0.00	0.00	3.98	5.09	13.21	0.17	2.86	42.04	6.25	9.86	0.00
6.	मेघालय	82.07	10.00	100.00	5.00	4.94	0.00	0.00	0.00	7.57	12.54	0.43	6.10	39.98	5.25	10.62	23.72
7.	मिजोरम	118.80	22.50	17.95	5.50	13.02	0.00	0.00	0.00	4.74	3.45	0.07	3.24	24.97	5.96	14.77	46.80
8.	नागालैण्ड	56.58	45.00	45.00	6.00	4.16	0.00	0.00	0.00	4.09	5.45	0.38	4.26	31.01	4.75	19.76	67.50
9.	सिक्किम	34.65	8.00	0.00	0.00	5.72	0.00	0.00	0.97	1.99	3.78	0.14	0.36	13.96	10.55	1.20	18.43
1.0	त्रिपुरा	105.81	29.70	60.30	3.00	16.62	0.00	0.00	10.80	3.35	10.00	0.94	3.84	26.14	5.23	8.77	76.50
11.	उत्तराखंड	530.26	330.00	23.39	0.00	18.95	0.00	0.00	0.50	19.07	32.17	1.10	0.99	44.77	7.43	149.98	247.50
	कुल (11एस.सी.एस.)	2208.40	760.70	633.04	30.00	229.84	74.40	0.00	52.80	156.16	183.01	10.74	42.63	491.48	84.58	338.02	519.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II.	**सामान्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.)**																
1.	आन्ध्र प्रदेश	143.16	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	134.63	154.89	14.97	18.58	347.19	15.46	750.00	45.00
2.	बिहार	100.00	115.00	30.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	39.70	399.46	13.80	2.29	1640.26	26.58	300.00	21.00
3.	छत्तीसगढ़	113.10	100.00	12.10	0.00	0.00	0.00	000	47.96	39.67	73.21	5.02	25.55	247.93	10.73	200.00	10.50
4.	गोवा	0.00	15.00	15.54	0.00	0.00	0.00	4.50	1.33	8.18	1.11	1.06	0.61	0.00	2.55	6.63	7.50
5.	गुजरात	178.80	350.00	27.50	0.00	11.29	0.00	0.00	38.91	99.21	56.01	9.30	27.22	107.07	13.69	586.06	27.00
6.	हरियाणा	20.32	10.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10	32.96	1.24	0.00	30.40	11.28	64.28	24.00
7.	झारखंड	4.52	30.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83	32.73	127.47	5.10	24.29	342.95	30.00	160.00	15.00
8.	कर्नाटक	433.81	200.00	25.00	0.00	0.00	14.01	0.00	6.94	95.13	112.38	12.93	7.70	107.88	7.45	604.91	24.00
9.	केरल	329.62	22.00	44.00	0.00	0.00	0.00	13.13	2.46	47.17	69.01	5.84	1.30	34.27	9.08	127.80	18.00
10	मध्य प्रदेश	199.00	550.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17	96.23	173.88	5.35	47.23	451.39	21.95	210.51	33.30
11.	महाराष्ट्र	312.54	350.00	22.00	0.00	0.00	0.00	23.17	36.86	160.85	234.21	16.79	32.33	362.25	19.20	991.68	60.00
12.	ओडिशा	72.21	390.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.14	52.01	170.21	4.88	31.44	454.26	18.43	60.92	24.00
13.	पंजाब	8.93	200.0	65.59	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	62.90	16.02	1.37	0.00	16.62	11.83	249.99	45.00
14.	राजस्थान	239.70	125.00	38.50	0.00	51.50	0.00	0.00	42.14	123.04	88.71	2.42	27.41	187.68	12.00	202.61	21.00
15.	तमिलनाडु	330.52	3.00	10.00	0.00	0.00	47.29	0.00	2.91	107.58	155.82	5.16	2.51	84.93स	3.95	447.79	60.00
16.	उत्तर प्रदेश	248.80	140.00	40.87	0.00	24.73	0.00	0.00	4.96	143.11	504.33	6.01	4.47	634.71	25.25	526.34	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	847.64	15.00	13.75	0.00	39.56	0.00	0.00	19.82	55.68	177.00	16.95	15.32	256.60	14.25	625.87	30.00
कुल (17 जी.सी.एस.)		3582.67	3865.00	466.40	0.00	170.78	61.30	40.80	464.49	1355.92	2546.77	128.19	268.24	5306.39	263.72	6115.13	465.30
कुल राज्य (28)		5791.07	4625.71	1099.44	30.00	400.62	135.70	40.80	517.29	1512.08	2729.78	138.93	310.87	5797.87	348.30	6453.15	984.52

विवरण-II

वर्ष 2008-2009(ए.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन (अनुमोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	ईएपी हेतु एसीए	एआईबीपी	एपीडी आरपी	झूम खेती	बीए डीपी	एचए डीपी	डब्ल्यूजी डीपी	टीएसपी	सड़के व पुल	एनएस एपी	एनपी एजी	सहायता अनुदान (अधि.275-1)	बीआर जीएफ	एनईजी एपी	जेएनएन यूआरएम	एक-बारगी एसीए	आरके वीवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	**विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.)**																	
1.	अरूणाचल प्रदेश	9.00	30.00	9.00	3.00	52.06	0.00	0.00	0.00	17.34	7.08	0.08	2.42	15.60	9.79	2.42	0.00	9.78
2.	असम	744.48	74.50	90.00	4.00	13.52	81.84	0.00	17.25	26.91	109.70	3.07	14.05	165.00	11.25	50.21	75.00	102.89
3.	हिमाचल प्रदेश	75.60	150.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00	9.79	18.07	26.83	2.83	1.44	30.46	12.41	10.36	450.00	13.00
4.	जम्मू और कश्मीर	326.05	136.38	250.00	0.00	105.00	0.00	0.00	13.17	53.92	18.88	1.97	5.17	48.00	7.57	70.00	0.00	0.00
5.	मणिपुर	62.11	192.00	50.00	6.00	12.00	0.00	0.00	9.50	5.50	14.00	0.50	3.00	42.04	6.25	30.00	0.00	0.00
6.	मेघालय	90.28	30.00	140.00	5.00	6.03	0.00	0.00	0.00	8.04	11.32	0.43	6.34	39.98	4.93	53.30	27.00	18.29
7.	मिजोरम	234.70	22.50	17.95	5.50	13.02	0.00	0.00	0.00	4.74	3.45	0.07	3.24	24.97	5.96	14.77	63.00	0.00
8.	नागालैण्ड	62.24	60.00	60.00	6.00	5.08	0.00	0.00	0.00	4.34	6.04	0.38	4.43	31.01	4.46	39.75	0.00	4.92
9.	सिक्किम	2.70	4.00	8.00	0.00	5.72	0.00	0.00	1.07	2.05	6.65	0.14	0.40	13.96	1.43	1.20	75.00	12.92
10.	त्रिपुरा	22.50	50.00	70.30	3.00	18.79	0.00	0.00	10.80	3.45	31.52	0.97	4.00	26.14	5.23	35.00	99.00	55.75
11.	उत्तराखंड	748.29	510.00	23.39	0.00	18.95	0.00	0.00	0.55	19.07	35.39	1.21	1.09	44.77	8.17	214.98	270.00	
कुल	(11एस.सी.एस.)	2377.95	1259.38	718.64	32.50	261.36	81.84	0.00	62.13	163.43	270.86	11.65	45.58	481.93	77.45	521.99	1059.00	217.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II.	**सामान्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.)**																	
1.	आन्ध्र प्रदेश	179.24	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.82	143.63	222.90	14.97	19.32	347.19	14.51	1250.00	49.50	326.88
2.	बिहार	0.00	450.00	49.20	0.00	31.72	0.00	0.00	5.50	40.89	455.77	13.80	2.52	1637.67	26.58	330.00	30.00	66.34
3.	छत्तीसगढ़	201.71	187.22	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71.55	39.97	89.20	8.00	37.95	280.00	14.07	316.50	15.00	0.00
4.	गोवा	0.00	25.00	15.54	0.00	0.00	0.00	5.44	1.47	8.43	1.80	1.06	0.63		37.39	60.00	10.50	2.70
5.	गुजरात	96.21	800.00	300.00	0.00	13.79	0.00	0.00	42.88	102.19	80.60	9.30	28.31	107.07	12.85	734.17	39.00	355.21
6.	हरियाणा	14.64	10.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.56	36.26	1.36		30.44	12.40	70.71	30.00	21.22
7.	झारखंड	0.00	130.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10	33.70	191.30	5.60	26.70	343.00	33.00	176.00	15.00	88.90
8.	कर्नाटक	317.19	215.00	50.88	0.00	0.00	26.32	0.00	7.63	103.82	161.73	12.93	8.01	108.17	6.99	665.40	30.00	316.57
9.	केरल	271.13	40.00	44.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.46	47.17	100.00	5.84	1.30	34.27	20.00	200.00	30.00	0.00
10.	मध्य प्रदेश	476.64	605.00	48.40	0.00	0.0	0.00	0.00	96.99	105.84	191.27	5.89	51.95	496.53	24.15	231.56	45.00	400.00
11.	महाराष्ट्र	161.27	1700.00	116.94	0.00	0.00	0.00	28.00	40.62	170.00	355.27	16.75	33.62	362.25	16.70	2582.57	75.00	292.00
12.	ओडिशा	219.21	800.00	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93	158.25	190.64	5.47	40.00	454.00	20.64	95.23	30.00	100.00
13.	पंजाब	10.20	100.00	65.59	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	62.90	17.62	1.51	0.00	16.82	13.01	275.00	60.00	100.00
14.	राजस्थान	205.20	200.00	43.84	0.00	76.59	0.00	0.00	46.35	119.95	97.58	2.66	30.14	262.29	13.26	202.61	30.00	68.88
15.	तमिलनाडु	295.50	3.00	10.00	0.00	0.00	52.00	0.00	3.20	110.81	274.10	5.16	2.76	113.78	13.95	492.50	75.00	71.52
16.	उत्तर प्रदेश	385.20	175.00	20.09	0.00	24.73	0.00	0.00	5.48	145.51	554.76	6.61	4.92	636.09	27.78	578.97	75.00	450.00
17.	पश्चिम बंगाल	273.06	150.00	37.60	0.00	39.60	0.00	0.00	19.80	57.40	265.30	18.60	15.30	256.60	15.70	688.50	45.00	119.20
	कुल (17 जी.सी.एस.)	3106.40	7590.22	900.0	0.00	205.13	78.33	53.44	522.76	1512.05	3285.90	135.55	303.43	5465.97	322.98	8949.72	684.00	2779.42
	कुल राज्य (28)	5484.35	8849.60	1618.73	32.50	466.49	160.17	53.44	584.89	1675.48	3556.76	147.20	349.01	5947.90	400.43	9471.71	1743.00	2996.97

विवरण-III

वर्ष 2009-2010(ए.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन (अनुमोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	ईएपी हेतु एसीए	एआईबीपी	एपीडी आरपी	झूम खेती	बीए डीपी	एचए डीपी	डब्ल्यूजी डीपी	टीएसपी	सड़के व पुल	एनएस एपी	एनपी एजी	सहायता अनुदान (अधि.275-1)	बीआर जीएफ	एनईजी एपी	जेएनएन यूआरएम	एक-बारगी एसीए	आरके वीवाई	टीआर पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	**विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.)**																		
1.	अरूणाचल प्रदेश	9.00	20.00	0.00	3.00	58.49	0.00	0.00	0.00	20.43	10.51	0.06	7.38	15.47	5.46	50.00	0.00	16.99	0.00
2.	असम	689.49	74.50	0.00	4.00	24.24	89.93	0.00	17.26	31.37	178.26	2.77	34.83	168.19	36.09	150.00	330.00	79.86	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	99.73	200.00	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00	10.77	22.12	40.24	3.11	3.50	30.46	13.65	50.00	0.00	15.32	0.00
4.	जम्मू और कश्मीर	446.80	254.27	134.00	0.00	100.00	0.00	0.00	13.17	61.88	28.02	1.97	12.43	48.00	12.12	120.00	0.00	42.05	0.00
5.	मणिपुर	62.11	190.00	50.00	6.00	0.00	13.36	0.00	9.50	6.60	18.81	0.25	7.83	42.09	8.54	51.00	0.00	5.86	0.00
6.	मेघालय	90.55	30.00	0.00	5.00	12.47	0.00	0.00	0.00	9.79	9.36	0.31	20.97	40.01	7.09	61.00	30.00	24.68	0.00
7.	मिजोरम	226.91	50.00	0.00	5.50	24.95	0.00	0.00	0.00	5.79	4.23	0.15	8.82	24.98	3.94	50.33	70.00	4.15	0.00
8.	नागालैण्ड	72.00	97.30	0.00	6.00	5.08	0.00	0.00	0.00	5.32	9.49	0.38	10.65	31.01	4.46	72.06	0.00	4.92	0.00
9.	सिक्किम	9.00	40.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	1.07	2.51	10.45	0.14	0.96	13.96	3.72	120.00	82.70	10.48	0.00
10.	त्रिपुरा	72.00	81.08	0.00	3.00	18.79	0.00	0.00	10.80	4.23	49.53	0.97	9.62	26.14	5.23	63.45	50.00	55.75	0.00
11.	उत्तराखंड	821.00	550.00	0.00	0.00	22.61	0.00	0.00	1.32	24.04	53.88	1.21	2.70	44.85	7.70	177.00	400.00	58.56	0.00
कुल (11 एस.सी.एस.)		2598.59	1587.15	184.00	32.50	290.44	103.29	0.00	63.89	194.08	412.78	11.32	119.69	485.16	108.00	964.84	962.70	318.62	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II.	**सामान्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.)**																		
1.	आन्ध्र प्रदेश	138.47	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.62	166.29	303.12	14.97	52.83	348.28	17.72	1350.00	62.50	410.00	5.00
2.	बिहार	0.00	600.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	5.50	40.89	555.77	13.80	2.52	1637.67	26.58	1000.00	33.00	66.34	0.00
3.	छत्तीसगढ़	254.64	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.22	67.88	173.52	4.02	69.66	248.48	12.31	316.50	18.76	119.12	0.00
4.	गोवा	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	1.60	10.54	2.37	1.06	1.71	0.00	105	40.00	12.00	11.87	0.00
5..	गुजरात	1.23	800.00	0.00	0.00	27.69	0.00	0.00	56.36	121.45	66.12	9.30	78.75	107.31	29.91	850.00	0.00	386.19	0.00
6.	हरियाणा	3.30	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.72	39.89	1.50	0.00	33.48	13.64	415.76	33.00	81.40	0.00
7.	झारखंड	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.11	40.16	283.12	5.61	64.13	342.95	33.00	300.00	16.50	88.85	0.00
8.	कर्नाटक	301.68	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32	16.48	120.30	272.43	12.93	36.45	108.17	14.91	500.00	79.04	410.00	0.00
9.	केरल	91.35	40.00	0.00	0.00	0.00	22.39	0.00	3.50	57.03	157.14	5.84	3.12	34.33	20.00	485.00	33.00	61.00	323.14
10.	मध्य प्रदेश	444.90	1167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	114.41	444.51	3.58	124.68	452.40	24.15	500.00	60.00	202.39	0.00
11.	महाराष्ट्र	161.27	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	51.55	204.06	407.58	16.79	90.27	265.57	12.83	2512.00	82.50	407.34	0.00
12.	ओडिशा	162.72	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.84	64.42	282.15	6.12	96.00	324.00	23.12	250.00	33.00	120.00	0.00
13.	पंजाब	7.60	110.00	0.00	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00	76.79	50.00	1.66	0.00	18.28	14.31	358.58	75.00	65.25	0.00
14.	राजस्थान	129.50	300.00	0.00	0.00	84.25	0.00	0.00	50.95	149.86	144.83	2.93	72.45	262.29	14.59	500.00	33.00	219.55	0.00
15.	तमिलनाडु	303.80	4.86	0.00	0.00	0.00	57.19	0.00	3.20	129.61	354.36	4.18	6.84	114.04	22.41	800.00	82.50	127.90	8.84
16.	उत्तर प्रदेश	143.25	500.00	0.00	0.00	28.69	0.00	0.00	5.40	161.07	901.86	6.61	12.60	636.09	61.16	1225.00	82.00	390.97	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	763.82	300.00	0.00	0.00	39.60	34.60	0.00	19.8	57.40	365.30	18.60	15.30	256.60	15.70	938.50	50.00	119.20	00.00
कुल (17 जी.सी.एस.)		2907.53	9786.86	0.00	0.00	233.83	114.20	67.3	573.2	1649.88	4804.07	129.50	727.31	5189.94	357.39	12341.34	785.80	3287.41	336.98
कुल राज्य (28)		5506.12	11374.0	184.00	32.5	524.2	217.50	67.31	637.11	1843.96	5216.85	140.82	847.00	5675.10	465.39	13306.18	1748.50	3606.03	336.98

विवरण-IV

वर्ष 2010-2011(ए.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन (अनुमोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	ईएपी हेतु एसीए	एआईबीपी	झूम खेती	बीए डीपी	एचए डीपी	डब्ल्यूजी डीपी	टीएसपी	सड़कें व पुल	एनएसएपी	सहायता अनुदान (अधि.275-1)	बीआरजीएफ	एनईजीएपी	जेएनएनयूआरएम	एक-बारगी एसीए	आरकेवीवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	**विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.)**															
1.	अरूणाचल प्रदेश	9.00	37.50	3.00	58.50	0.00	0.00	0.00	33.59	4.87	7.38	15.47	2.21	55.00	0.00	29.24
2.	असम	758.00	220.00	4.00	40.00	89.93	0.00	17.26	36.90	191.94	34.83	168.19	14.61	180.00	0.00	206.19
3.	हिमाचल प्रदेश	246.60	288.50	0.00	12.31	0.00	0.00	10.77	26.06	25.06	3.50	30.46	5.53	20.00	0.00	43.03
4.	जम्मू और कश्मीर	332.10	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	14.05	91.96	32.92	13.00	48.00	4.91	120.00	0.00	112.70
5.	मणिपुर	62.11	290.00	6.00	13.36	0.00	0.00	9.50	9.54	20.24	7.83	42.09	3.46	50.00	0.00	20.00
6.	मेघालय	90.55	130.00	5.00	12.47	0.00	0.00	0.00	11.20	11.99	21.93	40.01	2.87	128.95	0.00	42.49
7.	मिजोरम	276.71	60.10	5.50	24.95	0.00	0.00	0.00	8.81	6.54	8.82	24.98	1.59	30.00	0.00	8.37
8.	नागालैंड	72.00	125.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	6.97	12.00	11.14	37.00	1.81	75.48	0.00	39.60
9.	सिक्किम	34.58	94.24	0.00	20.00	0.00	0.00	1.07	3.30	10.43	0.96	13.96	1.50	150.00	0.00	5.64
10.	त्रिपुरा	91.00	150.42	10.00	35.79	0.00	0.00	13.80	4.95	63.35	9.62	26.14	2.12	62.00	0.00	108.81
11.	उत्तराखंड	969.52	500.00	0.00	22.61	0.00	0.00	1.41	27.35	64.45	2.82	44.85	3.12	215.00	0.00	22.79
कुल	(11 एस.जी.एस.)	2942.17	2095.76	39.50	364.99	89.93	0.00	67.86	260.63	443.79	121.83	491.15	43.73	1086.43	0.00	638.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	**सामान्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.)**															
1.	आन्ध्र प्रदेश	170.44	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.19	161.52	326.39	55.26	348.28	7.17	1500.00	50.00	605.50
2.	बिहार	0.00	700.00	0.00	37.15	0.00	0.00	9.29	50.84	704.48	8.38	2637.67	30.51	445.00	42.00	279.07
3.	छत्तीसगढ़	175.74	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43	62.96	188.39	72.86	248.48	7.54	325.00	51.00	439.02
4.	गोवा	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	6.04	1.71	5.87	2.54	1.79	0.00	0.43	50.00	260.00	24.06
5.	गुजरात	1.35	800.00	0.00	28.00	0.00	0.00	60.11	113.62	104.23	82.37	107.31	12.11	895.00	63.00	353.45
6.	हरियाणा	1.50	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	46.22	0.00	33.48	10.32	300.00	39.00	190.97
7.	झारखंड	200.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.71	41.85	246.86	78.04	342.95	13.35	135.00	40.00	160.80
8.	कर्नाटक	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	26.32	16.48	96.01	308.83	36.45	108.17	14.91	550.00	65.00	169.09
9.	केरल	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00	24.88	3.73	38.18	79.24	3.26	34.33	8.09	485.00	58.00	174.92
10.	मध्य प्रदेश	412.04	1225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.69	144.45	399.41	134.62	452.40	9.78	390.00	70.00	532.74
11.	महाराष्ट्र	57.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	39.56	54.98	189.42	444.33	94.42	265.57	16.44	2700.00	82.50	605.50
12.	ओडिशा	253.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.63	75.62	293.91	100.42	574.00	18.77	250.00	40.00	193.51
13.	पंजाब	16.00	637.28	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00	48.09	50.26	0.00	16.65	12.18	235.00	100.00	170.16
14.	राजस्थान	111.00	406.00	0.00	86.96	0.00	0.00	54.39	168.13	198.42	75.78	262.29	18.45	500.00	50.00	491.30
15.	तमिलनाडु	205.00	115.00	0.00	0.00	0.00	57.19	3.41	103.52	385.76	7.15	114.04	9.07	825.00	150.00	219.41
16.	उत्तर प्रदेश	100.92	615.00	0.00	29.05	0.00	0.00	5.82	149.77	1083.22	13.18	636.09	24.76	1150.00	82.00	516.81
17.	पश्चिम बंगाल	309.99	967.00	0.00	39.60	34.63	0.00	21.12	55.19	441.65	16.00	256.60	6.36	875.00	50.00	357.52
कुल	(17 जी.सी.एस.)	2214.01	12366.43	0.00	243.01	34.63	153.99	659.69	1557.54	5304.14	779.98	6438.31	220.24	11610.00	1292.50	5483.83
कुल	राज्य (28)	5156.18	14462.19	39.50	608.00	124.56	153.99	727.55	1818.17	5747.93	901.81	6929.46	263.97	12696.43	1292.50	6122.69

विवरण-V

वर्ष 2011-2012(ए.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन (अनुमोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	ईएपी हेतु एसीए	एआईबीपी	झूम खेती	बीए डीपी	एचए डीपी	डब्ल्यूजी डीपी	टीएसपी	सड़के व पुल	एनएसएपी	सहायता अनुदान (अधि.275-1)	बीआरजीएफ	एनईजीएपी	जेएनएनयूआरएम	एक-बारगी एसीए	आरकेवीवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	**विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.)**															
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	85.76	3.33	85.73	0.00	0.00	0.00	39.51	5.17	8.45	15.47	2.21	59.27	0.00	17.92
2.	असम	1074.24	747.56	7.92	31.61	98.86	0.00	19.70	43.62	173.81	39.86	168.19	14.23	296.20	0.00	238.99
3.	हिमाचल प्रदेश	312.30	250.00	0.00	20.00	0.00	0.00	12.29	30.66	27.65	4.01	30.50	5.53	26.00	0.00	95.00
4.	जम्मू और कश्मीर	315.00	350.00	0.00	125.00	0.00	0.00	16.03	108.61	37.43	14.88	46.85	4.23	146 90	0.00	71.84
5.	मणिपुर	100.00	290.00	8.33	20.00	0.00	0.00	10.84	11.23	16.25	8.96	42.09	3.46	77.04	0.00	41.80
6.	मेघालय	133.68	135.29	6.67	20.00	0.00	0.00	0.00	13.17	15.87	25.10	39.0	12.98	138.97	0.00	13.48
7.	मिजोरम	209.34	75.00	4.58	37.02	0.00	0.00	0.00	10.36	7.15	10.09	24.98	1.59	52.34	0.00	16.61
8.	नागालैण्ड	72.00	140.00	12.50	18.00	0.00	0.00	0.00	8.42	12.82	12.75	40.05	2.53	96.34	0.00	38.15
9.	सिक्किम	105.99	131.47	0.00	20.00	0.00	0.00	4.00	3.89	5.00	3.00	13.97	1.50	151.55	0.00	14.61
10.	त्रिपुरा	40.00	150.00	6.67	41.26	0.00	0.00	15.75	5.83	41.72	11.01	13.21	3.81	75.00	0.00	27.00
11.	उत्तराखंड	962.00	321.09	0.00	32.98	0.00	0.00	1.61	32.60	60.87	3.23	44.85	3.36	231.71	0.00	167.48
कुल	(11 एस.सी.एस.)	3324.55	2676.17	50.00	451.60	98.86	0.00	80.22	307.90	403.74	141.34	481.17	45.0	1361.32	0.00	742.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	सामान्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.)															
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	187.65	378.26	63.00	348.28	6.85	1605.00	60.00	658.57
2.	बिहार	0.00	700.00	0.00	55.77	0.00	0.00	10.60	60.89	747.38	9.59	3316.99	12.1.0	479.58	48.00	547.73
3.	छत्तीसगढ़	15.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.95	73.63	198.17	83.38	548.48	8.45	350.25	0.00	182.16
4.	गोवा	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00	5.98	1.71	6.48	1.29	1.79	0.00	3.63	50.00	60.00	64.30
5.	गुजरात	1.35	2000.00	0.00	41.64	0.00	0.00	68.53	132.58	89.98	93.90	107.31	11.70	900.00	70.00	561.49
6.	हरियाणा	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	50.77	0.00	30.44	10.32	323.31	42.00	176.28
7.	झारखंड	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.94	49.66	270.69	89.31	763.55	7.32	463.00	51.00	152.08
8.	कर्नाटक	306.60	744.36	0.00	0.00	0.00	29.07	18.5ब	131.28	332.67	41.50	108.17	9.01	575.00	60.00	610.27
9.	केरल	0.00	100.00	0.00	0.00	24.74	0.00	4.26	44.48	70.28	3.73	34.33	8.06	522.69	96.00	242.84
10.	मध्य प्रदेश	339.06	1119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	169.93	419.96	154.06	692.39	8.86	420.30	70.00	293.96
11.	महाराष्ट्र	57.03	1941.17	0.00	0.00	0.00	39.32	62.68	221.50	417.20	107.64	326.57	9.57	2889.00	90.00	647.96
12.	ओडिशा	156.70	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.96	89.83	475.19	102.56	919.95	18.77	269.43	50.00	322.48
13.	पंजाब	32.00	570.00	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00	57.06	50.34	0.00	16.65	12.18	253.26	120.00	115.37
14.	राजस्थान	69.37	240.00	0.00	114.09	0.00	0.00	62.06	199.49	180.64	86.72	262.95	18.45	538.85	60.00	651.59
15.	तमिलनाडु	43.15	175.00	0.00	0.00	62.96	0.00	3.89	121.57	399.62	8.18	114.04	10.47	888.7	60.00	253.83
16.	उत्तर प्रदेश	111.01	637.32	0.00	45.46	0.00	0.00	6.27	177.06	1146.82	14.20	666.09	14.42	1239.36	200.00	775.00
17.	पश्चिम बंगाल	182.06	752.14	0.00	142.91	38.07	0.00	36.62	65.43	474.67	55.48	285.90	7.75	942.99	144.80	538.98
कुल	(17 जी.सी.एस.)	1363.33	13796.60	0.00	432.79	125.77	74.37	764.21	1850.81	5703.93	915.04	8542.12	177.91	12710.77	1381.80	5794.89
कुल	राज्य (28)	4687.88	16472.77	50.0	884.39	224.63	74.37	844.43	2153.71	6107.67	1056.38	9023.29	223.00	14072.09	1381.80	7537.77

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. में आई.टी.एस. अधिकारी

2059. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री राकेश सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. में आई.टी. एस. अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है और जिन्हें इन उक्त संगठनों में आमेलित होने का विकल्प नहीं दिया गया है, को दूरसंचार विभाग में वापस भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन पी.एस.यू. में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि की समीक्षा की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पी.एस.यू. से सभी आई.टी.एस. अधिकारियों को वापस भेजने पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ङ) दूरसंचार विभाग ने दिनांक 3 नवम्बर, 2011 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिस के द्वारा, आईटीएस अधिकारियों सहित समूह 'क' के ऐसे अधिकारियों को जो बीएसएनएल/एमटीएनएल में समप्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने बीएसएनएल/ एमटीएनएल में आमेलित होने के लिए अपना विकल्प नहीं दिया था अथवा सरकारी सेवा के लिए विकल्प दिया था अथवा जिन्होंने विकल्प देने के लिए दिनांक 22 नवंबर, 2011 के विकल्प पत्र में निर्धारित की गई अंतिम तारीख अर्थात 8 नवंबर, 2011 तक सशर्त विकल्प दिया था, 9 नवंबर, 2011 से प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 29.11.2012 तक आमेलित नहीं किए गए 393 आईटीएस अधिकारियों को (354 बीएसएनएल द्वारा एवं 39 एमटीएनएल द्वारा) दूरसंचार विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया हैं बीएसएनएल एवं एमटीएनएल द्वारा दायर किए आवेदनों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 7.11.2012 के आदेश में आमेलित न हुए समूह 'क' के अधिकारियों को बीएसएनएल/एमटीएनएल में दिनांक 15.12.2012 तक बने रहने की अनुमति प्रदान कर दी है।

इसी बीच आईटीएस अधिकारियों सहित समूह 'क' अधिकारियों के बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन किए जाने संबंधी मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति (सीओएस) का गठन किया गया है। सीओएस की दो बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

विमानों में नि:शक्त व्यक्ति

2060. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :**
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान अधिनियम, 1937 के नियम 133क के प्रावधान के तहत नि:शक्त या न्यूनीकृत गतिशील व्यक्ति का विमान द्वारा वहन नियमों का उल्लंघन करने वाली विमान कंपनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का विशेष उल्लेख नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुछ नि:शक्त व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार संबंधी रिपोर्ट के कंपनी-वार कितने मामले हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) डी.जी.सी.ए. द्वारा अब तक उन विमानन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो नि:शक्त व्यक्ति के विमान सेवा संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। इस विषय से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाओं को कोई दंडात्मक कार्रवाई विनिर्दिष्ट नहीं है। तथापि, वायुयान नियम, 1937 के नियम 133क में यथा निहित नागर विमानन अपेक्षाओं का उल्लंघन करने या अनुपालन न करने पर 06 माह से अनधिक अवधि के कारावास या 2 लाख रूपये से अनधिक जुर्माने या वायुमान

नियम, 1937 की अनुसूची-VI के प्रवर्ग-III की क्रम संख्या-13 के अधीन दोनों से दंडित किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, विकलांग यात्रियों के उत्पीड़न के चार मामलों की सूचना डी.जी.सी.ए. को दी गई थी, इनमें वर्ष 2011 तथा वर्ष 2012 में दो-दो मामले थे, जिनका ब्यौरा संबंधित एयरलाइन और डी.जी.सी.ए. द्वारा की गई कार्रवाई के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। डी.जी.सी.ए. ने "नि:शक्त और/या न्यूनीकृत गतिशील व्यक्ति का विमान द्वारा यात्री वहन" पर नागर विमानन अपेक्षा जारी की है, जिसकी एयरलाइनों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।

विवरण

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

1. श्रीमती मनसुरी शबाना तथा मास्टर मनसुरी लुकमान (बच्चा) के मामले में किंगफिश एयरलाइंस ने ऐसी घटनाओं की पुनावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित निवारक कार्रवाई की है:

   (क) अहमदाबाद के कर्मीदल तथा संबंधी ग्राउंड सेवा स्टाफ को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं और उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं।

   (ख) सभी संबंधितों को ऐसी यात्रा के लिए कैरेज नीति पुन: परिचालित की गई है।

2. श्री मोहम्मद आसिफ इकबाल के मामले में किंगफिशर एयरलाइंस ने पटना हवाईअड्डे पर हवाईअड्डा प्रबंधक सहित सभी संबंधित कार्मिकों को बर्खास्त कर दिया है। इसके दृष्टिगत किंगफिशर एयरलाइंस ने निम्नलिखित तथ्यों को इंगित करते हुए सभी हवाईअड्डों के लिए दिशा-निर्देशों को दोहराया है:

   (क) एक नेत्रहीन यात्री जिसका कोई चिकित्सीय जटिलता नहीं है और वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णत: सक्षम है तो उसे अपनी उड़ानों में स्वीकार्य किया जाना चाहिए और उसे किसी प्रकार के क्षतिपूर्ति फार्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

   (ख) ऐसे यात्री को अकेले यात्रा करने की अनुमति है और अकेले यात्रा करने के लिए किसी साथी/एस्कोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

   (ग) स्टाफ द्वारा ऐसे यात्री का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।

   (घ) उड़ानों में व्यवधान होने की स्थिति में स्टाफ द्वारा ऐसे यात्रियों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।

3. सुश्री जिजा घोष के मामले में, स्पाइस जेट ने लागू नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रावधानों के संदर्भ में पायलट-इन-कमांड के उत्तरदायित्वों की पुन: जांच की है और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने में अधिक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए उसकी काउंसिलिंग की जा रही है। स्पाइस जेट ने यह भी सूचित किया है कि वे नि:शक्त व्यक्तियों की व्यवस्था संबंधी पर मौजूदा प्रक्रियाओं को पुन: लागू करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर रही है।

4. सुश्री अंजली अग्रवाल के मामले में, जेट एयरवेज ने सूचित किया है कि सुश्री अग्रवाल की शिकायत तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि वह एक स्लिम व्हील चेयर की मांग कर रही थी, जिसे कुछ ही समय में उपलब्ध करा दिया गया था। तथापि, जेट एयरवेज के स्टाफ के लिए नि:शक्त व्यक्तियों/तथा/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों की व्यवस्था से संबंधित दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रियाओं को दोहराया गया है।

विमान द्वारा यात्रा के दौरान शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जा रही दिक्कतों में वृद्धि के दृष्टिगत, नागर विमानन महानिदेशालय ने 20 मार्च, 2012 को अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के साथ परस्पर संपर्क के लिए सत्र का आयोजन किया है। बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी:

- सभी संबंधितों द्वारा "नि:शक्त व्यक्तियों तथा/या निम्न गतिशीलता वाले व्यक्तियों को विमान द्वारा वहन" विषय पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षा का समग्र रूप से अनुपालन किया जाएगा।
- विमान द्वारा यात्रा करते समय निम्न गतिशीलता वाले व्यक्तियों की व्यवस्था के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा "क्या किया जाना चाहिए तथा क्या नहीं किया जाना चाहिए", का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया

जाएगा। अनुसूचित एयरलाइनें इन्हें अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी।

- एयरलाइनें इस संबंध में अनुदेशों को प्रदर्शित करने के लिए अपने वेब होम पृष्ठ पर एक पृथक बटन की व्यवस्था करेगी।

- एयरलाइनें विमान द्वारा यात्रा करने वाले निम्न गतिशीलता वाले व्यक्तियों की व्यवस्था करते समय अपने उत्तरदायित्वों के संबंध में सभी हवाईअड्डा प्रबंधकों के लिए एक ओरिएंटल कार्यक्रम का आयोजन करेंगी, जो आगे उनके अधीन कार्य करने वाले ग्राउंड कर्मचारियों को इसके प्रति संवेदित करेंगे।

लंबी अवधि के लिए पूर्वानुमान

2061. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम मानसून के ठीक समाप्त होने के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान (आई.एम.डी.) द्वारा जारी किये गये लम्बी अवधि के पूर्वानुमान गलत साबित हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आई.एम.डी. के गलत पुर्वानुमान करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.एम.डी. के कार्यकरण में सुधार लाने और इसके कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) मानसून वर्षा के दीर्घावधि पुर्वानुमानों में सदैव ही त्रुटि की थोड़ी-बहुत संभावना रहती है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ई.एस.एस.ओ.) आई.एम.डी. का सदैव ही यह प्रयास रहा है कि सुधार के सतत् प्रयासों से त्रुटि के इस मार्जिन को कम किया जा सके। मात्रात्मक रूप से देश में समग्र रूप से मानसून ऋतु की वर्षा अपने दीर्घावधि औसत का केवल 92% रही हैं (8% की कमी) जबकि सामान्य मानसून आउटलुक निम्नानुसार जारी किए गए थे:

- 26 अप्रैल, 2012 को इसे दीर्घावधि औसत के 99±5% पर रखा गया था।

- 22 जून, 2012 को इसे दीर्घावधि औसत के 96±4% पर रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, देश के चार समांगी क्षेत्रों के लिए जारी मानसून वर्षा आउटलुक, माह जुलाई तथा अगस्त 2012 के लिए अखिल भारतीय मानसून वर्षा हेतु मासिक आउटलुक नीचे दिए गए हैं:

क्षेत्र	अवधि	दीर्घावधिक औसत के % में		
		22 जून को जारी	2 अगस्त को जारी	वास्तविक वर्षा सत्यापन
पश्चिमोत्तर भारत	जून से सितम्बर	93±8		93
मध्य भारत	जून से सितम्बर	96±8		96
पूर्वोत्तर भारत	जून से सितम्बर	99±8		89
दक्षिण प्रायद्वीप	जून से सितम्बर	95±8		90
अखिल भारत	जुलाई	98±9		87
अखिल भारत	अगस्त	96±9	96±9	101
अखिल भारत	अगस्त-सितम्बर		91±8	104

(ख) जी हां। कुछ हद तक वर्षा में कमी देश के विभिन्न भागों में मानसून के देरी से आगमन तथा आगे बढ़ने में विलम्ब के कारण हुई है (1-2 सप्ताह की अवधि में)। चालू ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर पर प्रधान वर्षा धारित चक्रवाती मौसम प्रणालियों (मानसूनी कम दबाव के क्षेत्रों) के निर्माण की निम्न आवृत्ति (प्रत्येक ऋतु में मानसूनी कम दबाव के क्षेत्रों की 4-6 की सामान्य आवृत्ति की तुलना में इस वर्षा बनी कम दबाव की प्रणालियों में से कोई भी कम दबाव के क्षेत्रों में तीव्र नहीं हुई) को देश में मानसून वितरण में कमी के लिए प्रमुख कारक माना गया है। उपर्युक्त ऋतुकालिक पैमाने की मानसून परिसंचरण विसंगतियों तथा सम्बद्ध विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन वर्ष 2012 के दौरान ऋतुकालिक वर्षा पर पड़े उनके प्रभावों के परीक्षण के साथ-साथ किया जा रहा है।

(ग) भारत में ऋतुकालिक मानसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए ई.एस.एस.ओ.-आई.एम.डी. अब तक संख्यिकीय मॉडलों के एक सूइट का प्रयोग कर रहा है। इस वर्ष यू.एस.ए. के गतिकीय मॉडल का प्रयोग करके भी पूर्वानुमान तैयार किया गया। हम यू.एस.ए. तथा यू.के. के युग्मित महासागर-वायुमण्डलीय मॉडलों के कार्य निष्पादन का भारत में ऋतुकालिक मानसून वर्षा पूर्वानुमानों के लिए उनकी उपयुक्ता का परीक्षण कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय मानसून के अंतर्गत उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जा सकें।

नार्थ-ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर

2062. श्री अशोक तंवर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ-ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर (एन.ई.एस.ए.सी.) के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) एन.ई.एस.ए.सी. द्वारा वर्तमान परियोजनाओं और किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए कुल बजटीय आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एन.ई.एस.ए.सी.) अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एन.ई.आर.) को विकासात्मक सहायता प्रदान करने हेतु अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) और उत्तर-पूर्वी परिषद् (एन.ई.सी.) का एक संयुक्त उपक्रम है। एन.ई.एस.ए.सी. सितंबर, 2000 में पंजीकृत एक सोसायटी है जिसमें एन.ई.सी. एवं डी.ओ.एस. की 50:50 की निधियां लगाई गई हैं। एक शासी परिषद् इस केन्द्र के क्रियाकलापों का दिशानिर्देशन करता है। शासी परिषद के निर्णयों की सोसायटी द्वारा समीक्षा की जाती है तथा उनकी अभिपुष्टि की जाती है। एक नियुक्त निदेशक केन्द्र के दैनंदिन क्रियाकलापों का आयोजन करता है। केन्द्र के वैज्ञानिक कार्यक्रम क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशित हैं और एन.ई.एस.ए.सी. सोसायटी और शासी परिषद द्वारा आवधिक रूप में इनकी समीक्षा की जाती है। केन्द्र भू-पर्यवेक्षण उपयोगों (इ.ओ.ए.), उपग्रह संचार (सैटकॉम), आपदा प्रबंध सहायता (डी.एम.एस.) और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में अनुप्रयोगात्मक परियोजनाओं का आयोजन करता है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एन.ई.एस.ए.सी. द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों में वानिकी एवं पारिस्थितिकी, कृषि एवं मृदा, जल संसाधन एवं जलविज्ञान, भूविज्ञान, अवसंरचनात्मक आयोजना, प्राकृतिक संसाधन गणना इत्यादि के क्षेत्रों में सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) प्रयोगात्मक परियोजनाएं; दूरचिकित्सा, दूरस्थ शिक्षा और ग्रामीण संसाधन केंद्र जैसी उपग्रह संचार उपयोग संबंधी परियोजनाएं; एयरोसोल विकिरणी प्रणोदन, वायुमंडलीय अनुरेख गैसों के अध्ययन से संबंधित अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी परियोजनाएं; और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली, सूखा मानीटरन और खतरा जोखिम संवेदनशीलता का मूल्यांकन जैसी आपदा प्रबंध सहायता संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एन.ई.एस.ए.सी. हेतु किए गए बजटीय आबंटन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	डी.ओ.एस. के बजट में एन.ई.एस.ए.सी. हेतु बजटीय आबंटन (लाख रु में)
2009-2010	700.00
2010-2011	800.00
2011-2012	800.00
2012-2013	800.00

महिला समाख्या कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता

2063. श्री निलेश नारायण राणे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में महिला समाख्या योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त स्वैच्छिक संगठनों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) असंतोषजनक कार्य निष्पादन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न पत्रों का लीक होना

2064. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने, धोखाधड़ी और प्रभावित करने को रोकने के लिए सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची में होने के नाते, इस संबंध में कार्रवाई करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा जानने के लिए विभिन्न उपाय करता है अर्थात् यह अपने द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को सुरक्षा सील लगे कपड़े के लिफाफों में रखता है और प्रश्न पत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जाता है जिन्हें केन्द्र के अधीक्षक को परीक्षा के आरम्भ होने से कुछ समय पहले सौंपा जाता है। शिकायतें मिलने पर सी.बी.एस.ई. गलती करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करता है और आरोप पत्र जारी करता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(घ) सी.बी.एस.ई. ने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपने स्कूलों में सतत् और व्यापक मूल्यांकन की स्कीम आरम्भ की है। सर्व शिक्षा अभिान (एस.एस.ए.) अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलने, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने, शिक्षकों को आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण देने, पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों की व्यवस्था करने, शिक्षकों को सीखने में वृद्धि करने के लिए नियमित शैक्षणिक सहायता देने सहित प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई हस्तक्षेप करता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुणवत्तायुक्त माध्यमिक शिक्षा की सर्वव्यापक सुलभता के उद्देश्य से सन् 2009 में शुरू किया गया है। केन्द्र प्रायोजित स्कीम "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर से पढ़ाई करने और आई.सी.टी. के प्रयोग को बढ़ावा देती है और उसके द्वारा शिक्षण और शिक्षा की प्रक्रिया को समृद्ध करती है।

विद्यालय प्रबन्धन समितियां

2065. श्री नवीन जिन्दल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय समिति (एस. एम.सी.) का गठन करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां एस.एम.सी. का गठन करना अपेक्षित था और विगत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार ऐसी समितियों का गठन कितने विद्यालयों में किया गया है;

(ग) क्या एस.एम.सी. अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एन.यू.ई.पी.ए.) ने देश-भर में इन एस.एम.सी. के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए कोई अध्ययन कराया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.यू.ई.पी.ए. के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(छ) स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ज) सरकार इन एस.एम.सी. के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल प्रबन्धन समिति गठित करने का अधिदेश करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए उन स्कूलों जहां स्कूल प्रबंध समितियां गठित की जानी है और उन स्कूलों जहां ऐसी समितियां गठित कर ली गई हैं; की संख्या संबंधी राज्य-वार अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है कि स्कूल प्रबंधन समितियां उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन राज्यों द्वारा अधिसूचित शिक्षा का अधिकार नियमों के अनुसार कर रही हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय (एन.यू.ई.पी.ए.) ने वर्ष 2009 में 14 राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उन शिक्षा समितियों, जिन्हें स्कूल प्रबन्धन और पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है, के कार्यकरण का एक अध्ययन किया है। 897 गांवों/वार्डों में स्थित और 42 जिलों में फैले 1006 स्कूलों में सम्बद्ध शिक्षा समितियों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है।

इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ समितियों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने और ऐसी समितियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने सहित माता-पिता को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की सिफारिश की गई है।

(छ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सांविधिक स्कूल प्रबंधन समिति के लिए व्यवस्था है और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि 75 प्रतिशत सदस्य संबंधित स्कूल में दाखिल किए गए बच्चों के माता-पिता/अभिभावक होंगे, लाभ वंचित समूहों और कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों के माता/अभिभावकों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

(ज) सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों को उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों को समझने और उनके कार्यकरण में सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

विवरण

स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करने वाले विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2011-12	
		स्कूलों की संख्या	गठित की गई स्कूल प्रबंधन समितियों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	309	309
2.	आन्ध्र प्रदेश	79673	79673
3.	अरूणाचल प्रदेश	3071	3071
4.	असम	48475	40095
5.	बिहार	70029	61656

1	2	3	4
6.	छत्तीसगढ़	47396	47394
7.	चंडीगढ़	104	104
8.	दादरा और नगर हवेली	270	270
9.	दमन और दीव	85	85
10.	दिल्ली	3154	0
11.	गोवा	1064	0
12.	गुजरात	34116	34116
13.	हरियाणा	15014	14974
14.	हिमाचल प्रदेश	15083	15083
15.	जम्मू और कश्मीर	31808	31808
16.	झारखंड	39849	39849
17.	कर्नाटक	45679	45679
18.	केरल	12647	12647
19.	लक्षद्वीप	44	44
20.	मध्य प्रदेश	111891	111891
21.	महाराष्ट्र	84834	84834
22.	मेघालय	12774	12774
23.	मणिपुर	2762	2762
24.	मिजोरम	2402	2402
25.	नागालैंड	2672	0
26.	ओडिशा	56335	55111
27.	पुदुचेरी	427	427
28.	पंजाब	20183	20183
29.	राजस्थान	68905	68905
30.	सिक्किम	781	781
31.	तमिलनाडु	44535	38569
32.	त्रिपुरा	4309	4309
33.	उत्तर प्रदेश	149985	149985
34.	उत्तराखंड	17760	17760
35.	पश्चिम बंगाल	79608	14263

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2066. श्री यशवंत लागुरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा सहित देश में गैर-सरकारी संगठनों को शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का गैर-सरकारी संगठन-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके तहत सहायता दी गई;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन अनियमितताओं की प्रकृति किस प्रकार की है;

(घ) क्या सरकार ने उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों पर कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास हेतु

स्वैच्छिक एजेंसियों को सहयोग की योजना के तीन संघटक हैं, जैसे जन शिक्षण संस्थान, राज्य संसाधन केंद्र और नवाचारी परियोजना हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता। पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) और चालू वित्त वर्ष के दौरान ओडिशा सहित राज्यों में जन शिक्षण संस्थानों और राज्य संसाधन केंद्रों के संबंध में जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I (क) और I (ख) पर दिया गया है। नवाचारी परियोजना हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंजीकृत सोसायटियों, सार्वजनिक न्यासों और लाभ न कमाने वाली कंपनियों को अनुदान जारी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में तथा चालू वर्ष के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में ओडिशा सहित देश भर में सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जहां तक सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, एक स्वैच्छिक एजेंसी यथा कथा, नई दिल्ली, जिसने 1.4.2010 से 31.3.2012 तक दिल्ली में अपनी परियोजना पर कार्य किया था, के विरुद्ध वित्तीय अनिमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है।

(च) इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान समिति आवधिक रूप से गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करती है। परियोजना के एक वर्ष पूरा होने के बाद अथवा परियोजना का पहला वर्ष समाप्त होने की आस-पास की तिथि पर संयुक्त मूल्यांकन दल, जिसमें सहायता अनुदान समिति का एक सदस्य, संबंधित राज्य के सर्व शिक्षा, अभियान के राज्य परियोजना निदेशक का नामिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक प्रतिनिधि होता है, द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों का मूल्यांकन किया जाता है। संयुक्त मूल्यांकन दल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण-I (क)

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान राज्यों में जन शिक्षण संस्थानों को जारी अनुदानों का विवरण

क्र.सं.	जन शिक्षण संस्थान का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	32941649.00	41064041.00	44152418.00	20351473.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2948395.00	3000000.00	2993000.00	1495330.00
3.	असम	9828416.00	14985523.00	14570484.00	7267113.00
4.	बिहार	28074065.00	33629308.00	37626109.00	19390759.00
5.	छत्तीसगढ़	10786157.00	20768542.00	20208283.00	9868738.00
6.	दिल्ली	11072600.00	8944624.00	8951517.00	4455433.00
7.	गोवा	2578893.00	2958621.00	2650469.00	1217316.00
8.	गुजरात	23690253.00	29918640.00	28994053.00	13861124.00
9.	हरियाणा	14565270.00	14997613.00	1497469.00	7468631.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1315802.00	2999997.00	2990130.00	1496000.00
11.	जम्मू और कश्मीर	4312361.00	6301571.00	5772661.00	3219062.00

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	13122952.00	15128708.00	14971527.00	7433858.00
13.	कर्नाटक	22191033.00	27775300.00	26061135.00	13717344.00
14.	केरल	25620911.00	27816964.00	25455328.00	13100798.00
15.	मध्य प्रदेश	79711211.00	98130528.00	94528114.00	47305093.00
16.	महाराष्ट्र	48174155.00	63846325.00	57908122.00	30629817.00
17.	मणिपुर	6661045.00	9000000.00	8938901.00	4448105.00
18.	मिजोरम	2565328.00	2996336.00	–	–
19.	नागालैंड	2894505.00	1497991.00	2998922.00	1389424.00
20.	ओडिशा	44834352.00	51710857.00	51565420.00	25874701.00
21.	पंजाब	5192436.00	5958584.00	5977797.00	2973000.00
22.	राजस्थान	19584452.00	22506514.00	22418774.00	10790595.00
23.	तमिलनाडु	23311243.00	31418000.00	28058733.00	12655194.00
24.	त्रिपुरा	2203450.00	2723424.00	2728394.00	1274224.00
25.	उत्तर प्रदेश	132476268.00	155448728.00	149595516.00	73225440.00
26.	उत्तराखंड	14351863.00	17677549.00	16625739.00	8242844.00
27.	पश्चिम बंगाल	21554732.00	29500000.00	24366710.00	12241710.00
28.	चंडीगढ़	2735688.00	3493516.00	3491133.00	1750000.00
29.	दादरा और नगर हवेली	1339455.00	2954833.00	2762566.00	1460440.00

विवरण-I (ख)

वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक 33 राज्य संसाधन केंद्रों को जारी अनुदानों का विवरण

क्र.सं.	राज्य संसाधन केंद्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	4	5	6	7
1.	प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत् शिक्षा राज्य संसाधन केंद्र-स्पेस, आंध्रा महिला सभा अकादमिक परिसर, उस्मानिया विश्वविद्यालय रोड, हैदराबाद	1,00,00,000	49,61,000	99,68,429	49,67,851

1	2	4	5	6	7
2.	राज्य संसाधन केंद्र, असम मंडोवी अपार्टमेंट, यूनिट सी और डी प्रथम तल जीएनबी रोड अम्बारी, गुवाहाटी	69,75,945	98,35,064	95,97,555	49,31,504
3.	राज्य संसाधन केंद्र, एशियन डवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीएसआईडीसी कालोनी, का. बोरिंग, पाटलिपुत्र रोड, पटना	93,76,732	58,74,982	73,40,719	30,96,307
4.	राज्य संसाधन केंद्र, दीपायतन, बुद्ध कालोनी, पटना	99,90,509	67,68,385	97,26,003	50,00,00
5.	जनदर्शन मीडिया केंद्र, देशबंधु काम्प्लेक्स, रामसागरपाड़ा रायपुर, (छत्तीसगढ़)	66,24,124	63,19,338	68,84,689	35,00,000
6.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केंद्र, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	66,93,164	57,78,229	69,99,566	35,00,000
7.	राज्य संसाधन केंद्र, सर्च, 42/29, चाणक्यपुरी शीला सिनेमा के पीछे रोहतक (हरियाणा)	68,67,000	89,22,000	77,01,211	27,08,492
8.	राज्य संसाधन केंद्र, राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र, शिवालिक सदन, इंजनघर, संजौली, शिमला	66,20,000	68,60,000	71,65,488	36,25,000
9.	राज्य संसाधन केंद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय 1/17 नसीमबाग केम्पस हजरतबल, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	20,80,000	70,00,000	62,29,888	34,54,467
10.	राज्य संसाधन केंद्र एशियन डवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 219 सी/रोड संख्या 2 अशोक नगर, रांची (झारखंड)	93,23,904	57,12,841	83,70,429	27,84,811
11.	राज्य संसाधन केंद्र, कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद्, पोस्ट बॉक्स 301 पुराना एचडी कोट रोड मैसूर (कर्नाटक)	1,00,00,000	50,00,000	97,73,002	44,84,492
12.	राज्य संसाधन केंद्र, पत्तम डाकघर तिरूवनंतपुरम (केरल)	100,00,000	22,57,379	72,68,656	47,36,093
13.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केंद्र, भातरीय ग्रामीण महिला संघ सेक्टर-आर महालक्ष्मी नगर इंदौर (मध्य प्रदेश)	62,53,916	83,64,954	87,44,890	38,10,432

1	2	4	5	6	7
14.	राज्य संसाधन केंद्र, अभिव्यक्ति ई-8/195 त्रिलंगा-भोपाल (म.प्र.)	44,91,540	85,59,510	72,67,447	38,03,730
15.	राज्य संसाधन केंद्र, पुणे, राष्ट्रीय सेवादल साने गुरूजी स्मारक, एस.एम. जोशी कला क्रीड़ा संकुल (एम.एस.)	50,00,000	82,11,252	96,07,504	48,15,520
16.	राज्य संसाधन केंद्र, महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान स्टेशन रोड, औरंगाबाद (एम.एस.)	68,97,820	55,07,169	69,99,566	34,99,800
17.	राज्य संसाधन केंद्र, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय बिजनी काम्प्लेक्स लेतुमखरा, शिलांग (मेघालय)	69,59,083	51,36,639	67,52,027	34,68,010
18.	राज्य संसाधन केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली	63,87,000	47,56,0000	56,79,131	24,49,766
19.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केंद्र, उड़ीसा, जन शिक्षा भवन यूनिट-ट, भुवनेश्वर (ओडिशा)	35,00,000	70,00,0000	58,36,835	–
20.	प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा राज्य संसाधन केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	–	–	–	–
21.	राज्य संसाधन केंद्र, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन 7-ए झालाना डूंगरी इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर	91,16,563	67,69,224	32,72,796	10,00,000
22.	राज्य संसाधन केंद्र संख्या 20, पहली गली वेंकटरत्नम नगर एक्स्टेंशन, अदयार, चेन्नई	1,00,00,000	41,91,177	41,91,177	–
23.	राज्य संसाधन केंद्र, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, त्रिपुरा जन शिक्षा भवन, मेलारमठ, नर्जुल छत्तरबास के समीप, अगरतला	49,16,776	22,57,684	24,43,519	12,17,675
24.	राज्य संसाधन केंद्र, लिटरेसी हाउस, पोस्ट मानस नगर, कानपुर रोड, लखनऊ	80,95,054	50,00,000	1,00,00,000	22,70,166
25.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केंद्र, 68/1 सूर्यलोक कालोनी, राजपुर रोड, देहरादून	60,30,480	38,39,000	86,25,562	25,46,673
26.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केंद्र, पश्चिम बंगाल, 50 बेलियाघाट मेन रोड, कोलकाता	99,97,387	79,62,114	99,57,190	47,49,522

1	2	4	5	6	7
27.	राज्य संसाधन केंद्र, अरूणाचल प्रदेश द्वितीय तल, दियाना अपार्टमेंट्स पुलिस स्टेशन के पास नाहरलागुन, 791110 अरूणाचल प्रदेश	–	55,00,000	59,99,638	32,66,178
28.	राज्य संसाधन केंद्र, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	–	62,00,000	67,34,000	14,06,520
29.	राज्य संसाधन केंद्र, जोधपुर, राजस्थान	–	50,00,000	70,00,000	26,09,429
30.	राज्य संसाधन केंद्र, नया राज्य संसाधन केंद्र, असम	–	–	30,00,000	–
31.	राज्य संसाधन केंद्र, नया राज्य संसाधन केंद्र, पलामू, झारखंड	–	–	30,00,000	–
32.	राज्य संसाधन केंद्र, रायगढ़, ओडिशा	–	–	25,00,000 (अनावर्ती)	–
33.	राज्य संसाधन केंद्र, भरूच, गुजरात	–	–	25,00,000 (अनावर्ती)	5,00,000

विवरण-II

सर्व शिक्षा अभियान के तहत गैर सरकारी संगठनों को जारी अनुदान

क्र.सं.	राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जारी राशि
1	2	3	4
2009-10			
1.	छत्तीसगढ़	रूपांतर, छत्तीसगढ़	1,19,902/-
2.	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखंड	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली	65,00,000/-
3.	दिल्ली	कथा, नई दिल्ली	73,19,000/-
4.	महाराष्ट्र	डोर स्टेप स्कूल, मुंबई	13,68,244/-
5.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश परियोजना हेतु प्रथम मुंबई	1,41,52,997/-
		कुल	2,94,60,143/-

1	2	3	4
2010-11			
1.	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखंड	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तराखंड में परियोजनाओं हेतु)	92,27,249/-
2.	बिहार	प्रथम, मुंबई (बिहार परियोजना)	1,06,20,392/-
3.	दिल्ली	निरंतर, नई दिल्ली	20,31,425/-
4.	दिल्ली	कथा, नई दिल्ली	62,37,164/-
5.	महाराष्ट्र	सबरंग न्यास, मुंबई	58,72,500/-
		कुल	3,39,88,730/-
2011-12			
1.	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखंड	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तराखंड में परियोजनाओं हेतु)	76,40,705/-
2.	दिल्ली	कथा, नई दिल्ली	1,45,50,200/-
3.	दिल्ली	निरंतर नियास, नई दिल्ली	15,00,000/-
4.	बिहार	देशकल सोसायटी, दिल्ली (बिहार परियोजना)	15,89,925/-
		कुल	2,52,80,830/-
2012-13			
			03.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार
1.	• बिहार	देशकल सोसायटी, (बिहार परियोजना) 220 एसएफएस फलेट्स, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009	12,62,898/-
2.	महाराष्ट्र	सबरंग न्यस, निरंतर, जुहू तारा रोड, जुहू मुंबई-400032	26,66,570/-
		कुल	39,29,468/-

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र के पी.एस.यू. का विलय

2067. **श्री के. सुगुमार :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के विलय के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. ने इस मामले पर अपने संगठनों के कर्मचारियों से पहले ही चर्चा कर ली थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम हुए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

2068. **श्री मनोहर तिरकी :**
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.सी.आर. द्वारा अन्य देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए प्रयोजित/प्रतिनियुक्ति सांस्कृतिक समूहों का देश-वार, विशेष अवसर और कार्यक्रमों के प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र से कलाकार या समूहों की सूची क्या है जिन्हें ऐसे अवसरों के लिए प्रायोजित/प्रतिनियुक्त किया गया;

(घ) क्या भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र से परम्परागत कला का प्रदर्शन और सांस्कृतिक समूहों को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) हालांकि, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) कोई अनुसंधान संस्था नहीं है, लेकिन यह अपनी वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत संस्कृति एवं भारतीय अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए विदेशी विद्वानों को सुविधाएं प्रदान करता है। उपर्युक्त योजना के अलावा, परिषद अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत में पी.एच.डी. और पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सहयोग भी देती है।

विदेशी विद्वानों के लिए लागू उपर्युक्त दो योजनाओं के अतिरिक्त, परिषद अपनी योजना "स्टडी विजिट्स ऑफ इंडियन स्कॉलर्स एबरॉड" के तहत 3 महीनों की अवधि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में फील्ड रिसर्च करने के लिए भारतीय शिक्षाविदों को सहयोग भी प्रदान करती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कला, संस्कृति तथा अन्य कार्यकलापों के निष्पादन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित/प्रतिनियुक्त समूहों का देश विशिष्ट अवसर, अवधि और कार्यक्रम के प्रकार का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ऐसे अवसरों के लिए प्रायोजित/प्रतिनियुक्त किए गए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कलाकारों/समूहों की सूची संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। जैसाकि अनुबंधों से देखा जा सकता है कि परिषद ने हमेशा ही इस क्षेत्र की पारंपरिक कला तथा सांस्कृतिक समूहों को शामिल करने का प्रयास किए हैं।

(च) लागू नहीं।

विवरण-I

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक कार्यान्वयन रिपोर्ट

क्र. सं.	देश जिनका दौरा किया गया	समूह का नाम	तारीख	दौरा का उद्देश्य	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	चीन	सुश्री गीता राधाकृष्ण, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 9 सदस्यीय मोहनीयअट्टम नृत्य समूह	5-8 अप्रैल, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
2.	तंजानिया लेसोथो दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे मोजाम्बिक	सुश्री सुशीला मेहता, आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व में के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	7 अप्रैल-6 मई, 2009	जिम्बाब्वे में 10वें हरारे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में भाग लेना और अन्य देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
3-5.	मॉरीशस,	(i) सदस्यीय कलारिपट्टू समूह, दिल्ली 10	7-20 अप्रैल, 2009	रीयूनियन दीप समूह में तमिल नव वर्ष समारोह के अवसर पर ए.आर.आर.सी.सी. द्वारा आयोजित महोत्सव में भाग लेना और मॉरीशस में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना।	
	रियूनियन द्वीपसमूह	(ii) दो दस्तकार : दिल्ली से एक मेंहदी कलाकार, और एक साज सज्जा (रंगोली/ कोलम) कलाकार दिल्ली से	13-20 अप्रैल, 2009		
	रियूनियन द्वीपसमूह	(iii) कथकली मेकअप का प्रदर्शन करने वाला एक कथक्रली कलाकार, केरल	13-20 अप्रैल, 2009		

1	2	3	4	5	6
6.	यू.एस.ए.	उस्ताद अली अहमद हुसैन खान (शहनाई), पश्चिम बंगाल को चार यात्रा अनुदान	9 अप्रैल-11 माई, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
7.	मलेशिया चीन	श्री कंवरप्रीत सिंह, दिल्ली के नेतृत्व में 13 सदस्यीय भांगड़ा समूह	14 अप्रैल-4 मई, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
8.	नेपाल	श्री विनोद कुमार, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय गजल समूह	18-20 अप्रैल, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
9.	स्पेन	सुश्री अदिति मंगलदास, दिल्ली के नेतृत्व में 13 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह, ''दृष्टिकोण''	20-23 अप्रैल, 2009	भारत के राष्ट्रपति महोदय की स्पेन यात्रा के अवसर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
10.	यू.के.	श्री दीपक कुमार चक्रबर्ती (तबला), पश्चिम बंगाल को एक यात्रा अनुदान	25 अप्रैल- 7 जून, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
11.	बंग्लादेश	जानकी सरकार, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 17 सदस्यीय आधुनिक नृत्य समूह 'डांसर्स गिल्ड'	27 से 30 अप्रैल,2009	''विश्व नृत्य दिवस'' में भाग लेना	
12.	यू.एस.ए.	दो सहयोगियों के साथ मोम गांगुली (मोहनी अट्टम) को तीन यात्रा अनुदान	29 अप्रैल से 7 मई,2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
13-14.	गुयाना, ट्रिनिडाड टोबैगो सूरीनाम वेनेज्वेला, यू.एस.ए. सेंट मार्टीन,	9 सदस्यीय संयुक्त समूह (i) सुश्री कुमुद दीवान, दिल्ली के नेतृत्व में 4 सदस्यीय लाइट क्लासिकल म्यूजिकल समूह	02 मई से 08 जून, 2009	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो तथा सूरीनाम में भारतीयों के आगमन दिवस समारोह के 171वें वर्षगांठ में भाग लेना और अन्य देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
	अरूबा गुयाबा, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो कोलम्बिया वेनेज्वेला, यूएसए सेंट मार्टीन अरूबा	(ii) सुश्री माहू शंकर, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कथन समूह	02 मई से 08 जून, 2009		
15.	बंगलादेश	डा. पी. बंद्योपाध्याय, पश्चिम बंगाल क नेतृत्व में 14 सदस्यीय अरोबिंदो अनुशीलन सोसायटी नृत्य समूह	13-17 मई, 2009	''सावित्री'' नृत्य नाटिका प्रस्तुत करना	
16.	यू.के.	श्री कुमार पाल राणा, गुजरात के नेतृत्व में ''श्री वासुकी सांस्कृतिक समूह'' का 12 सदस्यीय गुजरानी लोक नृत्य समूह	01-22 जून, 2009	ग्लासगो, नाटिंघम तथा बेलफोर्ड मेला में भाग लेना	
17.	दक्षिण कोरिया चीन	उत्तर पूर्वी आंचलिक सांस्कृति केन्द्र ''शीलॉग चैम्बर'' नागालैंड से 22 सदस्यीय गायन समूह	25 जून से 7 जुलाई 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	यह समूह दक्षिण कोरिया में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। परिषद ने चीन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए इस समूह को प्रायोजित किया

1	2	3	4	5	6
18-19.	स्पेन आस्ट्रिया	कलाकारों को 9 सदस्यीय अनुदान : (प) सुश्री बॉम्बे जयश्री रामनाथ (कार्नेटिक गायन), तमिलनाडु को 4 सदस्यीय यात्रा अनुदान	30 जून -03 जुलाई, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	परिषद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्पेन में बॉम्बे जयश्री रामनाथ समूह को प्रायोजित किया था। शेष पांच सदस्यों ने केवल आस्ट्रिया के लिए यात्रा अनुदान प्राप्त किया
	आस्ट्रिया	4-टी.एस. कृष्णा (कर्णाटक), तमिलनाडु को 4 सदस्यीय यात्रा अनुदान		साल्जबर्ग में भारतीय शास्त्रीय संगी महोत्सव में भाग लेना	
	आस्ट्रिया	श्री दुरजॉय भौमिक (तबला), दिल्ली को 1 यात्रा अनुदान			
20.	यू.एस.ए.	विश्व भारती, पश्चिम बंगाल गायन समूह को तीन यात्रा अनुदान	2-12 जुलाई, 2009	कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के निमंत्रण पर "फ्राम दि ट्रेडिशनल टू दि कंटम्पोरेरी" नामक उत्तरी अमेरिकन बंगाली सम्मेलन में भाग लेना	परिषद ने सैन फ्रांसिस्को सेक्टर के लिए यात्रा अनुदान किया था तथा हाउस्टन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रायोजित किया था
21.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री श्रुति बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	6-14 जुलाई, 2009	ग्राहम्सटाउन में राष्ट्रीय कला महोत्व में भाग लेना	
22-23.	जॉर्डन	9 सदस्यीय संयुक्त समूह :	15-21 जुलाई, 2009	जॉर्डन महोत्सव में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
		(i) सुश्री जयंती सुब्रामण्यम, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह (ii) सुश्री माला चंद्रशेखर, तमिलनाडु के नेतृत्व में 4 सदस्यीय बांसुरी वादक समूह			
24.	सीरिया	श्री धाने खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	6-13 अगस्त, 2009	बोसरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2009 में भाग लेना	
25.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो बार्बाडोस	सुश्री संगीता दास, ओडिशा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	7-20 अगस्त, 2009	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में भारत के महोत्सवमें भाग लेना और बार्बाडोस कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
26.	भूटान	सुश्री अदिति मंगलादास, दिल्ली के नेतृत्व में 13 सदस्यीय नृत्य समूह	13-17 अगस्त, 2009	भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
27.	श्रीलंका	श्री हरी और सुश्री चेतना, कर्नाटक के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	13-21 अगस्त, 2009	भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
28.	चीन	श्री तरुण प्रधान, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 14 सदस्यीय साराभुज समूह	13-26 अगस्त, 2009	11वें एशिया कला महोत्सव में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
29.	बंग्लादेश	देबारती मित्रा, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय रवीन्द्र संगीत समूह	14-19 अगस्त, 2009	भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
30.	नेपाल	श्री भजन सोपोरी, दिल्ली के नेतृत्व में 4 सदस्यीय संतूर समूह	14-16 अगस्त, 2009	भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
31.	मालदीव	श्री के.एस. रमेश, कर्नाटक के नेतृत्व में 11 सदस्यीय जादू समूह	17-20 अगस्त 2009	भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
32.	मालदीव	सुश्री शिल्पा उथप्पा, कर्नाटक के नेतृत्व में 5 सदुस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	19-22 अगस्त 2009	भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
33.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	4 सदस्यीय कवि समूह	22-28 अगस्त 2009	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में भारत के महोत्सव में भाग लेना	
34.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	सुश्री विद्या शाह, दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय भक्ति संगीत समूह	22-30 अगस्त 2009	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में भारत के महोत्सव में भाग लेना	
35.	बुल्गारिया मेसीडोनिया ग्रीक	श्री जोगिंदर एस हब्बी, हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व में 12 सदस्यीय ''चुरेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल'' नृत्य समूह	24 अगस्त,-14 सितम्बर 2009	बोरगास में 37वें अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव (आई.एफ.एफ.) और ग्रीक में थेसालोनकी अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
36.	उजबेकिस्तान	भुगरा खान, राजस्थान के नेतृत्व में 8 सदस्यीय राजस्थानीय लोग नृत्य समूह	24-31 अगस्त, 2009	अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव ''सार्क तरोनालारी'' में भाग लेना	
37.	श्रीलंका	तमिलनाडु से 12 सदस्यीय करगम एवं कवाडी लोक नृत्य समूह	3-10 सितम्बर, 2009	श्रीलंका के राष्ट्रीय साक्षरता एवं कला महोत्सव में भाग लेना	
38.	जर्मनी	सुश्री सोराजा टैगोर एवं श्री मिलन अधिकारी, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	3-13 सितम्बर, 2009	डी.आई.जी. चेन टूर के लिए	
39.	ग्रीक	सुश्री आरुषी मुदगल, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	4-14 सितम्बर, 2009	ग्रीक में थेसोलिनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेना	
40.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री दक्ष सेठ नृत्य कंपनी, केरल को 6 यात्रा अनुदान	9-18 सितम्बर, 2009	साझा इतिहास महोत्सव-2009 में भाग लेना	
41-42.	फ्रांस	(i) औरोविले फाउण्डेशन, पुदुचेरी का 4 सदस्यीय शुभादा संगीत समूह	14-18 सितम्बर, 2009	यूनेस्कों में श्री अरविंदों की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
		(ii) सुश्री रोजा खन्ना, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरटनाट्टयम नृत्य समूह			

1	2	3	4	5	6
43.	थाईलैंड वेंटेन सिंगापुर	कत्थक केन्द्र दिल्ली से 15 सदस्यीय कथक नृत्य समूह ''पुनरनावा''	15-24 सितम्बर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
44.	जापान	सुश्री मौमाला नायक एवं हेमंत कलिता, दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	17-30 सितम्बर, 2009	टोकियों में नए भारतीय सांस्कृति केन्द्र के उदघाटन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना और नमस्ते भारत महोत्सव और फुकुओका एशियाई कला महोत्सव में भाग लेना	
45.	जापान	पंडित दूबे चौधरी, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय सितार वादक समूह	24-27 सितम्बर, 2009	टोकियो में नए भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के उदघाटन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
46.	भूटान	सुश्री गुलाबी सपेरा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	29 सितम्बर- 9 अक्टूबर, 2009	इंट्रैट रेजिंग दिवस समारोह में भाग लेना	
47.	मॉरीशस	अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन, राजस्थान के नेतृत्व में 6 सदस्यीय गजल समूह	30 सितम्बर - 5 अक्टूबर, 2009	राष्ट्रीय ईद समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
48.	इटली	श्री नौरंग लाल, दिल्ली से 5 सदस्यीय कठपुतली नृत्य समूह	1-13 अक्टूबर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
49.	दक्षिण कोरिया	श्री जॉयचंद्रन के नेतृत्व में अट्टाकलारी सेंटर फॉर मूवमेंट के समकालीन नृत्य समूह को 11 यात्रा का 50 प्रतिशत अनुदान	5-8 अक्टूबर, 2009	सियोल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
50.	यमन कतर	सुश्री प्रतिष्ठा शर्मा, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	6-13 अक्टूबर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
51.	आस्ट्रेलिया मलेशिया सिंगापुर	श्री वी.पी. धनंजय एवं भारतनाट्यम नृत्य समूह को 8 यात्रा अनुदान	7 अक्टूबर-10 नवम्बर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
52.	सीरिया	श्री अदीप घोष, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में 2 सदस्यीय सितार वादक समूह	7-16 अक्टूबर, 2009	सीरिया सिल्क रोड महोत्सव में भाग लेना	
53.	न्यूजीलैंड	श्री अमरदीप सिन्हा जे.जे. जडेजा, गुजरात के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह ''सौराष्ट्र लोक कला केन्द्र''	8-25 अक्टूबर, 2009	दिवाली समारोह में भाग लेना	
54.	दक्षिण अफ्रीका लेसोथो	श्री अश्वनी कुमार, दिल्ली के नेतृत्व में ''फील्स इटरनेशनल समूह का 11 सदस्यीय लाइट क्लासिकल समूह	8-26 अक्टूबर, 2009	दिवाली समारोह में भाग लेना	
55.	सिंगापुर लाओ पी.डी.आर.	सुश्री जय गणेश लोक कला, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 12 सदस्यीय लवानी लोक नृत्य	9-17 अक्टूबर, 2009	दिवाली समारोह में भाग लेना	
56.	ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान	श्री गुलाम कादिर के नेतृत्व 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	8-15 अक्टूबर, 2009	ताजिकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय महोत्व-संगोष्ठी ''फलक'' में भाग लेना और उजबेकिस्तान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
57.	आस्ट्रेलिया	10 सदस्यीय मणिपुरी "जगोई मारुप", मणिपुर नृत्य समूह	9-19 अक्टूबर, 2009	दिवाली समारोह में भाग लेना	
58.	जापान दक्षिण कोरिया	सुश्री मंजू हेमामालिनी, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कुच्चीपुडी नृत्य समूह	9-29 अक्टूबर, 2009	दिवाली के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
59.	त्रिनीडाड एवं टोबैगो सेंट वेसेंट ग्रेनैडिनेस	सुश्री मेहदीरत्ता, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 11 सदस्यीय रंग पुहर लोग नृत्य समूह	13-30 अक्टूबर, 2009	दिवाली समारोह में भाग लेना	
60.	इथोपिया	श्री अभिजीत पोहंकर, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 6 सदस्यीय फ्यूजन समूह	16-21 अक्टूबर, 2009	दिवाली उत्सव में भाग लेना	
61.	फ्रांस	शगुन पुरुषोत्तमन, तमिलनाडु के नेतृत्व में गायन ग्रुप समूह को 5 यात्रा अनुदान	17-19 अक्टूबर, 2009	त्यागराज उत्वस में भाग लेना	
62.	नेपाल	पंडित विश्वमोहन भट्ट (गिटार), राजस्थान को एक यात्रा अनुदान	20-23 अक्टूबर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
63.	नाइजीरिया	सुश्री मनीष गुलयानी (कत्थक), राजस्थान को एक यात्रा अनुदान	3-9 नवम्बर, 2009	टूफेस्टा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव 2009 में भाग लेना	
64.	मेक्सिको	सुश्री गीतांजलि शर्मा, के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से 10 सदस्यीय लोक नृत्य समूह	4-10 नवम्बर, 2009	नाओ डे चीन महोत्सव में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
65.	मिश्र लीबिया माल्टा	इशिरा पारिख एवं श्री मौल्क शाह, दिल्ली के नेतृत्व में ''अनार्ट'' का 12 सदस्यीय समकालीन समूह	9-26 नवम्बर 2009	कैरो अंतर्राष्टीय फिल्म महोत्सव में भाग लेना तथा लीबिया एवं माल्टा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
66.	कम्बोडिया	श्री सोमेश्वर तरन, असम के नेतृत्व में ऐमोनी गोगोई बिहू दल का 10 सदस्यीय बिहू नृत्य समूह	10-13 नवम्बर, 2009	भारत-कंबोडिया व्यापार एवं निवेश व्यवसाय मंच में भाग लेना	
67.	इटली	श्री सोमेश्वर तरन, असम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय वायलिन वादक समूह	12-15 नवम्बर, 2009	''सुवोनी डाल मोंडो'' महोत्सव में भाग लेना	
68.	बंग्लादेश	सुश्री अनुराधा कपूर, नई दिल्ली के नेतृत्व में एन.एस.डी. से 16 सदस्यीय ''विवादी'' थिएटर समूह	13-19 नवम्बर, 2009	अंतर्राष्ट्रीय इब्सेन रंगमंच महोत्सव 'इब्सेन थ्रो न्यू आईज'' में ''जान गैब्रियल बोर्कमैन'' नामक नाटक का मंचन करना	
69.	इजरायल	सुश्री सुधा रधुनाथ, तमिलनाडु के नेतृत्व में कारनेटिक गायन समूह	16-20 नवम्बर, 2009	ओ.यू.डी. महोदत्व में भाग लेना	
70.	इजराइल तुर्की	सुश्री राजश्री चिंतक बहेरा, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिशा नृत्य समूह	20 नवम्बर-1 दिसम्बर, 2009	इजराइल में हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना तथा तुर्की में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
71.	श्रीलंका	श्री मधु गोपीनाथ एवं वाक्कोम सजीव, केरल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समकालीन नृत्य ''समुद्र'' समूह	21-25 नवम्बर, 2009	तीसरे सार्क विजनेस लीडर्स कंक्लेव (एस.बी.एल.सी.) में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
72.	थाईलैंड	श्री भाष्कर कोग्गा, कामथ (कर्णाटक), के नेतृत्व में	1-8 दिसम्बर, 2009	महामहिम नरेश के जन्म दिवस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भाग लेना	
73.	आस्ट्रेलिया	सुश्री मंजिरी केलकर (हिंदुस्तानी गायन), महाराष्ट्र को तीन यात्रा अनुदान	3-9 दिसम्बर, 2009	विश्व धर्म संसद, मेलबोर्न में भारत का प्रतिनिधित्व करना	
74.	यू.एस.ए.	सुश्री शांति हीरानंद, दिल्ली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय हिंदुस्तानी गायन समूह	3-13 दिसम्बर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
75.	कोलम्बिया त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो बार्बाडोस यू.एस.ए. कनाडा सेंट लूसिया	सुश्री प्रिया वेंकटरमन, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	25 नवम्बर-17 दिसम्बर, 2009	''भारत का महोत्सव'' में भाग लेना	
76.	नेपाल	सुश्री आलोक पर्व कानुगो, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय ओडिसी ''शिंजन नृत्यालय'' नृत्य समूह	7-14 दिसम्बर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
77.	म्यांमार	निजामी खुसरो बंधु के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	7-15 दिसम्बर, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
78.	यू.एस.ए.	सुश्री सुजाता महापात्रा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिशी नृत्य समूह	9-14 दिसम्बर, 2009	''उर्स'' महोत्सव के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
79.	मॉरीशस	सुश्री शैला हत्तांगदी गुलबादी क्वार्टेट को सात यात्रा अनुदान	13-19 दिसम्बर, 2009	मॉरीशस के राष्ट्रपिता तथा मारीशस के पहले प्रधानमंत्री के 24वें स्मरण दिवस में भाग लेना	
80.	अल्जीरिया	श्री प्रकाश वर्मा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय ''मीरा काला मंदिर'' राजस्थानी लोक नृत्य समूह	17-22 दिसम्बर, 2009	रेगिस्तानी लोगों का चौथा महोत्सव	
81.	ग्रीक	सुश्री यशोदा सी. राव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कुच्चीपुडी नृत्य समूह	20 दिसम्बर, 2009-10 जनवरी, 2010	बोलोस अंतर्राष्ट्रीय महोत्व में भाग लेना	
82.	वियतनाम	श्री नरेश कुमार के नेतृत्व में एक आधुनिक नृत्य समूह	30 दिसम्बर, 2009-5 जनवरी, 2010	डा लैट पुष्प महोत्सव में भाग लेना	
83.	मेक्सिको बेलिजे ग्वाटेमाला	सुश्री कुम कुम धर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	14-28 जनवरी, 2010	भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
84.	दक्षिण अफ्रीका	श्री अर्नुन मिश्र के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	23-30 जनवरी, 2010	भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	25-29 जनवरी, केपटाउन,
85.	भूटान भून्टशिलिंग	सुश्री भानु डेका, असम के नेतृत्व में 14 सदस्यीय बिहू नृत्य समूह	23-29 जनवरी, 2010	भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
86.	श्रीलंका	श्री एम. श्रीधर एवं सुश्री अनुराध श्रीधर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	24 जनवरी-2 फरवरी, 2010	भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
87.	चीन	सुश्री रश्मि विद्यालिंगम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कुच्चीपुडी नृत्य समूह तथा सुश्री रागिनी कृष्णन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय भरनाट्यम नृत्य समूह	25-30 जनवरी, 2010	भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
88.	यू.के.	सुश्री गीता चन्द्रन के नेतृत्व में 8 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	3-14 फरवरी, 2010	भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
89.	मलेशिया	श्री जयराम राव तथा सुश्री बंसारी राव, नई दिल्ली के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कुच्चीपुडी नृत्य समूह	8-12 फरवरी, 2010	मलेशिया में नए भारतीय सांस्कृतिक केन्द के उद्घाटन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
90.	अफगानिस्तान	श्री अलाउद्दीन खान, नई दिल्ली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय यसराज समूह	16-26 फरवरी, 2010	अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
91.	सीरिया	श्री जसविंदर सिंह पारस, दिल्ली के नेतृत्व में 15 सदस्यीय आधुनिक ''जसविंदर पारस'' (बॉलीवुड) नृत्य समूह	21 फरवरी,-6 मार्च, 2010	अंतराष्ट्र छात्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
92.	ओमान	श्री दिनेश सेन के नेतृत्व में 12 सदस्यीय हिमाचल लोक नृत्य समूह ''सूत्रधार कला संगम''	23 फरवरी,-1 माच, 2010	गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
93.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	श्री मुरारी लाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 10 सदस्यीय चारकुला नृत्य समूह	26 फरवरी,- 20 मार्च, 2010	त्रिनिडाड में होली महोत्सव तथा मोंटसेराट में पैट्रिक दिवस समारोह में भाग लेना	
94.	आस्ट्रेलिया	केरल कलामंडलम का 14 सदस्यीय कथकली समूह (यात्रा अनुदान) हतंदज)	2-12 मार्च, 2010	एडिलेड में वोमा दशक महोत्वस तथा मोंटसेराट में पैट्रिक दिवस समारोह में भाग लेना	मोहिंदर ढिल्लों ''नटराज''
95.	बंग्लादेश	सुश्री मंजरी चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सूफी कत्थक समूह	10-20 मार्च, 2010	आई.सी.सी. के उद्घाटन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
96.	फ्रांस	सुश्री कौशिक भट्टाचार्य (तबला) एवं उनके सहयोगी श्री राजनारायण भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल को दो यात्रा अनुदान	10 मार्च,-1 अप्रैल, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
97.	फ्रांस	सुश्री क्षेमवती कला मंडलम (मोहिनीअट्टम) को 5 यात्रा अनुदान	12 मार्च-3 अप्रैल, 2010	''फेस्टिबल डि इमैजनेरे'' नामक महोत्सव के 14वें संस्करण में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
98.	सर्बिया क्रोएशिया स्लोवेनिया हंगरी	सुश्री ममता शंकर, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 12 सदस्यीय आधुनिक समकालीन नृत्य समूह ''ममता शंकार बैलेट''	16 मार्च-2 अप्रैल, 2010	टैगोर पर एक सममेलन के अवसर पर स्लोवेनिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
99.	नेपाल	श्री वी, उन्नीकृष्णन के नेतृत्व में अंतराष्ट्रीय कथकली केन्द्र से 8 सदस्यीय कथकली नृत्य समूह	19-26 मार्च, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
100.	फ्रांस	श्री दीपक महाराज, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कत्यक नृत्य समूह	24 मार्च-9 अप्रैल, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

अप्रैल, 2010- मार्च, 2011

क्र. सं.	देश जिनका दौरा किया गया	समूह का नाम	तारीख	दौरा का उद्देश्य	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	रियूनियन द्विपसमूह	सुश्री इंदिरा देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह ''मेइतेई परंपरागत नृत्य''	4-19 अप्रैल, 2010	रियूनियन द्वीपसमूह में तमिल नव वर्ष समारोह में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
2.	यू.एस.ए.	प्रो.टी.आर. सुब्रामण्यम और डॉ. राधा वेंकटचलम (कर्णाटिक गायन), तमिलनाडु दो यात्रा अनुदान	14 अप्रैल,-29 जून, 2010	जी.एन. बालसुब्रामण्यम (जी.एन.बी.) वैश्विक शताब्दि समारोह के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
3.	सिंगापुर	सुश्री अरीत कौर, पंजाब के नेतृत्व में ''अमृतसर नाटक कला केन्द्र'' का 10 सदस्यीय पंजाबी रंगमंच समूह	22-24 अप्रैल, 2010	बैशाखी मेला में भाग लेना	
4.	मलेशिया	श्री दविंदर सिंह, पंजाब के नेतृत्व में 14 सदस्यीय भांगड़ा गिद्धा समूह ''जुगनी कल्चरल एण्ड यूथ''	22-26 अप्रैल, 2010	बैशाखी समारोह में भाग लेना	
5.	कम्बोडिया	सुश्री रीना देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	24 अप्रैल,-1 मई, 2010	सि.एम. रीप, कबोडिया में ''ट्रायल आफ सिविलाइजेशन'' के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
6.	जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका	श्री भोये शिवाजी कपरूभाई, गुजरात के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह ''युवक मंडल गधावी''	25 अप्रैल, 9 मई, 2010	जिम्बावे में हरारे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव (एच.आई.एस.ए.) में भाग लेना तथा दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
7.	जर्मनी	बंगलौर म्यूजिक स्कूल, कर्णाटक से बाल समूह को 14 यात्रा अनुदान 14 यात्रा अनुदान	1-10 मई, 2010	चिल्ड्रेन कोयर फेस्टिवल में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
8.	सिंगापुर मलेशिया	श्री प्रबुद्ध राहा, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 14 सदस्यीय रवीन्द्र संगीत समूह	10-15 मई, 2010	''एन एज इन मोशन : दि एशियन वोएज ऑफ रवीन्द्र नाथ टैगोर'' नामक सम्मेलन के दौरान सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
9.	इटली तुर्की	श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में बांसुरी वादन समूह	12-20 मई, 2010	इटली की ट्यूरिन अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तक मेला के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करना और तुर्की में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
10.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो सूरीनाम	सुश्री गंगाबाई कामद राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	25मई-8 जून, 2010	भारतीय आगमन दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
11.	म्यांमार	श्री माओसुबोंग, नागलैंड के नेतृत्व में पांच सदस्यीय म्यूजिकल बैंड समूह ''एबियोजेनेसिस म्यूजिक बैंड''	27-31 मई, 2010	राष्ट्रीय रंगमंच, रंगून में तथा राष्ट्रीय रंगमंच मण्डाले में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
12.	जापान	श्री कलाकृष्णन, आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कुचीपुडी नृत्य समूह	28 मई-10 जून, 2010	वेदांत सोसायटी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
13.	यू.के.	श्री समंदर खान मंगानेर, राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक संगीत समूह ''लोक रंग परिषद''	2-21 जून, 2010	प्रेस्टन मेला, ब्रैडफोर्ड मेला और ग्लासगो मेला में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
14.	वियतनाम	सुश्री अरुन्धती राय, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	5-13 जून, 2010	ह्यू महोत्सव में भाग लेना	
15.	साइप्रस	सुश्री सुकन्या राम गोपाल (ताल वाद्य काचेरी के साथ घाटम), कर्णाटक के नेतृत्व में 5 सदस्यीय महिला ताल वाद्य काचेरी समूह	6-11 जून, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
16.	मलेशिया	सुश्री उर्मिला सत्यनारायण, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भारतनाट्यम समूह	10-14 जून, 2010	भारतनाट्यम के दूसरे महोत्व में भाग लेना तथा व्याख्यान एवं कार्यशाला का संचालन करना	
17.	इटली	श्री सय्यद सलाउद्दीन पाशा, नई दिल्ली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय भारतनाट्यम समूह	10-20 जून, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
18.	मलेशिया	सुश्री शुभ्रा भारद्वाज के नेतृत्व में 17 सदस्यीय बालीवुड समूह	11-17 जून, 2010	क्वींस बैटन रैली के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करना	चीन में भारत महोत्सव से विपथन
19.	कांगो किंगशाशा	श्री अशोक शर्मा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय यू.पी. लोक कला समूह "बृज लोक कला मंच और और जागृति मण्डल"	22-28 जून, 2010	किंगशासा की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
20.	यू.एस.ए.	सुश्री श्रेयसी मित्रा (रबीन्द्र संगीत), पश्चिम बंगाल तीन यात्रा अनुदान	26 जून-8 जुलाई, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
21.	यू.एस.ए.	श्री रंगपुथाली, रघुनंनदन, कर्णाटक एक यात्रा अनुदान	28 जून-20 जुलाई, 2010	नाविक विश्व प्रथम कन्नड़ शिखर बैठक में कार्यक्रम	
22.	इटली यू.के.	सुश्री इलेना सिटारीसिट, ओडिशा से नेतृत्व में 8 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	30 जून-16 जुलाई, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
23.	दक्षिण अफ्रीका	श्री गुलाम सबीर एवं श्री गुलाम वारिस, दिल्ली के नेतृत्व मे 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	1-20 जुलाई, 2010	साबेरी उर्स महोत्सव में भाग लेना	
24.	रूस	सुश्री अनरूपा रॉय, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कठपुतली समूह	2-20 जुलाई, 2010	कठपुतली रंगमंच के छठवें अंतर्राष्ट्रीय इको-अर्थेटिक महोत्सव ''चिर छायायन'' में भाग लेना	
25.	नार्वे	सुश्री ज्योत्सना शौरी (भारतनाट्यम), नई दिल्ली को 4 यात्रा अनुदान *4 यात्रा अनुदान*	8-11 जुलाई, 2010	नार्वे में फोर्ड नृत्य एवं संगीत महोत्सव में भाग लेना	
26.	ओमान दोहा यू.ए.ई. (दुबई, अबुधाबी)	सुश्री चरनजीत सोनी एवं फरीद अहमद खान, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय संयुक्त संगीत समूह	10-25 जुलाई, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
27.	वियतनाम	श्री अरुनांगशू चौधरी, दिल्ली सदस्यीय फ्यूजन बैंड/हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र समूह 'इम्पल्स'	21-26 जुलाई, 2010	हो ची मिन्ह शहर में बीच महोत्सव में भाग लेना	
28.	आयरलैंड	श्री मोदानीदांबूर संजीव पुजारी, कर्णाटक के नेतृत्व में 12 सदस्यीय यक्षगान समूह ''संजीव सुर्वन''	22-28 जुलाई, 2010	विश्व संस्कृति महोत्सव (एफ.डब्ल्यू.सी.) में भाग लेना	
29.	उजबेकिस्तान	श्री सुरंजन दास, कुलपति, कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	25-30 जुलाई, 2010	उजबेकिस्तान में ''भारत का वर्ष'' के अंग के रूप में भारत - उजबेक मैत्री पर व्याख्यान देना	
30.	कनाडा	श्री कादरी गोपाल नाथ (सैक्सोफोन), चेन्नई 5 यात्रा अनुदान	28 जुलाई-3 अगस्त, 2010	श्रृंगेरी विद्या भारती फाउंडेशन द्वारा आयोजित एस.बी.वी.एफ.के. ग्रैस कंसीक्रेशन (कुंबाभिषेखम) के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
31.	मॉरीशस	श्री जौहर अली, नई दिल्ली के नेतृत्व में 7 सदस्यीय फ्यूजन समूह ''सरगम''	28 जुलाई,- 4 अगस्त, 2010	नवल बैटल ऑफ ग्रैंड पोर्ट की द्विशताब्दी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
32.	इजरायल	श्री राज कुमार भट्ट, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कठपुतली समूह	1-9 अगस्त, 2010	35वां अंतर्राष्ट्रीय कला एवं शिल्प मेला-2010 में भाग लेना	
33.	मालदीव	श्री मूथूकाड, केरल का 15 सदस्यीय जानू समूह	2-6 अगस्त, 2010	भारत-मालदीव मैत्री माह समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
34.	ओमान	श्री संदीप कुमार खीवा, पंजाब में नेतृत्व में 12 सदस्यीय भांगड़ा समूह	5-9 अगस्त, 2010	सलालाह, ओमान में खरीफ महोत्सव में भाग लेना	
35.	भूटान	श्री सुजात हुसैन खान, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय सितार समूह	13-16 अगस्त, 2010	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
36.	श्रीलंका	सुश्री शर्मीला विश्वास, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	13-21 अगस्त, 2010	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
37.	यू.एस.ए. कनाडा	गुरु राधामोहन, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कथकली समूह	14-22 अगस्त, 2010	यू.एस.ए. में ''इरेजिंग बार्डर फेस्टिबल आफ इण्डियन डांस 2010'' में भाग लेना और कनाडा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
38.	तुर्कमेनिस्तान	श्री अश्वनी कुमार, दिल्ली के नेतृत्व में 11 सदस्यीय पंजाबी समूह ''फील्स इंटर-नेशनल'' समूह	14-22 अगस्त, 2010	''आवाज 2010'' महोत्सव-संगीत, गायन एवं नृत्य के महोत्सव में भाग लेना	
39.	ग्रीक	श्री डी बालाराम रेड्डी, ओडिशा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय ओडिसी लोक कला समूह	20-30 अगस्त, 2010	लेफकास के 48वें अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में भाग लेना	
40.	मिश्र	श्री मोहम्मद रफीक लांगा, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय ओडिसी लोक कला समूह	23 अगस्त - 5 2010	सूफी सम्मा महोत्सव में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
41.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री मैत्रेयी पहाड़ी, दिल्ली के नेतृत्व में 20 सदस्यीय लोक कला समूह	28 अगस्त, 3 सितम्बर, 2010	इण्डिया शो में भाग लेना	
42.	दक्षिण अफ्रीका	मोहिनीअट्टम संस्था केन्द्र, नई दिल्ली से 18 सदस्यीय मोहिनीअट्टम नृत्य समूह	6-20 सितम्बर, 2010	साझा इतिहास महोत्सव 2010 के दौरान अपने प्रोडक्शन ''स्वान लेक'' को प्रस्तुत करना	
43.	आस्ट्रेलिया	प्रो. टी.एन. कृष्णन, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कर्णाटक वायलिन समूह	9 सितम्बर,-5 अक्तूबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
44.	यू.एस.ए.	श्री उदय भालवालकर (ध्रुपद), महाराष्ट्र *2 यात्रा अनुदान*	9 सितम्बर-9 नवम्बर	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
45.	यू.एस.ए.	सुश्री लुशिन दुबे (रंगमंच), नई दिल्ली, *8 यात्रा अनुदान*	10 सितम्बर-13 अक्टूबर, 2011	संगीतमय नाटक 'सलाम इण्डिया' का मंचन	
46.	मालदीव	श्री सुरेंद्र सागर एण्ड पार्टी, पंजाब के नेतृत्व में 14 सदस्यीय पंजाबी लोक नृत्य समूह	15-20 सितम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
47.	यू.के.	श्री कलामंडल गोपी, केरल के नेतृत्व में कथकली समूह 5 यात्रा अनुमादन	15 सितम्बर - 3 दिसम्बर, 2010	यू.के. में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना और कार्याशालाओं का संचालन करना	

1	2	3	4	5	6
48.	बंग्लादेश	सुश्री निवेदिता पार्थसारथी, तमिलनाडु के नेतृत्व में पांच सदस्यय भरतनाट्यम नृत्य समूह	15-24 सितम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
49-51.	कतर मस्कट यू.ए.ई(अनुधाबी)	(i) श्रीमती गोवर्धन कुमारी राजस्थान के नेतृत्व में दो सदस्यीय राजस्थानी नृत्य समूह	25 सितम्बर-5 अक्टूबर, 2010	दोहा में भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेना	
	कतर मस्कट यू.ए.ई.(अबुधाबी) कुवैत	(ii) निजामी बंधुओं (श्री चांद निजामी), नई दिल्ली का 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	25 सितम्बर-8 अक्टूबर, 2010		
	कतर	(iii) सुश्री रेखा मेहरा, नई दिल्ली के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	25-29 सितम्बर, 2010		
52-54.	मिस्त्र	(i) श्री रितेश रंजन सहाय, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय तलाशी म्युजिकल बैंड (ii) श्री अमरजीत सिंह, मणिपुर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह "रंग निकेतन" (iii) श्री जे.सी. जडेजा, गुजरात के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह "हलार लोक कला केन्द्र"	26 सितम्बर- 4 अक्टूबर, 2010	मिस्त्र में भारत सप्ताह में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
55.	दक्षिण कोरिया थाईलैंड	पंडित बिरजू महराज, नई दिल्ली के नेतृत्व में 21 सदस्यीय बैलेट समूह जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: (i) सुश्री दीपिका रेड्डी के के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कुच्चीपुडी नृत्य समूह (ii) 3-सुश्री प्रिया वेंकट रमन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह (iii) सुश्री पार्वती दत्त के नेतृत्व में तीन सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह (iv) सुश्री पर्मिता मैत्रा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कथक नृत्य समूह (v) सुश्री बिंबावती देवी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	28 सितम्बर- 18 अक्टूबर, 2010	थाईलैंड में 12वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव में भाग लेना और दक्षिण कोरिया में ज्योंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल की 10वीं वर्षगांठ में भाग लेना	
56.	भूटान	श्री अभिजीत पोहंकर, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 6 सदस्यीय फ्यूजन समूह	29 सितम्बर-6 अक्टूबर, 2010	इम्ट्रैट रेजिंग डे समारोह में भाग लेना	
57.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री चेतना जलान, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह ''पदाटिक''	30 सितम्बर - 5 अक्टूबर, 2010	डरबन में चौथे क्षेत्रीय पी.बी.डी. सम्मेलन में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
58.	यू.एस.ए.	श्री सदनम हरि कुमार वसंतम, केरल के नेतृत्व में कथकली नृत्य समूह ''सतविकम कला सदनम'' *7 यात्रा अनुदान*	30 सितम्बर - 8 अक्टूबर, 2010	भारतीय शास्त्रीय नृत्य के महोत्सव ''ट्रेडिशंस इंगेज्ड'' में भाग लेना	
59.	वियतनाम ताइवान	श्री गोपा कुमार कुम्मन, केरल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कलारीपयट्टू समूह ''सी.वी.एन. कलारी नाडा कवाऊ कालीकट''	1-17 अक्टूबर, 2010	नैन यिंग अतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में भाग लेना	
60.	नेपाल	श्री प्रहलाद ब्रह्मचारी, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय बौल समूह	2-6 अक्टूबर 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
61-62.	न्यूजीलैंड	(i) श्री गाजी खान, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी समूह (ii) श्री उदय जादूगर, कर्णाटक के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जादू समूह	13 अक्टूबर - 3 नवम्बर, 2010	दिवाली के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
63.	केन्या, दक्षिण अफ्रीका	श्री उमाकांत सिंह नामेराकपम, मणिपुर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह ''एन. इबोहनबी''	13 अक्टूबर - 1 नवम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
64.	नार्वे	सुश्री रुक्मिणी चटर्जी, नई दिल्ली के नेतृत्व में भरतनाट्यम नृत्य समूह	15-23 अक्टूबर, 2010	''नेशनल नार्वेजियन ओपेरा एण्ड वैलेट'' कार्यक्रम में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
65.	दुबई	श्री नील रंजन मुखर्जी, नई दिल्ली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन समूह ''आहंग'' *3 यात्रा अनुदान*	13-17 अक्टूबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
66.	सीरिया	श्री हरीश गंगानी, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	17-22 अक्टूबर, 2010	सीरिया में पालपिरा महोत्सव में भाग लेना	
67.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	श्री शहादत हुसैन, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कव्वाली समूह	19-28 अक्टूबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
68.	उजबेकिस्तान रूस	श्री आफताब शाबरी तथा श्री हाशिम शाबरी, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	19-25 अक्टूबर, 2010	उजबेकिस्तान में ''भारत का वर्ष'' के अंग के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
69.	मेक्सिको	सुश्री मंगला भट्ट, आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	20 अक्टूबर - 5 नवम्बर, 2010	सेरवैंटिनो महोत्सव औ ला नाओ महोत्सव में भाग लेना	
70.	आस्ट्रेलिया	श्री रहमत खान लांगा, नई दिल्ली का 15 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	27 अक्टूबर-13 नवम्बर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
71.	इटली	सुश्री सर्वपल्ली माधवीमाला, आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कुच्चीपुड़ी द्वीप समूह	29 अक्टूबर - 4 नवम्बर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
72.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो सूरीनाम यू.एस.ए.	श्री जोरावर सिंह जादव, गुजरात के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भावी बहुरूपी एवं एक्रोबेटिक समूह	29 अक्टूबर-14 नवम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
73.	क्यूबा सेंट डोमिनिगो	श्री रमेशन मारक्कर वल्लापील, केरल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कला समूह ''हिन्दुस्तानी कलारी संगम''	1-10 नवम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
74.	रूस	श्री बच्चू खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व में राजस्थानी लोक नृत्य समूह	4-11 नवम्बर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
75.	इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका	श्री सुभाष गोयल एवं सुश्री अंजू गोयल, नई दिल्ली के नेतृत्व में 16 सदस्यीय पंजाबी संगीत (वेरायटी) समूह	5-23 नवम्बर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
76.	चीन	सुश्री ऐश्वर्या नित्यानंद, आन्ध्रप्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	10-16 नवम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
77.	जापान इंडोनेशिया रूस	सुश्री राजश्री काले नागरकर, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 12 सदस्यीय लवानी समूह	11-25 नवम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
78.	वियतनाम	श्री सुबीर मलिक, नई दिल्ली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय बैंड समूह ''परिक्रमा''	12-16 नवम्बर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
79.	चीन	श्री बाबू खान, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	15-29 नवम्बर, 2010	ग्वांझाऊ, चीन में दूसरे फुबाओ ग्रामीण सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेना	
80.	इजरायल	उस्ताद इकबाद अहमद खान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन समूह	20-22 नवम्बर, 2010	ओ.यू.डी. महोत्सव में भाग लेना	
81-85.	बंग्लादेश	(i) श्री राजेन्द्र गंगानी (कत्थक) x 7, दिल्ली (ii) श्री रीता गांगुली (हिंदुस्तानी गायन) x 7, दिल्ली (iii) श्री देबज्योति बोस (सरोद) x 3, पश्चिम बंगाल (iv) श्री सुभाष गोयल एवं सुश्री अंजू गोयल (पंजाबी लोक कला) x 15, दिल्ली (v) श्री मनोज मित्रा (रंगमंच) x 20, पश्चिम बंगल	26 नवम्बर,-3 दिसम्बर, 2010	बंगलादेश में भारतीय महोत्सव ''आनंद यज्ञ'' में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
86.	नाइजीरिया	सुश्री राखी सपेरा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	27-30 नवम्बर, 2010	''अबुजा कार्निवाल'' में भाग लेना	
87.	यू.के.	श्री मुजफ्फर अली, कोरियोग्राफर, नई दिल्ली *दो यात्रा अनुदान*	1-8 दिसम्बर, 2010	''जहाने खुसरो'' परियोजना के लिए अग्रिम दौरा	
88.	सेनेगल	सुश्री सिद्दी रुमानाबेन छोटूभाई, गुजरात के नेतृत्व में 10 सदस्यीय सिद्दी गोमा समूह	21-26 दिसम्बर, 2010	अश्वेत कला एवं संस्कृति के विश्व महोत्सव में भाग लेना	
89.	म्यांमार	श्री अनवर साबारी बंधुओं, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कव्वाली समूह	11-19 जनवरी, 2011	म्यांमार के विभिन्न शहरों में सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
90.	मॉरीशस	श्री गोविंद रंजन एलानगोवन, दिल्ली के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कर्णाटिक गायन समूह	11-21 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
91.	सिंगापुर	सुश्री सोभना नारायणन, दिल्ली के नेतृत्व में 13 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	12-15 जनवरी, 2011	इण्डिया शो में भाग लेना	
92.	भूटान	श्री परविंदर सिंह, पंजाब के नेतृत्व में 14 सदस्यीय भागड़ा एवं गिद्धा समूह	22-27 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
93.	कतर (दोहा)	श्री राजिन्दर टोंक, नई दिल्ली के नेतृत्व में 14 सदस्यीय भांगड़ा समूह	24-27 जनवरी, 2011	एशियन दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
94.	श्रीलंका	श्री कोट्टाकल चंद्रशेखरन, केरल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कथकली समूह	24 जनवरी, 2 फरवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
95.	नेपाल	श्री सतीश बब्बर, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय गायन समूह	24-28 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
96-97.	यू.ए.ई. (अबुधाबी)	दो सांस्कृतिक समूह : (i) श्री जयपू खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य (ii) उस्ताद एम. जाफर निजामी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	25 जनवरी-2 फरवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
98.	थाईलैंड	सुश्री श्वेता मिश्रा, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कत्थक, नृत्य समूह	25-28 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
99.	यमन (साना)	श्री भोगरा खान, राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	25-29 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
100.	चीन	सुश्री नम्रता पमनानी, दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	25-29 जनवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
101.	तुर्की	सुश्री मंजरी चौधरी, उत्तर-प्रदेश के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	2-5 फरवरी, 2011	वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के दौरे के अवसर पर आयोजित इण्डिया शो में भाग लेना	
102.	जर्मनी पोलैंड	सुश्री सीमा तिवारी, एन.सी. आर., उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भोजपुरी समूह	8-15 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
103.	किरगिस्तान रूस	सुश्री अनीता शर्मा, असम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सत्रिया समूह	9-21 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
104.	आस्ट्रेलिया	श्री एन. नारायण सिंह, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय पुंग एवं ढोल चोलम समूह	11-19 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
105. 106.	फिलिपींस	(i) श्री जुनैन हलीम खान (सितार) X 3, महाराष्ट्र (ii) श्री अभिजीत राय चौधरी (सरोद) X 4, उत्तर प्रदेश	12-26 फरवरी 2011	तीसरे अंतर्राष्ट्रीय रोंडाला महोत्सव में भाग लेना	
107.	हंगरी स्लोवेनिया रोमानिया	सुश्री प्रियदर्शनी शोम, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समकालीन समूह	14-23 फरवरी, 2010	27वें सरजेवो शीत महोत्सव में भाग लेना	
108.	नेपाल	सुश्री जिला खान, दिल्ली के नेतृत्व में 4 सदस्यीय लाइट म्यूजिक (सूफी) समूह	17-21 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
109.	मॉरीशस	सुश्री पियुष कैलाश अनुज, दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय भक्ति संगत समूह	25 फरवरी-3 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
110.	बंग्लादेश	सुश्री विद्या शाह, दिल्ली के नेतृत्व में 4 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन (भक्ति संगत) समूह	1-5 मार्च, 2011	गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर ''वुमेन ऑन रिकार्ड'' पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
111.	मॉरीशस	सुश्री फर्नानांडा मारिया मेलिटा मेनेजेस ई डियास, गोवा के नेतृत्व में गोवा कला अकादमी का 12 सदस्यीय सांस्कृतिक समूह	6-14 मार्च, 2011	''कार्निवल ऑफ विक्टोरिया इंटरनेशनल'' में भाग लेना	
112.	मेक्सिको बेलिजे	सुश्री काकोली बोस, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	11-24 मार्च, 2011	इण्डिया वीक में भाग लेना	
113.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	श्री कार्तिकेश्वर राणा, ओडिशा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मयूर भंज छाऊ समूह ''दक्षिणी साही छाऊ नृत्य मंदिर''	14-24 मार्च, 2011	होली/फगुवा एवं सेट पैट्रिक्स दिवस समारोह में भाग लेना	
114.	यू.एस.ए.	सुश्री शिवानी वजीर पसरीचा, नई दिल्ली, आई.सी.सी.आर. के पैनल में शामिल कलाकार	मार्च, 2011 के मध्य में	''द्रौपदी'' नाटक का मंचन करना	परिषद ने समूह को 5 लाख रूपए की एकमुश्त राशि प्रदान की
115.	बंग्लादेश	पंडित जसराज, नई दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय गायन समूह	16-20 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
116.	आस्ट्रिया स्विटजरलैंड	सुश्री विधा लाल, नई दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समकालीन कत्थक नृत्य समूह	17-27 मार्च, 2011	आस्ट्रिया में भारत सांस्कृतिक सप्ताह में भाग लेना और बासेल, स्विटजरलैंड में हीरे एवं जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
117.	जर्मनी	श्री जौहर अली, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय वायलिन समूह	18-21 मार्च, 2011	मिटेलडिटसर रुंडफंक (एम.डी.आर.) मीडिल जर्मन रेडियो स्टेशन द्वारा स्टेशन द्वारा आयोजित ''रिचे इंश-फर्स्ट रो'' नामक कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
118.	जर्मनी अल्जीरिया स्विटजरलैंड	सुश्री सरोजा वैद्यनाथन, नई दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	18 मार्च- 4 अप्रैल, 2011		
119.	आस्ट्रिया यूक्रेन	श्री अनवर खान, राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	19-30 मार्च, 2011	आस्ट्रिया में भारत सांस्कृतिक सप्ताह में भाग लेना	
120.	स्विटजरलैंड	सुश्री लैशराम बिना देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	22-27 मार्च, 2011	बासेल, स्विटजरलैंड में हीरे एवं जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तत करना	
121.	यूक्रेन	सुश्री अनुराग वर्मा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समकालीन कत्थक नृत्य समूह	23-29 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
122.	यू.एस.ए. फ्रांस	श्री वसीफुद्दीन डागर (भक्ति संगीत) *5 यात्रा अनुदान*	28 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
123.	यू.एस.ए.	सुश्री विजयलक्ष्मी (मोहिनी अट्टम), नई दिल्ली *5 यात्रा अनुदान*	30 मार्च-8 अप्रैल, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
124.	मस्कट	श्री राकेश उपाध्याय, उत्तर-प्रदेश के नेतृत्व में 8 सदस्यीय भोजपुरी समूह	30 मार्च-2 अप्रैल, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

1 अप्रैल, 2011-31 मार्च, 2012

क्र. सं.	देश जिनका दौरा किया गया	समूह का नाम	तारीख	दौरा का उद्देश्य	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	वियतनाम	श्री तसेरिंग सोनम सोपानी के नेतृत्व में उत्तरीकला एवं संस्कृति सोसाइटी का 13 सदस्यीय जम्मू और कश्मीर लोक नृत्य समूह	5-13 अप्रैल, 2011	बौद्ध सम्मेलन तथा टैगोर पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए	
2-9.	यू.के.	(i) श्री हंस राज के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सूफी समूह	14-17 अप्रैल, 2011	जहाने खुसरो महोत्सव में भाग लेने के लिए	

1	2	3	4	5	6
		(ii) सुश्री मंजरी चौधरी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय सूफी कम्थक समूह (iii) श्री वजाहत हुसैन के नेतृत्व में 6 सदस्सीय कव्वाली समूह (iv) सुश्री मालिनी अवस्थी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय लाइट क्लैसिकल म्युजिक समूह (v) सुश्री मालविका सरुकई के नेतृत्व में 4 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह (vi) श्री नवतेज जिंह जौहर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह (vii) श्री गुलाम नबी नमथाहली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय हिंदुस्तानी गायन समूह (viii) रूमी फाउंडेशन को 11 यात्रा अनुदान			
10.	जिम्बाब्वे	सुश्री संगथिया सोलनबेन हंसदेव जी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गुजराती लोक कला समूह ''कंकड़''	25 अप्रैल,-5 मई, 2011	हरारे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव (एच. आई.एफ.ए.) में भाग लेना	
11.	यू.एस.ए.	श्री सैय्यद सलमान चिश्ती (शाही कव्वाली समूह) के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	25 अप्रैल,- 17 मई, 2011	हरारे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव (एच.आई.एफ.ए.) में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
12.	आस्ट्रेलिया	सुश्री स्नेहा चक्रधर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कव्वाली समूह	28 अप्रैल,- 8 मई, 2011	स्मिथसोनियन संग्रहालय में सूफी सम्मेल में भाग लेना	
13-15.	इजरायल	टीम वर्क के लिए यात्रा (i) सुश्री अदिति मंगल दास के नेतृत्व में कत्थक नृत्य समूह (ii) पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के नेतृत्व में पांच सस्यीय वाद्य यंत्र समूह (iii) चार विद्वान : सुश्री अल्का पाण्डे (क्यूरेटर), सुश्री नमिता गोखले, श्री तरुण तेजपाल और सुश्री उर्वशी बुटालिया (लेखक)	2-23 मई, 2011	''सेलेबरेटिंग इण्डिया इन इजरायल'' में भाग लेना	
16-17.	ईरान	(i) श्री बुंडू खान के नेतृत्व में 8 सदस्यीय राजस्थानी लोक संगीत समूह (ii) श्री अभय रुस्तम में 10 सदस्यीय राजस्थानी समूह समूह	10-17 मई, 2011 09-18 मई, 2011	''भारतीय संस्कृतिक के दिन'' में भाग लेना	
18.	मॉरीशस	श्री उमराव खान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी समूह	12-19 मई, 2011	महाराणा प्रताप दिवस कार्यक्रम में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
19.	यू.एस.ए.	सुश्री लिल्लेटी दुबे के नेतृत्व में थिएटर समूह प्राइम टाइम को यात्रा अनुदान	12-23 मई, 2011	अपना ''वेडिंग अलबम'' नाटक मंचित करने के लिए	
20.	स्लोवेनिया	सुश्री राधिका शाह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	23-26 मई, 2011	''संस्कृति में सामंजस्य'' कार्यक्रम में भाग लेना	
21.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो ग्रेनाडा बार्बाडोस सूरीनाम	श्री संदीप शर्मा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय ''नक्ष वर्षा'' भांगड़ा एवं गिद्धा समूह	28 मई,-18 जुन, 2011	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में 166वें भारतीय आगमन दिवस में भाग लेना और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
22.	सूरीनाम	श्री शिव प्रसाद दास के नेतृत्व में 14 सदस्यीय बिहू समूह ''असम ज्योति सांस्कृतिक गोष्ठी''	28 मई,-18 जून, 2011	भारतीय आगमन दिवस समारोह में भाग लेना	
23.	जर्मनी	श्री प्रेम कुमार मलिक के नेतृत्व में द्रुपद समूह को 5 यात्रा अनुदान	6 जून-5 जुलाई,2011	''मलिक फेमिली ड्रीम टूर 2011-ए न्यु जनरेशन और ऑन स्टेजेज'' नामक उनके कंसर्ट टूर के लिए	
24.	दक्षिण अफ्रीका	श्री अभिजीत अजय पोहंकर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय फ्यूजन बैंड समूह	16-26 जून, 2011	दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न शहरों में भारत के लघु महोत्सव में भाग लेना	
25.	अज़रबेजान	श्री अम्मन अली बंगम के नेतृत्व में 5 सदस्यीय सरोद वादन समूह	23 जून, 3 जुलाई, 2011	गंजा एवं शेखी शहरों में आयोजित होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव ''सिल्क वे'' में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
26.	दक्षिण अफ्रीका मॉरीशस	सुश्री उमा शर्मा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	23 जून-10 जुलाई, 2011	दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न शहरों में भारत के लघु महोत्सव में भाग लेना	
27.	मलेशिया	श्री मोहसिन अली खान के के नेतृत्व में 4 सदस्यीय सितार वादन समूह	24-28 जून, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
28.	इंडोनेशिया	श्री बाला कृष्णन नायर जगदीशन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कथकली नृत्य समूह	1-4 जुलाई, 2011	सोलो इंटरनेशनल पर्फामिंग आर्ट (एस.आई.पी.ए.) में भाग लेना	
29.	दक्षिण अफ्रीका	श्री यार मोहम्मद लंगा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	1-8 जुलाई, 2011	ग्राहम्सटाउन महोत्सव में भाग लेना	
30.	तुर्की रूस	श्री सिंधव करणभाई भायाभी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय गुजराती समूह	7-12 जुलाई, 2011	इंटरनेशनल गोल्डन कर्गोज फोक डांस कंपटीशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
31.	यू.एस.ए.	श्री नितिन नाथ हर्ष के नेतृत्व में राजस्थानी लोक कला समूह ''रिदम आफ राजस्थान'' को 7 यात्रा अनुदान	8 जुलाई, 30 अगस्त	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
32.	स्पेन अल्जीरिया	श्री रिदमल खान के नेतृत्व में 14 सदस्यीय राजस्थानी समूह	10-22 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक महोत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
33.	फिनलैंड इस्टोनिया	सुश्री मोनी माला बोराह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय बिहू नृत्य समूह ''दक्षायिनी सांस्कृतिक गोष्ठी''	20-30 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
34.	आस्ट्रेलिया	सुश्री कलापिनी कोमकली (हिंदुस्तानी गायन) को तीन यात्रा अनुदान	19-26 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
35.	यू.के.	श्री कायटानो फ्रांसिस्को नेपोलियो बैटेटो मार्टिन के नेतृत्व में गोवा कला अकादमी से 14 सदस्यीय गोवा सांस्कृतिक समूह	22-24 जुलाई, 2011	वैश्विक गोवा सम्मेलन 2011 में भाग लेना	
36.	मलेशिया सिंगापुर	सुश्री सुमन देवगन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय लाइट क्लासिकमल (गजल) समूह	22-26 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
37.	मस्कट	सुश्री संगीता सोनल बेन हंसी देवी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय गुजराती समूह ''कंकड़''	27 जुलाई-2 अगस्त, 2011	सलालाह में खरीफ महोत्सव में भाग लेना	
38.	नीदरलैंड	श्री राकेश उपाध्याय के नेतृत्व में 8 सदस्यीय भोजपुरी समूह	29 जुलाई-1 अगस्त 2011	हेग में मिलन महोत्सव में भाग लेना	
39.	दक्षिण अफ्रीका	श्री अमित चौधरी को 4 यात्रा अनुदान	29 जुलाई-2 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
40.	फ्रांस	पृथ्वी थिएटर के सदस्यों को 2 यात्रा अनुदान : श्री गोपाल और सुश्री कनि कुसरूती	2-21 अगस्त, 2011	फूट्स बार्न के वास्तविक वार्षिक रंगमंच कार्यशाला में भाग लेना	
41.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो ग्रेनाडा	सुश्री मरियालेना पी. मासकरेनहास एडियास के नेतृत्व में 14 सदस्यीय गोवा लोक नृत्य समूह ''गोयनचिम नोकेत्रम''	6-16 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
42.	मिस्त्र	सुश्री उर्मिला देवी ''चंचल भारती'' के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	11-26 अगस्त, 2011	सूफी महोत्सव ''समा'' में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
43.	यू.एस.ए.	श्री आशीष खोखर के समूह को 5 यात्रा अनुदान	11 अगस्त - 11 सितम्बर, 2011	तीन मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 नर्तकों द्वारा सीधा कॉस्ट्यूम प्रदर्शन के साथ मोहन खोखर नृत्य प्रदर्शनी का प्रदर्शन करने के लिए	
44.	भूटान	श्री मोआनुंगसन सुबोंग, नागालैंड के नेतृत्व में 4 सदस्यीय बैंड समूह ''एबियोजेनिस''	12-20 अगस्त, 2011	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
45.	श्रीलंका	सुश्री नलिनी तथा सुश्री कमलिनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	13-21 अगस्त, 2011	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
46.	फिजी	सुश्री मीरा दास के नेतृत्व में 12 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	13-23 अगस्त, 2011	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के 40 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
47.	हंगरी	सुश्री सिप्रा गोयल के नेतृत्व में 12 सदस्यीय बालीवुड समूह	14-22 अगस्त, 2011	वार्षिक पुष्प महोत्सव में भाग लेना	
48.	दक्षिण अफ्रीका	श्री थेक्के वीडू मणिकंदन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कर्णाटक गायन समूह गायन समूह	14-23 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
49.	नेपाल	सुश्री शोभना नारायण के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	15-20 अगस्त, 2011	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
50.	कनाडा	श्री ई.के. सिन्हा, नागालैंड के नेतृत्व में शिलांग चैम्बर कोयर ग्रुप को 19 यात्रा अनुदान	18-22 अगस्त, 2011	टोरंटो महोत्सव में भाग लेने के लिए	
51.	वियतनाम	सुश्री मोहिनी रूपनाथ के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	18-29 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
52.	उजबेकिस्तान	श्री नजीर अहमद खान हैदराबाद के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कव्वाली समूह	25-30 अगस्त, 2011	"शारक तरोनालरी" (मेलोडी ऑफ ओरिएंट) महोत्सव में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
53	नेपाल	सुश्री दीप माला मोहन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय गायन समूह	30 अगस्त - 9 सितम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
54	यू.एस.ए.	श्री अमोल पालेकर एवं उनकी पत्नी सुश्री संध्या गोखले को दो यात्रा अनुदान	1-3 सितम्बर, 2011	मुनाफा न कमाने वाले संगठन नाट्य भारती के लिए दो नाटकों का निर्देशन करना	
55-56.	बंगलादेश	(i) सुश्री सर्मिष्ठा मुखर्जी, नई दिल्ली के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह (ii) सुश्री जयति घोष के नेतृत्व में 5 सदस्यीय गायन समूह	6-8 सितम्बर, 2011	सार्क बैठक के सिलसिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
57.	किरगिस्तान	सुश्री सोनल सगतिया के नेतृत्व में 11 सदस्यीय गायन समूह	6-11 सितम्बर, 2011	''सेकण्ड वर्ल्ड फेस्टिल ऑफ इपिक पीपुल ऑफ दि वर्ल्ड'' में भाग लेना	
58.	तंजानिया केन्या	श्री गुलाम क़ादिर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	14-23 सितम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
59-61.	दक्षिण अफ्रीका	(i) श्री सलीम खान राजस्थानी लोक समूह को 8 यात्रा अनुदान	2-12 सितम्बर, 2011	ई/आई एण्ड टीम वर्क द्वारा आयोजित दक्षिण अफ्रीका में साक्षा इतिहास-भारतीय अनुभव के पांचवें संस्करण में भाग लेना	
		(ii) लीलीटे दुबे को 6 एयर टिकट	7-16 सितम्बर, 2011		

1	2	3	4	5	6
		(iii) श्री अस्ताद देवो (समकालीन नृत्य) x 10	13-24 सितम्बर, 2011		
62.	यू.एस.ए. यू.के. यू.एस.ए.	सुश्री कौशल्या रेड्डी को दो यात्रा अनुदान सुश्री भावना रेड्डी (कुच्चीपुडी)	18 सितम्बर - 6 अक्टूबर, 2011 18 सितम्बर - 17 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना एवं व्याख्यान-प्रदर्शन का संचालन करना	
63.	यू.के.	गायन कलाकार श्री सतीश बब्बर एवं सुश्री वाणी बब्बर को दो यात्रा अनुदान	22 सितम्बर - 22 अक्टूबर, 2011	गांधी जयंती के अवसर पर सोसायटी ऑफ फ्रेंड्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
64.	जर्जिया	श्री विक्रम आयंगा के नेतृत्व में ''रानन'' समूह को 9 यात्रा अनुदान	23-30 सितम्बर, 2011	तबिलिसी इंटरनेशन थिएटर फेस्टिवल भाग लेना	
65.	यू.के.	गोलम फकीर, बाबू फकीर, गोपन देबनाथ और नूर आलम से बने बाबू फकीरी समूह को 9 यात्रा अनुदान	26 सितम्बर - 9 अक्टूबर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
66.	अर्मेनिया	डा. यमनम सदानंद सिंह के नेतृत्व में कंगलेई माइमे थिएटर रेपरटोरी समूह को 15 यात्रा अनुदान	28 सितम्बर - 9 अक्टूबर, 2011	हाई फेस्ट इंटरनेशनल पर्फार्मिंग आर्ट फेस्टिवल 2011 में भाग लेना	
67.	यू.एस.ए.	सुश्री लीला सैमसन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कला क्षेत्र समूह	28 सितम्बर - 13 अक्टूबर, 2011	''भारत का वर्ष'' के अंग के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
68.	फ्रांस	श्री जी.एस. राजन (बांसुरी वादक) को 4 यात्रा अनुदान	30 सितम्बर - 12 अक्टूबर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
69.	श्रीलंका	श्री टी.एम. कृष्णा (कर्णाटक गायन) को चार यात्रा अनुदान	1-8 अक्टूबर, 2011	नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
70.	आस्ट्रेलिया	श्री रॉयस्टेन अबेल के नेतृत्व में मंगानेर सिडक्शन समूह को 15 यात्रा अनुदान	3-10 अक्टूबर, 2011	मेलबॉर्न महोत्सव में भाग लेना	
71.	जर्मनी	श्री जयचंद्रन पल्झी के नेतृत्व में अट्टाकलारी ग्रुप ऑफ अट्टाकलारी सेंटर फार मूवमेंट आर्ट को 9 यात्रा अनुदान	5-16 अक्टूबर, 2011	अपना डांस प्रोडक्शन ''ट्रेसेस'' और ''मेई ध्वनि'' प्रस्तुत करना	
72.	भूटान	श्री संजीव भार्गव के नेतृत्व में ''शेहर'' से तीन सदस्यीय समूह	10-14 अक्टूबर, 2012	महामहिम भूटान नरेश की साही शादी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
73-74.	न्यूजीलैंड	(i) सुश्री सीतालक्ष्मी साहूकारू का 4 सदस्यीय कठपुतली समूह (ii) सुश्री अमूसना देवी नोंगथोम्बम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	6-17 अक्टूबर, 2011	दिवाली समारोह में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
75.	मेक्सिको	श्री अमृत नटराज के नेतृत्व में 4 सदस्यीय परक्यूशन ग्रुप ''लाया नादामृत''	10-25 अक्टूबर, 2011	इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सरवेंटिनो के 9वें संस्करण में भाग लेना	
76.	बेरूत फिनलैंड तुर्कमेनिस्तान रूस	श्री सुदेश कुमार नायर नेतृत्व में 14 सदस्यीय बालीवुड ''मैट्रिक्स'' समूह	10 अक्टूबर- 7 नवम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
77.	ताइवान	श्री रतीकांत महापात्र के नेतृत्व में ''सृजन'' ओडिसी नृत्य समूह, ओडिसा X 10	12-23 अक्टूबर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
78.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो सूरीनाम	श्री इफ्तेखार अहमद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	13-23 अक्टूबर, 2011	ईद महोत्सव में भाग लेना	
79.	जर्मनी	सुश्री अलेख्या पुंजला के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कुच्चीपुडी नृत्य समूह	15-21 अक्टूबर, 2011	''भारत सांस्कृतिक सप्ताह'' में भाग लेना	
80.	कनाडा	सुश्री सर्मिष्ठा मुखर्जी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	15-23 अक्टूबर, 2011	''इंडिया शो'' सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत	
81.	आस्ट्रिया	रणजीत सेनगुप्ता (सरोद वादक) को एक यात्रा अनुदान	15-31 अक्टूबर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
82.	भूटान	सुश्री रीला होता के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	18-23 अक्टूबर, 2011	इमट्रैट रेजिम दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
83.	कतर	श्री एल्विस गोयस के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	19-25 अक्टूबर, 2011	''विश्व गोवा दिवस'' में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
84.	चेक गणराज्य	श्री सलीम खान लंगा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	19-22 अक्टूबर, 2011	संस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
85.	आस्ट्रिया कतर फंजंत	श्री नीले खान मोहदसद्दीकी के नेतृत्व में 18 सदस्यीय कव्वाली समूह	19-25 अक्टूबर, 2011	सालम ओरियंट फेस्टिवल में भाग लेना	
86.	इथोपिया	श्री अकबर मिया गुलमाली कादरी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गुजराती लोक कला ''सीदी धमाल सीदी गोमा'' समूह	21-29 अक्टूबर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
87.	आस्ट्रिया	श्री संतोष कुमार नायर के नेतृत्व में 13 सदस्यीय समकालीन ''साध्या'' समूह	25-31 अक्टूबर, 2011	पिंजगाउ फेस्टिवल में भाग लेना	
88.	आस्ट्रिया	सुश्री क्रुती सुभाष चन्द्र पारिख के नेतृत्व में 5 सदस्यीय इलूजन मैजिक ग्रुप	25-31 अक्टूबर, 2011	पिंजगाउ फेस्टिवल में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
89.	कनाडा यू.के. यू.ए.ई.	सुश्री सोहेला चरनालिया (कपूर) के नेतृत्व में 20 सदस्यीय थिएटर ग्रुप ''माहिम जंक्शन''	31 अक्टूबर - 21 नवम्बर, 2011	पिंजगाउ फेस्टिवल में भाग लेना	
90.	इंडोनेशिया फिजी	श्री संजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में 13 सदस्यीय रामायण समूह ''बृज लोक कला रामायण''	2-16 नवम्बर, 2011	भारत एवं इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरा होने के अवसर पर योग्याकार्टा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
91.	कोलम्बिया	श्री कल्पेश दलाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय गुजराती लोग कला समूह ''अविष्कार	7-26 नवम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
92.	स्पेन	सुश्री गीतांजलि लाल के नेतृत्व में कत्थक केन्द्र प्रोडक्शन ''ऋतु रंग X 12	11-13 नवम्बर, 2011	कासा डे ला इण्डिया की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
93-95.	अल्जीरिया	(प) सुश्री रानी खनम के नेतृत्व में 7 सदस्यीय सुफी कत्थक नृत्य समूह (पप) श्री अनीस सिद्दीकी, अरबी कैलियोग्राफिस्ट (पपप) श्री मोहम्मद बाबा मोहयुद्दीन	21-28 नवम्बर, 2011	त्लेमसेन-वर्ष के लिए विश्व की इस्लामी सांस्कृतिक राजधानी-2011 में ''इण्डिया वीक'' में भाग लेना	
96.	हांगकांग	श्री मधु मार्गी, केरल के नेतृत्व में कुडिअट्टम समूह को चार यात्रा अनुदान	22-29 नवम्बर, 2011	अदृश्य विरासत कार्यक्रम के 10वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर	

1	2	3	4	5	6
97.	तंजानिया	श्री पूरण भट्ट के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कठपुतली समूह एवं एक जादूगर	23-28 नवम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
98.	नाइजीरिया	श्री चंदू पाणिकर के नेतृत्व में 15 सदस्यीय थेयम समूह ''अनुष्ठान केन्द्र कोवाल''	25 नवम्बर - 4 दिसम्बर, 2011	''अबुजा कार्निवल-2011'' में भाग लेना	
99.	यू.ए.ई.	श्री तेहल सिह खीवा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय रंगला पंजाब समूह	26 नवम्बर - 6 दिसम्बर, 2011	40वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेना	
100.	नेपाल	श्री तसेर सिंह तसेरिंग दार्जी मेग्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय अजी ल्हासू मास्क नृत्य समूह	2-5 दिसम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना हिमालयन ओडिसी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
101.	थाईलैंड	श्री रमन कुट्टी नायर के नेतृत्व में 15 सदस्यीय कथकली नृत्य समूह	3-10 दिसम्बर, 2011	अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में भाग लेना	
102.	मॉरीशस	सुश्री पायल रामचंदानी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कुच्चीपुडी नृत्य समूह	4-10 दिसम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
103.	तंजानिया	श्री जे.सी. जडेजा के नेतृत्व 10 सदस्यीय गुजराती समूह	6-14 दिसम्बर, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
104.	क्यूबा	श्री जोये अल्वा रेस के नेतृत्व में नाद ब्रह्म बैंड समूह को 6 यात्रा अनुदान	14-20 दिसम्बर, 2011	विश्व संगीत महोत्सव में भाग लेना	
105.	मलेशिया फिजी	श्री परमजीत सिंह नरूला के नेतृत्व में 15 सदस्यीय बॉलीवुड समूह ''कार्मिक कनेक्शन''	22 दिसम्बर, 2011 - 6 जनवरी, 2012	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के 40 वर्ष पूरा होने पर भारत महोत्सव - 2011-12 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
106.	म्यांमार	श्री गुलाम हुसैन के नेतृत्व में नियाजी बंधुओं का 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	23 दिसम्बर 2011 - 2 जनवरी, 2012	उर्स महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
107.	ब्राजील	श्री एन. रवि किरण के नेतृत्व में 4 सदस्यीय विचित्र वीणा समूह	11-20 जनवरी, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
108.	चीन	सुश्री किरण सहगल के नेतृत्व में 13 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	12-19 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
109.	बंग्लादेश	सुश्री मोनालिसा घोष के नेतृत्व में 7 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	20-29 जनवरी, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
110	श्रीलंका	सुश्री अदिति मंगलदास के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह	20-31 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
111.	अल्जीरिया	सुश्री रविन्द्र कौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय भांगड़ा एवं गिद्धा समूह	22 जनवरी - 5 फरवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
112.	मालदीव	श्री अभिषेक माथुर के नेतृत्व में 9 सदस्यीय बैंड समूह ''अद्वैत''	24-27 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
113.	जाम्बिया तंजानिया	''पंजाब पुलिस सांस्कृतिक टोली'' का 14 सदस्यीय भांगड़ा एवं गिद्धा समूह	24 जनवरी- 02 फरवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
114.	फिजी	सुश्री सविता देवी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन संगीत समूह	24 जनवरी - 07 फरवरी, 2012	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के 40 साल पूरा होने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
115.	यू.ए.ई.	सुश्री अवनी मर्कंधभाईरूसी के नेतृत्व में समन्वय का 12 सदस्यीय गुजराती लोक कला समूह	25 जनवरी,-06 फरवरी, 2012	भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह में भाग लेना	
116	पाकिस्तान	पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का 6 सदस्यीय बाद्य यंत्र (बांसुरी) समूह	26-30 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
117.	मॉरीशस	सुरी लहरी कोलाचेला का 6 सदस्यीय कर्णाटिक गायन समूह	30 जनवरी- 10 फरवरी, 2012	कवाडी महोत्सव में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
118.	मॉरीशस	कारी वासिफ रजा नूरी नातख्वा को एक यात्रा अनुदान	3-15 फरवरी, 2012	ईद मिलाद उल नबी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेना	
119.	जापान	सुश्री सुभ्रा भारद्वाज के नेतृत्व में 25 सदस्यीय बालीवुड नृत्य समूह	4-9 फरवरी, 2012	भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापनाा के 60 साल पूरा होने के साल पूरा होने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
120.-121.	पाकिस्तान	(i) श्री परमजीत सिंह नरूला (मिक्की नरूला) के नेतृत्व में 24 सदस्यीय बालीवुड समूह ''कार्मिक कनेक्शन'' (ii) सुश्री कुमुदनी लखिया के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह ''कदंब''	12-14 फरवरी, 2012	फिक्की द्वार आयोजित लाहौर में इण्डिया शो के दौरान आई.सी.आर. ने इन दोनों की प्रतिभागिता को प्रायोजित किया	
122.	मॉरीशस दक्षिण अफ्रीका	उमराव सलोदिया का 8 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन समूह	12-27 फरवरी, 2012	महाशिवरात्रि महोत्सव में भाग लेना	
123.	थाईलैंड	सुश्री प्रीती के नेतृत्व में पंजाबी अकादमी का 14 सदस्यीय भांगड़ा एवं गिद्धा समूह	15-27 फरवरी, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
124.	आस्ट्रेलिया	श्री बंधु प्रसाद के नेतृत्व में अभिनय रंगमंच अनुरोध केन्द्र को 9 यात्रा अनुदान	19-27 फरवरी, 2012	हेनरिक इब्सन के ''लेडी फ्राम दि सी'' के मलयालम अनुकूल ''सागरकन्याका'' नाटक प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
125.	यू.एस.ए	श्री ए. लक्ष्मण स्वामी (भरतनाट्यम) को 5 यात्रा अनुदान	23 फरवरी - 31 मार्च, 2012	[illegible]तिलट के निमंत्र कंसर्ट ट्र	
126.	अर्जेंटीना	डॉ. मुस्ताफा रजा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय विचित्र वीणा समूह	25 फरवरी - 5 मार्च, 2012	सांस्कृतिक	
127.	मेक्सिको	सुश्री राजकी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोकनृत्य समूह	27 फरवरी, - 3 मार्च, 2012	इण्डिया ट्रेड शो में भाग	
128.	नेपाल	सुश्री प्रतीक्षा शर्मा के नेतृत्व में दो सदस्यीय लाइट क्लासिकल ग्रुप	1-5 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
129.	सेशल्स	सुश्री चंपा सपेरा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक कला समूह	1-5 मार्च, 2012	सेशल्स कार्निवल में भाग लेना	
130.	थाईलैंड	सुश्री रंजना गौहर के नेतृत्व में 9 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	04-07 मार्च, 2012	"चित्रांगदा" नाटक प्रस्तुत करना	
131.	इंडोनेशिया	सुश्री वासवती मिश्रा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	04-08 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
132.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री स्वाति सिन्हा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सूफी कत्थक नृत्य समूह	06-12 मार्च, 2012	"सेलेबरेशन ऑफ लाइफ डिलाइट्स" फेस्टिबल में भाग लेना	

1	2	3	4	5	6
133.	आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड	पंडित शिव कुमार शर्मा (संतूर वादक) को चार यात्रा अनुदान	07-23 मार्च, 2012	''स्प्रिट ऑफ इण्डिया कंसर्ट'' में भाग लेना	
134.	यूगांडा	श्री हयात मोहम्मद के नेतृत्व में 14 सदस्यीय राजस्थानी समूह	8-12 मार्च, 2012	होली के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
135.	यू.के.	सुश्री शिवानी वजीर पसरीचा एवं दो सहयोगियों के लिए तीन यात्रा अनुदान	09-11 मार्च, 2012	साउथ बैंक सेंटर में ''वुमन ऑफ दि वर्ल्ड'' फेस्टिवल में कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
136.	श्रीलंका	डॉ. कुमुद दीवान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय लाइट क्लासिकल ग्रुप	13-20 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
137.	इंडोनेशिया	सुश्री मालविका सैरुकई के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	17-22 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
138.	न्यूजीलैंड	पंडित देबू चौधरी को एक यात्रा अनुदान	22-24 मार्च, 2912	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
139.	इंडोनेशिया	सुश्री मनीषा गुलयानी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय (फ्यूजन कत्थक एवं राजस्थानी लोक कला) समूह	28 मार्च-2 अप्रैल, 2012	बाली स्प्रिट फेस्टिवल में भाग लेना	
140	यू.एस.ए. इटली	गुंडेचा बंधुओं (भक्ति संगीत) को पांच यात्रा अनुदान	28 मार्च- 6 मई, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

विवरण–II

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र से प्रायोजित समूहों की सूची

क्र. सं.	देश जिनका दौरा किया गया	समूह का नाम	तारीख	दौरा का उद्देश्य	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	दक्षिण कोरिया चीन	नागालैंड से उत्तर पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र ''शिलांग चैम्बर'' से 12 सदस्यीय गायन समूह	25 जून,–7 जुलाई, 2009	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	इस समूह को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया में प्रयोजित किया गया। परिषद ने चीन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए इस समूह को प्रायोजित किया
2.	आस्ट्रेलिया	10 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह ''जागोई मारूप'', मणिपुर	9–19 अक्टूबर, 2009	दिवाली समारोह में भाग लेना	
3.	कम्बोडिया	श्री सोमेश्वर तरन, असम के नेतृत्व में अइमोनी गोगोई बिहू दल का 10 सदस्यीय बिहू नृत्य समूह	10–13 नवम्बर, 2009	भारत–कंबोडिया व्यापार एवं निवेश व्यवसाय मंच में भाग लेना	
4.	भूटान भून्टशिलिंग	सुश्री भानू डेका, असम के नेतृत्व में 14 सदस्यीय बिहू नृत्य समूह	23–29 जनवरी, 2010	भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
5.	रियूनियन द्वीपसमूह	सुश्री इंदिरा देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह ''मेइतेई परंपरागत नृत्य''	4-19 अप्रैल, 2010	रियूनियन द्वीपसमूह में तमिल नव वर्ष समारोह में भाग लेना	
6.	कम्बोडिया	सुश्री रीना देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	24 अप्रैल,-1 मई, 2010	सि.एम. रीप, कंबोडिया में ''ट्रायल ऑफ सिवलाइजेशन'' के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
7.	म्यांमार	श्री मोसुबोंग, नागालैंड के नेतृत्व में 5 सदस्यीय म्यूजिक बैंड ग्रुप ''एबियोनेसिस म्युजिक बैंड''	27-31 मई, 2010	राष्ट्रीय रंग मंच, रंगून में तथा राष्ट्रीय रंगमंच मण्डाले में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
8.	मिस्र	श्री अमरजीत सिंह, मणिपुर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह ''रंग निकेतन''	26 सितम्बर - 4 अक्टूबर, 2010	मिस्र में भारत सप्ताह में भाग लेना	
9.	केन्या दक्षिण अफ्रीका	श्री उमाकांत सिंह नमीराकपम मणिपुर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय मणिुरी नृत्य समूह	13 अक्टूबर - 1 नवम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
10.	किरगिस्तान रूस	सुश्री अनीता शर्मा, असम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सत्रिया समूह	9-21 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
11.	स्विटजरलैंड	सुश्री लायसराम बीना देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	22-27 मार्च, 2011	बासेल, स्विटजरलैंड में हीरे एवं जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

1	2	3	4	5	6
12.	सूरीनाम बार्बाडोस	श्री शिव प्रसाद दास, असम के नेतृत्व में 14 सदस्यीय बिहू समूह ''असम ज्योति सांस्कृतिक गोष्ठी''	28मई-18 जून, 2011	''दि इण्डियन अराइवल डे'' समारोह में भाग लेना	
13.	फिनलैंड इस्टोनिया	सुश्री मोनीमाला बोराह, असम के नेतृत्व में 14 सदस्यीय बिहू समूह ''असम ज्योति सांस्कृतिक गोष्ठी''	20-30 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	
14.	भूटान	श्री मोयनुंगसैंग सुबोंग, नागालैंड के नेतृत्व में 14 सदस्यीय बैंड ग्रुप ''एबियोजेनेसिस''	12-20 अगस्त, 2011	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुत करना	
15.	कनाडा	श्री इके सिन्हा, नागालैंड के शिलांग चैम्बर गायन समूह को 19 यात्रा अनुदान	18-22 अगस्त, 2011	टोरंटो महोत्सव में भाग लेना	
16.	न्यूजीलैंड	सुश्री अमोसना देवी नोंगथोम्बन, मणिपुर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	6-17 अक्टूबर, 2011	दिवाली समारोह में भाग लेना	
17.	नेपाल	श्री तसेरिंग दार्जी मेग्जी, अरुणाचल प्रदेश के नेतृत्व में 10 सदस्यीय आजी ल्हासा मास्क नृत्य समूह	2-5 दिसम्बर, 2011	हिमालयन ओडिसी कार्यक्रम प्रस्तुत करना	

दूरसंचार उपकरण का आयात

2069. **श्री पी. कुमार :**
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आयातित और विपणित मोबाइल फोनों सहित विभिन्न दूरसंचार उपकरणों के लिए कोई गुणवत्ता मानक की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे गुणवत्ता मानक का अनुपालन और परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चीन सहित विदेशी विक्रेताओं के लिए कतिपय दूरसंचार उपकरणों के आयात हेतु प्रतिबंध लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जेड.टी.ई. सहित कुछ विदेशी कंपनियों को भारत में वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपकरण का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तकनीकी हस्तांतरण के लिए पूर्व-शर्तें क्या रखी गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) दूरसंचार विभाग के तहत दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र (टी.ई.सी.) मोबाइल फोनों सहित दूरसंचार उत्पादों के लिए विनिर्देशन/मानक बनाता है।

मोबाइल हैंडसेटों के संबंध में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित संशोधित विशिष्ट अवशोषण दर (एस.ए.आर.) सीमा के अनुपालनार्थ निर्देश जारी किए हैं:

(i) मोबाइल हैंडसेटों के लिए एस.ए.आर. स्तर को मानव ऊतक की 1 ग्राम मात्रा पर औसतन 1.6वाट/किलोग्राम तक सीमित किया जाएगा।

(ii) मोबाइल हैंडसेटों के सभी नए डिजाइन 1 सितंबर, 2012 से मानव ऊतक की 1 ग्राम मात्रा पर औसतन 1.6 वाट/किलोग्राम के एस.ए.आर. मान का अनुपालन करेंगे। तथापि, मौजूदा डिजाइनों वाले मोबाइल हैंडसेट जो मानव ऊतक की 10 ग्राम मात्रा पर औसतन 2.0 वाट/किलोग्राम के अनुपालन में हैं, वे 31 अगस्त, 2013 तक बने रह सकते हैं।

(iii) 1 सितम्बर, 2013 से, घरेलू बाजार के लिए केवल 1.6 वाट/किलोग्राम के संशोधित एस.ए.आर. मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के ही भारत में विनिर्माण या आयात की अनुमति होगी।

तथापि, वर्तमान में दूरसंचार विभाग के पास देशीय एवं आयातित मोबाइल फोनों के नियमन के लिए कोई विनियम/मानक नही है। देश में आयातित एवं विपणित मोबाइल फोनों सहित दूरसंचार उत्पादों के लिए टी.ई.सी. के विनिर्देशन/मानक अनिवार्य नहीं है।

(घ) और (ङ) चीन सहित देशी और आयातित दूरसंचार उपस्करों से दूरसंचार एवं दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा शंकाओं का समाधान करने के लिए दूरसंचार विभाग ने अभिगम सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस संशोधन दिनांक 31.05.2011 एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिनांक 3.6.2011 के द्वारा व्यापक सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभिन्न दूरसंचार सेवा लाइसेंस करार से संबंधित उक्त संशोधनों के प्रमुख बिन्दु संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(च) और (छ) वर्तमान नीति के अनुसार, भारत में बेतार ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपस्कर सहित दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और केवल औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.) में औद्योगिक उद्यमकर्ता का ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करना पड़ता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए किसी तकनीकी की जानकारी का शुल्क एवं रॉयल्टी का भुगतान ऑटोमैटिक रूट के तहत किया जाता है।

विवरण

विभिन्न दूरसंचार सेवा लाइसेंस करार में किए गए संशोधनों के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(i) लाइसेंस धारक अपने नेटवर्कों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह और अंतिम रूप से जिम्मेदार होगा। उनके पास अपने नेटवर्कों की सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रबंधन संबंधी संघठनात्मक नीति होगी।

(ii) लाइसेंसधारक नेटवर्क जांच व प्रमाणन अभिकरण से वर्ष में एक बार सुरक्षा के दृष्टिकोण नेटवर्क की जांच करवाने के लिए अपने नेटवर्क की जांच करेंगे।

(iii) लाइसेंसधारक केवल उन नेटवर्क घटकों को अपने दूरसंचार नेटवर्क में लगाएंगे जिनकी संबंधित समसामयिक भारतीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार जांच कर ली गई है। प्रमाणन 1 अप्रैल, 2013 से केवल भारत की प्राधिकृत एवं प्रामणित एजेंसियों/प्रयोगशालाओं से किया जाएगा।

(iv) लाइसेंसधारक खास पदों पर केवल निवासी, प्रशिक्षित भारतीय नागरिकों को नियोजित करेंगे।

(v) लाइसेंसधारक

1. मैनुअल रूप से प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखेंगे।

2. सभी सॉफ्टवेयर की अद्यतन स्थितियों एवं परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखेंगे।

3. उत्पाद (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) की आपूर्ति श्रृखला का रिकॉर्ड रखेंगे।

4. दूरस्थ अभिगम (आर.ए.) की शर्तों का अनुपालन करेंगे।

(vi) लाइसेंसधारक वेंडर के साथ उपयुक्त करार करके यह सुनिश्चित करेंगे कि वेंडर/आपूर्तिकर्त्ता दूरसंचार सेवा प्रदाता, लाइसेंस प्रदाता/दूरसंचार विभाग अथवा इसकी नामित एजेंसी को हार्डवेयर, सॉफवेयर, डिजाइन, विकास, विनिर्माण सुविधा एवं आपूर्ति श्रृंखला की जांच करने एवं उपस्कर की आपूर्ति के दौरान किसी भी समय सभी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा/जोखिम जांच की अनुमति प्रदान करेंगे। इस प्रकार के दौरे एक क्रय आदेश में दो तक समिति होंगे। 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आर्डर के लिए इस प्रकार के दौरो पर 40 मानव दिवस प्रति दौरे तक का व्यय लाइसेंसधारक द्वारा सीधे अथवा वेंडर के माध्यम से वहन किया जाएगा।

(vii) सुरक्षा में किसी भी कमी के लिए 50 करोड़ रु. तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

पूर्ववर्ती वी.एस.एन.एल. के भूमि का मूल्य

2070. श्री पी. विश्वनाथन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा कम्यूनिकेशन (पूर्ववर्ती वी.एस.एन.एल.) का प्रमुख शहरों में भूमि का अनुमानित मूल्य और भूमि के क्षेत्र का स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई स्पेशल परपस व्हिकल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो कंपनी का नाम तथा उनके शेयर की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) पूर्व में वी.एस.एन.एल. के पास अतिरिक्त भूमि के बिक्री से कुल कितना विनिवेश राशि प्राप्त होने का अनुमान है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार भूमि दरों के आधार पर मै. टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (तत्कालीन वी.एस.एन.एल.) की भूमि के मूल्य का आकलन 10.08.2011 को किया गया था। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने तत्कालीन वी.एस.एन.एल. (अब मै. टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड) द्वारा धारित अधिशेष भूमि के हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच.पी.आई.एल.) नामक परिणामी कंपनी के रूप में पृथक्करण/अविलयन को अनुमोदित कर दिया है जिसमें सरकार 2,55,600/- (दो लाख पचपन हजार छः सौ रू. केवल) के व्यय का वहन करते हुए 51.12% अर्थात 5 लाख रू. की प्रदत्त पूंजी का 51.12% भाग अधिग्रहित करेगी।

(घ) अधिशेष भूमि का बिक्री मूल्य बिक्री के समय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

विवरण

तत्कालीन वी.एस.एन.एल. की अधिशेष भूमि और इसके मूल्यांकन का ब्यौरा

क्र.सं.	अवस्थिति	राज्य	घोषित अधिशेष भूमि (एकड़ में)	राज्य सरकार की अधिसूचनाओं अनुसार भूमि-मूल्य (10.08.2011 की स्थिति के अनुसार) (करोड़ रू. में)
1.	दिघी-पूणे	महाराष्ट्र	524.00	512.13
2.	हाली शहर-कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	35.19	82.71
3.	छत्तरपुर-नई दिल्ली	दिल्ली	58.00	1511.58
4.	ग्रेटर कैलाश-नई दिल्ली	दिल्ली	70.00	3863.94
5.	पडियानल्लुर-चेन्नै	तमिलनाडु	53.44	186.22
	कुल		740.63	6156.58

अपराह्न 12.03

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लिया जायेगा।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : श्री अजित सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2010-11 के वार्षक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7631/15/12]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के

वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7632/15/12]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2012, जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2012, जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7633/15/12]

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 जो 29 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 655(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी, 7634/15/12]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 12)- एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिचालनात्मक निष्पादन के बारे में निष्पादन लेखा-परीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी, 7635/15/12]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के दो वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी, 7636/15/12]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी, 7637/15/12]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2011-2012 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी, 7638/15/12]

(5) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ कलासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7639/15/12]

(7) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7640/15/12]

(9) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), दादरा एण्ड नागर हवेली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), दादरा एण्ड नागर हवेली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी, 7641/15/12]

(11) बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) क.आ. 2165(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।

(दो) का.आ. 2389(अ) जो 8 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड राज्य में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।

(तीन) का.आ. 2512(अ) जो 17 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके

द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।

(चार) का.आ. 2513(अ) जो 17 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7642/15/12]

(12) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडीशा, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7643/15/12]

(13) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7644/15/12]

(14) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7645/15/12]

(15) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी, 7646/15/12]

(17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7647/15/12]

(19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7648/15/12]

(21) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7649/15/12]

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7650/15/12]

(25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7651/15/12]

(27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7652/15/12]

(29) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7653/15/12]

(31) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7654/15/12]

(33) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7655/15/12]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत 433 से 434 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति सीमा में इंडोर अनुप्रयोग हेतु न्यून विद्युत युक्ति अथवा उपकरण का प्रयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2012 जो 12 सितम्बर, 2012 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7656/15/12]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केबल लैंडिंग स्टेशनों में आवश्यक सुविधाओं की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार पहुंच (संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 416-3/2010-आई एण्ड एफ.एन. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार अंतरसम्पर्क (पत्तन प्रभार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 409-3/2011-आई एण्ड एफ.एन. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 116-15/2012-एम.एन. में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लेखा पृथक्करण संबंधी रिपोर्टिंग सिस्टम (संशोधन) विनियम, 2012 जो 15 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 14-07/2012-एफ एण्ड ईए में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दूरसंचार उपभोगक्ता संरक्षण (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 22 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 308-05/2011-क्यूओएम में प्रकाशित हुए थे।

(छह) दि इंटेलीजेंट नेटवर्क सर्विसेज इन मल्टी ऑपरेटर एंड मल्टी नेटवर्क सिनेरियो (संशोधन) विनियम, 2012 जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 416/1/2010-आई एण्ड एफ.एन. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी, 7657/15/12]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7658/15/12]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंगतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7659/15/12]

(ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी, 7660/15/12]

अपराह्न 12.05 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री राव इंद्रजीत सिंह (गुड़गांव) : महोदया मैं, सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

संचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'बैंककारी और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों का प्रबंध' विषय पर समिति के 62वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 13वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 19वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्यक्ष-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 20वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवदेन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाकघरों का आधुनिकीकरण' विषय पर समिति के 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 26वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवदेन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 27वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वी लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 28वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वी लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.05½

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें और 22वें प्रतिवेदन की निम्नलिखित प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शहरी विकास मंत्रालय की "अनुदान की मांगों (2012-13)" के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति का 21वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2012-13)" के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति का 22वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.06

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(एक) मुम्बई में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में एक भव्य स्मारक का निर्माण*

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा): महोदया, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं:

इस गरिमामय सदन की माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि 6 दिसंबर 2012 को भारत के महानतम नेताओं में से एक भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्य तिथि है। राष्ट्र हमारे संविधान के निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है, जिसने भारतीय लोकतंत्र के निर्माण की आधारशिला रखी थी।

बाबा साहेब अम्बेडकर की अस्थियां मुंबई स्थित नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की इन्दु मिल की भूमि के नजदीक चैत्य भूमि में रखी गई हैं। उनके लाखों अनुयायियों के लिए यह एक तीर्थस्थल है। जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए और महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध के प्रत्युत्तर में एवं महाराष्ट्र की विधायिका सभा के दोनों सदनों द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्मारक के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराने का विचार किया है।

सरकार ने इस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मैं शीघ्र ही आवश्यक विधायी प्रस्ताव संसद के अनुमोदनार्थ पेश करूंगा। मैं आपकी सहायता तथा सदन के समर्थन का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (धोसी) : मंत्री जी, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मंत्री जी, हम इसका समर्थन करते हैं।

*सभा पटल पर रखा गया ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7661/15/12

अपराह्न 12.06½

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : आपकी अनुमति से, मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7662/15/12

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोग सभा बुलेटिन, भाग-II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73ए के अनुसरण में दे रहा हूं ताकि वर्ष 2012-13 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) की अनुदान मांगों पर 227वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति से माननीय सदन को अवगत करा सकूं। इस समिति ने डी.एस.आई.आर. की कार्यप्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी 227वां प्रतिवेदन दिनांक 18 मई, 2012 को दोनों सदनें में प्रस्तुत किया। इस समिति के 227वें प्रतिवेदन में 26 सिफारिशें सम्मिलित थीं। इनमें से अधिकतर का स्वरूप परामर्शी एवं सराहनात्मक था। इस विभाग ने इन सम्मलित थीं। इनमें अधिकतर का स्वरूप नोट 29.08.2012 को समिति को भिजवाया है।

कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का यहां पुन: उल्लेख किया जा रहा है:-

- समिति इस बात से प्रसन्न है कि विभाग ने एक निगरानी तंत्र बनाया है जिससे इसे आवंटित निधियों का पूरा उपयोग करने में सहायता मिली है। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि विभाग ने लगातार दो वर्षों में 95.84% और 95.97% प्रतिशत का उच्च मिश्रित मूल्य स्कोर (हाई कम्पोजिट वैल्यू स्कोर) प्राप्त किया है जो उस उत्कृष्टता ग्रेड को दर्शाता है जिस स्तर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग अपने कार्यक्रमों और स्कीमों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सफल रहा है। तथापि, समिति आशा करती है कि विभाग भविष्य में इस निष्पादन को जारी और बनाए रखेगा;

- जबकि समिति इस बात की सराहना करती है, कि सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने में सफल रहा है, समिति चाहती है कि सी.एस.आई.आर. के वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अथक प्रयास करें। समिति यह भी चाहती है कि पेटेंट की खासी संख्या के साथ सी.एस.आई.आर. को भारतीय उद्योग को और भी विश्व स्तर पर प्रतियोगिता योग्य उत्पादों को विकसित करने में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि इसी से सी.एस.आई.आर. के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पेटेंटों की उपयोगिता सिद्ध होगी;

- तथापि, यह समिति महसूस करती है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विभागों के लिए योजनागत निधियों का उच्चतर आबंटन अत्यावश्यक है। अत: यह समिति वैज्ञानिक संगठनों के लिए निधियों की उच्चतर समग्र उपलब्धता (योजना के प्रतिशत हिस्से के रूप में) की सिफारिश करती है;

- समिति यह महसूस करती है कि बजटीय बाध्यताओं के मद्देनजर विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह इन योजनाओं के वित्तपोषण हेतु नये तरीके खोजे। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल, उपयुक्त प्रयोक्ता शुल्क को लगाया जाना, अन्य लाभार्थियों से वित्तपोषण, इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषित पेटेंटों के वाणिज्यिक दोहन से प्राप्त लाभों की हिस्सेदारी आदि कुछ ऐसे ज्ञात तरीके हैं जिनसे योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निधियां जुटायी जा सकती हैं;

- समिति ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकियों और सस्ती स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों में सी.एस.आई.आर. द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की सराहना करती है। तथापि, समिति महसूस करती है कि यदि देश को प्रौद्योगिकी संचालित आर्थिक सुपरपावर के रूप में उभरना है तो इसके लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। अत: समिति चाहती है कि विभाग को बारहवीं योजना के दौरान अपने प्रयासों को और तेज करके प्रेरित करना चाहिए ताकि भारत सच्चे प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष संचालित समाज के रूप में उभर सके।

227वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई विषयक नोट राज्यसभा सचिवालय को 29.08.2012 को अग्रेषित कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदया, मैं यह विवरण माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73ए, जो निम्नलिखित अनुसार है, के अनुसरण में प्रस्तुत कर रही हूँ:-

"संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में विभाग से संबंधित लोक सभा की स्थायी समिति की रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में छह माह के एक बार सदन में विवरण प्रस्तुत करेंगे"

2. मैं सदन के माननीय सदस्यों के जानकारी के लिए यह सूचित करना चाहूंगी कि 15वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की 18वां प्रतिवेदन लोक सभा में 25 अप्रैल, 2012 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रतिवेदन में 11 सिफारिशें निहित हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के आगे दर्शाई गई है। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई नोट शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को पहले ही भेज दिया गया था।

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि जहां कहीं आवश्यक होगा, आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

इस विवरण का अनुलग्नक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7663/15/12

अपराह्न 12.07½ बजे

(चार) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डाक विभाग, से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को डाकघरों द्वारा पारिश्रमिक का संवितरण' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : महोदया, मैं सभा का मूल्यवान समय लिए बिना सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के क्रियान्वयन के संबंध में विवरण के डाक विभाग से संबंधित विलंब विवरण के साथ सभा पटल पर रखती हूं।

प्रतिवेदन को अद्यतन नहीं किया जा सका और निर्धारित अवधि में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसका खेद है। मुख्यत: समिति के समक्ष अद्यतन इनपुट के साथ कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण यह विलंब हुआ। इसलिए प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिश पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के सभी संबंधित डिवीजनों से डाटा को अद्यतन करने में समय लगा।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि एफ.डी.आई. पर चर्चा तत्काल प्रारंभ की जाए ताकि मंत्री जी अपराह्न चार बजे उत्तर दे सके और उसके पश्चात प्रस्ताव लाने वाले प्रतिउत्तर दे सकते हैं।

अपराह्न 12.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामलें सभा पटल पर रखे जाएंगे। आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो, वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7662/15/12

**सभा पटल पर रखे माने जाए।

पटल पर पर्ची रख दें। केवल वहीं मामले सभापटल पर रखे जायेंगे। जिनके पर्ची निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रख दी गई। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) वर्तमान सप्ताह में दो दिन उज्जैन-भोपाल-कानपुर होकर चलने वाली इंदौर-पटना एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 19313/19314) को सप्ताह के अन्य पांच दिन बारास्ता उज्जैन-भोपाल-झांसी-खजुराहो-महोबा-चित्रकूट-मानिकपुर चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इंदौर-पटना एक्सप्रेस वर्तमान में सप्ताह में दो दिन ही चलती है, इस ट्रेन में हमेशा 300-400 की वेटिंग रहती है। वर्तमान में इंदौर-पटना रूट वाया उज्जैन, भोपाल, कानपुर होकर जाती है। इस ट्रेन को पांच दिन और बढ़ाया जाए तथा इसका रूट वाया उज्जैन, भोपाल, झांसी, खजुराहो, महोबा, चित्रकूट, मानिकपुर का रूट तैयार किया जाए। इससे चार धार्मिक एवं दो ऐतिहासिक स्थल एवं दो पर्यटन स्थल, देवास-इंदौर-उज्जैन सीधे मिल जाएंगे, जबकि खजुराहो को दिल्ली, मुंबई जैसी सभी महानगरों से जोड़ दिया गया है। इंदौर एक व्यापारिक स्थल है, इस प्रकार इंदौर और भोपाल जैसे महानगर भी खजुराहो से सीधे जुड़ जाएंगे। अत: दो दिन इंदौर-पटना वाया उज्जैन, भोपाल, कानपुर होकर चलती है, वैसे ही चलाई जाए परंतु पांच दिन वाया उज्जैन, भोपाल, झांसी, महोबा, खजुराहो, चित्रकूट, मानिकपुर होते हुए चलाई जाए। वैसे भी देवास जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक जिला है और पांच तहसीलों के लिए केवल एक ही रेलवे स्टेशन देवास ही है, अत: मालवा क्षेत्र हृदय देवास को ध्यान में रखते हुए इंदौर-पटना को पांच दिन अतिरिक्त चलाए जाने बाबत् उचित कार्यवाही करें। उक्त गाड़ी पांच दिन अतिरिक्त रूट से संचालित की जाती है तो उसके संचालन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उक्त रूट पर कोई इतना ट्रैफिक नहीं रहता है जिसकी वजह से टाईमिंग में किसी प्रकार की कोई परेशानी आए।

(दो) राजस्थान में बाघ अभयारण्यों को बेहतर बनाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : राजस्थान में कई अभ्यारण्य स्थल हैं और बाघ रिजर्व के सृजन के लिए दर्राह, जवाहर सागर और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इन अभ्यारण्य स्थलों को पर्यटन स्थल का रूप दिया जाए तो सरकार को एक अच्छी आमदनी हो सकती है। पर्यटकों को काफी संख्या में आकर्षित किया जा सकता है। बाघ संरक्षण हेतु बाघ रिजर्वों का मूल्यांकन करके तथा निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करके भारत की इस दुर्लभ वन्य प्रजाति को बचाया जा सकता है। अफ्रीकी देशों में अपने जंगल संबंधित पर्यटकों से काफी राजस्व प्राप्त हो रहा है। हमें भी ऐसे प्रयास करने चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के दर्राह, जवाहर सागर और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य को नए बाघ संरक्षण हेतु बाघ रिजर्वों का मूल्यांकन करके तथा निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करके भारत के अभ्यारण्य स्थलों को विश्व अभ्यारण्य स्थलों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाए। रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य को केला देवी जी, बयाना, जिला भरतपुर तक सीमाकंन किया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत महाराजगंज रेल लाईन के ऊपर आनंद नगर-घुघली बाईपास को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) : चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे अंतर्गत आनंदनगर-घुघली बरास्ता महाराजगंज रेल परियोजना अपडेट होकर 6.97 प्रतिशत प्रतिफल सर्वेक्षण रिपोर्ट को योजना आयोग ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते समय प्रदेश सरकार से मुफ्त भूमि एवं निर्माण व्यय का 50 प्रतिशत वहन करने की शर्त रखी।

योजना आयोग ने नई रेल लाईन निर्माण हेतु यह नीति इसी वर्ष से प्रारंभ की है। देश के पिछड़े राज्यों द्वारा निर्माण व्यय का 50 प्रतिशत वहन करना एवं मुफ्त भूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

ज्ञातव्य रहे कि स्वतंत्रता के पश्चात् देश में लगभग 10 हजार किलोमीटर के रेल लाईन निर्माण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में नाममात्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 किलोमीटर रेल लाईन का ही निर्माण हुआ है और नई नीति इसे आगे भी उपेक्षित रखेगी।

सरकार का यह दायित्व है कि पड़ोसी राष्ट्रीय नेपाल में बढ़ रहे चीन के प्रभाव के चलते नेपाल से सटे जनपद मुख्यालयों को राष्ट्रीय हित की सामरिक महत्ता की दृष्टि से उन्हें रेल से जोड़ने में प्राथमिकता बरते।

रेल संघीय विषय है परंतु नई नीति कालांतर में राज्यों को अपनी रेल चलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा।

अत: मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश एवं विशेषकर पूर्वी उत्तर की रेल लाईन निर्माण में अब तक हुई उपेक्षा को दूर करने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आनंदनगर-घुघली बरास्ता महाराजगंज रेल लाईन हेतु प्रदेश सरकार से व्यय एवं मुफ्त भूमि की शर्त को समाप्त कर तत्काल रेलवे बोर्ड निधि आवंटित कर कार्य शुरू करवाए।

(चार) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बालू के अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : मेरे संसदीय क्षेत्र में जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में तहसील तुलसीपुर एवं बलरामपुर में हो रहे बालू मोरंग के अवैध खनन में जनजीवन, सड़क एवं महत्वपूर्ण पुलों, वन्य जीवों तथा संरक्षित वन क्षेत्र को क्षति पहुंचाया जाने के संबंध में।

जनपद बलरापुर में खैरहनिया/धोबनिया/जगथरा एवं नैकिनिया में आवंटित रकबों से सैकड़ों एकड़ से अधिक अवैध खनन की अनदेखी ही नहीं की जा रही है, बल्कि यह भी संज्ञान में आया है कि उन पर अवैध खनन को लेकर लगाए गए अर्थदंड को भी अवैध तरीके से माफ कर दिया गया अथवा जुर्माना नहीं वसूला गया जिससे अवैध खनन को बढ़ावा ही नहीं बल्कि शासन एवं प्रशासन का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा असुरिक्षत हो रही है बल्कि करोड़ों की लागत से बनाए गए सड़क पुल/रेलवे पुल, विद्यालय एवं वन क्षेत्र शिवालिक से निकलने वाले नालों एवं राप्ती नदी द्वारा बरसात में हो रहे कटाव से निष्प्रयोज्य व बर्बाद हो रहे हैं, जोकि पिछड़े हुए जनपद की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वन के कटाव के साथ ही साथ वन्य जीवों एवं पर्यटन स्थलों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

गत बरसात में सात गांवों का वन कटाव के कारण अस्तित्व समाप्त हो गया, वहीं खरगौर पुल/कोड़री पुल एवं चौधरीडीह-तुलसीपुर मार्ग ललिया-कौव्वापुर मार्ग अपना अस्तित्व खो चुका है। पर्यावरण एवं जंगल पर भारी खतरा है। वहीं नक्सल गतिविधियां भी जन्म लेती जा रही हैं। दो दशक पूर्व बोल्डरों की खदान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी।

अत: मेरा अनुरोध है कि क्षेत्र में मोरंग के खनन से हो रहे नुकसान को देखते हुए अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना राजस्व की भांति वसूला जाए एवं सभी पट्टों को निरस्त किया जाए।

(पांच) उत्तराखंड के रामनगर, में गन्ना किसानों को निजी चीनी मिलों द्वारा भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : मैं इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के गन्ना किसानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तराई का यह क्षेत्र प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का गन्ना काशीपुर की चीनी मिल में पिराई के लिए जाता था। काशीपुर की यह मिल निजी स्वामित्व की है। इस मिल को रामनगर क्षेत्र के गन्ना किसानों का लगभग 25 करोड़ रुपये का भुगतान करना है जिसमें 2007-08 का ही 5 करोड़ रुपया है। मिल मालिकों ने इस वर्ष मिल को चलाने से मना कर दिया है जिससे वहां के किसानों के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पिछला बकाया नहीं मिला, ऊपर से इस वर्ष मिल के न चलने से किसानों की स्थिति काफी कष्टकारी हो गई है। हालात यह है कि खेत में अभी तक गन्ने नहीं कटे हैं जिससे दूसरी फसल की बुआई नहीं हो पा रही है। सरकारी मिलों ने तो अपने बकाये का भुगतान किसानों को कर दिया है, परंतु निजी मिल वालों ने गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया है।

केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को निर्देशित करें कि वह रामनगर क्षेत्र के गन्ना किसानों का भुगतान निजी मिल से शीघ्र करवाएं तथा उनके गन्ने की पिराई के लिए अन्य मिल की शीघ्र व्यवस्था करे।

(छह) दिल्ली की सभी मलिन/अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने और दिनांक 24.03.2008 को भारत सरकार की राजपत्र की अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : राजधानी दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों से लोग अपनी आजीविका हेतु आते हैं और यहीं पर बस भी जाते हैं। इसलिए दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2008 में नियम 3.3 के खंड "ग" जिसमें यह प्रावधान किया गया है

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

कि अनधिकृत कॉलोनियां/बस्तियां जिनमें नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि को 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तथापि उपर्युक्त कॉलोनियों में 31.3.2002 के बाद और नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि तक बने प्लॉटों को कॉलोनी की नियमन की पात्रता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखकर की जाएगी, उचित नहीं है।

यह विदित ही है कि 24 मार्च, 2008 का उपरोक्त राजपत्र काफी पुराना हो चुका है और सरकार ने इसमें जो आधार तिथि 31.3.2002 निर्धारित की है, उस तिथि से लेकर आज तक काफी संख्या में नई बस्तियां बस चुकी हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या में गरीब लोग रह रहे हैं। इन बस्तियों को उजाड़ने से इनमें रहने वाले नागरिक, जो आजीविका हेतु इन बस्तियों में बसे हुए हैं, बेघर हो जाएंगे और भूखे मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए, यह जनहित में आवश्यक है कि वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर राजधानी दिल्ली की सभी अवैध बस्तियों को नियमित किया जाना चाहिए।

अत: ऐसी स्थिति में मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर राजधानी दिल्ली की ऐसी सभी बस्तियों, जिनमें भले ही कुछेक मकान बने हुए हैं, उनको किसी भी सूरत में ध्वस्त न किया जाए और अनधिकृत कॉलोनियों की नियमन पात्रता निर्धारित किए जाने की संबंधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24 मार्च, 2008 के नियम 3.3 के खंड "ग" में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन करते हुए राजधानी दिल्ली की वर्ष 2012 तक बनी सभी अनधिकृत कॉलोनियों को बिना कोई विकास शुल्क लिए अविलम्ब नियमित किया जाए।

(सात) गरीब लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में पाइप द्वारा जलापूर्ति के कवरेज में विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती मौसम नूर (मालदा उत्तर) : अनेक राज्यों में भूजल में आर्सेनिक तथा फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत स्तर से अधिक पाई गई है। मैं पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी जो कि सबसे अधिक प्राभावित राज्यों में से एक है, जैसा क किए गए अनेक अध्ययनों तथा कुछ विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए अध्ययनों ने इंगित गया है कि ग्रामीण लोगों के लिए, पेयजल का मुख्य स्रोत भूजल है जिसे वे निबी घरेलू ट्यूब वैल से निकालते हैं तथा यह भूजल दूषित होता है। यद्यपि वर्ष 2011 के अंत तक "भारत निर्माण" कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से प्रभावित सभी गांवों में आर्सेनिक मुक्त पेयजल की आपूर्ति के लिए कदम उठाए गए है, लेकिन फिर भी कैंसर तथा अन्य हानिकारक रोगों से पीड़ित गरीब लोगों के लिए परिणाम अभी भी निराशाजनक हैं। लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर सहित पश्चिम बंगाल के ग्रामीण जिलों में पाइप लाइन जल की स्थिति निराशाजनक है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि गरीबों को स्वच्छ पेयजल तथा पाइपलाइन जल आपूर्ति के क्षेत्र के विस्तार के लिए नई पहलें की जानी चाहिए।

(आठ) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मकरोनिया-बहेरिया खण्ड पर रेल समपार संख्या 30 पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): सागर संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 पर वाहनों के आवागमन में लगातार वृद्धि हो रही है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर, कानपुर सहित फोरलाइन कोरीडोर और बुंदेलखंड के पांचों जिलों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 के मकरोनिया-बहेरिया खंड के बीच इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के अनेक प्राइवेट संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र सिद्गुवां, मकरोनिया रेलवे स्टेशन, निजी अस्पताल इत्यादि होने से उक्त सड़क मार्ग पर वाहनों के आवागमन में वृद्धि हुई है। इस खंड के बीच रेलवे समपार क्रमांक 30, किलोमीटर 1056/1-2 पड़ता है, जहां रेलवे फाटक दिनभर में अधिकाश समय बंद रहता है। जिस कारण फाटक के दोनों तरफ वाहनों का जाम लगा रहता है और नागरिकों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड में यातायात को सुगम बनाने के लिए लंबे समय से रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण की मांग की जा रही है। पूर्व में मेरे द्वारा लोकसभा में प्रश्न उठाने पर उत्तर दिया गया था कि ओवर ब्रिज निर्माण हेतु डिजाइन के टेंडर लग गए हैं। लेकिन ओवर ब्रिज

निर्माण हेतु अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जबकि नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए ओवर ब्रिज का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

(नौ) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रतनगढ़ सरदारशहर तथा सादुलपुर-हनुमानगढ़ खण्डों पर रेल अंडर-पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : संसदीय क्षेत्र चुरू राजस्थान में रतनगढ़-सरदारशहर एव सादुलपुर-हनुमानगढ़ खंड का आमान परिवर्तन होने जा रहा है। इन दोनों ही खंडों पर आने-जाने वो रास्तों पर मानवरहित-मानवसहित/रेल अंडर पास नहीं होने के कारण ग्रामीणों के समक्ष विकट संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों के सैंकड़ों वर्षों के रास्ते बंद होने जा रहे हैं। बड़ी लाइन गिरने के पश्चात तो यह संकट और भी विकट हो जाएगा। बड़े वाहनों की बात तो छोड़िए किसान अपने खेत में ऊंटगाड़ा तक को नहीं ले जा सकता। उक्त दोनों खंडों पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। रेलवे, राज्य सरकार व राज्य सरकार रेलवे पर जिम्मेदारी डाल रही है। यही स्थिति लोहारू-सादुलपुर-चुरू-रतनगढ़ रेल लाइन के पास पड़ने वाले गांवों के रास्तों की है। दिनांक 09.11.2012 को उक्त खंड के गुगलवा-किरतना हॉल्ट स्टेशन के पास रेल लाइन पर क्रॉसिंग नहीं होने के कारण बोलेरा में बैठे चार व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गईफ सादुलपुर-झूम्पा रेल लाइन के सड़क/कटानी रास्तों पर रेल समपार निर्माण की आवश्यकता है। रेलवे को रेल लाइन क्रॉसिंग की नीति में परिवर्तन करना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। मैं काफी समय से इसकी मांग कर रहा हूं। बार-बार अधिकारियों/सरकार को इस विकट समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ये रेल सूरक्षा सो जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरी सरकार से मांग है कि जनता की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए सैकड़ों वर्षों के कटानी मार्गों व खेतों के रास्तों पर मानव सहित/मानव रहित/रेल अंडर पास का निर्माण करवाकर जनता की महत्वपूर्ण मांग को पूरा किया जाए।

(दस) सतना नगर निगम की जलापूर्ति परियोजना को योजना यू.आई.डी.एस.एस.टी. योजना के अन्तर्गत अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान मेरे ससंदीय क्षेत्र सतना मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र की जलापूर्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यूआईडीएसएसएमटी योजना के तहत 24, जून, 2009 को राज्य स्तरीय बैठक में 11 नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रगस्ताव स्वीकृत हेतु शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था। जिनमें सतना नगर निगम क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु 73 करोड़ लागत की परियोजना शामिल थी। पुनः मध्य प्रदेश सरकार ने 13 जून, 2011 को सतना नगर निगम क्षेत्र को प्राथमिकता नं. 1 पर रखते हुए 19 प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से 10 प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य है कि प्रथम प्राथमिकता होते हुए भी सतना निगम का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया। मैंने समय-समय पर लोकसभा में इसकी स्वीकृति हेतु मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट कराया था और मंत्रालय से पूर्व में पत्राचार भी कर चुका हूं। महोदया, मेरी आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री जी से अपील है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सतना में भयंकर पेयजल की समस्या तथा शहर का विस्तार तेज गति से होने के कारण पुरानी पाइन लाइन, सीवर लाइन आदि का गंभीर संकट है। अतः प्राथमिकता के आधार पर सतना नगर निगम के प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा करें। ज्ञात हुआ है कि स्वीकृति नहीं दी जा रही है, जो पक्षपात की श्रेणी में आएगा।

(ग्यारह) विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन की धनराशि में वृद्धि किए जाने तथा इन योजनाओं के अंतर्गत बिहार के वंचित लोगों को पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : आज महंगाई की जो स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध व्यक्तियों को दिए जा रहे सामाजिक पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी की अत्यंत आवश्यकता है। आज सरकार सिर्फ 80 वर्ष के वृद्ध बीपीएल नागरिक को 500 रुपये की राशि मुहैया करा रही है। जबकि, 60 वर्ष के सभी बीपीएल नागरिकों को 500 रुपया की राशि दिया जाना चाहिए था। साथ ही विकलांग एवं विधवा महिला को इस योजना के लाभ के तहत नई राशि 500 रु. निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि, महंगाई के इस युग में सरकार द्वारा देय वर्तमान पेंशन राशि से अपना जीवन बसर करने में कुछ खास मदद नहीं मिल पाता। जिस कारण सरकार की इन योजनाओं की सार्थकता में कमी रह जाती है। अतः सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं को अधिक कारगर बनाने हेतु इस ओर ध्यान देना

[श्रीमती रमा देवी]

आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे नागरिक सामाजिक पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित है। ऐसे परिवारों की पहचान एक नई पैनल द्वारा पूरे बिहार में तैयार कराई जाए जिससे उक्त पेंशन के योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के साथ इस कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। तभी हम गरीबों के साथ न्याय कर पाएंगे।

अत: सरकार से अनुरोध है कि सामाजिक पेंशन योजनाओं में निर्धारित राशि 200 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये की जाये साथ ही सामाजिक पेंशन से वंचित गरीब परिवारों को नया पैनल तैयार कर जोड़ा जाए जिससे गरीबों को समुचित लाभ मिल सके।

(बारह) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाबागंज, कुंडा, सिराथू चायल और मंझनपुर विधान सभा क्षेत्रों के शेष रह गए गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : उत्तर प्रदेश के कौशांबी संसदीय क्षेत्र में आने वाले जनपद प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी के मुख्यत: बाबागंज, कुण्डा, सिराथू, चायल एवं मंझनपुर विधान सभाओं में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण से बहुत सारे गांव एवं पुखे (मजरे) छूट गए हैं। केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री जी की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए उन छूटे गांव पुरवों में तत्काल सर्वे कराके विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था करें।

(तेरह) पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदनीपुर के नंदीग्राम में एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक) : जीने के लिए मनुष्यों की पांच आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है चिकित्सकीय उपचार। आज यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि चिकित्सा विज्ञान सुखी और सेहतमन्द जीवन प्रदान करता है। परंतु स्वस्थ और स्वच्छ स्थिति से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हम एक अच्छे अस्पताल के अभाव में लोगों को बहुत असहाय और दुखी परिस्थिति में देखते हैं। किसी मरीज़ को यदि किसी बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता हो या हृदय संबंधी अथवा मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी हो तो उसे लंबी दूरी तय कर कोलकाता जाना पड़ता है। परिणामस्वरूप रास्ते में मरीज की स्थिति और खराब हो जाती है। नंदीग्राम में कई अस्पताल हैं। पर उपचार को संभावना को देखते हुए और आज के एक अच्छे अस्पताल के विचार के संबंध में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से अधिक कुछ नहीं है।

अत: यह मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्री, भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नंदीग्राम में एक एम्स जैसे अस्पताल के निर्माण पर विचार करें ताकि इसकी बिगड़ती हुई स्वास्थ स्थिति को सुधारा जा सके।

(चौदह) तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के अम्बुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 को चार लेन से छह लेन वाला बनाये जाने के बजाय कृष्णागिरी-वालाजापेट (एम.सी. रोड़) सड़क पर को चार लेन से छह लेन वाला बनाये जाने के बजाये या तो बाइपास रोड या पलाईओवर रोड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर) : अंबूर, वेल्लोर जिला तमिलनाडु में रा.रा. 46 पर कृष्णागिरी-बालाजापेट (एम.सी. रोड) को चार से छह लेन तक विस्तृत करने के प्रस्ताव हेतु वर्तमान रोड के दोनों ओर से दस मीटर भूमि उपार्जित करने की आवश्कता है। यह अस्थानीय लोगों और उनके परिवारों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा जो छोटे धंधों में शामिल है, इनसे उनकी आजीविका छिन जाएगी। इसके अतिरिक्त, चर्म उद्योग और जूता बनाने वाली इकाइयों के स्थानीय उद्योग भी प्रभावित होंगे।

दिसम्बर 2011 में मैंने माननीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्री को इस विषय में सोचने के संबंध में पत्र लिखा था और आग्रह किया था कि अल्पतम विस्थापन के साथ मध्यम मार्ग अपनाकर विकास कार्य जारी रहना चाहिए। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किए कि वर्तमान रोड पर या तो एक नया बाईपास या एक फ्लाइओवर निर्मित किया जाए जिससे कि मूल्यवान मानव जीवन को घातक दुर्घटनाओं से बचाया जा सके जिसकी वर्त्तमान दर कम से कम एक दुर्घटना प्रतिदिन है।

(पंद्रह) देश में 44 शैक्षणिक संस्थाओं को दिये गये मानित विश्वविद्यालय के दर्जे को बहाल किये जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : भारत सरकार ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनेक शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड टू.बी. यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था किन्तु 2010 में 44 डीम्म विश्वविद्यालय निर्धारित किए गए और उनका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दर्जा वापस लिया गया। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों छात्रों का भविष्य जोखिम में है। उन 44 डीम्ड टू बी. यूनिवर्सिटी में से एक मेरे संसदीय क्षेत्र भुवनेश्वर में है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपने पहले के आदेश की समीक्षा करे ताकि उनका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस दिया जा सके। इस संबंध में पारदर्शी और सही परिणामों के लिए सम्पूर्ण विषय की जांच हेतु एक नया समीक्षा पैनल स्थापित किया जाए। असंतुष्ट पक्षों को पैनल के सामने अपना मामला रखने का अवसर भी दिया जाए। जल्द से जल्द निर्णय लेने से संस्थानों के संबंध में फैल रही अनिश्चितता समाप्त होगी।

(सोलह) महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनगर समुदाय को शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी) : मैं **धनगार** समुदाय को लम्बित पड़ी मांगों के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाना चाहूंगा। **धनगर** समुदाय, जिसमें लोगों की काफी बड़ी संख्या है, महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हुआ समुदाय है। वे कई वर्षों से उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए जोरदार शेष प्रकट करते रहे हैं।

वास्तव में **धनगर** और **धनगड़** एक ही है। **धनगर** में क्रम संख्या 36 पर ओरांव **धनगड़** के रूप में शामिल है। राज्य में केवल एक ही समुदाय है जिसे **धनगड़** लिखा और **धनगर** बोला जाता है। महाराष्ट्र में **धनगड़** नामक कोई समुदाय ही नहीं है। रिपोर्टों में **धनगड़** और **धनगर** के बारे में दी गई नृवंशीय और नृजातीय सूचना समान है जो चरवाहों का पर्यायवाची है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही समुदाय है, अर्थात् महाराष्ट्र के चरवाहे। महाराष्ट्र सरकार पहले ही भारत सरकार से **धनगर** समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश कर चुकी है। यहाँ तक कि 1989 में कैग रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि **धनगर** समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

हालांकि कुछ तकनीकी अथवा अन्य कारणों से अभी तक धनगर समुदाय को अजजा का दर्जा नहीं दिया जा सका है। इस समुदाय से संबंध रखने वाले लोग पिछले कई वर्षों से शेष प्रकट करते रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके न्याय की मांग करते रहे हैं। उनकी मांगें उचित और विचारपूर्ण हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से इस विषय पर विचार करने तथा विलम्ब के लिए कारण बताने का आग्रह किया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि **धनगर** समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शीघ्रतम शामिल किया जाए और उन्हें सभी लाभ दिए जाएं जैसा कि अन्य अनुसूचित जनजातियों के मामले में किया गया है।

(सत्रह) महाराष्ट्र के कोपरा-पनवेल क्षेत्र में प्रस्तावित नवी मुंबई विमानपत्तन के लिए आवश्यक स्वीकृति दिए जाने तथा वहां पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : कोपरा-पनवेल क्षेत्र में प्रस्तावित नए विमानपत्तन को सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसमें 74 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र का होगा तथा 13% हिस्सा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का तथा 13% हिस्सा नगर और औद्योगिक विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र सरकार का होगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानन नागर संगठन ने पहले ही प्रस्तावित विमानपत्तन को तकनीकी व्यवहार्य की स्वीकृति दे दी है। विमानपत्तन क्रियाकलाप के लिए लगभग 11.4 कि.मी. भूमि की आवश्यकता होगी तथा 3700 मीटर लंबे समानांतर रनवे होंगे। दिसंबर 2012 तक निर्माण कार्य आरंभ हो जाने की संभावना है। तथापि, निर्माण कार्य में विलंब हो सकता है क्योंकि न तो केन्द्र सरकार ने अपने बोली-पूर्व दस्तावेज को स्वीकृति प्रदान की है और न ही भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध प्रदर्शन के कारण कोई विशेष प्रगति हुई है। सिडको के अध्यक्ष ने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया कि प्रस्तावित विमानपत्तन पर प्रक्रियागत कार्य शीघ्रातापूर्वक करे ताकि कार्य आरंभ किया जा सके। राज्य वन विभाग से प्रस्ताविक विमानपत्तन के लिए सिडको द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब तथा अन्य तकनीकी कारणों से निर्माण कार्य आरंभ करने में और अधिक विलंब होगा।

[डॉ. संजीव गणेश नाईक]

चूंकि प्रस्तावित विमानपत्तन स्थल एक दलदली भूमि तथा पहाड़ी स्थल है, इसलिए निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले भूमि को समतल करना आवश्यक है। तदुपरांत, सिडको के पास अन्य आवश्यक कार्य करेगा, जैसे कि, पहाड़ी को काटना तथा दलदली भूमि को भरना। तथापि, सिडको को ये कार्य अभी आरंभ करने हैं क्योंकि यह वन विभाग से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है।

यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इसे स्वीकृति अथवा अन्य विभागों के कारण इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा कोपरा-पनवेल क्षेत्र में प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का कार्य तेजी से प्रारंभ करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निदेश दें।

(अठारह) तमिलनाडु के चेन्नई मंडल में पवुर चतरम में रेलवे आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री पी. लिंगम (तेनकासी) : भारतीय रेल का चेन्नई संभाग एक महत्वपूर्ण संभाग है। इस संभाग में, तिरूनेलवेली तथा सेनकोट्टाई के बीच रेलवे लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में इस रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है तथा तिरूनेलवेली और सेनकोट्टाई के बीच इस मार्ग पर प्रतिदिन तीन यात्री रेलगाड़ियां चलती हैं और इस पर अधिक राजस्व एकत्रित किया जा सकता है यदि वर्तमान में प्रचालित रेलगाड़ियों में यात्री की भारी भीड को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर नई रेलगाड़ियों को प्रचालित किया जाए।

क्योंकि, इस रेलवे मार्ग पर एक पर्यटन स्थल कुटरालाम जलप्रपात है, बहुत से तीर्थस्थल हैं तथा सेनकोट्टोई है - जो केरल जाने का रास्ता है। पवूर चतराम एक रेलवे स्टेशन है। चूंकि इस रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत से गांव हैं, पवुर चेतराम से बहुत से यात्री तिरूनेलवेली तथा सेनकोट्टाई जाने के लिए रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। परंतु पवुर चेतराम पर कोई यात्री आरक्षण केन्द्र नहीं है। इसके कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि पवुर चेतराम पर एक यात्री आरक्षण काउंटर खोल दिया जाए तो इस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि पवुर चेतराम में एक नया यात्री आरक्षण केन्द्र खोला जाए।

(उन्नीस) बिहार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संबंधित सूची में तेली, कानु, लोहार, कुम्हार, मल्लाह, नोनिया, कहार, धानुक, ततवा, तांती, केवट, गोदी, गन्गोट गड़ेरिया, बेलदार, पल्दार चौपाल, खटवे और दधी जातियों को शामिल किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार राज्य के अंतर्गत तेली, कानू, लोहर, कुम्हार, मल्लाह, नोनिया, कहार, धानुक, ततवा, तॉती, केवट, केऑट, गोढ़ी, गंगौत, गरेडिया, बेलदार पलदार, चौपाल खतवे, ढाढी आदि जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दयनीय है। अत: इन जातियों का महासंघ बराबर अपनी तरक्की हेतु सवाल उठाते रहते हैं।

तेली जाति का संघ अति पिछड़ी अथवा अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होने हेतु लड़ रहे हैं। चौपाल, खतवे और ढाढी अनुसूचित जाति की स्वतंत्र सूची में शामिल होना चाहते हैं। लोहर, नोरिया, मल्लाह, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होना चाहते हैं। इसी प्रकार कुम्हार, तुरहा, ततवा, तॉती, कानू धानुक और अन्य जातियां अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होना चाहते हैं।

अत: आग्रह है कि राज्य सरकार से परामर्श कर इन जातियों के महासंघ की मांगों की स्वीकृति हेतु विधेयक लाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

(बीस) पश्चिम घाट के संरक्षण के बारे में माधव गाडगिल समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा केवल 500 मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रों को ही केरल के संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम) : मैं पश्चिम घाट की पारिस्थितिकी विशेषता के संरक्षण के संबंध में माधव गाडगिल समिति की सिफारिशों पर केरल के लोगों के अत्याधिक ऐस के बारे में बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह प्रतिवेदन अव्यावहारिक है तथा इसमें केरल में पश्चिम घाट क्षेत्र के साथ स्थापित समितियों के विशिष्ट जनसांख्यिकीय बनावट को शामिल नहीं किया गया है।

गाडगिल समिति ने केरल में 14 तालुक वर्गीकृत किए हैं जो अत्यंत सुकुमार पारिस्थितिकी क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों मे बाँधों के निर्माण, 10 एम.वी. से अधिक विद्युत निर्माण ईकाईयां, खनन तथा यहां तक कि खेती में रासायनिक खाद तथा पेस्टनाशकों के प्रयोग की भी अनुमति नहीं है। यद्यपि तमिलनाडु में पारिस्थितिकीय रूप से सुकुमार क्षेत्र में 500 मीटर की ऊंचाई से उपर की बसावट शामिल है, फिर भी गाडगिल समिति ने यह स्पष्ट किया है कि केरल में सुकुमार क्षेत्र में केवल 150 मीटर तथा उससे अधिक की उँचाई ऐसे क्षेत्रों के लिए शामिल की जाए। यह वनकी भेदभावपूर्ण है क्योंकि राज्य में अधिकतर कृषक वर्ग, जो छोटे किसान हैं पश्चिम घाट के साथ-साथ बसे हुए हैं जिनके पास दो एकड़ कृषि योग्य भूमि है तथा न्याय का उपहास होगा कि उन्हें उत्पादकता के उन्नत साधनों जैसे रासायनिक खादों तथा पेस्टनाशकों के लाभों से वंचित रखा जाए। केरल के लोग महसूस करते हैं कि आम लोगों के लिए आजीविका बनाए रखने के लिए ही विकास की कीमत पर पारिस्थितिकीय स्थिति को ध्यान में न रखा जाए।

अपराह्न 12.10 बजे

(एक) मल्टी-ब्राड खुदरा व्यापार में 5 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को वापस लेने संबंधी सिफारिश के बारे में प्रस्ताव

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत, जारी अधिसूचना में उपाबंध (क) और उपाबंध (ख) में उपांतरण के संबंध में प्रस्ताव

और

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के उपाबंध (ख) में उपांतरण के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा मद संख्या 19 से 21 को लेगी– श्री बसुदेव आचार्य बोलना जारी रखें। श्री बसुदेव आचार्य, आपके पास बहुत थोड़ा समय बचा है। कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, कल कपिल सिब्बल जी ने हमारी पार्टी के नेता, राज्य सभा के नेता कामरेड सीताराम येचुरी के एक स्टेटमेंट को रेफर किया था। यहां पर उन्होंने हम लोगों का इनकंसिस्टेंस, यह हमारी पार्टी का इनकंसिस्टेंस है कि आज हम एफडीआई इन रिटेल का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अपने बयान में उन्होंने रिटेल में एफडीआई का समर्थन किया। हम एफडीआई के विरोध में नहीं हैं, लेकिन तीन कंडीशंस में हम एफडीआई का स्वगत करेंगे। यही सीताराम येचुरी के स्टेटमेंट में था। ये तीन कंडीशंस क्या हैं? अगर एफडीआई हमारे देश में रोजगार दिलाने में मदद करे तो हम उसका स्वागत करेंगे, अगर एफडीआई हमारे देश में प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ाने में मदद करे, तो हमारा कोई ऐतराज नहीं है, अगर एफडीआई तकनीकी डेवलप करे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुदरा व्यापार में जो आप एफडीआई को ला रहे हैं, आप बताइए कि क्या ये रोजगार देंगे या छीनेंगे? ये रोजगार छीनेंगे। क्या हमारे देश में तकनीकी नहीं है, वह क्या नई तकनीकी लाएंगे?...*(व्यवधान)* उत्पादन बढ़ाने में क्या मदद देंगे, क्या एफडीआई मददगार होंगे, नहीं होंगे, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं, हमारी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी है। प्रधानमंत्री जी जब राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और उसमें एफडीआई इन रिटेल सेक्टर में विरोध किया था। आज प्रियरंजन दास मुंशी हमारे सदन में नहीं हैं, उन्होंने एफडीआई इन रिटेल सेक्टर को इसी सदन में एंटी नेशनल बताया था।...*(व्यवधान)* हमारा कंसिस्टेंसी है, आपका कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने फार्मास्युटिकल सेक्टर में एफडीआई के बारे में बताया कि शत-प्रतिशत एफडीआई फार्मास्युटिकल सेक्टर में लाने के बाद हमारी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनकर उभरी है। आज फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री की क्या हालत है? आपने दो फार्मास्युटिकल कंपनीज के बारे में बताया।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये दो कंपनियां भारतीय कंपनियां हैं? क्या ये भारतीय कंपनीज हैं इन कंपनियों का स्वामित्व बहु-राष्ट्रीय कंपनियों ने ले लिया है, आपने फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, और बहु-राष्ट्रीय कंपनियां हमारी स्वदेशी कंपनियों का स्वामित्व ले रही हैं:

[श्री बसुदेव आचार्य]

[हिन्दी]

आज दवा का भाव क्या हो गया, दवा का कितना भाव हो गया है? आप कह रहे हैं कि जब आपने एफडीआई की इजाजत दे दी तो हमारे देश की फार्मास्युटिकल कंपनीज ने बहुत तरक्की की है। आपने पश्चिम बंगल के वर्धमान जिले के किसानों के बयान को यहां पर बताया है। हम अमेरिका के किसान के बयान आपको सुना रहे हैं। कपिल सिब्बल जी जरा मेरी बात सुनिए।

[अनुवाद]

जबकि वॉल-आर्ट्स, सौप राइटस और अन्य चेन स्टोर्स अपने किस्म के ब्याज प्रति पाउंड 1.49 डॉलर से लेकर 1.89 डॉलर के भाव से बेचते हैं, स्वयं पावेल्सकी को 17 सेंट्स से ज्यादा नहीं मिलता। हाल ही में इसमें 12 सेंट्स से 12 सेंट्स की वृद्धि हुई है। उत्पादक को कितना मूल्य मिल रहा है? उत्पादक को केवल 5 डॉलर मिलते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? इसका विक्रय मूल्य 50 डॉलर से 200 डॉलर के बीच है। श्री कपिल सिब्बल को इस बारे में मालूम होना चाहिए। इसमें क्या अंतर है?

[हिन्दी]

आपने बताया कि किसान को बहुत लाभ होगा, किसान को उचित भाव मिलेगा। आज जो परिस्थिति हमारे देश में है कि किसान जिस भाव पर बेचते हैं, उनको मजबूरी में उस भाव पर बेचना पड़ता है। यह आपकी गलत नीति के कारण है। उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं, उसके भाव में और किसान को मिलने वाले भाव में बहुत अंतर है। फार्म गेट मूल्य और उपभोक्ता मूल्यों में व्यापक अंतर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी नीति जिम्मेदार है। क्या किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, इसके लिए दुनिया भर का क्या तजुर्बा है? न किसान को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा और न उपभोक्ताओं को सही भाव मिलेगा। यह मोनोपलाइजेशन हो जाएगा। क्या हम भूल सकते हैं कि आपने मॉनसैन्टो को हमारे यहां 2002 में बीटी कॉटन के लिए इजाजत दी। क्या हालत हुई? शिन्दे जी के राज्य में हम गए थे। जिस गांव में सबसे ज्यादा सूसाइडल डैथ्स हुई थीं—यवतमाल जिले के गोरेगांव में पूरी स्टैन्डिंग कमेटी को लेकर हम उस गांव में गए थे। हमारे सामने कम से कम 50 विधवा महिलाएं आई थीं जिनके प्रतियों ने सूसाइड किया था। दस साल के अंदर मॉनसैन्टो कंपनी ने बीज का व्यापार करके, हमारे देश के किसानों को लूटकर कितना पैसा कमाया—35000 करोड़ रुपये से 40000 करोड़ रुपये तक मॉनसैन्टों कंपनी ने बीज का व्यापार करके कमाया और हमारे देश के बेचारे 2,76,000 किसानों को खुदकुशी करनी पड़ी। क्या भाव मिलेगा? मोनोपोली होगी प्राइस डिटरमिनेशन के लिए और वस्तुओं के अधिग्रहण हेतु क्रेताधिकार होगा। पूरी दुनिया में जिस देश में वॉलमार्ट गया है, वहीं ऐसी हालत हुई है। न किसानों को मूल्य मिला, न उपभोक्ताओं को सस्ते में सामान मिला।

दूसरा क्या तर्क आनंद शर्मा जी दे रहे हैं कि इनफ्लेशन घटाएंगे। हमने देखा कि बहुत सारे बयान आए। भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौशिक सेन का ब्यान आया। हमारे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डॉ. मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया का बयान आया। सरकार इनफ्लेशन घटाने में कामयाब नहीं हुई है। क्या कारण है? एक ही कारण है कि हम अपने देश में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को इजाजत नहीं दे रहे हैं। जब हमारे देश में आ जाएगा तो मुद्रा स्फीति और इनफ्लेशन घट जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, प्लीज कनक्लूड।

श्री बसुदेव आचार्य : आज यूरोपियन कंट्रीज में क्या हालत है जहां पर वॉलमार्ट व्यापार कर रहा है? वहां इनफ्लेशन बढ़ रहा है।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैट्रो में क्या हुआ?

श्री बसुदेव आचार्य : अरे मैट्रो की बात छोड़िए। मैट्रो और एफ.डी.आई. दो अलग-अलग बातें हैं...*(व्यवधान)* क्या मैट्रो ने इनफ्लेशन घटाया है?

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव जी, आप कल भी बोल चुके हैं और आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे दो-तीन पॉइंट बाकी हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त कीजिए। आप कल भी बोल चुके हैं। मुख्य बातें आपने कल बोल दी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : तीसरी बात यह है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिज आप इतना बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं। मेरे पास आई सी ए आर की रिपोर्ट है। उसमें किसी भी कमोडिटी में, किसी भी क्रोप में 0.8 से 10 परसेंट से ज्यादा नहीं है। आप बता रहे हैं

कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिज को हम घटा सकेंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश में जितने कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, उतने नहीं है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश में 5365 कोल्ड स्टोरेज हैं। उसमें से ज्यादा प्राइवेट सैक्टर में है। अमरीका में डेढ़ हजार कोल्ड स्टोरेज है।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : वहां 70 परसेंट कैपेसिटी सरकार के नियंत्रण में है। आपने 11 फाइव ईयर प्लान में 30 मेगा फूड पार्क का सैक्शन किया था। लेनिक पांच साल में भी यह काम पूरा नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वॉलमार्ट आकर हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, सड़क बनाएगा, गांवों को सड़क से जोड़ेगा। वह जो काम करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने व्यापार के लिए करेंगे। हमारे देश में किसानों की सुविधा के लिए, इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इनवैस्ट नहीं करेंगे। आप बता रहे हैं कि तीस फीसदी. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद बासुदेव आचार्य जी।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इनको स्वदेशी, लघु और मध्यम उद्यमों से लगभग 30 प्रतिशत जुटाना है। लेकिन आनंद शर्मा जी के प्रैस नोट में वह कह रहे हैं-

> "तीस प्रतिशत संसाधन सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जुटाए जाने हैं जिसे विशेषकर भारत ही नहीं विश्व में कहीं से भी किया जा सकता है। तथापि, इस मामले में, यह विहित किया गया है कि 30 प्रतिशत संसाधन उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जुटाए जाएंगे जिसके पास एक मिलियन मूल्य की सुनियोजित पूंजीगत मशीनरी है।"

[हिन्दी]

यह तो साफ है कि वह कहां से हमारे देश में लाएंगे। कैसे हमारे देश में लाएंगे। कैसे हमारे देश में 30 परसेंट रिज़र्वेशन करेंगे?. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपका भाषण आपके दल को दिए गए समय से अधिक हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं समाप्त कर रहा हूं क्यों हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे देश के हित में नहीं है। हमारे देश के किसानों के हित में भी नहीं है। किसान भी मरेंगे और जो खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, चार-साढ़े चार करोड़ ही नहीं 25 करोड़ आबादी इसके ऊपर निर्भर है। इस 25 करोड़ आबादी को उजाड़ने के लिए आप एफडीआई की इजाजत दे रहे हैं। आप वॉलमार्ट को यहां ला रहे हैं। हमारे देश के किसानों की मदद करने की बजाय उसे भूल रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में जो संकट है, उसका आप समाधान नहीं कर सकेंगे। हम विरोध कर रहे हैं हम जानते हैं कि हम जब मांग कर रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन केवल चर्चा ही नहीं हम इस पर अपना मतदान भी दे सकें। आप पहले राजी नहीं हुए। चार-पांच दिन सदन नहीं चला। उसके बाद राजी हो गए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। श्री शरद यादव।

श्री बसुदेव आचार्य : जब आप नंबर मैनेज कर सके। लेकिन हमने कल भी बताया, जितना विरोध इस मुद्दे को लेकर देश भर में हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप पहले ही दी गई समय-सीमा से अधिक बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

आप अब बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानते हैं कि हमारा यह जो प्रस्ताव है, जिसका हम समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

[अनुवाद]

सरकार को इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना देश के हित में, हमारे किसानों और रिटेल क्षेत्र के हित में नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें।

[हिन्दी]

हम जानते हैं और हमले भी हमने देखा है कि वर्ष 1993 में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए। बसुदेव आचार्य जी, आप इतने सिनियर मैम्बर हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, उसको किस तरह से नाकाम कर दिया गया था। हमने देखा है कि वर्ष 2008 में 22 जुलाई को जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, उसको कैसे पारित किया गया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप इसे आज कैसे समाप्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानते हैं कि आज भी सरकार इसमें हमें कामयाब नहीं होने देगी। सदन में तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसको सदन के बाहर हम ले जाएंगे, सड़क पर ले जाएंगे और हमने यह फैसला लिया है कि जिन 53 शहरों में आप करना चाहते हैं, वहां हर जगह विरोध होगा। हम हमारे देश की मिट्टी में वॉलमार्ट को पैर नहीं रखने देंगे, इतनी आसानी से रखने नहीं देंगे, विरोध होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजए। अब आपने फिर से आरंभ कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं गया जाएगा। अब मुझे यह कहना होगा

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन वॉलमार्ट को हम इतनी आसानी से देश में नहीं आने देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शरद जी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। अब कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इस सवाल पर सुषमा जी, कपिल सिब्बल साहब, भाई मुलायम सिंह जी, बसुदेव आचार्य जी ने और राव साहब ने व्यापक चर्चा की है। मैं आप से, सरकार से और सदन से निवेदन करूंगा कि एक अवसर आया था न्यूक्लियर डील का और लेफ्ट के लोगों ने न्यूक्लियर डील पर विरोध स्वरूप सरकार का साथ छोड़ने का काम किया था। इसके बाद पिछले शीतकालीन सत्र में एफडीआई आया। उसमें तृणमूल कांग्रेस ने मजबूती से, हम लोगों से नहीं रुक रहा था और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसे हमें रोकने में मदद की।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की जो बहस हो रही है, उसमें मैं मानता हूं कि सरकार बाजिद है। इस सवाल पर कपिल सिब्बल जी ने कल जो भाषण दिया, मैं मानता हूं कि उनके मुंह से सच ही सच निकला। पूरा सदन हिंदी में बोला। बाहर इनको खबर मिल गई है कि इनकी जो भाषा है, वह दिल्ली के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में सुनी जाती है और दिल्ली के कुछ सीमित लोगों में जो भाषा चलती है, उसने भी देश को बहुत बर्बाद किया हैं।

महोदया, बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं है। बहुसंख्यक समाज, किसान

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपकी जीडीपी में 16.6 परसेंट देता है। खुदरा व्यापार में लगे हुए जो लोग हैं, वे आपसे रोजगार नहीं मांगते हैं। ये इस देश के वैसे नागरिक हैं जो हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपनी पुरूषार्थ से, अपनी मेहनत से इस देश की जीडीपी में 12.4 फीसदी योगदान देते हैं। ये लोग लगभग 85 प्रतिशत है। देश 85 प्रतिशत के साथ है या 15 प्रतिशत के साथ? जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनके बारे में कल कपिल सिब्बल जी ने बड़ी जोरदार बात कहीं। इस पक्ष के जिन लोगों ने बोला है, उससे मैं मानता हूं कि देश की जनता के पास खबर चली गई है कि क्या सवाल इधर का है और क्या सवाल आपका है?

वालमार्ट, केयरफोर, टेस्को में साईकिल वाले, स्कूटर वाले कहां जाएंगे? मैं आपसे कहूं कि हमने इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक भारतवर्ष है। कपिल सिब्बल साहब, हमारे और आपके बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक बात का अंतर है कि आपने दो भारत बना दिए। एक भारत की आपको चिंता है। आपको बाजार की चिंता है। आपने कल व्यथा कही कि बाजार तो चौपट हो गया। आपने जीडीपी की बात कही। आपने अर्थव्यवस्था की बात कही। अर्थव्यवस्था के लिए यह सरकार सबसे ज्यादा जीडीपी के लिए चिंतित है। मैं मानता हूं कि इस सरकार को जीडीपी के लिए जरूर चिंतित होना चाहिए।

मैं बाजार के बारे में मानता हूं कि दुनिया के बाजारों को मिलने से आप रोक नहीं सकते। इस देश का बाजार भी पांच हजार वर्षों का है। यह जान लें कि यहां की सभ्यता और चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। यह भी जान लें कि इतिहास में कभी यह देश सबसे ऊंचाई पर था। आज हम दुनिया में किसी देश की ऊंचाई उसकी जीडीपी से नापते हैं। हम नापते हैं इम्पोर्ट से। हम नापते हैं इस बात से कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऊंचा बढ़ा या नहीं। लेकिन, रुपया थमता नहीं, यह नीचे गिर रहा है। आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसकी बड़ी तारीफ में आप बोल रहे थे, वह तो घट रहा है। आपने वाजिब चिंता रखी कि बाजार ठप्प हो गया है, ये सभी चीजें बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं और इकॉनोमी को बचाना है। यह इकोनॉमी तो जो 85 प्रतिशत लोग हैं, उन्हीं के सर पर होगी। क्या आपको न्यूक्लियर डील पर हमने रोका था? पर, यह जो मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई है, इस पर हमने रोका है। आपने जो कहा वह ठीक कहा, पर आप ठीक से सच नहीं कह रहे थे। यदि हम आपकी सरकार गिराना चाहते तो तृणमूल कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, हमने क्यों नहीं गिराया? हम क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? सरकार गिराने में हम एक बार औंधे मुंह गिर गए। अब पता नहीं कैसे गिरे, क्या गिरे, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। आनंद साहब, न्यूक्लियर डील आपके यहां आने वाला नहीं है। वह अमेरिका भाग गया। वह इस मामले में नहीं आ रहा। वह कह रहा है कि इतनी कड़ी शर्तें मत लगाओ। इसका मतलब हमें कमाने दो और कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें भागने दो। इसी तरह से हम तो फेल हो गए। हम क्यों चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आए। आप कह रहे थे कि आप वहां बैठना चाहते हैं। हमारी इच्छा तो वहां बैठने की है। लेकिन, ऐसी इच्छा नहीं जैसी आपकी इच्छा है? आप खाट पर बैठेंगे क्या? क्या आप तख्त चाहते हैं? राजनीति में हम कोई संन्यासी थोड़े ही हैं। हम कहां कह रहे हैं कि हम वहां बैठना नहीं चाहते, लेकिन हम कोई गलत तरीके से नहीं बैठना चाहते। अगर हम गलत तरीके से बैठते तो तृणमूल कांग्रेस के नो-कांफीडेंस मोशन पर आपके साथ खड़े हो जाते। हमने अकले एफडीआई के मामले में आपको कहा है कि नहीं, कपिल सिब्बल जी मनमोहन सिंह जी चले गए, सोनिया जी चली गईं। मैं सोचता था कि आज वे मेरी बात को जरूर सुनते।...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : मैं बता दूंगा।

श्री शरद यादव : हां, बता दें तो अच्छा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम आपको गिराना चाहते तो इस नो-कांफिडेंस मोशन में जरूर साथ देते। ये हमसे नाराज हुए, इन्होंने हमारे साथ बता करनी बंद कर दी। कल्याण बनर्जी जी हमारा नमस्कार नहीं कर रहे। ये अपना ही कल्याण करना चाहते हैं, हम सब का नहीं करना चाहते हैं। ये आपको जरूर किनारा लगाना चाहता था। हम भी किनारा लगाना चाहते हैं, हम कहां चाहते हैं। हम जितनी जल्दी चाहें, उनको हटाना चाहते हैं, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं। देश बचाने के लिए हमने कहा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनका रोजगार खेती है और एक यह खुदरा व्यापार है। कपिल सिब्बल जी, मैं शहर में रहा और गांव में भी रहा। मैं जब गांव में छुट्टियों में जाता था तो मुझे वह टोकरी वाली फल लेकर आती हुई सब्जी वाली दिखाई देती थी। सड़क पर अमरूद और आम हरे पत्ते के साथ बिकते हुए दिखाई देते थे। लोगों ने चार करोड़ कहा है, बिलकुल गलत बात है। अपने देश में हम गरीबों की संख्या नहीं पता कर

[श्री शरद यादव]

पाए, इसलिए खुदरा व्यापार के लोगों की संख्या का भी हम ठीक से पता नहीं लगा पाते। ये पांच करोड़ लोग हैं। ये रोज कमाते हैं, रोज उठते हैं और पेट की भूख का जो पहिया है,उससे बंधे रहते हैं। ये जो बाजार है, इसे आंका जरूर है, लेकिन सारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए क्या किया? जब से बाजार आया है, तब से दो लाख 75 हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली। हिंदुस्तान के इतिहास में भूख से मौत हुई है, किसान सबसे ज्यादा सहने और बर्दाश्त करने वाला आदमी है, जो हर तरह के मौसम में अपना जीवन जीता है, लेकिन मरने के लिए, आत्महत्या के लिए तैयार नहीं होता था। आप इसके लिए बीस साल से कर रहे हो। कपिल सिब्बल जी, सरकार के लोगों, आपके सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को संपन्न बना दिया है, जिनके लिए वॉलमार्ट लाना चाहते हो। कमल नाथ जी, वॉलमार्ट यहां सेवा करने के लिए नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता कि वह सेवा करने के लिए आ रहा है, वह कमाने के लिए आ रहा है।...*(व्यवधान)* आप सब तरह से लाइए। आप इन 85 करोड़ के रोजगार में हाथ डालने की जगह किसी चीज में लाई। मैं बाजार के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि यह बाजार दुनिया को, यूरोप और अमेरिका को मजबूत करता है। उन्होंने चार-पांच सौ साल में बहुत खूबसूरत कमल उगाया है। क्या आप भी इस देश में कमल उगाना चाहते हैं? कमल कीचड़ में पैदा होता है। कल कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि कार वाले वहां पहुंच जाएंगे। कार वालों को डीजल में सब्सिडी दे रहे हो। आप क्यों मुंह बना रहे हो, डीजल में आप सब्सिडी दे रहे हो। जितनी किसान को आप सब्सिडी देते हो, उतनी आप एसयूवी में दे रहे हो। यहां जयपाल रेड्डी जी बैठे हैं, इसी बाजार के लिए आपने मंत्रालय से निकाला। आज कितना ही उन्हें मना करिए, लेकिन जो सच्चा है, देश बनाता है, उसे आप धक्का मारते हो। कमल नाथ जी, आप हमें भी इस मोर्चे पर जीत सकते हों, मोर्चा जीतोगे। संग्राम नहीं जीतोगे, अंतिम लड़ाई हमारी होगी और जीत हमारी होगी। अगर यह सरकार एफ.डी.आई. पर रोलबैक नहीं करेगी तो हम इस सरकार को रोलबैक करेंगे, यह हमारा संकल्प है। हम आकर यदि इसी तरह का गुनाह करेंगे तो जो आपकी दुर्गति हुई, वही हमारी दुर्गति होगी। आपने कहा न कि हमने बहुत से काम किए, आपने याद दिलाया तो हमको तो सजा मिल चुकी। सुषमा जी अपोजीशन में बैठी हैं, आडवाणी जी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, शरद चादव थे, अब कहां बैठे हैं? अब हम कुछ नहीं हैं, अब हमारे पास बोली भर है और याद रखना, बोली से दुनिया चल रही है, गोली से नहीं चल रही है, पर आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

भारत बंद हुआ तो डी.एम.के. हमारे साथ थी, अब डी.एम.के. वाले चले गए। मायावती के दारा सिंह जी भी हमारे साथ थे। लालू जी नहीं थे, ये तो कह रहे थे कि मिठाई पर मक्खी भिनकती है, वह मक्खी भाग जाएगी। वालमार्ट आएगा तो मक्खी भाग जाएगी। भाई मुलायम सिंह जी हमारे साथ थे और निश्चित तौर पर भारत बंद में जब हमारे साथ थे तो हमारे मन में लालच था कि एफ.डी.आई. भी वापस हो जाए। इन्होंने नो कॉन्फीडेंस मोशन नहीं लाने दिया, क्योंकि, एफ.डी.आई. वापस करना चाहते हैं। अब भी नियम 184 में हम वोट नहीं करेंगे, आप इसे वापस ले लीजिंए। जो आपने प्रणब मुखर्जी जी के बाद कहा था, जब वे नेता सदन थे, नेता सदन भी चले गए, मनमोहन सिंह जी भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे और यदि आप रहेंगे तो ऐसी हालत बुरी होगी, जो कल भाई मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कभी इतना बड़ा धक्का नहीं लगा था, जैसा एफ.डी.आई. के मामले में आपने झेला है।

याद रखना, हिंदुस्तान 17वीं ईस्वी तक दुनिया में सबसे बड़े बाजार के सिरे पर था। आप मेरी बात को जरूर कन्फर्म कर लीजिए और आपके जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वे फिर कभी आधे घंटे की डिबेट कर लें। मेंने गहराई से इस देश के पतन को और इस देश के उत्थान को काफी गहराई से जानने की कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि संपूर्ण जानकारी मुझे मिल गई है।

[अनुवाद]

पहली शताब्दी में, विश्व के सकल घरेल उत्पादन में भारत का योगदान 32.9 प्रतिशत था तब चीन और भारत के बीच मुकाबला था....यह 24.5 प्रतिशत था ...*(व्यवधान)*... दूसरे स्थान पर यह 24.5 प्रतिशत था। 25 प्रतिशत के साथ चीन प्रथम स्थान पर था। 17वीं शताब्दी में, 24.4 प्रतिशत के साथ भारत पुनः प्रथम स्थान पर था ...*(व्यवधान)*... क्या हो गया? हम अकेले निपट लेंगे, आप क्या बोल रहे हो।

आज, 65 वर्षों के बाद, देश का सकल घरेलू उत्पादन गिरकर 5.5 प्रतिशत हो गया है।

[हिन्दी]

पहले 5.5 लिखा था, अब और घट गई। कपिल सिब्बल साहब, मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास प्लानिंग कमीशन है, आपके पास बहुत से अर्थशास्त्री हैं। आप कभी एक घंटे की बहस यहां करा लीजिए। हिंदुस्तान दुनिया के शिखर पर था और तब मुकाबला हमारे और चीन के बीच में था। जब शरीर का पुरुषार्थ था तो हिंदुस्तान दुनिया में आगे था। हां, हमारे समाज की विसंगति ने इस देश में विज्ञान की डैथ कर दी, आविष्कारों की डैथ कर दी। यहां आविष्कार की मृत्यु हो गई, आविष्कार नहीं हुए। यूरोप का कमाल है कि सारे आविष्कार वहां हुए। इस आविष्कार के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद यह बाजार चौपट और बर्बाद हुआ। यह वेस्ट इंडिया लाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं कह रहा हूं कि ईस्ट और वेस्ट मेल से आगे बढ़े। इंसानियत का जज्बा दोनों के अंदर होना चाहिए। बाजार का मतलब यह नहीं है कि मैं भी लूटूं और तुम भी लूटो, तो जो तना है, जो कमजोर है, वही टूटेगा। हजारों वर्षों में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद यही हुआ। जो गरीब है, जो हाथ से काम करता है, इस देश के हाथ में यह कमाल था कि दुनिया के वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न यूरोप में हमारा बाजार चारों तरफ फैला हुआ था। चीन और हिंदुस्तान का बड़ा नाम था। उस समय विज्ञान के आविष्कार का इतना खेल नहीं था। हमने विज्ञान के सारे युद्ध हारे हैं। दुनिया में इससे बड़ी त्रासदी कभी नहीं हुई। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने हमलावर के घुटने टिकवाए थे, इसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया।... *(व्यवधान)* आप क्यों एकदम साथ में बोल देते हैं? अब टोकोगे तो बात बिगड़ जाएगी, हम आपको टोकेंगे। हम तो किसी को टोकते नहीं है, बिल्कुल सीधे बैठते हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ? इन 85 फीसदी लोगों को जब से हमने कमजोर किया है, भारत कहीं नहीं टिका है। हमलावर आया है तो वह हारकर नहीं गया, लूटकर गया है। जिसके मन में आया, उसने राज किया। मैं नहीं कह रहा कि राज करने वाले देशी या विदेशी हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। हमारे भगवान का रंग सांवला है। इस देश के जेनेटिक साइंस में सांवला आदमी पैदा हो सकता है, लेकिन जो दूसरे लोग बाहर से आ गए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रंग की चमड़ी से नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कल एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप एफडीआई चमड़ी में भी ले आओ। यह कहें कि नहीं हम सांवले हैं, गोरे कर दो, माइकल जैक्शन जैसे गोरे हो जाएंगे...*(व्यवधान)* यह क्या चल रहा है, सभ्यता से इतना क्यों पसर गए हो, क्यों सोशल हो गए हो? महात्मा जी ने अपने पुरूषार्थ में खड़े होकर दुनिया को यह दिखा दिया कि गोली मारने से गोली खाना बड़ी बात है, गोली मारने वाले के लिए एक छटाक कलेजा चाहिए और गोली खाने वाले के लिए एक टन कलेजा चाहिए। यह महात्मा जी ने दुनिया को बता दिया। मैं कह रहा हूं कि क्यों हमने अपनी ताकत को नहीं समझा? इस देश में 87 मिनरल्स हैं। यह दुनिया का तीसरे नंबर का देश है। आपने आयरन-ओर मिट्टी के दाम भी नहीं बेचा, फोकट में बेच दिया। अपने यहां के मिनरल्स को, जिन्हें हिंदी में खनिज पदार्थ कहते हैं, वह तेल कहां आपको तंग करता, जीडीपी आपकी कैसे नहीं बचती, बाजार कैसे नहीं बचता, आपका घाटा कैसे नहीं बचता? अपने यहां जो ताकत है, जो ह्यूमन रिर्सोस है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा। डब्ल्यू.टी.ओ. या दुनिया के किसी फोरम में आपने यह नहीं कहा कि आप सामान के लिए तो दुनिया में सब तरह का बाजार तैयार कर रहे हो, लेकिन इंसानों के आने-जाने पर इस तरह की रोक क्यों लगा रहे हो? हमारा ड्राइवर यहां 4-5 हजार रूपये में गाड़ी चला देता है और अमेरिका का ड्राइवर, यदि वह ज्यादा लेता है तो हमारा ड्राइवर वहां चला गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी। हमारा रसोइया कितनी तनख्वाह ले ता है और वहां का रसोइया कितनी लेता है? यह गजब बात है। मैं समझता हूं कि अगर महात्मा जी होते तो इसका भी रास्ता निकालते, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इधर से उधर चले जाओ। आप रोक लगाओ, लेकिन इंसानों पर रोक कैसे लगाओगे, आप इंसान और आदमियों पर रोक कैसे लगाओगे? आप सामान के लिए देश और बाजार को खड़ा करना चाहते हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम वहां भी नहीं आना चाहते, जनता ताकत देगी तो जरूर वहां आएंगे, नही देगी, तो फिर यहीं बैठेंगे, बहुत वर्षों से बैठे हैं। कभी-कभी हमें भी लगता है कि हम लोग यहां खड़े रहे और देश नहीं बन पाया। 65 वर्षों में किसान, मजदूर जो मेहनत करता हूं, पसीना बहाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप कुछ देर में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरद यादव : आप उन्हें ताबाही के कागार पर ले कर

[श्री शरद यादव]

गए हें। आप क्यों नहीं सब चीज में लाते हैं? सब लोगों ने कहा, सुषमा जी ने कहा, कौन कहता है हम बाजार वाले हैं, बाजार के खिलाफ हैं, बाजार को रोक भी नहीं सकते हैं। आपका बाजार 5 हजार वर्ष पुराना है। यह बाजार कितने वर्ष का है। वह बाजार विज्ञान और आविष्कार पर आगे बढ़ गया है और इतना आविष्कार किया कि यहां के साढ़े तीन सौ राज्यों को साढ़े तीन महीने में जीत लिया। वह बंद हो गया। उन्होंने नया तरीका निकाला है। आप को मालूम है कि आप के बारे में सारे अखबार वाले कितना सर्टिफिकेट दे रहे थे? आपने एफडीआई रिटेल में रोका तो वे इसके ऊपर आप को रोज कह रहे थे कि आप का यह खत्म, वह खत्म, अखबार वाले लिख रहे थे। आप चिंतित हो गए। आपके मन में फफोला पड़ गया। जब से आप एफडीआई लाए हैं वे हर तरह से प्रसन्न हो गए हैं। सुषमा जी कह रही थीं कि छोटी दुकान अमेरिका जा रही है। वहां छोटी दुकान जा रही है और यहां वे बाजार खोलना चाहते हैं। यह अजीब बात है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सबके भाषण तो ठीक हैं, कपिल सिब्बल ने सरकार का जो एक्सरे किया है, जो पर्दा उठाया है कि सरकार किस लाचारी में है, रुपया डूब गया, एक्सपोर्ट घट गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चला गया। जो घाटा है वह बढ़ते जाएगा और इस रास्ते से जाएगा तो 40 लाख रोजगार आएगा। 65 वर्ष से आप किसान का भजन कर रहे हैं। आप ही नहीं हम भी भजन कर रहे हैं। 65 वर्ष से हम लोग गरीबी हटाओ, आम आदमी की सरकार, हम इंडिया साइनिंग कर रहे हैं लेकिन साइनिंग नहीं हुआ। गरीबों की जिंदगी नही बदली। किसानों की जिंदगी जैसे पहले खड़ी थी वैसे ही आज है। यह आजादी किसानों और मजदूरों के हक में नहीं खड़ी हुई। आजादी आज यहां पर जा कर खड़ी हो गई है कि हम टिस्को और वालमार्ट को यहां दोस्त बना कर लाना चाहते हैं। और कार वालों को बाजार देना चाहते हैं।

हम ने दो देश बनाए हैं। एक देश पैदल चलता है, एक देश साइकल पर चलता है, एक देश दिन भर कमाता है और खाने के लिए जाता है और एक देश मौज-मस्ती, होटल अलग, ट्रेन अलग, खाना अलग, बोली अलग, उसकी हर चीज अलग है। ऐसा भारत मत बनाओ। यह विकलांग भारत होगा और विकलांग भारत दुनिया में कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस भारत को विकलांग मत बनाओ।

अंत में मैं अपने मित्रों से कहना चहाता हूं जो भारत बंद में भी साथ थे कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।

सदन में यह इतिहास का एक मौका है। सारे सदन से मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास माफ नहीं करेगा जो तटस्थ रहेंगे। बहुसंख्यक समाज के लोगों का जो तबाही होने वाला है, बर्बादी होने वाला है।...*(व्यवधान)*

अंत में, मैं फिर आप से कह दूं कि यह जो मोर्चा है, कपिल सिब्बल जी, कमलनाथ जी, इस मोर्चा पर हो सकता है कि आप जीत जाएं और हम आर जाएं, हम जीत जाएं और आप हार जाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत बंद का भी एक मोर्चा था, यह मोरचा लगाया है, वे टीवी वाले लोग घटा-बढ़ा रहे हैं, इनका कोई मतलब हमारे दिमाग में नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं गिराएंगे। हम ने सरकार को गिरा कर देख लिया। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि इस पर आप ने जो वादा किया था, फिर से सलाह करें और सलाह कर के इसको वापस नहीं करेंगे तो हमारा और आप का तो इतिहास बंधा हुआ है। हमें पक्का यकीन है कि आने वाले समय में देश में और तबाही और बर्बादी आएगा। देश में गरीबी और गुरबत और नीचे जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, गत दिसंबर में, तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस सभा में घोषणा की की थी कि "विभिन्न भागीदारों के बीच सहमति बन जाने तक मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय को लंबित रखा गया है।" मैं शब्दावली में इसके वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयास कर रहा था कि सहमति का उत्तर था "आम भावना अथवा सहमति"। विस्तार से यह "सहमति पर आधारित" भी थी। यह लैटिन शब्द "कॉन्सैंटायर" से व्युत्पन्न हुआ है। कोई यह कह सकता है कि इसमें पूर्ण सहमति नहीं परंतु, जहां तक मैं इस भाषा को समझता हूं, इसमें उल्लेख है कि भागीदारों के बीच सहमति होनी चाहिए।

"भागीदार" शब्द को आगे संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और साथ ही राजनैतिक दलों के नेताओं के रूप में स्पष्ट किया

गया है। भारत बंद और इसके बाद नियम 184 के अंतर्गत जब इस सभा में इस संकल्प पर चर्चा चल रही थी उस दौरान मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफ.डी.आई. उपलब्ध कराने के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पायी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों और मुख्य मंत्रियों जैसे भागीदारों को साथ लिए बिना, इस निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है।

माननीय वाणिज्य मंत्री ने मुख्य मंत्रियों और कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं से संपर्क किया। हमारे मुख्यमंत्री की श्री नवीन पटनायक ने आरंभ में इस नीति को अनुमोदित नहीं किया और बाद में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ''हम मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करते हैं'' हमारे दल, बीजू जनता दल का मत बहुत स्पष्ट है। हम छोटे खुदरा व्यापारियों, छोटे किसानों, लघु-स्तर के विनिर्माताओं की मृत्यु के वारंट को वैद्य नहीं ठहरा सकते विशेषकर तब जब उनका कोई दोष नहीं हों।

भारत के सुरक्षित खुदरा क्षेत्र को किसी भी प्रकार की विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोले का विचार वास्तव में सबसे पहले डी.एम. के., के श्री मुरासोली मारन द्वारा लाया गया था जब वे एन.डी. ए. सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। इस विचार को कुछ पक्षों से बहुत उत्साहजनक समर्थन मिला, परंतु समान रूप से सभी ने, पूरे देश में दलीय रेखा के पार, इसका समर्थन नहीं किया। श्री दत्तों पंत थेंगडी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ ने मुखर रूप से इसका विरोध किया; स्वदेशी समूह ने भी इसका विरोध किया। 2004 के हमारे घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख नहीं था तब हमने इसका विरोध किया था, गत दिसंबर में हमने इसका विरोध किया था और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक ने आज इसका स्पष्ट रूप से विरोध किया है और बीजू जनता दल भी इस सभा में इसका विरोध कर रही है।

अपराह्न 1.00 बजे

इससे हमारे कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को मदद नहीं मिलती है; इसके विपरीत हमें आशंका है कि इससे सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोलने की वकालत करने वाले मुख्य तर्कों में से एक अथवा, दूसरे शब्दों में, 22 लाख करोड़ रूपए से अधिक मूल्य के व्यापक खुदरा क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलने का अर्थ यह है कि इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अवसंरचना का समग्र विकास होगा विशेषकार भाण्डागारों और शीतागारों का। सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि देश में भंडारण सुविधा की कमी के कारण बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाता है। कल, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री सिब्बल ने भी इस संबंध में कुछ आंकड़े दिए थे गत वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के बजट में भी इसका उल्लेख किया गया था, परंतु ये सूचना पूर्ण रूप से सही नहीं थी शीतागारों में निवेश की कमी के कारण 50 प्रतिशत से अधिक सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं; और इस समस्या का एक समाधान खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है और ऐसा कहा जा रहा है।

यदि हम वास्तविकता को देखें तो ये नोट करना रूचिकर होगा कि एक दशक पूर्व भाण्डागारों और शीतागारों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। तथापि, इस क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित नहीं किया जा सका। महोदया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को वैद्य ठहराने के लिए, ये सरकार कृषि उत्पाद हेतु भंडारण सुविधा की कमी का सहारा ले रही है, क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि या तो वह स्वयं भंडारण क्षमता का सृजन करे अथवा राजसहायता, वित्तीय रियायत अथवा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ-साथ अवसंरचना का सृजन हुआ है। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप में, सरकारी समर्थन से यह कार्य किया गया है झूठे स्वप्न न बेचें।

यदि किसी का विचार है कि बहुराष्ट्रीय खुदरा क्षेत्र कंपनियों के प्रवेश से खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम होगी तो ये उनकी बड़ी गलती है। खाद्य बर्बादी से संबंधित वैश्विक आंकड़े दर्शाते हैं कि अमरीका, यूरोपीय देश और अन्य विकसित देश, भारत और अन्य एशियाई देशों की तुलना में अधिक खाद्य बर्बाद करते हैं। अतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, यूरोप में खाद्य क्षति और बर्बादी 280 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है और उत्तरी अमरीका में यह 295 किलोग्राम है जबकि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में यह केवल 125 किलोग्राम है। यह महज संयोग ही नहीं है कि जिन देशों में खाद्य बर्बादी अधिकतम है, वे देश हैं जहां बहुराष्ट्रीय सुसंगठित खुदरा विक्रेतोओं का प्रमुख है। इसी दुविधा का उत्तर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, एफ.ए.ओ. ने उपलब्ध कराया है:

[श्री भर्तृहरि महताब]

"खाद्य बर्बादी का एक मुख्य कारण है कि सुसंगठित खुदरा व्यापारी (सुपर मार्केट्स) अधिक गुणवत्ता के प्रति अधिक संचेत दिखने के लिए के कारण फसलों के भार आकार, आकृति और रूप रंग से संबंधित कठोर गुणवत्ता मानकों खेत पर ही कृषि उत्पाद का एक बड़ा भाग अस्वीकार कर देते हैं अत: फसलों का बड़ा भाग खेत से जाता ही नहीं, हालांकि कुछ अस्वीकृत फसलें जानवरों को खिलाने के काम आती है...

खुदरा व्यापार का निगमीकरण उन राज्यों से आया प्रतीत होता है जो या तो जी.डी.पी. में अपेक्षाकृत बेहतर स्थान पर हैं जैसे हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर कुशल कोल्ड चेन से थोड़ा लाभ जा रहे हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश - मुझे समझ में नहीं आता कि मणिपुर ने भी इसका विकल्प क्यों चुना।

काफी समस्याएं हैं। आप इसे वैकल्पिक कैसे बना सकते हैं? यदि कोई कहे कि, "उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ओडिशा के वास्ते पंजाब और महाराष्ट्र को विश्व बाजार के साथ और अधिक एकीकृत बनने के अवसर से क्यों वंचित किया जाये या यह बेतुका नहीं है कि दिल्ली में सुपरमार्केट्स की श्रृंखला खोलने की लिए टेस्को को अनुमति देने के निर्णय को तमिलनाडु अथवा उत्तर प्रदेश अमान्य कर देंगे।" किन्तु इसी प्रकार इस देश ने अपनी राजनीति की है और शक्तियों का पृथक्करण किया है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसी स्थिति मत बनाइए जिससे सामाजिक अशान्ति पैदा होने की संभावना हो।

वह आधारभूत प्रश्न जो कई लोगों को डराए हुए यह है कि-क्या संगठित खुदरा क्षेत्र भारत के कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाएगा? यह किस प्रकार निर्माण और सेवा क्षेत्र को प्रभावित करेगा? स्थानीय खुदरा दुकानों के लिए इसका क्या अर्थ होगा? क्या वे संगठित क्षेत्रों के उन व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे जिनके पास सस्ते वित्त और तकनीकी ज्ञान तक पहुंच है?

अध्यक्ष महोदया : श्री भर्तृहरि महताब अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं अभी समाप्त करता हूं, महोदया। भारत 200 लाख टन से अधिक के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल और सब्जी उत्पादक देश है। किन्तु सम्पूर्ण शीतागार क्षमता 50 लाख टन भी नहीं है और किसानों को फसल के समय ही बेचनी पड़ती है। यद्यपि शीतागार में सौ प्रतिशत एफ. डी.आई. है, किन्तु इस पर अधिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। मैं समझता हूं कि खुदरा में एफ.डी.आई. खाद्य श्रृंखला में मौजूदा आपूर्ति रूकावटों का समाधान नहीं करेगा।

संगठित खुदरा घरेलू विनिर्माताओं के लिए एक अवसर हो सकता है यदि वे सही गुणवत्ता सही दामों पर आपूर्ति कर सकें। चीन ने यही किया और अपने विनिर्माण क्षेत्र को विकसित किया। भारत का विनिर्माण क्षेत्र में उच्च पूंजी लागत, दमघोंटू विनियमों, घटिया अवसंरचना और कम मांग की अड़चने हैं। जब तक इन सरोकारों का समाधान नहीं किया जाता तब तक मल्टी-ब्राण्ड खुदरा की विदेशी निवेशकों के लिए खोलने से या बांग्लादेश जैसे कम लागत वाले देशों से आयातित माल की बाढ़ आ जाएगी जो बुनाई और वस्त्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को नुकसान पहुंचायेगा।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका और मैक्सिको का अनुभव नहीं भूलना चाहिए जहां खुदारा में एफ.डी.आई. उत्साहवर्धक नहीं है। एफ.डी.आई. रोज़गार को प्रोत्साहन देने के बड़े वायदों के साथ आता है। वालॅ-मार्ट जैसे बहुत बड़े व्यापारिक कम्पनियों के प्रवेश से 2001 और 2007 के बीच 40,000 अमरीकी कारखाने बंद हो गये। जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों का रोजगार समाप्त हो गया। इन वर्षों में चीन से अमरीका में आयात 9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 27 बिलियन अमरीकी डॉलर होकर तीन गुना बढ़ गयी। महोदया, अमरीका की जनगणना के अनुसार, 1992 और 2007 के बीच स्वतंत्र खुदरा व्यापारियों की संख्या 60,000 से अधिक तक कम हो गई।

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, मैं अभी समाप्त करना हूं, कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए।

यह 30 प्रतिशत खरीद से संबंधित है, जिसका उल्लेख किया जा रहा था। सरकार कह रही है कि 30 प्रतिशत भारत से लिया जाएगा। यह राजनीतिक चाल से अधिक कुछ भी नहीं इसका आगम उन लोगों की भावनाओं को दिलासा देना है जो खुदारा में एफ.

डी.आई. का विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकारों के संबंध में, उन्हें यह निर्णय लेने की अनुमति दी गई है कि वे किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अपने यहाँ दुकान खोलने दें या नहीं। वह 30 प्रतिशत उस राज्य के भीतर से या इस देश के भीतर से कहां से आयेगा। उदाहरण के लिए, ओडिशा इसे खोलने पर सहमत नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : मुझे समय का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास वास्तव में कम समय है।

श्री भर्तृहरि महताब : अन्तिम बात बता रहा हूं। ओडिशा मल्टी ब्राण्ड खुदरा में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं दे रहा है। तमिलनाडु भी मल्टी-ब्राण्ड खुदरा में एफ.डी.आई. के लिए मना कर रहा है। पश्चिम बंगाल भी मल्टी ब्राण्ड खुदरा में एफ.डी.आई. के लिए राजी नहीं है। मैं ओडिशा और अन्य बाज़ारों की बात कर रहा हूं जहां से हम विभिन्न खुदरा उत्पाद लाते हैं। आन्ध्र प्रदेश इसे स्वीकार करने जा रहा है। क्या यह मल्टी ब्राण्ड कम्पनी केवल आन्ध्र प्रदेश से उत्पाद लेगी? या ये पूरे देश से उत्पाद लेंगे? इसका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, केवल विशाखापत्तनम में मल्टी ब्रांड खुदरा क्यों है? जब ओडिशा में कुछ सस्ता होगा, जब तमिलनाडु में कुछ सस्ता होगा, वह कम्पनी उसी क्षेत्र से खरीदेगी और कहेगी, हाँ, हमने आपके नियम के अनुसार तीस प्रतिशत खरीदा है। आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं किन्तु समस्या यह है जो मैं देख रहा हूं, वह यही होने जा रही है। इसकी जांच कौन करेगा? किस प्रकार का तंत्र विकसित किया जाएगा? इसकी जांच होने की संभावना भी नहीं है और असली मुद्दा यह है कि इस प्रकार खंड लागू नहीं किया जा सकता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।

महोदया अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मुझे एक टिप्पणी करनी है। मल्टी-ब्राण्ड खुदरा को लाने का विचार बिचौलियों से छुटकारा पाना है। कृपया यह मत भूलिए कि यह बिचौलियों की संख्या का सवाल नहीं है क्योंकि अन्ततः उत्पादक और उपभोक्ता और यह खुदरा व्यापारी ही बिचौलिये हैं। कृपया यह मत भूलिए कि विचौलियों की संख्या प्रश्न नही है अपितु महत्व बिचौलियों के आकार का है। जितना बड़ा इनका आकार होगा उतना अधिक और व्यापक इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ेगा। हमारी पार्टी मल्टी-ब्राण्ड खुदरा में एफ.डी.आई. का विरोध करती है और पेश किए जा रहे संकल्प का समर्थन करती है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : धन्यवाद अध्यक्षा जी, खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश करने का जो सरकार का प्रस्ताव है, शिव सेना उसका विरोध करती है।

01.13 बजे

[श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए]*

सभापति जी, मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार को और सारे देश को यह चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : देश को चेतावनी देना चाहते हैं या चेतना देना चाहते हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि देश को चेताना चाहता हूं। वह चेतना इस सदन से देश को और जनता को मिलेगी। आप मेरे शब्दों का कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है। कि इस सदन से लोगों को चेतना मिलेगी। जैसा शरद यादव जी ने कहा कि संग्राम होगा इसी सदन में। वह जो संदेश दे रहे थे देश को, वही संदेश मैं देना चाहता हूं। इसी सदन से देश को चेतना मिलेगी। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कहीं फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे न्यौता दिया गया था, वैसा न्यौता तो नहीं देने जा रहे हैं? आप एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रण देने जा रहे हैं। इसलिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जो व्यापार आज हम एफडीआई के माध्यम से, 51 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी कंपनियों को देना चाह रहे हैं, आनंद शर्मा जी, वह व्यापार स्वदेशी व्यापारी कर रहे हैं। जो व्यापार आज स्वदेशी व्यापारी कर रहे हैं उसे आप विदेशी व्यापारियों को देना चाहते हैं। आप जैसे बुद्धिमान मंत्री हैं, जिनका मानना है कि यह देश के हित में है। जो स्वदेशी व्यापारी आज व्यापार कर रहे हैं इस देश में, उनके व्यापार को आप विदेशी कंपनियों को देना चाहते हैं और कहते हैं कि यह राष्ट्र के हित में है, मैं सरकार की इस बुद्धिमानी की दाद देता हूं। जो सरकार इस देश के स्वदेशी व्यापारियों के व्यापार को विदेशियों को देकर राष्ट्रहित मानती हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं।

इस खुदरा व्यापार में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग लगे

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

हुए हैं, इसलिए यह आंकड़ा बार-बार चर्चा में आ रहा है। एक व्यापारी के साथ अगर 5 लोग भी एक परिवार में जुड़े हुए हैं तो यह खुदरा व्यापार देश के 25 करोड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप खुदरा व्यापार के अंदर सीधे विदेशी निवेश को 51 प्रतिशत लाना चाहते हैं तो जो इसका परिणाम है, वह केवल खुदरा व्यापार पर नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा असर देश के छोटे-गरीब किसानों पर भी होने वाला है। जिस प्रकार से देश के लगभग 25 करोड़ लोग खुदरा व्यापार से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार लगभग 50 करोड़ लोग खेती से, किसानी से, बागवानी से जुड़े हुए हैं । आज भी देश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और खेती पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि आपकी नीति का असर देश की 75 करोड़ आबादी पर होने वाला है।

महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो स्वयं रोजगार के दो क्षेत्र हैं—एक खुदरा व्यापार है और दूसरा क्षेत्र खेती है। ये लोग सरकार पर निर्भर नहीं हैं, ये अपना रोजगार स्वयं ही ढूंढते हैं और अपना गुजारा स्वयं ही करते हैं। जब 51 प्रतिशत सीधा विदेशी निवेश इस खुदरा व्यापार में करेंगे तो उसका असर खुदरा व्यापार से जुड़े हुए 25 करोड़ लोगों पर होगा और 50 करोड़ लोग जो खेती, किसानी और बागवानी से जुड़े हैं उन पर इसका बुरा असर होने वाला है।

मुझे फिक्र इसलिए है कि मैं भारतीय हूं और जो भारतीय किसान हैं उनकी चिंता है। मुझे जो भारतीय खुदरा व्यापारी हैं, उनकी चिंता है, मुझे वॉलमार्ट की चिंता नहीं है। मुझे टिसको की चिंता नहीं है।...*(व्यवधान)* इसलिए जो निर्णय सरकार करने जा रही है, यह उचित नहीं है। आज मतदान में क्या होगा? वह शाम को पता चलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण) : क्या होगा, क्या वह आपको मालूम नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : मालूम है कि क्या होगा, वह हमें पता है।...*(व्यवधान)* क्या होगा, वह हम जानते हैं। कल यहां कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे। उन्होंनें कल इन सारी विदेशी कंपनियों की काफी वकालत की थी।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : देश के लिए वकालत की थी।

श्री अनंत गंगाराम गीते : नहीं, देश के लिए वकालत आपने नहीं की थी। आपने विदेशी कंपनियों की वकालत की थी। आप चांदनी चौक से यहां चुनकर आए हुए हैं और वहां तमाम व्यापारी हैं। मुझे लगता है कि आपने विजय गोयल को परास्त किया था। सभापति जी, अगली बार विजय गोयल जी को कुछ करने की जरुरत नहीं है। कल के कपिल सिब्बल के भाषण की सी.डी. व्यापारियों के घर पर भेज दें तो वे भी आपका सारा काम तमाम कर देंगी।. ..*(व्यवधान)* उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : सब मेरे साथ हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, यह केवल विवाद का मुद्दा नहीं है। सदन के अंदर आज किसका बहुमत है, उसका मुद्दा भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो सरकार का एक हिस्सा थी, एफडीआई के मामले पर सरकार से बाहर आ गई। उन्होंने सरकार को त्याग दिया। तृणमूल पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आज तैयार है। इसीलिए मेरा कहना है कि एक पार्टी जो सरकार का हिस्सा थी लेकिन उनकी नेता ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, यह कदम देश हित के विरोध में है, यह खुदरा व्यापारियों के विरोध में है और यह देश के किसानों और गरीबों के विरोध में है। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय किया है।

यहां कल मुलायम सिंह जी बोल रहे थे। मुलायम सिंह जी ने महात्मा गांधी जी की याद दिलाई कि महात्मा गांधी जी स्वदेशी के हक में थे और विदेशी के विरोध में थे। महात्मा गांधी जी के नाम पर भले ही आप सरकार चला लें लेकिन महात्मा गांधी जी की नीति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। कल मुलायम सिंह जी ने इनको याद दिलाई कि महात्मा गांधी जी हमेशा स्वदेशी के हित में थे और वह विदेशी के विरोध में थे लेकिन आज की यह सरकार स्वदेशी के हित में कुछ नहीं करना चहती है। यह सरकार केवल विदेशी के हितों की रक्षा करना चाहती है। यह उनका यहां पर स्वागत करना चाहती है। हमारे नेता शरद पवार जी यहां उपस्थित हैं। मैं शरदी पवार जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था तो सबसे पहले इस स्वदेशी के मामले में जो व्यक्ति शहीद हुआ था, वह मुंबई के अंदर बाबू गेनू शहीद हुआ था जो पुणे के अंबे गांव का एक नागरिक था। देश की आजादी

की लड़ाई में स्वदेशी के मामले पर पुणे के बाबू गेनू ने बलिदान दिया था। मुझे डर है कि कहीं बाबू गेनू का वह बलिदान व्यर्थ न हो जाए। आप उसे व्यर्थ करार कर रहे हैं। आज उनकी आत्मा आक्रोश करती होगी। आज उसकी आत्मा दुखी होगी, आक्रोश करती होगी कि क्या हमने इसीलिए बलिदान दिया कि विदेशी कंपनियां फिर आएं और इस देश पर फिर राज करें। सुषमा जी बोल रही थीं, उन्होंने सारी बातें सदन के सामने रखी कि इसका दुष्परिणाम किस प्रकार से हो रहा है। किस प्रकार का दुष्परिणाम खुदरा व्यापारियों पर हो रहा है। आप मुंबई शहर में जाइए, आप देखेंगे कि एक सीधी सी बात है कि गरीब किसान, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वह अपने खेत में उगने वाली सब्जी को सड़क पर बाजार में बेचता है। आप उसी सब्जी को वॉलमार्ट को बेचने का अधिकार दे रहे हैं। जो अधिकार गरीब किसान का है, गरीब आदमी का है, उसे आप विदेशी कंपनी को दे रहे हैं सड़क पर जो सब्जी बिक रही है, आप वॉलमार्ट को कह रहे हैं कि आप उसे बेचिए। आप सड़क पर सब्जी बेचने वाले किसानों का अधिकार खत्म करने जा रहे हैं। लाखों लोंग है, हर शहर में लाखों फेरी वाले जो सड़क पर सब्जी और फल बेचते हैं। मुंबई में 35 लाख उत्तर भारतीय हैं और इनमें से लगभग 20 लाख लोग सड़क पर सब्जी, फल और दूध बेचकर गुजारा करते हैं। आप 20 लाख सड़क पर सब्जी बेचने वालों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं और उनके मुंह का निवाला वॉलमार्ट को देने जा रहे हैं। हमारा विरोध इसलिए है कि कि गरीब से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनकर विदेशी कंपनियों को देने जा रहे हैं। हमारा इसलिए विरोध है और रहेगा। कपिल सिब्बल साहब, आप इंडिया गेट पर वॉलमार्ट का स्वागत करना चाहते हैं, टैस्को का स्वागत करना चाहते हैं, कार-4 का स्वागत करना चाहते हैं। मैं इस सदन से सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप भले इंडिया गेट पर स्वागत कीजिए लेकिन गेटवे आफ इंडिया पर हम इन कंपनियों को कदम नहीं रखने देंगे। किसी भी विदेशी कंपनी को मुंबई में कदम नहीं रखने देंगे। न केवल मुंबई में बल्कि देश की जनता पूरे देश में किसी भी शहर में इन विदेशी कंपनियों को कदम नहीं रखने देगी। हम किसी भी हालत में कदम नहीं रखने देंगे, हो जाने दीजिए एक बार। आनंद शर्मा जी हंस रहे हैं, कपिल सिब्बल जी हंस रहे हैं। आप चहाते हैं कि वॉलमार्ट यहां आए, पैसा कमाए और यहां का खुदरा व्यापारी और गरीब किसान गोली से मरे। आप यही करना चाहते हैं, इसलिए हमारा विरोध है। यह विरोध केवल हमारा ही नहीं है, देश के 70 प्रतिशत लोगों का विरोध है। इसलिए भारत बंद हुआ। भारत बंद क्यों हुआ? कौन लोग भारत बंद में शामिल हुए? 70 परसेंट देश की जनता का विरोध है। सरकार एफडीआई लाना चाहती है, हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। हम सदन में भी विरोध करेंगे, सड़क पर भी विरोध करेंगे।

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा-गोंदिया) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक अहम और महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। जब भी एफडीआई सवाल आता है, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण या लिब्रलाइजेशन का सवाल आता है तो हमेशा ही सदन में बहुत तीव्र चर्चा होती है। पक्ष विपक्ष में अलग-अलग पहलुओं पर बात होती है। जो नजारा आज भी हम सब यहां देख रहे है। मै सदन में 1991 से हूं, मैंने भी यहां पर कई चर्चाओं में हिस्सा लिया है और सुना भी है। 1990 के दशक से जब लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे देश में हम लोगों ने काफी परिवर्तन चाहा, जिसके परिणाम आज हमें नजर नहीं आ रहे हैं और उस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में चाहे सदन के इस हिस्से से हो या उस हिस्से से हो, यशवंत जी यहां बैठे हैं, वह भी इस देश के वित्त मंत्री रहे हैं, उदारीकरण की जो नीति एक बार हम लोगों ने अपनाई, उसे आगे बढ़ाने का काम ही सामने वाली सरकार ने किया और इस सरकार ने भी उसी नीति पर आपके बढ़े हुए कदमों को और आगे बढ़ाने काम किया। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यहां कोई नई चर्चा कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो आज हम एक मल्टी ब्रांड रिटेल की बात करते हैं। आज आप दिल्ली के या किसी अन्य शहर के माल में चले जाइए, देश-विदेश की हर वस्तु आज वहां ऑलरेडी उपलब्ध है। गीते जी, मल्टी ब्रांड रिटेल की बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है, मुंबई, जहां से आप आते हैं, मेरा मतलब यह है कि आप रत्नागिरि के हैं, लेकिन मुंबई...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है, यह वस्तुओं से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रफुल पटेल : इस देश का व्यापार हमारी खुद की वस्तुओं से भी चल रहा है और बाहर से आयात की हुई वस्तुओं से भी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रफुल पटेल]

चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोंदिया का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पर चाइना के फर्नीचर के कई शोरूम खुल गए हैं, गोंदिया और भंडारा में वे नाम अन्यथा अगर मैं न कहूं तो आपने नहीं सुने हैं। ऐसे छोटे-छोटे शहरों में भी आज बाहर से बनी हुई वस्तुएं आ रही हैं, बिक रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको मकान बनाने के लिए कारपेंटर की जरूरत पड़ती है। तो वे मिलते नहीं हैं, बेलदार भी आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए इस तरह की बात करना कि देश में विदेश का सामान आ गया, इसलिए हमारे यहां का बाजार ठप हो गया या आगे नहीं चलेगा, उचित नहीं है। मैंने आपको माल के उदाहरण दिए, माल का आप विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके ही नेता मुंबई में माल बना रहे हैं इसलिए आप माल का विरोध क्यों करोगे।...*(व्यवधान)* मुझे वह नहीं कहना है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि आज हम जिन देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, जिन मूर्तियों को हम घरों में रखते हें, वे भी चाइना से बनकर आ रही हैं। आज साइकिलें भी हमारे देश में विदेशों से आ रही हैं। क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से हम लोगों के द्वारा ट्रेड एक्सैप्ट करने के बाद ये सारा टू वे ट्रैफिक हो गया है। अभी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में जिन किसानों की बात हम यहां कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और हमाने नेता, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, इसलिए मैं और दोहरा कर कह सकता हूं कि आज वर्ष 2011-12 में हमारे देश से जो कृषि उपज का एक्सपोर्ट हुआ है, वह 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये का हुआ है। हमारे देश में जो पीएल 480 का गेहूं लाकर हम लोगों ने जनता को अनाज देने का काम किया, वही देश आज 1लाख 87 हजार करोड़ रूपये की कृषि उपज का एक्सपोर्ट कर रहा है तो इस बात को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। आज जो भावनात्मक बात करते हैं कि हम लोग इम्पोर्ट के बारे में जिस तेजी के साथ उत्तेजना के साथ बात करते हैं, आज अमेरीका में आउटसोर्सिंग को लेकर और हमारे यहां से जो सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है, उसका विरोध होता है, जिस सैक्टर में आज हमारे लाखों-करोड़ों नौजवान काम कर रहे हैं, उस एक्सपोर्ट और सोफ्टवेयर आउटसोर्सिंग का अमरीका में भरपूर विरोध होता है।, जिस तरह से आप एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल का भरपूर विरोध कर रहे हैं, वहां भी विरोध हो रहा है। लेकिन उसका मतलब क्या आप चाहेंगे कि यहां से सोफ्टवेयर का एक्सपोर्ट बंद हो जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव सेना को संबोधित नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी सभा को संबोधित कर रहा हूं। मैं सभापति को संबोधित कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी विशेष को संबोधित नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल एक विशेष मुद्दे पर कुछ उल्लेख किया था। मैं अन्य सभी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मुझे भी अधिकार है। मैं भी समझता हूं। मैं आपत्ति भी लेना चाहता हूं यहां पर कुछ लोगों ने आढ़त के धंधे को या रीटेल के खुदरा व्यापारियों को बिचौलिया कहा है। उस बात का आक्षेप हमें भी है। हम नहीं मातने हैं कि कोई छोटा व्यापारी या आढ़त का धंधा करने वाला आदमी बिचौलिया है। यह आढ़त हमारे देश की परंपरा रही है। यह हमारे देश की रीत है। आढ़त का धंधा करना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारी व्यापारी प्रणाली का एक हिस्सा है।...*(व्यवधान)* आप यहां पर व्यापारी की जो बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। में यह कहना चाहता हूं कि आज हम डब्ल्यू टी.ओ. के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं। आज जितना उमंग से हम चाहते हैं कि बाहर हमारी वस्तु एक्स्पोर्ट होनी चाहिए उतने ही उमंग से दूसरे देशों के लोग भी चाहते होंगे हमारे देश में एक्स्पोर्ट करें। लेकिन हम लोगों को एक बात नहीं भूलनी नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात कही है।

इस देश में आज अगर आधुनिक भारत का नौजवान एस्पिरेशनल चेंज चाहता है। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है, उसमें आज चाहे मॉडर्न रीटेल हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको कोई नहीं कर सकता है। आप विरोध कीजिए। पुणे में विरोध कीजिए, मुंबई में विरोध कीजिए और बैंगलोर में विरोध कीजिए कि हमारे यहां से

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कोई आपकी बात सुनेगा? बात यह है कि आज हम लोगों को सारी बदलती हुई परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की एक कंपनी कभी जो कभी इस देश के बाहर पैर नहीं रख सकती थी, आज चाहे वह टाटा हो, चाहे बिड़ला हो या कोई अन्य बड़ी कंपनी हो, आज वे वहां जा कर जैगुआर लैंडरोवर खरीदती है, वहां जा कर कोरस को खरीदती है,वहां पर आर्सेलर कंपनी खरीदती है। हमारी भारतीय कंपनियों द्वारा ऐसी इसलिए केवल वन साइडेड ट्रैफिक, एक ही बाजू से ही काम चलेगा, दूसरी ओर से गाड़ी की पटरी नहीं चलेगा, ऐसा बोलना सही नहीं है। यह हम लोगों की जिम्मेदारी से करना चाहिए।

मेरा यह कहना है कि इस तरह की भावनात्मक चर्चाएं तो इस हाउस में बहुत बार हो चुकी हैं।

मुझे याद है कि एक जमाने में हमारे देश से कोका-कोला को भगाया गया था। आज कोका-कोला हमारे देश में है। आपके, हमारे बच्चे और सभी कोका-कोला पीते हैं। इस देश के नागरिक कोका-कोला पीते हैं। कोका-कोला ने पार्ले का थम्स-अप ब्रांड खरीदा था। उन्होंने यह सोच कर थम्स-अप को खरीदा था कि अपनी कोका-कोला को चलाएंगे और थम्स-अप को बंद कर देंगे। लेकिन आज भी थम्स अप भारतीय भारतीय जनसाधारण में कोका कोला से अधिक लोकप्रिय है। यह मानना चाहिए।

इसलिए ऐसा कहना है कि बाहर से कुछ आएगा और इसीलिए अचानक हमारे देश से निवेश चला जाएगा, यह सही नहीं है। हमारे देश में बाहर की कुछ चीज आएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसी बातें बोलने में अच्छी लगती हैं। हमारे देश में मैकडोनल्ड आया, केंटकी फ्राइड चिकन आया। मुझे बताइए कि अगर उसमें एक चीज इंपोर्ट होती है? मैकडोनल्ड का आलू टिक्की बर्गर आता है। क्या उसकी ब्रेड बाहर से आती है? क्या उसका आलू बाहर से आता है? क्या उसकी राई बाहर से आती है?

मैं अभिमान के साथ कहना चाहता हूं कि शरद पवार साहब ने बाराती में एक विश्वस्तरीय डेयरी स्थापित की है। उसमें 51 प्रतिशत फॉरन इंवेस्टमेंट हैं। आप महाराष्ट्र के हैं, इसिलए कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कि केवल उस डेयरी में 12 लाख लीटर दूध रोज प्रोसेस होता है। 20 रुपये के हिसाब से किसान को उस दूध की कीमत मिलती है। केवल एक या दो ताल्लुका में उसका काम है। 2 करोड़ 40 लाख रुपये वहां के किसानों को रोज हाथ पर मिलते हैं। अगर साल भर का हिसाब करें तो 800 करोड़ रूपये से ज्यादा होता है। मेरा कहने का मुद्दा तो यह है कि उस डेयरी में बनी हुई हर वस्तु चाहे वह नेस्ले हो, डेनॉन हो, ट्रॉपिकाना के जूस हों, केंटकी फ्राइड चिकन हो, चाहे वह मैकडोनल्ड हो या पीजा हट हो, सारा सोर्सिंग केवल बारामती की उस डेयरी से करते हैं। क्या वह पैसा किसानों के हाथ में नही जा रहा है? क्या हमारे गांव में, जो आप चाहते हैं, जिस मंशा के साथ आप कह रहे हैं, क्या उसकी पूर्ति नहीं हो रही है? इसलिए मेरा कहना है, मैं मानता हूं कि छोटे व्यापारी का पूरा रक्षण होना चाहिए। मैं भी एक छोटे से एरिया के एक शहर से चुनाव लड़ता हूं, क्या मैं यह नहीं समझता हूं? सरकार ने कहा है कि दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में यह लागू होना चाहिए। यह इसका एक प्रयोग है, हो सकता है कि अगर कल यह प्रयोग ठीक से नहीं चले तो शरद पवार जी हों, हम हों, हमारी सोच को बदल सकते हैं। हमने कब कहा कि हमारी सोच नहीं बदलेगी। महाराष्ट्र में हमारी कोआलीशन की गवर्नमेंट है, कपिल जी, आपने कल भाषण में कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए हां भरी है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से भी कहना चाहूंगा कि वहां कोआर्डीनेशन कमेटी है, वहां बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसके गुण और दोष का हिसाब करने के बाद ही हमारी पार्टी की ओर से उसे वहां करना है या नहीं, करना उसके बारे में हम अपनी राय के बारे में सूचित करेंगे।...*(व्यवधान)* मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह से किसी भी चीज का विरोध करना, डंकल आया, डंकल आया, आपको याद है, डब्ल्यूटीओ गेट का जब करार हो रहा था, डंकल आया, मुझे आज भी याद है, क्योंकि गांव में हमें भी जाकर समझाना पड़ता था। किसान बोलता था कि तुम्हारी बिजाई अब चली जाएगी क्योंकि डंकल आ गया है, तुम्ही पूरी उपज ले जाएगा, क्योंकि डंकल आया है। किस कीमत पर दिया जाएगा, वह डंकल तय करेगा? ये सारी चीजें, इस तरह की भावनात्मक बातें हम लोगों ने भी इस देश में देखी हैं। जितनी भावना के साथ आप कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों के मन में एक डर या खौफ पैदा होगा, उतना ही

[श्री प्रफुल पटेल]

खौफ उस जमाने में डंकल के नाम से इस देश के हर किसान के मन में पैदा करने का काम हुआ था। आज आप देखिए, उसी डंकल की बात के बीस साल बाद, आज हमारे देश में अनाज का रिकार्ड प्रोडक्शन इस देश के किसानों ने करके दिया है। इस बात से भी हम इंकार नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। मैं डंकल की बात कर रहा हूं, जैसा कि यह नब्बे के दशक में प्रचारित किया जा रहा था। हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। आप भी उस जमाने में थे, पार्लियामेंट में थे और चुनाव लड़ते थे, मुझे याद है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : हम लोगों के विरोध के चलते डंकल प्रस्ताव नहीं निकल पाया, वह रुक गया।

श्री प्रफुल पटेल : मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि डंकल का बाजा बजाया, मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने यह नहीं कहा कि डंकल को पारित किया। मैंने यह कहा कि डंकल का प्रचार उस प्रकार से इस देश के हर किसान के मन में एक डर पैदा किया गया था। मैं आपको यह कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* यशवंत जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग मैक्डोनाल्ड की बात करते हैं, केएफसी की बात करते हैं, आपने देखा कि उसकी वजह से आज हमारे बीकानेर वाला और हल्दीराम की भी दुकानें कितनी अच्छी हो गई हैं। आप देखते हैं कि आज छोटे-छोटे गांवों में, छोटे-छोटे व्यापारियों की दुकानें पहले की तुलना में कितनी बदल गई हैं। मैं यह नहीं कहना चहाता हूं कि हमारे देश के किसानों का नुकसान होना चाहिए, छोटे व्यापारियों का नुकसान होना चाहिए, हम ऐसा क्यूं चाहेंगे? आखिर आप और हम जिम्मेदार लोग हैं, यह सदन जिम्मेदार के साथ कोई भी चर्चा करता है और इसीलिए हम भी चाहेंगे कि सब चीजों का नफा और नुकसान का पूरा जायजा किया जाए और उसके पश्चात ही हम लोग भी अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि केवल यह खौफ दिखाना कि बाहर से पैसा आएगा, बाहर से पैसा आएगा इसलिए चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि यह एक भारतीय व्यक्ति द्वारा खरीद ली गई है और अब यह एक भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में है। वह एक चेष्टा की बात है, लेकिन एक बात जरूर है और इस देश में आप लोगों को हमको यह भी कहने की दरकार नहीं है। हमारे देश के लोग आज विदेशों में जाकर अपना रोजगार कमाते हैं। मैं अभिमान के साथ कहना चाहूंगा और आप जानते हैं कि 70 बिलियनय डॉलर से ज्यादा, साढ़े तीन लाख करोड़ यहां पर वहां से हमारे इंडियन्स रीमिटेन्स हमारे देश को आज हर साल वापस करते हैं। यह संसार में सबसे अधिक है, चीन से अधिक। क्यों हम लोग हमारी काबिलियत पर इतनी शंका करते हैं? मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* सिर्फ एक मिनट, मुझे आपका समय चाहिए। आज हम किसानों की पैदावार की बात करते हैं। करुतुरि ग्लोबल नाम की बंगलौर की एक कंपनी है। यह न केवल भरत अपितु विश्व में कटे हुए गुलाबों का सबसे बड़ा निर्यातक है। अब यह हॉलैंड में नहीं है। हम लोगों को लगता था कि बाहर की कंपनियां आएंगी तो यही सब कुछ करेंगी। लेकिन आज हम लोगों को यह भी एकनॉलेज करना पड़ेगा कि आज हमारे देश की कंपनियां, हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का श्रमिक हर तरह से विश्व में मुकाबला करने की तैयारी के साथ अपने पैरों पर खड़ा है। जहां तक भावना का सवाल है, इमोशन का सवाल है, जरूर हम लोग यह बात कहते हैं, लेकिन यशवंत जी से मैं कहना चाहता हूं, कि इस बात को भी हमें एकनॉलेज करना पड़ेगा कि आज किसान की जो पैदावार होती है, इसमें कितना नुकसान होता है? सीफैड नाम की एक संस्था है जिसने खुद एकनॉलेज किया है, कि 50,000 करोड़ के आस-पास हर साल हमारे किसानों की पैदावार का नुकसान होता है। इसका मूल्यांकन अगर सही बाजार के हिसाब से करें तो शायद इससे ज्यादा भी होगा। इसका भी तो नुकसान कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। हर साल हम कहते हैं कि हमारे यहां अनाज पैदा होता है, अनाज सड़ता है, अनाज बराबर पहुंचता नहीं है, यह नहीं, वह नहीं। यह क्या केवल सरकार का ही काम है, अकेले सरकार के माध्यम से क्या यह हो सकता है? आप भी सरकार में थे, यहां भी सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की कुछ मर्यादा होती है। इसीलिए कहीं न कहीं प्राइवेट इनवैस्टमैंट आएगा लेकिन इससे हमें क्यों इतना डरते हैं? हो सकता है कि कल हमारे बिग बाजार, रिलायंस रीटेल, स्पैन्सर्स, क्रोमा या और कंपनियां भी कल बाहर से आने वाली कंपनियों को बराबर की टक्कर और जवाब देने के लिए तैयार हो सकती हैं, इनकी भी

क्षमता हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह ठीक है कि यह भावनात्मक सवाल है, सदन में सभी के अलग-अलग व्यूज हो सकते हैं, सबका अलग-अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत का कोई भी वर्ग हो, उसके प्रति हम लोगों को अपनी श्रद्धा और सद्भावना रखने की जरूरत है, तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : सभापति महोदय, खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के संबंध में चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीति गत निर्णय की घोषणा की है और बहु ब्राण्ड खुदरा में 51 प्रतिशत तक तथा एकल ब्राण्ड खुदरा में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. खोलने की अनुमति दी है। यह देश के लाखों परंपरागत खुदरा व्यापारियों के लिए एक भयंकर आघात के रूप में आया है।

महोदय, आप हमारी पार्टी का पक्ष भली भांति जानते हैं। हमारी पार्टी के नेता, तमिलनाडु की प्रमुख्यमंत्री माननीय अम्मा ने शुरू से ही इस नीति के प्रति अपनी आशंका व्यक्त की थी और इसकी पूर्णरूप से वापसी की मांग की है क्योंकि यह भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं पहुँचाने वाला है। यह केवल विदेशी कम्पनियों को लाभ पहुंचाएगा। अत: मेरी पार्टी ए.आई.ए. डी.एम. के. की ओर से मैं इस नीति का विरोध करता हूं। और हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए।

कल माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने सरकार और अपनी पार्टी की ओर से बोला था। उन्होंने खुदरा में एफ.डी.आई.की वकालत की थी। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि 2004 के अपने चुनावी घोषणापत्र में भाजपा ने खुदरा में 26 प्रतिशत एफ.डी.आई. का समर्थन किया था और उन्होंने चुनावों का सामना किया था। उस पार्टी का भाग्य देखिए। चूंकि उन्होंने चुनावी घोषणा-पत्र में इस नीति की, खुदरा में एफ.डी.आई. की वकालत की, वे 2004 में चुनाव हार गए। आपने अपने चुनावी घोषणापत्र में इसका उल्लेख भी नहीं किया है। 2009 के चुनावी घोषणापत्र में भी आपने इसका उल्लेख नहीं किया था। पर यह जानते हुए भी कि भारतीय खुदरा में एफ.डी.आई. को स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ दबाव के कारण अब आप अप्रत्यक्ष रूप से इस नीति को ला रहे हैं। यहां मैं यही कहना चाहता हूं।

2002 में जब कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो आपने खुदरा में एफ.डी.आई. का विरोध किया था। तो आप क्या सोचकर इस नीति को लाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या इससे किसानों और उपभोक्ताओं को कुछ मदद मिलेगी? इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। आप केवल अप्रत्यक्ष रूप से एक बार फिर विदेशियों को इस देश में आकर अपना नियंत्रण स्थापित करने दे रहे हैं। कांग्रेस और एन.सी.पी. के अलावा यहां उपस्थित अधिकतर पार्टियों ने इस नीति का समर्थन नहीं किया है। जब सरकार यह नीति लाई तो आपके सहयोगी दल टी.एम.सी. ने साथ छोड़ दिया और कांग्रेस नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार को अब अल्पमत सरकार बन दिया। अब यह बहुमत में नहीं है। बाहरी समर्थक हो सकते हैं। पर यह कांग्रेस सरकार अब एक अल्पमत सरकार है। एक अल्पमत की सरकार इस प्रकार की नीति कैसे ला सकती है जब लोग इसका विरोध कर रहे है? इसलिए उन्हें सोचना होगा और इसे वापस लेना होगा।

महोदय आप जानते हैं कि इस सदन के द्रमुक साथियों ने कल कहा था कि हालांकि वे विरोध कर रहे हैं, तथापि वे 'हाथ' का इलाज करना चाहते हैं चूंकि 'हाथ' को चोट लगी है। हाथ में चोट के कारण वे इसे ठीक करने के लिए उपचार देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री टी.के. एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : मैंने बताया कि हमने पता लगा लिा है कि समस्या कहां हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : हाथ को वह चोट क्यों लगी? यह 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के कारण है। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के कारण हाथ जल गया है। 2जी घोटाले के कारण कांग्रेस की छवि मैली हो गई हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डॉ. एम. तम्बिदुरई : भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री 2जी घोटाले के कारण जेल में थे। भारत के इतिहास में किसी केन्द्रीय मंत्री को

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

जेल नहीं भेजा गया। फैसला आ चुका है और वह जेल में हैं। महोदय वे कह रहे हैं कि 'हाथ' घायल है और वे इसका उपचार करना चाहते हैं। उन्हीं के कारण हाथ जला है। उसका उपचार नहीं किया जा सकता। उसे काटना ही पड़ेगा। अन्यथा, उस हाथ का उपचार नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डॉ. एम. तम्बिदुरई : उनके द्रमुक संसदीय दल के नेता ने भी कल कहा कि वे तमिलनाडु में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु श्रीलंका में है या भारत में। तमिलनाडु भारत में है। जब आप इस नीति को स्वीकार कर रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आप तमिलनाडु में इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तमिलनाडु भारत में है श्रीलंका में नहीं, इसलिए दोहरा खेल मत खेलिए। जब आपकी द्रमुक पार्टी ने खुदरा में एफ.डी.आई के विरूद्ध जनरल कौंसिल में संकल्प पारित किया है तो अब आप अपना पक्ष कैसे बदल सकते हैं? आपने अपनी द्रमुक पार्टी जनरल कौंसिल के संकल्प की कैसे उपेक्षा कर दी...*(व्यवधान)* देखते हैं आप कैसे वोट करते हैं। आप संकल्प का समर्थन करेंगे या नहीं? *...(व्यवधान)*

कल श्री मुलायम सिंह यादव ने भी ईस्ट इंडिया कम्पनी के संबंध में और भारत ने उनसे कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की, इस पर कुछ बिंदु उठाए हैं। यहां तक कि एन.सी.पी. सदस्य ने भी के.एफ.सी. वगैरह का समर्थन किया। हम उसके विरूद्ध हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम कैफे कॉफी डे तक भी नहीं चाहते। हम जानते हैं कि कौन देश में कैफे कॉफी डे चला रहा है। हम इसके पीछे के संबंधों को जानते हैं। मैं बता रहा हूं कि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के व्यापार करने और लाभ कमाने तथा हमारे देश के बाहम हमारा पैसा बारह ले जाने के खिलाफ हैं।

ईस्ट इंडिया कम्पनी हमारे देश में घुस आई। वे यहाँ केवल अपने उत्पाद बेचने आए और भारतीय उन उत्पादों को खरीदने के लिए लालायित थें। तत्पश्चात् उन्होंने धीरे-धीरे इस देश को हथिया लिया और हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। वे हमारे सारे खनिज और प्राकृतिक संसाधन इंग्लैंड व अन्य देशों में ले गए और माल तैयार किया एक बार फिर उन्हें वापस लाए और यहाँ बेचा।

इसी प्रकार उन्होंने बैंगलोर में लड़ाकू विमान बनाने के लिए एक कम्पनी एच.ए.एल. शुरू की जबकि उन्होंने कभी इस देश में साइकिल नहीं बनाने दी। हम साइकिलें आयात करते थे। उस समय हमारे देश में लड़ाकू विमानों की क्या आवश्यकता थी? ब्रिटिश रक्षा उद्देश्यों के लिए उन्होंने इस प्रकार के उद्योग स्थापित किए और ये केवल उनके अपने लाभ के लिए थे। तत्पश्चात् महात्मा गांधी ने इसके विरूद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हम 16 स्वदेशी चाहते हैं। काँग्रेस आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत लाने के लिए खुदरा में एफ.डी.आई. ला रही है। वे वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना चाहते हैं। श्री कपिल सिब्बल एक अच्छे वकील है। वे किसी भी पक्ष के समर्थक में तर्क कर सकते हैं। यह उनका काम है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। पर यहाँ वो एक कमजोर मामले की वकालत कर रहे है। ऐसा करते हुए आप स्वदेशी से विदेशी में अंतरण कर रहे हैं। आप विदेशी चीजों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां अधिक उद्योगों को स्वीकृति प्रदान की है, विशेषकर ऑटोमोबाईल उद्योग को तथा उन्होंने देश में अतिरिक्त कल-पुर्जों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। हम केवल अतिरिक्त कल-पुर्जे का निर्माण कर सकते हैं, न कि ऑटोमोबाईल गाड़ियों का। आज देश में क्या हो रहा है? अधिकतर लोग केवल विदेशी गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार में तीन या चार गाड़ियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उद्योग अथवा व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति देने की इस प्रकार की नीति हमें इन वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रलोभन देती है। भारतीय बचत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु अब वे अतिव्ययी हो चुके हैं तथा इन वस्तुओं को खरीदने के लिए ललाचित रहते हैं। प्रत्येक परिवार में तीन या चार टोयटा अथवा कॉक्सवैगन गाड़ियां हैं। यह प्रलोभन है। जब यह स्थिति है, तो आप अपने देश में विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं की अनुमति दे रहे हैं जिसे जनता खरीदेगी तथा उसकी बचत ऐसे ही व्यर्थ जाएगी तब तथा होगा?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 01.56 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

आपके दो बिंदुओं के आधार पर खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पक्ष लिया। एक, आप देश के भुगतानों के शेष बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए, आप विदेशी मुद्रा चाहते थे। इसलिए, आप यहाँ खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चाहते थे। विदेश मुद्रा लाने के लिए और भी कोई तरीके हैं, न कि यह कि केवल खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करके ही किया जा सकता है। बैंकों में हमारा बहुत पैसा है, और हम उस धन का उपयोग कर सकते हैं। निवेश के लिए तथा बाजार प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, अन्य कई तरीके हैं। देश खुदरा दुकानों को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न देशों से तकनीक हासिल करना उनमें से एक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि वॉलमार्ट को यहां आने के लिए तथा बाजार पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करें। यह हमारे लिए दयनीय स्थिति हो जाएगी ...*(व्यवधान)* मैंने अभी आरंभ ही किया है। कृपया मुझे और समय दिया जाए।

खुदरा में इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण, देश भर में सैंकड़ों, हजारों छोटे किराना दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे चालीस मिलियन लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। आरंभ में इससे कीमतों को कम हो जाएंगी। परंतु जब खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एक बार अपना पैर जमा लेंगी तो महंगाई तेजी से बढ़ेगी। आरंभ में, किसानों को पारिश्रमिक दिया जा सकता है। परंतु अंततः वे विशाल खुदरा कंपनिों की दया के पात्र बन कर रह जाएंगे। छोटे तथा मध्यम उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उनकी एकतरफा मूल्य निर्धारण नीति के शिकार बन जाएंगे। वैश्विक खुदरा कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ावा देने से सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला टूट जाएगी। यही कुछ बिंदु हैं।

कल हमने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें खुदरा व्यापारियों ने, विशेषकर तमिलनाडु से जिन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो संसद सदस्य खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में मत डालेंगे, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता संसद सदस्य के घरों का घेराव करेगी। उन्होंने यही चेतावनी दी है। इसलिए, मैं सभी संसद सदस्यों से आग्रह करता हूं कि खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरकार की नीति का विरोध करें तथा इस प्रस्ताव का समर्थन करें। यह लोगों के लिए मददगार साबित होगा। हमारे दल का यही निर्णय है।...*(व्यवधान)*

उन्होंने कहा कि चीन में, वालमार्ट असफल हो चुका है। परंतु अन्य देशों के बारे में क्या? चीन में पहले से ही सुस्थापित बाजार तंत्र है। सरकारी उपक्रमों द्वारा वे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं। वे देश में विभिन्न स्थानों पर अपने उत्पाद का विपणन कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, श्री प्रफुल पटेल ने कहा कि हम पहले से ही चीनी उत्पाद खरीद रहे है और उपयोग कर रहे हैं। यह एक सच्चाई है। भारत में इस प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी के बिना भी खुदरा बाजार में चीन के उत्पादों ने घुसपैठ कर रखी है। यदि आप किसी रेस्तरां अथवा किसी अन्य स्थान पर जाएंगे तो आप केवल चीन के फर्नीचर ही देखेंगे। हमारे अपने उत्पादों का क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)* यदि हम अपने बाजारों में इतनी अधिक विदेशी वस्तुओं को आने देंगे तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। आप निधि नहीं जुटा पाएंगे।

मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विदेशी पूंजी से कभी कोई अर्थव्यवस्था विकसित हुई हो। विभिन्न देशों की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण कारक संसाधन (जुटाने में स्वदेशीय) संचालन का योगदान रहा है।

अपराह्न 02.00 बजे

दूसरा, घरेलू तकनीक विकास अनुप्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा, रणनीति प्रबंधन तथा सरकार से समर्थन अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना, हम अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह इस नीति को वापिस लें। उसके बारे में भी सरकार ने यह निर्णय तब लिया है जब सभा सत्र में नहीं था। पिछली बार, जब सभा का सत्र चल रहा था, वे इसे अनेक घोटालों के कारण, विशेषकर कोयला घोटाले के कारण नहीं चला पाए। पूरा देश कोयला घोटाले पर चर्चा कर रहा है। परंतु अचानक, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, वे यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति ले आए। इसके लिए यू.पी.ए. सरकार अच्छा सबके सीखने वाली है। हालांकि वे यहां सफलता प्राप्त कर लें परंतु जनता शक्तिशाली है और वह इस सरकार को सबक सिखाएगी। वह हमारी किस्मत का फैसला करेगी। इसलिए, वर्ष 2014 बहुत दूर नहीं है, वह आने ही वाला है। अतः कांग्रेस तथा इसके गठबंधन यह महसूस

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

करेंगे कि खुदरा नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाकर उन्होंने गलती की है। इसलिए, एक बार फिर मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को वापस ले। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री तथा हमारी ए.आई.एडी.एम. के दल इसका विरोध कर रहा है। हम तमिलनाडु में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया।

महोदय, कड़े विरोध के बावजूद यू.पी.ए. सरकार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने में जनता विरोधी निर्णय लेने का प्रयास कर रही है जबकि इसका

[हिन्दी]

पूरे देश भर में एफडीआई रिटेल सैक्टर को अपोज करने के बाद भी यह गवर्नमेंट एफडीआई को लाना चाहती है। कल कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, ये अभी यहां बैठे नहीं हैं, हम सोच रहे थे कि इस समय वे यहां होते तो अच्छा होता। अगर वे टी. वी. में हमारी बात सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो इधर से तो हमारी कुछ बात जाएगी। कपिल सिब्बल साहब तो बहुत अच्छे सीनियर लॉयर हैं।...*(व्यवधान)* ये लॉयर्स कोर्ट में जिस तरह से बात करते हैं, अपनी फीस लेकर ये सीधे को उल्टा कर देते हैं और उल्टे को सीधा कर देते हैं। कल इनकी बात भी उसी तरह से थी। यह बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे कि वे बात कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में लॉयर जैसे बात की। वॉलमार्ट का लॉयर है, यह भी तो सही बात है। उन्होंने कल बात करते समय बहुत कुछ कहा, एक तो आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक्सेप्ट किया, उसी तरह से और 11 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम इस गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में सिर्फ 36 परसेंट वोट कांग्रेस को मिले हैं। आज के दिन आप गवर्नमेंट में रह सकते हैं, मगर 64 परसेंट लोगों ने आपके अगेन्स्ट में वोट डाला है। ऑल पार्टियों के कंसलटेशन के बाद एफडीआई के बारे में बात करेंगे, लास्ट टाइम इस हाउस में इन्होंने यह बात बोली है। आंध्र प्रदेश के जो 64 परसेंट लोग इनके अगेन्स्ट हैं, उन लोगों के बारे में ये क्या कर रहे हैं? पूरे देश भर में भी वे लोग इस तरह से कर रहे हैं। कल कपिल सिब्बल साहब ने एक और बात भी बोली है, किसान और बिचौलियों के साथ हैं। कपिल सिब्बल साहब, हम लोग तो किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और आगे भी सिकान के साथ रहेंगे। आप किसान के साथ नहीं हैं, आप इंडियंस के साथ नहीं हैं, आप फॉरेन कंपनियों के साथ हैं।...*(व्यवधान)* ये लोग फॉरेन कंपनियों के साथ हैं। कल ये कार के मेनुफेक्चरिंग के बारे में बात कर रहे थे। *[अनुवाद]* कार का निर्माण पूरी तरह अलग कार्य है। *[हिन्दी]* उसके तो मेनुफेक्चरिंग यूनिट्स यहां लगते हैं, इन्वेंस्टमेंट इधर आता है। एम्प्लॉयमेंट इधर जेनरेट होता है, अगर सरप्लस हो तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये ट्रेडर का बिजनैस है, ये लोग ट्रेडिंग करेंगे। एफडीआई वाला जो भी वॉलमार्ट आएगा, ये वॉलमार्ट न तो मेनुफेक्चरर है, न कंज्यूमर है।

ये बीच में ट्रेडर हैं, ये लोग बीच के ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी गई तो हम लोगों ने उस समय सोचा था कि बहुत ठीक हो गया, मगर आज ये लोग उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह एकदम ठीक नहीं है।

कल मुलायम सिंह साहब ने बहुत क्लियरली बोला है, उन्होंने महात्मा गांधी को कोट करके बोला कि उस समय भी गांधी जी थे और अभी भी गांधी है, मगर दोनों में बहुत फर्क है। यह बात भी देश के लोगों को जानने की जरूरत है। उस समय में महात्मा गांधी ने देश को बचाने के लिए वह काम किया था, लेकिन अभी भी इस गवर्नमेंट में उसको यह उल्टा कर रही है। यह फॉरेन कम्पनीज को लाने की कोशिश कर रही है। यह सब देश के लोगों को जानने की बहुत जरूरत है।

सुषमा जी ने बात करने के समय में शुगर मिल्स की बात बहुत सीधा बोली है। शुगर मिल में फार्मर्स और फैक्टरी वालों के बीच में कोई ट्रेडर नहीं है। उसी तरह से खेती-किसानों में जो एम. एस.पी. दिया है, वह एम.एस.पी. भी आज के दिन किसान को नहीं मिलता है। ये लोग कहते हैं कि फॉरेन का वाल मार्ट आकर किसानों को बचाएगा, मगर आप लोग किसानों को नहीं बचा रहे हैं। इसलिए

उन लोगों को लाकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कितने गलत तरीके से देश की बात बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पास टाइम कम है, मगर मैं बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूं, फिर भी आपने जो टाइम दिया है, मैं उसी में बात करूंगा। अभी ये लोग एम्पलायमेंट के बारे में बोलते हैं कि वाल मार्ट अगर आएगा तो एम्पलायमेंट आएगा, यह कितनी गलत बात देश के यूथ को ये लोग बोल रहे हैं, देश के लोगों को जिस तरह से बोल रहे हैं। एक वालमार्ट में 214 लोग काम करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री नामा नागेश्वर राव : एक वालमार्ट में जो टर्नओवर है, जो चीज उसमें बिकती है, वह 1500 किराना दुकानों के बराबर है। 1500 किराना दुकानों के इक्वल एक वालमार्ट में एप्रोक्सीमेटली टर्नओवर है। अगर 1500 किराना दुकानों में चार से गुणा करें तो कम से कम 6000 आदमी वहां काम करते हैं, जबकि यहां 214 लोग एक वालमार्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि इससे एम्पलायमेंट बढ़ेगा। इससे आप एम्पलायमेंट दे रहे हैं या अनएम्पलायमेंट कर रहे हैं? इतने गलत तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। उसमें मेनली क्या है कि वह सिस्टम ड्रिवन है। अभी क्या है कि वे लोग बिलिंग से लेकर सब कुछ में ऑटोमेशन करते हैं, लेकिन अपने देश की किराने की दुकानों में वह ऑटोमेशन नहीं है। वे सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, इसलिए अगर वाल मार्ट आया तो वे एम्पलायमेंट को कम कर देंगे। इसी तरह से यह एक ही बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी है। 1979 में अमेरिका में रिटेल सैक्टर में दो करोड़ एम्पलायमेंट थे, जबकि 2009 में 32 साल के बाद आज के दिन 1.26 करोड़ एम्पलायमेंट हैं। अमेरिका में यह हुआ कि अनएम्पालायमेंट हो गया और 80 हजार लोगों का वाल मार्ट वगैरह के आने के बाद अनएम्पलायमेंट हो गया। यह बात जानने की जरूरत है।

उसी तरह से फार्मर्स के बारे में बात आई है, जो बहुत गलत तरीके से की गई है। आज के दिन में इंडियन फार्मर्स की एवरेज फार्मिंग पांच एकड़ है। हमारे यहां वह किसान की पांच एकड़ है, लेकिन कहीं-कहीं तो एक किसान 2-3 एकड़ में काम करता है, मगर फॉरेन कंपनी में अगर कनाडा में देखें तो एक किसान 1798 एकड़ है, यू.एस.ए. में 1000 एकड़ है, आस्ट्रेलिया में 17 हजार एकड़ है, यू.के. में 432 एकड़ है। वहां का किसान पूरी मकेनाइज्ड खेती करता है। उस किसान के साथ हमारे देश का किसान कैसे कम्पीट करेगा? ये किसान को बचाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये लोग किसान को मारने के लिए काम कर रहे हैं। यह बहुत गलत तरीका है। किसान की जो लूट की जा रही है, यह गलत हैं

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : इसी तरह से एक बात और है, माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्रिन्योर्स के बारे में ये लोग बोल रहे हैं। उसमें बहुत क्लियरली बोला है कि 30 परसेंट एमएसएमई को लेंगे। ...*(व्यवधान)* 30 परसेंट एमएसएमई को लेकर 70 परसेंट बाहर से आएंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : उपाध्यक्ष जी, केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के दिन में इस सेक्टर में एमएसएमई में अगर देखें तो...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : एमएसएमई की अगर बात करें तो उसमें करीब-करीब तीन करोड़ की यूनिट्स हैं, सात करोड़ इंप्लाई हैं। उसमें अगर 70 परसेंट बाहर से डंप करेगा तो इंडिया को यार्ड जॉब करेगा। इसलिए आज के दिन में हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि ये एफडीआई को लाकर दस कंपनियों के लिए वोट करेंगे। हमने बीस करोड़ लोगों के लिए सोचा है, हम उनको वोट करेंगे।...*(व्यवधान)* अगर आप लोग दस कंपनी को वोट करेंगे तो बीस करोड़ लोग आपको बाहर में वोट नहीं देगा।...*(व्यवधान)* दूसरे को जिताकर आपको छोड़ देंगे। मैं इस बात को कहकर समाप्त करता हूं।

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और स्वाभाविक है कि जहां देश का बहुत बड़ा तबका यह महसूस कर रहा है कि इस फैसले का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, तो उनकी निगाहें हम पर टिकी हैं। मेरा यह मानना है कि इस फैसले से कोई क्रांति एकदम से नहीं आने वाली है। जो इस फैसले के सकारात्मक पहलू हैं, जो प्रभाव होने

[श्री जयंत चौधरी]

वाले हैं, निवेश होगा, कृषि पर इसका अच्छा प्रभाव होगा। रोजगार जो उत्पन्न होना है, हमारे आर्थिक वातावरण में सुधार की बात रखी गई है, इस सबके होने में देर है। वहीं मैं यह भी कह देना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का दूसरा पहलू यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि भूचाल आएगा और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि करोड़ों समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, करोड़ों घरों में रोशनी बंद हो जाएगी, यह कहना भी मैं गलत ठहराता हूं। एक अनावश्यक भ्रांति फैलाई जा रही है और अक्सर राजनीति में ऐसा होता है। मैंने सुना था, एक बार हरियाणा में चुनाव था, जब भांखड़ा नांगल डैम बनाया जा रहा था, तो बात रखी गई थी कि जो पानी आ रहा है, उससे बिजली निकालकर आपको पानी दिया जाएगा। यह राजनीति में होता है।

इसी सदन में कल चर्चा हुई थी और अमेरिका का सवाल उठा कि वहां बहुत विरोध हो रहा है। आप देखिए कि अमेरिका में भी हमारे देश की तरह लोकतंत्र हैं। वहां अगर आप चाहें तो कार्टून भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो राष्ट्रपति के आवास के बाहर बैठकर धरना भी दे सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि जो लोग वहां धरने पर बैठे हें, वे मुख्य धारा की आवाज हैं। अगर वहां आक्यूपाई मूवमेंट कुछ शहरों में चल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता है कि पूरा अमेरिका कैपिटलिज्म के खिलाफ हो गया। वहां की मार्केट में 85 परसेंट शेयर आर्गेनाइज्ड रिटेल का है। यू.के. में संगठित व्यापार का हिस्सा अस्सी प्रतिशत है। जो ई.यू. का डिक्लेरेशन आया था, उन्होंने कहा कि जो बाइंग पॉवर है, वह हमें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। हमें पॉलिसीज बनानी होंगी। मैं भी सदन में खड़े होकर कहता हूं कि सरकारों को इसमें दखल रखना ही होगा, संरक्षण देना होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस डिक्लेरेशन का आप यह तर्क दे दें कि एफडीआई को उस आधार पर रोका जाए। उन्हों ने सुपर मार्केट बंद करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने यह कहा कि अन्य वर्गों पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, उस पर हम कैसे नियम और कानून बनाएं ताकि उसका दुष्प्रभाव न पड़ सके।

स्वदेशी मंत्र का जिक्र इस सदन में हुआ। मैं भी गांधीवादी विचार का हूं और मुझ जैसे नौजवान आज भी उस दौर को याद करते हैं, समझते हैं कि वह जो एक दौर था, जिस दौर ने इस देश को स्वतंत्र किया, आजाद किया, किस उद्देश्य से गांधी जी ने वह नारा दिया था, ताकि हमारे देशवासियों में स्वाभिमान की भावना जग सके, आत्मनिर्भरता पैदा हो, देश स्वतंत्र हो। उपाध्यक्ष जी, क्या आज भी वही परिस्थितियां हैं? आज दुनिया का हिस्सा हम बन चुके हैं और मुझे विश्वास है कि जो शब्द का चयन हो रहा है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, मुझे विश्वास है कि देश का नौजवान, देश का व्यापारी, देश का किसान, देश का उद्योगपति इस देश के नवीन विचार राष्ट्र ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अपना स्थान हासिल करने के काबिल हैं और क्षमता रखते हैं। अब वह सवाल नहीं रह गया। अगर हम बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी तो यह पार्लियामेंट की अवहेलना हो रही है। हम किस दौर की बात कर रहे हैं। यह देश, यह समाज बहुत आगे बढ़ चुका है।

अध्यक्ष जी मैं इस संदर्भ में दो पहलू और बताना चाहता हूं कि पूरी चर्चा में उपाय क्या है, यह सामने नहीं आया। सब जानते हैं कि आज किसानों की कितनी भागीदारी है? जो आलू यहां 25-30 रुपये किलोग्राम बिक रहा है तो किसान को कितना मिल रहा है? क्या हम किसानों को वाजिब दाम दिला पाए हैं? लेकिन उपाय क्या है? क्या कॉपरेटिव से निवेश करेंगे? क्या किसान में वह क्षमता है? क्या हम निजी निवेशक को घुसने देंगे या घुसने नहीं देंगे? क्या ये सारी व्यवस्था कोल-चेन और फूड प्रोसेसिंग उद्योग की है? क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की बनती है?

दूसरा पहलू यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या वे विदेशी निवेश के खिलाफ हैं या संगठित व्यापार के खिलाफ हैं। अगर विदेशी निवेश के खिलाफ हैं तो क्या बिरला, रिलायंस और टाटा ये किसानों को बेहतर दाम देंगे? अगर आप प्रतिस्पर्धा के पक्ष में हैं तो क्यों नहीं इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो? मैं समझता हूं कि पैसे के रंग को न देखा जाए। महत्वपूर्ण यह है कि निवेश होना चाहिए। मंडी व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रदेश सरकारों को भी एपीएमसी ऐक्ट को देखना हो तो तर्क देते हैं एफडीआई फूड प्रोसेसिंग में खुली हुई है, निवेश क्यों नहीं हुआ? यह कैसे हो जाएगा? आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे घरेलू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या भाग है–1.5 परसेंट यह 2 परसेंट से भी कम है। हमारे यहां फसल 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत खराब हो जाती है।...*(व्यवधान)* सवाल यह है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री

अर्बन सेंटर्स में पैकेट फूड लेंगे और माइक्रोवेव में डाल कर खाएंगे, गांव के लोग यह नहीं करने वाले हैं। अब अर्बन सेंटर में व्यवस्थित व्यापार स्थापित नहीं होगा तो वे कहां बेचेंगे और निवेश क्यों करेंगे? यह बड़ा सवाल है।

एमएसएमईज का भी यही प्रश्न, यही चुनौती उनके सामने उठती है कि जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो किसी बड़े उद्योग पर आधारित हों उसके इर्द-गिर्द हों वे तो आज है। वे किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं? लेकिन उनसे हट कर आप देख लीजिए तो उन के लिए कोई मार्केट नहीं है। क्या वे छोटे-छोटे दुकानों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे माल को बेचो। क्या आढ़ती इकट्ठा हो कर कहेंगे कि हम कोल चेन बनाएंगे? यह संभव नहीं है। उपाय पेश नहीं हुए हैं। लेकिन विरोध बहुत हुआ है। मैं समझता हूं कि जो तर्क हैं वे जनता के सामने जरूर रखे जाने चाहिए। आज जो किसान और उपभोक्ता के बीच में जो कड़ियां है उसमें हमें किसान को भागीदारी दिलानी होगी।

गन्ना उद्योग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कल दिया गया। गन्ना उद्योग का क्या प्रभाव पड़ा? जिन जिलों में चीनी की मिलें हैं वहां जा कर देखिए कि क्या वहां किसान खुश हैं कि मिल आज हमारे क्षेत्र में आ गई है या नहीं आई है। समस्याएं बहुत हैं लेकिन किसानों के पास पहले क्या विकल्प थे? क्या आप चाहते हैं कि किसान सिर्फ बिचौलिए या कोल्हू के पास ही जा सके? कहीं न कहीं हमें वह विकल्प किसान को देना होगा।

हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी जो स्टेट एडवाइस प्राइस है वह घोषित नहीं है। किसानों को संघर्ष करना पड़ता है और सरकार की भी दखल रहती है। क्योंकि चीनी की जो व्यवस्था है उसमें बहुत ही चीजें कानून के माध्यम से निर्धारित होती हैं और सरकार की दखल रहनी चाहिए। लेकिन मिल मालिकों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो उनका क्षेत्र आरक्षित होता है उसमें उनकी रूचि रहती है कि यहां हम उत्पादन को बढ़ाएं। अड़हतिया का इंटरेस्ट नहीं होगा कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयंत चौधरी : सवाल यह है कि गन्ना का जो उद्योग है वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और वह एक चीज हमें और सिखाता है कि कहीं न कहीं हमें देखना होगा कि सरकारों का दखल कैसे रहे? चाहे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के माध्यम से या प्रदेश की जो सरकार हैं वे गारंटी को रोल दें ताकि जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं जिनके साथ समझौता होता है, यह सुनिश्चित हो कि उनसे खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है। इस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि आप निवेश को रोकें। जहां तक छोटे-मध्यम वर्ग के किसानों की बात है अगर दिल्ली या किसी भी महानगर के आसपास क्षेत्र में देखेंगे सब्जियों में जो पैदावार छोटे किसान कर पा रहे हैं वे बड़े किसान नहीं करते हैं। जिस ध्यान से वे पैदावार करते हैं बड़े किसान नहीं कर पाते हैं। स्वाभाविक है कि जब हार्टिकल्चर मार्केट विकसित होगा, हॉर्टीकल्चर में इजाफा होगा तो उसका लाभ भी छोटे-मध्यम वर्ग के किसानों को ही होगा।

जहां तक रोजगार की बात है, मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा कि कितने लोगों को नोकरी मिलेगी क्योंकि हम सबका अलग-अलग अनुमान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एक आकलन किया गया है कि वर्ष 2009 से 2020 तक जो नई लेबर सप्लाई हो रही है, उसका 90 प्रतिशत वे लड़के हैं जो बारहवीं कक्षा या उससे कम पढ़े-लिखे हैं। उन्हें और क्या नौकरी देंगे, मैं पूछना चाहता हूं? दिल्ली में मॉल स्थापित हैं। यूपी और हरियाणा के लड़कों को वहां हर महीने 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। क्या उनका गुजारा खेती से संभव है? हमें ग्रामीण क्षेत्र में विकल्प तैयार करने होंगे। किसान के बेटे भी किसानी से अलग हटकर व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, अपने काम-धंधे देखना चाहते हैं। और अपने बलबूते पर खड़ा भी होना चाहते हैं। वे रोजगार की मांग कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर मांग करता हूं कि हम सबको समझना होगा कि दुनिया में जो एक चीज परमानेंट है, वह परिवर्तन है। हम और आप लाख चाहें, परिवर्तन की उन शक्तियों के आगे नहीं खड़े हो सकते।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम अपने दिल की आवाज सुनें। जिन पार्टियों के लोग अपने आपको किसानों के हितैषी बताते हैं, उन्हें भी सोचना होगा कि हम कसान को स्वतंत्र और आजाद करना चाहते हैं या नहीं। हमें चुनकर पांच साल के लिए इसलिए नहीं

[श्री जयंत चौधरी]

भेजा जाता है कि आप अगला चुनाव भी जीतिए।...*(व्यवधान)* चुनाव इसलिए जिताया जाता है कि आप सही और गलत की पहचान करके खड़े हों।...*(व्यवधान)*

मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं। मैं परिवर्तन के साथ खड़ा हूं और इस विश्वास के साथ खड़ा हूं कि देश का नौजवान काबिल है, क्षमता रखता है और दुनिया में अपना नाम कमाए।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं श्रीमती सुषमा स्वराज और प्रो. सौगत राय द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मैं जानता हूं कि सरकार के पास संख्या बल है; मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि यह वास्तविक है या अवास्तविक परंतु सरकार के पास संख्या बल है। पर हम चर्चा करने से पीछे नहीं भागते हम इसका समर्थन करते हैं। मुझे इसका ज्ञान है कि सरकार के पास संख्या बल है, इसके लिए उन्हें राजनैतिक व्यवस्था के संगठनात्मक प्रबंधन का आभारी होना चाहिए क्योंकि उनके पास सदन में बहुमत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी है। यह मेरी आशंका है...*(व्यवधान)* मैं इसे वापिस लेता हूं...*(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: किसी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अगर कुछ अनपार्लियामैंट्री शब्द होंगे तो उन्हें हम प्रोसीडिंग से निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, यदि मेरे भाषाई अर्थ का किसी दल के संदर्भ में भिन्न अर्थ निकलता है, तो मैं इसे तुरंत वापिस लेता हूं। संसाधनों से मेरा अर्थ, राजनीतिक संसाधनों से था, मान-मनुहार, राजनीतिक प्रभुत्व और अन्य सभी कुछ। मेरा अर्थ धन से कभी नहीं है मेरा आश्य कभी भी धन से नहीं है। मेरा मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के संगठनात्मक प्रबंधन के पास पर्याप्त शक्ति है कि वे सदन में बहुमत की व्यवस्था कर सकते है। जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ गलत नहीं है।

महोदय, मुद्दा यह है। मुझे पता है कि अंत में क्या होगा पर हम मतदान में भाग नहीं रहे है। क्यों? हम देश को बताना चाहते है कि हमारी पार्टी का रूख क्या है। हम लोगों को और देश को बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का मत क्या है। यह आवश्यक है क्योंकि एफ.डी.आई. स्वयं महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु वर्तमान आर्थिक स्थिति में एफ.डी.आई., राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव के साथ एफ. डी.आई; अपने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के साथ एफ.डी.आई; और अमेरीकी प्रशासन द्वारा समर्थित एफ.डी.आई. का निश्चित रूप से इस देश पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मेरा मुद्दा यह है। हम नियम 184 के अंतर्गत इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सरकार ने नियम 184 के अंतर्गत चर्चा हेतु सहमत होने के लिए इतना समय क्यों लगाया। वे प्रारंभ में ही सहमत हो सकते थे, बजाए इसके उन्होंने समय लिया। इसके परिणामस्वरूप, हमने संसद के कार्यकरण की एक बड़ी अवधि खो दी। 2जी स्पेक्ट्रम पर जे.पी.सी. हेतु मांग के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या सरकार अपना मत बना पाने में इतनी कमजोर है? सरकार कोई मत बनाने पर हिचकती क्यों है? इसका क्या अर्थ हुआ कि सरकार को अपनी स्थिति की जानकारी नहीं है?

महोदय, मुद्दा यह है कि खुदरा में मल्टी-ब्रांड एफ.डी.आई. पर सरकार का दृढ़ मत है। प्रारंभ में वह हिचक रही थी। अब वह दृढ़, पूरी तरह दृढ़ है। कृपया मेरी टिप्पणी पर क्रोधित न हों। सरकार इतनी दृढ़ है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ हुआ? कृपया इसके प्रभाव को समझिए। प्रभाव का अर्थ है कि वालमार्ट के लिए 120 करोड़ की जनता वाले देश का प्रधानमंत्री अपनी सरकार तक की बलि

देने के लिए तैयार हैं। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? सरकार इतनी दृढ़ क्यों है? मैं सीधे अपने प्रश्न पर आ रहा हूं।

मैं स्पष्ट बात करने के लिए श्री कपिल सिब्बल का धन्यवाद करता हूं। वह अदालत में और सदन में भी काफी स्पष्ट रहते हैं। उन्होंने क्या कहा है? अपनी चर्चा में उन्होंने एक वाक्य कहा; फिर उसे वापिस ले लिया। उन्होंने कहा-''अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए।'' उसके पश्चात श्री चिदम्बरम ने उनकी ओर देखा होगा। उन्होंने विषय बदल दिया। परंतु प्रश्न यह है कि ''अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिएं।'' यही कारण है कि सरकार इतनी दृढ़ क्यों है। सरकार मानती है कि देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। सरकार ने संसद को स्पष्ट नहीं बताया है। संसद को अंधेरे में रखा गया है। हमें नहीं पता कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है। संकट क्या है? आप जी.डी.पी. की बात कर रहे हैं। आज जी.डी.पी. कहां पर है? यह 5.3 पर पहले जितना ही निम्न है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कितना है? यह एक प्रतिशत से कम है। कृषि के संबंध में क्या स्थिति है? खरीफ उत्पादन के लक्षित स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं है। देश कहां पहुंच गया है? निवेश कम हो रहा है। बैंकों के पास निधियों के अंबार लगे हुए हैं। कोई भी निवेश करने के लिए नहीं आ रहा है। यही नहीं रोजगार सृजन न्यूनतम स्तर पर है। अर्थव्यवस्था की हालत यह है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

आप आठ या नौ वर्षों से अधिक समय से सत्ता में हैं। आपके द्वारा लागू की जाने वाली आर्थिक नीति से यह विफलता या विध्वंस हुआ है। अत: मुद्दा यह है कि आप यह मानते हैं और इसलिए ही सरकार इस पर दृढ़ है। सरकार का मानना है कि एफ.डी.आई. भारत की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। आप मानते हैं कि एफ. डी.आई. भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बचा सकता है। इसलिए आप दृढ़ हैं। श्री कपिल सिब्बल को वह वाक्य बोलने तथा मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए धन्यवाद।

खुदरा में एफ.डी.आई. अंत नहीं है। यह तो एक संकेत है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समूचे समुदाय को विदेशी निवेशकों के सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में दिखाने का संकेत देना चाहती है। आप यह संकेत देना चाहते हैं। यही प्रश्न उठता है? क्या यह सही रणनीति है? क्या किसी ने भारत की मंदी और खाद्य उत्पादों की आसमान छूती कीमतों से प्रभावित होने वाली स्थिति में विदेशी निधियों के अधिक प्रवाह पर अत्यधिक निर्भरता के प्रश्न को उठाता है? क्या यह विदेशी निधियों के अधिक प्रवाह पर अत्यधिक निर्भर होने का सही समय है? क्या यह सही रणनीति है? इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। हम सभी इस देश के वासी हैं। आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि विदेशी निधियों पर अत्यधिक निर्भरता की यह रणनीति किस प्रकार भारत को बचाएगी? क्या यही भारत की परंपरा है।

[हिन्दी]

आप परम्परा की बात कर रहे हैं। *[अनुवाद]* कांग्रेस को हम सभी ने बनाया ...*(व्यवधान)*। महोदया, आप को इतिहास की जानकारी नहीं है। यही समस्या है। जब कांग्रेस बनी तब कम्यूनिस्ट कांग्रेस का भाग थे। हम कांग्रेस के सदस्य थे। हमारी पार्टी कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य थी और कलकत्ता के कांग्रेस सत्र में स्वतंत्र भारत हेतु पहला संकल्प एक कम्यूनिस्ट द्वारा ही लाया गया था।...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, आदर सहित मैं कल से पहली बार उनसे कुछ कहने का अनुरोध कर रहा हूं। वे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं। मैं उनसे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का पुनर्वालोकन करने का अनुरोध करता हूं। 1920 के दशक में कम्यूनिस्ट कांग्रेस के अलग हो गए और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मेरे युवा मित्र वाणिज्य मंत्री को इतिहास की जानकारी नहीं है। इतिहास 1920 में समाप्त नहीं हुआ। इतिहास 1942 में प्रारंभ नहीं होता। इसके बीच में भी इतिहास है।...*(व्यवधान)* इसके बीच में भी इतिहास है। उन्हे इतिहास में तोड़-मोड़ नहीं करना चाहिए। इतिहास तो प्रक्रिया को जारी रखना है...*(व्यवधान)*

महोदय, मुद्दा यह है। मैं यह मानता हूं कि भारत सरकार पर दबाव है; बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव है; बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, कृपया मुझे थोड़ा और समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल दो और मिनट।

श्री गुरूदास दासगुप्त : फिर मैं नहीं बोलूंगा। महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त नहीं कर सकता। कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं यह मानता हूं कि भारत सरकार पर दबाव है; बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव है। बहुराष्ट्रीय कंपनिया चाहती हैं कि भारत को उनके लिए खोला जाए। क्यों? समूचे विश्व में संकट है। यूरोप में संकट है; अमेरीका में संकट है। बाजार का, मांग का अभाव है। इसलिए, उन्हें नए बाजार की आवश्यकता है। अत: वे भारतीय बाजार को खोलने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं।

ओबामा तो अपने देश के खुदरा व्यापारियों के समर्थक हैं, पर क्या ओबामा भारत में वालमार्ट के प्रवेश हेतु तरफदारी नहीं कर रहे हैं। यह ही राजनीति का विरोधाभास है। यह एक स्वर्णिम त्रिभुज है। आइए इसे समझें। भारत सरकार खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. पर बनी है। अमेरीका द्वारा तरफदारी की जा रही है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी दबाव है। यह एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाता है और, हम संकट में है; देश संकट में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी रणनीति गलत है, पूर्णत: गलत और खुद ही हार करवाने वाली। मैं कामना करता हूं कि सरकार मुझे बताए, श्री आनंद शर्मा मुझे बताएं। मैं उनसे स्पष्ट रूप से उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। विश्व में कहां पर खुदरा मल्टी ब्रांड में एफ.डी.आई. ने किसानों की सहायता की है? संसार में कहां पर खुदरा मल्टी ब्रांड में एफ. डी.आई. ने आम आदमी हेतु साम्य वृद्धि को बढ़ावा दिया है तथा रोजगार पैदा किए हैं? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं।

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली) : चीन।

श्री गुरूदास दासगुप्त : नहीं, चीन नहीं, वहां तो केवल 10 प्रतिशत है...*(व्यवधान)*, महोदया, चीन में केवल यह 10 प्रतिशत है ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे सुनने के लिए धैर्य रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, कृषि में, एफ.डी.आई. ने अमेरीकी किसानों की कोई सहायता नहीं की है; उनकी सहायता तो संघीय समर्थन से हुई है। आज अमेरीका में कृषि हेतु आवंटन 307 बिलियन डालर है। भारत में कृषि हेतु आवंटन कम हो रहा है और, आप विदेशी फर्मों को आमंत्रित करके कृषि हेतु बजटीय आवंटन की कमी की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। क्या यह विरोधाभासपूर्ण नहीं है? वे यहां परोपकार के लिए नहीं आ रहे हैं। संसार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकमात्र चाह लाभ का लालच होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं दो से तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

यह कृषि के संबंध में है।

आप मूल्यों के बारे में बात कर रहे थे। आनंद शर्मा जी, आपके पास उनकी ओर देखने के लिए काफी समय है; कृपया मुझे देखिए...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपको बता रहां हूं कि अनुभवाश्रित अध्ययन से पता चला है कि लेटिन अमेरीका, अफ्रीका और एशिया में सुपर मार्केट की कीमत मुक्त बाजार से 30 प्रतिशत अधिक है। एक अध्ययन है जो यह दर्शाता है...*(व्यवधान) [हिन्दी]* चाइना में दस प्रतिशत है, चाइना की बात छोड़िए।

महोदय, मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं। मैं यह खुले आम स्वीकार करना चाहता हूं कि चीन मेरे लिए कोई मॉडल नहीं है। चीन मेरे लिए कोई मॉडल नहीं है; भारत मेरा मॉडल है। चीन मेरे लिये कोई मॉडल नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, वे कह रहे हैं कि बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी चुभन महसूस हो रही है। वे चुभन महसूस कर रहे हैं और इसलिए जोश में हैं। मैं अपने मकसदमें सफल रहा...*(व्यवधान)*

बिचौलियों के संबंध में, मैं यह कह सकता हूं कि बिचौलिए तो समाप्त नहीं होंगे। बिचौलिए की एक नई जमात आ जाएगी। वे कौन है? वे हैं-गुणवत्ता नियंत्रक, मानकीकरण करने वाले, प्रसंस्करणकर्ता और पैकेजिंग परामर्शदाता। बिचौलिओं की एक नई जमात आ जाएगी।

मैं आपको एक कम्यूनिस्ट देश वियतनाम से एक और उदाहरण देता हूं, वियतनाम में, सुपर मार्केट में काम करने वाले 4 लोग 18 फेरी विक्रेताओं का कार्य कर लेते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य 18 फेरी वाले विक्रेताओं द्वारा किया जा सकता है; और एक सुपर मार्केट में केवल 4 लोग उस कार्य को करते हैं। यह वियतनाम का एक तथ्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि मजूदरी हर जगह कम है। मेरे पास समय नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी स्तर के संबंध में आपको और जानकारी देना चाहता था। मजदूरी हर जगह कम है। जी हां, चीन में कुछ स्थानों पर मजूदरी कम है; मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं इसे मानता हूं। केवल यही नहीं, महोदय, भ्रष्टाचार भी है। क्या हुआ? वाल-मार्ट द्वारा 5 अधिकारियों को रोजगार से हटा दिया गया। क्यों?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : वे भारत में रिश्वत दे रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं। वे भारत में रिश्वत दे रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह से कार्य करती हैं। इस तरीके से भारत राजनीतिक व्यवस्था ने अपने को संवेदनशील बना लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मल्टी ब्रांड में एफ.डी.आई. बड़ी कंपनियों द्वारा लगाया जाएगा। वे बाजार और मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। यह मान कर मत चलिए कि प्रतिस्पर्धा होगी। विशालकाय और बौनों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। हमारे खुदरा विक्रेता बौने हैं। विशालकाय और बौनों के बीच प्रतिस्र्धा नहीं हो सकती। अत: आप एकाधिकारी वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और एकाधिकारी वृद्धि राष्ट्रीय हित की अनदेखी करते हुए बाजार के लिए अपने साथ छेड़छाड़ करेगी। *[हिन्दी]* हम जानते हैं कि आपको मजबूर क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप देश-विरोधी काम कर रहे हैं। *...(व्यवधान) [अनुवाद]* मैं प्रिय रंजन दासमुंशी को दोहरा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं प्रिय रंजन दासमुंशी को दोहरा रहा हूं। उनकी बात कार्यवाही वृतांत में शामिल की जाएगी। आप राष्ट्र-विरोधी दिशा में जा रहे है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। अगर कोई असंसदीय शब्द बोला गया है तो उसे हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हमने बोल दिया है, अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। किसी की भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आप बैठ जाइये। *...(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): देश-विरोधी काम कर रहे हैं ऐसा कहना अन-पार्लियामेंट्री नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब श्रीमती हरसिमरत कौर।

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : महोदय, नवंबर, 2011 में जब हमने सरकार द्वारा 'मल्टी ब्रांड रिटेल' में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) लाए जाने के बारे में सुना तो अन्य अनेक भारतीय की भांति हमने भी उसका स्वागत इसको देखते हुए किया कि सरकार द्वारा लागू की जा रही यह नई नीति स्पष्टत: हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग की जीविका और हितों की रक्षा करेगी... *(व्यवधान) [हिन्दी]* आप मेरा टाइम नोट करे लें, मैं अब बोलना शुरू कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलना शुरू कीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, 2011 में जब यह नीति स्पष्टत: हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग की जीविका और हितों की रक्षा करेगी हमे सरकार द्वारा 'मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाए जाने के बारे में सुना तो अन्य अनेक भारतीयों की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती हरसिमरत कौर बादल]

भांति हमने भी उसका स्वागत इसको देखते हुए किया, कि सरकार द्वारा लागू की जा रही महोदय, मात्र यह कल्पना करना कि सरकार वैश्विक मान्यता और कार्पोरेट प्रशंसा प्राप्त करने के लिए विशाल विदेशी 'मल्टी ब्रांड' खुदरा कंपनियों के साथ स्वयं अपने हजारों लोगों की जीविका का सौदा करेगी केवल अविश्वसनीय नहीं; बल्कि अकल्पनीय है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, जिसका उपयोग अवसंरचना को सुदृढ़ करने, निर्यात को बढ़ावा देने और नौकरी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए किया जाना चाहिए था, एक ऐसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के रूप में सामने आई है जो वस्तुतः इन उत्पादों के बाजार को नियंत्रित और उस पर एकाधिकार करके इन छोटे व्यापारियों का शोषण केवल अनेकों बिलियन डालर की खुदरा विशालकाय विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, लाखों व्यापारियों, दुकानदारों, मजदूरों, किसानों और अन्य अनेक लोगों का रोजगार और जीविका छीन रही है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ नहीं बोल रही हैं। वह केवल अपने विचार रख रही हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार की गई मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति हमारे अपने लोगों और हमारे देश के हितों का सौदा करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन, महोदय, मेरा मानना है कि जो सरकार पिछले अनेक वर्षों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसके पास क्षुब्ध मतदाताओं को लुभाने के लिए भारी भ्रष्टाचार, बढ़ते मूल्य और कम वृद्धि दर और किसी प्रकार का लालच दिखाने के अलावा कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदया : बाजवा जी, आपको मैंने बैठने के लिए कहा है। आप बैठ जाइए। आपको जब बोलने के लिए समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : इस प्रकार, आधार योजना के नाम पर 10 करोड़ गरीब लोगों को रिश्वत दी गई। यह तथा कथित एफ.डी.आई. नीति केवल कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक साथ दो सदस्य नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, समयाभाव के कारण, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहती हूं सरकार कहती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नए रोज़गार पैदा करेगी।

[हिन्दी]

सर, मैं कहना चाहती हूं कि आज जो देश की जनता है, 1.2 बिलियन पोपुलेशन जो है, उनमें से कोई किसानी कर रहा है, लाखों किसानी के धंधे से जुड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)* कोई किसानों से चीजें खरीद रहा है, कोई किसानों को चीजें बेच रहा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ...*(व्यवधान)* और सब मिलकर ...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* चाहे वह श्रमिक हो अथवा मजदूर अथवा किसान या कोई व्यापारी, वह निर्भर है और देश की अर्थव्यवस्था से अपनी जीविका चलाता है। *[हिन्दी]* जो यह एफ.डी.आई. रिटेल आ रही है, ...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* यदि हम चार सबसे बड़ी कंपनियों टेस्को, वालमार्ट, केयरफोर और मेट्रो पर नजर डालें तो दुनिया भर में उनके 24000 स्टोर हैं जिनमें 33 लाख लोग काम करते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई शून्यकाल नहीं चल रहा है। आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : एक शहर जिसमें दस लाख से कम की पोपुलेशन होती है, आज उस सिटी में कम से कम 35000 ट्रेडर्स, मैनयुफैक्चरर्स होते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए। शांत रहिए। आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: लाखों करोड़ों काम करने वाले मजदूर होते हैं। लेकिन केवल 140 लोगों को प्रति स्टोर एम्पलॉयमेंट मिलता है। लाखों करोड़ों ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के पेट पर लात मारकर जब 140 मुलाजिम प्रति स्टोर को नौकरी देने वाली बड़ी जायंट कंपनी आएगी तो मैं पूछना चाहती हूं कि वह वॉलमार्ट जॉब क्रिएट कर रहा है या जॉबलैस क्रिएट कर रहा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरकार कहती है कि एफ.डी.आई. से अवसंरचना सृजित होगी। *[हिन्दी]* सर, मैं पूछना चाहती हूं *[अनुवाद]* ग्रामीण अवसंरचना निर्माण के लिए केवल 7687 करोड़ रूपए की आवश्यकता है। *[अनुवाद]* वेअरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज में सालों पहले एफ.डी.आई. का एलाउ कर दिया गया था लेकिन एक नया पैसा वहां से नहीं आया। क्यों?...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* इसका कारण यह है कि कोई भी विदेशी कंपनी, जो भारत में अवसंरचना निर्माण करेगी, ऐसा हमारे किसानों के शोषण के लिए और, लाभ कमाने के लिए करेगी न कि हमारे किसानों और अन्य लोगों के फायदे के लिए।...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहती हूं कि अवसंरचना निर्माण सरकार की जिम्मेदारी है अथवा यह किसी विदेशी कंपनी की जिम्मेदारी है?...*(व्यवधान)*

महोदय, श्री सिब्बल कहते हैं कि 35 से 40 प्रतिशत भोजन बर्बाद होता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर)**:** सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बाजवा जी, एक मिनट में बोलिए कि बात क्या है? आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर, मुझे बोलने की परमिशन तो दीजिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। किस नियम के तहत आप बोलना चाहते हैं? बताइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर, मैं मैम्बर साहिबा से पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कौन से नियम के तहत आप पूछना चाहते हैं? यह आप बताइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आप किसी नियम के तहत बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा: यह चिट्ठी इनके हसबैंड की है, सुखबीर सिंह बादल जी की है। मैं वह चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, यह मेरे बोलने का समय है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अवसंरचना में निवेश की बात कर रही थी जैसा कि सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, ग्रामीण अवसंरचना भांडागारण और शीतागार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। एक भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हुआ क्योंकि विदेशी कंपनियों की रूचि केवल लाभ कमाने और हमारे किसानों के शोषण करने में है; हमारे देश की प्रगति को सुकर बनाने में नहीं।

श्री सिब्बल कहते हैं कि सड़ने के कारण 35 ये 40 प्रतिशत खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। लेकिन कृषि मंत्रालय का एक अग्रणी निकाय उनकी अपनी आई.सी.ए.आर., भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ने सितंबर, 2010 में स्पष्ट कहा है कि सड़ना केवल 0.8 से 10 प्रतिशत है। क्या मंत्री महोदय का विश्वास करना चाहिए अथवा सरकार के अपने रिकार्ड का या फिर मंत्री महोदय की जबान इसलिए फिसली है कि यह सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तर्क के अनुरूप है? ...*(व्यवधान)*

अब मैं उस बात पर आती हूं जिसके बारे में मेरे सहकर्मी शोर मचा रहे हैं कि एफ.डी.आई. से किसानों को फायदा होगा। मैं बताना चाहती हूं कि 1988 में पेटसी एक विदेशी कंपनी, ने वोल्टास टाटा की एक कंपनी और पंजाब सरकार के साथ मिलकर कृषकों के फायदे के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है।

[हिन्दी]

आज के क्या हालात हैं? इन्होंने फ्रूट और वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट टमेटो सॉस बनाने के लिए चलाया था, वह कुछ ही सालों बाद बेच दिया। बेचारे किसान जिन्होंने टमाटर से डाइवर्सिफाई किया था, मशीनरी पर लोन लिया था, मशीन भी बेकार जा रही है। यह उसका हाल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी, केवल माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में जायेगी।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: पोटैटो फैक्टरी संगरूर में है, पेप्सी कंपनी मैज्योरिटी ऑफ पोटैटो पंजाब के बाहर से खरीद रही है ...*(व्यवधान)* जो पोटैटो दे नहीं सकता है, ...*(व्यवधान)* यह हालत जालंधर के फार्मर्स की है, जिन्होंने अपने आलू सड़कों पर फेंक दिये, क्योंकि कोई पेप्सी कंपनी उन्हें खरीद नहीं रही थी ...*(व्यवधान)* आप यह फोटो देखें, बयानबाजी न देखें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब दूसरा सदस्य बोल रहा हो तब आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए जब आपका नाम पुकारा जाए तब आप अपनी बात रखें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, मैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को उद्धत करना चाहती हूं जो जालंधर आलू उत्पादक संघ ने भी है। इसके अनुसार, कृपया इसको ध्यान से सुनें, उसमें कहा गया है:-

> "हम कच्चे भुट्टों की आपूर्ति करते हैं। संविदागत मूल्य 8 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था। लेकिन, सामान्यत: वे यह कहकर एक रूपया प्रति किलो कम कर देते हैं कि यह सामान निर्धारित मानकों से कम अथवा कुछ पूर्णतया नकार देते हैं।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका समय आयेगा तो आप बोलियेगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, बार-बार खड़े होते हैं। आप बार-बार खड़े होते है? एक बार आपने बोल दिया तो बोल दिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : इसमें आगे कहा गया है:

"अंतत: यह मूल्य मंडी के मूल्य से जो 50 पैसे से एक रूपया तक अधिक बनता है।" *...(व्यवधान)* महोदय, जंगबहादुर, जिन्हें आलू का बादशाह कहा जाता है, का कहना हैं कि आपूर्ति श्रृंखलाएं आलू को किसानों से न खरीदकर इसे मंडिया से खरीद रही है।. *..(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महेदया : आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं? आप एक बार खड़े हुए, दो बार खड़े हुए, तीन बार खड़े हुए, आप जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, जालंधर से आलू के बादशाह यही कह रहे हैं, तत्पश्चत् वे एक ठोस प्रश्न करते हैं:

"एफ.डी.आई. के साथ, खुदरा श्रृंखलाओं को आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए किसानों के साथ वायदा संविदा करनी होगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए किसी नुकसान की स्थिति में; सामान्यत; बाजार ताकतें मूल्य वृद्धि के रूप में प्रतिपूर्ति करती हैं। लेकिन, पूर्व-निर्धारित संविदाओं की स्थिति में किसान इन खुदरा श्रृंखलाओं की दया पर निर्भर रहेंगे।"

अत: मैं यही कहना चाहती हूं। *[हिन्दी]* जिस देश में कभी फ्लड आता है, अभी ड्राउट आता है तो क्या यह प्री कांट्रैक्ट में फिक्स होगा? फार्मर्स की क्राप जब खराब हो जाती है तो सरकार मार्केट कंट्रोल करके उन्हें कम्पैनसेशन देती है, जिससे उनका कुद फायदा होता है। फॉरेन कंपनी उन्हें कम्पैनसेट करेगी या विदेश से आलू, टमाटर, प्याज ही नहीं, बल्कि राइस, चीनी और चावल के लिए बहाना ढूंढेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य में लाखों टन चावल को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें कीटनाशक के अंश हैं। इसलिए, वे हमारे चावल को, गेहूं को, आलुओं को तथा टमाटरों को अस्वीकृत करने के बढ़ाने ढूंढते हैं, *[हिन्दी]* कौन सा फार्मर सेफगार्ड हो रहा है और कौन इनको इनके रिक्शन या क्वालिटी कंट्रोल से सेफगार्ड करेगा?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, सरकार बार-बार कहती है कि आपूर्ति श्रृंखला में से बिचौलियों को हटाया जाना चाहिए। महोदय, यह दर्शाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होने जा रहे हैं। ऐसा सरकार स्वयं भी कह रही है। क्या सरकार ने इस बिचौलियों के पुनर्वास के लिए कोई पुर्नवास नीति बनाई है जो विस्थापित हो जाएंगे? अथवा, क्या वे भारतीय नहीं है? क्या उनकी आजीविका उनके व्यापार पर निर्भर नहीं है? क्या हमें उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है?

महोदय, जब आप एक विशालकाय बिचौलिए वालमार्ट के पास जाएंगे, जैसा कि मेरे साथी श्री दासगुप्ता ने कहा *[हिन्दी]* क्या उनके मिडिलमैन क्वालिटी कंट्रोलर्स नहीं होंगे, क्या नई तरह के मिडिलमैन नहीं आयेंगे। जो उनकी पैकेजिंग और क्वालिटी को मेनटेन करने के चक्कर में उनका सारा माल रिजैक्ट करेंगे। यह मिडिलमैन को हटाकर बहुत बड़े जाइंट मिडिलमैन को अपने किसानों को तंग करने के लिए खड़ा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं एक बात जानना चाहूँगी। यदि वॉलमार्ट किसानों की सभी समस्याएं सुलझाने में सक्षम था, तो संयुक्त राज्य में संयुक्त राज्य के किसानों की 20 बिलियन की राजसहायता क्यों दी जा रही है? मैं यह इसलिए जानना चाहती हूं क्योंकि वहां वॉलमार्ट कई दशकों से है।

[हिन्दी]

उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो हमारी प्राब्लम कहां से सोल्व हो जायेंगी। वाल्टन फैमिली, वालमार्ट की ओनर है, उनकी पर्सनल

[श्रीमती हरसिमरत कौर बादल]

असैट 100 बिलियन डालर्स की है, क्या यह 100 बिलियन डालर्स की पर्सनल प्रोपर्टी उन्होंने गरीबों की मदद करके, फार्मर्स को अच्छी प्राइसेज देकर और सस्ते दामों में चीजें बेचकर कमाई है या फार्मर्स का खून चूसकर इतने पैसे बनाये हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बीच में फिर खड़े हो गये, हमने आपका नाम नहीं लिया है, फिर आप बीच में क्यों खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हमने आपका नाम नहीं लिया है, फिर आप बीच में कैसे खड़े हो गये। आप ऐसे ही बीच में खड़े हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, क्या यह सच्चाई नहीं है कि संयुक्त राज्य में वॉलमार्ट के प्रवेश से 40,000 फेक्ट्रियां 2001 तथा 2007 के बीच हो गई हैं जिससे लाखों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.00 बजे

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त राज्य में पिछले तीन वर्षों में चीन से आयात तिगुना हो गया है, जो यू.एस. डॉलर 9 बिलियन से यू.एस. डॉलर 27 बिलियन हो गया है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कर के बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब चाहते हैं, खड़े हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट ऑफ ऑडर नहीं नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति जिसका प्रयोग इस देश के हितो की रक्षा करने के लिए किया गया होता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, आप उनके व्यवस्था के हैं, परंतु आपको उन्हें उनकी व्यवस्था का प्रश्न पूछने की अनुमति अवश्य प्रदान करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। हमने समय दिया है। उन्होंने बोला क्यों नहीं है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संजय निरूपम (उत्तरी मुम्बई) **:** महोदय, आप उनके व्यवस्था के प्रश्न को नकार नहीं सकते...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, दो मिनट मुझे अपनी बात बोलने तो दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, सरकार की एफ.डी. आई. पॉलिसी कहती है कि केवल 30 पर्सेंट ...*(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज देश में स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि *[अनुवाद]* एक सामान्य भारतीय परिवार अपनी आय का 33 प्रतिशत ताजे फल तथा सब्जियों पर खर्च करते हैं।

[हिन्दी]

ये फॉरेन कंपनीज़ फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल हमारे लोगों से लेंगी और सौ फीसदी मैनुफैक्चरिंग चाइना को चली जाएगी। आज होली के गुब्बारों से लेकर दिवाली के पटाखे तक चाइना से आते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: जब सब कुछ चाइना से आने लग जाएगा तो हमारी 100 पर्सेंट मैनुफैक्चरिंग का वही हाल होगा ...*(व्यवधान)* जो आज यूएस में है। ...*(व्यवधान)* हम भी उनके गुलाम हो जाएंगे ...*(व्यवधान)* क्योंकि सब कुछ चाइना से बन कर आएगा। ...*(व्यवधान)* हमारे यहां की मैनुफैक्चरिंग ठप्प हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा : महोदय, मेरी व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के तरत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि वह हमारे राष्ट्रपिता के शब्दों को याद करें, जिन्होंने कहा था कि: ''यदि मेरे जुलाहे भाई का काम आयात्तित कपड़े के कारण खत्म हो जाता है, तो यह मेरे लिए बेहतर कैसे हो सकता है?''...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा : नियम 376ए के तहत

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: मैं आज पूछना चाहती हूं कि अगर 53 शहरों में एफडीआई इन मल्टीब्रान्ड रीटेल खुलता है। ...*(व्यवधान)* एक भी किराने का दुकानदार, एक भी मजदूर, एक भी किसान की रोजी-रोटी जाती है, तो इसमें हमारे देश का भला कहां से हो सकता है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रताप सिंह बाजवा : यह पंजाब का मसला है। हम नहीं बैठेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह रूल 376 में नहीं आता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर ये लोग महात्मा गांधी जी के नाम पर भी नहीं चुप नहीं हो रहे हैं तो किसके नाम पर चुप होंगें?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा: ''यदि मेरे जुलाहे भाई का काम आयातित कपड़े के कारण खत्म हो जाएगा, तो यह मेरे लिए बेहतर कैसे हो सकता है''...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने अपना विखर्पथ दे दिया है और इसके साथ ही बात समाप्त होती है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि हमारे देश के 53 शहरों में, एक भी दुकानदार के लिए जगह नहीं होगी, एक भी व्यापारी के लिए जगह नहीं होगी, सभी यदि एक भी मजदूर अपने काम से हाथ धो बैठेगे तब, एक विदेशी कंपनी भारत के लिए बेहतर कैसे हो सकती है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: आज यह सरकार जवाब दे कि ये देश के दुकानदारों के साथ हैं ...*(व्यवधान)* या विदेशी दुकानदारों के साथ हैं। ...*(व्यवधान)* ये अपने लोगों की नौकरी सुरक्षित चाहते हैं ...*(व्यवधान)* या अपनों के पेट में लात मार के विदेशियों का पेट भरना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* यह सरकार जवाब दे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने रूलिंग दे दी है, उसके बाद भी आप खड़े हो गये हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने रूलिंग दे दी है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। किस नियम के तहत आप यह उठा रहे है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये। लालू जी, आप बोलिये

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : पहले आप उन्हें बिठाइये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये। आप फिर उन्हें भड़का रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः हमें बोलने दीजिए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः लालू जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप उन्हें बोलने दीजिए, आपने फिर शुरू कर दिया है। कौन-कौन मिला हुआ है, उससे क्या मतलब है?

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः हमारी बात सुनिये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः लालू जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः यहां ढंग से बैठिये। *...(व्यवधान)*.

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः आप बीच-बीच में ऐसे ही बोल देते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य आप इधर देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः आप ज्यादा काबिल मत बनिये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः आप इधर देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः तुम जो चाहोगे सब वही करेंगे। *...(व्यवधान)* आप बैठिये**

उपाध्यक्ष महोदयः हम कह रहे हैं कि आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः हम यह बोल रहे हैं कि आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः हम कह रहे हैं कि आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लालू प्रसादः महोदय, आज पूरा देश रहा है, एफडीआई पर प्रधानमंत्री की इस घोषणा को कि चाहे सरकार रहे या जाये, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके रहेंगे। अब कोई माने या ना माने, जरा सुनिये, आप इधर देखिये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः हम उनको मना कर रहे हैं।

श्री लालू प्रसादः उन्हें क्या मना कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदयः मना तो करना होगा।

श्री लालू प्रसादः वे इसी के लिए आये हैं। देश माने या ना माने, एफडीआई के मामले में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। यह बहस कल से हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदयः आप सीधे देखकर बोलिये।

श्री लालू प्रसादः *...(व्यवधान)** आप सुनने की कोशिश कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा)**:** ये चेयर पर आक्षेप लगा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप हमारे ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः हम कहां क्वेश्चन कर रहे हैं?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप चेयर को ऐसा नहीं कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः मैं चेयर का कोई अनादर नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* चेयर के पद का आदर है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः जो भी अनपार्लियामेंट्री है, उसे निकाल दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः जो भी अनपार्लियामेंट्री है, उसे निकाल दिया जायेगा। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः हमने रिकॉर्ड से निकालने के लिए बोल दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः एक मिनट सुन लीजिए, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः हमने कोई डेरोगेट्री बात नहीं बोली है। *..(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मेरा विपक्ष के नेता से सामने के बेंच पर बैठे सदस्यों से आग्रह है कि उकसाने का काम न करें। हमारे पास पहले ही समय कम है। बहुत से वक्ता हैं*...(व्यवधान)* मैं उन्हें भी कह रहा हूं। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं*...(व्यवधान)* मुझे विश्वास है कि श्री लालू प्रसाद जी भी उकसाने वाली बात नहीं बोलेंगे*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल प्रसाद (सारण) : ये * है*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)***

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। उन्हें माफी मांगनी होगी*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मैंने उनसे भी आग्रह किया है तथा अन्य से भी आग्रह किया है। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

लालू प्रसाद जी, थोड़ा ठंडे हो जाइए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सुन तो लीजिए लालू जी क्या बोल रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं, ... का मतलब होता है खिलाड़ी। यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है। अगर अनपार्लियामेंट्री है तो हमें दिखाइए। *...(व्यवधान)* का मतलब होता है खिलाड़ी। ताली बजाने वाला। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कह दिया है कि मैंने प्रोसीडिंग्ज़ से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: लालू जी माफी मांगें। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: इन्होंने प्रोवोक किया हमको कि उधर बैठो। क्या बोला हमको? *...(व्यवधान)* इन्होंने बोला हमको कि तुम उधर बैठो। क्यों बोला हमको? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लालू जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। रिकार्ड से निकालना है तो निकाल दें। *...(व्यवधान)* माफी मांगे? *...(व्यवधान)* हम बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि यह उधर का है। क्यों बोला? ये पहले ही बोला हमको। ....* यह पहले ही हमें बोल। *...(व्यवधान)* इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि यह तो इधर का है। क्यों बोला? तुम किधर का है? कौन किधर का है? *...(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय: किसी की भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3:26 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.26 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.26 बजे

लोक सभा अपराह्न 03.26 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

(एक) मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को वापस लेने संबंधी सिफारिश के बारे में प्रस्ताव

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उपाबंध (क) और उपाबंध (ख) में उपांतरण के संबंध में प्रस्ताव

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के उपाबंध ख में उपांतरण के संबंध में प्रस्ताव — *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद अभी उपस्थित नहीं है। इसलिए, डॉ. मुरली मनोहर जोशी।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।*...(व्यवधान)* पिछले दो दिनों से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आज उनके बाद बोल सकते हैं। आप उपस्थित नहीं थे। मैंने डॉ. मुरली मनोहर जोशी का नाम बुला लिया। आप उनके भाषण के बाद बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मेरे भाषण को खत्म होने दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं?

सभापति महोदय: हां।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: महोदय, इन लोगों ने किताब में देखा है कि यह शब्द अनपार्लियामेंटरी है तो हमें भी आज मालूम हो गया कि यह अनपार्लियामेंटरी है। मैं इसे वापस लेता हूं। *...(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, लालू जी ने जो अभी वापस लिया है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा किया। अगर पहले ही वापस ले लेते तो बहुत कुछ नहीं होता।*...(व्यवधान)*

महोदय, मैं यहां सुषमा स्वराज जी और खगेन दास जी के द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कल मैंने सरकार की तरफ से श्री सिब्बल जी का भाषण सुना। सरकार का पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। जब वे बोल रहे थे तो मुझे अपने विश्वविद्यालय के दिनों की याद आ गई। हमारे यहां विधि विभाग के एक प्राध्यापक थे–प्रोफेसर के. के. भट्टाचार्य। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्लास फेलो थे। वे बहुत वयोवृद्ध थे। उनकी बहुत ही इज्जत थी। उनसे एक बार लड़कों ने पूछा कि साहब, आपने हमें पढ़ा तो दिया, पास भी हो गए। लेकिन यह बताइए कि अच्छे वकील कैसे बने? उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो अध्यापक हूं, मैंने वकालत तो की नहीं, लेकिन मेंने जो सुना है कि अच्छा वकील कैसे बना जाता है, वह मैं बताता हूं। उन्होंने कहा

[अनुवाद]

"यदि कानून आपके पक्ष में है, तो न्यायाधीश के सर पर कानून मढ़ दो यदि तथ्य आपके पक्ष में है, तो जूरी के सर पर तथ्य मढ़ दो; यदि आपके पक्ष में कुछ भी नहीं है, तो जोर से चिल्लाओ और इससे ही वार करो" *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मुझे स्मरण हुआ कि वकालत का अच्छा गुण शायद इन्होंने वहीं से सीखा है। बहुत कुछ शोर किया, मगर उसमें से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन, चूंक इन्होंने सरकार का पक्ष लिया है तो उसके बारे में मैं जरूर कुछ कहूंगा। उसके बाद मुझे जो कुछ और कहना है, वह आपके सामने निवेदन करूंगा।

उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि यह ऑप्शनल है, इनेब्लिंग है। जिसे करना है, वह करे और न करना हो तो न करे। फिर आपकी फर्मनेस कहां रही? फिर आप जो कहते हैं कि यह देश के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसके बिना देश का हित हो ही नहीं सकता तो फिर आप इतनी रियायतें क्यों दे रहे हैं? थोड़ा-बहुत करने से भी अगर देश का अहित हो रहा है तो क्यों? अगर देश का इसमें हित है तो लोगों को समझाइए, उनसे बात कीजिए। यही कहा जा रहा था कि इसमें पूरी बात होनी चाहिए और उसी का नतीजा था कि आपने, आपके सरकार के लोगों ने, उस समय के वित्त मंत्री जी ने यहां और वाणिज्य मंत्री जी ने दूसरे सदन में यह कहा था कि:

[अनुवाद]

"बहुराष्ट्रीय खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय को तब तक स्थगित किया जाता है जब तक कि विभिन्न हितधारकों के मध्य सर्वसम्मति न बन जाए"

[हिन्दी]

स्टेक होल्डर्स में राजनैतिक पार्टियां आएं तो ठीक है, लेकिन इसमें किसान, छोटा व्यापारी और किसानी से संबंधित मजदूर भी है। जो सारा इस एफडीआई से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, उन सबके लोगों से बात होनी चाहिए थी। उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात होनी चाहिए थी। फिर क्या बात हुई, वह राजनैतिक पार्टियों को बताई जानी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं किया। आप जल्दी में आए, जिस दिन सारा देश विरोध कर रहा था, भारत बंद था, उस दिन आपने ऐलान किया और कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए, हम अपनी गर्दन कटा देंगे, मगर एफडीआई को जरूर लागू करेंगे। ठीक है, आपकी गर्दन है, आप कटवाएं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन देश की गर्दन मत कटवाएं। देश के गरीब आदमी एवं किसान की हत्या मत कीजिए। इस देश के छोटे व्यापारी की हत्या मत कीजिए। फिर आपने कुछ चर्चाएं कीं कि हमारे समय में हमने कुछ कहा था और हम बदल रहे हैं। ये बदला-बदली तो बहुत हो रही है, सभी जगह से हो रही है। ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होतीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। अभी जो आपके वित्त मंत्री हैं, इनसे शुरू होती हैं और ये अक्तूबर, 1996 से शुरू होती है। जब वाशिंगटन

में एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग में बोलते हुए श्री चिदम्बरम ने यह कहा :–

[अनुवाद]

"वाशिगटन की बैठक से एक सप्ताह पहले लंदन बैठक में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख किया है कि, आप भारत आए और आपने 200 वर्षों तक राज किया। अगर आप निवेश की तैयारी कर के आएं और अगले 200 वर्षों तक राज किया। अब अगर आप निवेश की तैयारी कर के आएं और अगले 200 वर्षों तक यहां रहे तो आपको बड़े लाभ मिलेंगे।"

[हिन्दी]

आप एक बार आए थे,...*(व्यवधान)* दो सौ साल आपने हमें यहां लूटा है। अब आप फिर से आइए और दो सौ साल यहां इन्वेस्ट कीजिए। आपको बहुत ईनाम मिलेगा, ह्यूज रिवाड्र्स मिलेंगे, ज ूवेम बवेजण उनको ईनाम मिलेंगे, हमारा क्या होगा? उसके बाद इनसे कुछ लोगों ने पूछा कि भई, आपने क्यों कहा, कैसे कहा तो जवाब नहीं दिया। अगर कोई जवाब दिया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में आज तक कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। सरकार की नीयत की शुरूआत वहां से होती है। इसीलिए जैसे ही वे वित्त मंत्री बने तो फटाफट काम चालू कर दिया। जब तक पुराने दूसरे वित्त मंत्री थे, जो अब भारत के महामहीम राष्ट्रपति बन गए हैं, तब तक कुछ नहीं। जैसे ही नए सम्माननीय वित्त मंत्री जी आए तो एकदम पूरी सुपर फास्ट एफडीआई इन रिटेल...*(व्यवधान)* अब जो भी कुछ हो। फिर आपने कुछ हमारे मेनिफेस्टो और उन सब की बात की, ठीक है। सन् 2002 में श्री मुरासोली मारन ने कोई नोट बनाया था। उसे रिजेक्ट कर दिया, वह नहीं माना गया। उस समय शरद जी और मैं भी केबिनेट का सदस्य था। हमने उसे नहीं माना, किसी ने नहीं माना। केबिनेट ने उस पर विचार ही नहीं किया। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का 2004 के लिए डाकुमेंट था, उसमें भी नहीं है। लेकिन जो एनडीए का डाकुमेंट था, उसमें उसका उल्लेख है। सन् 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी का मेनिफेस्टो बना, उस डाकुमेंट में जो था, उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

[अनुवाद]

"**खुदरा व्यापार** : भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र द्वारा प्रदत्त रोजगार और सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षा व्यापार के महत्व को समझती है और इसलिए खुदरा व्यापार में असम्मिलित क्षेत्र की प्रभुत्वशाली भूमिका की पक्षधर है। इस प्रयोजन हेतु ये खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देगी (मैं दोहराता हूं कि ये खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देगी।) कृषि के बाद खुदरा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है जो लगभग चार करोड़ लोगों को रोजगार देता है।"

[हिन्दी]

अब उसको आपने कहा, आप नेता विरोधी पक्ष से सवाल कर रहे हैं कि आप वे कहां से लाएंगे। आप अनऑर्गनाइज सैक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। हमने कभी नहीं कहा, आपने कहा कि अब आप इसमें कहां से लाऐंगे। आप पूछते हैं–

[अनुवाद]

"अत: आपने कहा है कि आप खुदरा क्षेत्र में असम्मिलित क्षेत्र की प्रभुत्वशाली भूमिका के पक्ष में हैं और अम्मिलित क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं।" असम्मिलित

[हिन्दी]

हमने कहीं नहीं कहा, आप हमारे मैनीफैस्टो में अपनी भावना क्यों रख रहे हैं। यही वकालत का करिश्मा है। यदि आपके पास कहने को कुछ नहीं है, तो जोर से चिल्लाओ। खूब चिल्लाओ, लेकिन इससे सच नहीं होता। हमने यह कभी नहीं कहा। फिर आप कहते हैं कि जब आपने 2004 में निर्णय लिया और 2009 में बदला तो आप बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला और किस वजह से बदला। हम बता देंगे कि हमने क्यों बदला, मगर पहले आप बताइए कि आपने क्यों बदला।

आपके श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो चीफ व्हिप थे, उन्होंने सदन में, लोक सभा में ही 2002 में कहा :

[अनुवाद]

"इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसाकि तथाकथित है कि बहुराष्ट्रीय खुदरा विक्रेता नीकरशाही के माध्यम से लगातार सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय लेकर सरकार राष्ट्र-विरोधी निर्णय ले।"

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

[हिन्दी]

यानि वे ब्यूरोक्रेटिक प्रैशर कर रहे थे। यह भी श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि एक एंटी नेशनल काम करें, यानि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एंटी नेशनल काम में शामिल है। यह कितना बड़ा आरोप है। क्या यह सच है? मैं नहीं समझता कि कोई देशभक्त, कोई भी स्वाभिमानी ब्यूरोक्रेसी या कोई भी राजनीतिज्ञ इस बात को स्वीकार करेगा। अगर यह एंटी नेशनल एक्ट तब था तो अब नेशनल कैसे हो गया, आप क्यों बदल गए? आप कैसे हो गए? आप एंटी नेशनल से नेशनल हो रहे हैं, हम भी नेशनल हो रहे हैं। हम तो पहले से ही नेशनल हैं। यह तो समझ में आया और आज हम पूरे तौर पर कहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत चर्चा एन.डी.ए. के डाक्यूमेंट में है, हम समझ गए कि वह भी नहीं होनी चाहिए थी, वह गलत थी। लेकिन आप अपनी गलतियां क्यों नहीं मान रहे, आप अपनी गलती तो मानिए। हम कहते हैं कि एफ.डी.आई. को मल्टी ब्रांड रिटेल में लाना बहुत गलत है। हमको समझ में आया औरह मने खुले रूप में कहा, मैनीफेस्टो में कहा कि हम इसको नहीं चाहते।

मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप जरा इसको समझें और देखें कि आपकी पार्टी का क्या रूख है। आपने ही कहा है कि यह एंटी नेशनल एक्टिविटी थी तो अब कैसे नेशनल हो गई? 200 साल तक आप पहले हिंदुस्तान में आए थे, आपने राज किया, आपने खूब पैसे बनाए। अब आप फिर से आइए और फिर से हिंदुस्तान को लूटिये। तब तो अकेली एक कंपनी आई थी, अब तो कई आएंगी। वाल मार्ट भी आएगी, अब तो ईस्ट ही नहीं कह रहे, वैस्ट इंडिया कंपनी भी आ रही है। वह कंपनी थी और ये कम्पनीज हैं। इसको समझ कर देखिए कि आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं, कुछ आपने बंगाल का हिसाब बताया, पर आपने जो बात कही, वह बहुत ही खतरनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत ही चिंता है। आप यह कह रहे हैं कि पहले जो फार्मर्स थे, उनकी बहुत ज्यादा अब संख्या बढ़ गई है। पहले पेपिस्को का 1800 फार्मर्स के साथ समझौता था, लेकिन अब 10 हजार फार्मर्स हो गए हैं। वर्ष 2008 में 1800 फार्मर्स थे, लेकिन अब 10 हजार फार्मर्स के साथ उनका समझौता है। जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन था, वह 2011 में 5500 एकड़ था, आज वह सात हजार एकड़ है। इतनी जमीन इन मल्टीनेशनल्स के हाथ में जा रही है। इसको मोनोपोली फार्मिंग कहते हैं, इसको सारे किसानों को कब्जे में कर लेना कहते हैं, जो पहले 1800 किसानों को उन्होंने फंसाया, अब 10 हजार किसानों को फंसाया। क्यों, यही उनकी नीति है। अगर आप उनकी व्यापारिक नीतियों को समझेंगे तो उसमें यही हुआ करता है, उसका तरीका यही है।

फिर आपने कहा था कि वे जब वहां चाइना में आए और 18 साल तक वे घाटा सहते रहे। कितनी उनकी आर्थिक ताकत है, यह समझ लीजिए कि 18 साल तक घाटा सहने के बाद वे आज भी चाइना में डटे हुए हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। 18 साल में उन्होंने तमाम सारी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों पर कब्जा किया और उसके व्यापार पर कब्जा किया और अब वे मुनाफा कमा रहे हैं। उसने डिवोस्टेट कर दिया, वरना कौन सी ऐसी कंपनी है, जो 18 साल तक निरंतर घाटा सहेगी, क्या वजह है? क्या वे बड़े उपकारी हैं, क्या चीन के लिए उनका बड़ा स्नेह आ गया है, बड़ा प्यार आ गया है कि चीन वालों के प्रति हमदर्दी आ गई है कि चीन की बड़ी मदद करेंगे। जी नहीं। उनको वहां से सस्ता सामान लेकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है। आज वह हो रहा है। आज 6 हजार ऐसी यूनिट्स वहां है, जो 80 परसेंट वालमार्ट का सारा सामान बना रही है। इन 6 हजार यूनिट्स का कब्जा लेने में उन्हें 18 साल लगे। उनको घाटा हुआ होगा, तो हुआ होगा, लेकिन चीन की इन 6 हजार यूनिट्स से वे अपना 80 परसेंट सामान बंधवा रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। यही प्रिडेटर कहलाता है। यही वह पॉलिसी है कि पहले सबको नष्ट कर दो और उसके बाद फिर आराम से कमाओ। ऐसा नहीं है, आप बड़े इत्मीनान से यूं सिर हिला रहे हैं। कुछ दिनों में यह सिर यूं हिलने लगेगा।. ..*(व्यवधान)* वह कह रहे थे कि न कि कोई दवाई ऐसी दीजिए कि हमें समझ आ जाए, शायद दवाई आपको ऐसी मिलनी चाहिए कि जरा सिर स्थिर रखकर सोचें, दिमाग को ठंडा और स्थिर रखें। आप बहुत ज्यादा वॉलमार्ट की मदद में मत बैठे रहिए, देश की तरफ देखिए। वह कह रहे थे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम देश की तरफ देख रहे हें। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप देश की तरफ देखिए, आम जनता की तरफ देखिए। मुलायम सिंह जी ने कल कहा था कि किसान की तरफ देखिए, शरद जी ने कहा था किसान की तरफ देखए, मजदूर की तरफ देखिए। मैं

आपको बताऊंगा कि आप इस वक्त क्या-क्या नुकसान करने वाले हैं?...*(व्यवधान)*

आपने कहा कि हिंदुस्तान में 35 से 40 प्रतिशत सामान खराब हो जाता है। मेरे पास सरकारी कमेटी की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

फसल के दौरान और फसल के पश्चात- हानियां, राष्ट्रीय स्तर पर अनाज का प्रतिशत-धान,-समग्र हानि 5.2; गेहूं,-6.0; मक्का- 4.1; बाजरा-4.8; ज्वार-3.9; 6.2; सूरजमुखी-4.5; मुंगफली-10.1; सेब-12.3; केला-6.6; नींबू प्रजाति-6.3; अंगूर-8.3; अमरूद-18; आम-12.7; पोप्पइ-7.4; सपोता-5.8; बंदगोभी-6.9; फूलगोभी-6.8; हरा चना-10.3; मशरूम-12.5; प्याज-7.5; आलू-90; कसावा-9.8; सुपारी-7.9; काजू-1.1; नारियल-5.4; गन्ना-8.7; काली मिर्च-3.9; मिर्ची-5.6; धनिया-7.3; हल्दी-7.4; अंडे-6.6;अंतर्देशीय मछली-6.9; समुद्री मछली-2.9; मीट-2.3; पॉल्टी मीट-3.7; दूध-0.8 गुड और खांडसारी-1.81 31 जनवरी 2012 तक रिपोर्ट-की गई यही स्थिति है।

[हिन्दी]

यह सब इसमें कहा गया है। यह 31 जनवरी, 2012 की पोजीशनल रिपोर्ट है। बहुत सारी बातें इसमें आई हैं, लेकिन इसमें 30, 40 या 50 परसेंट वेस्टेज कहां होता है?...*(व्यवधान)* यह कहां होता है, किस जगह होता है? हां, होता है, जब आप वॉलमार्ट के पास सामान लेकर जाते हैं। जो उसके ग्रेडेशन के मुताबिक नहीं आता है, वे निकाल देते हैं। वह उसके यहां नुकसान होता है। उनके यहां 30 से 40 परसेंट नुकसान है वह मानते हैं। मैंने कहा कि आपके यहां होता होगा, हमारे यहां तो नहीं होता है। आप जबरदस्ती किसान को यह बता रहे हैं कि तुम्हारा 30, 40 परसेंट नुकसान हो रहा है और तुम वॉलमार्ट के पास जाओ, तुम्हें वहां नुकसान नहीं होगा।...*(व्यवधान)* क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* मैं आपकी रिपोर्ट से ही कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* किस जगह यह होता है?...*(व्यवधान)* इसका जवाब मुझे नहीं देना है, इसका जवाब दे देंगे।...*(व्यवधान)*

मेरे पास फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र से खत आया था। इन्होंने इसमें लॉसेज के बारे में पूरे आंकड़े दिए हैं, जो इन्होंने रिसर्च कराई उसके आधार पर ये आंकड़े हैं।

[अनुवाद]

ज्यादा गहन अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि ये कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों खुदरा विक्रेताओं जो भारत में दुकानें खोलना चाहते हैं। जैसे वॉलमार्ट, टेस्को, मेट्रो जी.एम.बी.एच., और कैरेफोर द्वारा सृजित मिथक है।

सर्वप्रथम, भारत सरकार द्वारा प्रचारित किए गए अनुसार फलों और सब्जियों की फसल पश्चात् हानि 40 प्रतिशत है जिसे प्रधानमंत्री और माननीय वाणिज्य मंत्री ने अपना सिरहिलाते हुए बारंबार उल्लेख किया है, बिल्कुल गलत है...*(व्यवधान)* फल एवं सब्जी विक्रेता संघ जो एफ.ए.एम. के सदस्य हैं उन्होंने भी वर्ष 2008 में मंत्रालय को लिखा है कि जिसमें वास्तविक आंकड़े देने को कहा है जो पांच से सात प्रतिशत पाए गए हैं। हरहाल में, संसदीय स्थायी समिति के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा वृहत अध्ययन आरंभ किए गए और केन्द्रीय शस्योत्तर इंजीनियर्स तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पंजाब द्वारा करवाए गए इसमें फल व सब्जियों की बर्बादी केवल छह से 18 प्रतिशत के बीच है। वह भी सेम है, मैंने पढ़ कर सुनाया। यह सरकारी समिति की रिपोर्ट है। भारत सरकार इस समय जानबूझ कर इस रिपोर्ट को प्रकट नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

खूब हल्ला मचाओ कि 40 परसेंट नुकसान है, 40 परसेंट नुकसान है, उसके बाद खूब टेबल थपथपाओ कि 40 परसेंट नुकसान है और समझ लो कि हिंदुस्तान में 40 परसेंट नुकसान हो गया और उसके बाद वालमार्ट आएगा और आपका नुकसान घटा देगा। आप देखिए क हर बार यह कहा जाता है कि किसानों को बहुत पैसा मिलेगा। उसको उसकी लागत से ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले तो मैं आपको अमरीका का बता दूं।

[अनुवाद]

उपभोक्ता का हिस्सा-अमरीकी अनुभव, 1987 और 1997 में फार्म मूल्य घरेलू उत्पादित खाद्यान्नों हेतु खुदरा मूल्य के प्रतिशत के अनुसार लिया गया।

[हिन्दी]

दस साल में क्या फर्क पड़ा? वर्ष 1987 में मीट में 47 परसेंट ऑफ रिटेल प्राइस का हिस्सा जाता था। अब वह 1997 में

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

37 परसेंट हो गया। डेयरी में 42 से घट कर 32 हो गया। पॉल्ट्री में 45 से घट कर 41 हो गया। एग्स में 54 से घट कर 46 हो गया। क्रॉप प्रोड्क्टस में, फ्रेश फ्रूट्स में 26 से घट कर 18 हो गया। फ्रेश वेजिटेबल्स में 31 से घट कर 21 हो गया और शेयर ऑफ टॉप ट्वन्टी रिटेलर्स, ये जितने भी हैं कि जिनकी आप बड़ी वकालत कर रहे हैं उनका शेयर वर्ष 1987 में 39.2 था जो बढ़ कर वर्ष 1998 में 50.3 हो गया। उसने 50 परसेंट मार्केट कब्जा कर लिया और किसान को जो मिलना चाहिए था, कंज्यूमर को जो मिलना चाहिए था, वह घट गया।

[अनुवाद]

अंतिम मूल्यों में किसानों के अंश के संबंध में यूनाईटेड किंगडम से वास्तविक आंकड़ों में 2000 में सुपर मार्केट के संचालनों के अध्ययन जो प्रतिस्पर्धा आयोग यूनाईटेड किंगडम द्वारा करवाएं गए दर्शाते हैं कि अंतिम उपभोक्ता मूल्यों में किसानों के अंश का प्रतिशत निम्न है।

[हिन्दी]

मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वर्ष 1996 में 39 था, वह वर्ष 2006 में 35 हो गया। वर्ष 1996 में, फ्रूट्स एप्पल्स एंड पीयर्स में किसान को 35 परसेंट मिलता था, अब 25 परसेंट मिल रहा है। मीट एंड पोर्क में 59 मिलता था अब 47 हो गया। मार्केट शेयर ऑफ द टॉप फोर रिटेलर्स जो 53 परसेंट था वह बढ़ कर 65 परसेंट हो गया। जरा मस्तिष्क को सीधा रखिए।...*(व्यवधान)* वह दवाई खाइए जो बुद्धि देती है जो आप के लोग कह रहे थे।...*(व्यवधान)* जवाब तो उनको देना है। सिब्बल साहब तो बोल कर चल दिए।...*(व्यवधान)* सिब्बल साहब को तो अब जवाब देना ही है।...*(व्यवधान)* मैंने अभी आप को बताया कि क्या हाल है?...*(व्यवधान)* हमारे यहां का जो सबसे अच्छा मॉडल अमूल है जो आदमी और उपभोक्ता के बीच में किसी बिचौलिए को नहीं रखता है। उसका हाल देखिए कि क्या है?

[अनुवाद]

तथाकथित दक्षता लाभ-यानि वे मल्टीनेशनल के लिए कह रहे है; केवल बड़े विक्रेता क्योंकि वे लगातार इंटरनैशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क द्वारा समेकित आंकड़ों के अनुसार मूल्यों को कम करते रहते हैं, अमेरिका के दूध उत्पादकों को दूध पर व्यय किए गए उपभोक्ता डॉलरों में केवल 38 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त होता है।

[अनुवाद]

अगर कंज्मूर ने एक डालर खर्च किया है तो किसान को 38 सेंट मिल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वह वालमार्ट ला रहा है जिससे वह लॉबिंग करता है।

[अनुवाद]

भारतीय दूध उत्पादक जिनको 78 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होता है और इनकी तुलना में ब्रिटेन के उत्पादकों को केवल 36 प्रतिशत प्राप्त होता है। अमेरिका में संगठित रिटेल की 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उपभोक्ता मूल्य में किसानों का हिस्सा 36 प्रतिशत है; फ्रांस में यह 42 प्रतिशत है; यह जर्मनी में 46 प्रतिशत: जापान में 41 प्रतिशत: और मलेशिया में यह 30 प्रतिशत है परंतु भारत में संगठित क्षेत्र का हिस्सा चार प्रतिशत है और किसान का हिस्सा सत्तर प्रतिशत है। अमूल दे रहा है।

[हिन्दी]

कहां है बिचौलिए? ऐसे बिचौलिए जैसे अमूल कर रहा है, अगर हों तो देश का कल्याण हो। आप कोई बात तो सच कहिए। फिर वही है कि चिलाओ और ज्यादा चिल्लाओं और टेबल पीटो बार-बार थपथपाई करो, बार-बार हल्ला मचाओ, तड़क-तड़क कर बोलो कहां हैं, कहां हैं सुषमा जी, कहां हैं बताएं। सुषमा जी यहां बैठी हैं और हम भी यहीं बैठे हैं।...*(व्यवधान)* जयंते जी परिवर्तन की बात कर रहे थे। वह जब होगा तब उसकी बात करूंगा।

आप हमें क्या-क्या बातें बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इन सबके द्वारा नौकरियां मिलेंगी। मैं अभी नौकरियों का जिक्र भी करूंगा कि कितनी मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कहां से मिलेंगी।...*(व्यवधान)* आप सुषमा जी के लिए कहते हैं, आप कहती हैं कि फार्मर को क्या फायदा होगा? सिब्बल साहब कहते हैं—मैंने बता दिया कि पैसा ज्यादा मिलेगा। फिर कहते हैं टाइम से मिलेगा। मैं आपको उसका किस्सा भी बता देता हूं—आम ऋण अवधि नब्बे दिन है, अर्थात तीन माह। भारत के अधिकांश प्लेयरों द्वारा दिया गया अधिकतम ऋण समय एक सप्ताह है। मल्टी नेशनल के तरीके

जो इन्हें बहुत पसंद हैं, वे यह हैं। फिर कहते हैं पैसा टाइम से मिलेगा। वह नहीं मिल रहा है। कमीशन खत्म हो जाएगी। इसमें नए चार कमीशन वाले आएंगे, मैं आगे बताऊंगा कि वे कौन-कौन से होंगे, कितना कमीशन खाते हैं, मार्क अप कितना है और किस तरह से नौ-दस गुना दाम हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी प्रोड्यूसर से लेकर कन्ज्यूमर को बेचते हैं। फिर कहते हैं किसान के लिए टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है। मुलायम सिंह जी, वॉलमार्ट द्वारा किसान को बताया जाएगा कि कैसे बोना है, खेत में कैसे बोया जाएगा, बीज कैसे डाला जाएगा, ऊपर से डाला जाएगा या नीचे से डाला जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : हिंदुस्तान का किसान अंगूठे से बता देता है कि बोने लायक जमीन है या नहीं।...*(व्यवधान)* मशीन की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह इन्हें बताइए। यह कह रहे हैं।

हिंदुस्तान का किसान पांच हजार साल पहले जिस ढंग से खेती करता था, विदेशी वैज्ञानिकों को उसका पता अभी एक शताब्दी पहले लगा है। हमारे यहां पूरा का पूरा आर्कियोलॉजी वालों ने खोदकर निकाला। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोद रहे थे, उसके अंदर पूरा खेत निकला, उसमें पूरा खेत जुता हुआ निकला है। उसमें वैसे ही लाइनें खिंची हुई हैं जैसी आजकल किसान खींच रहा है। उसमें एक साथ एक खेत में दो फसल बोई जाती है—सरसों भी बोई जाती है और गेहूं भी बोया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह इसे नहीं जानते।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : इनको क्या पता? चांदनी चौक में खेती नहीं होती।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : चांदनी चौक में खेती नहीं होती।...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट में खेती नहीं, चिल्लाओं, चिल्लाओं और चिल्लाओं और मेज पीटो ...*(व्यवधान)* गेहूं-सरसों, चना-सरसों उसी तरह बोया जा रहा है जिसे आज का वैज्ञानिक देखकर आश्चर्य में है कि इन्हें आज से पांच हजार साल पहले कैसे पता था कि सूर्य की किरणें किधर से घूम रही हैं, कैसे पड़ रही हैं और फसल कैसे हो रही है। उसे रखा है, सामने है, आर्कियोलॉजी की किताबों में है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आप भी उसे पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। फिर कहते हैं कि साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है। कब बोना है, यह किसान को अमरीकन वॉलमार्ट बताएगा कि कब बोना है। गेहूं जुलाई में बोंना है, जनवरी में बोना है या नवम्बर में बोना है, वह बताएगा। यह कब बोना है, बताइए? उसमें कितना पानी और कितनी खाद देनी है? फिर कहते हैं कि वेस्ट नहीं होगा,उसका एक श्योर बॉयर है। उसका बॉयर पक्का हो गया है और उसका एक समझौता हो गया है—प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट। वह यही तो करते हैं। इसी के बहाने, इसी के रास्ते वे सारे किसानों को चूस रहे हैं। प्री प्राइसिंग यानी यह इस दाम पर देना पड़ेगा, नहीं देना है तो घर जाओ। हम नहीं खरीदेंगे। पहले 18 सौ किसानों से कहा, फिर अब 10 हजार किसानों से कह रहे हैं कि इस दाम पर देना हो तो दो, नहीं तो ले जाओ। वास्ट ट्रैक्स ऑफ लैंड्स। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कहीं यह वॉलमार्ट आएगा, जब कहीं ये मल्टी नैशनल्स आएंगी जो एग्री बिजेनस में होंगी, छोटा किसान को-ऐग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये निगमित घराने, निगमित कृषि और छोटे किसान सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते देबगौडा जी, वह नहीं बचेगा। कर्नाटक का छोटा रैयत बचेगा नहीं। शरद जी, बिहार में सबसे ज्यादा मार्जिनल और छोटे किसान हैं, कोई नहीं बचेगा। मुलायल सिंह जी, उत्तर प्रदेश...*(व्यवधान)* लालू जी के यहां ...*(व्यवधान)* मैं बोल रहा हूं। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपसे सहमत हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आप मेरे से ज्यादातर सहमत रहते हैं, लेकिन वोट के वक्त जरा उधर हो जाते हैं।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* हर वक्त सहमत रहिए। हम आपके साथ हैं।...*(व्यवधान)* अरे, ऐसे सहमत रहेंगे, तो किसी दिन उधर ऊंची गद्दी पर बैठेंगे।...*(व्यवधान)* हम तो लेंगे। अब वे कह रहे हैं कि कॉर्न की बात पूछी और किसान से पूछा गया कि तुम्हें इतना मिलता है, बाजार में तो इतना दाम है। यह सही बात है। आपका फारवर्ड ट्रेडिंग वाला यही करता है। आपका क्या ख्याल है कि वॉलमार्ट सस्ता देगा? वॉलमार्ट तो और भी ज्यादा महंगा देता है। वह रिपोर्ट्स भी आपको दूंगा, जो दुनिया भर में यह कर रहा है। फिर आप कहते हैं कि मिस्टर येचुरी और हम एक साथ बैठ गए। सिब्बल साहब, यह मसला ऐसा है कि आपको भी हमारे साथ बैठना चाहिए। येचुरी ही क्यों, ...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : अगर आपके साथ बैठते तो वहीं बैठे रहते।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आप जिस वक्त इधर आएंगे, तो यह उधर हो ही जाएगा...*(व्यवधान)* वह तो जयंत जी ने कहा है कि परिवर्तन होगा।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : मल्टी नेशनल्स को आपने अपोज किया।...*(व्यवधान)*फिर आपने समझौता किया।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वह तो उसने कहा है। नौजवान, वह परिवर्तन के साथ हैं, हम उस परिवर्तन के पैरोकार हैं। नौजवान, तुम्हें परिवर्तन के साथ लेकर जाएंगे। कहां तू इस बदबू में पड़ा है। आ, परिवर्तन के साथ आ, किसान के साथ आ, अपने बाबा जी की तरह, स्वर्गीय चौधरी चरण की तरह से आ। वे किसान के साथ थे। तुम कहां इनके साथ चले गए? उनके साथ आओ।...*(व्यवधान)* उन्होंने मलटी नेशनल्स का विरोध किया था।...*(व्यवधान)* वे अकेले राजनेता थे, जो चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े थे। हार गए, वह बात अलग है। क्यों मुलायम सिंह जी?...*(व्यवधान)* हां, वह विरोध में लड़ थे।...*(व्यवधान)* क्या बात है? आओ न हम तुम्हें परिवर्तन दिखाएंगे कि कैसा होता है।...*(व्यवधान)* चंद्रमा और मंगल तक ले जाएंगे। क्या बात करते हो? हम नौजवानों के लिए परिवर्तन के पैरोकार हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.58 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

आप इसमें फिर जनसंख्या के बारे में कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। मॉल में अनाज पैदा नहीं होता। अनाज तो खेत में पैदा होता है। इनका ख्याल यह है कि वॉलमार्ट में जो पैकेट में बना रहता है, वहीं अनाज पैदा होता है। नहीं, वहां नहीं होता।...*(व्यवधान)* अनाज खेत में पैदा होता है और खेत किसान जोतता है। खेत के बारे में अगर आपको जानकारी न हो, देखिए, हमारे वाणिज्य मंत्री जी बहुत गंभीर हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप गंभीर रहें।...*(व्यवधान)* इस समय जब आप गंभीर हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। आप सोचिए।...*(व्यवधान)*

आप कहते हैं कि कम्पीटिशन होगा। मैं आपको बता दूं कि यह कभी कंपीटिशन होने नहीं देंगे। यह कंपीटीशन को ध्वस्त करके आएंगे। हमारा बाजार गांव से लेकर शहर तक सबसे ज्यादा कंपीटिटिव है और इतना कंपीटिटिव है कि वह सिर्फ बारदाने पर काम कर लेता है। क्या आप बारदाना समझते हैं? लालू जी समझते हैं, यानी वह बैग जिसमें सामान आता है। सिर्फ उस पर सौ बोरे अनाज नो लॉज नो प्रॉफिट पर बेच देगा।

अपराह्न 4.00 बजे

दुनिया में सबसे अधिक और सबसे टिकाऊ का सिस्टम अगर कोई है, तो वह हिंदुस्तान का है।...*(व्यवधान)* मुझे कोई ऐसा सिस्टम बता दीजिए दुनिया में जिसमें पहाड़ की ऊंची चोटी पर और रेगिस्तान के हिंगलाज जैसे मंदिर में, जब हिंगलाज हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान का व्यापारी बैठा हुआ था। क्या मुनाफा था उसका? उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ पर, जम्मू-कश्मीर में कहां तक जाता है दुकानदार? सब जगह पहुंच जाता है। क्या मुनाफा पाता है? वहां वालमार्ट नहीं जाएगा। वह हमको-आपको ही करना पड़ेगा। जैसे फॉरेन बैंक्स आए, लेकिन कहीं गांवों में नहीं गए, वैसे ही वह वालमार्ट छपरा नहीं जाएगा लालू जी। यह रहेगा यहीं। ज्यादा से ज्यादा पटना या मुजफ्फरपुर तक चला जाएगा और कहीं नही जाएगा।...*(व्यवधान)* मधेपुरा भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।...*(व्यवधान)* इसलिए इसको समझिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप कागज मत देखिए, बस बोलते रहिए।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : ये वकील लोग हैं, उनको बताना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जोशी जी, अब आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैडम, अभी तो शुरू ही हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ऐसे नहीं होता है। समय के अनुसार ही हमें चलाना होता है। अगर आप नाराज होइएगा, तो कैसे होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हमें समय के अनुसार चलाना है। इस बात पर नाराज नहीं होते। इस बात को लेकर नाराज नहीं होते।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैडम, थोड़ा समय दीजिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वे किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इससे किसानों की दुर्दशा होगी, उनी आमदनो नहीं बढ़ेगी। दुनिया के धनी देशों के किसानों को बड़ी मात्रा में सब्सिडाइज किया जा रहा है, उसकी पूरी तादाद बताई गई है और आप किसान की सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं। आप यहां किसान को बढ़ाइए, वालमार्ट को मत बढ़ाइए। आपको मैं एक बहुत बड़े आर्थिक विचारक की बात कहता हूं–श्री जोसेफ स्टिगलिट्स, जो क्लिंटन साहब के सलाहकार थे, नोबल लॉरिएट हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बहुत दिनों तक सलाहकार रहे।

[अनुवाद]

जोसेफ स्टिगलिट्ज़ ने बताया-

''आप वॉल-मार्ट संस्कृति को क्यों आयात कर रहे हैं? वॉल-मार्ट न केवल एक दुकान के रूप में बल्कि वॉल-मार्ट एक संस्कृति के रूप में। भारत प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक अरबपतियों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध रहा है। औसत देश में ऐसे इतने अधिक लोगों का होना बहुत आकस्मिक सफलता है। अब शीर्ष से ही बहुत बड़ी खाई है तो अब समाज में जाति-आधारित नहीं परन्तु धन आधारित विभाजन को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। जब असमानता बढ़ रही है, उसी समय हमने धन संबंधी हितों को ज्यादा वरीयता देने के लिए खेल के नियम बदल दिए है। एक फर्म अमरीकी परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है उसे पूर्ण दायित्व उठाना चाहिए परंतु ये ऐसा अमरीका में भी नहीं करते राज्य की राजसहायता इनकी रक्षा करती है। भारत में, प्रतिभाशाली उद्यमी वर्ग है और विशाल है, इनके पास काफी बचत और धन है। इसे किसी भी क्षेत्र में विदेशी उद्यमियों की क्या जरूरत क्यों है।

[हिन्दी]

किसी भी सेक्टर में किसी विदेशी की क्या जरूरत है?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं जानती हूं ये कार्य अचछा नहीं है कि मुझे समय विनियमित करना पड़ता है, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

उन्होनें आगे बताया- ''भ्रष्टाचार के मामलों का प्रभाव तो पड़ता है जनता धन की ताकत जानती है। पैसे से पैसा बढ़ता है और ये राजनैतिक प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ता है।''

[हिन्दी]

आप वह क्यों करना चाहते हैं? जो कहावतों में ऊंट था कि एक अरब सौदागर के यहां ऊंट घुस गया था, पहले सिर, फिर गर्दन और फिर बाद में पूरा ऊंट घुस गया। यह वालमार्ट इसी तरह का है, पहले एक ऊंट आएगा, फिर सारे के सारे घुस जाएंगे।

आपने कहा कि आप किसान के साथ हैं या किसके साथ हैं, हम किसान के साथ हैं। हम मजदूर के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, हम हम गरीब नौजवान के साथ है, तो नौजवानों के रोजगार के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदया : आपने अच्छी तरह से अपनी बात रखी है, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन हम डेमोक्रेसी के भी पक्के समर्थक हैं। हम रिटेल डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम रिटेल डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। हम वाल-मार्ट की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम फोरेन केपिटल की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। हम इंडियन रिटेल की डेमोक्रेसी चाहते हैं। अगर हमारे देश का व्यापारी, किसान आजाद है तो इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी, अगर यह वाल-मार्ट का गुलाम हो गया, तो उनकी डिक्टैटरशिप आएगी और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें।

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद जोशी जी। अब आप बैठ जाएं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं खत्म ही कर रहा हूं, केवल एक मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, एक मिनट में अपनी बात कहकर आप खुद ही बैठ जाएं, क्योंकि मुझे अच्छा नही लग रहा है आपको टोकना।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वाल-मार्ट और ये जो कंपनीज हैं, ये हाइली करप्ट हैं। ये पूरी दुनिया में करप्शन फैला रही हैं। हमारे देश में भी फैला रही हैं। इसके लिए आपने बताया कि कितने लोगों को उन्होंने यहां सजा दी है। लेकिन यहां ही नहीं, मेक्सिको में और अन्य जगह भी इनके ऊपर घूसखोरी के मुकदमे चल रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, एक कंपनी पर नहीं, अनेक कंपनीज पर। इनका तो सिद्धांत है कि चाहे जैसे भी लूटो और खाओ। गरीब देशों में और घुसो, उनके बाजारों पर कब्जा करो। हिंदुस्तान का रिटेल बाजार अपने आपमें बहुत सक्षम हैं। लाखों-करोड़ों रूपयों का व्यापार यहां आठ से दस प्रतिशत की दर वार्षिक दर से बढ़ रहा है। और यह सैल्फ इम्प्लायड है। यह सरकार की मेहरबानी से नहीं है, यह हिंदुस्तान के नौजवान की हिम्मत और मेहनत से है। वरना आपके पास आकर खटखटा सकता था और ऑक्युपाई दि वालस्ट्रीट की तरह ऑक्युपाई दि पार्लियामेंट स्ट्रीट कर सकता था, लेकिन उसने वह नहीं किया। उसने अपने कंधों पर, अपना पेट पालने और अपने परिवार को पालने के लिए रास्ता चुना है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश भी करेंगे, तो हम लोग जितने यहां हैं, उसे खत्म नहीं होने देंगे, वह खत्म नहीं किया जा सकता, न हिंदुस्तान का किसान, न हिंदुस्तान का मजदूर, न हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी और न हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद, अब आप अपनी बात समाप्त करें। कृपया आसन की मजबूरी भी समझें। आपने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात का समापन किया है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, भगवान के वास्ते कि आप देश के सभी हितों का ध्यान रखेंगे और देश के लिए, आनेवाली पीढ़ी के लिए सोचेंगे, नहीं तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने यह हरकत की कि इस देश में फिर से कारपोरेट गुलामी विदेशों की लाई जाए, तो देश आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी हालत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा।...*(व्यवधान)* हमारे ही हाथमें है, आपके हाथ से निकल गया है। आपका हाथ तो केजरीवाल ने छीन लिया, अब आपके पास बचा ही क्या है।

श्री लालू प्रसाद : मैडम, नेता विरोधी दल ने इस विषय पर चर्चा शुरू करते हुए कहा है।

अध्यक्ष महोदया : मैं शुरू में ही बता देना चाहती हूं कि आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी है, क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री लालू प्रसाद : मैडम, नेता विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं, डटकर विरोध करता हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं...*(व्यवधान)* देखिए, फिर से छेड़छाड़ न करें। आपने वेदना रैली की थी।...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलिए, क्यों हर चीज पर रिएक्ट करते हैं।

श्री लालू प्रसाद : इनका कोई मुंह नहीं है विरोध करने का। ये लोग 2014 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर रंगीन चश्मे से देश को गुमराह कर रहे हैं। नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में देश को बताया कि एफडीआई विकास की तरफ नहीं, देश को गड्ढे में धकेल रहा है। मैं आदर करता हूं अटल जी का, अस्वस्थ हैं। किस मुंह से आप लोगों ने एफडीआई रिटेल में डंका बजा-बजाकर 100 प्रतिशत अनुशंसा किया। वर्ष 2002 के मैनीफैस्टो में आपने यह किया।...*(व्यवधान)* अभी जोशी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे।

मैं बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूं कि आप कितने की विदेशी घड़ी पहने हुए हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपकी तरह से ही पहने हुए हैं

श्री लालू प्रसाद : हमारे पास तो है ही नहीं।...*(व्यवधान)* मैडम, मैं कोई सैलूलर फोन नहीं रखता हूं, ये छाती पर लगाए रखते हैं और जब टेलीफोन आता है तो 100 मीटर दौड़ते हैं कि कहां से आ गया फोन। गांधी बाबा का नाम लेते हैं लेकिन जब मैं रेल मंत्री था तब मैंने देखा कि कोच में गांधी जी की पुरानी तस्वीर रखी थी और वे रेल के तीसरे दर्जे में सफर करते थे। आप किस दर्जे में सफर करते हैं? बीजेपी के नेता जो रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं उनकी इच्छा रहती है कूपे में और यहां गांधी बाबा का नाम लेते हैं। विदेशी गाड़ी में, मर्सिडीज में सफर करते हैं। इनके एक उम्मीदवार जो देश के प्रधान मंत्री होने वाले हैं वे कहते हैं जापान के लोग आओ, विदेशी लोग आओ, आंचल पसार-पसार कर आओ-आओ, विदेशी मेरे यहां कारखाने लगाओ। दीदी को मैं दीदी मानता हूं, अनादृत मत होना, मुझे एक शेर आपको देखकर याद आता है।

"मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना नहीं आता,
आके बनारस में पान खाना नहीं आता।"

मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि मरुआ बोया जाता है या रोपा जाता है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मरुए की बुवाई भी होती है रूपाई भी होती है।

श्री लालू प्रसाद : हुक्मदेव जी, आप हमारे समधी हैं, आप मत बोलिए, मैं इनसे पूछता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : समधी नहीं हैं आप हमारे चचेरे भाई के ससुर हैं।

श्री लालू प्रसाद : ठीक है, कुछ भी हैं हैं तो सही। जोशी जी, आज नौजवानों को, किसानों को पढ़ा रहे हैं। जब आप मंत्री थे तो ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, देश को कहां ले जा रहे थे। मैडम, जो हाई-हील वाला जूता, परिस्तान वाला जूता, अमरीका का जूता और चप्पल, जो पैर के नीचे हम रखते हैं वह कहां बिक रहा है—मॉल में और एयर-कंडीशन में। जो हम खाते-पीते हैं, जिसे हम अनपूर्णा कहते हैं, मांस है, मछली है, अंडा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, बैगन है गोभी है, वह फुटपाथ पर है। आप पिसा हुआ मसाला खाते हैं और हम बिना पिसा हुआ खड़ा मसाला लाकर पीसते हैं। आज देश में मात्र 34:35 प्रतिशत जमीन पर खेती हो रही है। क्यों हो रही है क्योंकि किसानों की उपज को कोई लेने वाला नहीं है। किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे सीधे किसानों को पैसा मिलेगा, बिचौलिए खत्म होंगे और जब किसी पर कोई कमपलशन नहीं है।...*(व्यवधान)*

भारत बंद कर आप लोग बोल रहे हैं। जलेबी नहीं बिकेगी, चाय नहीं बिकेगी। अत्याचार होगा, मारेगा, पीटेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी रिटैल दुकानदारों पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। 100 किस्म की मछली बिकेगी। अब मुलायम सिंह जी के यहां यू.पी. में बिग बाजार है। सब जगह बिग बाजार है। यह जो दुकान खुलेगी...*(व्यवधान)* कपिल सिब्बल जी ढंग से बोल नहीं पाए। जो बात वह कहना चाहते थे, वह अपनी बात ढंग से रख नहीं पाए।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपको ऐसे दोस्त मुबारक हों।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ये हमारे वकील थे।...*(व्यवधान)* ये हमारे बिना फीस के वकील थे। सिब्बल जी ने जो भाषण दिया ...*(व्यवधान)* अरे दिल्ली शहर में यह नहीं खुलेगा। दूर खुलेगा जहां लाखों स्क्वायर फुट जमीन मिलेगी। वहां अपने देश की साग, सब्जी, मांस, मछली और वह नैसकेफे कॉफी जो सब पीते हैं, वहां हर देश की कॉफी रखी रहेगी। गुड़िया सब रखा रहेगा। लेना है तो लो और नही लेना है तो नहीं लो। आपकी मर्जी।...*(व्यवधान)* जहां से लेना है, वहां से आप लीजिए। कोई कमपलशन नहीं है। कोई रोक नहीं है। अगर देश के किसान, हमारा रिटेल वाला, कोई दुकानदार अगर जिस दिन हम लोग देखेंगे कि कोई खतरा आया और अगर यह एंटी हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल सारी दुकानों में आग लगाकर खत्म कर देगा। ...*(व्यवधान)* इसलिए आप ज्यादा गुमराह मत करिए।...*(व्यवधान)* आप बात सुनिए।...*(व्यवधान)* देश में पूंजी आएगी।...*(व्यवधान)* ये लोग हमें बोलने नहीं देंगे। मैडम, आप इन्हें रोकिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्षा महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मेरे पास वक्ताओं की लंबी सूची है जो वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरे लिए ये संभव नहीं कि मैं उनमें से किसी को भी अभी अनुमति दूं, क्योंकि, अब समय आ गया है कि माननीय मंत्री को वाद-विवाद में हस्तक्षेप करना चाहिए। वे सदस्य, जो सभा पटल पर अपना भाषण रखना चाहते हैं, वे अब ऐसा कर सकते है; और ये भाषण कार्यवाही का अंश बनेंगे।

मैं माननीय मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन) **:** अध्यक्ष महोदया, मैं यहां अपना भाषण सभा पटल पर रखने नहीं आया हूं। मैं यहां अपने विचार व्यक्त करने आया हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप पांच मिनट के लिए बोल सकते हैं। माननीय मंत्री; पूर्व प्रधानमंत्री को बोलने दें और फिर हम आगे की कार्यवाही कर सकते है।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : अध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी के दो वक्ता रहे हैं। दो मुख्य राजनैतिक दल हैं। हमें भी दो वक्ताओं की अनुमति दी जानी चाहिए? ये समस्त है ...*(व्यवधान)* माननीय देवेगौड़ा जी को अनुमति दी जानी चाहिए। मेरे विचार से, इनको अनुमति दी जाए. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। मैं इनको अनुमति देती हूं। देवेगौड़ा जी आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह संभव नहीं हैं मेरे पास बहुत लंबी सूची है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : देवेगौड़ा जी, कृपया बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यह संभव नहीं है। आप स्पीच सभापटल पर ले कर दीजिए। यह प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों के भाषण धैर्यपूर्वक सुन रहा हूं। कई वरिष्ठ नेताओं ने तर्क वितर्क दिए हैं। मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं बहुत खुश हूं। मैं खुदरा व्यापार कारोबार में निवेश हेतु बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देने के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं।

1991 में जब देश कई संकटों का सामना कर रहा था, तब आप आर्थिक सुधार से प्रवर्तक थे। देश कर्ज के जाल में फंसने जा रहा था। महोदय, इस प्रकार की स्थिति में आपने देश के सम्मान को बचाने के लिए सोना गिरवी रखने का निर्णय लिया और आर्थिक सुधार लाए।

मेरा इस माननीय सभा में पहला प्रवेश 1991 में हुआ था और मैंने 1991 के अपने भाषण में आर्थिक सुधारों के बारे में कुछ आशंकाएं जताई थीं। मैं उन आशंकाओं पर अभी कायम हूं। इससे हमें कोई सहायता नहीं मिली। कुछ क्षेत्रों, चाहे वह विनिर्माण क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हमें कुछ फायदा हुआ है। 1991 में मैंने स्पष्ट रूप से अपने विचार रखे थे कि नए आर्थिक सुधारों से कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान होगा चाहे यह वैश्वीकरण हो या औद्योगिकीकरण या उदारीकरण।

महोदया, 1991 में सुधारों का पहला चरण आपने कार्यान्वित किया था जब स्वर्गीय, श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। संयुक्त मोर्चा सरकार कार्यकाल बहुत छोटा था। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमने उसमें कुछ सुधार किया। 1998 में, राजग की सरकार आई। पूर्व वित्त मंत्री यहां हैं। जब उन्होंने अपना बजट पेश किया, तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह पूरी गंभीरता से आर्थिक सुधारों

का दूसरा चरण कार्यान्वित करने का रहे हैं। ये शब्द उस समय के माननीय वित्तमंत्री, श्री यशवंत सिन्हा के थे। तो उन्होंने भी इसे कार्यान्वित किया और हमें इसका कुछ फल मिला। कृषि क्षेत्र के बारे में क्या है?

महोदया, राजग सरकार ने चार प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था। क्या वे किसी वर्ष इस लक्ष्य तक पहुंच पाये है? उत्तर है नहीं। बिहार के हमारे वर्त्तमान मुख्यमंत्री उस समय कृषि मंत्री थे।

महोदय आपने भी संप्रग-एक का कार्यकाल पूरा होने पर कहा था ''हमने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है।''

महोदय, जब मैं अभ्यावेदन के साथ आपके पास पहुँच्स था, जो मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था और वही अभ्यावेदन मैंने आपको दिया था। जिसमें मैंने उल्लेख किया था कि इस देश में हमारे किसान किस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं। उस अभ्यावेदन को नाम दिया गया था 'मैग्ना कार्टा' और महोदय, मैंने वही अभ्यावेदन आपको तथा तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री पी. चिदंबरम को दिया था।

महोदय, संप्रग-एक सरकार के आखिरी समय में आपने 72,000 करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी। मैं कहना चाहता कि संभवनत: इसने कुछ किसानों की मदद मिली हो परंतु यह कुछ बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया था जिन्होंने लूट मचाई थी और उसी मुद्दे पर इस महान सभा में चर्चा हुई थी।

महोदय, मैं वित्तीय स्थिति के बारे में अपनी कठिनाई जानता हूं। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण, हम भी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और आप मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. लाना चाहते हैं। महोदय, मेरी अपनी शंकाएं हैं। महोदय, यदि आप मेरी शंकाएं दूर करना चाहते हैं, तो कृपया आप अपने आप कीजिये या माननीय वाणिज्य मंत्री से कराइये। संयुक्त मोर्चा सरकार के वित्त मंत्री भी यहां बैठे हैं। उन्होंने भी उस समय कुछ निर्णय लिए थे। चाहे वे राजमार्ग परियोजनाएं हों, मेट्रो रेल परियोजना हो जिसे बारामूला से लेकर कश्मीर तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था यहां मैं उन सब चीजों की सूची नहीं बता रहा हूं। किन्तु हमारे समय में मैंने कृषि क्षेत्र को नुकसान होने दिया। हमारे समय में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री बुल्फेनस्टीन भारत आए। मैंने रात्रि भोज दिया था। आप भी उसमें उपस्थित थे। डॉ. मोंटेके सिंह अहलूवालिया भी वहां उपस्थित थे। उस समय उन्होंने कहा था ''आप विश्व बैंक और आई.एम.एफ. द्वारा लगाई गईं शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति में मैंने उन्हें बताया था, ''आप केवल अपने ऋण के हकदार हैं, जो आपने भारत में निवेश के लिए दिया है। आप उसका ब्याज लेते हैं। पर जहां तक प्राथमिकता क्षेत्र की बात है, यह हमारे निर्णय पर है कि उस राशि को किस क्षेत्र में उपयोग में लाये।''

हमने कृषि क्षेत्र को अनेक रियायतें दी थीं। आज उस समय वित्त मंत्री थे। इस देश के लोगों ने हमारे बजट को ड्रीम बजट का नाम दिया था।

मैं अखबारों की कतरने निकालकर इस सब चीजों की व्याख्या करने नहीं जा रहा है। पर अपनी अल्प स्मरणशक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इस सभा पेश किए प्रथम बजट को ड्रीम बजट कहा गया था। यहाँ तक कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी प्रसंशा की थी।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद देवेगौड़ा जी।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यदि आप मुझे अनुमति नहीं देना चाहती हैं तो मैं बैठ जाऊंगा,

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको अनुमति देना चाहती हूं, किन्तु हमारे पास समय की कमी है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं जानता हूं कि मेरी पार्टी के तीन सदस्य हैं; और आपने मेरा नाम अपराह्न 4.30 बजे पुकारा यद्यपि मैंने बोलने के लिए दो दिन तक प्रतीक्षा की। इसी प्रकार, सर्वदलीय बैठक के बारे में, श्री कमल नाथ जी ने मुझसे अनुरोध किया और मैंने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया यह पहली बार था कि मैं किसी सर्वदलीय बैठक में आया। किन्तु वहां पर भी मैं अंत में बोलने वाला व्यक्ति मैं ही था।

माननीय वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। जहां तक देश में मल्टी ब्राण्ड खुदरा क्षेत्र का संबंध है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं इसके बिल्कुल विरूद्ध हूं। मैंने सभा को अपने सारे तर्कों, अपनी सारी आशंकाओं के साथ समझाने का प्रयास किया है।

मैं उस समय हमने जो किया उसका एक संदर्भ देता हूं। आपने हमें सुझाव दिया था। 1994 में और उस समय मैं मुख्यमंत्री था,

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

मैं भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम लाया अन्यथा कर्णाट में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। इसके साथी ही, मैंने नियमों में शर्ते लगाई थी कि उन निवेशकों को भूमि कैसे दी जानी चाहिये। इस अधिनियम में भूमि की लूट की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली बार मुख्यमंत्री, के रूप में श्री देवराज अर्स यह अधिनियम लाए। मैं उन सभी बातों को पढ़ सकता हूं कि हमने क्या निर्णय लिए थे। हमने संशोधन किया और एक व्यापक भूमि सुधार अधिनियम लाये। श्री मोइली जी यहां बैठे हैं। वे जानते हैं। यह सबसे पहले स्वर्गीय, देवराज अर्स लाया गया था। कृषि से बाहर बारह हजार रूपए कमाने वाले किसी को भी भूमि लेने की अनुमति नहीं थी। वह श्री देवराज अर्स द्वारा लाया गया व्यापक भूमि सुधार विधेयक था। इसमें मैंने संशोधन किया ताकि विभिन्न देशों के कथित निवेशक आ सकें। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।

विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में, कोजेट्रिक्स का क्या हुआ और एनरॉन का क्या हुआ? एनरॉन का व्यक्ति जेल में है, जिसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मैं कई दृष्टांत बता सकता हूं।

महोदया, भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक लाते समय मुझे बड़ी तकलीफ हुई और हमने बहुत स्पष्ट से नियम बनाए कि कोई व्यक्ति जो मेरे राज्य में निवेश करने के लिए आना चाहता है उसे अपेक्षित भूमि मिल सकती है। हमने स्पष्टतः पूछा कि रोज़गार सृजन कैसा होगा मैंने नियमों के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की और हमने कहा कि ये सब बातों का उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये, पर इन सभी चीज़ों की अनदेशी की गई है और बहुत सारी चीजे़ हो रही हैं। बंगलौर-मैसूर अवसंरचना गलियारे में क्या चल रहा है? यमुना एक्सप्रैसवे में क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कृपया समय दे, मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदया : देवेगोड़ा जी नाराज न होइये।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : हम सभा को आश्वस्त करना चाहते थे।

अध्यक्षा महोदया : हमारे पास समय की कमी है। हमें इसे समय के भीतर पूरा करना है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आज दिल्ली-जयपुर एक्सप्रैसवे सात टाऊनशिप के बारे में समाचार छपा है। मैं तर्क कर सकता हूं। कर्णाटक में क्या हुआ? मैंने भूस्वामियों के कष्ट के बारे में बहुत सारे पत्र लिखे। आज भू संपदा के से एक वरदान है। 1991 से विभिन्न अवसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए कितनी भूमि ली गई है? कितनी कृषि योग्य क्षेत्र कम हो गई है? भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों का क्या प्रभाव पड़ा है? कितने छोटे भूमि स्वामी है? आप इसके बारे में तकी कर रहे थे। वहां कितने छोटे भू-स्वामी-उन्हें आप क्या लाभ देने जा रहे हैं? आप उनका कैसे पुनर्वास करने जा रहे हैं? में इन सब बातें पर चर्चा कर सकता हूं पर मेरे पास समय नहीं है।

मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। एक किसान के रूप में, एक कृषक के रूप में अपने अनुभव से मैं इस देश में मौजूद समस्याओं को समझता हूं। इतने सारे किसानों ने आत्महत्या क्यों की? क्यों? क्या वे स्वयं ही आत्महत्या करना चाहते हैं? क्या किसी कार्पोरेट घराने अथवा कथित बड़े व्यवसायिक धरानों में से किसी ने आत्महत्या की है? मैं नहीं जानता। मैं यह बता सकता हूं कि कार्पोरेट घरानों में हमनके कितना पैसा लगाया। हमने उन कार्पोरेट घरानों को उस समय बैंक सहायता दी थी जब वे बिखरने के कगार पर थे। मैं बता सकता हूं कि हमने उन्हें कितना पैसा दिया था।

जब महोदया इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण्ण किया था, उस समय भी प्राथमिकता वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र ही था। बैंकों को उनके ऋणों का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने के लिए कहा गया था। किस बैंक ने 18 प्रतिशत दिया?

महोदया, आप उस समय वित्त मंत्री थे। मैंने ये सभी आंकड़े अद्धत किए हैं लेकिन मैं यह सिद्ध करने के लिए कितने भी मुद्दे उद्धत कर सकता हूं कि यह गरीब किसानों को किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। रोजगार सृजन के लिए आप कहां जाएंगे? रोजगार तब सृजित हुआ था जब आपने आर्थिक सुधार आरंभ किए थे। निवेशकों द्वारा ठेका मजूरों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले लोगों को 3000 रुपए, 4000 रुपए मिलेंगे। जब मैं हवाई जहाज से उतरा तो लोग दरवाजे तक आ गए।

यदि मैं उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछता हूं तो वे कहते हैं, मैं बी.एस.सी. हूं, मैं बी.ए. फेल हूं। उन्हें क्या मिल रहा है? 4000 रुपए अथवा 3500 रुपए।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

अब, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ा : मैं विरोध में बोलूंगा...*(व्यवधान)* ऐसा आपके प्रस्ताव के कारण नहीं है। जो कुछ हुआ, मैं उसके बारे में तर्क कर सकता हूं। श्री वाजपेयी के शासन के दौरान कितने लोगों ने आत्महत्या की थी? मैं 2000 लोगों को रेलगाड़ी से लाया था। इस देश में लाखों लोग मरते रहे हैं...*(व्यवधान)* मुझे बिना वजह न भड़काएं।

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाएं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : जब मैंने किसानों की समस्याओं के बारे में महाधिकार पत्र प्रस्तुत किया तब मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। श्री वाजपेयी जी वहां मौजूद थे। एक अन्य राज्य मंत्री भी वहां मौजूद थे। कृषि मंत्री के रूप में श्री अजीत सिंह भी वहां उपस्थित थे। मैंने हाथ जोड़कर वाजपेयी जी से प्रार्थना की थी कि मैं अकेला आदमी हूं। मैं आपकी सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाउंगा। कृपया किसानों को बचा लीजिए। उन्होंने कहा, कुछ करेंगे, क्या हुआ? *[हिन्दी]* बाद में मरेगा, कुछ करेंगे बाद में *[अनुवाद]* क्या हुआ *[हिन्दी]* मरेंगे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात पहली बार आप आन्ध्र प्रदेश में उस किसान के घर गए जिसने आत्महत्या की थी। आन्ध्र प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदया, वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनके बोलने के दौरान नहीं बोलना चाहता।

अध्यक्ष महोदया : मैं जानती हूं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मैंने किसानों की समस्याएं समझने के लिए कृषि संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह किसी पारिश्रमिक के लिए नहीं है। चिदंबरम जी, मैंने समिति के सभापति से भी इस विषय पर चर्चा की थी। नाबार्ड अध्यक्ष का कहना है कि आन्ध्र प्रदेश में केवल मौखिक पट्टेदारी है। हम किसानों को कोई ऋण नहीं दे सकते। शरद पवार जी यहां उपस्थित हैं जो कृषि मंत्री हैं, वहां केवल मौखिक पट्टेदारी है। आप उन्हें कोई ऋण नहीं दे सकते, वे क्या कर सकते हैं? प्रतिवर्ष आप कृषकों के लिए ऋण घटक में वृद्धि कर रहे हैं और यह 5,82,000 करोड़ रुपए है, लेकिन यह धन कहां जाएगा?

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद, देवगौड़ा जी। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : कुछ राज्यों में भूमि सुधार क्रियान्वित नहीं किए गए हैं। वे जमींदार हैं। मैं प्रधानमंत्री को जानकारी दे सकता हूं। मैं संप्रग-दो के अध्यक्षा के पास भी जा सकता हूं और किसी को भी आश्वस्त कर सकता हूं। यदि मैं गलती कर रहा हूं तो मैं अपने में सुधार करूंगा। कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि इससे आर्थिक स्थिति बच जाएगी। मैं कहता हूं इससे किसी की भी सहायता नहीं होगी। हमारे गरीब किसानों की सहायता करने के लिए अपना धन लगाने कोई यहां नहीं आ रहा है। हमारा आयात हमारे निर्यात से अधिक होगा क्योंकि उपभोक्ता वस्तुएं चीन और अन्य देशों से आएंगी। जैसा कि लालू जी ने काह है, सभी वस्तुएं खरीदनी होंगी। इसका कारण यह है कि उन निवेशकों के लिए भारतीय बाजार बहुत आकर्षक है। वे यहां धमार्थ नहीं आए हैं, वे अधिकाधिक फायदा और लाभ कमाना चाहते हैं। यही कारण है कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं इस प्रस्ताव का पूर्णरूपेण विरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : मैं खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का सरकार के निर्णय के खिलाफ हूं और मैं मांग करता हूं कि इस निर्णय को शीघ्र ही वापस लिया जाए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश देश के लिए घातक एवं विनाशक रहेगा। जैसे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी वयापार के लिए आई थी मगर हम सब जानते हैं कि इसके जरिए हम दो सौ साल गुलाम रहे थे। मैं समझता हूं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी के निवेश से देश का किसान, उपभोक्ता, युवा, गरीब एवं सभी वर्गों के लोग बेहाल हो जाएंगे।

मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि एक साल पहले जब सरकार 51 फीसदी खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का प्रस्ताव लाई थी तब समुचित विपक्ष एवं देशवासियों के विरोध पर वित्तमंत्री और लोकसभा के नेता ने भरोसा जताया था कि ये निर्णय सभी स्टेक होल्डर्स, यानि कि समूचे विपक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में ले के ही किया जाएगा।

मुझे खेद इस बात का है कि सरकार ने सदन में दी हुई बात से पलट कर, चुपचाप निर्णय लागू कर दिया है। यह सदन का लोकतंत्र और प्रजा से द्रोह है। मैं समझता हूं कि यू.पी.ए.-2 सरकार होश में नहीं है और बहक गई है। ये सरकार अल्पमत में होते हुए भी, कुछ प्रादेशिक पक्षों की मजबूरियां और सी.बी.आई. के दुरुपयोग की वजह से बहकावे में आ गई है।

इसकी वजह से बेरोजगारी हो जाएगी। कृषि के बाद रोजगार देने में खुदरा व्यापार क्षेत्र कुल रोजगार का 7.2 फीसदी रोजगार देता है, जो कुल मिलाकर 33 करोड़ से भी ज्यादा रोजगारी देता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) रिपोर्ट, 2010 के अधिकृत आंकड़े है।

दूसरा खतरा यह है कि एफ.डी.आई. की वजह से अस्वस्थ कंप्टीशन होगा, जसिका मुआवजा छोटे-छोटे किराने की दुकानवाले, लारी और गल्ले वाले गरीब को भुगतना पड़ेगा। वालमार्ट जैसी राक्षसी कंपनियां उनको निगल जाएंगी। इसकी वजह से पूरे के पूरे कुटुंब का रोजगार तबाह हो जाएगा। एफ.डी.आई. की वजह से असंगठित मजदूर, जो बड़ी संख्या में हैं वो बेकार हो जाएंगे। कोई भी नीतिगत निर्णय के तहत अगर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हाशिए में चले जाते हैं तब हमें ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए। जब तक उन लोगों को रोजगार सुनिश्चित नहीं किया जाए।

ये बड़े वालमार्ट जैसे रिटेलर शुरूआत में कम दामों पर छोटे-छोटे दुकानदार एवं किराने वालों को बाहर कर देंगे और जब व्यापार में उनका दबदबा और मोनोपोली होंगी तब उपभोक्ताओं को अपनी रकम पर मेगा माल बेचकर मजबूर करेंगे। साथ-साथ चाइना घुसने पर किसानों और मेन्युफेक्चरर को अपने भाव का सस्ता माल बेचने पर भी मजबूर करेंगे। यानि कि दोनों एंड परवो भारी मुनाफा लेके सबको लूटेंगे।

ये लोग एक और बेरोजगारी पैदा करें गे साथ-साथ युवा वर्ग का शोषण करके, बहुत कम पगार पर कुछ नौकरियां देकर उनको सेल्समेन और सेल्सगर्ल तक ही सीमित कर देंगे।

इसकी वजह से अपने छोटे-छोटे मेन्युफेक्चर्स की जगह ये वालमार्ट जैसे स्टोर्स चाईना से बड़े पैमाने पर सस्ते दाम पर, घटिया सामान लाकर भारत के बाजार में बेचेंगे। मेरा मानना है कि भारत के बाजार में चीन का सस्ता और घटिया माल बेचा जाएगा और भारतीय उत्पादक तबाह हो जाएगा।

ये सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अभी-अभी समाचार आए थे कि वालमार्ट को भारत में घुसाने को इनके द्वारा बड़ी मात्रा में घूस दी गई है। जब ये सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है तब ये मामला बड़ा गंभीर है और सरकार की मंशा पर अनेक सवाल खड़ा करते हैं।

अत: मैं प्रजा विरोधी तथा अमेरिकी दबाव में लिए गए ये खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय शीघ्र ही वापस लिया जाए।

[अनुवाद]

***श्री पी. करूणाकरन** (कासरगोड) : मैं सरकार द्वारा खुदरा व्यापार में 51% एफ.डी.आई. की अनुमति देने के निर्णय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। पहले दिसंबर, 2011 में दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी थी। सभी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था और सरकार आगे बढ़ने के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकी थी। लेकिन, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने सदन में कहा था कि सरकार सभी राजनीतिक दनों की सहमति के बिना इसे क्रियान्वित नहीं करेगी और सरकार को पणधारकों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विचार-विमर्श आरंभ कर देना चाहिए। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा ने राज्य सभा में भी यही वक्तव्य दिया था।

लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है लेकिन सरकार ने आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है। पांच दिन व्यर्थ हो चुके हैं क्योंकि सरकार अनुच्छेद 184 के अंतर्गत चर्चा कराने के प्रति उदासीन है। अध्यक्ष महोदया की मेहरबानी से अब हम अनुच्छेद 184 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने इन 5 दिनों का प्रयोग अन्य दलों से किसी भी कीमत पर समर्थन प्राप्त करने के लिए किया है। लेकिन फिर भी इस सभा में राजनीतिक दलों ने निर्णय ले लिया है कि उनमें से अधिकांश इसका समर्थन नहीं करेंगे। बाहर से सरकार का समर्थन करने वाले एस.पी. और बी.एस.पी. जैसे दलों ने भी सदन में स्पष्ट कर दिया है कि वे खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. के विरुद्ध करेंगे अथवा नहीं, यह अलग मुद्दा है। इस सरकार का समर्थन करने वाले दल डी.एम.के. ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. के पक्ष में नहीं हैं लेकिन सरकार गिराने के लिए भी तैयारी नहीं है। संप्रग का निकट सहयोगी, टी. एस.सी. पहले ही एफ.डी.आई. का विरोध करने का निर्णय ले चुका है। समूचा राजग और अन्य सभी वाम दल विरोध कर रहे हैं। फिर सरकार के यह कहने का क्या औचित्य है कि उसके पास बहुमत है। कुछ दल जो एफ.डी.आई. का कड़ा विरोध कर रहे हैं, वे कभी मतदान से अनुपस्थित रह सकते है अथवा कभी केवल इस कारण से सरकार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं कि वे सरकार नहीं गिराना चाहते। इस प्रकार, 2011 में भी हुई चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसद सरकार के इस कदम के विरुद्ध है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए तर्क निराधार हैं कि यह अधिक रोज़गार के अवसर देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बढ़ावा देगा। यहां तक कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी वे इस प्रकार की बड़ी कंपनियों के कारण सम गंभीर समस्या का सामना कर रहे है और रोज़गार खो रहे हैं। अत: वे स्वयं अब खुदरा व्यापारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह कहना विश्वासजनक नहीं है कि आने वाली वॉलमार्ट और अन्य बड़ी कंपनियां अधिक रोज़गार के अवसर लाएंगी पर यह सत्य है कि वे वर्तमान रोज़गार अवसरों को कम कर देंगी क्योंकि वे इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। लगभग चार करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और कर्मचारियों व परिवार के सदस्यों की संख्या 25 से 30 करोड़ के बीच होगी। रोज़गार के अभाव में ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे।

अगला मुद्दा किसानों को बढ़ावा देने का है। पिछले कई सालों से सरकार नई उदार नीतियां लागू कर रही है। यहां तक कि रिपोर्टों के अनुसार कृषि क्षेत्र में भी ढ़ाई लाख से अधिक किसानों ने कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट के कारण आत्महत्या कर ली है। उन्हें सहायता देने के लिए सरकार कोई ठोस प्रयास नहीं कर पाई/यहां वॉलमार्ट और अन्य कंपनियों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है कर्मचारियों को रोज़गार देना नहीं। पश्चिमी देशों में भी यह सिद्ध हो चुका है।

इतना कड़े कदम उठाने के पीछे सरकार का मंतव्य क्या है, जैसा कि कुछ अन्य सदस्यों ने बताया कि एक ओर तो वे राजकोषीय धाटा कम करना चाहते हैं तो दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना जो अंतत: परिस्थिति और खराब करेगा।

सरकार ने 2011 में सदन में दिए गए आश्वासन का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया है। यद्यपि वे कभी-कभी अस्थायी रूप से और तकनीकी रूप से ठीक हो सकते हैं, परंतु अंतत: यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल देगा और वह संप्रग के लिए भी विनाशकारी भविष्य होगा।

***श्री खगेन दास** (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं भारत में बहु ब्राण्ड खुदरा खोलने के सरकार के निर्णय का सख्त विरोध करता हूं। न केवल भाजपा के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार ने 2002 यह कदम उठाया था, परन्तु विरोधी दबाव के कारण इसे त्याग दिया वामपंथी दलों ने इसका उस समय विरोध किया बल्कि कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने भी उसे 'राष्ट्र विरोधी' बताया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देश में बहुराष्ट्रीय खुदरा कम्पनियों को अपने स्टोर खोलने देने का सरकार का निर्णय ''राष्ट्रविरोधी'' और ''जन विरोधी'' है।

यहां तक कि जब कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर दोगलेपन और अवसरवादिता के आरोप लगाती हैं वही ध्यान देने वाली बात यह है कि वाम दलों ने हमेशा इस मुद्दे पर एक सिद्धांतपूर्ण पक्ष लिया है और निरन्तर बहु ब्राण्ड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. का विरोध किया है।

''संसदीय स्थायी समिति'' ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ''बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए इस क्षेत्र को खोलना अत्यधिक विनाशकारी होगा और सरकार को इस नीति से परहेज़ करना चाहिए।''

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री खगेन दास]

जब श्री प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सोचा था कि इस निर्णय को स्थगित किया जाएगा और अन्य दलों के साथ परामर्श के द्वारा एक मतैक्य बनाया जाएगा। पर सितम्बर 2012 में सरकार द्वारा एक-पक्षीय निर्णय लिया गया। यह लोकतांत्रिक संस्थान प्रणाली के लिए अत्यधिक अशिष्ट है। हमारे पास क्या आर्थिक स्वतंत्रता रह जाएगी यदि वॉलमार्ट रेस्को और केअरफॉर जैसी विदेशी कम्पनियां हमारे बाज़ारों पर कब्जा कर लेंगी?

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेताओं की स्मृति अल्प है या वे साम्राज्यवादी दबाव के अंतर्गत देश के लोगों को जानबूझकर परदे में रखना चाहते हैं।

यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं कि सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घनिष्ठ संबंध है और वे किसी भी कीमत पर इस निर्णय को लागू करना चाहते हैं।

1. हम समझते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप आदि में आर्थिक मंदों और प्रचण्ड प्रतियोगिता के कारण और उसके परिणामस्वरूप उनके लाभ में कमी ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हरी चारागाहों ढूंढने के लिए मजबूर किया और उन्होंने भारत को एक उपयुक्त गंतव्य पाया है।

2. विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने से भ्रष्टाचार में वृद्धि होना स्वाभाविंक था और यह एक खुदरा कम्पनी की बेलेंस सीट से स्पष्ट है। जिसका दावा है कि उसने भारतीय प्रचालनों के लिए परमित प्राप्त करने हेतु 53 लाख यू.एस. डॉलर खर्च किये।

3. एफ.डी.आई. के लिए खुदरा क्षेत्र को खोलने का निर्णय उन 3.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा जो छोटी दुकानें चलाते हैं या कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं और अन्य 1.5 करोड़ लोगों को भी प्रभावित करेगा जो थोक व्यापार, परिवहन, भंडारण इत्यादि धंधे करते हैं। सम्पूर्ण रूप से 5 करोड़ लोग और लगभग 20 करोड़ परिवार जन अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।

4. एक करोड़ नौकरियां सृजित करने का सरकार का दावा ''स्पष्ट झूठ'' है- 10 मिलियन नौकरियां- हंसी आती है- यह अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा की देन है। जिससे विश्व में गत तीन दशकों से बेरोजगारी की वृद्धि हुई है।

भू संपदा क्षेत्र राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने का महत्वपूर्ण अंग है। आज हमारे नीति निर्माता ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे हमारे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार दिला सके।

इन परिस्थितियों के अंतर्गत सरकार के पास यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वह इस क्षेत्र में पहले से नियोजित (अधिकांशतः स्व-नियोजित) लोगों को विस्थापित करे।

आधारभूत वास्तविकता और छोटी किराना दुकानों को होने वाले नुक्सान का आकलन किए बिना सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारों पर नाच रही है।

वॉलमार्ट और अन्य यहां दान के लिए नहीं आते, वे यहां अपने लाभ के लिए भारतीय खुदरा बाजार पर कब्जा करते आते है।

5. नब्बे के दशक की शुरूआत से ही नव उदारवादी वैश्वीकरण से छोटे किसानों को होने वाले फायदे के बारे में बड़े-बड़े दावे किए गए हैं। अनेक कदम उठाए गए जिसमें बीज जैसे क्षेत्रों में 100% एफ.डी.आई. शामिल है। सबके विपरीत परिणाम हुए।

इन कदमों ने किसानों की ऋणता दोगुनी कर दी और आत्महत्याओं की आज तक की सबसे बड़ी लहर को उक्साया/इसके अतिरिक्त हमने एक दशक में साढ़े सात लाख लोगों को कृषि छोड़ते हुए देखा-जिसमें से अनेकों ने किसानों को 'लाभ' पहुँचाने वाली नीतियों के कारण इसका त्याग किया।

6. यदि सरकार यह दावा करती है कि खुदरा व्यापारी भंडारण और शीतलगारों जैसी ग्रामीण अवसंरचनाएं उपलब्ध कराऐंगे तो यह पूर्णतः भ्रामक है क्योंकि भंडारण और शीतलगारों में एम. डी.आई. को एक दशक पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। परंतु इस क्षेत्र में किसी विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं किया जा सका।

अवसंरचना का प्रावधान सरकार की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता के छः दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी सरकार भंडारगृहों और शीतलगारों के रूप में अवसंरचना उपलब्ध करवाने में बुरी तरह नाकाम रही है।

7. यदि सरकार यह सोचे कि बहुराष्ट्रीय खुदरा कम्पनियां खाद्यान्न बर्बादी को कम करेंगी, तो यह उनकी गलतफहमी है। खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने कहा है कि संगठित क्षेत्र (सुपर

मार्केटस) गुणवत्ता के प्रति अधिक संचेत दिखाई देने के लिए कृषि उपज का एक बड़ा भाग खेतों में ही अस्वीकृत कर देते हैं।

एफ.ए.ओ. के अनुसार किसानों द्वारा सीधे ग्राहकों या दुकानों के खाद्य वस्तुओं की बिक्री खाद्यान्न बर्बादी का समाधान है।

8. बहुराष्ट्रीय निकायों ने 1960 के दशक में खुदरा व्यापार में आगमन किया। सिर्फ चार दशकों में ही इन कंपनियों ने अनेक देशों विशेषकार विकसित और विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गहरी पैठ स्थापित कर ली है। वॉलमार्ट, टेस्को, केरफोर इत्यादि जैसे विशाल निकायों की आय विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय को भी पार कर चुकी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का नब्बे प्रतिशत खुदरा व्यापार, अधिकांश यूरोपीय देशों का 80% खुदरा व्यापार, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का 50-60% खुदरा व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में चला गया है।

अधिकांश खुदरा व्यापारियों ने अपनी आजीविका खो दी है क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चके हैं।

अत: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इस क्षेत्र को खोलने का निर्णय छोटे व्यापारियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकतर अपनी खरीदारी वैश्विक स्तर पर करती हैं। इसलिए अगला क्षेत्र जो प्रभावित होगा वह है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्र।

9. यू.एस.ए. में वॉलमार्ट के आगमन के बाद वास्तव में अधिकतर उपभोक्ता सामान उद्योग बंद हो चुके हैं। विश्व का प्रसिद्ध जूता उद्योग अब अस्तित्व में नहीं है क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिकी जूते नहीं खरीदती हैं।

इग्लैंड की प्रसिद्ध कपड़ा बनाने वाली कंपनी अब व्यापार में नहीं है क्योंकि ये कंपनियां इंगलैंड से कपड़ा नहीं खरीदती हैं।

10. राष्ट्रव्यापी बंद, विरोध, प्रदर्शन, संसद में गतिरोध, सरकार के सहयोगी दलों द्वारा कड़ा और निरन्तर विरोध, विपक्षी दल, व्यापारी, मजदूर संगठन एवं अन्य सामाजिक संगठन सरकार के मल्टी ब्राण्ड खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को 51% तक खोलने के निर्णय के विरुद्ध है, ये सब दर्शाता है कि राष्ट्र ने सरकार के जन-विरोधी निर्णय को ठुकरा दिया है।

हमारा दल सरकार की हानिकारक नीति के खिलाफ लोगों को संघटित करेंगी।

हम एक भी वॉलमार्ट शॉप नहीं खुलने देंगे।

हम उन्हें भारत में कोई जगह नहीं देंगे।

हमारा नारा होगा "वॉलमार्ट रोको"

हमारे दल और वाम दलों ने दृढ़ निश्चय से इस प्रस्ताव का विरोध किया है और हमारी मांग है कि सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए।

[हिन्दी]

***डॉ. किरोड़ी लाला मीणा** (दौसा) : ऐसे समय जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुदरा कारोबार में एफडीआई खोलने के फैसले को देश-हित में बताते हुए इसे वापस लेने से इंकार कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राय इससे उलट है। 26 नवम्बर को उन्होंने ट्वीट किया--अपनी पसंदीदा स्थानीय दुकान से सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों का समर्थन करें। ओबामा अपने देश के हित की बात कर रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह अमेरिकी हितों को सुरक्षित करने की। मनमोहनसिंह की यह दलील तथ्यों पर खरी नहीं उरती कि रिटेल एफडीआई से हमारे देश को फायदा होगा, ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं में सुधार होगा, कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी और हमारे किसान अपनी फसल के बेहतर दाम हासिल कर सकेंगे। परेशानी की बात यह है कि वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दलीलों का कोई आर्थिक आधार नहीं है। इनकी महज राजनीतिक उपयोगिता है। इनसे यही पता चलता है कि सत्ताधारी दल के राजनीतिक एजेंडे को न्यायोचित ठहराने के लिए आर्थिक तथ्यों को किस तरह तोड़ा-मरोड़ा और गढ़ा जा सकता है।

मल्टी ब्रांड रिटेल के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह है कि इससे सन् 2020 तक एक करोड़ रोजगार पैदा होंगे। इस दावे के पीछे कोई तर्क नहीं है। अमेरिका में रिटैल कारोबार में वालमार्ट का वर्चस्व्व है। इसका कुल कारोबार चार सौ अरब डॉलर (लगभग 20 लाख करोड़ रुपये) है, जबकि इसमें महज 21 लाख लोग काम करते हैं। विडंबना है कि भारत का कुल रिटेल क्षेत्र भी 20 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि इसमें 4.40 करोड़ व्यक्ति काम करते

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. किरोड़ी लाला मीणा]

हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय रिटेल कहीं बड़ा नियोक्ता है और वालमार्ट सरीखे विदेशी रिटेलरों को भारत में बुलाने से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इंग्लैंड में दो बड़ी रिटेल चेन टेस्को और सेंसबरी है। दोनों ने पिछले दो वर्षों में 24,000 रोजगार देने का वायदा किया था, जबकि इस बीच इन्होंने 850 लोगों को नौकरी से निकाल दिया।

सररकार का कहना है कि रिटेल एफडीआई से किसानों की आमदनी 30 प्रतिशत बढ़ जाएगी। इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए अगर वालमार्ट किसानों की आमदनी बढ़ाने में सक्षम होती तो अमेरिकी सरकार को यूएस फार्म बिल 2008 के तहत 307 अरब डॉलर (करीब 15.35 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम सब्सिडी नहीं देनी पड़ती। इनमें से अधिकांश सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में जोड़ी जाती है। अगर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वापस ले ली जाती है तो अमेरिकी कृषि का विनाश हो जाएगा। 30 धनी देशों के समूह की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इन देशों में 2008 में 21 फीसदी और 2009 में 22 फीसदी सब्सिडी बढ़ गई है। केवल 2009 में ही इन औद्योगिक देशों ने 12.6 लाख करोड़ रुपये की कृषि सब्सिडी दी है। इसके बावजूद यूरोप में हर मिनट एक किसान खेती छोड़ देता है। यह इसलिए हो रहा है कि वहां किसानों की आय लगातार गिर रही है। केवल फ्रांस में 2009 में किसानों की आमदनी 39 फीसदी गिर गई है।

सरकार की तीसरी दलील है कि बड़ी रिटेल कंपनियां बिचौलियों को हटा देती है, जिस कारण किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। एक बार फिर यह झूठा दावा है। अध्ययनों से पता चलता है कि बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में अमेरिका में प्रत्येक डॉलर की बिक्री पर किसान को 70 सेंट बच जाते थे, जबकि 2005 में किसानों की आमदनी महज 4 फीसदी रह गई है। यह वालमार्ट और अन्य बड़े रिटेलरों की मौजूदगी में हुआ है। दूसरे शब्दों में जैसा कि आम धारणा है, बड़े रिटेलरों के कारण बिचौलिए गायब नहीं होते, बल्कि बढ़ जाते हैं। नए किस्म के बिचौलिए पैदा हो जाते हैं, जैसे गुणवता नियंत्रक, मानकीकरण करने वाले, सर्टिफिकेशन एजेंसी, प्रोसेस, पैकेजिंग सलाहकार आदि इसी रिटेल जगत के अनिवार्य अंग होते हैं और ये सब किसानों की आमदनी में से ही हिस्सा बांटते हैं। यही नहीं, बड़े रिटेलर किसानों को बाजार मूल्य से भी कम दाम चुकाते हैं।

उदाहरण के लिए इंग्लैंड में टेस्को किसानों को चार फीसदी कम मूल्य देती है। सुपरमार्केटों के कम दामों के कारण ही स्कॉटलैंड में किसान 'फेयर डील फूड' संगठन बनाने को मजबूर हुए हैं।

चौथी दलील यह कि रिटेल एफडीआई छोटे व मध्यम उद्योगों से 30 प्रतिशत माल खरीदेंगे और इस प्रकार भारतीय निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। यह लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। सच्चाई यह है कि विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत भारत किसी भी बड़े रिटेलर को कही से भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है और कोई भी सदस्य देश इसका उल्लंघन कर जीएटीटी 1994 की धारा 3 या धारा 11 के तहत निवेद प्रतिबंध झेलने की मुसीबत मोल नहीं ले सकता। विश्व व्यापार सं गठनों के प्रावधानों का इस्तेमाल कर मल्टी ब्रांड रिटेल सस्ते चीनी उत्पादों से बाजार पाट देंगे और छोटे भारतीय निर्माताओं को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। निवेश नियमों की आड़ में रिटेलर भारत में खाद्यान्न भंडारण व परिवहन आदि का बुनियादी ढांचा भी खड़ा करने नहीं जा रहे हैं। नियम के अनुसार कंपनियों के मुख्यालय में होने वाला खर्च भी भारत में निवेश में जुड़ जाएगा। इस प्रकार भारत में एक भी पैसा निवेश किए बिना ही रिटेल एफडीआई 50 प्रतिशत से अधिक निवेश कर चुके पेनसिलिवेनिया यूनिविर्सिटी के अध्ययन वालमार्ट और गरीबी से पता चलता है कि अमेरिका के जिन राज्यों में वालमार्ट के स्टोर अधिक है उनमें गरीबी दर भी अधिक है। यह ऐसे देश के लिए खतरे की घंटी है जिसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी, भुखमरी और मलिनता में जीवन बिता रही है।

यह तर्क मूर्खतापूर्ण है कि अभी के खुदरा बाज़ार में बिचौलियों की संख्या अधिक है और इसलिए उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते चीजों की कीमत बढ़ जाती है। यह भी सामान्य सिद्धांत है कि बाजार में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, दाम उतने ही कम होंगे। अभी के खुदरा बाजार में करोड़ों लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। जो न्यूनतम मुनाफे पर वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। मुनाफा इसलिए भी कम है कि व्यापार की लागत कम है। खुदरा बाजार पटरी से लगा कर छोटी और मझोली दुकानों तक फैला है। उनमें घुसने के लिए कम पूंजी, साधारण कुशलता और अपार मेहनत चाहिए, जो देश के

बहुसंख्यक लोगों में है। अब तक देश ने जो भी स्मृद्धि पाई है वह अपने साधारण लोगों की मेहनत के बल पर ही पाई है। जिसे हम आधुनिक तकनीक कहते हैं उसका देश को समृद्ध बनाने में योगदान नगण्य है।

अगर तथाकथित आधुनिक क्षेत्र ने देश का कुछ भला किया होता तो खेती और कारखानों का अब तक कायाकल्प हो गया होता। भारत में कृषि वैज्ञानिकों की संख्या किसी भी और देश के मुकाबले अधिक ही बैठेगी। लेकिन खेती की आधुनिक तकनीकों ने खेती की लागत जितनी बढ़ा दी है, उतनी उत्पादकता नहीं बढ़ाई। भारत के पास दुनिया की सबसे उर्वर धरती, सबसे बड़ा, कृषियोग्य क्षेत्र, पर्याप्त धूप और प्रबंध ठीक कर ले तो पर्याप्त जल है। उसके बाद भी हमारे यहां अनाज की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घटती ही जा रही है।

तकनीकी कुशलता के मामले में भारत के साधारण कारीगरों की ख्याति रही है। कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की उन्हें आदत रही है। फिर भी औद्योगिक क्षेत्र का जिस गति से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। दुनिया में सभी जगह आर्थिक प्रगति खेती और उद्योग के भरोसे होती हैं। हमारे यहां वह सेवा क्षेत्र के भरोसे है। अपने जीवन में सादगी बनाए रख कर ही लोग महंगी होती जा रही अर्थव्यवस्था में अपने आप को टिकाए हुए हैं।

जिस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना जीवनयापन सेवा क्षेत्र में ही तलाशना हो, उसमें कोई खुदरा क्षेत्र को बड़ी कंपनियों के हवाले करने की सोचे यह विचित्र लगता है। इसका मतलब है कि आपको देश के साधारण लोगों की चिंता नहीं है। लेकिन यह केवल रोजगार का मामला नहीं है, जैसा कि सरकार और विपक्ष दोनों ने बना दिया है। यह दो भिन्न जीवन प्रणालियों और दो भिन्न सभ्यताओं का मामला भी है। भारत में खुदरा व्यापार लोगों को रोजगार ही नहीं देता, स्वतंत्र जीवनयापन की सुविधा भी देता है। खुदरा व्यापार एक ऐसा कौशल है जो सीखने के लिए मोटी फीस देकर किसी शिक्षा संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने परिवार या आसपास की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वह देश के सबसे साधारण लोगों की पहुंच में है। अगर यही व्यापार बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाए तो उनमें मिलने वाला रोजगार नौकरी होगा, जो अपनी स्वतंत्रता किसी को सौंप कर ही प्राप्त होगा। देश के करोड़ों लोग अपने स्वतंत्र काम-धंधों में हो तो वे एक विविध और समाजोन्मुखी सभ्यता रचते हैं और अगर वे मुनाफाखोर कंपनियों की नौकरी में लगा दिए जाएं तो एक स्वार्थी, आत्म-केंद्रित और यांत्रिक जीवनशैली को जन्म देते हैं।

इतना ही नहीं, खुदरा बाजार के बड़ी कंपनियों के हाथ में चले जाने का अर्थ होगा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में विविधता का अभाव। बड़े स्टोरों में मिलने वाली वस्तुएं पैकेजिंग प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचती है। उनकी गुणवता की जांच करना उपभोक्ता के लिए संभव नहीं रह जाता। विशेष कर खाद्य पदार्थों में तो गुणवत्ता इतनी तेजी से घटती है कि वह पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। बड़ी कंपनियां फलती-फूलती हैं, वे विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तुओं का आकर्षण पैदा करती है और न खाने योग्य वस्तुएं इतनी प्रचलित हो जाती हैं कि उनका नशा छुड़ाना मुश्किल होता है। कोई भी वस्तु अपने स्थान विशेष से पहचानी नहीं जा सकती। धीरे-धीरे बड़ी कंपनियों की सुविधा और मुनाफा यह तय करता है कि कौन-सी वस्तु कहां पैदा की जाए। अत: रिटेल में एफ.डी.आई. लागू करना देश की जनता के हित में नहीं हैं, सरकार इसे वापस लें।

[अनुवाद]

***श्री सुखदेव सिंह** (फतेहगढ़ साहिब) : यह सत्य है कि थोक में एफ.डी.आई. "सर्वश्रेष्ठ तरीका" था और देश के किसानों, आम आदमी दोनों और व्यापारियों के लिए लाभदायक था।

मैंने अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लंबे अनुभव से महसूस किया है कि एफ.डी.आई. खुदरा विक्रताओं, किसानों, देश के आम आदमी और व्यापारियों के लिए लाभदायक होगा जिससे मध्यस्थ इस वृत्त से बाहर निकल जाएंगे।

मैं इस माननीय सदन का ध्यान एफ.डी.आई. के कुछ सकारात्मक पक्षों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:

1. सर्वप्रथम, एफ.डी.आई. देश में आधुनिक तकनीक लाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सम्पूर्ण सदन इससे सहमत है कि एफ.डी.आई. नई आधुनिक तकनीक लाएगी जिससे कि देश विकसित देशों के साथ चल सके।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुखदेव सिंह]

2. दूसरी बात, एफ.डी.आई. ग्रामीण अवसंरचना को बेहतर बनाएगी, यह अवसंरचना निर्मित करने और एक प्रतिस्पर्धी बाज़ार बनाने में भी सहायता करेगी।

3. तीसरी बात, एफ.डी.आई. कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी कम करेगा क्योंकि एफ.डी.आई. के पास बाज़ार की और गोदामों की श्रृंखला है। यह कृषकों के अत्यधिक हित में ही है क्योंकि स्थानीय मार्केटिंग और शीतल गोदामों की कमी के कारण हमारे देश में कई टन सब्जी, फल, अनाज, गेहूँ और चावल खराब हो जाता है। मैं समझता हूं कि इन तथ्यों से कोई भी असहमत नहीं होगा।

4. चौथा, एफ.डी.आई. के कारण उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कम दामों पर अच्छी गुणवत्ता मिलेगी। एफ.डी.आई. की वजह से भारी प्रतिस्पर्धा के चलते उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की वस्तुएं मिलेंगी। भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाज़ार है अतः सभी को लाभ होगा।

5. एफ.डी.आई. का सबसे अधिक लाभ छोटे किसानों को होगा जो अपनी उत्पादकता बेहतर करेंगे और सीधे बड़े सुव्यवस्थित व्यापारियों को फसल बेचकर तथा खेत से उपभोक्ता तक की श्रृंखला छोटी करके उच्च पारिश्रमिक पाएंगे।

6. वस्तुओं की अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार निगरानी और एफ.डी.आई. का आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन तंत्र सरकार के लिए भी अच्छा है। इससे सरकार करों के द्वारा अतिरिक्त यू.एस. डॉलर प्राप्त करने की आशा भी कर सकती है।

7. खुदरा को खोला जाना खाद्य पदार्थों की महंगाई के लिए समाधान के रूप में देखा जा सकता है जिससे नीति निर्माता हतबद्धि हो गए हैं। खुदरा में एफ.डी.आई. अति आवश्यक बैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने में सहायता करेगा। शीतलगार श्रृंखला अवसंरचना में अतिरिक्त निवेश कृषि उत्पाद की बर्बादी को कम करेगा और किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा।

8. एफ.डी.आई. और भू-वैश्वीकरण के कारण सम्पूर्ण विश्व एक परिवार बनेगा तथा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश के आम आदमी के हित में विकसित होगी।

मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन के विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।

[हिन्दी]

***श्री बलीराम जाधव** (पालघर) : मैं मल्टीब्रांड रिटेल में एफ.डी.आई. नीति का समर्थन करता हूं। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. को मंजूरी दी है। इस नीति में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि वे इस नीति के अंतर्गत मल्टीब्रांड रिटेल को अपने राज्य में अनुमति दे सकते हैं। अगर राज्य सरकारें एफ.डी.आई. नहीं चाहती तो वे अपने राज्य में एफ.डी.आई. को आने से रोक भी सकती हैं। सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इससे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके व्यवसाय की दिशा बदलने के लिए भी सहायता मिलेगी। आज इस नीति का कुछ राजनीतिक दल और व्यापारी वर्ग विरोध कर रहे हैं। व्यापारी संगठनों के मन में कुछ आशंकाएं हैं। लेकिन वे सारी आशंकाएं निर्मूल हैं। ऐसी आशंकाएं उनके मन में आने के लिए कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

इस नीति का सही मायने में लाभ ग्राहकों को मिलेगा। कम से कम कीमत में उनको अपने जरूरत की चीजें मिलेंगी। उसी तरह किसानों को भी इसका लाभ होगा। किसानों को ज्यादा से ज्यादा अपने माल की कीमत मिलेगी।

कई लोगों के मन में ऐसी आशंका है कि बड़े-बड़े मल्टीब्रांड रिटेलर्स छोटे-छोटे व्यापारियों से कम कीमत पर माल लेकर ग्राहकों को जयादा कीमत में बेचेंगे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी यह आशंका निर्मूल है। सरकार ने इन सब बातों का पहले ही अध्ययन किया है। सरकार ने इसके लिए कॉम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की है। यह कमीशन पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखेगा। इस तरह का निर्णय लेकर सरकार ने रिफार्म के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। मल्टीब्रांड रिटेल पॉलिसी के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी इंवेस्टर्स

*मूलतः मराठी में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सिर्फ उन राज्यों में अपना इंवेस्टमेंट करेंगे जहां राज्य सरकारों ने अनुमति दी है। इस निर्णय के कारण वॉलमार्ट एडीडास, लुई स्रोतों और गुच्ची जैसी कंपनियां सिर्फ 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आने से विदेशी मुद्रा भी भारत को मिलेगी। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में ऐसोचैम, फिक्की और सामान्य नागरिकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। इस निर्णय से सबसे ज्यादा लाभ ग्राहकों को मिलेगा और उत्पादक या किसानों को भी लाभ होगा। इस निर्णय से करीब 80 लाख रोजगार पैदा होंगे। बहुत सारे रिटेलर्स सीधे किसानों से उनके उत्पाद खरीदेंगे। जिससे किसानों को अपने उत्पाद ज्यादा कीमत में बेचने का मौका मिलेगा। इस निर्णय से कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती आएगी और ग्राहकों को कम कीमत में माल मिलेगा।

सदन में कई माननीय सदस्यों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि एफ.डी.आई. के कारण छोटे-छोटे दुकानदारों को अपना कारोबार समेटना पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी आशंका मन में न रखें। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे देश में पहले से ही कई-कई बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स चल रहे हें। कई मॉल्स चल रहे हैं। इस एफ.डी.आई. के कारण ग्राहकों को लाभ ही हुआ है। यह बात हम देखते आए हैं। इससे कारोबार में स्पधा बढ़ गई है। अब इस स्पर्धा से किसान और ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अब सिर्फ फर्क यह आने वाला है कि यह कारोबार बड़े पैमाने पर होगा। सामान्य ग्राहकों को कम कीमत पर क्वालिटी की चीजें मिलेंगी।

अंत में मैं सभी सदस्यों को अनुरोध करूंगा कि वे इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करें, खुले दिल से समर्थन करें। आपके समर्थन से सरकार को इस नीति को कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के इस निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। भारतीय कृषि क्षेत्र और भारतीय ग्राहकों को लाभ होगा और देश की अर्थव्यवस्था उन्नत होगी।

***श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** (अहमदनगर) : खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश (एफ.डी.आई) के केंद्र के फैसले के विरोध में मैं कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत में रिटेल व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का मुद्दा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित होगा। इस नीति को लागू करने से पहले सरकार ने इस नीति से देश के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। देश में आज भी खुदरा व्यापार में कार्यरत रिलायन्स/बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनियां किसानों से कृषि उपज कम दामों पर और उधार खरीदते हैं और वही कृषि उपज उच्चतम दामों पर नगद बेचते हैं और किसानों की उधार 3-3 महीने नहीं देते हैं। भारतीय कंपनियों के इस व्यवहार का सरकार ने कभी अध्ययन किया है? इस अध्ययन के बगैर देश के छोटै-छो किसानों को भारतीय कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों को भी लूटने का लायसेंस देने की व्यवस्था है। देश के सभी राजनैतिक दल और रिटेल व्यापार से जुड़े सभी वर्गों का प्रबल विरोध की भी सरकार ने अनदेखी की हे। लोकतंत्र में केवल सरकार बनाना ही राजनैतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम जनता की जीने की भी एक पद्धति है। इस पहलू को ध्यान में रखकर ऐसे ऐसे फैसले लेने के पहले जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी है, उसकी अनदेखी करना जनविरोधी साबित हुआ है।

दुनिया के अन्य देशों में जहां एफ.डी.आई. लागू की है वहां के किसानों का क्याअनुभव रहा है, अध्ययन बताता है कि वहां के किसान उचित मूल्य हासिल कराने के लए जूझ रहे हैं। उन्हें जीवन-यापन की परेशानी झेलनी पड़ रही है। अपने देश में रिटेल सेक्टर में पहले से ही मौजूदा औद्योगिक घराने सिर्फ बड़े किसानों से ही माल खरीदते हैं, और छोटे किसान इनकी खरीद व्यवस्था से बाहर ही है। हमारे देश में 78 प्रतिशत (सेवर्टी एट परसेंट) किसान छोटी जाति के हैं, जिनके पास दो हेक्टयर से भी कम जमीन है जबकि देश का 90 प्रतिशत से ज्यादा खाद्य उत्पादन यही लोग करते हैं। प्रतयक्ष विदेशी निवेश इन सबके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। एफडीआई से खेतिहार मजदूरों के हालात में भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका में जहां-जहां वॉलमार्ट है वहां गरीबी बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि सुपर मार्केट आपसी प्रतिस्पर्धा से बचते हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि सुपर मार्केट उन्हें कम कीमत पर माल बेचने पर विवश करता है। बेशक हमारे देश में किसानों को मिलने वाले मूल्य एवम् रिटेल मूल्य के अंतर को कम किया जाना चाहिए लेकिन

[श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी]

इसका उपाय खुदरा में विदेशी निवेश नहीं है। दूध क्षेत्र में अमूल जैसा सफल सहकारी प्रयोग हो सकता है तो खाद्य उत्पादों में क्यों नहीं? कार्पोरेट रिटेल के बजाय मार्केटिंग कोऑपरेटिव को दुरुस्त किया जा सकता है। सरकार का एक तर्क है कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के नियगमीकरण से बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि लाखों छोटे बिचौलिए की जगह बड़ी-बड़ी कंपनियां लेगी।

अमेरिका और यूरोप की रियायती खाद्य सामग्री हमारे घरेलू बाजार में आएगी, इससे किसानों से उनका बाजार छिन जाएगा। जाहिर है कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई जैसे फैसलो को छोटे किसानों के पक्ष में मोड़ने के लिए तमाम तरह के नियम-कायदों की जरूरत होगी, क्योंकि बेलगाम कंपनियां खेती और खुदरा क्षेत्र में तबाही मचा सकती है। इसकी चिंता देश के वित्त मंत्रालय ने भी (30 नवंबर को) जताई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी संसद ने चीनी कंपनियों की गहरी पड़ताल के बाद अमेरिका में इनका कारोबारी विस्तार रोक दिया है। यह खुफिया रिपोर्ट वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पास पहुंचते ही सरकार में सनसनी फैल गई है। क्योंकि खुफिया निष्कर्ष यह बताता है कि चीन सरकार की वित्तीय मदद से इन कंपनियों द्वारा सुरक्षा को खतरा है। जब एफ.डी.आई. से अमेरिका को खतरा महसूस हो रहा है वहीं हम विदेशी कंपनियों का भारत में रेड-कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हें। हमारी सरकार की नीति से यह स्पष्ट होता है कि अगर एफ.डी.आई. लाना ही है तो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जैसे ग्राम सुधार, तालाब पुनर्भरन योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजना में लाएं। लेकिन सरकार 120 करोड़ देशवासियों की कीमत पर विदेशों के कार्पेरेट घराने को लाभ देने हेतु एफ.डी.आई. को सामान्य जनता पर लागू कर रही है जबकि अमेरिका जैसा देश इसे बंद कर रहा है। रही बात सरकार की नीतियों की, देश के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री और विद्यमान प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन वो भूल गए हैं कि देश की आम जनता के वोट भी पेड़ पर नहीं आते, वो लोगों के दिलों से आते हैं। अब दिल पर ही ठेस लग गई तो नतीजा क्या होगा, यह सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री के सिवा अच्छा कौन जान सकेगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा में करोड़ों का खर्च, टू जी स्कैम, कोयला घोटाला, इतना ही नहीं तो यह सरकार घटती (कोयला) आकाश (2 जी स्कैम) के बाद अब समुद्र में भी घोटाले से अछूत नहीं रही, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में खनिज संपदा की खोज के लिए ब्लाकों के आवंटन में हुए घोटाले की सी.बी.आई. से जांच शुरू करवा दी गई है। इतना काफी नहीं तो जे.एन.एन.आर.यू.एम. में भी 115 करोड़ की अनियमितता कर रखी है। इस घोटाले पर आम जनता की नजर न जाए इसलिए खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का झटका देकर जनता का ध्यान बंटाने के लिए किया है, ऐसा मेरा अनुमान है।

मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र विरोध करते हुए सरकार ने एफ.डी.आई. खुदरा क्षेत्र निवेश का जो अनीतिगत फैसला लिया है उसे तुरंत खारिज किया जाए, ऐसी मांग करते हैं। आखिरकार इतना ही कहूंगा कि देशवासियों के लिए, देशवासियों का शासन विदेशियों द्वारा चलाना राष्ट्रहित के लिए उचित है क्या?

***श्री नलिन कुमार कटील** (दक्षिण कन्नड़) : मेरा विचार है कि इस कदम से स्थानीय व्यापारियों के हित प्रभावित होंगे। सरकार ने इनके हितों की सुरक्षा के उपाय किए बिना जल्दबाजी में निर्णय लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का सरकार का निर्णय से अपने आप में यह स्पष्ट होता है कि सरकार खुदरा उद्योग का महत्व भूल गई है। सरकार यह समझने में असफल है कि भारत में खुदरा उद्योग केवल कारोबार का एक रूप नहीं है। बल्कि ये उन हजारों लोगों की आजीविका का साधन है जो समुचित रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए। इसी कारण मैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करता हूं। यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो बेरोजगारी की दर और बढ़ जाएगी। इससे गरीबी, किसानों द्वारा आत्महत्या, असमानता तथा अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याएं बढ़ जायेंगी।

जब वॉलमार्ट जैसी स्टोर श्रृंखला हमारी घरेलू श्रृंखलाओं जैसे कि पैतांलूंस, रिलायंस फ्रेश आदि के लिए खतरा बन गई है संभवतः इससे पूरे बाजार से स्थानीय खुदरा व्यापारियों का सफाया हो जाएगा एफ.डी.आई. देश में लगभग 2 मिलियन रोजगार सृजन करने का वादा करता है, जबकि भारत का खुदरा और संभार तंत्र उद्योग पहले ही लगभग 40 मिलियन भारतीयों को रोजगार दे चुका है, इनमें से बहुत से लोगों को अपना रोजगार खोने का खतरा है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अन्य घटक भारतीय बाजार में बड़े ब्रांडों का एकाधिकार है। एफ.डी.आई. का भारतीय किसानों की बिक्री और लाभ मार्जिन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं कि एकल ब्रांड रिटेलर अपनी 30 प्रतिशत वस्तुएं अनिवार्य रूप से भारत से जुटाएं। अब बाजार के रूझानों को समझते हुए, चेन-स्टोर मालिकों की प्रवृत्ति बाजार पर नियंत्रण करने। और एकाधिकार का प्रयोग करने की है।

छोटे किसानों और शिल्पकार समूहों तक पहुँचने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उनको अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बर्बादी न हो'' यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो इन वर्गों के लोगों अपनी रोजी-रोटी गँवा देंगे।

इससे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में आसानी से पहुंच बना सकती हैं। इससे किसी भी प्रकार से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता नहीं मिलेगी।

खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. से जनता को लाभ पहुंचाने का सरकार का आश्वासन मात्र एक दिखाता है और इससे भारत में विदेशी कंपनियों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

कुछ समाचार पत्रों में कुछ दृष्टान्त छपे हैं कि पूरे विश्व में रिटेल स्टोर चेन मालिकों को विरूद्ध ये शिकयतें दर्ज की गई हैं कि वे अपने आपूतिकर्त्ताओं को समय पर पैसों का भुगतान नहीं करते। किसी अन्य देश के बारे में भूल जाईए, वॉलमार्ट जैसी रिटेल श्रृंखला स्वयं अपने देश में व्यापक विरोध का सामना कर रही हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बेरोजगारी और रोजगार दोनों की दर में वृद्धि होगी। वर्तमान परिदृश्य में केवल 20 प्रतिशत खुदरा बाजार ही संगठित है। शेष 80 प्रतिशत असंगठित है, तथा विकास के अत्यंत प्रारंभिक चरण में है। बड़े वैश्विक रिटेलरों के प्रवेश से धीरे-धीरे परंतु निश्चित रूप से घरेलू रिटेलर हाशिए पर आ जाएंगे और दीर्घावधि में स्थानीय दुकानें बंद हो जाएंगी और लाखों रोजगार समाप्त हो जाएंगे।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न देकर सरकार हमारे किसानों, खुदरा व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

***श्री जे.एस. आरुन रशीद** (थेनी) : विश्व में किसी भी अन्य उपभोक्ता भारतीय उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते उत्पाद प्राप्त करने के समान अधिकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने हमारे देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है और इस निरंतर इस विकास को बनाए रखना होगा।

हमारे देश में 50 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और हमारे पास कृषि के लिए पर्याप्त उपज़ाऊ भूमि है परंतु हम अभी भी हमारी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। अवसंरचना की कमी के कारण संपूर्ण उत्पादित खाद्य में से 30 से 40 प्रतिशत तक बर्बाद हो जाता है। किसानों को अपनी फसलों के लिए बाजार मूल्य का केवल 10 से 23 प्रतिशत मिल रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य विकसित देशों में यह 70 से 89 प्रतिशत के बीच है, जहां बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखलाएं किसानों का समर्थन करती हैं और किसानों से सीधे उत्पाद लेती हैं। हम समझ सकते हैं कि यदि 1 कि.ग्रा. टमाटर का बाजार मूल्य 20 रुपए है, तो भारतीय किसानों को केवल 5 रुपए मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संविदा कृषि आयेगी और किसानों को नई किस्मों के बीज तथा अन्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मिलेगी और कृषि उत्पादों के लिए सुनिश्चित क्रेता को अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे और फिर किसानों के मूल्य के लिए बिचौलियों के साथ सौदेबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए किसान 10 रुपये में 1 किग्रा. टमाटर ले सकता है और उपभोक्ता इसे 15 रुपए में खरीद सकता है।

अन्य खुदरा उत्पादों के लिए भी यही स्थिति है। मान लिजिए मुझे एक नया भवन बनाने के लिए कुछ बिजली के सामान की आवश्यकता है, तो मुझे कई बार पूरे शहर में विभिन्न दुकानों के चक्कर लगाने होंगे कुछ उत्पाद खरीदने के लिए मेरा समय और पेट्रोल बर्बाद होगा और कई बार ये सामान उपलब्ध नहीं होगा तथा गुणवत्ता भी खराब होगी। परंतु मैं कहूंगा कि जब मैं अमरीका, ब्रिटेन में होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती।

यदि मुझे कोई बिजली का या यान्त्रिक उत्पाद खरीदना है तो वहां बिल्टेमा जैसी बड़ी दुकानें होती हैं, जिनके पास हजारों उत्पाद है जिनके विशिष्ट क्रम संख्या देकर अलग-अलग किया गया है। मैं उनकी वस्तुसूची उत्पाद चिन्हित करके खरीद सकता हूं और इसमें

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जे.एस. आरुन रशीद]

ऐसे कई नवोन्मेष उपकरण हैं जो काम को बहुत आसानी से और शीघ्र कर सकते हैं और मैं कहूंगा कि ये बहुत सस्ते होते हैं। यदि मुझे घर या इंटीरियर फर्नीशिंग के लिए कुछ खरीदने की जरूरत होती है तो आई.के.ई.ए. है, इनके पास जेड़ अच्छी गुणवत्ता और बहुत सस्ती चीजे होती हैं। ये बक्सों में आते हैं ताकि इनकी आसानी से दुलाई की जा सकेती है और, कोई भी अकुशल व्यक्ति इन उत्पादों को जोड़ सकता है। वहां खाद्य उत्पाद भी अच्छे होते हैं और सुपरमार्केट के पास खाद्य सुरक्षित रखने की प्रौद्योगिकी है।

भारत में कई प्रसिद्ध ब्रांड के उत्पाद खरीदने के बाद हमें पता चलता है कि ये नकली हैं। मैं कहूंगा कि अधिकांश दुकानों के पास घटिया किस्म के सस्ते चीनी उत्पाद बेचने के लिए ब्रांड अंबेसडर बनने की अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा 40 बिलियन डॉलर का है। हम चीन से 57 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के उत्पाद आयात करते हैं और केवल 18 बिलियन अमरीकी डॉलर की वस्तुएं निर्यात करते हैं। प्रमुख निर्यात कच्चे माल का होता है जैसे कि लोहा, इस्पात आदि परंतु बहुत से विनिर्मित उत्पादों का निर्यात नहीं है। हम बिना अधिक रोजगार सृजन किए अपने प्राकृतिक संसाधनों को खो रहे हैं।

हमें इस स्थिति में परिवर्तन लाना होगा और हमारे किसानों को लाभ दिलाना होगा, पशुपालन और कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी होगी बर्बादी रोकनी होगी, मुद्रास्फीति कम करनी होगी तथा उपभोक्ताओं को गुणवतापूर्ण वस्तुएं सस्ती दरों पर प्राप्त होनी चाहियें। यदि उत्पादन अधिक होगा तथा खुदरा क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी तो स्वाभाविक रूप से मूल्य कम हो जाएंगे और चूंकि भारत विनिर्माण का हब है और हमारे पास सस्ता कुशल श्रम तथा प्राकृतिक संसाधन हैं इनमें से अधिकांश कंपनियां देश में लघु विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने जा रही हैं, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा और इससे एक प्रकार से निम्न गुणवता वाले चीनी उत्पाद हमारे बाजारों में आने से सकेगा तथा साथ ही अन्य देशों में हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। हमारे देश में पहले से ही भारतीय कंपनियों जैसे कि रिलायंस, बिड़ला आदि की बड़ी सुपरमार्केट हैं जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी हैं। भारती समूह के सहयोग से वालमार्ट देश में प्रवेश कर चुका है। इसलिए, मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 100 प्रतिशत की अनुमति देने के कारण लघु व्यापार क्षेत्र में ज्यादा मुद्दे नहीं उभरेंगे। इसके अलावा, इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, विशेषकर ग्रामीण भारत में जिसे अर्थव्यवस्था में तेजी का लाभ नहीं मिला है क्योंकि एफ.डी.आई. का 50 प्रतिशत निवेश अवसंरचना विकास में चला जाएगा। हमारा देश 1 बिलियन आबादी वाला विशाल देश है, इसलिए 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले 50 बड़े शहरों में बड़े रिटेल ब्रांड की खुदरा दुकान खुलने से छोटे व्यापारियों का संपूर्ण कारोबार बंद नहीं हो जाएगा।

हमारी हर प्रकार के सुधार के प्रति विरोध करने की एक परम्परा रही है और भारत की जनता को विपक्ष द्वारा अपने खुद के हित के लिए भ्रमित किया जाता है न कि राष्ट्र के हित में। यदि विश्व के 26 सबसे तेज विकासशील देशों में 10 वर्षों से अधिक से मल्टी-ब्रांड खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. हो सकता है तो भारत भी उसी नीति को क्यों नहीं अपना सकता? एक समय था जब भारत में कम्प्यूटर पहली बार लाए गए थे, तब अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह रोजगार छीन लेगा और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभर कर आया है जिससे 100 बिलियन डालर का राजस्व प्राप्त होता है और 2.8 मिलियन से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप और 8.9 मिलियन अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित है। वाहन उद्योग में एफ.डी.आई. की अनुमति से ने केवल भारतीय उपभोक्ताओं ने मोबाइल फोन को आम आदमी के पास भी उपलब्ध होने वाला उपकरण बना दिया है और अब हम अन्य देशों को कारों का निर्यात करते हैं। दूरसंचार में एफ.डी.आई. ने मोबाइल फोन को आम आदमी के पास भी उपलब्ध होने वाला उपकरण बना दिया है। विकसित देश 4जी पर पहुंच चुके हैं और हम अभी भी 2जी पर ही रूके हुए हैं।

अत: यदि हम एक विकासशील देश के विकसित देश बनना चाहते हैं, तो कड़े आर्थिक सुधार लाने होंगे और उन्हें समय पर लाना होगा तथा खुदरा क्षेत्र में एक होगा। अत: मैं मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं और इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

*श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड) : संसदीय स्थायी समिति के विरोध में बावजूद केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नागर विमानन, पेंशन, बीमा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है। अब सरकार संसार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है।

सरकार में नीतिगत निर्णय लेने वाले शक्तिशाली लोग कहते हैं कि वे खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. की अनुमति केवल देश के आर्थिक विकास हेतु दे रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए कोई ऐतिहासिक परिपेक्ष्य मौजूद नहीं है कि राष्ट्र का आर्थिक विकास विदेशी निवेश के कारण होता है। इसके विपरीत, संसार के कई देश आर्थिक हमले के कारण गुलाम बन गए हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है। व्यापार के लिए भारत आने वाले ब्रिटिश हमारे मालिक बन गए और उन्होंने हम पर शासन किया। हम इतिहास की इस सीख को भूल नहीं सकते हैं।

यह तर्क दिया जाता है कि छोटे व्यापारी, जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य कार्य करते हैं, उत्पादों की मूल्य वृद्धि का कारण है। यह भी तर्क दिया जाता है कि छोटे व्यापारी व्यापार की स्थापना के लिए आवश्यक होने वाले आधारभूत ढांचे को नहीं बना सकते हैं; और विदेशी निवेशक बड़ा निवेश कर सकते है जिससे बड़ी व्यापार स्थापनाएं बनाई जा सकती हैं और उपभोक्ताओं को उत्पाद सस्ती दर पर मुहैया करवाए जा सकते हैं। प्रारंभ में कुछ ही समय तक विदेशी निवेशक इस प्रकार का व्यवहार करेंगे जो उत्पादों तथा उपभोक्ताओं को लाभप्रद लगेगा। ऐसे परिदृश्य में, छोटे व्यापारियों को बड़े विदेश निकायों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाने में असमर्थ होने के चलने अपना व्यापार छोड़ना पड़ेगा।

प्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर हो जाएंगे और पूरा नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में आ जाएगा। उत्पादकों और उपभोक्ताओं का उपयोग ऐसी कंपनियों के लाभ हेतु किया जाएगा। इस प्रकार उत्पादक और उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. की अनुमति देने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। ऐसी बातों का उपयोग केवल रूचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और यह किसी अनुभव पर आधारित नहीं है। किसानों के उत्पादों का मूल्य निर्धारण विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। बीजों का चयन, उन्हें बोने का तरीका और उनकी मात्रा का निर्णय विदेशी कंपनियों द्वारा लिया जाएगा। भारतीय किसानों को विदेशी कंपनियों के इशारों पर चलना होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धी बाजार मौजूद नहीं होगा। इस प्रकार, देश की कृषि विदेशियों के नियंत्रण में होगी।

उत्पादकों के उनके उत्पादों का वही मूल्य मिलेगा जो विदेशी कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उपभोक्ताओं को भी विदेशी कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्य अदा करना होगा। उत्पादक और उपभोक्ता उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। भारत में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों के दरवाजे खोलना केवल आर्थिक एकाधिकार का कारण बनेगा। इस श्रृंखला में रत उत्पादक, उपभोक्ता और छोटे व्यापारी सभी प्रभावित होंगे।

वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसका संसार के कई देशों पर प्रभाव हुआ था, का भारत पर कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था गांव पर आधारित है। महात्मा गांधी का स्वप्न भारत में स्व-शासन, राम राज्य का था। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को जलाया। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हमारा देश विदेशियों के लिए उनकी वस्तुओं को बेचने के लिए एक बाजार बने। उन्होंने हम में देशभक्ति की भावना जगाई।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित किया। वर्ष 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जो विदेशी निवेशकों के नियंत्रण में थी। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी.डी. देशमुख ने कहा था कि ''यह एक ऐसा निर्णय है जो देश को समाजवाद की ओर ले जा सकता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके समाजवाद की नींव रखी।

श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा डाली गई नींव को धवस्त करने में लगी हुई है। खुदरा क्षेत्र में एफ. डी.आई. की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह उत्पादकों, उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारियों, किसानों तथा हम में से प्रत्येक की आजीविका को प्रभावित करता है।

*मूलतः तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

[श्री ए. गणेशमूर्ति]

मैं मारूमलीर्ची द्रविड मुनेत्र कणगम (एम.डी.एम.के.) की ओर केन्द्र सरकार से खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने के अपने निर्णय को वापिस लेने का आह्वान करता हूं।

*श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट) : मेरा दल आर.एस.पी. माननीय सुषमा स्वराज और प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि सरकार आम जनता के हित में तुरंत मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वापस ले। मैं सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी और लॉर्ड क्लाइव का स्मरण कराना चाहता हूं। साथ ही मैं इनको रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों का स्मरण कराना चाहता हूं जिन्होंने कहा हैं कि ब्रिटिश व्यापारियों के रूप में आए और शासन बन गए।

सरकार दावा कर रही है कि यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आरंभ किया गया तो 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और बाद के चरण में, 60 लाख और लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इससे मुझे एक बात याद आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, माताएं लोरी गाती हैं या कहानियां गढ़ती है ताकि उनके बच्चे जल्दी से सो जाएं। यह सरकार भी आम जनता के लिए रोजगार की कहानियां बुन रही है क्योंकि हम जानते हैं कि रोजगार वृद्धि दर केवल एक प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता में भारी गिरावट आई है। देश की आबादी भी बढ़ रही है। इसलिए रोजगार सृजन की गुंजाइश कहा है?

पुन: यदि हम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि वॉलमार्ट, मेट्रो कैश और कैरे के कर्मचारी संबंधी आंकड़ों को देखें तो हम पाते हैं कि यह अनुपात: 1:17 का है अर्थात् यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, तो खुदरा क्षेत्र में 17 अन्य लोग अपना रोजगार खो देते हैं।

हमारे देश में, 5 करोड़ छोटे व्यापारी कई वर्षों से बढ़िया व्यापार कर रहे हैं और अपने परिवारों की सहायता कर रहे हैं। यदि ये 5 करोड़ दुकानें, फैक्ट्रियां अथवा छोटी स्थापनाओं को बंद कर दिया जाए, तो 25 करोड़ लोगों की आजीविकास छिन जाएगी क्योंकि वे बड़े व्यापारिक घरानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।

*मूलत: बंगला में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सरकार यह भी दावा करती है कि किसानों को लाभ होगा क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा और किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलेंगे। यह सच है कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सीधे कृषि उत्पाद खरीदेंगी। वे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम करने तथा अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। धीरे-धीरे, जब बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी, तो कंपनियां किसानों जो मूल्य देंगी उनको उसी में संतोष करना होगा क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। उपभोक्ताओं का भी नुकसान होगा।

इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि बड़ी कंपनियां इनको पूर्वनिर्धारित दर पर भुगतान करेंगी। यदि बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय पर कृषि उत्पाद की आपूर्ति नहीं होगी, तो संविदा के अनुसार भूमि कंपनियों के स्वामित्व में आ जाएगी और किसान श्रमिक बन कर रह जाएंगे।

सरकार कह रही है कि अवसंरचना, गोदाम, शीतागार और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण 30 प्रतिशत खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों की भी हानि होती है। अत: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इन सुविधाओं का विस्तार करके कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी। परंतु वास्तव में कृषकों को अपने उत्पाद का भंडारण करने के लिए इस अवसंरचना का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। वॉलमार्ट, मेट्रो आदि उन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देंगी जो अधिक लाभप्रद हैं। हम नील की खेती के इतिहास को नहीं भूले हैं। इसके अलावा देश की पारंपरिक भोजन की आदत में भी परिवर्तन होगा।

इसके अलावा, यदि खाद्य उत्पादों, सब्जियों, मछली, मांस, अंडे, दूध, फल, आलू, और टमाटर आदि का उत्पादन करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया और यदि इनको वर्षों तक शीतागार में भंडारित किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों का मूल्य कम हो जाएगा और इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, उलखे, चिली जैसे देश अब ताजा खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना चाहते हैं और छोटी दुकानों के द्वारा ही यह प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। इसके कारण, वॉलमार्ट ने इन देशों से अपना कारोार समाप्त कर लिया है।

विदेशी कंपनियां पर्यावरणीय सुरक्षा की दलील देकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भारत में प्रवेश कर रही हैं और इससे

हमारी आर्थिक संप्रभुता को खतरा है। मैं महान कालिदास का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम पेड़ की जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया था।

[हिन्दी]

***श्री राजू शेट्टी** (हातकंगले) : स्वतंत्रता पूर्व से आज तक देश के सभी किसान अपने कृषि उपज और उससे मिलने वाले उचित एवं लाभकारी मूल्य के बारे में पूरी व्यापार व्यवस्था के शोषित रहे हैं। सामाजिक रंगमंच पर तो गुलामों की भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के जरिए किसानों को सहायता करने के लिए आज तक की सरकारों को इतने साल क्यों लगे? इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन किसानों की उपज को उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सरकार ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के बारे में जो कदम उठाए हैं, इस पहल का स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और स्वाभिमानी पक्ष, महाराष्ट्र, खुले दिल से स्वागत करते हैं और इस उचित निर्णय की सराहना करते हैं। इस निर्णय का स्वागत करते हुए हमें सरकार से आश्वासन चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के खुदरा व्यापार (रिटेलिंग) के क्षेत्र में आने से हमें किसान ओर देहाती लोगों को बुनियादी सुविधा जैसे कि शीतकक्ष, अनाजों के भंडार, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को रोजगार की सुविधा दूर-दराज के क्षेत्र में बसे हुए छोटे-छोटे गांवों को जोड़ने के लिए पक्के रास्ते और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए सरकार कारगर कदम उठाए व अन्य देशों की तुलना में उत्पादन के खर्च में कमी लाने के लिए किसानों को विभिन्न स्तरों पर राहत मिलनी चाहिए।

अंत में, किसानों को खुली सांस लेने के लिए इस कदम का मैं फिर एक बार खुले दिल से स्वागत करता हूं उसके साथ-साथ यह भी आशा करता हूं कि आने वाले समय में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

***श्री जोसेफ टोप्पो** (तेजपुर) : मैं असम गण परिषद् पार्टी की ओर याद दिलाना चाहता हूं कि रिटेल में एफडीआई के मसले पर पहले सरकार ने सदन में तब के वित्त मंत्री तथा सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि रिटेल में एफडीआई को बिना आम सहमति के देश में लागू नहीं किया जाएगा पर इस सरकार ने केवल कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिना विपक्ष की बात सुने खुदरा बाजार में 51 प्रतिशत एफडीआई को देश की जनता पर थोप दिया। ये इस सरकार की सिर्फ मनमानी है जिसे यूपीए सरकार जबरदस्ती देश में लागू करना चाहती है। एफडीआई को लेकर सरकार ने जितने फायदे बताए हैं वो सब कहीं से भी सच नहीं है। देश में रोजगार बढ़ाने के नाम पर जिस तरह इन विदेशी कंपनियों को लाया जा रहा है उसके गंभीर परिणाम होंगे। ये विदेशी कंपनियां पहले तो सस्ता सामान बेचेंगी लेकिन जब बाजार पर इनका पूरा कब्जा हो जाएगा तो अपने हिसाब से सामान को महंगी कीमत पर बेचेंगे। एफडीआई से 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं पर करोड़ों छोटै दुकानदार तथा खुदरा व्यापारी जरूर बेरोजगार हो जाएंगे और देश का गरीब किसान इन कंपनियों से अपने लाभ के लिए नहीं लड़ सकता, ये कंपनियां जो रेट देंगी उसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंपनियां बाजार में किसी और को ठहरने ही नहीं देंगी जो उसका मोल खरीद सके।

वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार में एफडीआई के माध्यम से घुसने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत दी है और इसी कारण उन्होंने अपने एक बड़े अधिकारी को हटा दिया है। भ्रष्टाचार से घिरी वर्तमान यूपीए सरकार का एफडीआई के माध्यम से यह जनता पर एक और अत्याचार है। वॉलमार्ट पूरी दुनिया में जहां भी खुदरा बाजार में घुसा वहां पर छोटे दुकानदार या खुदरा व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। ये वॉलमार्ट भी वही करेगी जैसा पैप्सी जैसी दूसरी विदेशी कंपनियां कर रही हैं। ये व्यापार तो यहां करेंगी पर कच्चा माल विदेश में अपनी शर्तों पर मनाएगी जिससे चीन के व्यापारी तो मालामाल हो जाएंगे पर हमारे छोटे व्यापारी बरबाद हो जाएंगे। इसलिए सरकार को विदेशियों की नहीं अपने देश के छोटे व्यापारियों तथा इससे जुड़े गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। 53 शहरों में सरकार जहां स्टोर खोलने की बात कर रही है जरा सोचिए इन शहरों के छोटे व्यापारी या उस छोटे व्यापारी की दुकान पर काम करने वाले गरीब आदमी का क्या होगा। एफडीआई न तो देश के आम आदमी, न छोटे दुकानदार और न ही किसी भी रूप से किसान के हित में है। आज यह एफडीआई 53 शहरों में लाने का प्रस्ताव है कल पूरे देश के हर शहर में होगा तब क्या होगा। कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये एफडीआई व्यवस्था सिर्फ इस देश को फिर से बरबादी की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जोसेफ टोप्पो]

ओर लेकर जाएगी और कुछ नहीं, इस ओर सरकार को सोंचना होगा।

जिस अमेरिका के दबाव में सरकार एफडीआई को लाना चाहती है वह अमेरिका खुद अपने यहां एफडीआई पर रोक लगा चुका है और जो देश खुद अपने यहां पर बेरोजगारी से परेशान हो वो क्या वहां की कंपनियां हमारे यहां कैसे रोजगार पैदा करेंगी ये सरकार क्यों नहीं समझ रही हैं, क्यों इस देश की जनता के साथ जानबूझकर धोखा कर रही है? माननीय मंत्री सिब्बल साहब कहते हैं कि वॉलमार्ट के आने पर या किसी भी विदेशी खुदरा व्यापार कंपनी के आने पर उसे 100 मिलियन डालर देने होंगे जिसमें से 50 मिलियन डालर विकास पर खर्च होगा, क्या हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है या इस देश के जनता का विकास किसी विदेशी के दिए 50 मिलियन डालर की रकम पर निर्भर है। ऐसा नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल मत खेलिए, सच्चाई आप भी जानते हैं ये सब सिर्फ अमेरिकी दबाव और अपनी विदेशों में अपनी इज्जत बचाने के लिए किया जा रहा है पर प्रधानमंत्री जी विदेशों में अपनी इज्जत बचा कर क्या करेंगे जब देश में ही आपका विरोध हो रहा है। सरकार को अपने इस कदम से पीछे हटना चाहिए तथा अगर देश के हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना होगा और आम आदमी तथा देश के विकास में कोई उचित कदम सरकार को उठाने होंगे। किसी भी विकास के मुद्दे पर अगर सरकार कोई फैसला लेना चाहती है तो सभी दलों तथा एक आम सहमति के साथ कोई फैसला लिया जाए जिसमें सब शामिल हों, सिर्फ जोड़-तोड़ के बहुमत के बल पर कोई मनमानी ना की जाए क्योंकि हम इसका भरपूर विरोध करेंगे और हम अपने राज्य असम में तो वालमार्ट को घुसने भी नहीं देंगे और हमारी पार्टी असम गण परिषद रिटेल में एफडीआई के सरकार के निर्णय का विरोध करती है।

*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : यह बहुत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील चर्चा का विषय है। पूरा देश इस चर्चा को बड़े ध्यान से देख और सुन रहा है। चर्चा सिक नियम के तहत हो इसको लेकर भी काफी व्यवधान पैदा हुआ। आखिरकार कल से चर्चा प्रारंभ हुई, नेता प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष की ओर से श्री कपिल सिब्बल तथा अन्य दलों के माननीय सांसदों द्वारा अपने-अपने विचार रखे गए। सभी के विचारों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि रिटेल में एफ.डी.आई. देश हित में है और देश को आगे बढ़ाने का साधन है।

किसानों, उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभदायक है तथा खुदरा व्यापारियों के लिए कोई नुकसान या हानिकारक नहीं है। सदन में लंबी-चौड़ी बहस में नेता प्रतिपक्ष ने सन् 2002 में एन.डी.ए. सरकार की रिटेल में एफ.डी.आई. के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि यह एक नीति निर्धारण संबंधी मामला है। हर सरकार के नीति संबंधी निर्णय लेने का अधिकार हैं।

एन.डी.ए. के समय में रिटेल में एफ.डी.आई. 100 प्रतिशत रखा गया था, लेकिन हमने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 51 प्रतिशत रखा है। यू.पी.ए. सरकार ने एन.डी.ए. की नीतियों में यह भी संशोधन किया है कि रिटेल में एफ.डी.आई. की पूंजी को 50 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण एवं कृषि के क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं जैसे कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, गोदाम, रैफ्रीजरेटेड वैन इत्यादि पर खर्च किया जाएगा। जब हर क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है तो कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निवेश क्यों न हो और नई तकनीक तथा प्रबंधन की उच्चतम् सुविधाएं इस क्षेत्र को क्यों न मिलें। एन.डी.ए. की सरकार की नीति में यह भी संशोधन किया गया है कि रिटेल में एफ.डी.आई. प्रदेशों में तभी लागू होगी जहां पर प्रदेश सरकारें अपनी सहमति प्रकट करें। केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय किसी भी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। यह भी एन.डी.ए. के निर्णय में संशोधन किया गया है कि संगठित क्षेत्र में रिटेल के लिए जो भी स्टोर खोले जाएंगे उनकी आवश्यकता का 30 प्रतिशत हिंदुस्तान के लघु एवं मध्यम उद्योगों से खरीदा जाएगा।

भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फोरमों पर जो भी विचार प्रस्तुत किए गए उनके आधार पर यू.पी.ए. सरकार द्वारा अच्छी नीति तैयार की गई है, जसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए।

यह भी कहा गया है कि अभी खुदरा व्यापार विकेंद्रीकृत रूप से सभी जगह फैला हुआ है और प्रतियोगी बाजार की बजाय एकाधिकार व्यापार बना दिया जाता है तो उपभोक्ता और किसानों के शोषण की संभावना बनी रहेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारतीय जनता पार्टी की सोच में केवल वॉलमार्ट ही एक मात्र विकल्प है और उनके द्वारा हर स्थान पर स्टोर खोलने पर दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। मैं यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही हैं, क्योंकि रिटेल में एफ.डी.आई. की अनुमति देने के बाद केवल वॉलमार्ट ही नहीं उनके अनेक प्रतियोगी भी मैदान में होंगे और उनके आपस के कंपटीशन के कारण किसानों और उपभोक्ताओं का हित पूर्णतया: सुरक्षित है।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि रिटेल में एफ.डी.आई. आने से रोजगार के जो आंकड़े दिए गए हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। इसकी पुष्टि में यह बताया गया है कि वॉलमार्ट में 21000 कर्मचारी है और 40 लाख रोजगार का लक्ष्य किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम रोजगार की बात करते हैं तो सभी स्टोरों में लगे कर्मचारियों की संख्या का आकलन नहीं किया जाता बल्कि स्टोर खुलने के बाद जो आर्थिक गतिविधियों से जो माहौल उत्पन्न होगा, उससे रोगजार के अवसर उपलब्ध होंगे। इन स्टोरों की 30 प्रतिशत खरीदारी लघु एवं मध्यम उद्योग से करने का प्रावधान रखा है, ऐसी स्थिति में लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी तो रोजगार से अवसर अपने-आप बढ़ेंगे, जिससे रोजगार संबंधी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त गोदाम कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, रैफ्रिजरेटेड वैन में भी तकनीकी कर्मियों के अतिरिक्त बहुत से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

भारतीय जनता पार्टी की और से रिटैल में एफ.डी.आई. को लेकर अनेकों तर्क दिए गए हैं जिसमें एक यह भी है कि 5 करोड़ खुदरा व्यापारी बेघर हो जाएंगे, जो कि बेबुनियाद है। हिंदुस्तान के संगठित क्षेत्र में रिटेल केवल 5 प्रतिशत है, जो मुख्यत: सिंगल ब्रांड एफ.डी.आई. तथा भारतीय उद्यमियों द्वारा संचालित स्टोर इत्यादि के माध्यम से है। यदि वर्तमान नीति के अनुसार रिटेल में एफ. डी.आई. आती है तो अधिक से अधिक 5 प्रतिशत से बढ़कर 10 या 15 प्रतिशत तक रिटेल की संगठित क्षेत्र में भागीदारी हो सकेगी, उसके बाद भी 85 से 90 प्रतिशत खुदरा व्यापार असंगठित क्षेत्र में ही रहेगा। आज संगठित क्षेत्र की भी वृद्धिदर 20 प्रतिशत है और असंगठित क्षेत्र की भी वृद्धि दर 20 प्रतिशत ही है। इससे स्पष्ट है कि रिटेल में एफ.डी. आई. आने से कोई हानि नहीं होगी। और यदि पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन में 20 वर्षों से रिटेल में 100: एफ.डी.आई. की अनुमति दे रखी है। यहां पर 20 वर्ष बाद भी रिटेल में 20 प्रतिशत संगठित क्षेत्र की भागीदारी हो सकी है और बाकी 80 प्रतिशत खुदरा व्यापार के हाथ में ही है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि रिटैल में एफ.डी.आई. आने से खुदरा व्यापारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भारतीय जनता पार्टी संगठित खुदरा व्यापारियों को वोट बैंक के रूप में देख रही है उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनको 5 करोड़ लोगों की चिंता है, लेकिन 80 करोड़ किसान व खेतिहर मजदूरों की चिंता नहीं है। 120 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता। एक निहित स्वार्थवश कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को आधुनिक तकनीक/प्रबंधन से वंचित नहीं रखा जा सकता।

मेरा भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले और देश हित में इस निर्णय को अपना समर्थन दें।

मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री देवजी एम. पटेल** (जालौर) : मैं नेता विपक्ष के प्रस्ताव मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस लेने का समर्थन करता हूं।

भारत भी अजीब देश है यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सारे दरवाजे खोल देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नि यम कानून बदल देते हैं। वही दूसरी तरह सरकार ने किसान गरीब मजदूर पिछड़ी जन जातियों, अल्पसंख्यकों की बातों को सुनना बंद कर दिया है। सरकार की इस संवेदनहीनता की वजह से भारत का प्रजातंत्र आज नाजुक मोड़ पर खड़ा है।

आज देश में कृषि जोत निरंतर घट रही है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश 20.2 प्रतिशत से घटकर 15.4 प्रतिशत रह गया है। दूसरी तरफ छठे वेतन आयोग के बाद सरकार के चपरासी की मासिक आय 15000 रु. है। इसके विपरीत एक सर्वे के अनुसार एक सिकान की मासिक अैसत आय लगभग 2115 रु. आंकी गई है। आज एक किसान नरेगा मजदूर से अधिक नहीं कमा पाता है बल्कि भारत के अन्नदाता की आय नरेगा श्रमिक से भी कम है। दिनभर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री देवजी एम. पटेल]

खेत पर काम करने वाले किसान को उतना भी नहीं मिलता जितना घरेलू नौकरानी प्रतिदिन एक घंटाकाम करके कमा लाती है। इस देश में किसानों को उसके परिश्रम का दाम नहीं मिलता, 18 से 20 घंटा काम करने के उपरांत भी उसे दोहरी मार झेलनी पड़ती है।

मेरा संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान है मैं किसानों की समस्या से दिन प्रति रूबरू होता रहता हूं। मेरे क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए पानी, पेयजल, उर्वरकों की कालाबाजारी, पाला, फसल के बंपर पैदा वार के बाद उचित मूल्य न मिलना, प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव, बिजली, भंडारण, आदि जैसी प्रमुख समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो वो किसानों से छांट कर फसल खरीदेंगे। बाकी का माल किसानों को फेंकना पड़ेगा। उदाहरण के लिए गुजरात में रिलायंस फ्रेश बड़े आलू तो खरीदता है लेकिन बाकी आलुओं को छोड़ देता है। जो किसानों को कम दाम में बेचना पड़ता है। उदाहरण के लिए पूरे राज्य में आलू 8 रुपये किलो बिक रहा होता है तब रिलांयश किसानों से 10 रुपये में खरीदने का दावा करता है। हकीकत इससे अलग है। रिलांयस किसानों से कुल पैदावार का मात्र 40 प्रतिशत ही 10 रुपयों के भाव से खरीदता है। बाकी आलू को आकार और रंग के आधार पर रिजेक्ट कर देता है। शेष आलू किसान मात्र 5 रुपये या उससे भी कम दाम पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। अत: किसान को कुल उत्पाद का 5.30 या 6 रूपये ही मिलता है। आलू जैसा देश का सबसे बड़ा कॉपरेटिव भी इसका विरोध कर रहा है। अमूल से ज्यादा सफल कॉपरेटिव विश्व में नहीं है।

मेरे क्षेत्र में टमाटर, जीरा, इसफगोल की बम्पर पैदावार होती है। पूरा फसल अगर उञ्झा मंडी पहुंच जाता है तो वह एक भाव पर बिक जाता है। लेकिन ये बडे रिटेल छांट कर खरीदारी करते हैं। उदाहरण के रूप में 1 पंजाब में पेप्सी पंजाब के किसानों से आलु नहीं खरीदता, 2. मेकडोनालड आलू फ्राइ के लिए भारत के किसानों से आलू नहीं लेता है। जिससे किसानों की बाकि की फसल को फेंकने के अलावा कोई चारा नही बचेगा। और भारत का किसान कर्ज में दब जायेगा और किसानों के सामने आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा।

न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक एडवोकेट शबिल-दो ब्लासियोश ने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज के अर्थशास्त्रियों की एक टीम का वॉलमार्ट पर किया गया शोध भी प्रकाशित करवाया है। वॉलमार्ट पर वर्ष 2010 में तैयार की गई 12 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉलमार्ट की हर दो नौकरी के बदले में तीन नोकरियां खत्म हो जाएंगी। रिपोर्ट में शिकागो ओर ओहायो राज्यों में वॉलमार्ट के खोले जाने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या का भी आकलन किया गया है। एक विरोध प्रदर्शन में न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक एडवोकेट बिल दो—ब्लासियां ने वॉलमार्ट के बारे में कहा, वॉलमार्ट कंपनी लोगों को अच्छी नौकरी और अच्छा पगार देने का वादा करती है, लेकिन सब झूठ है, आप अगर देखें तो जहां वॉलमार्ट स्टोर खुला है वहां नौकरियां खत्म हो गईं, छोटी दुकानें तबाह हो गईं। यह कंपनी शहर की अर्थव्यवस्था तबाह करके रख देती है। पूरे अमरीका में इस स्टोर के खुलने का यही नतीजा हुआ है और मध्यम वर्ग को कमजोर करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, भारतीय मूल के कमलेश शाह न्यूयॉर्क के जैक्सन हाइट्स इलाके में एक किराना स्टोर चलाते हैं, वह कहते हैं कि अगर वॉलमार्ट उनके इलाके में खोली गई तो उनकी दुकान भी बंद हो सकती है। कमलेश शाह कहते हैं, वॉलमार्अ जिस इलाके में भी स्टोर खोलेगी, वहां तो असर पड़ता है। वो सभी तरह की चीजें बेचते हैं और सस्ते दाम में बेचते हैं। उससे हमारे ऊपर भी असर पड़ सकता है। और फिर दुकान बंद हो सकती हैं, नौकरियां भी जा सकती हैं।

बड़े रिटेल की भले सुनहरी तस्वीर पेश की जा रही हो, मगर सच्चाई अलग है। दरअसल, इस धंधे में लगे बड़े खिलाड़ी है रिलायंस फ्रेश, सुपरमार्केट चलाने वाले आदित्य बिरला ग्रुप, सुभिक्षा, फ्यूचर ग्रुप, पिछले दस साल से वॉलमार्ट भारती ग्रुप के साथ साझे में कारोबार चला भी रही हैं। लेकिन इन्होंने किसानों के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। किसान आज भी अपनी फसलों को ओने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर हैं। इनके पास ग्रामीणों के रोजगार के नाम पर सिर्फ गार्ड की नौकरी होती है। अगर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाना है तो सरकार को आधारभूत संरचना में लाना चाहिए। किसानों के लिए सिंचाई हेतु नहर, सड़क, रेलवे, पुल, हवाई, अड्डा, बंदरगाह, भंडारण, फसल बीमा आदि में न कि चावल गेहूं बेचने के लिए।

मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

एक छलावा है। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न दी जाए।

[अनुवाद]

***शेख सैदुल हक** (बर्धमान-दुर्गापुर) : यू.पी.ए.-दो ने मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है इस कदम से वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिए गए इस विशेष आश्वासन का उल्लंघन होता है कि सरकार सभी भागीदारों की 'सर्वसम्मति के बिना आगे कदम नहीं बढ़ाएगी।

भारत में कृषि के बाद भारतीय खुदरा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें एन.एस.एस. के 2009-10 के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 4 करोड़ (40 मिलियन) से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें से अधिकांशत: वे लघु असंगठित अथवा स्वरोजगार प्राप्त खुदरा विक्रेता है; जिनको अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार नहीं मिल पाया।

एम.एन.सी. सुपरमार्केट और हाईपर मार्केट श्रृंखलाओं के प्रवेश से लघु और संगठित खुदरा व्यापारियों का गंभीर होगा वर्ष 2008 में आई.सी.आर.आई.ई.आर द्वारा करवाए गए असंगठित खुदरा व्यापारियों के नमूना सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया कि असंगठित दुकान का औसत आकार लगभग 217 वर्ग फीट होगा। संयुक्त राज्य अमरीका में वॉलमार्ट सुपरमार्केट का औसत आकार 108000 वर्ग फीट है जो लगभग 225 व्यक्तियों को रोजगार देता है। वर्ष 2010 में वॉलमार्ट ने 28 देशों में स्थित अपनी 9800 दुकानों के माध्यम से 405 बिलियन डॉलर की वस्तुएं बेंची और लगभग 2.1 मिलियन (21 लाख) लोगों को रोजगार दिया।

इसका तात्पर्य है कि एक वॉलमार्ट सुपर मार्केट 1300 से अधिक भारतीय छोटी खुदरा दुकानों को विस्थापित कर सकती है और इससे लगभग 3900 लोग बेरोजगार हो सकते हैं इसकी तुलना में उस सुपर मार्केट में सृजित रोजगार की संख्या 214 होगी अथवा अधिकतम 225, जो संयुक्त राज्य अमरीका का औसत है। स्पष्ट रूप से, यदि भारतीय बाजार में बड़ी एम.एन.सी. सुपर मार्केटों को प्रवेश की अनुमति दी गई तो रोजगार की गंभीर हानियां होंगी। अत: वित्त मंत्री का ये दावा कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से 3 वर्षों में 4 मिलियन (40 लाख) प्रत्यक्ष, तथा पृष्ठ भूमि संभार तंत्र में 6 मिलियन (60 लाख) तो यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। यह केवल कोई दावे हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है, जैसा कि वियतनाम में लगाया गया है, कि एक सुपरमार्केट में चार कामगारों द्वारा संचालित उत्पाद की मात्रा 8 दुकान विक्रेताओं, 10 खुदरा व्यापारियों या 18 पथ विक्रताओं द्वारा संचालित मात्रा के समान थी।

सरकार दावा करती है कि छोटे विक्रेताओं के हितों का संरक्षण किया जायेगा क्योंकि केवल 10 लाख से अधिक की आबादी वाले बड़े शहरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। परंतु यह सही नहीं है। ऐसे 53 शहर हैं और इन शहरों में लगभग 17 करोड़ लोग रहते हैं। उच्च खरीदारी क्षमता वाले लोग प्रमुख रूप से ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं और एम.एन.सी. रिटेल ऐसे बाजारों में ही रूचि रखते हैं इन 3 शहरों में खुदरा तथा थोक व्यापार में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। यही पर सर्वाधिक विस्थापन होगा।

सरकार की एक अन्य शर्त कि खुदरा व्यापार में न्यूनतम एफ. डी.आई. 100 मिलियन डॉलर (लगभग 500 करोड़ रूपए) होना चाहिए ये भी असंगत है क्योंकि भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश करने की रूचि लेने वाले एम.एन.सीज. वैश्विक रूप से बड़े है- विश्व के सर्वाधिक बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट का वार्षिक राजस्व वर्तमान में 400 बिलियन डॉलर से अधिक है। ये एम.एन.सीज. अपने मूल देशों में धीमी प्रगति कर रही हैं और विदेश में, विशेषकर भारत के बढ़ते बाजार में अपने प्रचालनों का विस्तार करने की लिए प्रबल इच्छा रखती है।

सरकार यह कहकर लोगों को मूर्ख बना रही है कि निवेशकों को भारतीय एस.एम.ईज से 30 प्रतिशत की खरीदारी करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जी.ए.टी.टी. का अनुच्छेद तीन स्पष्ट रूप से ये अधिदेश देता है कि प्रत्येक संविदाकार पक्ष अन्य संविदाकार पक्षों के उत्पादों के लिए 'राष्ट्रीय अभिक्रिया' प्राप्त करे और घरेलू उद्योगों से साधन जुटाने की विशेष अपेक्षा जैसे विनियमनों का स्पष्टत: निषेध करता है।

इसके अलावा एस.एम.ईज से साधन जुटाने की आवश्यकता फर्जी प्रतीत होती है, क्योंकि एम.एन.सी. रिटेलरों को केवल मध्यस्थ एस.एम.ई की आवश्यकता होगी।

सरकार का एक और दावा यह है कि किसानों को लाभ

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[शेख सैदुल हक]

होगा। परंतु तथ्य यह है कि विद्यमान मध्यस्थों की तुलना में बड़े रिटेलरों की खरीद क्षमता किसानों की बहुत अधिक होगी। किसान एम.एन.सीज. पर निर्भर होंगे और उनके शोषण की सम्भावना होगी। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ऐसा ही बताता हैं यहां तक कि यूरोपीय यूनियन ने फरवरी, 2008 में एक घोषणा को अंगीकार किया जिसमें कहा गया है कि सुपरमार्केट अपनी क्रय शक्ति का दुरूपयोग कर रहे हैं ताकि आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त मूल्यों को अवहनीय स्तरों तक कम किया जा सके और उन पर अनुचित शर्तें अधिरोपित की जा सकें। समग्र यूरोपीय देशों में सुपरमार्केटों के विरूद्ध किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में यह घोषणा की गई है।

सरकार का एक और दावा सही नहीं है कि खुदरा में एफ. डी.आई. के परिणामस्वरूप खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण होगा और बैक एंड आधारभूत ढांचे का विकास होगा अभी तक, बड़े खुदरा व्यापारियों अथवा कैश एंड कैरी होलसेलरों ने एकत्रीकरण और वितरण केन्द्र स्थापित करने के अतिरिक्त कोई बड़ा बैक एंड निवेश नहीं किया है। बैक एंड आधारभूत ढांचा वास्तव में शहरों में खुदरा विक्रय केन्द्र के निर्माण हेतु होंगे। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कुछेक कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रीजरेटिड परिवहन और अन्य संभार तंत्र केवल उनके स्वयं के व्यापार के लिए होंगे न कि किसानों तथा उपभोक्ताओं के। सरकार का एक और दावा कि एफ.डी.आई. के परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट आएगी, सत्य से काफी परे है। बड़े खुदरा व्यापारी कम लाभ पर बड़ी मात्राओं में सामान बेच कर लाभ कमा रहे है। जब कभी भी उनकी बिक्री गिरती है, वे अपने लाभ को बनाए रखने के लिए मूल्य बढ़ा देते हैं। उनका व्यापार अपने लाभ को अधिकतम करने की आवश्यकता से चलता है और मुद्रास्फीति को कम करने के प्रतिबद्धता से नहीं।

कुछ हलकों द्वारा यह तक दिया जा रहा है कि भारतीय बाजार की वृद्धि पर्याप्त रूप से अधिक है कि एम.एन.सी. सुपरमार्केटों तथा असंगठित रिटेल दोनों की साथ-साथ वृद्धि सुनिश्चित कर सके। परंतु ऐसा नहीं है। आर्थिक मंदी के दृश्य भारत में देखे जा सकते है। एम.एस.एस. सर्वेक्षण 2009-10 ने रोजगार रहित वृद्धि की पुष्टि की है। इस प्रकार, इस परिदृश्य में एम.एन.सी. खुदरा व्यापारी को भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देना, वृद्धि तथा रोजगार सृजन में योगदान देने से बहुत दूर, एक संकट को न्योता देना होगा।

अत: मैं मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि सरकार अपने इस निर्णय को वापिस ले।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : आपने मुझे देश के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश जैसे संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पूरा राष्ट्र चिंतित है। मल्टी ब्रांड किराने में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की इजाजत देकर सरकार ने जिस तरह खुदरा व्यापार या रिटेल के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी भूमिका के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, उसका विभिन्न स्तरों पर देश भर में जारी विरोध सर्वथा उचित है। देश के विभिन्न विरोधी दलों के साथ जिस तरह यूपीए के सहयोगी दलों ने भी इस जनविरोधी कदम के विरुद्ध आवाज उठाई है, वह स्वागत योग्य है। इससे हमारे लोकतंत्र की इस लुप्त हो रही विशेषता को नवजीवन मिला है कि राष्ट्र हित के मामलों पर सभी को संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए।

सरकार ने इस निर्णय के पक्ष में जो अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए हैं, वे किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। संभावित दुष्परिणामों की ओर तो सरकारी प्रचार में ध्यान ही नहीं दिया गया है। यहां तक कि बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों व दावों का आधार क्या है, यह भी नहीं बताया गया है। देश के किराना क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के प्रवेश के परिणाम कितने व्यापक व प्रतिकूल हो सकते हैं, इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। दूर-दूर के खेत-खलिहानों तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों या उनकी देशी सहयोगी कंपनियों ने अपने बीज, तकनीक व दवाएं फैलाने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाया हुआ है। कुछ फसलों पर इन बीज कंपननियों का नियंत्रण इतना बढ़ गया है कि उनके बीज का कोई विकल्प ही किसानों को नहीं मिलता है। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें छोटे व मध्यम किसानों के लिए सस्ती व स्वावलंबी खेती की संभावनाएं समाप्त हो रही हैं। भारत का आयात बाजार पहले ही बहुत खुला हुआ है। पेटेंट कानून के कारण कई स्थानीय उत्पादकों की बिक्री कम हो चुकी है। बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपनियां विश्वस्तर की खरीद नीति अपनाकर जहां भी सबसे सस्ते उत्पाद मिले, उनसे स्टोर भर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सकती है। इस तरह से उपभोक्ताओं के बड़े हिस्से को कम समय में ही आकर्षित कर सकती हैं। परंतु इससे देश के छोटे व मध्यम उद्योगों व किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि उनके उत्पादों के स्थान पर विदेशों से मंगवाए गए उत्पादों के सस्ते होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसका सबसे प्रत्यक्ष नुकसान देश के खुदरा व्यापारियों व रेहड़ी पटरी वालों को होगा क्योंकि जिन उपभोक्ताओं की अनेक जरूरतों को वे पूरा कर रहे थे, वह व्यापार अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां संभाल लेंगी। जिस तरह विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर ये कंपनियां सस्ता सामान खरीदना चाहती हैं उससे किसानों व छोटे उद्यमियों को लाभ मिलने वाला नहीं है। इसका सही आकलन करने के लिए विश्व व्यापार संगठन, मुक्त व्यापार समझौतों, पेटेंट कानूनों, कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तेज प्रसार और अब किराना क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के निर्णयों को जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारत जैसे देश की जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना जीवनयापन सेवा क्षेत्र में ही तलाशना हो, उसमें कोई खुदरा क्षेत्र को बड़ी कंपनियों के हवाले करने की सोचे, यह विचित्रा लगता है। जिस तरह धीरे-धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों, उपभोक्ताओं, उद्यमियों तथा मजदूरों आदि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है उसकी बड़ी कीमत देश को चुकानी होगी। देश के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से उत्पन्न खतरों से जागने का यह सही वक्त है। अत: मैं देश के किसान और मजदूर को बचाने के लिए सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए।

इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि देश के कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तेज प्रसार पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए तथा छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, छोटे उद्यमियों व रेहड़ी पटरी वालों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा) : मैं विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश होने पर क्या हालत होगी उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूं तथा उसके पश्चात मैं इस वॉल मार्ट प्रस्ताव का विरोध प्रकट करना चाहूंगी।

अभी हाल में यह पता चला है कि वॉलमार्ट कंपनी ने भारत में अपनी दुकानें खोलने हेतु सरकार पर दबाव डाला है। बिक्री की दृष्टि से वॉल मार्ट दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी है। 2010 में उसकी बिक्री 421 अरब डॉलर थी। भारत के जीडीपी की तुलना में 25 प्रतिशत वॉल मार्ट की बिक्री है। दुनिया के 15 देशों में इसकी 8,500 सुपर मार्केट हैं जिसमें 21 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इसकी एक माह की बिक्री 1.95 लाख करोड़ रुपये है। अमेरिका में जो खुदरा बिक्री होती है इसमें 50 प्रतिशत ज्यादा वॉल मार्ट की दुकानों से होता है।

पहले तो यह कंपनी बाजार के वर्तमान दामों से कम में माल बेचती है जिससे अन्य खुदरा दुकानें बंद हो जाती हैं। अमेरिका में जो किराना माल बेचा जाता है उसमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा माल वॉल मार्ट की दुकानों से बेचा जाता है। वॉल मार्ट की बाजार दाम से कम बेचने की नीति से अमेरिका में पुरानी किराना दुकानें एक के बाद एक करके बंद होने लगी हैं।

अमेरिका की आईवोआ स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि जिस विस्तार में वॉल मार्ट दुकानें शुरू होती थी वहां पर 10 वर्षों में 90 प्रतिशत चलने वाली पुरानी दुकानें बंद हो जाती थी।

दूसरे अध्ययन के मुताबिक 2001 से 2005 के बीच वॉलमार्ट कंपनी के कारण 2 लाख अमेरिकन बेकार हुए थे। उसका कारण वॉलमार्ट कंपनी में जिस माल का उत्पादन हो रहा था उसका आयात चीन से करना शुरू किया, फल स्वरूप अमेरिका में कारखाने बंद हुए और लोग बेकार हुए तथा बेरोजगारी को बढ़ावा मिला।

अगर भारत में उसका आगमन हुआ तो दुकान मालिकों को वॉलमार्ट की नौकरी करनी पड़ेगी। भारत सरकार ने वॉल मार्ट को उसकी दुकानों में बेचने (70 प्रतिशत) वाले माल को आयात करने की छूट दी है फलस्वरूप भारत के 6 करोड़ छोटे उत्पादक बेकार होने का भय पैदा हुआ है। वॉल मार्ट कंपनी के कारण कॉर्पोरेट फार्मिंग बढ़ रहा है जिसमें मालिकी कंपनी की होती है। भारत में यदि इसका पदार्पण हुआ तो अनेक किसान अपने खेत बेच देंगे तथा उनके ही खेतों में खेतिहर मजदूर बने रहेंगे। भारत में वॉलमार्ट भारत के सप्लायरों का शोषण करेगी। जैसे कि उत्पादकों ने अपना माल उचित/सस्ते दाम न बेचा तो उसकी खरीदी बंद करके उसे दिवालिया घोषित कर देगी।

अगर वॉल मार्ट भारत में आई तो अपने उपभोक्ताओं को चीजें सस्ते दर में मिलेगी यह केवल परिकल्पना है वॉल मार्ट की नीति

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती जयश्रीबेन पटेल]

ऐसी है कि प्रारंभ में सस्ते दर में माल बेच के स्थानिक स्पर्धा खत्म कर देना–एवम् उसकी विस्तार में मोनोपोली स्थापित होने के पश्चात दामों में बेलगाम वृद्धि करके ग्राहकों का शोषण करना–इसके आने से अपने व्यापारी, ग्राहकों, उत्पादकों, किसानों इत्यादि को लाभ होने की संभावना नजर नहीं आ रही है।

मैं सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चहाती हूं कि एफ.डी.आई. की मर्यादा 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत करने का प्रावधान देश के इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हानिकारक है जो भी फायदा होना है वह विदेशी कंपनियें को होगा। पहले वित्त मंत्री जी एवम् स्टेंडिंग कमेटियों ने उपरोक्त मत का अनुमोदन किया था। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त मामले को प्रस्ताव में न लें।

अंत में मैं कहना चाहूंगी कि मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस लें।

[अनुवाद]

***श्री एम. राजा मोहन रेड्डी** (नैल्लोर) : हम मानवीयता के साथ सुधार चाहते हैं। हम समानता के साथ वृद्धि चाहते हैं। हम विदेशी पूंजी का तब तक स्वागत करते हैं जब तक कि उससे रोजगार का सृजन हो और हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका से वंचित न हो। हम विनिर्माण, विद्युत और अन्य आधारभूत ढांचा क्षेत्रों में एफ.डी.आई. प्रवाहों का स्वागत करते है क्योंकि उनका एक मजबूत गुणक प्रभाव होता है।

मुद्दे के केन्द्र में करोड़ों लोगों की आजीविका है। हमारी जनसंख्या के बड़े भाग के बीच एक वास्तविक आशंका है कि खुदरा क्षेत्र में प्रस्ताविक एफ.डी.आई. निश्चित रूप से करोड़ों स्व-नियोजित खुदरा व्यापारियों को विस्थापित करेगा और कृषि समुदाय को अस्त-व्यस्त कर देगा। इस चिंता पर एफ.डी.आई. नीति की घोषणा करने से पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। सरकार को इस निर्णय की घोषणा करने से पूर्व इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से व्यापारियों तथा किसानों, के साथ चर्चा करना चाहिए थी। इसके बजाए आप एक निर्विवादित तथ्य को प्रस्तुत कर रहे है।

यदि सरकार मानती है कि हमारे विद्यमान लाखों खुदरा व्यापारियों के लिए आजीविका की कोई हानि नहीं होगी या किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उसे केवल विश्वास जताने के बजाए अपनी प्रतिबद्धता यह आश्वासन देकर दर्शाना चाहिए था कि वह समेकित निधि से उपयुक्त मुआवजा देकर आजीविका की हानि, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी होंगी।

सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों कार्रवाई कर रही है? क्या किसी ने शिकायत की है कि उन्हें अपने आसपास कोई उत्पाद या वस्तु नहीं मिल रही है? हमें अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है न कि वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में।

जी, हां शिकायतें मिली हैं। विद्युत की अनुपलब्धता, सुरक्षित पेय जल की अनुपलब्धता कोयले की अनुपलब्धता, प्राकृतिक गैस और ऐसी केई आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के संबंध में शिकायतें मिली है परंतु निश्चित रूप से खुदरा उत्पादों के संबंध में तो नहीं। परंतु सरकार उनकी उपलब्धता में सुधार करने के लिए कुछ नहीं करती है।

यह आश्चर्यजनक है कि खुदरा व्यापार जैसा मुद्दा जिसके संबंध में कोई भी शिकायतें नहीं थीं, सरकार अत्यधिक सक्रिय हो गई, यह दावा करते हुए कि भारतीय किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

1. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि हमारे किसान कृषि-उत्पादों में सट्टेबाजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संभावित एकाधिकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों क्योंकि सट्टा बाजार में ऐसे मजबूत निकाय कृत्रिम दुर्लभता उत्पन्न करेंगे और लाभ भी कृषक समुदाय को नहीं दिया जाएगा।

2. सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि सभी बहुराष्ट्रीय खुदरा विक्रेता अपने समूचे कृषि उत्पादों को देश के भीतर से प्राप्त करे और किसी भी प्रकार का कुल आयात उनके टर्नओवर के 20 प्रतिशत से अधिक का नहीं होना चाहिए।

3. सरकार को यह भी निर्धारित करना चाहिए कि खुदरा विक्रेता हमारे किसानों के उपयोग हेतु गोदाम और कोल्ड स्टोरेज जैसी समान सुविधाएं बनाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

4. सरकार को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिसमें किसान, सरकार भी भविष्य के क्रियाकलापों में बड़े निकायों के साथ एक पक्ष बने। सरकार को छोटे तथा लघु दुकानदारों के बचाव के लिए कड़े नियम बनाने का सुनिश्चय करना चाहिए।

हमारी पार्टी वर्तमान स्वरूप में खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. का समर्थन नहीं कर सकती जब तक सरकार आजीविका तथा किसानों के हितों के संरक्षण के संबंध में आश्वासन न दे।

***श्री कल्याण बनर्जी** (श्रीरामपुर) : प्रधान मंत्री ने वर्ष 2005 में भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सच्चर समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट संसद में 30 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार खुदरा व्यापार में 17.1 प्रतिशत कार्यशील मुस्लिम जनसंख्या नियोजित है जबकि इसकी तुलना में हिंदू केवल 8 प्रतिशत और अन्य अल्पसंख्यक 10 प्रतिशत ही नियोजित हैं। व्यापार एवं खुदरा व्यापार में नियोजित व्यक्ति बहुसंख्यक समुदाय की तुलना मे मुस्लिम समुदाय में दोगुने हैं, और उनकी आजीविकास के मुख्य स्त्रोत को यू.पी.ए. सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में सौंप रही है।

भारत में 2 प्रतिशत संगठित खुदरा व्यापार है और 98 प्रतिशत असंगठित खुदरा व्यापार है। इसके अतिरिक्त, भारत की कुल जनसंख्या का 4 प्रतिशत खुदरा व्यापार में है, जो भारत के सामाजिक-आर्थिक संतुलन में इस महत्वपूर्ण व्यापार के बारे में काफी कुछ कहता है।

भारत में अभी भी खुदरा के परम्परागत रूप का प्रभुत्व है, अर्थात् लोकल किराना दुकानें, पान-बीड़ी दुकाने, हार्डवेयर स्टोर। देश में लगभग 100 मिलियन दुकानों के साथ भारतीय खुदरा उद्योग अत्यधिक खंडित है। वैश्विक परामर्शदात्री फर्म ए.सी. नीलसन और के.एस.ए. टेक्नोपार्क के अनुसार, संसार में दुकान घनत्व सबसे अधिक है। वर्ष 2001, में अनुमान लगाए गए अनुसार प्रति 100 व्यक्ति पर 11 दुकाने थीं। इसके अतिरिक्त, मैकिन्से एंड कंपनी और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया गया था कि टेस्को, किंगफिशर, कैरीफोर और ए-होल्ड जैसे वैश्विक रूप से बड़े खुदरा निकाय खुदरा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। यह रिपोर्ट यह भी कहती कि भारतीय खुदरा बाजार के वर्ष 2010 तक 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का होने की संभावना है।

हमारे देश में खुदरा व्यापारियों की इतनी बड़ी संख्या देश में बेरोजगारी तथा कम रोजगार की उपलब्धता के कारण है। खुदरा दुकाने खोलने के पश्चात वे स्व-रोजगार वाले बन गए। खुदरा व्यापारी इच्छा के बजाए परिस्थितिों के कारण उत्पन्न होता है।

विश्व के सबसे बड़े खुदरा व्यापारी ''वालमार्ट'' का टर्नओवर 256 बिलियन डालर है और यह प्रतिवर्ष 12-13 प्रतिशत की औसत से बढ़ रहा है। असंगठित क्षेत्र की तो बात छोड़िए, कोई भारतीय खुदरा व्यापारी वालमार्ट जैसी फर्म के आ जाने पर उसके प्रभाव से बच पाएगा। अपने अत्यधिक बढ़ते हुए प्रभाव के साथ वालमार्ट कई वर्षों तक हानि सहन का लेगा जब तक उसका निकट प्रतिद्वंदी समाप्त न हो जाए।

भारत में प्रत्येक में 1 मिलियन से अधिक की न्यूनतम जनसंख्या वाले 35 शहर है। यदि वालमार्ट को औसतन इन शहरों में से प्रत्येक में एक वालमार्ट स्टोर खोलने की अनुमति दी जाए तो 83,330 मिलियन रूपए से अधिक के टर्नओवर को देखते हुए वालमार्ट का प्रति स्टोर औसत कार्य-निष्पादन केवल 10,195 कर्मचारियों का होगा। इसका अर्थ लगभग 4,32,000 व्यक्तियों को विस्थापित करना होगा। यदि एफ.डी.आई. चालित खुदरा विक्रेताओं की बड़ी संख्या 20 प्रतिशत खुदरा व्यापार ले लेती है, जैसा कि दबाव में जकड़ी हुई हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड चिंतित होकर प्रत्याशा करती है, तो इसका अर्थ होगा कि आज के आधार पर 800 बिलियन रूपए का टर्नओवर। इसका अर्थ मात्र 43,450 व्यक्तियों को रोजगार मिलना होगा, जिससे असंगठित खुदरा क्षेत्र में नियोजित लगभग आठ मिलियन व्यक्ति विस्थापित होंगे।

खुदरा दुकानों में एफ.डी.आई. की अनुमति देने के इस निर्णय का प्रभाव पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012 को सरकारी अनुमोदन के प्रभाव को समाप्त करना होगा। यदि इस प्रकार के निगमों को पथ विक्रेताओं से प्रतियोगिता करने की अनुमति दी जाती है, तो पथ विक्रेताओं की आजीविका की केवल विक्रय क्षेत्र बना कर रक्षा नहीं की जा सकती।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : भारत के संविधान की उद्देशिका का पाठ यह है "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता. .."इत्यादि।

किन्तु सभी क्षेत्रों जिसमें बहुब्राण्ड खुदरा भी शामिल हैं, में निजीकरण और एफ.डी.आई. का वर्तमान अल्पमत के गैर जिम्मेदाराना समर्थन से ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस देश की सर्वोच्च विधि के आधारभूत सिद्धांतों से पीछे हट रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व, जो अन्यथा श्रीमती इंदिरा गांधी और पं. जवाहरलाल नेहरू जैसे अपने नेताओं की अवमानना के लिए किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार रहता है, हमारे देश के लिए इन दोनों महान नेताओं के विजन से अनजान है और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित नीति से हटने के लिए अडिंग है।

स्वर्गीय इंदिरा, गांधी की कांग्रेस सरकार ने संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 पेश किया और स्वीकार किया था जिसके छारा 'समाजवादी' शब्द उद्देशिका में शामिल किया गया था। तब से किसी भी मत की सरकार ने समाजवादी शब्द को बदलने या हटाने के बारे में नहीं सोचा, यद्यपि इन वर्षों में संविधान में अनेक संशोधन किए गए।

संक्षेप में मूल प्रश्न है कि "क्या वर्तमान संविधान में एफ. डी.आई. अनुक्षेय है?" चूंकि हम सभी संसद सदस्यों ने देश के संविधान को कायम की शपथ ली है इसलिए केन्द्र सरकार को भी संविधान का अनुसरण और पालन करना चाहिए।

यदि हम भारत में एफ.डी.आई. की अनुमति देते हैं, तो यह देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् भारत के संविधान के विरूद्ध है।

*श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लम) : मैं बहु ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को वापस लेने के लिए विपक्ष की नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कारोबार, व्यापार और उद्योग के वैश्विक एकीकरण के युग में, विश्व के साथ चलने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हम जानते हैं हमारे लाखों इंजीनियर और डॉक्टर विदेशों में काम कर रहे हैं और हमारे देश के बहुत सा विदेशी मुद्रा लाते हैं। लाखों लोगों को भारत में रहते हुए आउटसोर्सिंग के जरिए काम मिला हुआ है। हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग फल-फूल रहा है और अपने उत्पाद विदेश में बेच रहा है।

बहु-ब्राण्ड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारी सरकार द्वारा बिना किसी शर्त्त या प्रतिबन्ध के नहीं आ रहा है। प्रथम दृष्ट्या में जो भी विदेशी कंपनी भारत में कारोबार करना चाहेगी उसे देश में 100 मिलियन डॉलर निवेश करना होगा। इसमें से 50% बैकइंड अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करना पढ़ेगा। इससे शीतागार श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, माल प्रबंधन, किसान सहायता तंत्र, खाद्य प्रसंस्करण करने वालों और इसके वितरकों को लाभ होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को उत्पादन सामग्री का तीस प्रतिशत एस.एम.एस.ई. क्षेत्र से लेना होगा। बहु-ब्राण्ड खुदरा क्षेत्र मैं भारी एफ.डी.आई. का सीधा नतीजा होगा रोज़गार सृजन।

हमारा देश विश्व में दूसरे सबसे बड़े फल और सब्जी उत्पादक है। हम 200 मिलियन टन से अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। बाज़ार की अनुपलब्धता और हमारे देश के किसानों के पास शीतागार सुविधा के होने के कारण उन फल और सब्ज़ियों का 35 से 40 प्रतिशत सड़ जाता है। इससे हज़ारों करोड़ रूपए की हानि होती है। बहु-ब्रांडिंग द्वारा उत्पादित मद किसानों से सीधे खरीदी जाती हैं और उन्हें उचित मूल्य अथवा उससे अधिक मूल्य भी, दिया जाता है क्योंकि उसे ऐसी जगह बेचा जा सकता है जहां उसकी अच्छी कीमत मिले। इस प्रकार उन बिचौलियों से बचा जा सकता है जो लाभ का एक बड़ा भाग रखते थे।

एफ.डी.आई. उत्पादक क्षमता को बढ़ाएगा। यह देश में रोज़गार सृजन के अतिरिक्त, अवसंरचना और परिसांपत्तियां निर्मित करने में सहायता करेगा। इससे प्रौद्योगिकी उन्नयन होगा और इस प्रकार कारोबार और व्यापार बढ़ेगा। इससे देश का आर्थिक विकास होगा।

हम देख सकते हैं कि चीन किस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ वैश्विक बाजार में प्रगति कर रहा है। यदि भारत को विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करती है तो हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे और विदेशी कंपनियों को भारत आने व निवेश करने देना होगा।

हम जानते हैं कि अपने बाजार में विश्व ब्राण्डों की अनुमति देकर यह उपभोक्ताओं के लिए मात्रा, प्रतिस्पर्धा और संसद में सुधार लायेगा और इस प्रकार रोज़गार सृजन व अर्थव्यवस्था का विकास होगा।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने देश के किसी भी राज्य पर एफ.डी.आई. को थोपा नहीं है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में एफ. डी.आई. के स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री जोस के मणि** (कोट्टायम) : मैं बहु ब्राण्ड खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. के संबंध में अपने दल केरल कांग्रेस (एम) के विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार ने बहु ब्राण्ड खुदरा में एफ.डी.आई. की अनुमति दी है और इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यद्यपि एक पक्ष ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है क्योंकि यह आशा की जाती है कि एफ.डी.आई. से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा प्रौद्योगिकी में निवेश होगा, जनशक्ति और कौशल विकास होगा, बाजार के आकार में वृद्धि होगी और अधिक जी.डी.पी., कर आय इत्यादि द्वारा सरकार के। लाभ होगा। दूसरी ओर लोग खुदरा में एफ.डी. आई. का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे असंगठित खुदरा व्यापार में नियोजित लोगों का भारी विस्थापन होगा और इसे अतिरिक्त जनशक्ति को समाहित कर लेने में वर्तमान विनिर्माण क्षेत्र असमर्थ है। इन वैश्विक खुदरा व्यापारियों का एकाधिकार वादी रूख अपनाने और आपूर्तिकत्ताओं तथा उपभोक्ताओं दोनों के उत्पीड़न की भी आशंका है।

यद्यपि खुदरा में एफ.डी.आई. के संबंध में ये मुख्य मुद्दे हैं, तथापि मेरे राज्य केरल को एक अनौखी स्थिति का सामना कर रहा है। वहां बड़ा खुदरा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र की मजबूत अर्थव्यवस्था है। खुदरा श्रृंखलाओं की संख्या के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच भेद नहीं किया जा सकता।

जैसा कि आप जानते हैं, केवल उत्तर से दक्षिण केरल तक एक विस्तृत शहर है कसारगोड से त्रिवेंद्रम तक यह नगर क्षेत्र है। इस और इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोई भेद नहीं है। केरल एक छोटा सा राज्य है यहां की जनसंख्या घनी है और एक उपभोक्ता राज्य है। पर्याप्त भूमि की उपलब्धता की कमी और पर्यावरणीय खतरों के कारण, केरल में कोई भी श्रम प्रधान विनिर्माण उद्योग नहीं हैं। केरल की अधिकांश जनसंख्या के लिए रोज़गार का मुख्य स्रोत छोटी खुदरा दुकानों की स्थापना अथवा मध्यम खुदरा स्थापनों के अंतर्गत रोजगार पाना है।

राज्य के छोटे व्यापारियों के बीच एक वास्तविक आशंका यह है कि विदेशी खुदरा व्यापारी उन्हें पंगु बना देंगे। और उन्हें समाप्त कर देंगे। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि अधिकांश विकसित देशों में जहां खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को अनुमति दी गई है, छोटे व्यापारी समाप्त हो गए।

आरंभ में विदेशी खुदरा व्यापारी बहुत उपभोक्ता हितैषी होने का दिखावा करते हैं और अंतिम उपभोक्ता को काफी कम कीमत पर वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इसी दौरान छोटे खुदरा व्यापारी बड़े व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। धीरे-धीरे छोटे व्यापारी परिदृश्य से गायब हो जाएंगे। इसी प्रकार बहु राष्ट्रीय कंपनियां आरंभ में आपूर्तिकर्ताओं नामत: कृषकों को बहुत अधिक मूल्य देते है। परंतु एक बार जब एम.एन.सी. बाजार में अग्रणी बन जाते हैं तो इनको एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी और ये आपूर्तिकर्ता तथा उपभोक्ता से मनमानी कीमत वसूलेंगे।

केरल में अधिकांश किसान छोटे भूमि धारक हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम क्षेत्र की भूमि है। अगर एक बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है तो एम.एन.सी. सैंकड़ों और हजारों एकड़ भूमि वाले बड़े भू धारकों के साथ वृहत कृषि संविदा करेंगी। छोटे किसानों का सफाया हो जाएगा अथवा उनको मजबूरन बड़े भू धारकों को कृषि के लिए भूमि देनी पड़ेगी और अंतत: छोटे किसान ठेकेदार अथवा बड़े भूमि धारकों के अधीन मजदूर बन जाएंगे।

अत: मेरे दल का मत है कि नीति का कार्यान्वयन करने से पहले पूरा ध्यान रखने और सावधानी बरतनी होगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की केरल सरकार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति की है। इंडोनेशिया, जापान और थाइलैंड में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण छोटे व्यापारियों का कारोबार सिमट गया है और इन देशों को नियंत्रण तंत्र के रूप में जोनिंग कानून और आकार विनियमों का सहारा लेना पड़ा था। भारत को भी ऐसी प्रतिबंधात्मक नीतियों को सख्ती से अपनाना चाहिए।

माननीय मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं, जिनमें से कुछ विचार करने योग्य हैं।

किराना और खाद्य वस्तुओं के खुदरा व्यापार में विदेशी निगमित रिटेलरों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और अन्य उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री पर भी कुछ प्रतिबंध लगाया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जोस के मणि]

चयनित उत्पादों के लिए छोटे और मध्यम खुदरा व्यापारियों हेतु आरक्षण नीति अपनाई जाए और इनके आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन एक स्वतंत्र निकाय द्वारा कराया जाना चाहिए। मेरे दल का विचार है कि खुदरा क्षेत्र में बड़े खुदरा व्यापारियों को अनुमति देने में बहुत गंभीर मुद्दे और जोखिम हैं। अतः, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से पहले हालांकि यह विधेयक भी नहीं है, हमें इस नीति को शुरू करने की व्यवहार्यता के संबंध में जनता की राय प्राप्त करनी चाहिए। अतः सरकार को रक्षोपाय और प्रतिबंध का पैकेज तथा पुनर्वास की योजना तैयार करनी चाहिए। रक्षोपायों और पुनर्वास के ऐसे पैकेज को जनता की राय के लिए भी प्रस्तुत किया जाए।

हमारा दल के.सी. (एम) यू.पी.ए. का एक घटक है। हमारा विश्वास है कि हम सरकार के हाथों का मजबूत करेंगे और हम सरकार के समर्थन के लिए वचनबद्ध है। हालांकि सरकार ने, इस नीति को स्वीकार करने अथवा नहीं करने का विशेषाधिकार राज्यों को दिया है, हमारे दल का तर्क है कि सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करे और बहुत से लोगों के मस्तिष्क में इसके विरोध में जो मुद्दे हैं उनका समाधान करे और इनको स्पष्ट करे।

***श्री एस. सेम्मलई** (सलेम) : हम मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध में है। माननीय विपक्ष के नेता द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं दो या तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे परम पूजनीय नेता ने, तमिलनाडु की जनता और व्यापारियों को यह पूर्ण वचनबद्धता दी है कि तमिलनाडु में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

माननीय कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए रोजगार सृजन, किसानों के लिए लाभप्रदता, और बिचौलियों का उन्मूलन करने के तर्क बेकार हैं और झूठे विचार हैं। माननीय मंत्रीगण आपकी जानकारी के लिए, ये एक आदर्श स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होगा। जैसा कि हमारे नेता ने कहा है कि खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना आत्महत्या का प्रयास करने जैसा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

30 प्रतिशत उत्पादों को स्थानीय क्षेत्र से खरीदने की पूर्व-शर्त को लें। बड़े खुदरा व्यापारियों द्वारा स्थानीय बिल्कुल गारंटी नहीं है।

हालांकि भारतीय लघु उद्योगों से 30 प्रतिशत खाद्य पदार्थों की खरीदी रखी गई है परंतु इसमें निम्नवत जोड़कर इसको हल्का कर दिया गया है

सर्वप्रथम आवश्यकतानुसार खरीद अपेक्षा को पूरा किया जाएगा, जो कि पांच वर्ष की अवधि में खरीदे गए विनिर्मित/संसोधित उत्पादों के कुल मूल्य का औसत होगा, ये अवधि उस वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होगी जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रथम भाग प्राप्ति की गई हो।

इस प्रकार वैश्विक रिटेलर कम से कम पहले चार वर्षों में विश्व में कहीं से भी 100 प्रतिशत तक की खरीद करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यह 30 प्रतिशत जोड़ गया और वैश्विक रिटेलर 30 प्रतिशत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी वस्तु का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के समर्थक कहते हैं कि केवल 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में ही ऐसी दुकानें खोलने की सीमा है।

परंतु इसके विपरीत, अधिसूचना में प्रावधान है कि ''जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नहीं है, वहां इनकी अपनी रूचि के शहरों में खुदरा बिक्री की दुकानें खोली जा सकती हैं।

इससे स्पष्ट होता है, कि वैश्विक खुदरा विक्रेता कहीं भी रिटेल दुकानें खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था बचत पर आधारित है। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक स्तर पर हिस्सेदारी बचत से आती है, यह लगभग 23 प्रतिशत है जो चीन के आस-पास ही है।

जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है यदि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी जाती है तो यह हमारी अर्थव्यवस्था की बचत का बड़ा भाग हड़प सकती है। केवल इतना ही नहीं आगे चलकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, खुदरा क्षेत्र में बिचौलियों का सफाया नहीं करेगी और किसानों को भी बेहतर लाभ सुनिश्चित नहीं होंगे। अमरीकी एजेंसी द्वारा कराए गए एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वॉल-मार्ट द्वारा सृजित प्रत्येक रोजगार के लिए, समुदाय के दो लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इसके अलावा, जैसा कि केन्द्र का अनुमान है, कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से विदेशी कंपनियों के बड़े निवेश आकर्षित नहीं होंगे।

सामान ऋण पर खरीदा जाता है और बिक्री नकद की जाती है। इसलिए कार्यकारी पूंजी नगणय है। सुधार किसके लिए? आम आदमी के लिए? अथवा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के लिए।

आरंभिक अवसंरचना के पश्चात् वे भारत से अर्जित पूंजी में से बड़ी धनराशि अपने देशों को प्रेषित करेंगे। इस प्रकार, अंतत: इससे तमिलनाडु की पूंजी की भी दुर्दशा होगी। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस कदम को आत्महत्या करने के प्रयास के समान बताया है, यदि अगर यहीं सरकार की इच्छा थी, तो उसने खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत की अनुमति क्यों दी? इसका क्या परिणाम होगा? बहुराष्ट्रीय निगमों का पूर्ण नियंत्रण होगा। वे निबंधन और शर्तों के आदेश देंगे। उपभोक्ताओं को वही खरीदना होगा जो वे बेचेंगे। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दीर्घावधि में, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खेले जा रहे खेल में केवल मोहरा बन कर रह जाएंगे। अत: मैं सरकार से इस कदम को न उठाने और करोड़ों छोटे खुदरा व्यापारियों की आजीविका के लिए मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह करता हूं।

अत: मैं सरकार से इस प्रस्ताव को छोड़ने का आग्रह करता हूं ताकि करोड़ों छोटे खुदरा व्यापारियों की आजीविका के निर्वहन का मार्ग खुला रहे।

[हिन्दी]

***श्री बदरुद्दीन अजमल** (धुबरी) : सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे हाऊस में एफडीआई पर चल रही बहस में अपनी बातें रखने का मौका दिया। हमारी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूपीए की अलाई है और मैं पार्टी का लीडर होने की हैसियत से हुकूमत की पॉलिसियों से अमूमन मुत्तफिक रह हूं और उसकी ताईद और हिमायल करता रहा हूं। मगर चूंकि आम आदमी का नुमाइंदा होने के नाते मेरे लिए उनका मफाद सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए अगर हुकूमत के सिकी डिसीजन से किसी आम आदमी पर बैड इफैक्ट पड़ता है तो उसे वाजेह करना भी मेरी जिम्मेदारी है ताकि उसकी इसलाह हो सके और शकूक व शुबहात दूर हो सके। आज एफडीआई (खुदरा बाजार में बराहे रास्त गैर-मुल्कि सरमायाकारी) पर बहस हो रही है। जो आज मुल्क में बहस व मुबहासे का टौपिक बना हुआ हैं बहुत से लोग इसे हुकुमत का एक तारीफि कदम करार देकर उसकी हिमायत कर रहे हैं तो बहुत से लोग इसे अवाम मुखालिफ कहकहर उसकी मुखालफत कर रहे हें। खुखालफत करने वालों में यूपीए की बहुत सी अलाई पार्टियां भी शामिल हैं। उनके बहुत से ऐतेराजात और शकूक व शुबहात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि उसे संजीदगी से हल किया जाना चाहिएं हकीकत यह है कि एफडीआई के निफाज में जहां मुल्क की मईशत में पाजिटिव तब्दीजी का पहलू है वहीं ये बहुत से नेगेटिव पहलू भी रखता है। मिसाल के तौर पर एफडीआई के इंपीलीमेंट होने से किसान और आम कंज्यूमर को फायदा होगा। क्योंकि किसान अपने प्रोडेक्ट की सही कीमत पा सकेंगे और कंज्यूमर्स अच्छी कीमत देकर अच्छा माल हासिल कर सकेंगे। अभी हमारे मुल्क में बहुत बड़ी ट्रेजिडी यह है कि किसान पूरी मेहनत करके अनाज पैदा करता है मगर वो उसकी सही कीमत हासिल नहीं कर पाते। बल्कि वाजदफा लागत से भी कम कीमत मिलती है। जिससे मायूस होकर वो खुदखुशी कर लेता है या अपनी मांग को लेकर ऐहतजाज करता है तो उन्हें पुलिस की गोली खानी पड़ती है और यह सब होता है बिचौलिया लोगों की वजह से। जो कम से कम कीमत पर खरीद कर ले जाते हैं और मार्किट में उसे बड़ी कीमत पर बेचते हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को उस प्रोडेक्ट को हासिल करने के लिए ज्यादा कीमत हासिल करनी पड़ती है। एफडीआई के जरिए इस प्रोबलम के हल होने की उम्मीद है क्योंकि उसमें बिचौलिये का रोल खत्म हो जाएगा और कंपनियां किसानों से डायरेक्ट माल खरीदकर सारफीन को मुहैया कराएंगी और चूंकि कंपीटिशन की वजह से हर कंपनी अच्छी कीमत देकर किसान की पैदावार को खरीदने की कोशिश करेगी और मार्किट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई के लिए कम से कम मुनाफे पर उम्दा और फ्रैश माल फरोख्त करने की कोशिश करेगी तो किसान और कंज्यूमर्स दोनों का फायदा होगा। इस तरह एफडीआई से मुल्क में जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लग सकेगी और आवाम को फूड शार्टिज से निजात मिलेगी। बारेहा देखा गया है कि एक मखसूस प्रोडेक्ट अचानक मार्किट से गायब हो जाता है और उसकी कीमत आसमान छूने लगती है और यह अफवाह फैलाई जाती है कि मुल्क में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे हालत में लोग मजबूर होते हैं कि वो बड़ी कीमत देकर उस प्रोडेक्ट को हासिल करे। मगर हकीकत में ये जमाखोर हजरात जिनका मार्किट पर कंट्रोल है और जो कालाबाजारी करके लोगों की जेब पर डाका डालते हैं उनकी चालबाजी होती है। यही वजह है कि जब छापामारी की जाती है तो वही चीज जिसकी बाजार में शार्टिज होती है वह बड़ी मिकदार में गोदाम में पड़ी हुई मिलती है। एफडीआई के जरिए जमाखोरों की इस हरकत से छुटकारा मिलने की उम्मीद है।

हमारा मुल्क फलों और सब्जियों की पैदावार की ताल्लुक से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मगर उन प्रोडेक्ट का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हमारे मुल्क में कोल्ड स्टोरेज वगैरह की कमी है। जहां उसे महफूज रखा जा सके। एफडीआई की बदौलत

*मूलत: उर्दू में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री बदरुद्दीन अजमल]

जब बड़ी कंपनियां मार्किट में आएंगी तो उन पर प्रोडक्टस को सेफ करने के जराए में इजाफा होगा और वो बर्बाद होने से बच जाएगी। जिसका फायदा मुल्क को होगा। इसी तरह इंपोर्ट, एक्सपोर्अ और ट्रांसपोर्ट के मैयार में मैं भी मुसबत तब्दीली का इमकान है।

मगर यह बात वाजिहा कर देना चाहता हूं कि एफडीआई के ताल्लुक के बहुत से खदशात है जिसे दूर करने की जरूरत है और बहुत सी चीजें हैं जिसे वाजिहा करने की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि एफडीआई के नेगेटिव पहलू और उससे पैदा होने वाले मिश्र असरात को भी जहन में रखे और उसका मुनासिब हल तलाश करने के बाद ही इस स्मित में कदम उठाए। मिसाल के तौर पर बहुत से मुल्क में एफडीआई का तजुर्बा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है और वहां से उसे खत्म करने की तहरीक चली है। अमरीका, इंग्लैंड और थाईलैंड इसकी मिसाल है। अब हमें उन तमाम प्वाइंटस को, जिनकी वजह से इन कंट्रीज में एफडीआई का तजुर्बा नाकाम हुआ, उसको नजर में रखना जरूरी है। एफडीआई के तालुक से यह बात भी कही जा रही है कि इससे मुल्क के छोटे-छोटै ताजर बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे किराना दुकानदार, पंसारी, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, ठेले पर मोहल्ले-मोहल्ले घूम-घूमकर बेचने वाले, वीकली मार्किट में दुकान लगाने वाले और इस तरह गांव-मोहल्ले और बाजार में छोटी-छोटी दुकान वाले या मिडिल क्लास के ताजिर। क्योंकि जब वामलार्ट, कारफोर और टेस्को जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां आ जाएंगो और बड़े-बड़े माल्स और सुपरस्टोर्स खुल जाएंगे तो स्माल, लोकल बिजीनेसमैन उसके मुकाबले मार्किट में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि एफडीआई के जरिए रोजगार के जो मौके पैदा होंगे वो जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे। जो इन तमाम की बेरोजगारी दूर कर दे। नेज इन कंपनियें में नौकरियों के लिए जो शराइत होंगी और उनका जो स्टैंडर्ड होगा उस पर उस तब्के के ज्यादातर लोगों का खतरा होना मुश्किल होगा।

मेरे ख्याल से एफडीआई का बुरा असर मैन्यूफेक्चर सैक्टर पर ज्यादा पड़ेगा। अगरचे 30 प्रतिशत लोकल कंपनी से खरीदने की शर्त लगाई गई है। मगर यह कम है। उसे बढ़ाकर 80 फसीदी करना चाहिए। मैडम, हमारे मुल्क में अक्सरियत गरीब तबके और मीडिल क्लास लोगों की है। उनमें ज्यादा अफराद नौकरीपेशा है और अमूमन अपने पड़ोस में वाक्या दुकान से राशन और दीगर जरूरी सामान लेते रहते हैं और महीने की सैलरी मिलने परउसे अदा करते हैं। मगर जब माल और सुपरस्टोर सिस्टम हो जाएगा तो तमाम मामलात नकद होंगे जिससे इस तबके के लिए परेशानियां पैदा होंगी।

इस बात का अंदेशा है कि शुरू में अपने कंदम जमाने के लिए और लोकल बिजनेसमैन को मार्किट से हटाने के लिए बड़ी कंपनियां किसानों को उनकी पैदावार की अच्छी कीमत अदा करें। मगर बाद में वो किसानों के मफाद को इग्नोर करके पैदावार की कमल कीमत अदा करें। मगर बाद में वो किसानों के मफाद को इग्नोर करके पैदावार की कम कीमत लगाएंगे और फिर ना चाहते हुए भी किसान उन्हीं कंपनियों को फरोख्त करने पर मजबूर होंगे। क्योंकि उनके पास उन कंपनियों के अलावा दूसरा ऑपशन नहीं होगा।

हो सकता है शुरूआत में कंपीटिशन की वजह से कंज्यूमर्स को प्रोडेक्ट कम कीमत में मिल जाएं। मगर बाद में ये कंपनियां जब चाहेंगी, कीमतों में इजाफा कर देंगी और चूंकि ये कंपनियां हुकुमत को टैक्स अदा करेंगी इसलिए हुकूमत भी खामोश, तमाशाई बनी रहेगी। इस तरह कंज्यूमर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

मुझे मौजूदा हुकूमत की नीयत पर कोई शुबा नहीं है और उसकी पॉलिसियों से मुझे इत्तेफाक है। मगर मैं समझता हूं कि हुकूमत एफडीआई के तालुक से जल्दबाजी से काम न लें बल्कि मुल्क के आवाम को जहन में रखकर एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क तैयार करे। एक मानिटरिंग कमेटी तशकील दी जाए जो उन कंपनियों पर नजर रखे और उनको मनमानी से रोक सके। हुकूमत छोटे ताजिरों को माली इमदाद दे ताकि वो मार्किट में बाकी रह सके।

मेरे ख्याल से हुकूमत का एफडीआई के इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स को आजाद रखना अच्छी बात है। उससे यह होगा कि अगर एफडीआई का रिजल्ट हमारे यहां नेगेटिव रहा तो कम से कम वो स्टेट जिसने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया है, नुकसान से महफूज रहेगा और अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहा तो तमाम स्टेट्स खुद ही इसकी इजाजत दे देंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का 50 प्रतिशत हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करने की शर्त लगाई गई है। मगर उसमें इस बात की वजाहत जरूरी है कि उससे मुराद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर न हो। जो कंपनियों का फायदा पहुंचाने वाला हो, बल्कि आवाम के लिए भी हो।

मैं एफडीआई के लिए 10 लाख की आबादी की शर्त को भी बेहतर समझता हूं। इससे एक तो अचानक मुल्क के तमाम छोटे ट्रेडर्स मुतास्सिर नहीं होंगे। दूसरे यह देखने का मौका मिलेगा कि *[अनुवाद]* इसका विस्तार किया जाए या नहीं *[हिन्दी]* आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि एफडीआई के सिलसिले में हुकूमत के खिलाफ नहीं हूं बल्कि मेरी हिमायत हुकूमत के साथ है। मगर मैं हुकूमत से पुरजोर दरख्वास्त करता हूं कि वो जल्दबाजी से काम न ले बल्कि पहले जो कंसर्न ओब्जेक्शन हैं उस पर गौर करके उसे दूर करने की कोशिश करें। *[अनुवाद]* तब आगे की कार्यवाही करें।

میڈم اسپیکر صاحبہ!

سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی ہاؤس میں FDI پر چل رہی بحث میں اپنی باتیں رکھنے کا موقع دیا۔

میڈم اسپیکر صاحبہ! ہماری پارٹی آل انڈیا یونائیٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یو پی اے کی ally ہے۔اور میں پارٹی کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے حکومت کی پالیسیوں سے عموماً متفق رہا ہوں اور اس کی تائید اور حمایت کرتا رہا ہوں۔مگر چونکہ عام آدمی کا نمائندہ ہونے کے ناطہ میرے لئے ان کا مفاد سب سے زیادہ اہم ہے، اس لئے اگر حکومت کے کسی decision سے عام آدمی پر bad effect پڑتا ہے تو اسے واضح کرنا بھی میری ذمہ داری ہے تاکہ اسکی اصلاح ہو سکے اور شکوک وشبہات دور ہو سکے۔آج ایف ڈی آئی (خوردہ بازار میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری) پر بحث ہو رہی ہے جو آج ملک میں بحث ومباحثہ اور چرچہ کا topic بنا ہوا ہے۔بہت سے لوگ اسے حکومت کا ایک تاریخی قدم قرار دیکر اس کی حمایت کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ اسے عوام مخالف فیصلہ کہ کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔مخالفت کرنے والوں میں یو پی اے کی بہت سی ally پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ان کے بہت سے اعتراضات اور شکوک وشبہات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے سنجیدگی سے حل کیا جانا چاہیئے۔حقیقت یہ ہے کہ ایف ڈی آئی کے نفاذ میں جہاں ملک کی معیشت میں positive تبدیلی کا پہلو ہے وہیں یہ بہت سے negative پہلو بھی رکھتا ہے۔مثال کے طور پر ایف ڈی آئی کے implement ہونے سے کسان اور عام consumers کو فائدہ ہوگا۔کیونکہ کسان اپنے products کی صحیح قیمت پا سکیں گے اور consumers اچھی قیمت دیکر اچھا مال حاصل کر سکیں گے۔ ابھی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی tragedy یہ ہے کہ کسان پوری محنت کر کے اناج وغیرہ پیدا کرتے ہیں مگر وہ اس کی صحیح قیمت نہیں حاصل کر پاتے بلکہ بعض دفعہ لاگت سے بھی کم قیمت ملتی ہے جس سے مایوس ہو کر وہ خودکشی کر لیتا ہے یا اگر اپنی مانگ کو لیکر احتجاج کرتا ہے تو انہیں پولس کی گولی کھانی پڑتی ہے۔اور یہ سب ہوتا ہے بچولیا لوگوں کی وجہ سے جو کم سے کم قیمت پر خرید کر لے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں اسے بڑی قیمت پر بیچتے ہیں۔اور دوسری طرف consumers کو اس product کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔FDI کے ذریعہ اس problem کے حل ہونے کی امید ہے کیونکہ اس میں بچولے کا role ختم ہو جائیگا اور کمپنیاں کسانوں سے direct مال خرید کر صارفین کو مہیا کرائینگی۔اور چونکہ competition کی وجہ سے ہر کمپنی اچھی قیمت دیکر کسان کی پیداوار کو خریدنے کی کوشش کریگی اور مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ supply کیلئے کم سے کم منافع پر عمدہ اور fresh مال فروخت کرنے کی کوشش کریگی تو کسان اور consumers دونوں کو فائدہ ہوگا۔ Laid on the table out 42

اسی طرح FDI سے ملک میں جمع خوری اور کالا بازاری پر لگام لگ سکے گی اور عوام کو food shortage نجات ملے گا۔ بار بار دیکھا گیا ہے کہ ایک مخصوص product اچانک مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی قیمت آسمان چھونے لگتی ہے۔ اور یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ ملک میں اس کا stock ختم ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بڑی قیمت دیکر اس product کو حاصل کریں۔ مگر حقیقت میں یہ جمع خور حضرات جن کا مارکیٹ پر کنٹرول ہے اور جو کالا بازاری کر کے لوگوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی چالبازیاں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب چھاپہ ماری کی جاتی ہے تو وہی چیز جس کی بازار میں shortage ہوتی ہے وہ بڑی مقدار میں گودام میں پڑی ہوئی ملتی ہے۔ FDI کے ذریعہ جمع خوروں کی اس حرکت سے چھٹکارا ملنے کی امید ہے۔

ہمارا ملک پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے تعلق سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ مگر ان products کا ایک بڑا حصہ برباد ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں کولڈ اسٹوریج وغیرہ کی کمی ہے جہاں اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ FDI کی بدولت جب بڑی کمپنیاں مارکیٹ میں آئیں گی تو ان پر products کو save کرنے کے ذرائع میں اضافہ ہوگا اور وہ برباد ہونے سے بچ جائیں گے جس کا فائدہ ملک کی معیشت کو ہوگا۔ اسی طرح امپورٹ، اکسپورٹ اور ٹرانسپورٹ کے معیار میں بھی مثبت تبدیلی کا امکان ہے۔

میڈم اسپیکر! مگر میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایف ڈی آئی کے تعلق سے بہت سے خدشات ہیں جسے دور کرنے کی ضرورت ہے، نیز بہت سی چیزیں مبہم ہیں جسے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ FDI کے negative پہلو اور اس سے پیدا ہونے والے مضر اثرات کو بھی ذہن میں رکھے اور اس کا مناسب حل تلاش کرنے کے بعد ہی اس سمت میں اقدام کرے۔ مثال کے طور پر بہت سے ملک میں FDI کا تجربہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا ہے اور وہاں سے اسے ختم کرنے کی تحریک چلی ہے America, England اور Thailand وغیرہ اس کی مثال ہے۔ اب ہمیں ان تمام points کو جس کی وجہ سے ان [illegible] میں FDI کا تجربہ ناکام ہوا اس کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ FDI کے تعلق سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس سے ملک کے چھوٹے چھوٹے تاجر بے روزگار ہو جائیں گے جیسے کرانہ دوکاندار، پنساری، سڑک کنارے دوکان لگانے والے، ٹھیلوں پر محلہ در محلہ گھوم گھوم کر بیچنے والے، weekly market میں دوکان لگانے والے اور اسی طرح گاؤں، محلہ اور بازار میں چھوٹی چھوٹی دوکان والے یا مڈل کلاس کے تاجر۔ کیونکہ جب walmart, Carrefour اور Tesco جیسی بڑی بڑی کمپنیاں آجائیں گی اور بڑے بڑے malls اور super stores کھل جائینگے تو یہ small local businessmen اسکے مقابلہ میں مارکیٹ میں نہیں رہ پائینگے۔ کیونکہ FDI کے ذریعہ روزگار کے جو مواقع پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہونگے جو ان تمام کی بے روزگاری دور کر دے۔ نیز ان کمپنیوں میں نوکری کے لئے جو شرائط ہونگی اور ان کا جو Standard ہوگا اس پر اس طبقہ کے زیادہ تر لوگ کا کھرا اترنا مشکل ہوگا۔

सेडम اسپیکر! میرے خیال سے FDI کا برا اثر manufacture sector پر زیادہ پڑیگا۔ اگر چہ 30% local company سے خریدنے کی شرط لگائی گئی ہے مگر یہ کم ہے اسے بڑھا کر 80% کیا جانا چاہیئے۔

سیڈم اسپیکر! ہمارے ملک میں اکثریت غریب طبقہ اور مڈل کلاس کے لوگوں کی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد نوکری پیشہ ہیں اور عموماً اپنے پڑوس میں واقع دوکان سے راشن اور دیگر ضروری اشیاء لیتے رہتے ہیں اور مہینہ کی salary ملنے پر اسے ادا کرتے ہیں۔ مگر جب mal اور super store سسٹم ہو جائیگا تو تمام معاملات نقد ہوں گے جس سے اس طبقہ کے لئے پریشانیاں پیدا ہوں گی۔

میڈم اسپیکر! اس بات کا اندیشہ ہیکہ شروع میں اپنے قدم جمانے کے لئے نیز local businessmen کو مارکیٹ سے ہٹانے کیلئے بڑی کمپنیاں کسانوں کو ان کی پیداوار کی اچھی قیمت ادا کریں مگر بعد میں وہ کسانوں کے مفاد کو ignore کر کے پیداوار کی کم قیمت لگائیں گے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کسان ان ہی کمپنیوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہوں کیوں کہ انکے پاس ان کمپنیوں کے علاوہ کوئی دوسرا option نہ ہوگا۔

میڈم اسپیکر! ہوسکتا ہے کہ ابتدا میں کمپیٹیشن کی وجہ سے consumers کو product کم قیمت میں مل جائیں مگر بعد میں یہ کمپنیاں جب چاہیں گی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گی اور چونکہ یہ کمپنیاں حکومت کو ٹیکس ادا کریں گی اسلئے حکومت بھی خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ اس طرح consumers کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑیگا۔

میڈم اسپیکر! مجھے موجودہ حکومت کی نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کی پالیسیوں سے مجھے اتفاق ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایف ڈی آئی کے کے تعلق سے جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ ملک کی عوام کو ذہن میں رکھکر ایک strong framework تیار کرے۔ ایک مانیٹرینگ کمیٹی تشکیل دی جائے جو ان کمپنیوں پر نظر رکھے اور ان کو منمانی سے روک سکے۔ حکومت چھوٹے تاجروں کو مالی امداد دے تا کہ وہ مارکیٹ میں باقی رہ سکیں۔

میڈم اسپیکر! میرے خیال سے حکومت کا FDI کے Implementation کے لئے states کو آزاد رکھنا اچھی بات ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر FDI کا result ہمارے یہاں negative رہا تو کم سے کم وہ state جس نے اسے Implement نہیں کیا ہے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر positive result رہا تو تمام states خود ہی اس کی اجازت دیدیں گے۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ investment کا 50% حصہ infrastruture کے لئے استعمال کرنے کی شرط لگائی گئی ہے۔ مگر اس میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس سے مراد صرف وہ infrastracture نہ ہو جو کمپنیوں کو فائدہ پہونچانے والا ہو بلکہ عوام کیلئے بھی ہو۔

میڈم اسپیکر! میں FDI کے لئے دس لاکھ کی آبادی کی شرط کو بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ اس سے ایک تو اچانک ملک کے تمام چھوٹے traders متاثر نہیں ہوں گے۔ دوسرے یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ it shoud be extended or not۔ آخر میں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایف ڈی آئی کے سلسلے میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں بلکہ میری حمایت حکومت کے ساتھ ہے مگر میں حکومت سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ پہلے جو concerns اور objections ہیں اس پر غور کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرے، then go ahead۔

*श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने के लिए जल्दबाजी दिखा रही है। यदि वह केवल इसलिए कर रही है कि नीति की गतिहीनता के व्यापक भ्रम को तोड़ जा सके तो यह एक बड़ी गलती है। ऐसी नीति परिवर्तन जो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाले, उसे इतने हल्के तौर पर आरंभ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस नीति के संबंध में क्या कर रही है?

1. सरकार अपने गठबंधनों तथा साथियों की सर्वसम्मति के बिना ही ऐसा एकतरफा कर रही है, जो समझ से बाहर है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना, सरकार को निर्णय लेने से पूर्व सबकी सहमति से सर्वसम्मत विचार बनाना चाहिए। क्योंकि यह मुद्दा लाखों लोगों तथा उनकी आजीविका को प्रभावित करता है।

2. गठबंधन में अन्य दल तथा इसके बाहर के दल, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में आवश्यक रूप से वही दृष्टिकोण नहीं रखते, की राय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो सकती है।

3. इसके अलावा, निर्णय लेने का यह समय उचित नहीं प्रतित होता है। सरकार ने, यह निर्णय डीजल के मूल्यों में वृद्धि के समय लिया था जनता पहले से ही बढ़ते मूल्यों के कारण महंगाई अधिक है, को झेल रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाए जाने के कारण मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

4. बड़े स्टोर मशीनें स्टाक तथा प्रक्रियाओं का करती है जिससे अन्य व्यापार की प्रक्रियायों के अलावा उनका बंधा खर्च भी उपयोग करती हैं जिनका व्यय अन्य व्यापार प्रक्रियाओं के अतिरिक्त बंधे व्यय से अधिक होता है।

5. यह भी वाद विवाद का विषय है कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत की खेती संबंधी समस्याओं का हल है। वास्तव में, किसानों का इन कंपनियों जिनकी एकाधिकार की पछीत रही है, द्वारा और अधिक शोषण किया जा सकता है।

6. इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का निर्णय बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेगा, जो वर्तमान में व्यापार तथा स्थानीय खुदरा व्यापार कर रहे हैं। जैसे-जैसे बड़े खुदरा व्यापार देश भर के छोटे खुदरा व्यापार का स्थान लेंगे भारी संख्या में लोगों की नौकरियां चली जाएंगी क्योंकि लोग तथा व्यापार कार्यविहीन हो जाएंगे। विनिर्माण क्षेत्र में भी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। यदि ये बड़े खुदरा व्यारी अधिकतर खरीदारी स्थानीय की बजाए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी करेंगे तो।

7. जिस समय सरकार को रोजगार सृजन के बारे में तथा स्व-रोजगार को सृजित करने के बारे में विचार करना चाहिए सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था में उनका स्थान नहीं रहेगा।

हमारे संसदीय लोकतंत्र में राजनीति तथा नीति लोगों की मदद के लिए होनी चाहिए जिससे वे स्वयं को सशक्त महसूस करें। समावेशी तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति नहीं लेती। तथापि, पिछले कुछ वर्षों से पछुवारा में लाभ हेतु कोयला खनन तथा वनों की कटाई हो रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जो राज्य अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करता है जो केवल विरोध करने के अपने अधिकार को व्यक्त करता है वह मिथ्या लोकतंत्र का चिन्ह है और वह समय की परीक्षा पर खरा नहीं उतरता। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले आंदोलन जैसे कि नक्सलवाद तथा माओवाद देश के सभी कोने में उत्पन्न हो रहे हैं जिसे 'स्थानीय जनता का समर्थन आधारभूत विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने में असफल रहने के कारण में लोगों का विश्वास बहुत कम हो चुका है। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) विधेयक को लाना सही दिशा में उठाया गया कदम होगा। यह अंतरण लागत को कम करने में मदद करना तथा वस्तुओं के आवागमन को सुगम बनाएगा। भारत में पूंजी प्रवाह को बेहतर बनाने की आवश्यकता, बढ़ते वित्तीय घाटे तथा वर्तमान खाते के घाटे और रूपए के गिरते मूल्य के विरूद्ध एक सहारा बनेगा।

वस्तु एवं सेवा कर भारत का सर्वाधिक महत्वकांक्षी कर सुधार है जिसका लक्ष्य देश को एक आम बाजार में समरूप करना है। इसके क्रियान्वयन में विलंब केन्द्र तथा राज्य के बीच इस कर व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सर्वसम्मति नहीं होना है, जिससे विवाद समाधान पैनल का निर्माण तथा बैंड के साथ वास्तविक दर की आवश्यकता शामिल है। पिछले एक वर्ष में केन्द्र द्वारा राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति का भुगतान न करना भी एक विवाद का विषय बना हुआ है।

दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सही नेतृत्व की आवश्यकता है तथा यह उच्च स्तर पर राजनैतिक नेतृत्व का विशेषाधिकार होना चाहिए और यह आशा की जाती हैं कि देश में उच्च स्तर पर निर्णय सबसे निचले स्तर के लिए उदारहण बन जाते हैं।

केन्द्र सरकार ने 20 सितम्बर, 2012 को एक अधिसूचना द्वारा खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की है जो व्यापारियों, किसानों, फेरीवालों, ट्रांसपोर्टरों, छोटे उद्योगों, उपभोक्ताओं तथा देश के अन्य खुदरा व्यापार के क्षेत्रों के लिए अत्यधिक हानिकारक होगी।

लगभग 5 करोड़ व्यापारिक संस्थाएं तथा 22 करोड़ से भी अधिक खुदरा व्यापार पर निर्भर लोग जो अपनी आजीविका चला रहे हैं। इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। भारत का वर्तमान खुदरा व्यापार लगभग 20 लाख करोड़ रूपए का वार्षिक टर्नओवर सृजित कर रहा है तथा देश के जी.डी.पी. में प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा खुदरा व्यापार पर इसके प्रभाव का विचार किए बिना दी बहुत हड़बड़ी में अधिसूचना जारी की है। सरकार ने भारतीय खुदरा व्यापार के वास्तविक तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए कोई विश्वसनीय अध्ययन नहीं कराया। तथ्य स्वयं यह बता रहे हैं कि सरकार ने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देकर खुदरा व्यापार के साथ न्याय नहीं किया।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर) : मैं रिटेल में एफ.डी.आई. के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करती हूं। परंतु समर्थन करने के बावजूद सरकार से रिटेल में एफ.डी.आई. पर मेरी कुछ सन्देह एवं प्रश्न है, जिसका उत्तर एवं समाधान के लिए सरकार से मैं अपेक्षा करती हूं।

भारत में करीब एक करोड़ 20 लाख खुदरा व्यापारी है और करीब चार करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिटेल सेक्टर में रोजगार मिला हुआ है। वॉलमार्ट जैसे दिग्गज रिटेल कंपनियों के आने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि रिटेल सेक्टर से अपनी रोजी-रोटी चला रहे 4 करोड़ किराना व्यवसायी बेरोजगार हो जाएंगे। मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि किराना व्यवसाय में लगे करोड़ों लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जब आधुनिक रिटेल क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी 25 से 30 फीसदी हो जाएगी, तब छोटे व्यापारियों एवं किराना दुकानदारों पर रिटेल व्यापार में एफ.डी.आई. का असर पड़ना तय है, ऐसी स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि छोटे व्यापारियों एवं किराना दुकानदारों के रोजगार को संरक्षित करें। वॉलमार्ट का रास्ता साफ करने के लिए सरकार द्वारा तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं परंतु हाल ही में वॉलमार्ट ने न्यूयार्क में अपना पहला मेगा स्टोर खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां के लघु व्यापारियों एवं यूनियनों ने वॉलमार्ट का कड़ा विरोध किया। जिससे कंपनी को न्यूयार्क में मेगा स्टोर खोलने की योजना को रद्द करना पड़ा है।

1. सरकार द्वारा रिटेल में एफ.डी.आई. की इजाजत वॉलमार्ट जैसे कंपनियों को देने से पहले न्यूयार्क में हुए भारी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती जयाप्रदा]

विरोध के कारणों को बारीकी से समझने की जरूरत है।

2 दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इसमें किसानों से संबंधित है। रिटेल में एफ.डी.आई. से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ऐसी दलील सरकार द्वारा दी जा रही है, परंतु किसानों की आमदनी तभी बढ़ सकती है, जब उपभोक्ता मांग में बढ़ोत्तरी होगी और मांग में बढ़ोत्तरी तब होगी, जब महानगरों के साथ-साथ बड़े एवं छोटे शहरों में भी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने स्टोर खोलें।

2012-13 में शुरूआती महीनों में एफ.डी.आई. में भयंकर कमी आई है। सरकार का राजकोषीय एवं चालू खाते का घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। विदेशी निवेशक भारत के बजाय चीन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। खजाने का संतुलन बनाए रखने के लिए एफ.डी.आई. का प्रवाह बना रहना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत है, परंतु सरकार एफडीआई लाने के साथ-साथ करोड़ों किराना व्यापारियों एवं किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए आश्वासन दें।

इसी के साथ सरकार का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात खत्म करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री नरहरि महतो** (पुरूलिया) : खुदरा क्षत्र में एफ.डी.आई. लाने का कदम बड़ी संख्या में रोजगार समाप्ति में परिणत होगा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाते है कि सुपर मार्केट अनिवार्यत: छोटे खुदरा व्यापारियों को विस्थापित कर देते हैं। अमेरीका और यूरोप जैसे विकसित देशों में छोटे खुदरा व्यापारी लगभग समाप्त हो गए हैं। दक्षिण एशियाई देशों को छोटे खुदरा व्यापारियों के विस्थापित होने के पश्चात सुपर मार्केट की वृद्धि को रोकने के लिए कड़े क्षेत्र तथा लाइसेंसिंग विनियमों को लागू करना पड़ा था। भारत में प्रति 100 व्यक्ति पर 11 दुकानों के साथ संसार में दुकान घनत्व सबसे अधिक है। इसमें 1.2 करोड़ दुकानें हैं जिनमें 5 करोड़ से अधिक लोग नियोजित है; इनमें से 95 प्रतिशत स्व-नियोजित लोगों द्वारा चलाई गई छोटी दुकानें हैं। आपके मत का सम्मान करते हुए, मैं भी आपको कुछ सूचित करना चाहूंगा। आपने केवल खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. के प्रभावों पर ही विचार किया है। भारतीय जनसंख्या का 70 प्रतिशत सुदूर गांवों में रहता है, जहां कनेक्टिविटी, परिवहन, संचार आदि का अभाव हैं। और मैं आश्वस्त हूं कि वालमार्ट महानगरों, टियर 1 तथा 2 शहरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्टोर नहीं खोलेगा और गांव के गरीब लोगों के लिए शहरों में वालमार्ट स्टोरों पर पहुंचना महंगा पड़ेगा। अत: उन्हें ''किराने की दुकानों'' पर निर्भर रहना पड़ेगा जिनकी दशा व्यापारियों जैसी ही होगी। इस प्रकार, जनसंख्या का एक विरल भाग ही अप्रत्यक्ष रूप से वालमार्ट तथा टेस्को से कर सकते हैं परंतु जरूरतमंद लोग जस के तस रहेंगे। गरीब में केवल किसान ही शामिल नहीं है, गरीब तो वे भी जो 30 रूपए प्रति दिन से कम कमाते हैं, जैसा कि योजना आयोग द्वारा इस तथाकथित ''विकासशील देश'' के लिए कहा गया है जहां एक व्यक्ति तो डिस्को तथा पब में हजारों रूपए खर्च कर रहा है और कोई सड़क पर भोजन की तलाश में मर रहा है। एफ.डी.आई., नीतियां सभी बाद में है।

एफ.डी.आई. एक बिना मिश्रित वरदान नहीं है। विकासशील देशों में निजी विदेशी निवेश की सीमा, पैटर्न तथा शर्तों का निर्णय करते समय सरकारों को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। विदेशी निवेश के संभावित प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित है:

1. जब विदेशी निवेश घरेलू निवेश के साथ प्रतिस्पर्धा करता है तो घरेलू उद्योगों में लाभ कम होता है जो घरेलू निवेश के साथ प्रतिस्पर्धा करता है तो घरेलू उद्योगों में लाभ कम होता है जो घरेलू बचत में कमी में परिणत होता है।

2. मेजबान सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई उदार कर छूट, निवेश भत्ते, प्रछन्न लोक आर्थिक सहायताएं तथा प्रशुल्क बचाव के कारण निगमित करों के माध्यम से लोक राजस्व में विदेशी फर्मों का योगदान तुलनात्मक रूप से कम होता है।

3. विदेशी फर्में दोहरे सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर बल देती हैं और आय की असमानताओं को बढ़ाती हैं। वे अत्यधिक उच्च वेतन वाले आधुनिक क्षेत्र के कार्यपालकों का एक छोटा समूह बनाती हैं। वे अत्यधिक उच्च वेतन वाले

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आधुनिक क्षेत्र के कार्यपालकों का एक छोटा समूह बनाती है। वे स्थानीय अमीरों के उपभोग हेतु महंगे उत्पादों के विनिर्माण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संसाधनों का विपथन करती है। चूंकि वे शहरी क्षेत्रों वे स्थित होती है, इसलिए ग्रामीण और शहरी अवसरों के मध्य असंतुलन उत्पन्न करके शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण जनसंख्या के प्रवाह को बढ़ाती हैं।

4. विदेशी फर्में अत्यधिक विज्ञापन और एकाधिकारी बाजार शक्ति के माध्यम से अनुचित उपभोग पद्धतियों को बढ़ावा देती हैं। घरेलू बाजार हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पाद आवश्यक तौर पर कम मूल्य तथा उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। उनकी प्रौद्योगिकी आमतौर पर पूंजी प्रधान होती है जो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती।

5. विदेशी फर्में विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धी सरकारों से बड़ी मात्रा में आर्थिक तथा राजनैतिक छूट प्राप्त कर पाने में समर्थ होती है। इसके परिणामस्वरूप, इन कंपनियों के निजी मुनाफे सामाजिक लाभों से अधिक हो सकते हैं।

6. कई सालों में मुनाफे का लगातार बाहर जाना काफी अधिक होता है जो विदेशी मुद्रा भंडारों पर दबाव डालता है। विदेशी निवेशक मुनाफे को वापिस ले जाने के संबंध में काफी दृढ़ मत रखते हैं।

7. विदेशी फर्में विकासशील देशों में राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते है। उनके बड़े आकार और शक्ति को देखते हुए, राष्ट्रीय समप्रभुता तथा आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण खतरे में पड़ सकता हैं। अत्यधिक विकट मामलों में, विदेशी फर्म अनुचित लाभ लेने के लिए उच्चतम स्तर के लोक पदाधिकारियों को रिश्वत भी दे सकती है। इसी प्रकार, वे वित्त राजनैतिक दलों को चंदा दे सकती हैं तथा मेजबान देश की राजनैतिक प्रक्रिया में उलटफेर कर सकती है।

***श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर** (पोन्नानी) : मैं विपक्ष द्वारा पेश किए गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा करते समय सभी संगत पहलुओं को एक सोध चर्चा की जानी चाहिए। मुद्दों को पृथक करने का कोई अर्थ नहीं है। एक साथ चर्चा करने से मेरा मतलब है:

1. राष्ट्र की अर्थव्यवस्था
2. भारत में कृषक समुदाय का भला
3. भारत में खुदरा व्यापारियों का अस्तित्व
4. खुदरा विपणन में रोजगार के अवसर

यदि हम इन विषयों का एक व्यापक तरीके से विश्लेषण करें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे सकते हैं कि खुदरा में एफ.डी.आई. को एक शत्रु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह तो एक आवश्यकता है। हमें यह महसूस करना होगा कि वास्तविक समकालीन भारतीय स्थिति क्या है। भारत की आर्थिक स्थिरता का हमारा गर्व कम हो रहा है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि मंद हो रही है। विदेश संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) देश से बाहर जा रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत से 2497.50 करोड़ रूपए आहरण के चलते रूपए के मूल्य में भारी कमी आई है। भारत को आधारभूत ढांचा अस्पताल, मकान और स्कूल तथा अन्य सुविधाओं को निर्माण और रोजगार सृजन हेतु अरबो डॉलर की आवश्यकता है। भारतीय रिटेल उद्योग को ज्ञान और वैश्विक एकीकरण की आवश्यकता है। यदि देश के शासक जागने के अलार्म के बावजूद सोते रहेंगे तो एक राष्ट्र के साथ घोर अन्याय होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार सही दिशा में जा रही है।

एफ.डी.आई. पर पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दिए जा रहे है। यह निर्विवादित तथ्य है कि भारत समूचे के सबसे प्रसिद्ध निवेश गंतव्यों में से एक है।

'यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेन्स आन ट्रेड एंड डवलपमेन्ट' (अकटाड) द्वारा हाल में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत चीन के बाद दुनियाभर की पहली पसंद है। एक अन्य तथ्य यह है कि खाड़ी देश पूर्व की ओर देखते हैं; हम अरब देशों से भारत में करोड़ों डालर के निवेश की आशा कर सकते हैं। वे भारत को दुनियाभर में सबसे सुरक्षित निवेश केन्द्र मानते हैं। वे अपना निवेश पश्चिम से हटाकर पूर्व की ओर करना चाहते है; सउदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देश भारत में भारी निवेश की योजना बना रहे हैं। देश

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर]

का आर्थिक नीति निर्माता अर्थात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आई.सीआर.आई.ई.आर.) ने 2011-2012 तक भारत खुदरा क्षेत्र के 496 बिलियन पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है और उसने यह भी कहा है कि दीर्घावधि में खुदरा क्षेत्र में एफ. डी.आई. के प्रवेश से भारत के इस छोटे और परंपरागत खुदरा क्षेत्र के हितों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

कुछ वर्ग यह तर्क देते हैं कि एफ.डी.आई. घरेलू डीलरों को बबार्द कर देगा और बेरोजगारी फैलाएगा। उनका कहना है कि दुनिया की बड़ी खुदरा कंपनियां भारतीय खुदरा बाजार को निगल जाएंगी और फिर उपभोक्ताओं के साथ मनमाना व्यवहार करेंगी। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ये सभी आरोप आधारहीन हैं। हमें यह विश्लेषण करना होगा कि विभिन्न देशों में खुदरा में एफ.डी.आई. के आने के पश्चात उनका निष्पादन कैसा रहा।

चीन का अनुभव देखिए, 1992-2001 के बीच खुदरा और थोक, दोनों व्यापारों में रोजगार 4% से 7% हो गया। चीन का अनुभव सिद्ध करता है कि नौ वर्ष में 26 मिलियन नए रोजगारों का सृजन हुआ। पांच वर्ष में परंपरागत छोटे खुदरा व्यापारियों की संख्या में भी 30% की वृद्धि हुई। मैं पूछना चाहता हूं, जब चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? यह संदेह भी कि विश्व की बड़ी कंपनियां हमारे घरेलू खुदरा खेत्र को निगल जाएंगी, मात्र कल्पना ही है। वालमार्ट, केयरफोर, टेस्को, टारगेट, मेट्रो, कूप, खुदरा क्षेत्र की ये कंपनियां 30 वर्ष से भी अधिक से असंख्य देशों में कार्यरत हैं लेकिन उनका एकाधिकार नहीं हुआ है। मलेशिया, ताईवान, थाइलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों का उदाहरण देखिए, एफ.डी.आई. होने से उनको अत्यधिक लाभ हुआ है।

मैं विदेशियों द्वारा एकाधिकार के संदेह के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भारत में खेत के स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद पर मध्यस्थों और बिचौलियों का एकाधिकार है। अब कोई भी इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता कि छोटे भारतीय किसानों को भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए कुल मूल्य का 1/3 हिस्सा मिलता है। भारतीय टमाटर उत्पादक को क्रेता द्वारा दिए गए अंतिम मूल्य का केवल 30% मिलता है। इस तथ्य को समझिए कि भारतीय किसान और औद्योगिक संघ (आई.एफ.आई.ए.), भारतीय किसान संघ महासंगठन (सी.आई.एफ.ए.) भी इसका समर्थन करते हैं। इस वाद-विवाद में सबसे उपेक्षित वर्ग क्रेता है। प्रतियोगी दरों से क्रेताओं को गुणवत्तापूर्ण सामान मिलेगा। यह तथ्य है। भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, एक अनुमान के अनुसार, 40% खाद्य उत्पादन उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता है। वह सड़ जाता है। यह ऐसे देश में हो रहा है जहां 50 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। यह सच है कि समुचित भंडारण और परिवहन व्यवस्था से किसानों को सहायता मिलेगी।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि देश को सावधान रहना होगा। मैं भारत सरकार द्वारा उठाए गए सावधानीपूर्ण कदमों का स्वागत करता हूं। भारत में 'मल्टी-ब्रांड' और 'सिंगल ब्रांड' भंडारों को अपना लगभग एक तिहाई सामान छोटे और मध्यम आकार वाले भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से लेना होगा। भारत में सभी 'मल्टी-ब्रांड' और 'सिंगल ब्रांड' भंडारों को अपने कार्यकलाप एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 53 विभिन्न शहरों तक सीमित रखने होंगे। ऐसा अनुमान है कि इन भंडारों की भारत के 200 मिलियन शहरी उपभोक्ताओं तक पूरी पहुंच होगी। 'मल्टी ब्रांड' खुदरा विक्रेता को न्यूनतम 100 मिलियन अमेरीकी डालर का निवेश करना होगा जिसमें से कम से कम आधी राशि पृष्ठ भूमि अवसंरचना में निवेश की जाएगी जिसमें शीतागार श्रृंखला, रेफ्रीजरेशन, परिवहन, पैकिंग, छंटाई और किसानों को लाभदायक मूल्य देना शामिल है। खुदरा प्रतियोगिता का खोला जाना भारत सरकार के संघीय ढांचे के दायरे में होगा।

दूसरे शब्दों में, यह नीति भारत के लिए एक समर्थकारी विधिक ढांचा है। भारत के राज्यों को यह विशेषाधिकार होगा कि वे इसे स्वीकार और क्रियान्वित करें अथवा ऐसा न करने का निर्णय लें। नीति का वास्तविक क्रियान्वयन राज्य विधि और नियमों के पैरामीटर के दायरे में रहेगा।

***श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल** (वडोदरा) : खुदरा में एफ. डी.आई. के मुद्दे पर बहुत कुछ कहा गया है। हालांकि इसे इतनी बार उलटा-पलटा गया है कि यह कल्पना के साथ मिश्रित हो गया है। अब यह मुद्दा वैचारिक विचार-विमर्श की बजाए राजनैतिक बनता जा रहा है।

खुदरा में एफ.डी.आई. पर वर्तमान विचार विमर्श की पृष्ठ भूमि के तौर पर खुदरा क्षेत्र के भूदृश्य को समझना अत्यावश्यक है। वर्ष 2012 में भारत का खुदरा क्षेत्र अनुमानत: 18,673 बिलियन रु.

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का है और यह जी.डी.पी. का लगभग 15 प्रतिशत तथा कुल रोज़गार का 8 प्रतिशत होता है। यह क्षेत्र, लगभग 96 प्रतिशत दुकानें असंठित क्षेत्र में होने के कारण अत्यधिक विखंडित हैं। इनमें से अधिकांश दुकानें पारिवारिक श्रमिक से पारिवारिक स्वामित्व वाली हैं। इस मीनार के तल में भारत के लाखों पटरी के खोमचे हैं।

बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (2012) ने आकलन किया कि 2011 में खुदरा विक्रय 471 बिलियन डॉलर था जिसमें 7 प्रतिशत (34 बिलियन डॉलर) हिस्सा संगठित खुदरा का था। इससे यह भी पता चलता है कि 2020 तक नियोजित संगठित खुदरा का आकार लगभग 260 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा जिससे उसकी हिस्सेदारी 21 प्रतिशत तक हो जाएगी। मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई आय और वाहनों रेफ्रीजरेटरों, क्रेडिट कार्डों का प्रयोग तथा आपूर्ति शृंखला के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से महानगरों और छोटे शहरों में पलड़ा संगठित खुदरा व्यापार के पक्ष में होने का अनुमान है।

आज भारत खुदरा क्षेत्र के संबंध में दोराहे पर है। संगठित और असंगठित खुदरा क्षेत्र के बीच परिवर्तन प्रत्यक्ष है, जिससे भारतीय खुदरा व्याप्तत के भाग्य पर अनेक अटकलबाजियों हुई हैं। असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सरकार या कोई भी भारतीय अर्थव्यवस्था के इन नींव के पत्थरों को निकाल सके।

भारतीय उपभोक्तावाद का चेहरा बदल रहा है: न कि भारतीय उपभोक्तावाद बजाज स्कूटर वाले सामान्य व्यक्ति से बजाज पल्सर ट्रेंडी वाले आधुनिक युवा के रूप में विकसित हो रहा है। उपभोक्ताओं की यह बदलते हुई रूचि और जीवनशैली कहीं न कहीं स्वत: ही संगठित क्षेत्र को कुछ लाभ पहुंचा रहा है। यह असंगठित खुदरा क्षेत्र के लिए अत्यावश्यक बनाता है कि वह बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करने तथा रूझानों के अनुसार चलते उपभोक्ता अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए स्वयं को पुनर्गठित करे। वे क्या कर सकते हैं और वे क्या कर रहे हैं?

अस्सी के दशक से पहले, भारत जहां हज़ारों कस्बे और शहर हैं विकास के लिए जूझता हुआ राष्ट्र था। विकास विभिन्न स्तरों पर महसूस किया जा रहा था विकास विभिन्न स्तरों पर महसूस किया जा रहा था और देश के लोग व्यापारी और उपभोक्ताओं के रूप में नई भूमिकाएं निभाना सीख रहे थे। एक मज़बूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही थी, युवा सभी क्षेत्रों में नई जागरूकता की ओर खिंच रहे थे और यह खुदरा उद्योग के प्रसार का एक अवसर लाया। सबसे पहले मेट्रो और बड़े शहरों में तत्पश्चात् उपनगरों और ग्रामीण बाजरों पर इसका प्रभाव पड़ा।

इस चरण में भारत में खुदरा व्यापार पूर्णत: असंगठित था और यह छोटे तथा मध्यम उद्यमियों द्वारा उनकी अपने क्षेत्रों में संचालित पृथक निकायों के रूप में फल-फूल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का अभाव था और केवल कुछेक भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर खुदरा मंच को जांचा था। विदेशों से केवल लिवाइस, पेपे, रिलायंस, मोर, मार्क्स एण्ड स्पेन्सर आदि कंपनियों ने भारतीय उच्च मध्यम और उच्च वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आगमन किया था। हालांकि चूंकि 50% से अधिक जनसंख्या निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की थी अत: बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सका। इसे बाद में बिग बाजार और पेन्टाटून्स जैसे ब्राण्डों ने महसूस किया जिन्होंने लोगों के सभी वर्गों को उत्पाद और सेवाए उपलब्ध करवाई और आज इन ब्राण्डों की सफलता भारतीय खुदरा बाजार की क्षमता को प्रमाणित करती हैं।

भारतीय खुदरा क्रांति में एक महान परिवर्तन जो हुआ वह था सभी क्षेत्रीय बाज़ारों में मॉक्स का खुलना। अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी मॉल संस्कृति वास्तव में भारत में खुदरा का नियोजित प्रारूप लाई जो पहले अनुपस्थित था। हालांकि अभी भी भारतीय मॉल संस्कृति के बढ़ने की बहुत संभावना है क्योंकि वातावरण और ब्राण्डिंग के अतिरिक्त अन्य कई पक्ष है जिनमें खुदरा सेवा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया जाना रहता है।

असंगठित खुदरा व्यवसायियों का एक बड़ा वर्ग अभी भी व्यवसाय में रहना चाहता है और स्पर्धा करना चाहता है, यह चाहते हुए भी कि अगली पीढ़ी इसी तरह बढ़े।छोटे खुदरा व्यापारी उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और जोड़े रखने के लिए अधिक उधार दे रहे हैं। हालांकि केवल 12 प्रतिशत असंगठित खुदरा विक्रेताओं की संस्थागत ऋण तक पहुँच है और 37 प्रतिशत व्यवसायिक बैंक ऋण तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता महसूस करते हैं। अधिकांश असंगठित खुदरा विक्रेता स्वतंत्र रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं जबकि केवल 10 प्रतिशत ने संगठित खुदरा विक्रेताओं की फ्रेंचाइज़ी बनने को प्राथमिकता दी।

असंगठित खुदरा विक्रेता होना एक गंभीर कदम है; भारत में अभी भी संगठित खुदरा के लिए चुनौतियाँ हैं। परंपरागत खुदरा व्यापार

[श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल]

भारत में कुछ शताब्दियों से स्थापित है। कम लागत संरचना है, अधिकांशत: स्वामी संचालित, उसकी मामूली भूसंपदा और श्रम लागत तथा कम और न के बराबर आयकर वाली।

परंपरागत खुदरा व्यापार क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपभोक्ता का परिचय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके विपरीत, संगठित क्षेत्र में निकायों को बड़े व्यय करने पड़ते हैं और फिर भी परम्परागत क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ होने के लिए मूल्यों को कम रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, खुदरा व्यापार को मध्य वर्ग की इस मानसिकता से निपटना होता है कि बिक्री की दुकान जितनी बड़ी और चमकदार होगी, वह उतनी ही अधिक महंगी होगी।

परंपरागत खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के समर्थक इसकी अनुमति देने के निम्नलिखित तीन लाभ गिनवाते है:

- इससे रोजगार उत्पन्न होंगे और रोजगार अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे किसानों को अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे।
- इससे उपभोक्ताओं को वस्तुओं के वितरण की लागत में कमी आएगी।
- इससे मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता मिलेगी।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के पश्चात बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन के संबंध में सरकार किस प्रकार झूठे दावे कर रही है।

सरकार ने यह दावा किया है कि खुदरा व्यापार में एफ. डी.आई. से 3 वर्षों में 10 मिलियन (1 करोड़) रोजगार उत्पन्न होंगे जिसमें 4 मिलियन (40 लाख) रोजगार सीधे उत्पन्न होंगे और शेष बैकएंड लॉजिस्टिक्स में उत्पन्न होंगे। मैं आपको इसकी गणना दिखाना चाहूंगा और सदन में मेरे माननीय साथी सदस्य इस दावे के पीछे की भयानक भूल को निश्चित रूप से देख पाएंगे।

मैंने वालमार्ट और मेट्रों की वेबसाइटों को देखा है। वालमार्ट प्रति स्टोर 214 कर्मचारियों को और मेट्रो प्रति स्टोर 133 कर्मचारियों को नियोजित कर रही है। मल्टी ब्रांड रिटेलर का औसत रोजगार लगभग 100 व्यक्ति प्रति स्टोर है। यह समूचे विश्व का आंकड़ा है।

यदि हम प्रति स्टोर 200 व्यक्तियों का भी रोजगार लेकर चले, तो भारत को तीन वर्षों में 4 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए कम से कम 20,000 सुपर मार्केट अथवा मेगा माल्स खोलने की आवश्यकता होगी। यदि हम 100 रोजगार का औसत ले तो अगले तीन वर्षों में 4 मिलियन रोजगार हेतु कम से कम 40,000 सुपर मार्केट अथवा मेगा मॉल्स स्थापित करने होंगे। भारत के शहरीकरण और शहरीकरण पर संबंधी आंकड़ों को देखते हुए क्या अगले तीन वर्षों में कम से कम 20,000 स्टोर अथवा सुपर माकेर्ट खोलना संभव होगा? इस प्रकार, बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने का तर्क आधारहीन है।

जरा सोचिए कि सरकार अगले तीन वर्षों में 40,000 सुपर मार्केट या मेगा मॉल खोले और 4 मिलियन रोजगार उत्पन्न कर सकती है। तो समूचे भारत में 5,000 शहरों तथा 600,000 गांवों में फैली हुई 12 मिलियन किराना दुकानों का क्या होगा? क्या वे बेरोजगार नहीं हो जाएंगे?

मैं आपको केवल यह दर्शाना चाहता हूं कि सरकार के दावे कितने झूठे है। किसानों को लाभ के दावे के संबंध में भी यही स्थिति है। तथ्य यह है कि बड़े खुदरा व्यापारियों के पास किसानों तथा विद्यमान बिचौलियों की तुलना में काफी अधिक क्रय शक्ति होगी। कृषि खरीद में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसानों के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न कर देगा। आज प्रचालन करने वाले बाजार यार्ड या मंडिया, जहां कई व्यापारी किसानों के उत्पाद को खरीदने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं कि तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामले में केवल एक ही क्रेता होगा। यह किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर बना देगा और इससे उनका शोषण होने की संभावना बनी रहेगी। मैं इसे अनायास ही नहीं कह रहा हूं। यूरोपीय यूनियन की संसदों ने वर्ष 2008 में निम्नलिखित प्रस्ताव अपनाया था कि

> "समूचे ईयू में, खुदरा व्यापार में अधिकाधिक रूप से सुपरमार्केट श्रृंखलाओं की छोटी सी संख्या का प्रभत्व है... समूचे ईयू के सबूर्त दर्शाते हैं कि बड़ी सुपरमार्केटें आपूर्तिकर्ताओं (ईयू के भीतर तथा बाहर) को अदा किए जाने वाले मूल्यों

को अपोषणीय स्तर पर लाने और उन पर अनुचित शर्तें लादने के लिए दबाव डालने हेतु अपनी क्रय शक्ति का दुरूपयोग करती है।''

मलेशिया और थाइलैण्ड में, सुपरमार्केटों ने धीरे-धीरे समय के साथ फल तथा सब्जी आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को कम करना और किसानों के बजाए थोक विक्रेताओं तथा अन्य बिचौलियों से अधिकाधिक हिस्से की खरीद करना प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त, कई अध्ययनों में सुपरमार्केटों द्वारा कई कदाचार प्रमाणित किए गए हैं जैसे कि विलंबित भुगतान, अंतिम क्षण में मूल्यों को कम कर देना जब आपूर्तिकर्ता के पास कोई विकल्प न हो, बिना किसी सूचना तथा सहायता के मात्रा और गुणवत्ता मानकों में परिवर्तन, बिना किसी ठोस कारण के आपूर्तिकर्ता को सूची से हटा देना, ऋण पर उच्च ब्याज प्रभारित करना आदि।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल और केवल सरकारी नीति ही असंगठित क्षेत्र के आधुनिकीकरण और मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. की अनुमति दिए बिना इसकी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और इसे ऐसा करना चाहिए।

परंतु प्रश्न यह है कि सरकार की सही भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या इसे संगठित खुदरा व्यापार को सीमित करके परम्परागत खुदरा व्यापारियों के बचाव हेतु नीति बनानी चाहिए? अथवा संगठित खुदरा व्यापारियों द्वारा उठाए गए नामों से लाभन्वित होने के लिए संगठित खुदरा क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए।

एक अथवा दूसरे को प्रोत्साहित करने अथवा संरक्षित करने के लिए क्या तंत्र होना चाहिए? सरकार केवल एक सुकरकर्ता अथवा समर्थकारी के रूप में कार्य कर सकती है अथवा दोनों रूपों में/कथित संदर्भ में, असंगठित खुदरा स्वरूप को बचाए रखने, प्रतियोगिता करने और अर्थव्यवस्था को वृद्धिशील बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक योजना विकसित किया जाना आवश्यक है।

अत:, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आधुनिक खुदरा व्यापार की सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी समान लाइसेंस नीति खुदरा क्षेत्र को 2020 तक 2000 बिलियन अमेरिकी डालर तक ले जाने में मदद करेगी जो बोस्टन समूह के पूर्वानुमानों का दोगुना है। असंगठित खुदरा व्यापारियों के लिए सस्ते संस्थागत ऋण तक पहुंच समय की मांग है ताकि खुदरा दुकानें संगठित खुदरा क्षेत्र से प्रतियोगिता कर सकें। वर्तमान में, केवल 12% असंगठित खुदरा क्षेत्र की संस्थागत ऋण तक पहुंच है।

मैं (कैश एंड कैरी) दुकानें स्थापित करने का सुझाव देना चाहता हूं जो किसानों से खरीद करेंगी और असंगठित क्षेत्र को बेचेंगी। इससे असंगठित खुदरा क्षेत्रों को अंतत: खुदरा बिक्री के लिए थोक मूल्यों पर खरीद में सहायता मिलेगी जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। किसानों को भी लाभ होगा क्योंकि वे आकर्षक मूल्यों पर बेच सकते हैं और त्वरित तथा पारदर्शी ढंग से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार यह सहायता मिलने पर, असंगठित खुदरा क्षेत्र को सरकार से कोई शिकायत नहीं रहेगी और यदि होगी भी तो सरकार उसकी अनदेखी कर सकती है?

मेरा सुझाव अवसंरचनागत सुविधाओं के संबंध में है। अवसंरचनागत सुविधाएं यथा शीतागारों की स्थापना, बाजार स्थलों का आधुनिकीकरण, आधुनिक सुविधाओं के साथ संभारिकी में सुधार और आधुनिक सुविधाओं के साथ भांडागारों की स्थापना अनिवार्य और समय की मांग है। सरकार को असंगठित खुदरा व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए अपेक्षित अवसंरचनागत सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को असंगठित खुदरा व्यापारियों के लिए आवश्यक अवसंरचनागत सुविधाओं के सभी क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए।

यदि सरकार असंगठित खुदरा क्षेत्र (भारत में कुल खुदरा व्यापार का 96%) में सुधार और उसका आधुनिकीकरण करेगी तो स्वत: लाखों की संख्या में रोजगार सृजित होगा और इस आधुनिकीकरण से किसान तथा अंतिम प्रयोक्ता, दोनों लाभान्वित होंगे।

हम सभी को राजनैतिक और वैचारिक सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए और 18,673 बिलियन रूपये के भारतीय खुदरा क्षेत्र में लिए सर्वोत्तम संभावित नीतियां तैयार करनी चाहिए जो जी.डी.पी. का लगभग 15% है और 8% रोजगार प्रदान करता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने असंगठित खुदरा क्षेत्र का आधुनिकीकरण कर और उसमें परिवर्तन लाकर अन्य देशों को मार्ग दिखाना चाहिए।

***श्री ए. सम्पत** (अटिंगल) : मैं भारत सरकार के खुदरा क्षेत्र में 51% एफ.डी.आई. और परिणामस्वरूप 'फेमा' को संशोधित करने के प्रयासों के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं। काफी गर्मागर्म

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए. सम्पत]

बहस के बाद और चार दिन तक सभा बाधित रहने के पश्चात ही सरकार और विशेष रूप से इसका प्रमुख दल कांग्रेस, नियम 184 के अंतर्गत चर्चा के लिए तैयार हुआ। यह अहंकार क्यों?

तत्कालीन वित्त मंत्री ने दिसंबर, 2012 को आश्वासन दिया था कि इस संबंध में सभी हित धारकों के साथ परामर्श किया जाएगा और जल्दी में कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन यह गलत सिद्ध हुआ है। सहमति न होने पर पर्याप्त परामर्श और चर्चा के बिना, भारत जैसे बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र के लिए इस प्रकार जल्दबाजी में निर्णय लेना स्वास्थ परंपरा नहीं है।

सरकार का यह कहना ठीक हो सकता है कि खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने से घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा आएगी, लेकिन किस कीमत पर और किस क्षेत्र में? भारत में खुदरा क्षेत्र में लगे अनुमति चार करोड़ लोगों को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं है। उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। अधितकर छोटी दुकानें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। खुदरा विक्रताओं के रूप में रोज संघर्ष करके दो जून की रोटी कमाने वाले बर्बाद हो जाएंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके समकक्ष, शहरी व्यापारी और उनके अधीन काम करने वाले लाखों असंगठित कामगार उस काम से बेरोजगार हो जाएंगे जिससे वे अपनी दो जून की रोटी कमाते हैं और वह भी सरकार से बिना किसी सहायता के।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब तक दूर क्यों है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अवसंरचना निर्माण में आगे क्यों नहीं आती? इसका केवल एक ही उत्तर है: ''लाभ, लाभ और केवल लाभ और केवल तत्काल लाभ''। भारत के लाखों छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं द्वारा कमाया गया लाभ कई गुणा होकर स्वयं घरेलू अर्थव्यवस्थ में ही खर्च हो जाता है जबकि हर आदमी जानता है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका क्या करेंगी? केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं, बल्कि अनेक विकासशील राष्ट्र भी विभिन्न रूपों में अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को संरक्षित, प्रोत्साहित और विस्तारित करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और हम पुनः उल्टी दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अपने लोगों को बाजार के रूप में ही देखते हैं? तब तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है?

मैं सरकार से राष्ट्रहित में इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : एफडीआई इन रिटेल देश हित में नहीं है अतः मैं श्रीमती सुषमा स्वराज एलओपी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एफडीआई इन रिटेल सेक्टर के सरकारी आदेश को वापिस लिया जाना चाहिए। यदि एफडीआई बहुत जरूरी हो तो आधारभूत सुविधाओं के विकास में एफडीआई को एलाउ किया जाना चाहिए। सरकार सभी तथ्यों का अध्ययन करके तत्कालीन एलओएच के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए सबसे विचार विमर्श करके ही इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही देश हित में होगा।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू) : सरकार ने संसद में वादा किया था कि खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. लागू करने से पूर्व संसद में विचार विमर्श किया जाएगा। राजनैतिक दलों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर आम सहमति बनाई जाएगी, लेकिन सरकार ने यह वायदा पूरा नहीं किया और खुदरा बाजार में विदेशी निवेश का निर्णय लागू कर दिया। देश में एक भी ऐसा विरोधी दल नहीं है, जिसने सरकार के इस निर्णय का विरोध नहीं किया हो। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने की क्षमता भारत के खुदरा बाजार में है। खुदरा क्षेत्र का देश की जी.डी.पी. में योगदान करीब 14 फीसदी है। किसी भी देश के लिए स्वाभिमान सबसे जरूरी होता है, आजादी के बाद अनाज की कमी के कारण अमेरिका से पी. एल. 480 स्कीम के अधीन सहायता ली थी, उसमें वो शर्तें थी जो देश के स्वाभिमान को कम करती थी। नेहरू जी के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की बागडोर संभाली तो, उनके आहिवान पर देशवासियों ने एक दिन का वृत्त रखा, लेकिन सबसे पहले पी.एल. 480 स्कीम को खत्म किया। भारत में 1990 से आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू होने के बाद आज हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि हम खतरे पर खड़े हैं, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की गिर रही कीमत, औद्योगिक उत्पादन दर का बुरा हाल, पूंजी बाजार के लगातार गिरते सूचकांक और मुद्रा स्फीति के साथ-साथ महंगाई से आम आदमी के हालात अत्यंत खराब हो गए हैं। देश में निर्यात के मुकाबले बढ़ते हुए आयात के कारण घाटा खतरे के निशान से बहुत ऊपर चल रहा है और हम 1990-91 की नाजुक आर्थिक स्थिति से बहुत दूर नहीं है। एफ.डी.आई. जैसे प्रावधान लागू

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करके इसमें जान डालने का औचित्य क्या है? आजादी के बाद 1950 में भारत निर्यात के मामले में 16वें स्थान पर था, और संसार के कुल निर्यात में 2.2 प्रतिशत भारत का भाग था, आज संसार के निर्यात में हमारा भाग लगभग 1 प्रतिशत है। सरकार कहती है कि यह नीति उपभोक्ताओं के हित में है, चीजें सस्ती व अच्छी होगी। एकाधिकारी बाजार उपभोक्ता के हित में नहीं होता, पहले दाम नीचे आएंगे, ताकि बाजार समाप्त हो जाए बाद में भारी दाम बढ़ा देंगे, फिर ग्राहक के पास कोई चारा नहीं होगा। सरकार इस नीति को किसानों के हित में होना बतला रही है, ये कम दाम देकर किसान का माल खरीदेंगे, कर्मचारियों को कम वेतन देंगे, अमेरिका व अन्य यूरोपिए देशों के किसानों ने भी इनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। मल्टी ब्रांड रिटेल के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह है कि इससे सन् 2020 तक एक करोड़ रोजगार पैदा होंगे। अमेरिका में रिटेल कारोबार में वालमार्ट का वर्चस्व है, इसका कुल कारोबार चार सौ अरब डालर लगभग 20 लाख करोड़ है, जबकि इसमें महज 21 लाख लोग काम करते हैं। भारत का कुल रिटेल क्षेत्र भी 20 लाख करोड़ रूपये का है, जबकि इसमें 4.40 करोड़ व्यक्ति काम करते हैं।

वॉलमार्ट जैसे विदेशी रिटेलरों को भारत में बुलाने से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। खुदरा व्यापार का ढांचा खत्म हो जाएगा। सरकार की दलील है कि ए.डी.आई. छोटे व मध्यम उद्योग। से 30 प्रतिशत माल खरीदेगी, और भारतीय निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। यह लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। सच्चाई यह है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत भारत किसी भी बड़े रिटेलर को कहीं से भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह विश्व व्यापार संगठन नियमों के खिलाफ है। देश का खुदरा बाजार मामूली नहीं है, उसे बड़ी कंपनियों को सौंप देने का सवाल केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, भारत का खुदरा व्यापार लोगों को रोजगार ही नहीं देता, स्वतंत्र जीवन-यापन की सुविधा भी देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतनी आर्थिक व प्रचार की ताकत है कि देश में स्थापित खुदरा बाजार उजड़ जाएगा। भारी पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। एक बार बाजार से प्रतियोगिता के खत्म होने और बाजार में बड़ी विदेशी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित होने के बाद उत्पादकों यानी किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को इन बड़ी कंपनियों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। विदेशी कंपनियें को भारत का बड़ा बाजार दिख रहा है। ये भारत के मध्यम वर्ग को लूटना चाहती है। उन्हें तो यहां व्यापार बढ़ाना है, लेकिन हम यह क्यों कर रहे हैं, यह कार्य राष्ट्र विरोधी है, जहां-जहां वॉलमार्ट आया, वहां खुदरा बाजार खत्म हो गया। छोटी दुकानें बंद हो गई। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज अपने देशवासियों को छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहन देने की बात करता है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। आप हमारे छोटे व्यापार को खत्म नहीं करे। एफ.डी.आई. कॉमन आदमी के हित में नहमीं है। यह देश के लिए खतरे की घंटी है। सरकार देश के हितों को दर किनार कर भारत को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रही है।

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरुनेलवेली) : भारतीय अर्थव्यवस्था में मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आरंभ करने के संबंध में अपने कुछ विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

कृषक लोग अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए परेशान हैं। भारत में ग्रामीण कृषि उत्पादों पर बिचौलियों तथा दलाली एजेंटों का भी नियंत्रण रहता है। चूंकि ये वस्तुओं का उचित मूल्य देने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए कृषक लोग हमेशा साहूकारों और स्थानीय बैंकरों के ऋणी रहते हैं। उनके लिए ऋण चुकाना और अन्य वचनबद्धताएं पूरी करना बहुत कठिन होता है।

इसलिए भारत में इन कृषि उत्पादों को बचाना और इनको संरक्षित रखने के लिए हमें मूल्य निर्धारित करने और दलाली एकत्र करने में और दलालों की संलिप्तता को समाप्त करने की आवश्यकता है।

खुदरा व्यापार में विदेशी राष्ट्र के निवेशक हमारे देश के कृषि उत्पाद सीधे खरीदेंगे और कृषक लोगों को लाभ मिलेगा।

राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने खुदरा व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में 22 प्रतिशत विदेशी निवेश आरंभ किया है। अब इस विधेयक के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राशन बढ़ा दिया गया है।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकांश केवल बड़े शहरों में इनके मॉल स्थापित करने के लिए ही जा रहा है। छोटे दुकानदार और अन्य छोटे व्यापारी किसी भी प्रकार से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.एस. रामासुब्बू]

इससे प्रभावित नहीं होंगे। छोटे व्यापारियों के बीच भ्रम उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दल दस एफ.डी.आई. का विरोध कर रहे हैं।

सस्ती दर पर मानक उत्पाद मिलने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यहां तक कि छोटे व्यापारी और छोटे दुकानदार बाजार से गुणवतापूर्ण उत्पाद प्राप्त कर पाएंगे।

कर वंचन में कटौती होगी। इससे सरकारी राजकोष में भी अधिक राजस्व आएगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास की उपलब्धि तभी हो सकती है जब विभिन्न व्यापारों में विभिन्न देशों के विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जाए। भारत के विकास के लिए अनिवार्य रूप से विदेशी निवेशकों का उपयोग किया जाए। सरकार द्वारा इसकी निगरानी अनिवार्य रूप से की जाए। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन करता हूं।

***श्री एन. चेलुवरया स्वामी** (मांडया) : सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से ही यह बात स्पष्ट हो गई कि सरकार खुदरा उद्योग का महत्व भूल गई है। सरकार यह समझ नहीं पाई है कि भारत में खुदरा उद्योग केवल व्यापार का एक रूप नहीं है। परंतु ये उन हजारों लोगों की आजीविका का साधन है जो उचित रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसी कारण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करता हूं।

भारतीय बाजारों मुख्यत: खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) का प्रवेश किसान विरोधी और जन-विरोधी निर्णय है। चूंकि ये कृषक समुदाय के हित के विरोध में है मैं इस प्रस्ताव का पूर्णत: विरोध करता हूं।

इस नीति से केवल बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को सहायता मिलेगी। कृषि उत्पादों से संबंधित भी खुदरा क्षेत्र में पहलें की गई हैं, परंतु किसानों को अब तक इससे बहुत लाभ नहीं मिला है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बेरोजगारी और अल्प रोजगार दोनों की दर को बढ़ाएगा। वर्तमान परिदृश्य में केवल 20 प्रतिशत खुदरा बाजार दी संगठित है, शेष 80 प्रतिशत असंगठित है और विकास के अत्यंत प्रारंभिक चरण में है। बड़े वैश्विक खुदरा व्यापारियों के प्रवेश में धीरे-धीरे परंतु निश्चित रूप से घरेलू खुदरा व्यापारी हाशिए पर आ जाएंगे और दीर्घावधि में स्थानीय दुकानों तथा लाखों रोजगार समाप्त हो जाएंगे।

दूसरा कारक भारतीय बाजार में बड़े ब्रांडों का एकाधिकार है। एफ.डी.आई. का भारतीय किसानों की बिक्री और लाभ पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं कि एकल ब्रांड खुदरा व्यापारी को अनिवार्य रूप से भारत से अपनी 30 प्रतिशत वस्तुएं प्राप्त करनी होंगी। अब बाजार के रूझानों को देखकर लगता है कि, चेन स्टोर मालिकों ने बाज़ार पर नियंत्रण करने और एकाधिकार का प्रयोग करने का रूख बना लिया है।

एफ.डी.आई. से बड़ी बहु राष्ट्रीय कंपनियों को बाजार पर नियंत्रण आसानी से हो सकता है। इससे किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. से जनता को लाभ पहुंचाने का सरकार का आश्वासन केवल एक दिखावा है और इससे भारत में विदेशी कंपनियों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

कुछ समाचार पत्रों में ऐसी कुछ घटनाएं आईं है कि पूरे विश्व में रिटेल स्टोर चेन स्वामियों के विरूद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं कि ये अपने आपूर्तिकर्ताओं को समय पर पैसों का भुगतान नहीं करते। अन्य देशों के बारे में भूल जाइए, वॉलमार्ट जैसी खुदरा शृंखला स्वयं अपने देश में व्यापक विरोध का सामना कर रही है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन समस्त पहलुओं पर ध्यान दे और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर हमारे किसानों, खुदरा व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करे।

***श्री प्रेमा दास राय** (सिक्किम) : सिक्किम के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी सरकार का समर्थन करने हैं। कोई भी व्यवस्था कितने भी अच्छे ढंग से तैयार की गई हो, कभी भी परिपूर्ण नहीं होती। इसलिए, वे मुद्दे बने रहेंगे। जिन्हें विपक्ष इस सभा में खींचता रहा है। तथापि, सरकार के लक्ष्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संबंधित और बहुप्रतीक्षित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण होगा, उचित स्तर वाले रोजगार का सृजन होगा जैसा कि हमारे देश के अनेक महानगरों में खुलने वाले मॉल और खुदरा दुकानों में देखने में आया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों से अनेक युवाओं को खाद्य काम और रोजगार मिल रहा है। ये सभी 'मल्टी ब्रांड' खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के अच्छे पहलू हैं।

राष्ट्र वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें मतभिन्नता छोड़कर इसे अपनाना चाहिए। इससे हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दुनिया भर में फैलने में मदद मिलेगी। इन्ही शब्दों के साथ में सही दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री सी. शिवसामी** (तिरूपुर) : मैं एफ.डी.आई. के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने से छोटे व्यापारी, लघु उद्योग और किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हमारी संपदा को वालमार्ट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश ले जाएंगी। हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अतीत में जो भारत में व्यापार करने आए वे हमारे शासक बन बैठे और एक लंबे संघर्ष के बाद, हमारे पुरखों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई। लेकिन, एफ.डी.आई. कर रहे हैं और भविष्य में हमारी स्वतंत्रता प्रभावित होगी।

राष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार को खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को अनुमति देने का अपना निर्णय वापस लेना चाहिए।

[हिन्दी]

****श्री मनोहर तिरकी** (अलीपुरद्वार) : मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्यों के चर्चाओं पर ध्यान दे रहा था। सरकार कहती है कि एफडीआई चालू होने पर देश का कल्याण होगा, महंगाई घटेगी, किसानों का भला होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा और विकास में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को देश के स्वार्थ खिलाफ बताया। देश के किसानों, मजदूरों पर आर्थिक धक्का लगेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ ही इनका कहना है कि हमारे देश का पैसा विदेशों में चला जाएगा।

मैं विपक्षों के सवालों को पूरा समर्थन करता हूं। वामपंथी पार्टियों ने जिसमें हमारे पार्टी आर एस पी ने पहले यूपीए सरकार के समय एफडीआई के मामले में विरोध किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस मामले को हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं उसे सरकार के सहयोगी दलों ने समर्थन कर सरकारी मुद्दा को जन विरोधी करार दिया है।

हमारे देश में स्वाधीनता की लड़ाई भी विदेशी वर्सेस स्वदेशी ग्रहण के आंदोलन से प्रभावित था। स्वदेशी आंदोलन ने पूरे भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजों को हटाया। स्वाधीनता पश्चात् देश में जो भी नीति ली गई उसमें देशी विचारों से प्रेरित सरकारी उद्योग, नवरतन गठन कोयला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जमींदारों, राजा महाराजा की पेंसन बंद, आदि कल्याणकारी सिद्धांत ग्रहण कर देश को अग्रगति के पथ पर लाया गया।

जो पार्टी इन मुद्दों को लेकर लंबे समय तक देश में शासन चलाया वही पार्टी बी-इंडियन बाई-इंडियन का नारा छोड़कर विदेशी सामानों के व्यवहार के लिए सरकार को मजबूर कर रही है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम पर फिर से देश को विदेशियों के हाथों में देने का काम कर रही है।

मुझे और भी आशंका हो रही है कि सरकार की यह नीति हमारे देश के हित के खिलाफ है, देशवासियों के लिए कलंक का काम कर रही है। सरकार का तर्क है कि देश की परिस्थिति को सुधारने के लिए एफडीआई बहुत जरूरी है। मैं इसका विरोध करता हूं। अपने देश की समस्या के समाधान करने के लिए हमारे देश के ही शिक्षा, टेकनोलोजी, प्राकृतिक संपदा का विकास कर विदेशों से आगे बढ़े। हमें गर्व है कि हमारे देश की सभी तरह की प्राकृतिक संपदा, जलबल, खाद्य निर्भरता और हर तरह की तकनीकी व्यवस्था मौजूद है। विदेशी लोग हमें लूटेंगे। वे हमें कमजोर करेंगे।

जो पार्टी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आजादी हासिल कर देशी तकनीकी का विकास कर अग्रगति को बढ़ानें के बजाय विदेशों पर निर्भरता पर विश्वास कर, सभी सरकारी उद्योग, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जन विरोधी काम की निंदा करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री रमेन डेका** (मंगलदोई) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 'मल्टी ब्रांड' खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. से भारतीय लोकतंत्र

*मूलतः तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रमेन डेका]

का मूल ढांचा प्रभावित होगा। खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और न ही इससे किसानों को सहायता मिलेगी अथवा रोजगार में वृद्धि ही होगी।

भारत के लोग खुदरा विपणन से भलीभांति परिचित हैं। खुदरा क्षेत्र के लोग नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। खुदरा बाजार देश के सभी हिस्सों में, यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी, यहां यांत्रिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, मौजूद हैं। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खुदरा व्यापार से अपनी जीविका कमा रहे हैं। कृपया लाखों लोगों की जीविका मत छीनिए। माननीए मंत्री कृपया एफ.डी.आई. के निर्णय को वापस लें।

[हिन्दी]

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल) : आज इस सदन में विदेशी निवेशक खुदरा व्यापार में आने का मैं घोर विरोध करती हूं।

यह देश की आधारभूत ढांचे में विभिन्न स्तंभों एवं मजबूत जिस पिलरों पर देश की नींव रखी एवं खड़ी है उसमें यदि इनमें एफ.डी.आई. का आयात देश को कमजोर ही नहीं देश को उस दुर्दशा की ओर ले जाएगा जहां आज देश जाना नहीं चाहता। उसे मजबूर करना एक अपराध ही नहीं है बल्कि देश के साथ एक धोखा है। अध्यक्ष जी, जिस एफ.डी.आई. से किसान ही नहीं देश का व्यापारी ही नहीं देश का एक बड़ी संख्या में रहने वाला युवा बेरोजगार भी इस आग में जल कर खत्म हो जाएगा। हमें देश के इन प्रमुख तीन स्तंभों को बचाना है जिससे देश के अस्तित्व की ही नहीं देश को विदेशी निवेशकों से खुदरा व्यापार में न लाकर विदेशी निवेशकों को अधो-संरचना के विकास एवं पुल-पुलिया-रोड़-पावर आदि में हम विदेशी निवेशकों को लाना आवश्यक करें लेकिन खुदरा व्यापार में न लाएं, यही मेरी मांग है। हम इससे देश के विकास को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं।

***श्री राजाराम पाल** (अकबरपुर) : मैं एफ डी आई के सरकारके प्रस्ताव के समर्थन में हूं (1) एफडीआई आने के बाद किसानों के हालात में आमूल परिवर्तन होगा। किसानों की उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्र का मूलभूत ढांचा परिवर्तन होगा। क्योंकि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सब्जी व फल पैदा करने वाला देश है। इनका उचित रख-रखाव न होने से 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत फल व सब्जी सड़ जाता है। एफडीआई के आने के बाद किसानों/उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होंगी। एफडीआई आने के बाद नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा किसानों और नौजवानों के विकास से देश का विकास होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नदियों, नालों, रेलवे लाइन के किनारे रहने वालों को एफडीआई का काम कैसे मिलेगा क्योंकि उनके पास राशन कार्ड, आई कार्ड नहीं है। उनको पूरे देश की झुग्गी, झोंपड़ियों का सर्वे कराकर देश की तरक्की से जोड़ा जाए वरना संविधान निर्माताओं एवं देश आजाद कराने वाले का सपना पूरा नहीं होगा।

इसके साथ ही एफडीआई रिटेल में लागू करने के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के. सुगुमार** (पोल्लाची) : सरकार यह कदम किसानों और व्यापारियों के हितों के विरूद्ध है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी और गरीब लोग अत्यधिक प्रभावित होंगे। व्यापारिक कार्यकलाप बर्बाद हो जाएंगे। मैं सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करता हूं।

****श्री शिवराम गौडा** (कोप्पल) : 14 सितंबर, 2012 को भारत सरकार ने भारतीय राज्यों की मंजूरी के अध्याधीन, भारतीय खुदरा बाजार के 51% एफ.डी.आई. की अनुमति दी। मैं कहना चाहता हूं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा होगा। खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. के बारे में में मेरी कुछ गंभीर चिंताएं हैं। भारतीय में खुदरा व्यापार अर्थव्यवस्था का स्तंभ है और यह जी. डी.पी. का 14-15 प्रतिशत है। एफ.डी.आई. से खुदरा व्यापारियों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि एफ.डी.आई. की घोषणा से देशभर में आंदोलन शुरू हो गया। विशाल खुदरा श्रृंखला स्वामियों के लिए हमारा देश निवेश के लिए आदर्श स्थान बन गया है। हमारे अपने खुदरा व्यापारियों के लिए आजीविका चलाना कठिन हो गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारतीय बाजारों, विशेषत: खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक किसान-विरोधी और लोक-विरोधी निर्णय है। चूंकि यह कृषक समुदाय के हितों के विरूद्ध है, अत: मैं इस प्रस्ताव का पूर्णरूपेण विरोध करता हूं।

इस नीति से केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होगा। कृषि उत्पादों से संबंधित खुदरा क्षेत्र में पहले की गई है। लेकिन अब तक किसानों को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला है।

छोटे किसानों और दस्तकार समूहों तक पहुंचने की त्वरित आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि बर्बादी न हो। यदि एफ.डी.आई. लागू होता है तो ये वर्ग अपनी आजीविका खो देंगे।

बाजार को नियंत्रित करने में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आसानी हो जाएगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. से आम आदमी को लाभ का आश्वासन मात्र एक भ्रम है और इससे विदेशी कंपनियों को भारत में स्थापित होने में मदद मिलेगी।

अमरीका और यूरोप में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि खुदरा क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उछाल के बावजूद, कृषि क्षेत्र को सरकार से सर्वाधिक राजसहायता प्राप्त होती है।

उदाहरणार्थ, अमरीका में 2008 में कृषि विधेयक में सरकार ने 308 बिलियन डॉलर की कृषि राजसहायता प्रदान की थी। यदि उस देश में खुदरा क्षेत्र इतना सफल होता तो इतनी बड़ी राजसहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अमरीका में हुए एक अध्ययन के अनुसार, 1950 से पहले एक किसान अपने बेचे गये प्रत्येक एक डॉलर उत्पाद का 70 प्रतिशत कमाते थे पर 2005 में खुदरा क्रांति के बाद से यह कमाई केवल 4 प्रतिशत रह गई है।

एक और कारक भारतीय बाज़ार पर बड़े ब्राण्डों का एकाधिकार है। एफ.डी.आई. का भारतीय किसानों की बिक्री और सीमांत लाभ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने ये दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि एकल ब्राण्ड खुदरा व्यपारियों को अपना 30 प्रतिशत कच्चा माल भारत से खरीदना होगा। पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सामान्यत बड़ी कंपनियोंकी यह प्रवृत्ति होती है, कि वे विदेशों से कम कीमत पर सामन खरीदकर बाजार पर कब्जा जमा लें और उसी सामान को विकासशील देशों में बेचकर खूब मुनाफा कमायें। इस प्रकार के परिदृश्य में घरेलू उत्पादन और उत्पादकों को हानि होगी। इस प्रकार बड़ी कंपनियां एकाधिकार का प्रयोग करती हैं।

ये बड़ी कंपनियां भारतीय कृषि क्षेत्र में मौजूदा कमीशन एजेंटों को प्रतिस्थापित कर सकती है और बहु ब्राण्ड खुदरा में एफ.डी.आई. से किसानों की दशा और खराब हो जाएगी।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन सब पहलुओं की जांच करे और खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को अनुमति न देकर हमारे किसानों, खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करे।

[हिन्दी]

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : देश की अर्थव्यवस्था उठाने, जी.डी.पी. बढ़ाने, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने एवं आर्थिक सुधारों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। उन्हीं में से एक कदम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुदरा ब्रांड खोलने की घोषणा एक स्वागतयोग्य कदम है। इससे निवेशकों के विश्वास को बहाल करने और विदेशों से और अधिक धनराशि आकर्षित करने की उम्मीदें बढ़ी हैं। मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पादकों, श्रमिकों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं सहित कई हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है साथ ही संगठित खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जो हमारे देश में अभी तक असंगठित है। विदेशी निधि और विदेशों से होने वाले धनप्रवाह से हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ प्रौद्योगिकी भी मजबूत होगी। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि वैश्विक आर्थिक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ना एक शुभ संकेत है। आज संपूर्ण विश्व की नजर हमारी और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित हैं क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये दो ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जो तेजी से विकास कर रही हैं, ऐसे में प्रत्यक्ष विदेश निवेश हमारी अर्थव्यवस्था को द्रुत गति से बढ़ाने में सहायक होगा।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से किसान और निर्माता जिनकी कीमत संगठित खुदरा क्षेत्र के माध्यम से बढ़ेंगी। अभी तक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सतपाल महाराज]

कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रशीतित परिवहन में कम निवेश के कारण हमारे उत्पादन का काफी हिस्सा खराब हो जाता है, परंतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस क्षेत्र में काफी सुधार व संवर्धन होगा जिससे हम अपने उत्पाद को खराब होने से बचा सकेंगे। भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल से कई लाभ होंगे जैसे खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा लाभ किसानों को प्राप्त होगा, यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में ही संलग्न है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से ही उनके उत्पाद खरीदेंगी, जिससे मध्यस्थ के कारण उनको होने वाले नुकसान का जोखिम कम होगा। इस प्रकार किसानों को बेहतर कीमत प्राप्त होगी जिससे उन्हें 20 से 30 प्रतिशत तक का फायदा होगा। आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विक्रेताओं के एक ही समय में मध्यम पुरुषों के लिए जो भी कर रहे हैं उनसे शेयर होल्डरर्स के उन्मूलन आपूर्ति में बाधा को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा। बड़े खुदरा विक्रेताओं की सीधी खरीद नीति से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पारित करने में मदद करेगा, इस प्रकार खाद्य आधारित मुद्रास्फीति काफी हद तक कम होगी। मेगा बहु ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को भारत में निवेश करना होगा जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर डालने एवं अध्ययन से पता चलता है कि जिन देशों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोला है वहां रोजगार के अवसर काफी अधिक संख्या में बढ़े हैं। भारत जैसे विकासशील देश में एफ.डी.आई. आने से लाखों करोड़ों रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे हमारे देश में काफी हद तक बेरोजगारी समाप्त होगी। हमारे देश का कुल 30 से 40 प्रतिशत तक उत्पाद उचित परिवहन व भंडारण के अभाव में हर वर्ष नष्ट हो जाता है। खुदरा विक्रेताओं के लिए 50 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रकचर में व्यय आवश्यक बनाकर सरकार बेहतर भंडारण एवं त्वरित परिवहन से इस खाद्य अपव्यय को रोकेगी। कंपनियों बीच में स्वस्थ व्यापार परंपरा से उपभोक्ताओं को अच्छे विकल्प मिलेंगे जिससे उन्हें न्यूनतम कीमत पर अधिक गुणवत्ता का सामान प्राप्त होगा।

आपको आश्चर्य होगा परंतु यह सही है कि मेगा खुदरा विक्रेताओं की बिक्री छोटे खुदरा विक्रेताओं की बिक्री की 30 प्रतिशत है। इसका आदर्श उदाहरण पंजाब राज्य का कैश एंड कैरी मॉडल है।

विदेशों की अनेक कंपनियां जिस तरह अन्य अनेकों देशों में पूंजी निवेश करती है, उसी तरह भारत की अनेक कंपनियों द्वारा भी विदेशों में पूंजी निवेश किया जाता है। अफ्रीका, चीन, इंग्लैंड ही नहीं वरन् अमेरिका जैसे देश में भी हमारे देश की कंपनियों ने पूंजी निवेश कर रखा है। जब कोई विदेशी कंपनी हमारी देश में पूंजी निवेश करना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम भारत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होती है, इसी प्रकार कई अन्य विदेशी कंपनियां इसके पूर्व भी भारत सरकार से अनुमति लेकर हमारे देश में पूंजी निवेश कर चुकी है फिर चाहे वो कोका कोला हो, नोकिया हो, यह सब कंपनियां विदेशी हैं और सभी लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं फिर एफ.डी.आई. पर शोर किस बात का यह समझ से परे है।

एफ.डी.आई. का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देश में तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं। जो सिर्फ देशी पूंजी निवेश से बनी है, दूसरी जो देशी और विदेशी पूंजी निवेश से बनी हैं तथा तीसरी जो सिर्फ विदेशी पूंजी निवेश से बनी है। अब जिस पर बहस हो रही है तो हैं देशी कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियें का निवेश। सरकार ने विदेशी कंपनियों को आधे से ज्यादा पूंजी निवेश के लिए अनुमति दे दी है। संयुक्त पूंजी निवेश पर आधारित अनेक कंपनियां है। नोकिया एवं कोका कोला ये सीधे पूंजी निवेश के उदाहरण हैं।

खेती का स्वरूप एवं खेती विषयक कायदे अच्छी तरह समझने के बाद यह ध्यान में आता है कि मल्टी ब्रैंड रिटेल क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश को अनुमति देने से किसानों को लाभ होगा। खेती और उसके उत्पादों का बाजार अभी बंदिश में है। यहां किसान अपने उत्पाद अन्यत्र नहीं बेच सकते, उन्हें मार्केट में लाना आवश्यक होता है। रिटेल क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश से खेती उत्पादों के खरीदारों में फिर से स्पर्धा जागृत होगी। एक और खरीददार का बाजार में आना उत्पादकों के लिए एक सुअवसर होगा यह सीधा अर्थशास्त्र है। इस आधार पर हम सीधे विदेशी निवेश का स्वागत कर सकते हैं। रिटेल क्षेत्र में सीधे निवेश का दूसरा लाभ खेती उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को भी हो सकता है। हमारे देश में बनने वाले कुछ ही उत्पादों पर प्रक्रिया की जाती है। बहुत

सा माल जाया ही जाता है, सड़ जाता है। माल जल्द खराब होगा इस डर से जो माल स्थानीय बाजार में मिट्टी के भाव बेचना पड़ जाता है, वही माल दूर के बाजार में भी बेचने के लिए ले जाया जा सकेगा। इस वजह से इसकी मांग भी बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ किसानों को प्राप्त होगा।

विदेशों से कच्चा माल लाकर भारत में प्रक्रिया करना विदेशी कंपनियों का लाभदायक नहीं होगा। इसकी तुलना में भारत से ही कच्चा माल खरीदकर उसकी प्रक्रिया करना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रक्रिया उद्योगों को नियमित रूप से माल की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय किसानों के लिए इस वजह से उनके अपने बाजार का निर्माण होगा। विदेश से मजदूर लाकर कोई भी विदेशी कंपनी काम नहीं करती वो कभी भी लाभदायक नहीं होता। इन उद्योगों से सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों का फायदा हमारे देश के मेहनतकश लोगों को होने वाला है। प्रक्रिया उद्योगों को इसी तरह का श्रम बल उपलब्ध करवाने का काम शिक्षण संस्थानों को करना पड़ेगा। शैक्षिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बेरोजगारों का निर्माण करने वाले कारखानों के शैक्षिक व्यवस्थाओं में अमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। गर पिताजी मर रहे हों और बेटे में उन्हें बचाने की क्षमता नहीं है और ऐसी परिस्थिति में पड़ोस की गली से डॉक्टर आकर उनका उपचार करे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम विदेशी हो? क्या पिता की जान बचाना आवश्यक नहीं है? इसी प्रकार यदि हमारी अर्थव्यवसथा में तेजी के लिए एफ.डी.आई. आ रहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

आज हमारे खुदरा क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खुदरा क्षेत्र में 95 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र से हैं। महज 5 फीसदी लोग संगठित क्षेत्र से हैं। खुदरा क्षेत्र का 70 प्रतिशत कारोबार खाद्य से जुड़ा है। बस इसी को सामने रखकर विरोध में कहा जा रहा है कि हमारी खाद्य सुरक्षा पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिपत्य हो जाएगा। मगर इसके पक्ष में भी बेशुमार तर्क है। उदाहरण के तौर पर, इससे उपभोक्ताओं को 5 से 10 प्रतिशत की बचत होगी। किसान को अपने उत्पाद के 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा दाम मिलेंगे। 30 से 40 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तौर से 40 से 60 लाख रोजगारों का सृजन होगा। सरकार को इससे जुड़े ढांचागत विकास मसनल प्रोसेसिंग, मैन्युफेक्चरिंग, वितरण, डिजाइन, गुणवत्ता, कोल्ड चेन, वेयर हाउस और पैकेजिंग जैसे कामों में तेजी लानी होगी। इन सब वजहों की कमी के चलते सलाना 50 हजार करोड़ का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। मसलन 16500 करोड़ का अनाज जो उत्पादन का 10 प्रतिशत है, बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार 15 प्रतिशत दालें, 30 प्रतिशत फल और सब्जियां और 40 प्रतिशत फलोरीकल्चर से जुड़े उत्पाद रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं। अगर निवेश का 50 प्रतिशत हिस्सा इस बुनियादी क्षेत्र को विकसित करने में लगता है जैसे कि कहा गया है तो स्थिति में तेजी से सुधार होगा। सरकार के अनुसार बैंक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर में कुल निवेश का 50 प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले से वॉलमार्ट, कैरीफोर, टेस्को, और मेट्रो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में कारोबार करने का रास्ता खुलेगा जिससे हमारे देश की जनता को न्यूनतम मूल्य में अधिक गुणवत्त की वस्तुएं प्राप्त होंगी।

***श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन) : एफडीआई हमारे देश के किसानों एवं छोटे बड़े व्यापारियों को पूरी तरह बर्बाद करने का काम करेगी। एफडीआई लाना देश हित में नहीं है। देश में बेरोजगारी इससे बढ़ेगी जिससे देश का नौजवान बेरोजगार होगा। आर्थिक तंगी से जूझकर एवं किसान और नौजवान एवं छोटे व्यापारी को मजबूरन आत्म हत्या करना पड़ेगा। करोड़ों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। देश हित में यही होगा कि ऐसे कानून को नहीं लाया जाए। मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार एफ.डी.आई. को वापिस ले और देश हित में काम करे। गरीबों एवं नौजवानों के हित में कार्य करें मैं सरकार से अपील करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी लाओ विदेशी हटाओ का नारा दिया एवं संघर्ष किया आप गांधी जी के सपनों को तोड़ रहे हैं। यह देश आपको आने वाले समय में माफ नहीं करेगा, और ऐसा लगता है कि आप सरकार से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि यह निर्णय जन विरोधी निर्णय है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आज देश के सामने यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जाहिर है कि सबके अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। बहुत से लोग इस विषय पर अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

सभी राजनीतिक दलों के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। स्वाभाविक है कि सारे दृष्टिकोण एक से नहीं हो सकते। तभी हमारा प्रजातंत्र है, तभी हमारी संसद है। तभी सब अपने विचार रखते हैं और हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं मगर सभी के विचारों का हम सम्मान करते हैं।

मैं इस बहस में अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहा था। मैंने यह समझने की काफी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को किस बात का गुस्सा है, ये किसके खिलाफ हैं? क्या वे मल्टीब्रांड रीटेल के खिलाफ हैं या एफडीआई के खिलाफ हैं? क्योंकि अभी जो प्रश्न हमारे सामने हैं, वह एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रीटैल का प्रश्न है। जहां तक मल्टी ब्रांड रीटेल की बात है, वह हमारे देश में पहले से चल रहा है। बहुत से स्टोर्स, रिलायंस, फ्रैश, भारती, बिग बाजार, बहुत से स्टोर्स जो एनडीए के समय पर शुरू हुए और एनडीए के समय से चल रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों में आ रहे हैं। जाहिर है इन्होंने कभी उनकी खिलाफ़त नहीं की, उनके खिलाफ नहीं बोले। तो ये मल्टी ब्रांड रीटेल के खिलाफ नहीं हैं, संगठित व्यापार के खिलाफ नहीं हैं। तो क्या ये एफडीआई के खिलाफ हैं? एफडीआई के खिलाफ नहीं हो सकते। सुषमा जी स्वयं कल कह रही थीं कि प्रधान मंत्री जी के साथ जाकर एफडीआई को देश में लाने का प्रयास करने के लिए वे तैयार हैं। जब भातरीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी तो एफडीआई के नए-नए आयाम स्थापित किए गए—टेलीकॉम सैक्टर की कुछ सर्विसेज में एफडीआई खोला गया, टोबैको में, लिकर में, स्टील में, एल्कोहल में, कोयले में और यहां तक कि फार्मास्युटिकल सैक्टर में भी एनडीए ने एफडीआई खोलने का काम किया। जाहिर सी बात है कि ये एफडीआई के भी खिलाफ नहीं हैं और संगठित व्यापार के खिलाफ भी नहीं हैं।

महोदया, आज हमारे देश में जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, संगठित व्यापार के अंदर रिलायंस रीटेल और रिलायंस फ्रैश के नाम से स्टोर्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के मोर ग्रुप के नाम से स्टोर्स बन रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 60 शहरों में 500 स्टोर्स बनाए हैं। बिग बाजार मल्टी ब्रांड रीटेल की सबसे बड़ी चेन है जो फ्यूचर ग्रुप का है और 90 शहरों के अंदर अपने 200 स्टोर्स खोल चुका है। भारती वॉलमार्ट का ईजीडे भी करीब 220 स्टोर्स खोल चुका है। नेचर्स बास्केट और पूर्ति ग्रुप भी सुपर मार्केट और मल्टी ब्रांड रीटेल में अपने स्टोर्स लगातार खोले जा रही है। हमारे देश के अंदर टाटा, बिरला, रिलायंस, पूर्ति और भारती सभी मल्टीब्रैंड रिटेल्स के शॉप्स खोल रहे हैं। सुषमा जी ने अंबाला का जिक्र किया।...*(व्यवधान)* पूर्ति पर मैं आऊंगा। सुषमा जी ने अंबाला का जिक्र किया। अंबाला में 10-15 ऐसे स्टोर्स में सुषमा जी को बताना चाहता हूं। हमें खुशी होती है जब आप अंबाला की बात करती हैं, क्योंकि आप अंबाला से आती हैं। हम इस बात का सम्मान करते हैं। रिलांयस फ्रैश के अंबाला कैंट और अंबाला सीटी के अंदर स्टोर्स खुल चुके हैं। उनके साथ किराना स्टोर्स भी हैं और उनको खोलने वाले भी वही व्यापारी हैं। किराना के स्टोर भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। रिलायंस का स्टोर भी चल रहा है, बढ़ रहा है। इजी डे, बिग बाजार और वी मार्ट का स्टोर भी अंबाला के अंदर है। केवल अंबाला के अंदर तकरीबन 15 ऐसे स्टोर्स खुल चुके हैं। सुषमा जी अंबाला की बात तो करती हैं, लेकिन उन्हें शायद अंबाला गए हुए काफी समय हो गया है। काफी दिनों से अंबाला नहीं गई हैं । अंबाला में क्या बदलाव हुआ है, इन्होंने नहीं देखा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : हर भाई दूज और रक्षा बंधन पर जाती हूं। ऐसा मत कहो कि नहीं गई। पता कुछ है नहीं, बेवजह कुछ भी बोल दिया।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं माफी मांगता हूं और मुझे खुशी है कि कम से कम साल में एक बार आप अंबाला हो ही आते हैं।

• पूर्ति ग्रुप के बड़े-बड़े स्टोर्स हैं और खुल रहे हैं। पूर्ति की बेवसाइट पर, जिसके भारतीय जन ता पार्टी के अध्यक्ष चैयरपर्सन हैं, उस पर लिखा हुआ है—

[अनुवाद]

> "समूह ने खुदरा व्यापारी और किसान के बीच दूरी को कम करने के उद्देश्य से गहरी मध्यम वर्ग को उचित मूल्य और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए पूर्ति सुपर बाज़ार ब्राण्ड के अंतर्गत सुपर मार्केट्स की बहुब्राण्ड खुदरा शृंखला स्थापित की है। किसानों को सीधे उचित मूल्य देने के लिए समूह ने पूर्ति एग्रोटेक नामक एक कृषि उत्पादन पैकेजिंग युनिट शुरू की है।

[हिन्दी]

अच्छी विजन है। मैं मानता हूं कि पूर्ति ग्रुप में भी सारा काम खराब नहीं हो रहा है। कुछ काम वह भी अच्छा कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं और मैं इससे सहमत हूं कि जो पूर्ति ग्रुप की बवेसाइट पर लिखा है और जो उनका, विजन है कि सीधा फार्मर को प्राइज दिया जाए। मगर मुझे इनका विरोध समझ नहीं आया। इनका दृष्टिकोण समझ नहीं आया। यह मल्टीब्रैंड रिटेल के भी खिलाफ नहीं हैं। इनके समय में बिग बाजार शुरू हुआ, पूर्ति ग्रुप शुरू हुआ। यह एफडीआई के भी खिलाफ नहीं हैं। यह किसके खिलाफ हैं? यह कांग्रेस के खिलाफ हें, यूपीए के खिलाफ हैं और किसी के खिलाफ नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है।

महोदया, मुझे लगता है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। एफडीआई मल्टीब्रैंड रिटेल में एक शुरूआत की है। मैं नहीं समझता कि बड़े-बड़े जो क्लेम किए जा रहे हैं कि वह खत्म हो जाएंगे, व्यापारियों को नुकसान होगा। मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि इसमें सैफगार्ड का प्रबंधन किया गया है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि इससे किसानों की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानों का दर्द समझता हूं। सारी समस्याएं इससे हल नहीं होने वाली हैं। मगर यह अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है। जितना विकल्प दे सकें, उतना अच्छा है। यह किसान के लिए खराब नहीं है। आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू एक-दो रुपये प्रति किलो पर बेचता है। उसके तीन महीने बाद अपना ही आलू तीस-चालीस रूपये पर खरीदने को मजबूर होता है। ऐसे ही टमाटर की बात है। अपनी ट्रॉली का डाल खोल कर किसान सड़कों पर अपना आलू गिराने को मजबूर होता है, जो फोटो पंजाब के सांसद दिखा रहे थे। इसलिए किसानों को जितना विकल्प दें, वह उनके लिए बुरा नहीं हो सकता है। विकल्प देने की आवश्यकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वह इन्हीं को देगा। अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का स्टोर किसान को ज्यादा भाव देगा तो वह उसको देगा। देश का किसान बेवकूफ नहीं है। देश के किसान को मूर्ख न समझिए। जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको अपनी फसल देगा, किसी और को नहीं देगा। अगर आढ़तिया देगा तो उनको देगा, जिनको आपने परंपरागत एटीएम का नाम दिया है। आपने कहा कि किसान और परंपरागत एटीएम के रिश्ते को महिमामंडित करने का काम किया है। मैं यह कहना चहाता हूं कि मेरे ज्ञान के चक्षु आपने खोल दिए, जब आपने एक परंपरागत एटीएम का नाम दिया और कहा कि किसान को अपने दुख, में, अपनी हारी-बीमारी और ब्याह-शादी में जब उस पर मजबूरी होती है तो इनके पास जाते हैं और वहां से इनको विश्वास के ऊपर पैसा मिल जाता है, जैसे कि दिन-रात एटीएम से पैसा मिल जाता है। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि विश्वास पर पैसा नहीं मिलता, ब्याज पर पैसा मिलता है। वे एटीएम जरूर हैं, दिन-रात पैसे देने को तैयार जरूर हैं। मगर, जब पैसा मिल जाता है तो एटीएम की तरह नहीं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का ब्याज उस पैसे पर चलता है और उस ब्याज का चक्कर इतना जबरदस्त होता है कि किसान की जान और जमीन इनके पास होती है। इस पर बहुत-सी स्टडीज हैं। नाबार्ड की स्टडी है। मैं एक स्टडी कोट करना चाहता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यरल डेवलपमेंट की एक स्टडी से मैं कोट करना चाहता हूं। यह स्टडी थी आंध्र प्रदेश और क र्नाटक के किसानों की इनडेटेडनेस की कि वे कर्ज के बोझ के तले इतने दबे हुए क्यों हैं? इतनी सुसाइड्स क्यों हो रही हैं? मैं उद्धंत करता हूं:

[अनुवाद]

> "कई मामलों में आत्महत्या का कड़ा कदम निजी साहूकारों द्वारा भारी दबाव और अपमान के कारण उठाया गया। इसका मुख्य कारण है किसानों विशेषकर छोटे, सीमान्त व मझोले किसानों का बिचौलियों और व्यापारियों के साथ समझौता होता है जो कृषि जिन्स के आदान आपूर्तिकताओं साहूकारों और व्यापारियों के रूप में भी काय करते हैं।

[हिन्दी]

आप टाइ-अप की बात कर रहे थे, विश्वास के रिश्ते की बात कर रहे थे। एक नाबार्ड की भी स्टडी है। बहुत सारी स्टडीज हैं। मगर, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता। आपकी विचारधारा हो सकती है। आपकी विचारधारा उन एटीएम्स के प्रति हो सकती हैं। वे जो बीच के एटीएम जिन्हें आप परंपरागत एटीएम कहते हैं, उनको लेकर आपकी विचारधारा है। मैं आपकी विचारधारा का सम्मान करता हूं। हम उस बात से सहमत नहीं हैं, मगर सम्मान कर सकते है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। आप इस विचारधारा को लेकर

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

और उस परंपरागत एटीएम, बीच में जो साहूकार किसान को चूसने का काम करता है, उसको अपना ब्रांड अम्बैसडर बनाकर वर्ष 2014 में आप लोक सभा चुनाव में जाकर देखें, आपको देश के लोग बताएंगे।

आपने मैक्डोनाल्ड्स का नाम लिया, आपने किसान की बात कही। आपने मैक्डोनाल्ड्स का नाम लिया और कहा कि मैक्डोनाल्ड्स अपना आलू अमरीका से ला रहा है, वहां से जहाज आ रहे हैं, पेप्सीको अपना आलू, टमाटर कहीं बाहर से ला रहा है, उसके जहाज आ रहे हैं। हमने पता किया कि मैक्डोनाल्ड्स कहां से आलू ला रहा है? पता चला कि मैक्डोनाल्ड्स गुजरात के किसानों से आलू ला रहा है। सबसे ज्यादा मैक्डोनाल्ड्स के स्टोर इस देश में कहां हैं? पता चला कि सबसे ज्यादा मैक्डोनाल्ड्स के स्टोर गुजरात में हैं। आपकी कल की भाषा सुनकर मैक्डोनाल्ड्स भी घबरा गया। मैक्डोनाल्ड्स की रात में एक प्रेस स्टेटमेंट आई कि हम सारे आलू इस देश से लेते हैं। गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है। लेकिन जैसे ही वह आलू जमीन से निकल कर बाहर आता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैक्डोनाल्ड्स की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं कि मैक्डोनाल्ड्स वाले को घबड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में आपका मान-सम्मान नहीं हो रहा है तो आप हरियाणा में आ जाएं, अंबाला आ जाएं। आप छः इंच और बाहर इंच के आलू की बात करते हैं, हम आपको चौबीस इंच का आलू पैदा करके दे देंगे। आप यहां पर आ जाओ।

हरसिमरत जी ने पेप्सीको के बारे में कहा।...*(व्यवधान)* मैं आपके दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं।...*(व्यवधान)* हरसिमरत जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं। मैं आपके विचारों का भी सम्मान करता हूं और मैं अपने भाई सुखबीर बादल जी के विचारों का भी सम्मान करता हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात मान गया कि उनके विचार पहले के थे।...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात मान गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बात करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, नहीं, ऐसा कैसे चल रहा है? इधर देखकर बात कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं आपकी बात मान गया।...*(व्यवधान)* आप लोग हमारे बड़े प्रदेश के हैं। जब आप लोग कभी बोलते हैं तो हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं काते। यह हम मान गए कि सुखबीर जी के जो विचार थे, वे एफडीआई पॉलिसी के पहले के थे जब उन्होंने कहा था कि एफडीआई आनी चाहिए। उन्होंने जोर से कहा था कि एफडींआई आनी चाहिए। उन्होंने जोर से कहा था कि एफडीआई आनी चाहिए और अब इनके विचार बदल गए। उन्होंने पिछले नवंबर में कहा था–

[अनुवाद]

"हम मानते हैं कि बहु ब्राण्ड खुदरा में एफ.डी.आई. खोलने से विदेशी खुदरा व्यापारियों की विशेषता, अनुभव और संसाधन आऐंगे। बैक हैण्ड निवेश का सबसे अधिक लाभ किसानों को होगा जो अतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रणाली का लाभ उठाएंगे।"

सुखबीर बादल जी की यह स्टेटमेंट है। वे आगे कहते हैं कि:

"आपूर्ति शृंखला और स्टोर में निवेश से ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए रोज़गार के लाखों अवसर उत्पन्न होंगे। एक सक्षम आपूर्ति शृंखला से मुद्रास्फीर्ति को भी कम करने में सहायता मिलेगी जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।"

"....इन लाभों को देखते हुए मैं, आपको और आपकी सरकार को यह बड़ा कदम उठाने के लिए पूर्ण समर्थन देता हूं जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा"

[हिन्दी]

मगर कोई बात नहीं, आपने विचार बदल लिए। संगरूर के अंदर पेप्सी फैक्ट्री वाले आज घबरा रहे हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि वे अगर लगाना चाहें तो अपनी फैक्ट्री हरियाणा, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में लगाएं। आपकी भाषा से आज वे घबरा

रहे हैं। उपभोक्ता के बारे में कहा गया कि प्रीडेटरी प्राइसिंग हो जाएगी। पहले बड़े स्टोर आएंगे, वे अपना दाम कम करेंगे, सस्ते में देंगे और उसके बाद अपनी मनचाही कीमत वसूल करेंगे और प्रीडेटरी प्राइसिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यह कहा, उन लोगों को शायद हमारे देश के कानून में जो मेक्सिमम रिटेल प्राइस का कानून है, उस बारे में ज्ञान नहीं है। कोई भी हमारे देश में ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकता। छोटे व्यापारी की बात आई। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो सेफगाड्र्स आए, वे जो सेफगाड्र्स हैं।...*(व्यवधान)* एक फर्क है, जब प्रियरंजन दासमुंखी जी ने इसके विरोध में बयान दिया था, बार-बार उनका नाम लिया गया। जो अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसी संसद की गरिमा है, क्योंकि वे अपना पक्ष नहीं रख सकते। उनके एक बयान के बारे में बार-बार कहा गया। मुझे लगता है कि उन्होंने जब इसका विरोध किया था। उस वक्त 2004 में जो नोट था, एनडीए का जो नोट था, पूरे देश के अंदर सौ फीसदी एफडीआई, 53 शहरों में नहीं,...*(व्यवधान)* इसीलिए उन्होंने विरोध किया। उनकी नीति में कोई सेफगाड्र्स नहीं थे। छोटे शहरों के लिए ग्रामीण व्यवस्था एवं ग्रामीण अंचल के लिए कोई सेफगाड्र्स नहीं थे। उस नोट का जो विरोध था, मुझे लगता है कि वह विरोध उन बातों को लेकर किया गया हो। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी के अंदर एक और बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया। जब उन्होंने देखा कि सब के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं, कंसेंसस नहीं है तो प्रदेशों पर छोड़ा। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करने की तरफ ये एक बहुत बड़ा फैसला था। प्रदेशों पर छोड़ा कि प्रदेश अपना फैसला खुद लें। मैं ममता बनर्जी जी का सम्मान करता हूं। पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्य मंत्री और बंगाल के एक-एक व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूं। एक कहावत है–''आज बंगाल जो सोचता है, कल देश उसे सोचेगा'' मैं बंगाल का सम्मान करता हूं और उनका भी सम्मान करता हूं। पश्चिम बंगाल में जो होगा, उसका फैसला ममता बनर्जी की कलम से होगा, अन्य किसी की कलम से नहीं होगा। मैं इस बात का सम्मान करता हूं, उनके अधिकार का सम्मान करता हूं। मगर हरियाणा के अंदर जो होगा, उसका फैसला भी हरियाणा के चुने हुए मंख्य मंत्री जी करेंगे, अन्य कोई नहीं करेगा, यह बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है। लोग संघीय ढांचे के बारे में बोलते हैं, संघीय ढांचे को मजबूत करने की तरफ यह फैसला है। इस फैसले के ऊपर भी बहुत से लोगों ने बात की, मगर यह फैसला लागू हुआ। इसका चारों तरफ राजनैतिक विरोध हुआ।

जहां तक आर्थिक दृष्टि की बात है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर एक नयापन आया, खुशहाली आई। सेंसेक्स के अंदर उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछले दो महीने के अंदर दस प्रतिशत आगे बढ़ा। जहां करोड़ों निवेशक हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से छोटे व्यापारी भी निवेशक हैं, वह दस प्रतिशत आगे बढ़ा। हमारे रुपए की जो वेल्यू है, रुपए बनाय डॉलर तकरीबन नौ प्रतिशत आगे बढ़ा।...*(व्यवधान)* रैटिंग एजेंसियों ने भारत के आउटलुक को अच्छा किया, मगर इन्होंने विरोध किया। आप लोग विरोध कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं संवाद करूगा, विरोध करने का अधिकार आप लोगों को है, आप लोग विरोध कर सकते हैं। विपक्ष में आप लोग बैठते हैं, विरोध आप कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन इनकी विरोध की आदत कोई नई नहीं है, ये शुरू से विरोध करते रहे।...*(व्यवधान)* अभी चौधरी जी कह रहे थे कि जब भाखड़ा का डेम बना था, नेहरू जी ने भारत के लिए भाखड़ा का डेम बनाया था, उस वक्त भी विरोध हुआ था। उस वक्त मेरे दादा जी पंजाब के सिंचाई मंत्री थे। उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने एक प्रचार किया था कि अगर भाखड़ा का डेम बन जाएगा...*(व्यवधान)* तो सारी बिजली पानी में से कांग्रेसी निकाल लेंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

कांग्रेसी क्या करेंगे, पानी में से सारी बिजली निकाल लेंगे और जो फोका पानी आएगा, वह हरियाणा-पंजाब की जमीन को बंजर कर देगा। वही नेहरू जी का भाखड़ा डैम है, जिसकी वजह से आज हरियाणा और पंजाब पूरे देश की भूख मिटाने का काम करता है।

जब कम्प्यूटर की बात आई थी, राजीव गांधी जी जब कम्प्यूटर लेकर आए थे तो यही लोग थे, इन्होंने कहा थी कि कम्प्यूटर्स आ गए तो सारा काम कम्प्यूटर्स करेंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इस देश के लिए कम्प्यूटर ठीक नहीं है। आज वही कम्प्यूटर्स हैं, जो पूरे देश के अंदर हैं और भारत एक कम्प्यूटर की सुपर शक्ति के रूप में जाना जाता है। जब गैट, डब्ल्यू.टी.ओ. और डुंकेल ड्राफ्ट के समझौते पर, गैट पर समझौता होने लगा था तो इन्होंने एक प्रचार

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

चलाया था कि अगर यह ड्राफ्ट आ गया तो पांच साल के अंदर हमारा देश अमेरिका का गुलाम हो जाएगा, दातुन करने के लिए, नीम से डंडी तोड़ने में भी हमें अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ेगी। आज वही नीम है, वही डंडी है, वही दातुन है, लेकिन क्या हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता है। जब मैट्रो की बात आई थी तो कुछ लोग कहने लगे कि ऑटोरिक्शा और रिक्शा वाले बेरोजगार हो जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर वही मैट्रो है, बहुत से रिक्शा और ऑटोरिक्शा वाले अपना रोजगार मैट्रो की वजह से कमा रहे हैं। आज एफ.डी.आई. का ये विरोध कर रहे हैं, पहले ये न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहे थे, मैं कन्क्लूजन में कह रहा हूं, अपनी बात को कन्क्लूड करते हुए कहना चाहता हूं कि एक तरफ देश के विरोध की राजनीति है, देशवासी वह देख रहे हैं, दूसरी तरफ देश को आगे ले जाने की राजनीति है, विकास की राजनीति है, देश वालों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको भी चुनना है, विरोध की राजनीति आगे आने वाले समय में उनको ठीक लगेगी या विकास की राजनीति, इस देश को आगे ले जाने की राजनीति।

आखिरी बात, सुषमा जी ने कल कहा, उन्होंने कहा कि पिछले साठ सालों में से 50 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। मुझे लगता है कि आप लोग भी सोचें कि क्या कारण हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी इच्छा से नहीं रही है, बल्कि देश के लोगों की इच्छा से रही है। क्या कारण है कि देश के लोग बारी-बारी कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी विरोध की राजनीति को ऐसे ही आगे चलाओगे तो 2014 में भी देश के लोग एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे।

[अनुवाद]

***श्री हरिभाऊ जावले** (रावेर) : सरकार देश में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने जा रही है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 51% तक बढ़ाने का प्रस्तावित किया है। खुदरा में यह सीमा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवेश भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को पंगु कर सकता है।

भारत में खुदरा अर्थव्यवस्था के स्तंभों में से एक है, और यह जी.डी.पी. का 14 से 15 प्रतिशत है। भारतीय खुदरा बाज़ार अनुमानत: 450 बिलियन अमरीकी डॉलर का है और आर्थिक भव्य के आधार पर विश्व के पांच सबसे बड़े खुदरा बाज़ारों में से एक है। 1.2 अरब लोगों के साथ भारत विश्व के सबसे तेज बढ़ते खुदरा बाज़ारों में से एक है। भारत का खुदरा उद्योग मूलत: मालिक द्वारा संचालित छोटी किराना दुकान है। 2010 में, बड़े बड़े आकार के सुविधा स्टोर और सुपमार्केट उद्योग का लगभग 4 प्रतिशत थे और ये केवल बड़े शहरी केन्द्रों में मौजूद थे। भारत के खुदरा उद्योग लगभग 40 लाख भारतीयों को रोज़गार देता है जो भारतीय जनसंख्या का 3.3% है। दूसरे शब्दों में वत्तर्मान खुदरा उद्योग देश की जनसंख्या के बड़े भाग को नौकरियां देता है।

वर्त्तमान परिदृश्य में, यह खुदरा उद्योग किसानों से कृषि उत्पाद खरीदता है और किसानों के पास उनके कृषि उत्पाद खरीदने के लिए अनेक खुदरा क्रेता हैं।

यदि देश में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शुरू किया जाता है, तो सम्पूर्ण देश में छोटी दुकानों के मालिकों पर यह पहला आघात होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण देश में बड़े स्टोर आरम्भ होंगे तो छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हो जायेंगी। समाज के एक बड़े भाग की नौकरियां खत्म हो जायेंगी। समाज का यह वर्ग देश की जी.डी.पी. में 14-15% तक योगदान देता है। देश की जी.डी.पी. में कमी आ सकती है जो देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभार डाल सकता है।

दुकान मालिकों की तरह ही देश में मालिकों द्वारा संचालित दुकानों के बन्द होने के कारण कृषि उत्पादों के खरीदार भी घट जाएंगे। देश के किसानों के कृषि उत्पाद की खरीदारी के लिए बाजार में चुनिंदा और नाममात्र के स्टोर मालिक रह जाएंगे। अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। कुछ एफ.डी.आई. निवेशक कृषि उत्पादों की खरीद में अपना एकाधिकार जमा लेंगे। किसानों के उत्पादों के कम मूल्य का भी आशंका है।

दूसरी ओर, निवेशक कंपनी पर लाभ अर्जित धन को भारतीय बाज़ार या भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने का प्रतिबन्ध नहीं है। तो ये कम्पनियां भारतीय मुद्रा में अर्जित लाभ को सीधे विदेशों में अंतरित करेंगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस प्रकार देश में खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. देश के वर्तमान खुदरा और कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है।

अत: देश में किसी भी कीमत पर एफ.डी.आई. न लाई जाए।

[हिन्दी]

***श्री अशोक अर्गल** (भिंड) : एफ.डी.आई. के भारत में आने से रिटेल में छोटे-छोटे व्यापारियों, आम आदमी का रोजगार छिनेगा जिससे देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश मानार जाता था जिसे विदेशी शक्तियों ने नष्ट किया है कमजोर किया है। देश के हजारों लोगों ने देश की आजादी हेतु अपनी जान इस देश के लिए दी है तब कहीं हमें आजादी प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में एफ.डी.आई. यदि भारत में आई तब यहां का मार्केट धारासाई होने का खतरा आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर चायना के माल बाजार में 70-75 प्रतिशत देखने को मिल रहा है जो टिकाऊ नहीं है, गारंटी नहीं है तथा सुधार योग्य नहीं है। इलैक्ट्रोनिक सामान हो अथवा खिलौने, टायर, बैट्री हो विभिन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं।

आज देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। खेती घाटे का सौदा बन कर रह गई है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है। आज देश में करोड़ों युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। एफ.डी.आई. को लाना है तो बिजली, सड़क के क्षेत्र में लाए रिटेल में एफ.डी.आई. का मैं विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री धनंजय सिंह** (जैनपुर) : भारत में खुदरा उद्योग प्रगतिशील क्षेत्रों में से एक है जिसमें व्यापक विकास क्षमता है। सकल घरेलू उत्पाद में ये लगभग 12 प्रतिशत का योगदान देता है तथा कृषि के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है जो कुल कार्य बल का लभग 8 प्रतिशत रोजगार देता है।

तथापि, यह भी सही है कि पूरे विश्व में खुदरा उद्योगों की तुलना में भारतीय खुदरा उद्योग का विकास नहीं हुआ है तथा कुल खुदरा व्यापार का 95 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। अत: मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा जटिल है और इसके लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है। समय की मांग है कि सरकार विभिन्न भागीदारों के परामर्श प्रत्येक खंड की विस्तृत जांच करे और अंतिम निर्णय लेने से पहले उनको भी शामिल करे। पूरे विश्व में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को खोलने के अनुभवों पर प्रभावी ढंग से विचार किया जाए। सरकार का प्रेरक और अंतर्निहित प्रयोजन एक सुदृढ़ नीति लाना होना चाहिए जिसका आशय न केवल भारत में खुदरा क्षेत्र में सुधार और वृद्धि करना हो बल्कि यह नीति ऐसी हो जिसमें पर्याप्त संशोधन हों ताकि जो लोग आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं उन पर कुप्रभाव न पड़े। निर्वाचित सरकार का दायित्व है कि वह ये सुनिश्चित करे कि विभिन्न समूहों तथा साथ ही विपक्ष की समस्त चिंताओं और शंकाओं का निराकरण कर दिया गया है ताकि उनका विश्वास में लिया जा सके।

यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए यह आवश्यक है जनता के व्यापक लाभ के लिए सभी दल अपनी निजी राजनैतिक महत्वकांक्षाओं को अलग रखते हुए साथ मिलकर काम करें। निम्नलिखित कुछ बिन्दु और विचार हैं जिन पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:

हानिकर मूल्य निर्धारण : बड़े विदेशी खुदरा व्यापारी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास में मूल्यों में हेर फेर करने लगते हैं। रहे हैं। ऐसी आशंका है कि वॉलमार्ट और ऐसी ही अन्य कम्पनियां आरंभ में उत्पादन मूल्य घटाने हानि उठा कर भी सीमा उत्पाद मूल्य घटाने तक जाएंगे। जिससे व्यापार से छोटे खुदरा व्यापारियों का सफाया हो जाए। इससे उनको व्यापार में एकाधिकार जमाने में सहायता मिलेगी। उत्तरोत्तर में, ये खुदरा विक्रेता आपने लाभ बढ़ाने के लिए मूल्यों को बढ़ाएंगे।

अत:, इन प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों के विरूद्ध कड़ी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। सरकार अनिवार्य रूप से उन प्रभावित कदमों को स्पष्ट करे जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऐसे हानिकार बड़े रिटेलरों को व्यवहारों का पालन करने के लिए प्रोत्साहन न मिले।

30 प्रतिशत स्थानीय खरीद संसाधन : भारत में विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए भारत के "लघु उद्योग" से विनिर्मित उत्पाद की प्रागण/संसाधित उत्पादों को खरीद, को बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री धनंजय सिंह]

सरकार वस्तुओं और उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय प्रापण के लिए मानकों और विनियमों का भी स्पष्ट निर्धारण करे। अंत में ऐसा परिदृश्य न हो जो चीन जैसी मजबूत और सस्ती विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं के हितों के अनुकूल हो।

संविदा कृषि : कुछ मामलों में, यह देखा गया है कि कई बार बड़े रिटेलर किसी एक फसल का ऊँचा दाम देकर किसानों के साथ किसी फसल विशेष का उत्पादन करने के लिए गुलाम बनाने वाली संविदाओं पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इससे न केवल कृषि भूमि का विपथन हो रहा है बल्कि विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

यह भी संभव है कि भविष्य में बड़े रिटेल आउटलेट बनाने के लिए कृषि भूमि का काफी अधिक प्रयोग हो। इसको अवश्य रोका जाए। बिचौलियों की बढ़ती संख्या इस धारणा के विपरीत कि बड़े रिटेलर बिचौलियों की संख्या कम कर देंगे, ये वस्तुत: अपने स्वयं के अलग बिचौलिए गुणवत्ता नियंत्रक, पैकेजिंग सलाहकार, प्रमाणन अभिकरण, संसाधक, आदि लाते हैं।

अत: यह देखा जाए कि बड़े रिटेल के प्रचारकों द्वारा किए गए दावे के अनुसार किसानों को हुए अधिक लाभ में से, वास्तव में कितना लाभ प्राप्त होगा।

चीन में खुदरा क्षेत्र को खोलने का मामला : मैं चीन ने जिस प्रकार रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अपने द्वार खोले है मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आरंभ में चीन ने रिटेल के केवल 26 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति दी और 12 वर्षों के बाद इसे 51 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। रिटेल खुदरा क्षेत्र को क्रमिक रूप से खोलने से स्थानीय शृंखलाओं को अपनी सुरक्षा करने और बड़े विदेशी रिटेलरों से प्रतिस्पर्धा करना सीखने के लिए पर्याप्त समय मिल गया।

अत:, मैं सरकार से इस साक्ष्य पर विचार करने तथा भारतीय खुदरा क्षेत्र को धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का आग्रह करता हूं।

रोजगार की हानि और असंगठित खुदरा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण : मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि भारतीय खुदरा क्षेत्र को विदेशी रिटेलरों के लिए खोलने से पहले, यह छोटे खुदरा विक्रेताओं का संवर्धन करने और इनकी सुरक्षा करने के लिए समग्र आवश्यक कदम उठाए। छोटे खुदरा विक्रेताओं को अपनी स्थापनाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए आसान ऋण दिया जाएं। यदि बड़े रिटेलर भारतीय बाजार में प्रवेश करेंगे तो इससे उनको बड़े रिटेलरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, छोटे खुदरा विक्रताओं को अपने लाभ बढ़ाने के लिए आपस में सहकारी समितियां बनाने की अनुमति तथा आगे प्रोत्साहन दिया जाए।

सुदृढ़ विनियामक स्थापना : अंत में, जैसा कि 2009 में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा सुझाया गया है, यदि बड़े रिटेलरों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो सरकार को सुदृढ़ विनियामक ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता होगी जिससे कि बड़े रिटेलरों के अनुचित कार्य व्यवहारों पर रोक सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न विचारों जैसे कि बड़ी रिटेल दुकानों का आकार व संख्या, छोटे खुदरा विक्रेताओं से इनकी समीयता, श्रम कानून पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ये सभी मुद्दे इस तथ्य को दोहराते हैं कि कई लोगों को भारतीय बाजार में बड़े विदेशी रिटेलरों के प्रवेश के संबंध में अभी भी कई संदेह है। सरकार अपनी ओर से समस्त भागीदारों के मतों और हितों पर अवश्य विचार करे। मैं भी सरकार से मेरे विचारों का बिन्दु-दर-बिन्दु उत्तर देने का अनुरोध भी करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी द्वारा देश में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध में 184 में चल रही चर्चा में हम इस विरोधका समर्थन करते हुए सरकार की गलत व आत्मघाती नीति का जिसमें देश में परंपराओं से चल रहे 120 करोड़ जनता की आबादी वाले देश में छोटे-छोटे व्यापार पर कृषि क्षेत्र पर आघात को देखते हुए विरोध करता हूं। खुदरा व्यापार में विदेशी से रोजगार नहीं बढ़ेगा बल्कि जो छोटे व्यापार में स्वयं रोजगार करने वाले छोटे दुकानदारों पर गाज गिरेगी। उनका रोजगार समाप्त होगा। इन छौटै-छोटे दुकानों के मालिक नौकरी करेंगे या बेरोजगार बनेंगे परिवार भूखा रहेगा। रोजगार छीना जाएगा। गांव-गांव में गली-गली में इन छोटे दुकानों की संस्कृति समाप्त होगी जो देश

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की परंपरा व समाज मान्य संस्कृति है। वैसे ही किसानों की उपज का जो सरकार ने मूल्य देना है व सरकार एमएसपी बढ़ाकर दे सकती है। सरकार मूल्य बढ़ाकर देने की जिम्मेदारी से हटकर विदेशी कंपनियों को सामने लाकर उन्हें मूल्य बढ़ाकर देने की विनती करेगी इससे बढ़कर शर्म की बात सरकार के लिए नहीं होगी। किसानों की उपज को एमएसपी बढ़ाकर देने की मांग कांग्रेस पार्टी छोड़कर सभी दल करने आए हैं। सरकार कृषि उपज का मूल्य बढ़ाए विदेशी कंपनियों पर क्यों निर्भर है? आपके अधिकार है। मूल्य बढ़ाईये हम समर्थन देंगे।

सरकार द्वारा लाया जा रहा विदेशी निवेश जो खुदरा बाजार मे उचित नहीं है। सरकार इसे वापस ले यह गलती सरकार न करे। आने वाली पीढ़ी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

मैं इस विदेशी निवेश का विरोध करता हूं।

***श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव) : आपने मुझे इस अति-महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार ने जो खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. 51 प्रतिशत लाने का फैसला किया है वह भारतीय आम जनता क

विरोधी है। इसका असर पूरी तरह गरीब और आम आदमी पर पड़ने वाला है। हमारे देश में पहले से ही कोई नीति-निर्धारण नीति नहीं थी। सरकार ने जो देश के किसानों को इसका लाभ हो सके, अभी तक सरकार ने 'मिनिमम सपोर्ट प्राइज' सभी उत्पादन पर नहीं बनाई है। हर वर्ष हमारे किसान अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलने से ओने-पोने मूल्य पर उसे बेचने को मजबूर हो जाते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र के किसान और जलगांव, जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, यहां पर देश का सबसे ज्यादा केला उत्पादन होता है। ऐसे छोटे-मोटे किसानों पर इस एफ.डी.आई. नीति का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से किसान बहुत छोटे हैं, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 एकड़ जमीन होती है।

इसी जमीन में उसे सभी तरह का उत्पादन करना है तो वह किसान कहां जाएगा, बेचने के लिए। वह मजबूर हो जाएगा, उसे विदेशी कंपनियों के एजेंटों को बेचने के लिए और वे लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जिन लोगों ने गांव में या शहरों के गरीब झुग्गी-झोंपड़ी में अपना किराना शॉप लगाई है वे कहां जाएंगे। ऐसे लोग अपने देश में कितने हैं? इसका सरकार ने कोई आकलन नहीं किया है। मैं विशेषकर महाराष्ट्र के किसानों के बारे में बताना चाहता हूं। आज जो स्थिति महाराष्ट्र के किसानों की है वह एफ.डी.आई. के बाद बहुत खराब होने वाली है और आत्महत्या के केस बढ़ने वाले हैं।

इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस एफ.डी.आई. को आम सहमति बनाने के लिए कोशिश करें। उसे अब वापस ले लेना चाहिए।

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़) : एफ.डी.आई. से आने वाले दिनों में जहां देश का खुदरा व्यापार प्रभावित होगा। छोटा-छोटा काम करने वाले, छोटी दुकानों वाले, खोमचा वाले, रेहड़ी वाले, हाथ ठेला वाले प्रभावित होंगे। वहीं करोड़ों की संख्या में बेरोजगारी बढ़ने से घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। लोग फांका मारने को मजबूर हो जाएंगे जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। देश का आर्थिक-सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा। देश का उत्पादन प्रभावित होगा। विदेशों में निर्मित वस्तुओं से बाजार पट जाएंगे। पारंपरिक रूप से अनेक समाज कुछ विशेष वस्तुओं का निर्माण एवं व्यापार करते आ रहे हैं वह उत्पादन बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। वालमार्ट जैसे बड़े-बड़े स्टोर खुलने से बड़े-बड़े शहरों में चमक अवश्य बढ़ जाएगी किंतु करोड़ों घरों एवं अनेक छोटे-छोटे शहरों की रोशनी बुझ जाएगी। विदेशी वस्तुओं के नाम पर चायना का 70 प्रतिशत माल देश के बाजार में भर जाएगा। जहां विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर सॉस एवं चिप्स बनाने के नाम पर किसानों का टमाटर, आलू, अंगूर खरीदने की बात करेंगी वही कंपनियां बाद में कहेगी टमाटर खट्टा है, आलू छोटा है, अंगूर बेस्वाद है।

सेब की पेटी में से एक सेब खराब होने पर कहेंगे, पूरे ट्रक में बैक्टीरिया हो गया, रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह देश का किसान ठगा जाएगा तथा बाहर का टमाटो सॉस, आलू चिप्स महंगे दाम पर तो खरीदना ही पड़ेगा तथा हमारे यहां के किसान का टमाटर, आलू वही खरीदने से वह बेरोजगार भी होगा तथा पूरा घर भूखा मरने पर मजबूर हो जाएगा। जहां सरकारें खेती को लाभ का सौदा बनाना चाहती है, घाटे का व्यापार बन जाएगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। आज देश का किसान तथा खेती से जुड़ा हुआ मजदूर सभी एफ.डी.आई. के आने से होने वाले दुष्परिणामों से काफी चिंतित है। जहां वालमार्ट जैसे माल के केवल उच्च शिक्षित नौजवानों को ही रोजगार है तो हमारे देश में करोड़ों नौजवान जो गांव-कस्बों से लेकर शहरों तक में कम शिक्षित होने पर भी रोजगार में लगे हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे। एफ.डी.आई. जहां देश की कृषि, खुदरा व्यापार एवं निर्माण को प्रभावित करेगी वहीं नौजवानों में हताशा भी पैदा करेगी। अत: एफ.डी.आई. को अगर लाना ही है तो शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में सड़क मार्ग, बिजली निर्माण के क्षेत्र भी पहल करें ताकि देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर सकें । एफ.डी.आई. के केवल भयावह रूप से जहां लोग भयभीत हैं वहां इनके निर्माणव क्षेत्र में आने से विकास के लिए भी आशांवित हो सकेंगे। कुल मिलाकर एफ.डी.आई. किसी भी दृष्टि से देश के हित में नहीं है।

[अनुवाद]

***डॉ. मिर्जा महबूब बेग** (अनंतनाग) : नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अन्य नेताओं को सुनने के पश्चात् ऐसा लगता है कि वे किसानों, छोटे व्यापारियों को ऐसे डराने में लगे हुए है जैसे कि कोई विदेशी हमला होने वाला है। इसके बजाएं, उन्हें इनको भरोसा दिलाना चाहिए तथा उन्हें वैश्विक प्रतियोगिता हेतु प्रेरित करना चाहिए था। वस्तुत: एफ.डी.आई. भारतीय किसानों तथा व्यापारियों की तेज प्रगति के लिए एक आधुनिक अस्त्र है। नेता प्रतिपक्ष का यह तर्क कि "वालमार्ट गरीब किसान की बहन की शादी की चिंता करेगा" हिला देने वाला तथा निरर्थक था।

आर्थिक प्रकृति वाले एक मुद्दे को राजनीतिक बना दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष, सहमति और परामर्श की बात करती है, भाजपा द्वारा मतदान के लिए कहना और सत्ता तथा विपक्ष में होने पर अलग-अलग रूख अपनाना गैर-जिम्मेदाराना है। यहां तक कि खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. का सांप्रदायिक दिखना या खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. का कर्मनिरपेक्ष होना, में कोई संबंध नहीं है। पिछले सत्र में, भाजपा पूरी तरह से संघीय प्रणाली का मुद्दा उठा रही थी और अब जब यू.पी.ए. राज्यों को एफ.डी.आई. अपनाने या न अपनाने का विकल्प दे रही है तो वे इसका विरोध कर रहे हैं। गुजरात, जम्मू और कश्मीर के लिए निर्णय नहीं ले सकता और न ही जम्मू और कश्मीर, गुजरात के लिए ऐसा कर सकता है। हम उन किसानों की सहायता किस प्रकार करेंगे, जिनकी मेहनत से उगाए गए खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त भंडारण, शीतागार शृंखलाएं, रेफ्रीजरेटर तथा खेत से थाली तक चीजें पहुंचाने के लिए साधन नहीं होते। क्या के.एफ.सी. ने ढाबों को समाप्त कर दिया या क्या पेप्सी तथा कोक ने शर्बत का स्थान ले लिया?

अंत में, जिन देशों में खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. लागू किया गया है उन्हें या तो अत्यधिक लाभ हुआ है या ज्यादा लाभ नहीं हुआ, परंतु इससे किसी देश को हानि नहीं पहुंचाई है।

***श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला** (संगरूर) : मैं मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा और सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज का यह कथन सही नहीं है कि पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसने आलू चिप्स के विनिर्माण हेतु अपनी इकाइयां लगाई हैं, पंजाब के किसानों से आलू तक नहीं खरीदती। मैं यह रिकार्ड पर कहना चाहूंगा कि केवल संगरूर से पेप्सी की एक यूनिट द्वारा लगभग 40 हजार टन आलू की खरीद की जा रही है जिससे समूचे राज्य में 1000 किसानों को लाभ मिल रहा है। केवल यही नहीं संगरूर, कोलकाता तथा पुणे में स्थित पेप्सी की 3 इकाइयों की भारत के 9 राज्यों से 2 लाख 40 हजार टन आलू की आपूर्ति की जा रही है जिससे देश में 19 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

आलू में पेप्सी संविदा खेती पहलों से किसानों को उन्नत खेती व्यवहार पर पहुंच, मौसम का बीमा, किसानों से वापिस खरीदने का मूल्य जिससे उन्हें एक नियमित आय मिले। यह एक भागीदारी उद्यम है और सभी को लाभ देता है। संविदा खेती आलू, टमाटर, बासमती चावल, लाल मिर्च और मूंगफली हेतु की जा रही है। संविदा कृषि तकनीकें और बिचौलियों से छुटकारा मिलता है। क्या भाजपा को मध्यम वर्ग और व्यापारी समुदाय में अपने वोट बैंक को खोने का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भय है? क्या वे ऋणदाताओं, कमीशन एजेंटों का समर्थन कर रहे हैं? क्या विपक्ष किसानों के हितों की अनदेखी करके प्रति सहानुभूति रखने का दावा कर रहा है।

क्या किसी को उपभोक्ता की चिंता है? क्या उपभोक्ता को कृषि में खामियों के कारण खामियाजा भुगतना चाहिए? भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, महाराष्ट्र में संविदा कृषि की जा रही है। क्या वहां संविदा कृषि के विरोध में कोई प्रदर्शन हुए हैं? जी, नहीं।

मैं मानता हूं, कि यदि हम उक्त तथ्यों को देखे तो मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई., न केवल किसानों, व्यापारियों की सहायता करेगा बल्कि बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार अवसर भी सृजित करेगा और हमारे देश में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेगा।

[हिन्दी]

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह) : मैं खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के सरकार के निर्णय क खिलाफ हूं और मैं मांग करता हूं कि इस निर्णय को देश के हित में शीघ्र ही वापस लिया जाना चाहिए।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश देश के लिए घातक एवं विनाशक है। जैसे अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी हींग, चाय इत्यादि के व्यापार हेतु भारत में प्रवेश किए थे और लगभग ढाई सौ वर्ष भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़कर खून चूसा था। ठीक वैसे ही यहां पर भी हम कहीं वैसी ही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी के निवेश से देश के किसान, उपभोक्ता, युवा, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, गरीब एवं सभी वर्गों के लगभग 25 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएंगे। उनके घर में अंधेरा हो जाएगा।

यदि सरकार इतनी ही उदार है तो मल्टी नेशनल कंपनियों, बड़े-बड़े पुल निर्माणों तथा बड़े-बड़े कारखाने लगाने, पावर प्लांट हेतु भारत में आएं तो उनका स्वागत है। बेरोजगारों हेतु रोजगारोन्मुखी योजना लाएं तो देश का हित निश्चित है।

इस गलत नीति की वजह से सारे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान और अधिक आत्महत्याएं करेंगे। जो आज मालिक है कल वो उन्हीं के यहां मजदूरी करेंगे, यह निश्चित है। और कब उनकी नौकरी चली जाएगी यह भी उन्हें नहीं पता होगा। कृषि के बाद रोजगार देने में खुदरा व्यापार क्षेत्र कुल रोजगार का 7.2 फीसदी रोजगार देता है, जो कुल मिलाकर 33 करोड़ से भी ज्यादा रोजगारी देता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) रिपोर्ट, 2010 के अधिकृत आंकड़े के अनुसार है।

वॉलमार्ट जैसी राक्षसी कंपनियां छोटे उद्यमियों को निगल जाएंगी। इसकी वजह से सारा कुटुंब का रोजगार तबाह हो जाएगा। एफ. डी.आई. की वजह से असंगठित महदूर, जो बड़ी संख्या में है वो बेकार हो जाएंगे। कोई भी नीतिगत निर्णय के तहत अगर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हाशिये में चले जाते हों, तो हमें ऐसी नीति नहीं लानी चाहिए।

बड़े-बड़े वॉलमार्ट जैसे रिटेलर शुरूआत में कम दामों पर छोटे-छोटे दुकानदार एवं किरानेवालों को बाहर कर देंगे और जब व्यापार में उनका दबदबा हो जाएगा, तब वे उपभोक्ताओं को अपने मनमर्जी के दामों पर माल लेने को मजबूर करेंगे। साथ ही साथ चाइना के भारत आने पर किसानों और उत्पादकों को अपने भाव पर सस्ता माल बेचने पर भी मजबूर करेंगे। यानि की दोनों और से वो भारी मुनाफा लेकर सबको समाप्त कर देंगे।

ये लोग एक और बेरोजगारी पैदा करेंगे साथ-साथ युवा वर्ग का शोषण करके, बहुत कम पगार पर कुछ नौकरियां देकर उनको सेल्समेन और सेल्सगर्ल तक ही सीमित कर देंगे।

इस नीति की वजह से छोटे-छोटे उद्यमियों की जगह ये वॉलमार्ट वाले स्टोर्स चाईना से बड़े पैमाने पर सस्ते दाम पर, घटिया सामान लाकर भारत के बाजार को बर्बाद करेंगे। मेरा मानना है कि भारत के बाजार में चीन का सस्ता और घटिया माल बेचा जाएगा और भातरीय उत्पादक तबाह हो जाएगा।

यह सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अभी-अभी समाचार आए थे कि वॉलमार्ट को भारत में स्थापित करने हेतु इनके द्वारा बड़ी मात्रा में घूस दी गई है। जब ये सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है तब ये मामला बड़ा गंभीर है और इससे सरकार की मंशा पर अनेक सवाल खड़े होते हैं।

मैं समझता हूं क यू.पी.ए.-2 सरकार यदि अपने होश में नहीं आती है तो आने वाले समय में देश की जनता ही इनको सबक सिखाने के लिए सक्षम है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय]

अत: मैं जनता विरोधी तथा अमेरिकी दबाव में लिए गए खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय शीघ्र ही वापस लेने हेतु आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. काकोली घोष दस्तिदार** (बारासात) : मैं इस देश के सभी छोटे व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों तथा किसानों और कृषि भूमि तथा कृषि भूमि पर कार्य करने वाले श्रमिकों के समर्थन में आवाज उठाते हुए खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव को वापिस लेने की मांग करता हूं जो कि व्यापारी के रूप में छिपी विदेशी शक्तियों को आसानी से हमारी अर्थव्यवस्था नियंत्रण सौंपने की एक चाल है। खुदरा बाजार के प्रति वर्ष 8-10 प्रतिशत से बढ़ने की संभावना है और जल्द में ही यह लगभग 600 मिलियन डॉलर के टर्नओवर पर पहुंच जाएगा। इस बाजार को भारत के मेहनती लोगों द्वारा विकसित किया गया है और सरकार अभी तक इसके प्रति उदासीन रही है। मैं नार्थ-वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, अमेरीका के आर.के. स्वामीहंस को उद्धृद करता हूं ''खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई., भारत में मुसलमानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा।'' भारत में 7वीं सदी ईसवी, से मुस्लिम शासन के प्रारंभ से यह समुदाय व्यापार में लगा हुआ है। मसाले ईत्र, रेशम और हस्तशिल्प को बेच कर उन्होंने देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित है। सच्चर समिति की रिपोर्ट दर्शाती है कि 17 प्रतिशत मुस्लिम अभी भी खुदरा व्यापार से संबद्ध हैं जबकि केवल 8 प्रतिशत हिन्दू और 10 प्रतिशत अन्य समुदाय खुदरा व्यापार से संबद्ध है। व्यापार और परिवहन में 6 प्रतिशत मुस्लिम और केवल 4 प्रतिशत हिंदू शामिल है। इस प्रकार, 16 मिलियन लोग इसमें शामिल है जो खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. से प्रभावित होंगे।

महोदया, हमारे किसान अपने माथे से पसीना पोंछते हुए, तथा खेतों में अपना खून बहाते हुए अकेले ही जुताई, बुआई, फसल उगाना तथा कटाई करते हैं। सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था करने में कोई अधिक सहायता नहीं की है, उच्च उत्पादन वाले बीजों को देने के लिए ''कृषि अनुसंधान'' में सहायता नहीं है और न ही सरकार ने प्रभावी रूप से आधारभूत ढांचा और भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था की है। ऊर्वरक कंपनियों बंद पड़ी रहती है और सरकारी की उन्हें पुन: खोलने की इच्छा है। आयातित यूरिया को खरीदना किसानों के लिए ''कृषि अनुसंधान'' में सहायता नहीं की है और न ही सरकार ने प्रभावी रूप से आधारभूत ढांचा और भंडारणन सुविधाओं की व्यवस्था की है। ऊर्वरक कंपनियों बंद पड़ी रहती है और सरकार की उन्हें पुन: खोलने की इच्छा नहीं है। आयातित यूरिया को खरीदना किसानों के लिए लगभग असंभव हो रहा है। कोई और नहीं बल्कि वर्तमान कृषि मंत्री का ही सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य है कि ''आर्थिक सहायता को बढ़ाते रहना संभव नहीं है, किसानों को जैव-उत्पादों के विकल्प को चुनना चाहिए।'' चलिए ऐसा ही सही, पर क्या सरकार ऐसी तकनीकों हेतु किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई पहल कर रही है? जी, नहीं। पर दूसरी ओर किसानों के उत्पादन को विदेशियों का बोल कर व्यापारियों कोक दिया जा रहा है जो फिर से 1947 के पूर्व के समान ही व्यापार के माध्यम से फिर भी हमारी संप्रभु प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करेंगे। यह घोर संकट का समय है। राष्ट्र खतरे में है। हमारे खुदरा व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों की जिंदगी तथा उनकी आजीविका खतरे में है। गरीबों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को बचाने के लिए इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाना चाहिए।

***श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम) : मैं खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने के सरकार के निर्णय से सहमत नहीं हूं। मैं सरकार से अपना निर्णय वापस लेने का पुरजोर अनुरोध करता हूं। उद्योग और वाणिज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के कारण विदेशी पहले ही अपना प्रभुत्व जमाने और शोषण करने में लिप्त हैं। इस तरह भारत फिर से एक औपनिवर्ग, राष्ट्र बनता जा रहा है। छोटे और बड़े व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हैं। अब खुदरा खेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने से करोड़ों छोटे व्यापारी और बुरी तरह से प्रभावित होंगे। पूंजीवाद का बोलबाला होगा। भारत में पैदा होने वाले उत्पाद और उनके स्थानीय बाजार नष्ट हो जाएंगे। यह एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण करेगा जो धीरे-धीरे हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को विनाश की ओर ले जाएगा। अत: मैं इस कदम का सख्त विरोध करता हूं।

यह तर्क दिया जा रहा है कि वॉलमार्ट, केअरफार और टेस्को जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) को खुदरा क्षेत्र में निवेश

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: तमिल में सभा पटल रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातंर।

करने की अनुमति देकर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह स्वीकार्य तर्क नहीं है। वॉलमार्ट एक अमेरिकी कंपनी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से ही बेराजगारी की समस्या है। अर्थशास्त्रियों ने मीडिया में बताया है कि वर्ष 2001 से 2007 तक यू.एस.ए. में 40,000 औद्योगिक प्रतिष्ठन बंद हो चुके हैं और इस कारण, लाखों लोगों ने अपनी नौंकरी खो चुके हैं और बेरोजगार हो चुके हैं।

यह पता चला है कि बिल्कुल हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा अपने बच्चों को ताहफे के रूप में देने के लिए कुछ किताबे खरीदन एक छोटी सी किताबों की दुकान पर गए। 2010 से ही यू.एस.ए. प्रत्येक शनिवार को 'स्मॉल बिजनेस डे' के रूप में मना रहा है। इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बच्चों के साथ उस छोटी सी किताबें की दुकान गए थे जहां अमेरिकी सरकर स्वयं छोटे व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं को प्रोत्साहन देने और सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है वही' भारतीय सरकार अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट को भारत में आने की अनुमति देकर छोटे व्यापारियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यह बहुत खतरनाक है।

मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को अनुमति देने के अपने निर्णय की समीक्षा करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उसे बीमा और पेंशन क्षेत्रों में एफ.डी.आई. की अनुमति देने का अपना निर्णय वापस लेना चाहिए।

***श्री सानछुमा खुंगुर बेसीमुथियारी** (कोकराझार) : आपके सुझाव की प्रतिक्रिया में मैं देश में बहु ब्राण्ड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. खोलने के लिए केन्द्र की यूपीय-दो सरकार की नीति पर विचार और स्वीकृति के विरूद्ध विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा मैं अपना भाषण, सभा पटल पर रखता हूं जिसे बोला हुआ माना जाए।

आई.एम.एफ. के अनुसार एफ.डी.आई. को एक ऐसे निवेश के रूप में पारिभाषित किया गया है जो कि निवेशक से अलग किसी अर्थव्यवस्था में संचालित उद्यम में एक दूरगामी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निवेशक का उद्देश्य होता है प्रबंधन उद्योग में प्रभावशाली होना।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एफ.डी.आई. का सार है मेज़बान देश को पूंजी, कार्यकुशलता और तकनीकी ज्ञान के एक पैकेज का हस्तांतरण। सामान्य रूप में एफ.डी.आई. एक विदेशी फर्म के प्रबंधन में सहभागिता के प्रबंधकीय नियंत्रण के उद्देश्य से और उत्पादक गतिविधि के उद्देश्य से किया जाने वाला लंबे समय का अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश है।

जैसे कि भारत में प्रतिबंधों के साथ खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. खोलने के बारे में अधिकांश सदस्य सहयोगियों ने चिताएं व्यक्त की हैं वैसी ही चिंताएं और कारण मेरे भी हैं।

पहली चिंता है बड़ी विदेशी कंपनियों का रोज़गार पर पड़ने वाला प्रभाव।

2007-08 में कृषि के पश्चात् खुदरा क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।

खुदरा क्षेत्र कुल कार्यशक्ति का 7.2% प्रतिशत नियोजित करता है जिससे 2010 की रिपोर्ट के अनुसार 33.10 मिलियन रोजगार हुए।

दूसरी चिंता यह है कि एफ.डी.आई. गलत प्रतिस्पर्धा की ओर ले जा सकता है जो अंततः घरेलू खुदरा व्यापारियों विशेषकर छोटे पारिवारिक स्वामित्व वाले पदस्थ उद्योग की बड़े पैमाने पर निकासी में परिजत होगा। क्योंकि खुदरा क्षेत्र का अनियोजित घटक एक बड़ा मुद्दा है।

इसके अतिरिक्त मैं गंभीर सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय महत्व के निम्न मुद्दों को ध्यान में रखे बिना बहु ब्राण्ड व्यापार में एफ.डी.आई. पर नीति के कार्यान्वियन से करोड़ों भारतीय लोगों अधिकांशतः युवाओं और छोटे दुकानदारों, सड़क विक्रेता आदि के नौकरी खोने की संभांव्यता के बारे में भी चिंतित हूं

अतः महोदया मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बहु ब्राण्ड में एफ.डी.आई. के खतरों और हानियों से संबंधित निम्नलिखित मुद्दारें पर विचार किया जाए।

उत्पादों का 75% भाग एम.एन.सी. और टी.एन.सी. द्वारा उच्चतर उचित मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए

हथकरघा क्षेत्र, कुटीर उद्योगों, छोटे लघु उद्योग, हस्तशिल्पों के उत्पादों का 90% भाग उच्चतर सही कीमत पर खरीदा जाना चाहिए।

[श्री सानछुमा खुंगुर बेसीमुथियारी]

एम.एन.सी. और टी.एन.सी. के अंतर्गत 100% नौकरियां भारतीय लोगों मुख्यत: युवाओं और औरतों को दी जानी चाहिए।

लोगों के खेतों की मूल तथा प्राकृतिक उत्पादक क्षमता और गुणवत्ता की सुरक्षा व संरक्षण को खतरनाक रासायनिक खादों और कीटनाशकों आदि के अत्यधिक प्रयोग से एम.एन.सी.आर. टी.एन.सी. द्वारा विकास की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

एफ.डी.आई. का लाभ पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों जैसे कि हमारे बोडोलैंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूरे देश में सभी छठे और आठवें अनुसूचित क्षेत्रों को मिलना चाहिए।

भारत सरकार को हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित करने के लिए एफ.डी.आई. की सहायता पर ही निर्भर नहीं रहना चाहए, इसका कारण यह है कि एफ.डी.आई. ही सभी क्षेत्रों में भारत की प्रगति और विकास के पीछे नहीं है और नहीं होगा।

केन्द्र को अपनी निधि से पूरे देश में सभी पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों जैसे कि बोडोलैंड क्षेत्रफल, पूर्वोत्तरी क्षेत्र और पांचवें व छठे अनुसूचित क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

स्वदेशी आदिवासी लोगों के परंपरागत हैडलूम और बुनकर क्षेत्रों और संस्कृतियों जैसे कि बोडो जनजाति और अन्यों को विशाल एम. एन.सी. और टी.एन.सी. जो एफ.डी.आई. के मार्ग से भारत में आने वाले हैं वे राक्षस जैसे भयानक जबड़ों बचाने और सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

***डॉ. तरुण मंडल** (जयनगर) : मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा खुदरा व्यापार क्षेत्र में 51% एफ.डी.आई. के विरुद्ध लाए गए संकल्प का समर्थन करता हूं और प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत फेमा में संशोधन का भी समर्थन करता हूं। केवल 51% ही नहीं, मैं भारत में 'मल्टीब्रांड' करता और 'सिंगल ब्रांड' खुदरा क्षेत्र में एफ. डी.आई. के प्रवेश के ही पूर्णत: विरुद्ध हूं। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी भी अन्य क्षेत्र यथा अवसंरचना, विनिर्माण, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि आदि जैसी सेवाओं में भी एफ.डी.आई. के प्रवेश के विरुद्ध हूं। मैं सामान्य, कृषि और वाणिज्यिक बजटों तथा वित्त विधेयक, 2012 पर भी अपनी पूर्ववर्ती चर्चाओं में बार-बार एफ.डी.आई. के प्रवेश का विरोध कर चुका हूं। एफ.डी.आई. वैश्वीकरण और उदारीकरण नीतियों का सीधा परिणाम है जो कांग्रेस (आई) सरकार के शासन के दौरान 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डा. मनमोहन सिंह ने लागू की थी। भारत में एफ.डी.आई. की अनुमति और विदेशी पूंजी को राष्ट्रीय पूंजी मानना डब्ल्यू.टी. ओ. और जी.ए.टी.टी. की बाध्यता है। अत:, भाजपा, सी.पी.एम. और ऐसे ही अन्य दल जो खुदरा व्यापार में 51% प्रतिश एफ.डी.आई. की अनुमति का विरोध करने वाले दल वस्तुत: लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बल्कि भाजपा, ए.आई.टी.सी., बीजद जैसे दल अन्य क्षेत्रों में एफ.डी.आई. के पक्ष में हैं। इसके अलावा, जब वे उनके द्वारा शामिल राज्यों में सत्ता में थे तब उन्होंने यादृच्छिक रूप से एफ.डी.आई. को आमंत्रित किया है और वैश्वीकरण-उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। यह सत्य है कि जब 2004 में भाजपा ने खुदरा क्षेत्र में 26% एफ.डी.आई. लाने का प्रयास किया तब कांग्रेस (आई.) ने विरोध किया था। माननीय सी.पी.आई. (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने स्वीकार किया है कि इस एक ध्रुवीय विश्व में वैश्वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण केवल विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और रोजगार में सहायता के लिए आवश्यक है जैसा कि माननीय कपिल सिब्बल जी ने अपने भाषण में इंगित किया है। सी.पी.आई. (एम) द्वारा विगत में शासित पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में उन्होंने निजीकरण, वाणिज्यीकरण किया और हमारे लोगों के शोषण के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया। अब राजग के नेता के रूप में भाजपा खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. का विरोध कर रही है और कांग्रेस (आई) इसे लागू करने का प्रयास कर रही है। आम आदमी के चिंतक के रूप में ये विरोधी तेवर केवल सत्ता आने के लिए हैं जैसा कि कांग्रेस (आई) ने उस समय किया था जब वह विपक्ष में थे। ये सभी दल मृतप्राय: पूंजीवाद को बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

जब एफ.डी.आई. को चुनने का अधिकार राज्यों को हैं तो केन्द्र सरकार इसे देश में लागू करने के लिए इतनी आतुर क्यों है? राज्य को ही निर्णय लेने दें कि वह एफ.डी.आई. किसके पक्ष में है- हमारे 120 करोड़ आम आदमियों के पक्ष में अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कार्पोरेट घरानों, पूंजीवादियों और साम्राज्यवादियों के पक्ष में है? भारतीय एकाधिकारवादी पूंजीवादी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अत्यधिक लाभ कमाने और हमारे गरीब लोगों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के शोषण के लिए मिलीभग कर रही है। भारतीय पूंजीवादी भी यूरोप और अमरीका सहित विदेशी लोगों का शोषण कर रहे हैं और बदले में विदेशी पूंजीवादियों को हमारे नागरिकों को शोषण की अनुमति दे रहे हैं। इसी कांग्रेस (आई) के नेतृत्ववाली सरकार ने 1991 में सुधारों की पहली पारी बताते हुए कहा था कि इससे रोजगार सृजन होगा, राष्ट्र का विकास होगा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि और किसानों की समृद्धि होगी। 1991 के सुधारवादी उपायों के फलस्वरूप आज हम क्या देख रहे हैं? भुखमरी, भूख, किसानों द्वारा आत्महत्या, बेरोजगारी में वृद्धि, देश मे अमीर गरीब के बीच खाई में वृद्धि और देश के मुट्ठी भर पूंजीवादियों द्वारा अथाह पूंजी का संचय। मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी के कारण लोग अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कृषि उत्पादों की वृद्धि और निर्यात में कमी आई है। अर्थव्यवस्था में दो अंकों की अनुमानित वृद्धि घटकर 5.5 से 6% रह गई है जैसा कि श्री पी. चिदंबरम ने हाल ही में कहा है। पुन: संप्रग-II सुधारों की दूसरी पारी का गुणगान कर रही है। यह भयावह है और राष्ट्रीय तथा बहुरारष्ट्रीय पूंजीवादी भारतीयों का निर्मम शोषण करेंगे। राष्ट्र को बचाने के लिए, हमारे आम लोगों को बचाने के लिए, भारत के लोगों को पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करना चाहिए।

एफ.डी.आई. से वालमार्ट, ट्रेस्को, मेट्रो कैश एंड कैरी जैसी बड़ी कंपनियां आएंगी जिनकी विशाल पूंजी हमारे खुदरा व्यापारियों को निगल जाएगी, हमारे किसानों को बर्बाद कर देंगी। इस प्रकार, इससे रोजगार सृजन नहीं होगा। बल्कि इससे खुदरा व्यापार और खेती में लगे हमारे 18 से 19 करोड़ परिवार बर्बाद हो जाएंगे। सभी व्यापार नीतियों की भांति-कुछ वर्ष तक वे स्थानीय बाजार की तुलना में कुछ बेहतर भाव देकर हमारे किसानों को खुश करेंगे और अपने भंडारों से बाजार की तुलना में कुछ कम मूल्यों पर उत्पाद बेचेंगे। लेकिन स्थानीय बाजार को बर्बाद करने के पश्चात, कुछ ही वर्ष में वे हमारे किसानों और उपभोक्ताओं के साथ मनमाना व्यवहार करेंगे और तब हमारे किसानों अथवा नागरिकों को बचाने के लिए स्थानीय बाजार अथवा खुदरा व्यापार नहीं होगा। इस प्रकार हमारे नागरिक, बेरोजगार लोग और किसान, किसी को भी फायदा नहीं होगा। केवल बड़े व्यवसायी ही लाभान्वित होंगे जो उनके भागीदार होंगे अथवा अपना व्यवसाय चलाने के लिए बिचौलिए बन जाएंगे। यदि सरकार यह जानती है कि बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं तो वह कार्यवाही क्यों नहीं करती। हमारे किसानों की सहायता का एकमात्र तरीका यही है कि खाद्य वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं का समूचा व्यापार राज्य ही करे। अर्थात सरकार सीधे किसानों से लाभकारी मूल्यों पर खरीद करे और निश्चित मूल्यों वाली दुकानों के माध्यम से बिक्री करे न जमाखोरी न कालाबाजारी। दुनिया भर में, यहां तक कि यूरोपीय देशों और अमरीका में भी, एफ.डी. आई. का विरोध हो रहा है। सरकार को वहां से सीख लेनी चाहिए जहां एफ.डी.आई. बहुत पहले लागू किया गया था।

आज सोशालिस्ट यूनिटी सेन्टर आफ इंडिया (साम्यवादी) दिल्ली राज्य ने एफ.डी.आई. सहित सरकारी की पूंजीवाद समर्थक नीतियों के विरूद्ध एक विशाल विरोध रैली आयोजित की और दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। सभी दल यदि वे वास्तव में एफ. डी.आई. और कांग्रेस (आई) से लड़ना चाहते हैं तो वे लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरें।

***श्री पी.सी. मोहन** (बंगलौर मध्य) : दिनांक 12.12.11 को तारांकित प्रश्न सं. 260 उत्तर देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि ''सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकार के माध्यम से 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति देने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। तथापि, विभिन्न हितधारकों के मध्य एक व्यापक सहमति बनाने के लिए इस आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।''

इससे पहले 7 दिसम्बर, 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी सदन में उक्त आश्य का एक वक्तव्य दिया था कि राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और राजनैतिक दलों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से सहमति बनाने एक मल्टीब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति देने के निर्णय को स्थगित रखा गया है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्रीयों को शामिल किए बिना इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता।

इन सब आश्वासनों के बाद भी, सरकार ने उनका उल्लंघन किया है और मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफ.डी. आई. की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसी भी प्रकार से किसानों और व्यापारियों को फायदा नहीं होगा।

जब वालमार्ट आदि जैसी अरबों/खरबों रूपए वाली कंपनियां समूचे देश में अपने बड़े मॉल स्थापित करने लगेंगी तो देश भर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.सी. मोहन]

में छोटे व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। लाखों व्यापारी और ऐसी दुकानों में काम कर रहे करोड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे जिसके चलते इन करोड़ों लोगों के परिवारों को अपनी गुजर-बसर के लिए भीख मांगनी पड़ेगी।

ये बड़े व्यापारी किसानों का शोषण करेंगे क्योंकि वे अपनी शर्तों पर काम करेंगे तथा किसानों को उनकी शर्तें माननी पड़ेगीं वे यह भी तय करेंगे कि क्या बोया जाए, कब बोया जाए तथा किस प्रकार कटाई की जाए। किसानों को यह निर्णय ऐसी कंपनियों के निर्देशों के अनुसार लेने पड़ेगे। इससे अमेरीकियों तथा अन्य देशों या चीन के किसानों को मदद मिलेगी जहां से कृषि उत्पादों को भारत लाया जाएगा।

जैसा कि कई वक्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है, यदि इस निर्णय को लागू किया जाता है तो इससे कृषि तथा व्यापार दोनों क्षेत्रों में काफी सारा श्रमिक बल विस्थापित हो जाएगा।

वालमार्ट जैसी कंपनियों के प्रवेश से हजारों लघु उद्योग बंद हो जाएंगे जिससे ऐसे उद्यमों में कार्य कर रहे अनगिनत लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अपनी आय तथा आजीविका से वंचित हो जाएंगे।

जहां एन.डी.ए., वामपंथियों और अन्य दलों सहित सभी विपक्षी दल मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, सरकार जिन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है उनकी भावनाओं पर उसे ध्यान देना चाहिए और इस निर्णय को तत्काल वापिस लेते हुए, 7 दिसम्बर, 2011 को दिए गए अपने आश्वासन के अनुसार आगे बढ़ने से पूर्व सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके एक सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह** (टिहरी गढ़वाल) : मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन करती हूं कि मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस लें। क्योंकि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेशमसें 3.3 करोड़ लोगों की आजीविका प्रभावित करेर्गी। इससे किसानों का जीवन बहुत प्रभावित होगा। देश में वॉलमार्ट जैसी बड़ी विदेशी कंपनी के आने से छोटे-छोटे खुदरा व्यापारी प्रभावित होंगे और इससे छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से ये कंपनियां पहले सस्ता सामान बेचकर छोटे व्यापारियों को बर्बाद करेंगी। उसके बाद रिटेलर अपना दाम बड़ा देते हैं। एक समय अंग्रेज भी व्यापारी बन कर ही आए थे। उस समय तो बादशाह थे, और आज हमारी चुनी हुई सरकार ही हमें आर्थिक तौर पर विदेशी निवेश के नाम पर बेकार और गुलाम बनाने का दरवाजा खोल रही है। खुदरा क्षेत्र में निवेश से हमारी आर्थिक स्थिति भी अमेरिका और यूरोप जैसी हो जाएगी। हमारे छोटे-छोटे व्यापारी और किसान विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। छोटे व्यापारियों का रोजगार पूरी तरह से उजड़ जाएगा। बरसों से एक ही व्यापार कर रहे लोगों का रोजगार छूट जाएगा तो वह दूसरा काम भी नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे दूसरे काम करने का कोई अनुभव नहीं होगा। सरकार कितना भी दावा करें, लेकिन एफडीआई से किसानों तथा उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुनाफा विदेशी कंपनी डकार जाएगी, सरकार अच्छे भाव मिलने का किसानों को सब्जबाग दिखा रही है, वह पूरी तरह गलत है। देश का किसान अभी आत्महत्या कर रहे हें बाद में खुदरा व्यापार के कारण आत्महत्या को मजबूर होंगे। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए खुदरा व्यापार में विदेशी नि वेश पर रोक लगाई जाए।

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज) : आज जब संपूर्ण दुनिया वैश्विक मंदीकरण के दौर से गुजर रही है तो क्या कोई देश बिना निवेश के प्रगति कर सकता है। अत: किसी देश का अपनी विकास दर एवं प्रगति बढ़ानी है तो उस देश को 'डोमेस्टिक एंड फॉरेन इनवेस्टमेंट' लाने के लिए सा र्थक उपाय करना पड़ेगा। पहले तो हमें जानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में एफ.डी.आई. की जरूरत क्यों पड़ती है। एफ.डी.आई. से क्या-क्या फायदा होगा। आज केंद्र की कांग्रेस सरकार ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश 51 प्रतिशत लाने का निर्णय किया है तो इससे एक तरफ देश के किसानों को फायदा होगा वहीं दूसरी तरफ देश के आम उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। इसके लागू होने से कम से कम उपभोक्ताओं को 15 से 20 प्रतिशत का फायदा होगा। आज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत के कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा एवं अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इससे कृषि उत्पाद की सुरक्षा के लिए विदेशी पूंजी निवेश खुदरा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन एवं वेयर हाउसिंग आदि का निर्माण होगा। आज भारत में खुदरा क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ लोग लगे हैं। भारत में खुदरा व्यापार का विशाल क्षेत्र है। आज खुदरा व्यापार 350 अरब डालर से अधिक भारत में हो रहा है। भारतीय खुदरा बाजार में असंगठित 95 प्रतिशत केवल 5 प्रतिशत ही संगठित क्षेत्र में है। भारत में खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश से 'शॉपिंग हब' बनेगा। खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. से पहले सिंगल ब्रांड में एफ.डी.आई.की अनुमति दी जा चुकी है। जिससे भारत में दूरसंचार, वाहन, बीमा क्षेत्र एवं नागरिक उड्डयन एवं ऊर्जा में काफी कामयाबी मिल चुकी है। थोक व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश से भारत काफी प्रगति कर चुका है।

भारत सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेशे में 51 प्रतिशत की इजाजत दी है तथा राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ा है कि यदि कोई राज्य नहीं लागू करना चाहता है तो राज्य न लागू करे। लेकिन कोई भी राज्य जो खुदरा क्षेत्र में निवेश किसानों के हित में लागू करने का निर्णय करना चाहते हैं। उन्हें विपक्ष क्यों रोकने का प्रयास कर रही है। आज भारत सरकार ने एफ.डी.आई. का 'मल्टी ब्रांड रिटेल' में 51 प्रतिशत लागू किया है। जो देश के 53 शहरों में लागू होगा, जिस शहर की आबादी 10 लाख होगी। आज इस निर्णय के पीछे इसलिए आवश्यकता है क्योंकि भारत में प्रत्येक वर्ष 50 हजार करोड़ का नुकसान होता है। हर साल अनाज के उत्पादन का 10 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। 15 प्रतिशत दालें, 30 प्रतिशत फल और सब्जियों का नुकसान हो जाता है। 40 प्रतिशत फ्लोरीकल्चर के उत्पाद का भी नुकसान होता है। जबकि इस क्षेत्र में कुल निवेश का 50 प्रतिशत बुनियादी ढांचे में खर्च होगा। क्योंकि खुदरा क्ष्ज्ञे का 70 फीसदी कारोबार खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बावजूद उनके ऊपर प्रतिबंध होगा कि वे कम से कम 30 फीसदी भारत के ही लघु, छोटे और मझोले उद्योगों से खरीदना होगा। जो भी विदेशी पूंजी निवेश भारत में करेगा उसे 50 प्रतिशत विदेश बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवश्य करना होगा। इससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा तथा कोल्ड चेन कैपसिटी में सुधार होगा। इससे अलग तीन साल में एक करोड़ रोजगार बढ़ेगा। गुणवत्ता में सुधार होगा, स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी। आज भारत में किसानों को नासिक में प्याज का उत्पादन मूल्य 2 रूपया प्रति किलो पाता है और जब वही प्याज दिल्ली के आजादपुर मंडल में आता है तो वह 25 रूपया मिलो बिकता है। आखिर इतने बड़े अंतर का फायदा किसको मिलता है। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन एफ.डी.आई. इन रिटेल के आने से किसानों को सीधा लाभप्रद मूल्य मिलेगा। नाबार्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर सीधे किसान से खरीद की जाती है तो 7 से 17 फीसदी तक के नुकसान को कम किया जा सकता है। क्योंकि किसान के पास न तो स्टोरेज की क्षमता है और न परिवहन का खर्च उनके पास है। आज राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की स्थिति निम्न है। स्वरोजगार 51 प्रतिशत कैजुअल लेबर 33.5 प्रतिशत तथा वेतनभोगी या रेगुलर वेज 15.6 प्रतिशत क्षेत्र में है। इसके लागू होने के बाद देश में 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तथा अप्रत्यक्ष रोजगार से 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसा नहीं, ये निर्णय भारत में कांग्रेस की सरकार सबसे पहले खुदरा क्षेत्र में पूंजी निवेश की इजाजत दे रही है। जबकि 1992 में चायना 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश खुदरा क्षेत्र में इजाजत दे चुकी है। चायना के साथ-साथ थाईलैंड, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया में 100 प्रतिशत विदेशी पूजी निवेश का निर्णय खुदरा क्षेत्रों में कर चुकी है। यहां तक कि ब्राजील, अर्जेंटीना, सिंगापुर एवं चिली में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. इन रिटेल सेक्टर पहले से ही है। अगर इन देशों के बाद भारत में 51 प्रतिशत खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय लिया गया है तो इससे देश में फूड प्रोसेसिंग, खाद्यान्न एवं सामानों की गुणवत्ता, रोजगार में वृद्धि तथा बुनियादी ढांचा में 51 प्रतिशत का पूंजी निवेश होगा। इसके बावजूद भाजपा एवं विपक्ष के लोग हमारे इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं जबकि 2004 में बीजेपी एवं एनडीए के घोषणा-पत्र में यह शामिल किया था कि खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई इन रिटेल सत्ता में लाएंगे। अब जब आपकी पार्टी ने इसे सन् 2002 एवं 2004 के चुनाव घोषणा-पत्र में बीजेपी ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश लाने का प्रस्ताव किया था। आज भाजपा के लोगों का क्यों हृदय परिवर्तन हो गया है। इस पर देश के लोग भाजपा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होंगे कि बीजेपी की कथनी एवं करनी में काफी फर्क है। इसी लिए बीजेपी आज जनता के समक्ष बेनकाब हो चुकी है। मैं बीजेपी के साथियों से कहना चाहूंगा, एक शेर के माध्यम से–

[श्री जगदम्बिका पाल]

'वो जिन्होंने रौंद डाले सारे के सारे चमन।
आज दम भर रहे हैं, अपनी आसनाई का।'

भाजपा को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि आज देश में 240 मिलियन वेजिटेबल्स पैदा किया कर रहा है जिसका 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष सब्जियों का नुकसान हो जाता है। एफ.डी. आई. इस रिटेल में आने से 50 प्रतिशत पैसा बुनियादी ढांचे में खर्च होगा। जिससे खाद्यान्न की बर्बादी रुकेगी तथा कोल्ड चेन्स से वेजिटेबल्स एवं फलों की सुरक्षा हो सकेगी। भाजपा के मित्र जान लें कि ये फील गुढ एवं इंडिया शायनिंग का नारा नहीं है, जो उड़ गया। कांग्रेस सही मायने में हम भारत निर्माण की गाथा लिख रहे हैं, सुषमा जी, आप लिख लीजिए कि हमारी भारत निर्माण की इस गाथा में देश की जनता हमारे साथ है जिसका परिणाम 2014 में फिर कांग्रेस के पक्ष में आएगा। भाजपा के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारी नीतियों के कारण ही सन् 2004 एवं 2009 में जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था।

हमारी सरकार ने सदन में आश्वासन के मुताबिक सभी स्टोकहोल्डर्स से बात करके खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के निर्णय का क्रियान्वयन किया है। चाहे राजनैतिक दल, मुख्यमंत्री, किसानों के संगठन, फल एवं सब्जियों के संगठन आदि सभी से बात करके हमारी सरकार ने इसे लागू किया है। आज भारत में फूड प्रोसेसिंग केवल 2 प्रतिशत है जबकि दुनिया के तमाम देशों में 98 प्रतिशत आस्ट्रेलिया, फिलीपिन्स एवं यूएसए में हो रहा है। अत: मैं कहना चाहूंगा कि सुषमा जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें तथा एक मजबूत भारत को बनाने में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इसमें साथ दें जिससे भारत एक नए युग में प्रवेश कर सके।

***श्री राजेन्द्र अग्रवाल** (मेरठ) : मैं नेता प्रतिप्रक्ष, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सरकार के निर्णय को वापिस लेने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दो दिन तक चली चर्चा में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा एफ. डी.आई. के संबंध में प्राय: सभी पहलुओं पर विचार रखे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का निर्णय यदि हो गया तथा एक बार यदि वालमार्ट सरीखे रिटेल स्टोर देश में आ गए तथा बाद में देश का अनुभव ऐसा ही आया जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तथा इस प्रस्ताव के समर्थन में विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है, अर्थात् बेरोजगारी बढ़ी, तब उसका क्या हल निकाला जा सकेगा।

खुदरा व्यापार में लगे जिन पांच करोड़ लोगों की रोजी समाप्त होगी उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? इस निर्णय के परिणाम दूरगामी हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई तो वालमार्ट आदि से कैसे मुक्ति पाएंगे? क्या फिर से आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी? मेरा निवेदन है कि इस निर्णय को निरस्त किया जाए। यदि सरकार इसे आवश्यक ही समझती है तो अभी इस पर और अधिक विचार करे, ऐसा न हो कि करोड़ों के भविष्य को संकट में डालने का अपराध यह सरकार कर बैठे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो दिनों से इस सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय, जो अहम चर्चा का है, उस पर चर्चा हो रही है। उसके लिए प्रस्ताव प्रतिपक्ष की सम्माननीय नेता सुषमा स्वराज जी और दूसरे राजनैतिक दलों के द्वारा आया।

प्रश्न यह है कि सदन में चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखें,देश की जनता जान ले कि किसकी सोच क्या है, किसकी समझ क्या है। यही हमारे प्रजातंत्र का सही मायने में शक्ति है। बातें होती हैं, बहस भी होती है विचारधाराएं अलग हैं, नीति अलग है, कुछ बातें इन्होंने भी कहीं, कुछ खट्टी थीं, कुछ मीठी थीं, कुछ तीखी थीं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा एक ही निवेदन है कि हम भी अपनी बात कहेंगे, जिसमें कटुता नहीं होगी, सच्चाई होगी, प्रयास होगा कि तथ्यों को इस माननीय सदन के सामने रखूं, इसीलिए मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष को सुना, जोशी जी को सुना, बसुदेव आचार्य जी को सुना, मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, सब को सुना, सब माननीय नेतागण उसमें शामिल हैं। मैंने अपने सहयोगियों को भी सुना। कलिप सिब्बल जी को सुना, बहुजन समाज पार्टी के दारा सिं जी को सुना और हमारे नौजवान साथी दीपेन्द्र हुड्डा जी अभी बोले, प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बहुत अच्छा बोले, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। मुझे अब यही बात कहनी है कि यह जो निर्णय हुआ है, यह रातों-रात हुआ निर्णय नहीं है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह वर्षों से देश में चर्चा का विषय रहा है। इसकी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। हमारे दो मत हो सकते हैं। पृष्ठभूमि यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है, अपना परिवार चलाने के लिए, पोषण के लिए, आमदनी के लिए हमारा किसान मेहनत करता है। हम सब इस बात को समझते हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। दुनिया में खाद्यान्न के उत्पादन में भारत का दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा है भारत का फल और सब्जी के उत्पादन में, पहला दर्जा है भारत का दूध के उत्पादन में, यह एक वास्तविकता है और यह इस देश की शक्ति भी है। पर यह भी एक वास्तविकता है कि हमारे पास जो फूड की मैनेजमेंट होनी चाहिए, फसल पैदा होने के बाद जो नुकसान होता है, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा आंकड़े दिए गए, मैंने तुरंत पता कराया। कृषि मंत्री जी जो किसान की नब्ज को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, उनसे भी मैंने सलाह-मशविरा किया। मेरे पास वर्ष 2011 के आंकड़े हैं, जो मैं माननीय जोशी जी को भेजूंगा और सभा पटल पर रखूंगा। जो फल और सब्जी है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इस देश के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कमी है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षा जी, जो आंकड़े हैं, वे तीस और पैंतीस प्रतिशत के बीच में हैं। केवल फल-सब्जी खाद्यान्न के नुकसान से लगभग साठ से पैंसठ हजार करोड़ रुपए साल का किसान का नुकसान होता है। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है। यह आंकड़ा वर्ष 2012 में छपा है कि भारत के किसान की जो प्राइस रियिलाइजेशन है, वह 11 और 15 प्रतिशत के बीच में है। इसलिए आपकी सरकार में भी और हमारी सरकार में भी यह चर्चा हुई। यह बात माननीय सदस्यों ने रखी, नेता प्रतिपक्ष ने भी रखी। किसकी सोच क्या थी? आपकी भी सोच थी, जब आप उस समय इधर थे, हमारी भी ऐसी सोच थी। यह सही कहा कि परिस्थितियां देखते हुए रायशुमारी करते हुए, राजनैतिक दल अपनी बात में कई बार संशेधन भी कर लेते हैं। जब बड़ा संशोधन हो तो प्रश्न भी उठता है। आपने हमसे ठीक प्रश्न किया। कपिल जी ने और हमारे साथियों ने जो प्रश्न उठाया, वह भी उचित प्रश्न था, क्योंकि हमारा जो विषय था, उस समय एक विपक्ष के रूप में था। हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनने के बाद इस विषय पर कभी अपने मैनीफेस्टो में विरोध नहीं किया, सदन में विरोध नहीं कया। आपको इसका अधिकार है। वर्ष 2002 में जो फैसला था, वह ऐसे अचानक नहीं हुआ था। वर्ष 2000 में देश में चर्चा शुरू हुई। उस समय का कैबिनेट का फैसला मैं आपके सामने रखूंगा। उस कैबिनेट के फैसले के तहत चर्चा शुरू हुई, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है, मुझे उसे कहने की अनुमति दें।

[अनुवाद]

> "मंत्रिमंडल द्वारा 1 फरवरी, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. सहित विद्यमान क्षेत्रक नीतियों की समीक्षा करने तथा आवश्यक परिवर्तनों पर निर्णय लेने के लिए एक मंत्रि-समूह का गठन किया गया जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, संचार मंत्री, रसायन और ऊर्वरक मंत्री, विदेश मंत्री और लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल है।"

यह निर्णय फरवरी, 2000 का था। यह नोट उस मंत्रि-समूह के लिए था जिसका गठन उक्त निर्णय के अनुसार किया गया था। मैंने मंत्रिमंडल के एक निर्णय से उद्धृत किया है। चूंकि सरकार की संपत्ति है, मैं इसे सदन के समक्ष रखूंगा। नवम्बर, 2001 में इसकी पहली बैठक हुई थी, मैं इसके ब्यौरे पर नहीं जाऊंगा परंतु उसके दो या तीन छोटे अंशों को पढ़ूंगा।

> "भारत में संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र देश की कुल खुदरा बिक्री का मात्र दो पप्रतिशत होता है जबकि इसकी तुलना में यह संयुक्त राज्य अमेरीका में 85 प्रतिशत, मलेशिया में 55 प्रतिशत थाइलैण्ड में 40 प्रतिशत ब्राजील में 36 प्रतिशत, चीन में 10 प्रतिशत है।"

फिर इसमें यह ब्यौरा दिया गया है कि यह किस प्रकार आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहायक होगा और इसमें क्या कठिनाइयां है। राष्ट्रीय संस्थानों और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कई अध्ययन रिपोर्टें है जिन्हें इस उद्धृत किया गया है। एक अन्य उद्धरण का उल्लेख संगत होगा-

> "कई देशों के कुल एफ.डी.आई. प्रवाह में खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. का एक बड़ा हिस्सा है।"

[श्री आनंद शर्मा]

देशों के नाम दिए गए है।

"भारतीय उपभोक्ता बाजार के आकार, 10 से 11 प्रतिशत जी. डी.पी. और खाद्य उद्योग के आकार को देखते हुए, खुदरा व्याार क्षेत्र अगले पांच वर्षों में आसानी से चार बिलियन लोगों को समाहित कर सकता है।"

इसमें यह भी कहा गया है कि खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफ. डी.आई. की मजबूत मौजूदगी अपस्ट्रीम क्रियाकलापों में भी एफ.डी. आई. को आकर्षित करने में एक प्रेरक बल के रूप में कार्य करेगी, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग उद्योगों में, क्योंकि कई बड़ी खुदरा शृंखलाएं पश्चगामी एकीकरण के माध्यम से अपने स्वयं के ब्रांडों को भी बढ़ावा देती है और यह भी कहा गया है कि इसीलिए खाद्य उद्योग में एफ.डी.आई. हेतु संभाव्यता काफी अधिक है; और खुदरा व्यापार क्षेत्र में वैश्विक निकायों का प्रवेश इस अंतर को काफी हद तक कम कर देगा।

इस नोट में कहा गया है कि इस देश में जब संगठित खुदरा व्यापार आया, जब मैकडोनाल्ड और केंटुकी फ्राइड चिकन को अनुमति दी गई थी तो देश में यह बहस हुई थी कि बीकानेरवाला का क्या होगा, हल्दीराम का क्या होगा, नाथू स्वीटस का क्या होगा, निरूलास का क्या होगा।

[हिन्दी]

मैंने अंग्रेजी में उस नोट का उल्लेख किया है उस समय भी यह चिंता का विषय उठा था और अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं। आपकी सरकार ने मसौदा तैयार करते हुए ध्यान रखा कि हल्दीराम और बीकानेर का क्या होगा? पर, यहां मैक्डोनाल्ड भी आ गया। अभी दीपेन्द्र भाई ने बताया कि वह भी आलू की टिक्की बनाने के लिए मजबूर हुआ। हिंदुस्तानियों का स्वाद अपना ही है। जैसा चटपटा खाने की आदत है, यह स्वाद तो कोई बाहर वाला नहीं देगा। हल्दीराम पूरी दुनिया में पहुंच गया है। यूरोप में इस के 34 स्टोर्स खुल गए हैं और उसके बाद 3 स्टोर्स लंदन में हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्षा जी, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं।...*(व्यवधान)* मेरे मित्र उत्तेजित न हों। मैंने एक सरकारी नोट, कैबिनेट को पढ़ कर बताया और उसका उल्लेख किया।...*(व्यवधान)* मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। दूसरा बीकानेर वाला एक हजार करोड़ रुपये का हो गया है। यह सौ करोड़ का था। आप बीकानेर वाले की साइट पर जाएं। इसके 85 स्टोर्स दुनिया में खुल गए हैं। अगर दूसरे देश के लोग यहां आए तो हमारे लोग भी बाहर गए। यहां से लोग बाहर गए और उन्होंने दुकानें खोली। आज अंग्रेज और अमेरीका के नागरिक हल्दीराम की चाट खाते हैं। बीकानेर वाले की चीज खाते हैं, नाथू की मिठाई खाते हैं।...*(व्यवधान)* आप क्यों आपत्ति करते हैं?

दूसरी बात, जो संगठित रिटेल है उसकी भी यहां चर्चा हुई कि संगठित रिटेल इस देश में कब आया?

श्री लालू प्रसाद : आजमगढ़ के मुस्तफा ने पूरा सिंगापुर कब्जा किया हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा : मुझे कहना है कि ये सारी बातें सोचकर आपने निर्णय किया था। आज मुझे मालूम हुआ कि वह निर्णय क्यों रुका। पहले हमारे मित्र पूर्व मंत्री, मेरे दशकों से जो सहयोगी रहे, बड़े दुख के साथ हम कहते हैं कि वे वर्षों से गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, दासमुंशी जी का जिक्र आया। इसी सदन में उस समय के राज्य सभा के माननीय नेता, प्रतिपक्ष और हमारे पंत प्रधान डॉ. मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य का जिक्र आया। मुझे कहना है कि उस समय इसलिए विरोध हुआ, क्योंकि आपने देश में किसी से चर्चा नहीं की थी—न किसान के संगठन से, न कन्ज्यूमर फोरम से, न छोटे लघु उद्योग से। वह सारी फाइल मैंने पढ़ी कि क्या कोई सलाह-मशविरा हुआ था। सलाह-मशविरा नहीं हुआ था। बिना सलाह-मशविरे के सौ फीसदी बिना किसी शर्त के लाना चाहते थे, इसलिए तब विरोध हुआ।...*(व्यवधान)*

आपने अपने मैनिफैस्टो में लिखा। आप कहते हैं, चलिए आपने अपना मन बदल लिया, जोशी जी ने भी कहा। अपना मन बदलना आपका अधिकार है। आप राजनीतिक दल हैं। आपने वर्ष 2004 में कहा कि हम 26 प्रतिशत करेंगे। शायद आपने देखा कि विरोध है, शायद आपने यह भी देखा कि जो आपके समर्थन का क्षेत्र है, वह भी इसके विरोध में है, तो आपने उसे सौ प्रतिशत से घटा दिया। उसके बाद विजन डॉक्यूमेंट में अलग बात हुई। आज

आप पूरी तरह से विरोध में है। यह आपका निर्णय है। हम आपके निर्णय से झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे एक चीज कहनी है। अगर आज आपको वह ज्ञान विपक्ष में रहकर मिला, जो दस साल पहले सत्ता पक्ष में नहीं था, तो यह देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आपने उस समय बड़े फैसले किए थे।... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : वाणिज्य मंत्री बार-बार जोर देकर जो बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ये यील्ड नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : नोट बनना एक बात है और फैसला करना दूसरी बात है। फैसला कब हुआ?...*(व्यवधान)* ये बता नहीं रहे हैं कि फैसला कब हुआ।...*(व्यवधान)* हमने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा : धन्यवाद। मैं यशवंत सिन्हा जी का सम्मान करता हूं। इन्होंने मुझे भी ज्ञान दिया कि इन्होंने विरोध किया। आज यही ज्ञान मुझे भाई शरद यादव जी ने दिया, डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने दिया कि इन्होंने कैबिनेट में उसका विरोध किया। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मगर उसके बाद भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा : मुझे एक चीज कहनी है कि कील नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही। मैं उसके विषय में बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। एक प्रश्न द्वारा गंभीर आरोप लगाया। 7 दिसम्बर, 2011 का हवाला दिया गया कि 7 दिसंबर, 2011 को उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया। उसे पढ़कर सुनाया गया कि सरकार अपने कैबिनेट को फैसले को सस्पैंड करती है। सबसे चर्चा करेगी, सब स्टेक होल्डर्स से चर्चा करेगी और स्टेक होल्डर्स में राज्य सरकार, राज्य राजनीतिक दल शामिल हैं। मेरे वक्तव्य का उल्लेख हुआ। मैंने राज्य सभा में यही वक्तव्य दिया। एक स्पष्टीकरण में मैंने कहा– *[अनुवाद]* परामर्श में राज्य सभी सम्मिलित है। बाहर नहीं किया गया है बल्कि राजनीतिक दलों को भी सम्मिलित किया गया है। *[हिन्दी]* मैं उस पर कायम हूं।

प्रश्न यह है कि कल सुषमा जी ने कहा कि उन्होंने आडवाणी जी से चर्चा की कि आपकी यादाश्त में पहले कभी देश में ऐसा हुआ कि सरकार ने सदन को आश्वासन देकर तोड़ा हो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपकी बात को मानता हूं। अगर यह बात सही है, तो सरकार पर बहुत गंभीर आरोप हैं। वास्तविकता क्या है? 7 दिसम्बर के बाद जो पहला फैसला था, वह चर्चा के बाद था। वह चर्चा, 6 जुलाई, 2010 को डिसकशन पेपर जब जारी हुआ, तब शुरू हुई। उसके बाद निर्णय कमेटी ऑफ सैक्रेट्रीज की सिफारिशों के बाद, जो सरकार के पास जुलाई 2011 से थीं और 24 नवम्बर, 2011 को यह फैसला हुआ था। 7 दिसंबर की बात है। 24 नवम्बर के निर्णयके बाद घोर विरोध हुआ, संसद बंद हुई। आपने ठीक कहा, सारे देश को मालूम है। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। मैंने हर राजनैतिक दल के नेता, जो दोनों सदनों में हैं, उनको पत्र लिखा।

मैं माननीय बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल उन्होंने स्वीकार किया कि वाणिज्य मंत्री ने तीन पेज की चिट्ठी लिखी। हमारी हर आपत्ति का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे नहीं माना। आपकी पार्टी के पोलित ब्यूरो ने फैसला कर दिया, प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, प्रधान मंत्री जी ने मेरे पास भेज दी। मैंने उसके बाद भी पत्र लिखकर आग्रह किया कि पुनर्विचार करें, लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है और वह आपको मुबारक है। हमारी वह सोच नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पत्र 27 नवम्बर को भेजा गया।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा : जी नहीं, मैंने बाद में पत्र भेजा था। महोदया मैं उनके साथ मामलों को मिलाना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, समाप्त नहीं कर रहे है। कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्षा जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 7 दिसंबर के बाद सरकार ने अधिकृत रूप में एक बार फिर किसानों के संगठनों से बात की—भारतीय किसान यूनियन, भारतीय कृषिक समाज, कॉन्फैडेरशन ऑफ इंडियन फार्मर एसोसिएशन, ऑल इंडिया फ्रूट इंडिया फ्रूट एंड वेजीटेबल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो पुणे बेस्ड संगठन है आदि 12 किसान संगठनों को बुलाया गया। उन्होंने जो कहा, वह लिखित में हमारे पास है। आज मैं सदन को वह मसौदा देने वाला हूं। उसके बाद दूसरा उपभोक्ता संगठन, फूड और कन्ज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, थामस जी यहां बैठे हैं, इन्होंने कन्ज्यूमर फोरम्स को देश के अलग-अलग हिस्सों से बुलाया। जो रिकोग्नाइज्ड कन्ज्यूमर के संगठन हैं, 17 संगठन आए। सरकार ने अपने खर्चे पर उन्हें बुलाया और विचार-विमर्श किया। किसानों के 12 संगठन और 17 कन्ज्यूमर के संगठनों ने इसके पक्ष में लिखकर दिया। उसके बाद देश की फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के 6 बड़े संगठन बुलाए गए। उन 6 संगठनों ने पक्ष में लिखकर दिया। अब प्रश्न यह है कि मैंने कोई कोताही की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैंने 7 दिसंबर के बाद हर सम्मानित मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा। सुषमा जी, आडवाणी जी आप बड़े हैं और जानते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों से कैसे चर्चा करती है। केंद्र सरकार के सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखते हैं। हमारे जो सैक्रेट्री डीआईपीपी हैं, उन्होंने इस साल जुलाई में भीतर के हर राज्य को लिखकर भेजा। उस पर 21 राज्यों ने अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 मुख्यमंत्रियों ने लिखित में अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेजी। अब प्रश्न यह है कि कितने पक्ष में हैं और कितने नहीं हैं। मैंने आपको संगठन बता दिए, किसान बता दिए, उपभोक्ता बता दिए। जो 21 जवाब आए, उन 21 में से 11 कृषि प्रधान राज्यों, बागवानी वाले राज्यों ने उसके पक्ष में पुरजोर मांग की और सात राज्यों ने विरोध किया। मुझे मालूम है कि यहां यह सवाल उठा और मैं जवाब दूंगा कि 11 और 7, लेकिन 11 बड़े होते हैं और 12 किसान के संगठन भी बड़े होते हैं, 17 कन्ज्यूमर फोरम्स भी बड़े होते हैं। स्मॉल और मिडियम इंटरप्राइसेज के सारे संगठन, स्टेक होल्डर्स में सब शामिल हैं।

कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लिखकर कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगे, वे तीन राज्य थे। अब सवाल यह था कि देश के अंदर एक संघीय प्रणाली है। मैं अगर चंडीगढ़ गया, तारीख सदन को दे देता हूं—जुलाई महीने में मैं माननीय प्रकाश सिंह बादल जी से मिला। उनका बड़ा सम्मान करता हूं, देश के बहुत बड़े लीडर हैं, वह मुख्यमंत्री हैं। भुवनेश्वर गया, स्वयं जाकर नवीन पटनायक जी से मिला, सही बात है कि उन्होंने इसके पक्ष में बात नहीं की। वह बड़े शालीन हैं। उन्होंने कहा कि आनंद जी, मैंनें लिखकर विरोध किया था, फिर भी जो आपने कहा है, हम एक बार फिर सोचेंगे। उनकी सोच नहीं बनी, उनका अधिकार है। मेरी नीतीश कुमार जी से लंबी बात हुई। बहन ममता जी से बात हुई। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया है। वह और मैं सहयोगी रहे हैं। आज से 27 वर्ष पहले जब मैं भातरीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। मैं खुद गया पश्चिम बंगाल। मैंने तीन बार उनसे बात की—एक बार बंगाल में और दो बार दिल्ली में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हमने कहा, हम आपका सम्मान करते हैं। इसलिए सोच-समझकर यह फैसला किया कि संघीय प्रणाली है, संवैधानिक परंपरा है, संविधान का सम्मान करते हुए, क्योंकि हर राज्य को बराबर अधिकार है, यह निर्णय लागू करना है या नहीं, यह राज्य की चुनी हुई सरकारों पर छोड़ दिया जाए। सरकार ने केवल उन 11 राज्यों के लिए नोटिफाई किया है, जहां की चुनी हुई सरकार इससे सहमत है। ठीक कहा दीपेन्द्र हुड्डा जी ने कि हरियाणा का फैसला वहां के मुख्यमंत्री करेंगे, आंध्र प्रदेश का फैसला वहां के मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार करेगी, जम्मू-कश्मीर का फैसला वहां के मुख्यमंत्री करेंगे, दिल्ली का फैसला वहां की मुख्यमंत्री करेंगी, महाराष्ट्र का फैसला वहां की सरकार करेगी। कोई एक चुनी हुई सरकार को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। हम किसी राज्य पर नहीं थोप रहे हैं। केंद्र की यह नीयत नहीं है।, हमने एक सहायक नीति दी है, वह भी जो 12 वर्ष की सारी चर्चा हुई, उसको बताते हुए दी है।

सुषमा जी, आपने कहा कि इसमें राजनीतिक दल शामिल हैं या नहीं, मैं कहूंगा हां, शामिल हैं। शायद आपको याद होगा कि सात दिसंबर के दिन आपकी पार्टी के माननीय अध्यक्ष गडकरी जी ने उस समय के वित्तमंत्री से बात की, उनके साथ लंच किया। *...(व्यवधान)* लंच के बाद उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू दिया, भारतीय

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से और उन्होंने कहा, वह बयान मेरे पास है, कि प्रणब जी से मेरी बात हुई, हमने स्पष्ट कर दिया। भातरीय जनता पार्टी की नीति है, हम इसके पक्ष में नहीं, विरोध में हैं। सीपीएम के पोलिट ब्यूरो की चिट्ठी बाद में प्रधानमंत्री को आई, जिसमें ए.बी.वर्धन जी के दस्तखत है और प्रकाश करात जी के भी दस्तखत हैं। वह चिट्ठी चार महीने पहले की है। सब वामपंथी दलों ने लिखकर भेजा। अब इन्होंने अपना निर्णय कर लिया, ये राजनीतिक दल हैं या नहीं हैं। ये कहते हैं कि चर्चा होती रहनी चाहिए, आखिर तक होनी चाहिए। मेरी इसमें थोड़ी असहमति थी, मैं बताऊंगा। अब कहा कि राजनीतिक दलों से चर्चा हुई या नहीं हुई। मैं प्रकाश सिंह बादल जी से मिला, पटनायक जी से मिला, वे लोग अपने-अपने दलों के अध्यक्ष हैं या नहीं, वे क्रमश: शिरोमणि अकाली दल और बीजू जनता दल के अध्यक्ष हैं। ममता जी तृणमूल कांग्रेस की हैं, नीतिश कुमार जी जेडीयू के लीडर हैं। अब अगर मैं टैक्नीकैलिटी में जाऊं, तो अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है कि *[अनुवाद]* जिद्दी की परिभाषा में यह आता है कि बार-बार वही काम करना और भिन्न परिणाम की अपेक्षा करना। *[हिन्दी]* अगर आप एक ही काम को बार-बार करते रहें और अलग नतीजे की अपेक्षा करें, तो आपका कहीं संतुलन गड़बड़ा गया है। आप सोचिए, बादल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वह हमारे बुजुर्ग हैं। मैं उनसे चंडीगढ़ में मिला। वहां बड़ी विस्तार से बात हुई, उन्होंने हमें खाना भी खिलाया। पंजाब के बारे में काफी बात हुई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्षा जी, मेरा आपके माध्यम से बड़ा निवेदन है कि मित्रो मेरी बात सुन लो। मैं यह सच्ची बात आपको बता रहा हूं, अक्षरश: सत्य आपके सामने रख रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरी सुखबीर जी से बात हुई। मेरे पास उनका पत्र है, आपकी सरकार का है। आपकी सरकार ने वह पत्र वापस नहीं लिया है। अभी की जो परिचर्चा है उसमें जिन राज्य सरकारों ने लिखित में विरोध नहीं किया उनमें पंजाब, हिमालच प्रदेश और गुजरात, तीनों में बीजेपी और उनके समर्थकों की सरकारें हैं। तीन तीन राज्य सरकारों ने आज भी लिखित में विरोध नहीं किया। आप लोगों के लिए यह जानना जरूरी है। आप कहते हैं कि केरल में विरोध हुआ, वह ठीक है। जब राज्यों पर छोड़ दिया है, तो उन्होंने अपना निर्णय लिया है। अब आप अपने मुख्यमंत्रियों से झगड़ा न करें कि क्यों नहीं किया।

मैंने जो तथ्य हैं, वे सदन के सामने रखे हैं। जब मैंने मुख्यमंत्री बादल जी से बात की या मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी से बात कर ली। उसके बाद मैं कहता कि साहब आप एक इंटरवेल करें और 15 मिनट के बाद दोबारा मिलूंगा। फिर मैं कहता हूं कि देखिए अब मैं आपसे मिलने आया हूं आपसे शिरोमरिण अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में और वही बात मैं दोबारा करने आया हूं। मैं कैसे यह करता, क्योंकि उन्हें मेरे बारे में चिंता हो जाती, जो मैंने अंग्रेजी की कहावत पढ़ी, वह सोचते कि मंत्री का संतुलन चला गया। सब से चर्चा हुई, जो आरोप है, वह सही नहीं है, नहीं होना चाहिए था।

सुषमा जी ने कहा मुझे कि चेंज क्या हुआ 2011 और 2012 की नीति में। आपने ठीक पूछा कि राज्यों पर आपने पहले भी छोड़ा था। सुषमा जी, राज्यों पर छोड़ा था वह एक इम्प्लाइड था कि राज्य ट्रेड लाइसेंस देते हैं, दुकान खोलने का लाइसेंस देते हैं, यही हमारा 2011 का वक्तव्य है। केबिनेट नोट में इम्प्लाइड, इस बार इम्प्लीसेट एक्सीप्लिट जो कहें, वह है। पहला पैराग्राफ यह है कि राज्यों का फैसला होगा, यह बड़ा फर्क है।

दूसरा बड़ा फर्क मैं बताना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। फारूक अब्दुल्ला जी हैं। मेरा जन्म जहां हुआ, वहां की चर्चा कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* बहन सुषमा जी भी यूपी, मध्य प्रदेश सब जगह हो आई अम्बाला के बाद, मेरा भी वह अधिकार है, क्योंकि देश हम सबका है। दूसरी बात हुई। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने मुझसे एक बात कही। इनके अलावा असम के मुख्यमंत्री तरुण गगोई जी ने भी मुझसे कहा, मैं उनका नाम लेना भूल गया था। इन्होंने कहा कि आनंद जी, केंद्र सरकार की नीति लाएगी और हमें वंचित करेगी। हम लैंड-लॉक्ड स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, हमारे बागबानों का क्या होगा, आप उनके लिए क्या करेंगे अगर आप केवल दस लाख से ऊपर आबादी के शहरों में खोलेंगे, तो मैंने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने इस बारे में प्रधान मंत्री जी से बात की और केबिनेट में चर्चा हुई। हमने इसमें स्पेशल डिस्पेंसेशन कर दिया, स्माल स्टेट के लिए, क्योंकि राज्यों पर छोड़ा है कि वे अपना निर्णय स्वयं करें। ये दोनों फर्क हैं पिछली नीति और इस नीति में।

मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सदन में बात रखी, कई बातें और हुईं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कल मेरे योग्य साथी कपिल

[श्री आनंद शर्मा]

जी ने कुछ उत्तर दिया। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने सारी बातें यहां रखी हैं, हमने कहा था कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब आम सहमति, कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति नहीं होता है, जहां तक मेरे अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया है। अगर सर्वसम्मति की इंतजार हो तो फिर समाधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कभी मानेंगे नहीं और हम बैठे रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। *[अनुवाद]* इस प्रकार सर्वसम्मिति और एकरूपता के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। इसका कारण यह है कि यदि आप सर्वसम्मति की प्रतीक्षा करते है तो आप को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी और हम कभी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। *[हिन्दी]* अब कई यहां पर बातें हुईं, प्रीडेट्री प्राइसिंग की और मेरे साथियों ने भी उत्तर दिया। हमारे यहां कम्प्टीशन का कानून है, कम्प्टीशन कमीशन है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। यह नहीं है कि वह एकदम से भाव गिरा देगा। मानवीय मुलायम सिंह जी की भी चिंता थी और सही चिंता थी कि भाव गिरा देगा, छोटा कारोबार बंद हो जाएगा, फिर एक दम से बढ़ा देगा, यह नहीं हो सकता है, हमारे देश का कानून अनुमति नहीं देगा। अध्यक्षा जी, हमने शर्त लगाई है और अब प्रश्न यह है कि हमने शर्त क्या लगाई? हमारी सोच अलग कैसे है और हमारी नीति शुद्ध रूप में भारतीय नीति है। हमने अपनी जमीन की हकीकत को समझा है, तभी कहा है कि 100 मिलियन डॉलर से कम का निवेश नहीं होगा। एफआईपीबी स्क्रूटनी करेगी, 50 परसेंट गांव में लगेगा। यह नहीं कि करेगा या नहीं करेगा? वह जब बिजनैस का प्रपोजल आता है तो एफआईपीबी स्क्रूटमी करता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो अनुमति नहीं मिलेगी। अगर 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग नहीं होगी तो अनुमति नहीं मिलेगी।

माननीय सुषमा जी ने कहा कि केवल 30 प्रतिशत, बाकी 70 प्रतिशत चीन से या बाहर से आएगा। हमने कहा कि मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कहा। वह भी एमएसएमई से कहा और यह नहीं कहा क्योंकि देश में मध्यम उद्योग भी है, देश में बुनकरों के, आर्टिजन के क्लस्टर्स हैं, वहां से ऑलरेडी सोर्सिंग हो रहा है–सिंगल ब्रांड रिटेलर्स का, मल्टी ब्रांड रिटेलर्स का। हवाला दिया गया कि चीन से इतने का सोर्सिंग है तो आज भारत का डेढ़ बिलियन का है और भारत का भी चीन से बढ़ जाएगा, पर हमारा किसान क्या खरीदेगा। जो देश में बिकेगा और जो देश में नहीं बिक पाएगा वह दुनिया के बाजार में जाएगा, हमें विदेशी एक्सचेंज भी आएगा, हमारे बेटे-बेटियों को रोजगार मिलेगा।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी केवल प्रतिपक्ष की नेता की बातों का नोटिस ले रहे हैं इसलिए हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है और हम वाक-आउट करते हैं।

अपराह्न 5.38 बजे

तत्पश्चात् श्री दारा सिंह चौहान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

श्री आनंद शर्मा : माननीय अध्यक्षा जी, एक प्रश्न उठा कि जा आप 30 परसेंट लोकल सोर्सिंग करते हैं वह डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के खिलाफ है, कल यह बात रखी गई। माननीय अध्यक्षा जी, 30 परसेंट सोर्सिंग हमारे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ नहीं है क्योंकि वह जो देश में आएगा वह पोस्-स्टेबलिशमेंट आएगा, जिसका मतलब यह है कि जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत आएगा और यह प्री-स्टेबलिशमेंट पॉलिसी है, पोस्ट-स्टेबलिशमेंट नेशनल ट्रीटमेंट की बात आती है, प्री-स्टेबलिशमेंट में नहीं आती। यह सार्वभौम अधिकार है हर राज्य का जो हमने अख्तियार किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष से विनम्र निवेदन है कि मैं अपनी बात पूरी करूं। मेरा यह कर्त्तव्य है कि जो बात सदन में कही गई है, मैं उसका उत्तर दे सकूं। जो एक बात कही गई, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरिएंस की कही गई, छोटे दुकानदार का माननीय मुलायम सिंह जी ने जिक्र किया, खुदरा व्यापार का सुषमा जी ने जिक्र किया। दूसरे हमारे सम्मानित शरद यादव जी ने जिक्र किया कि 25 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं और आपने 12 करोड़ कहा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह बात सही है कि अगर आज 2011 के आंकड़ों को भी मैं मानकर चलूं, 4 करोड़ लोग खुदरा व्यापार में हैं। 4 करोड़ का मतलब मुलायल सिंह जी ने कहा कि 5 परिवार के सदस्य होंगे या 4 होंगे। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें अमरीका का उदाहरण नहीं देखना कि वहां खुदरा व्यापार क्या है? वह तो आपने अपने कागजों में लिखा हुआ है कि यू.के. में कितना है। भारत में 2011 में संगठित रिटेल का 4 प्रतिशत हिस्सा है। 93.7 प्रतिशत खुदरा व्यापार में जो हिस्सा है, वह हिस्सा छोटे खुदरा व्यापारी का है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आप ई.यू. की स्टडी पढ़ती हैं? वर्ष 2011 की जो स्टडी है, दो प्रमुख अर्थशास्त्री जो दोनों भारतीय हैं और जिनके नाम जगदीश भगवती और राजेश कोहली हैं तथा दुनिया में जितना बहुत नाम है। भारत में संगठित खुदरा व्यवस्था : मामले और दृष्टिकोण में उन्होंने यह लिखा है। यह जानना आवश्यक है। इसमें पृष्ठ 6 से मैं कोट करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

मैं आपकी अनुमति से उद्धरित करना चाहूंगा : ''समग्र खुदरा व्यवस्था-सर्वप्रथम समग्र खुदरा बिक्री 2004 और 2009 के बीच लगभग 70 प्रतिशत हो गई जो 294 बिलियन अमरीकी डालर से 496 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। दूसरे इस अवधि में बिक्री खुदरा बाजार में औपचारिक रूप में लगभग 43 प्रतिशत और अनौपचारिक रूप से लगभग 97 प्रतिशत बढ़ गई। अत: 2004 से 2009 के बीच खुदरा बिक्री औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग दुगुनी हो गई। संगठित क्षेत्र में वृद्धि 7 प्रतिशत हुई और असंगठित क्षेत्र में खुदरा व्यापार में लगभग 15 प्रतिशत हुई।

[हिन्दी]

इस चीज को बताना जरूरी है। इसलिए यह डर फैलाना कि छोटा खुदरा व्यापारी कहां जाएगा? जब संगठित रिटेल आ गया और जब 12 साल में नहीं गया तो आप भारत की स्टडी पढ़ लें। ब्रसल्स की स्टडी न पढ़ें। उसका नुकसान नहीं होगा। जैसा आपका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। मैं भी एक छोटे मध्यवर्गीय परिवार में छोटे शहर में पैदा हुआ। शिमला में हम भी जाते थे। जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे और हमारी मां बोलतीं थीं कि सब्जी खरीदकर लाओ। मैं खुद और मेरा छोटा भाई थैले में सब्जी वगैरह लेकर आते थे। हम पिताजी के साथ सब्जी खरीदने जाते थे। हम कहीं ऊपर से नहीं आए हैं। हम भी इसी जमीन से जुड़े हैं। हम भी अपने देश को समझते हैं। हमें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हम भारत को समझते हैं या नहीं। हम एक छोटे व्यापारी की समस्या को समझते हैं या नहीं? वह सुरक्षित है। जैसा कि कहा गया है कि बड़ी दुकान कहां खुलेगी, केवल बड़े शहरों में? उसे एक लाख स्कवेयर फुट जगह चाहिए। मुलायम सिंह जी, वह पड़ोस की दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज भी आप और हम जब अपने घर गावं या शहर में जाते हैं या यहां पर भी हमारे पास जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें कहते हैं कि सामान ले आओ, वे कोई मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर से नहीं लाते हैं, वे देंगे भी नहीं, क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में छोटा दुकानदार जो सामान देगा कर्ज पर देगा। छोटा दुकानदार आधी डबलरोटी, दो अंडे भी दे देगा, कर्ज पर देगा और फिर महीन बाद ले लेगा। बच्चा जाएगा और कहेगा कि लाला जी यह दे दो, वह कापी में लिख लेगा और महीने बाद उसके पिताजी से पैसे मांग लेगा। आप यह डर मत फैलाइए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के चंद मिनट और लूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं दो बातें जरूर कहूंगा। पहली बात है कि बड़े अहम फैसले हुए, हर सरकार फैसला करती है। बार-बार अमरीका का हवाला दिया गया, बार-बार टीका टिप्पणी हुई, बार-बार कटाक्ष हुआ। मैं बहस में नहीं जाता। मेरे पास सन् 2000 का कागज है, यह कागज किसी ने नहीं दिया यह सरकारी संपत्ति है। यह उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव थे, उनका नाम आपने लिया, मैं कभी नाम नहीं लेता, वे दूसरे सदन के सदस्य हैं। आप आपत्ति मत कीजिए, आपने एन.के. सिंह जी का नाम लिया था। यह चिट्ठी 26 अगस्त, 2000 की है। एन.के. सिंह जी को सैक्रेट्री डीआईपीपी का पत्र है कि आपने हमसे ब्यौरा मंगाया है, हम उसे भेज रहे हैं। यह कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर का निर्णय है। कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बता दिया जाए, उनके अमरीका के दौरे से पहले। यह पत्र शुरू होता है--

[अनुवाद]

> ''प्रधानमंत्री शीघ्र भारत में निवेशक हित की समीक्षा के लिए अमेरिका जायेंगे और भारत में सुधार प्रक्रिया जारी रखने के बारे में भी संकेत देंगे। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के बारे में कुछ घोषणायें करना चाहेंगे।''

[श्री आनंद शर्मा]

उसमें है:

"मल्टी ब्रांड रिटेल में स्वत: ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 प्रतिशत अनुमति दी जाये। रक्षा में भेषज में, वायुसेना में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाये...."

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : जी नहीं, यह कोई संकेत नहीं था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा : क्या मैं इसे सभापटल पर रख दूं।... *(व्यवधान)* मुबारक है। माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर व्यवधान न हो तो उचित है। हमें बचपन में एक चीज बताई गई थी कि हकीम खुराक देता है कड़वी होती है तो असरदार होती है, इसी तरह सच्चाई भी कड़वी होती है, इसे मान लीजिए।...*(व्यवधान)* हमने आपकी बात सुनी, आज आप हमारी बात सुनिए।

कल सुषमा जी ने एक बात और कही कि वे प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी दुनिया के देशों में जाना चाहती हैं, चाहे वाशिंगटन हो या लंदन हो, वे इन्वेस्टर्स को भारत आने को कहेंगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। पहले कहा कि यह निर्णय प्रभावित निर्णय है, आपके शब्द से भ्रष्टाचार की बदबू आती है। सुषमा जी, आप ऐसी बात न कहें तो अच्छा है। आप विरोध करें लेकिन ऐसी गंभीर बात मत कहें। वॉलमार्ट अकेला इन्वेस्टर नहीं है, दुनिया में टेस्को, सेलिसबरी, कार-प्ट के अलावा जो भी आना चाहते हैं, उन्हें क्यों डरा कर भगा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने मुझसे से सलाह मशविरा नहीं किया, यह उनका विशेषाधिकार है। अगर वे आपको लेकर जाएंगे तो क्या चमत्कार होगा कि यहां पर दो साल से चर्चा हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं, यहां ऐसे लोग हैं जो हर नंबर के आगे दस सिफर और लगाते हैं, निवेश करने वाले यूं ही घबराकर भाग रहे हैं। आप जाएंगे और डराएंगे। पहले अपने विचार बदलें ताकि प्रधानमंत्री जी आपको साथ लेकर आएं, देश और दुनिया यहां आए, हमारे लोग बाहर जाएं, कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े।

अंत में आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुझे एक चीज कहनी है, यह अंतिम बात है, इस देश के अंदर जब भी बड़ा फैसला हुआ है, शोर हुआ है, विरोध हुआ है। 1985 में भारत बंद हुआ था, तब भी बीजेपी और लैफ्ट फ्रंट एक साथ आ गए थे। 1991 में उदारीकरण की बात हुई, बॉम्बे क्लब बना, कहा गया कि देश का उद्योग खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? श्री प्रफुल पटेल ने जिक्र किया टाटाज ने जाकर कोरस स्टील खरीद लिया, लैंड रोवर, जगुआर खरीद लिया, हमारा नुकसान नहीं हुआ।

मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूं कि थोड़ा संयम से सोचें और अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें, वरना मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सदन इस प्रस्ताव को खारिज करे।

***श्री मुलायम सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदया, इसमें खुदरा व्यापार की उपेक्षा की गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसका बहिष्कार करती है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 05.51 बजे

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

अध्यक्ष महोदया : प्लीज बैठिए, आप लोग क्यों खड़े हैं? आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : गुरुदास दासगुप्ता जी, बैठ *[अनुवाद]* जाइए कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? आप बैठ जाइए। अब सुषमा जी बोल रही हैं, वह खड़ी हैं, आप बैठ जाइए। प्लीज, टेक योर सीट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, एफडीआई के विषय पर कल दोपहर से शुरू हुई चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। चर्चा बहुत सार्थक और विस्तृत भी हुई है। मुझ समेत 18 पार्टियों के 22 सम्मानित साथियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। बीजेपी के दो, कांग्रेस के तीन एवं बाकी दलों से एक-एक सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। अधिकतर दलों के नेता सदन ने ही चर्चा में भाग लिया है। जो नहीं बोल सके, वहां उनके बहुत वरिष्ठ साथियों ने अपना पक्ष रखा है।

अध्यक्षा जी, मैं खुश हो रही थी कि 18 से 14 पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में भाषण दिया था। मात्र चार दल-कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी और आरएलडी ने एफडीआई के पक्ष में भाषण दिया था। अभी मैं भाषण की बात कर रही हूं। जो लोग एफडीआई के विरोध में जो भी बोले, किसी ने हल्केपन से विरोध नहीं किया है। बहुत शिद्दत के साथ अपनी बात रखी है। आंतरिक वेदना के साथ अपनी बात रखी है और बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रखी है। जहां तक एफडीआई के पक्ष में बोलने का सवाल है, पक्ष में बोलने वालों का नेतृत्व भाई कपिल सिब्बल जी ने किया है। लेकिन कल मुझे हैरानी हुई कि उनका भाषण अंतर्विरोधों से भरा हुआ था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे एफडीआई के पक्ष में बोल रहे हैं या एफडीआई के विरोध में बोल रहे हैं। इसीलिए आज भाई शरद यादव जी ने कह दिया कि कल वे सच बोल रहे थे। क्योंकि वह दुविधा मेरी समझ में आ गई है। वह दुविधा इसलिए थी कि वे दिल्ली से जिस क्षेत्र, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां का मतदाता पूरी तरह एफडीआई के खिलाफ है। लेकिन वे जिस सरकार का बचाव करने के लिए खड़े हुए थे, वह सरकार एफडीआई के पक्ष में है। कहते हैं कि कभी बूंद के इधर, कभी बूंद के उधर, वे बच-बच के निकल रहे थे। कभी अपनी बात कह कर अपने मतदाताओं को रिझाना चाहते थे और कभी अगली बेंचों पर बैठे अपने दोनों नेताओं को देख कर, मुक्के मार कर एफडीआई के पक्ष में बोलना चाहते थे। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रही हूं। जहां तक आपके द्वारा दिए गए तथ्यों का ताल्लुक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. जोशी जी ने आंकड़े दे-देकर आपके तथ्यों को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी। उन्होंने मेरा काम, राइट टू रिप्लाई बहुत आसान कर दिया है। लेकिन आपके भाषण के अंतर्विरोध मैं आपके सामने रखने चाहती हूं।

यह उन्हीं का भाषण है–

"मैं चांदनी चौक से मैंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही बात करता हूं, बाकी की बात नहीं करता हूं। अगर वॉलमार्ट यहां आएगा तो कहां पर दुकान लगाएगा? वह दिल्ली में तो दुकान लगा ही नहीं सकता है। अगर लगाना चाहेगा तो भी उसे जगह नहीं मिलेगी। यदि जगह मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि उनका इकनॉमिक मॉडल ही खराब हो जाएगा। फिर निश्चित रूप से उसे एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।"

यह वह पहला अंतर्विरोध है,*...(व्यवधान)* दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी सबसे बड़ा वायदा कर रही हैं कि एफडीआई का वॉलमार्ट पहले दिल्ली में आएगा। *...(व्यवधान)* एफडीआई के लिए उन्होंने बड़ी रैली की है। आनंद शर्मा जी के पास जिन 11 मुख्यमंत्रियों के पत्र आए हैं, उनमें एक पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री का है कि मैं एफडीआई के पक्ष में हूं और एफडीआई लाना चाहती हूं।*...(व्यवधान)* दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बड़ा दावा कर के कह रही हैं कि पहली एफडीआई वहां आएगी, उन्हीं की पार्टी के मंत्री और चांदनी चौक के एमपी खड़े होकर कह रहे हैं कि दिल्ली में एफडीआई नहीं आएगी।*...(व्यवधान)* उन्होंने पूरी दिल्ली की बात कही है। आप सुन लीजिए, मैं फिर से पढ़ देती हूं।

उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जगह कहां मिलेगी? उन्हें एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।

अध्यक्षा जी, जहां तक एनसीआर का ताल्लुक है, उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है?

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

सायं 06.00 बजे

एनसीआर में नोएडा आता है, जो यू.पी. में है, एनसीआर में गुडगांव आता है, रोहतक आता है, बहादुरगढ़ आता है, जो हरियाणा में है तो एनसीआर के बारे में दिल्ली की मंख्यमंत्री नहीं बोल सकती हैं। वे दिल्ली में लगाने की बात करते हैं, मगर संसद के फर्श पर खड़े होकर दिल्ली के संसद, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पहले बोलने वाले वक्ता कहते हैं कि दिल्ली में वह कहां आएगा, दिल्ली में जगह ही नहीं मिलेगी। यह पहला अंतर्विरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यदि सभा सहमत हो तो इस चर्चा के पूरा होने तक समय बढ़ा दिया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां महोदया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं दूसरा अंतर्विरोध बताती हूं। वे कहते हैं कि यह नीति किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है, गरीबों के हित में है, छोटे लोगों के हित में है और कहते हैं कांग्रेस पार्टी क्योंकि किसान-मजदूर-गरीब की हितैषी है, इसलिए यह नीति लेकर आई है। लेकिन यहां भाषणमें क्या बोलते हैं, मोटर साइकिल पर वॉलमार्ट में कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जाएगा, साईकिल पर चढ़कर कोई नहीं जाएगा, फिर वॉलमार्ट से कौन खरीदेगा, बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोग वॉमलार्ट से खरीदेंगे। आप किसान के हित में हैं, मजदूर के हित में हैं, उपभोक्ता के हित में हैं और नीति बना रहे हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोगों के लिए।...*(व्यवधान)* बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोग जाएंगे तो ये कौन से उपभोक्ता का हित देख रहे हैं, कौन से उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है? बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है, यह दूसरा अंतर्विरोध है।

तीसरा अंतर्विरोध, वे कहते हैं कि वॉलमार्ट तो वर्ष 2008 तक घाटे में था तो घाटे का सौदा करने वाला हर तरह का हथकंडा अपनाकर क्यों आने की बात कर रहा है? अगर वॉलमार्ट के लिए आना घाटे का सौदा है तो वह इतने तरह के हथकंडे अपनाकर क्यों आना चाह रहा है, क्यों तड़प रहा है भारत में आने के लिए? दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में है, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा है।

महोदया, एक घाटे वाला दूसरे घाटे वाले को कैसे उबारेगा, जरा मुझे यह तो बता दीजिएगा। इसलिए जहां तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, कल वे पूरी तरह कन्फ्यूज्ड थे, उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि यहां से उठकर चांदनी चौक भी जाना है, वहां लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपने दोनों नेताओं के सामने भी खड़ा होना है, वहां क्या कहेंगे। कपिल सिब्बल जी का पूरा भाषण कन्फ्यूजन से भरा हुआ था और बाकी चीजें डॉ. जोशी ने ऑरलेडी बता दी हैं, सारे आंकड़ों से उनके भाषण को धराशाही कर दिया।

दूसरा भाषण लालू जी का आया। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यहीं घड़ा लगता है। मुझे लगता है कि उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ु शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मसखरी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता।...*(व्यवधान)*

महोदया, कांग्रेस से दूसरे वक्ता दीपेन्द्र हुड्डा जी आए, अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वे इतने उत्तेजित हो गए कि दो फुट का आलू उगा गए।...*(व्यवधान)* उन्होंने मैक्डोनाल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी दो फुट का आलू उगाकर उन्हें देंगे।...*(व्यवधान)* वे कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। अरे बेटा, किसान के बेटै हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो।

महोदया, दो फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। दो फुट की तो लौकी भी उगाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ये दो फुट का आलू उगाकर दे रहे हैं और वह भी मैक्डोनाल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जब ये कुतर्क से सारी बातें यहां रख रहे हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से अधिकृत जवाब आया भाई आनन्द शर्मा का। बहुत शालीनता से बोले, बहुत संजीदगी से बोले, अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखने का प्रयास

भी किया। लेकिन क्योंकि वह तथ्यों पर आधारित नहीं था, इसलिए वे प्रभावित नहीं कर सके। एक अजीब तर्क उन्होंने दिया। जब स्टेकहोल्डर्स की बात की थी, तो उन्होंने बाकायदा पूछा था कि कौन हैं। यह तो उन्हें पता था कि ग्राहक संगठन होंगे, किसान संगठन होंगे, और उसमें प्रणब दा ने साफ कहा था, जो इन्होंने भी राज्य सभा में कहा कि राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे। अध्यक्ष जी, आप देखिए कि प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का इंटरव्यू देखकर ये समझते हैं कि परामर्श हो गया। जवाब क्या दिया है?...*(व्यवधान)* नहीं, उनका इंटरव्यू आया और उनका इंटरव्यू देखकर परामर्श हो गया।

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदया, शायद प्रतिपक्ष की नेता सुषमा जी को मेरी बात समझ नहीं आई, मैं माफी चाहता हूं। वह उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री प्रणब जी को मिले और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर प्रैस इंटरव्यू दिया और यह कहा कि मैं उनसे लंच पर मिला और हमने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मैं दूसरी बात कहूंगा। आपने कहा कि आप दलों से नहीं, जो सदन के अंदर अपने राजनीतिक दलों के नेता हैं, सरकार को उनका सम्मान करना है। सबको पत्र लिखा, दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष को लिखा। मैं अपेक्षा करता था कि कम से कम सुषमा जी इंकार कर दें पर चिट्ठी का जवाब जरूर दें, वह जवाब आज तक तो आया नहीं है। फिर कहेंगे कि चर्चा नहीं हुई।...*(व्यवधान)* तीसरी बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि गडकरी जी और सुषमा जी के संबंध कितने मधुर हैं। अगर उन्होंने इनको नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जो पत्र इन्होंने हमें लिखा, बसुदेव आचार्य जी ने ठीक कहा कि वह 7 दिसंबर से पहले का है। चर्चा में 7 दिसंबर को आश्वासन दिया गया, इसलिए आप यह मत कहिए कि आपने हमें पत्र लिखा। वह चर्चा 7 दिसंबर के बाद होनी चाहिए थी। वह पत्र 7 दिसंबर के बाद नहीं गया। इसलिए मैंने कहा कि वह गलत तथ्य रख रहे हैं। जहां तक राजनीतिक दलों से चर्चा होनी थी, प्रणब मुखर्जी की उस मीटिंग में ये नहीं थे। वह एक कर्टसी मीटिंग थी उस मीटिंग में क्या परामर्श हो गया और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो उसको इन्होंने परामर्श मान लिया। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। प्रणब दा के स्टेटमैंट में दो चीजें थीं—परामर्श और कनसैन्सस या आम सहमति। अगर प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता के उस बयान के बाद आपको यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है तो आम सहमति कैसे बन गई? आप कनसैन्सस की बात करते हैं। मैं यही कहती हूं कि आपने उसको स्वीकार कर लिया तो आम सहमति कहां बनी? हम भी सर्वसम्मति की बात नहीं करते। हम भी आम सहमति की बात करते हैं। लेकिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल की खाने के बाद के एक इंटरव्यू को देखकर इन्हों ने परामर्श समझ लिया और यह कहा कि ये एग्री नहीं करते तो क्या हुआ, आम सहमति हम वैसे ही बना लेंगे। अध्यक्ष जी, पहली बार आम सहमति इस सदन में उभरी है और मैंने आपसे कहा कि 18 में से 14 पार्टियों ने इसके पक्ष में भाषण किया।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सुषमा जी ठीक कह रही हैं कि सदन में पिछली बार जब यह चर्चा आई थी तो उस पर यहां विरोध हुआ था। उसी के बाबत दोनों जगह यह बयान आया था। आपने जिस तरह से चिट्ठी लिखकर...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा : 14 मुख्य मंत्रियों से मैं स्वयं मिला।

श्री शरद यादव : आप सुनिए तो सही। वह मुख्यमंत्रियों के लिए भी था और यहां सदन में जो पार्टियां हैं, उनके लोगों से भी आप परामर्श करेंगे, यह बात थी। परामर्श हमेशा मीटिंग बुलाकर होता है और वह आपने नहीं किया। सुषमा जी यह बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपने परामर्श को बिल्कुल राजी समझ लिया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आम सहमति आज सदन में उभरी है या आम सहमति उस दिन उभरी थी, जिस दिन एफडीआई पर भारत बंद हुआ था। एक व्यापक विपक्षी एकता दिखी थी। कभी नहीं दिखी होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दोनों ने बंद किया था। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों ने विरोध किया था। तमिलनाडु में अन्ना-डीएमके और डीएमके दोनों ने विरोध किया था और एनडीए तो पूरे का पूरा विरोध में था ही। इनके अपने यहां भी पूरी सहमति नहीं है। इनके यहां कैबिनेट में केरल से रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी इसके खिलाफ हैं। इनके केरल के मुख्यमंत्री और केरल की कांग्रेस की इकाई इसके खिलाफ है। कल मैंने शशि थरूर जी से पूछा कि क्या आप बोलना चाहते थे और आपको मना कर दिया गया है? उन्होंने कहा, हां मुझे मना कर दिया गया है कि मैं इसके पक्ष में न बोलूं। कहां है आम सहमति? 18 में से 14 पार्टियों ने भाषण दिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर) : अध्यक्ष महोदया चूंकि मेरा नाम लिया गया है, मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, उन्होंने मेरा नाम लिया है। गलियारे में नेता विपक्ष ने हँसते हुये टिप्पणी की थी जिसका मैंने हँसकर जवाब दिया। मुझे विश्वास नहीं या कि इसे इस प्रकार सभा में उद्धरित किया जायेगा मेरा सम्मानपूर्वक निवेदन है कि इसे वापस लिया जाये। मैंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, 18 में से 14 पार्टियों ने इसके विरुद्ध भाषण दिया है।...*(व्यवधान)* चाहती तो मैं यह थी कि भाषणों में जो सोच आई, वह सोच वोट में भी उसी तरह से परिलक्षित होती। क्योंकि मैंने उन 14 पार्टियों का हिसाब लगाया, जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में बोला, जिन्होंने एफडीआई के विरोध में बोला। नंबर बनता है 282, इस सदन के बहुमत से 10 ज्यादा और जिन्होंने पक्ष में बोला, उनका नंबर बनता है 224। मैं अभी भाषणों की बात कर रही हूं कि जो भाषण हुए उनमें पार्टियों की संख्या है, उसको मैंने जोड़ा तो 282 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में बोला है और 224 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के पक्ष में बोला है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि पूरे सदन की सोच और उसके माध्यम से देश का मानस आपके सामने नजर आ गया है कि देश का मानस यह है। वह सदन में प्रतिबिम्बित हुआ है। मैं चाहती थी कि सोच वोट में परीलक्षित हो, क्योंकि संसद की इन दीवारों ने दो दिन जो भाषण सुने हैं, उसके बाद वोट का परिणाम इन्हीं दीवारों पर चस्पा होगा और वह इतिहास में दर्ज हो जाएगा।...*(व्यवधान)* वोट का मतलब होगा। वोट का मतलब अभी बताऊंगी कि वोट का मतलब क्या होगा। वह चस्पा हो जाएगा और वह लोक सभा की कार्यवाही का हिस्सा बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ें कि किसने कहा क्या और किया क्या? मैं चाहती थी कि कथनी और करनी में कोई अंतर यहां दिखाई न दे। कितनी शिद्दत से मुलायम सिंह यादव जी बोले थे और उन्होंने सोनिया गांधी जी से अनुरोध किया था कि आप इसे वापस करने का निर्देश दीजिए। उन्होंने आखिर में एक बात कही थी कि अगर आज गांधी, लोहिया, जय प्रकाश होते तो एफडीआई यहां आ नहीं सकती थी। मैं कहना चाहती हूं कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश तो आज नहीं हैं, लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव आज वोट करते तो एफडीआई नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। लेकिन क्या करें, दुविधा हो गई।...*(व्यवधान)* भाजपा के साथ वाला मामला नहीं है। वह भी बता दूं, क्योंकि डीएमके वाले यही कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चैन्ने उत्तर) : हमने सभा में अपने विचारों से पहले ही अवगत करा दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आज कोई सैक्युलर या कम्युनल विषय पर बहस नहीं हो रही है। आज 20 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी के बारे में बहस हो रही है। 4 करोड़ की रोजी और 20 करोड़ की रोटी पर बहस हो रही है। खुदरा व्यापार में जो लोग लगे हैं, वह हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, सिक्ख और ईसाई दोनों लगे हैं, हर धर्म के लोग लगे हैं। सच्चर कमेटी ने कहा था डिटैल ट्रेड पर, एफडीआई का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर होगा तो वह मुसलमानों पर होगा। हिंदू से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान रिटेल ट्रेड और खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। इसलिए आज सेक्युलर और कम्युनल की बहस नहीं है। आज बहस रोजी-रोटी की है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जे.डी.एस. के नेता देवगौड़ा जी को। उन्होंने कहा कि *[अनुवाद]* मैं आपके प्रस्ताव के कारण नहीं बल्कि गरीब किसानों के कारण मतदान कर रही है। *[हिन्दी]* इसलिए हर कोई अपने-अपने कारणों से वोट दे सकता था। लेकिन, दिक्कत यह है कि जब कारण एफडीआई बनाम सीबीआई बन जाए तो फिर रास्ता क्या होगा? फिर सीबीआई नजदीक कि एफडीआई नजदीक? फिर सीबीआई नजदीक। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहती हूं कि सदन की मंशा तो यह है । सदन में भाषणों का आंकड़ा यह है। 282 लोगों के दलों ने एफडीआई के विरोध में बात की है। यह देश का मानस है जो सदन में प्रतिबिम्बित हुआ है।...*(व्यवधान)* बसपा वाले कहते हैं कि सांप्रदायिकता के साथ वोट नहीं करेंगे। जब एस.सी., एस. टी. आरक्षण के विधेयक परवोट लेने की बात होती है तो बहन जी चलकर आती है और कहती हैं कि आप राज्य सभा के नेता को भी बुला लो ताकि हम दोनों बहन-भाई से एक साथ मिलूं।

अब वोट देने की बात हो तो हम सांप्रदायिक और जब वोट लेने की बात हो तो हम बहन-भाई। यह "मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू" नहीं चल सकता। आप तय करें कि आप वोट लेंगे या वोट देंगे अगर आपको हर समय पर यह रटा-रटाया तर्क देना है। मेंने पहले ही कहा कि आज कम्युनल-सेक्युलर की बहस नहीं है, आज बहस छोटे व्यापारी के हित की है, खुदरा व्यापार में लगे हुए चार करोड़ लोगों की रोजी और बीस करोड़ लोगों की रोटी की है। इसलिए मैं आपसे और आज जितने साथी यहां बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपनी अपील दोहराना चाहूंगी कि आम सहमति यह है। परामर्श की जगह विचार-विमर्श हो गया है। पूरी की पूरी चर्चा हो गई, विस्तृत चर्चा हो गई है। यह देश की बहस हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने सुनी है। इसलिए आप यह कह सकेते हैं कि यह लोकतांत्रिक देश है और अगर संसद इसे नहीं मानती है तो लोकतंत्र में मुझे जनमत के आगे झुकना है। इसलिए हमने निर्णय जरूर किया था, लेकिन हमारे यहां लोग इसके विरोध में है, मैं इसको नहीं लागू कर सकता, आप अगर इस निर्णय पर पुनर्विचार करके यह कह दें तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि आपको हराकर नहीं, मनाकर हम लोग जीतना चाहेंगे। लेकिन, अगर आप अड़े हुए हैं। जिस तरह से जवाब में अभी आया है तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगी। उर्दू का एक शेर है–

तारीख की आंखों ने वह हाल भी देखा है,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है

मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वह लम्हा जिस समय आप मतदान करने के लिए बटन दबा रहे होंगे, आपकी उंगली बटन पर होगी तो वह लम्हा उन बीस करोड़ लोगों की तकदीर बनाने या बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए बिना कोई दूसरी बात सोचे, जैसे देवगौड़ा जी ने कहा है, किसान के हित में, छोटे व्यापारी के हित में, गरीब के हित में, ये बड़े मैक्डोनाल्ड्स और पेप्सीको के हित में नहीं, ये बड़े वॉल मार्ट या टेस्को के हित में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आम आदमी के हित में आप 'यस' का बटन दबाइए और इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए, एफडीआई को गिरा दीजिए। सरकार नही जाएगी और एफडीआई चली जाएगी, और देश बच जाएगा। यह निवेदन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब प्रो. सौगत राय।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदया, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : जी नहीं, हमारा प्रस्ताव चर्चाधीन हैं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : विपक्ष की माननीय नेता ने उल्लेख किया कि मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही हूं। मैं ईमानदारी से कहूं। मैं विपक्ष की माननीय नेता और उनके दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देवेगौडा जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय जो बालेंगे उसके अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बातें बहुत संक्षेप में बोलूंगा, क्योंकि इस पर हाउस में बहुत चर्चा हुई है। सुषमा जी ने विरोधी दलों के पक्ष में अपने बयान रखें हैं। लेकिन मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा था, वह खास करके एक सरकारी नोटिफिकेशन को संशोधन करने के लिए था। ये नोटिफिकेशन 19 अक्तूबर, 2012 को जारी किया गया था और वह लोक सभा में 30 नवम्बर, 2012 को रखा गया था। मेरा जो संशोधन है, वह बहुत सीमित है। वह जो 19 अक्तूबर का संशोधन था, उसमें सरकार ने काफी क्षेत्रों में दर्जा विदेशी पूंजी निवेश के लिए खोल दिया है। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। शेड्यूल आठ में कौन-कौन से क्षेत्र खोल दिए। एग्रीकल्चरल में सौ परसेंट

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. सौगत राय]

खोल दिया, टी-प्लांटेशन, माइनिंग, पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सौ परसेंट, मेनुफेक्चरिंग, डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग 74 परसेंट खोल दिया। प्रिंट मीडिया, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट सौ परसेंट विदेशियों के लिए खोल दिया। मुल्क को क्या हो रहा है, मुल्क को सब लोग समझेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप सौ परसेंट, इंडस्ट्रिलय पार्क्स सौ परसेंट, सेटेलाइट्स सौ परसेंट, स्पेस में जो जाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां 49 परसेंट, टेलीकॉम सर्विसेज 74 परसेंट, रीकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग प्राइवेट सैक्टर खोल दिया गया। बैंकिंग इवन इन पब्लिक सैक्टर खोल दिया गया, सभी को बेचा जा रहा है। कमोडिटी एक्सचेंजेस 49 परसेंट,...*(व्यवधान)* संजय जी, आप हमारी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सौगत राय जी, आप इधर देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए।

प्रो. सौगत राय : क्रेडिट इन्फोरमेशन सर्विसेज 49 परसेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, ये सब जो 26 क्षेत्र खोल दिए गए, उसमें भी सब-क्लॉजेस हैं, सब मिला कर तीस क्षेत्र खोल दिए गए। मेरा अमेंडमेंट बहुत ही सीमित है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : मेरा जो संशोधन है, वह सीमित है। 16 नम्बर ठीक नहीं है। 16 नम्बर धारा क्या है–ट्रेडिंग, ये सौ परसेंट खोल दिया गया है। कैश एंड कैरी होल सेल, सौ परसेंट खोल दिया गया है। कल शायद अधीर चौधरी जी बोल रहे थे कि कोलकाता में मेट्रो कैश एंड केरी चल रहा है। वह होल सेल ट्रेडिंग है, वह तो पहले से ही खोल दिया गया था। वाम फ्रंट के जमाने में उसकी दुकान खोली है तो उसके लिए हमें क्यों कहा जाता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : टेस्रूट मार्केटिंग खोल दिया गया। सबसे जरूरी सिंगल ब्रांड प्रोडेक्ट रिटेल सौ परसेंट कट गया। मैंने बाहर से प्रफुल पटैल जी का भाषण सुना। वे प्रेक्टीकल आदमी हैं, उनका बड़ा व्यापार है। वे कह रहे थे कि जिसको पसंद है, वह वॉलमार्ट में जाएगा, जिसको पसंद है, वह किराना शॉप में जाएगा। प्रफुल जी, यह सही बात है। आप लोगों को तो ऐसे ही संतुष्ट होना चाहिए कि अभी सिंगल ब्रांड रिटेल सौ परसेंट कर दिया गया।

अभी मुल्क में कौन आएगा, लुई बुइटो, कोस्टा कॉफी, प्रादा, गुच्ची, स्वरोस्की, ओमेगा, ये बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें हमारी तो क्षमता नहीं है। बाबा लोग जाना चाहते हैं तो फिर वालमार्ट को क्यों लाना चाहते हैं। इन्होंने तो फॉरेन कम्पनीज सब के लिए 100 परसेंट पूरा खोल दिया। बाबा लोग जाइए, बीबी लोग जाइए, हममें कोई आपत्ति नहीं है। वे स्वरोस्की क्रिस्टल खरीदें, हमें आपत्ति नहीं है। इतने सारे मामलों में एक मल्टी ब्रांड रिटेल पर हमारा संशोधन है। मैडम समझिए, मेरी चाहत बहुत ही कम है। मैं सब के खिलाफ संशोधन नहीं लाया, केवल हमारा फोकस कम्पोजीशन मल्टी ब्रांड रिटेल पर है।

आनन्द शर्मा जी ने सही बात कही और बहुत तरीके से उन्होंने जवाब दिया, भाषण दिया। वे मम ता बनर्जी से मिले। ममता जी क्या बोलीं? बोलीं कि इसको हम नहीं मान सकते हैं। हमारी मैडम बोलीं, क्या बोलीं, मेरी टूटी-फूटी हिंदी को माफ कर दीजिए, यह हमारी मातृभाषा नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बोलिए।

प्रो. सौगत राय : ममता जी क्या बोलीं कि हमारे मैनीफेस्टो में है कि हम एफ.डी.आई. रिटेल के खिलाफ हैं, आनन्द शर्मा जी, हम आपकी बात नहीं मान सकते। आपने जो बोला, सही बोला। मैंने तो बोला कि आपका जो भाषण था, बहुत ही सही भाषण था। मैं कहता हूं कि प्रणब मुखर्जी जी ने हमारे हाउस में कंसेंसस की बात बताई थी। आनन्द शर्मा जी ने एक मुख्यमंत्री का जिक्र किया। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक सारे हिंदुस्तान में नौ मुख्यमंत्रियों ने सहमति दी है, उसमें भी बड़े प्रदेश 6 हैं और तीन में दिल्ली, छोटी सी जगह है, दमन एंड दीव, वह भी दिखा रहे हैं और मणिपुर है, जहां की आबादी कम है।...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात का जिक्र करूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

प्रो. सौगत राय : हिंदुस्तान में 28 प्रांत है। और सात यूनियन टैरीटरीज हैं। उनमें से अगर नौ लोग सहमति देते हैं तो यह क्या आम सहमति होगी? सुबह मेरे खास दोस्त श्री भर्तृहरि मेहताब जी ने डिक्शनरी लाकर बोला कि कंसेंसस का क्या मतलब होता है और आनन्द शर्मा जी, क्या इसी को कंसेंसस कहते हैं? आपका बात करने का तरीका अच्छा है, लेकिन यह कंसेंसस नहीं है। आप अपनी बात को मुल्क पर लाद रहे हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब अपनी बात समाप्त करिए।

प्रो. सौगत राय : मैडम, मैं दो मिनट लूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया इसे अधिक मत खींचिएगा।

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, वायदा करता हूं। *[हिन्दी]* आप मुझे बोलने दीजिए। आपके बीच में बोलने से हम बहुत शरमा जाते हैं, इसलिए हमें बोलने दीजिए।

मुझे यह कहना है, ये लोग कहते हैं, कपिल सिब्बल जी ने लंबा भाषण दिया कि आप क्यों फिक्र करते हैं। अगर कोई प्रांत, कोई मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहते हैं तो ठीक है, वे न मानें। कपिल सिब्बल जी ने उदाहरण भी दिए कि हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमान चंडी जी रिटेल में एफ.डी.आई. के खिलाफ हैं उनको बोलना चाहिए था कि हमारे रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने भी एफ.डी.आई. के खिलाफ बयान दिया है। ठीक है, आप उन पर जबरदस्ती नहीं करें, लेकिन...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में जो एम. पी. हैं, सांसद हैं, उनमें से बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, जब आपके मुख्यमंत्री एफ.डी.आई. के खिलाफ हैं तो क्या आप पार्लियामेंट में एफ.डी.आई. रिटेल के पक्ष में वोट देंगे, यह आप बताइए, आप अपने दिल को साफ करिए?

दूसरी बात कपिल सिब्बल जी बोले हैं कि अगर कोई प्रांत नहीं चाहता है तो लागू नहीं करे। यह सही बात है, पर आज किसी मुख्यमंत्री ने लागू किया और कल वहां पर वोट हुआ और दूसरी पार्टी सरकार में आई, वह एफडीआई के खिलाफ है, तो क्या वॉलमार्ट की दुकान तोड़ देंगे? यह कभी क्या प्रैक्टिकल बात हो सकती है? यह लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। हम इस पर भरोसा नहीं रखते हैं। कपिल सिब्बल जी ने भाषण देते हुए कहा कि यह सब डिबेट करने की क्या जरूरत है?...*(व्यवधान)* आप इतना घबराते क्यों हैं? हिंदुस्तान में केवल 53 शहर हैं, जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है। जब इतने प्रांत न कर रहे हैं, तो केवल 18 में यह चालू होगा, तो इसे लेकर इतनी डिबेट की क्या जरूरत है? कपिल सिब्बल जी, सही बात है। आप लोग भी क्यों अड़े हुए हैं? अगर 18 में ही चालू करना है तो इसके लिए दिल्ली में इतना टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है? आप इसे वापस ले लीजिए। आप तो कहते हैं कि कोई सवाल नहीं है। आप ही ने बताया है कि एनसीआर में वॉलमार्ट होगा। जिसके पास गाड़ी होगी, वही लोग पहुंचेंगे, साईकिल वाले वहां नहीं जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया दोहराए नहीं। संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : सुषमा जी ने सही कहा, उन्होंने चांदनी चौक में धंधा करने वालों के बारे में बताया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्लीज कंक्ल्यूड करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। कृपया समाप्त करें। सौगत राय जी, कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : मैडम, दो मिनट में हम संक्षेप करके खत्म करते हैं।...*(व्यवधान)* दीपेन्द्र हुड्डा, नौजवान हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बेटे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद, सौगत राय जी, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : उन्होंने भाषण दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपको क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मेरा विश्वास कीजिए, मैं केवल पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा; अन्यथा आप मुझे सदन से निष्कासित कर दीजिएगा. *..(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आपको समाप्त करना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : मैडम, दीपेन्द्र हुड्डा जी ने 22 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको एक मिनट दे रही हूं। कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : दीपेन्द्र हुड्डा ने 22 जुलाई 2012 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा।

[अनुवाद]

नागर विमानन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना चाहिए और एयर इंडिया की निजीकरण किया जाना चाहिए। ये युवाओं का समूह हैं। *[हिन्दी]* यह सब आ रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कराना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* आपने आर्टिकल लिखकर कहा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महेदया : एक मिनट हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट पूरो गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए?

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : विलास जी, मैं भी दुखी हूं कि आप मंत्री नहीं बने। *...(व्यवधान)* आप टोकिए मत।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्याा बोल रहे हैं? अब आप क्यों खड़े हो गए?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट पूरा हो गया। बहस मत कीजिए। आपका एक मिनट समाप्त हो गया जल्दी कीजिए।

प्रो. सौगत राय : महोदया, कृपया सबको समय देती हैं। बस अंतिम है।

3 दिसम्बर, 2012 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख आया था जिसे जल्दी से पढ़ देता हूं, विशेषकर शरद पवार जी के लाभ के लिए।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप पूरा लेख नहीं पढ़ सकते।

प्रो. सौगत राय : सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था और नीति कॉरपोरेट क्षेत्र की सेवा करने में लगी हुई है और छोटे कृषि फर्मों के विरूद्ध है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे है? आप क्यों बात बढ़ा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप पढ़ते क्यों जा रहे हैं? कृपया पढ़िए मत। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब, कार्यवाही वृत्तात में कुछ भी सम्मिलित नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : अब हसन खान जी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हसन खान जी, आप शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्क्ष महोदया : क्या आपको बोलना है। क्या आपको बोलना है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलि नहीं किया जा रहा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हसन खान (लद्दाख) : इस हाउस में 30 तारीख को लोक सभा की टेबल पर यह रखा गया था। इसमें कोई प्रोवीजन जो है, वह शेड्यूल 8 में एनेग्जर बी.के. बारे में *[अनुवाद]* प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिशत के बारे में, उसके बारे में मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था, जो कि बहुत कुछ मिलता-जुलता है. *..(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। हमारे पास सीमित समय है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हसन खान: तकरीबन प्रोफेसर सौगत राय ने जो रेज्यूलूशन मूव किया है वह बिल्कुल आइडेन्टिकल है। हमारा भी और इनका भी वही नोटिफिकेशन के बारे में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह आप की बात कर रहे

...(व्यवधान)

श्री हसन खान: यह भी उसी नोटिफिकेशन के बारे में है। मेरा भी इसी नोटिफिकेशन के बारे में है। 30 तारीख को फेमा के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन इस हाउस के टेबल पर रखा गया था, उसका एक प्रोवीजन है - शेड्यूल 1 के एनेक्सचर-बी में, मेरा भी उसी में एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है उसके बारे में था, चूंकि प्रोफेसर साहब का जो है उन्होंने नहीं माना और वे वोट के लिए इन्सिस्ट कर रहे हैं। वैसे ही, हाउस में इस दो दिन की जो चर्चा हुई है उसमें खास कर गवर्नमेंट की तरफ से जो डिटेल दिया गया है, जो एक्सप्लैनेशन उन्होंने दी है, इसके बारे में जस्टिफिकेशन दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं, लिहाजा मैं अपने मोशन को विदड्रा करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया, अब सदन में व्यवस्था बनाए। अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा लाए गए प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि शहरी ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिश प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति के अपने निर्णय को तत्काल वापस करे।"

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें।

कुछ माननीय सदस्य : महोदया, हम मत विभाजन चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊं तो सभा में पूरी तरह शांति होनी चाहिए। मैं दोबारा कोई आवाज नहीं सुनना चाहती, अन्यथा, मैं कोई कार्यवाही नहीं चलाऊंगी।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : कृपया नियमों का अध्ययन करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

अब महासचिव स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के बारे में सभा को बताएंगे।

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:-

मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्षपीठ के दोनों तरफ 'सूचना बोर्ड' पर लाल बत्ती जल रही हैं। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सकिय कर दी गयी है।

मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा एक 'लाल' बटन और साथ ही सीट में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बटनों में से एक बटन:-

पक्ष में	–	हरा बटन
विपक्ष में	–	लाल बटन
भाग नहीं लिया	–	पीला बटन

जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए और 'लाल' बत्ती 'बूझ' न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण : माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि यदि दूसरी बार अलार्म बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है, तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

मत-विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बटन (पी) नहीं दबाएं।

माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान सूचक बोर्डों पर तथा अपने 'डेस्क यूनिट' पर देख सकते हैं।

यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले।"

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या-1 सायं 06.43 बजे

पक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजनाला, डॉ. रतन सिंह

अडसुल, श्री आनंदराव

*अधिकारी, श्री शिशिर

अधिकारी, श्री सुवेन्दु

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

इस्लाम, शेख नूरूल

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करूणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री विरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमारी, श्रीमती पुतुल

खैरे, श्री चंद्रकांत

श्री एन. कृष्टप्प

गणेशमूर्ति, श्री ए.

गदीगौदर, श्री पी.सी.

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुलरशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोहौन, श्री राजेन

गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे

गौडा, श्री शिवराम

घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जायसवाल, डॉ. संजय

जावले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जेना, श्री मोहन

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोम्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बदुरई, डॉ. एम.

तराई, श्री बिभू प्रसाद

तिरकी, श्री मनोहर

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिवेदी, श्री दिनेश

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्ता, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नटराजन, श्री पी.आर.

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

*नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

पक्कीरप्पा, श्री एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पॉल, श्री तापस

पोटाई, श्री सोहन

*प्रधान, श्री नित्यानंद

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बक्शी, श्री सुब्रत

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बासवराज, श्री जी.एस.

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बाबर, श्री गजानन ध.

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराज

मंडल, डॉ. तरूण

मडल, श्री मंगनी लाल

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महता, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

*मित्रा, श्री सोमेन

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री पिनाकी

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

*मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघराव, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

*यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकान्त

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजेन्द्रसिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर, प्रो.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो, सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, श्री के. चन्द्रशेखर

*राव, श्री के. नारायण

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगापाल

लागुरी, श्री यशवंत

लिंगम, श्री पी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

*विजय शान्ति, श्रीमती एम.

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डा. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शिवाजी, श्री अधवलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ल, श्री बालकृष्ण खांडेराव

*शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनुप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री कल्याण

सिंह, श्री गणेश

सिंह,, श्री जसवंत

सिंह, श्री दुश्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

*सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

सुशान्त, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

*सोलंकी, श्री दीनूभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, शेख सैदुल

हजारी, श्री महेश्वर

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हसन, डॉ. मोंनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनंत कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मत विभाजन संख्या-1 सायं 06.43 बजे

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन, श्री मोहम्मद

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कलमाडी, श्री सुरेश

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कृपारानी

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री मणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द्र

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चितन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

*जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जयाप्रदा, श्रीमती

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

ठाकोर, श्री जगदीश

डिएस, श्री चार्ल्स

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिंद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

धनपाल, श्री के.पी.

ध्रवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

'बाबा', श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

भोई, श्री संजय

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मणि, श्री जोस के.

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायण

मीणा, श्री रघुवीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

*मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

बोस्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजा, श्री ए.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई

रेड्डी, श्री के.आर.जी.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लालू प्रसाद, श्री

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.

*विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

*व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

शेट्टी, श्री राजू

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सत्यनायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इन्दर

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री उमाशंकर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री एन. धरम

*सिंह, श्री जगदानंद

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुधाकरण, श्री के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

हुसैन, श्री इस्माइल

हेगड़े, श्री के जय प्रकाश

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। मुझे परिणाम की घोषणा करनी है।

शुद्धि अध्ययधीन*, मत विभाजन का परिणाम है:

पक्ष में : 218

विपक्ष में : 253

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदया : मैं अब विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत दिनांक 19 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सा.का.नि. 795(अ) के संशोधन हेतु प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन के समक्ष मतदान हेतु रखती हूं।

प्रश्न यह है कि :

''कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना (सा.का. नि. 795(अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012), में निम्नानुसार उपांतरण किया जाए:-

अनुसूची 8 में,-

(एक) उपाबंध क में, मद (ज) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

''(एक) मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार; और

*निम्नलिखित ससदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में 218 + सर्वश्री शिशिर अधिकारी, श्री सोमेन मित्रा, श्री गोपीनाथ मुंडे, श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव, श्री नित्यानंद प्रधान, श्री के. नारायण राव, श्री राजू शेट्टी, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती एम. विजय शान्ति, श्री दिनेश चन्द्र यादव, और श्री दीनूभाई सोलंकी-229

विपक्ष में 253 + डॉ. मन्दा जगन्नाथ, सर्व श्री अभिजीत मुखर्जी, श्री जगदानंद सिंह, श्री पी. विश्वनाथन, और डॉ. गिरिजा व्यास,-258

(दो) उपाबंध ख में,

16.5	मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	सरकार

से आरंभ

और "(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफ.आई.पी.बी. द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदन को प्रोसेस किया जाएगा" से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हों।"

अध्यक्ष महोदया : जो पक्ष में है वे "हां" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : दीर्घाएं खाली करा दी गई है। महासचिव महोदय ने श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर मत विभाजन के दौरान ऑटोमैटिक वोट रिकार्डिंग मशीन के प्रचाल की प्रक्रियाविधि के संबंध में पहले ही सूचित कर दिया है।

मैं अब विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत दिनांक 9 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सा.का.नि. 795(अ) के संशोधन हेतु प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन के समक्ष मतदान हेतु रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोग सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना (सा.का. नि. 795(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012), में निम्नानुसार उपांतरण किया जाए:-

अनुसूची 8 में

(एक) उपाबंध क में, मद (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"(एक) मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार", और

(दो) उपाबंध ख में

16.5	मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	सरकार

से आरंभ और "(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफ.आई.पी.बी. द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा" से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या-2 सायं 06.43 बजे

पक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजनाला, डॉ. रतन सिंह

अडसुल, श्री आनंदराव

अधिकारी, श्री शिशिर

अधिकारी, श्री सुवेन्दु

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

इस्लाम, शेख नूरूल

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करूणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री विरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कृष्टप्प, श्री एन.

खैरे, श्री चंद्रकांत

गणेशमूर्ति, श्री ए.

गदीगौदर, श्री पी.सी.

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे

गौडा, श्री शिवराम

घुबाया, श्री शेर सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जायसवाल, डॉ. संजय

जावले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जेना, श्री मोहन

जैना, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोम्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तिरकी, श्री मनोहर

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिवेदी, श्री दिनेश

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री खगेन

दासगुप्ता, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नटराजन, श्री पी.आर.

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पॉल, श्री तापस

पोटाई, श्री सोहन

प्रधान, श्री नित्यानंद

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बक्शी, श्री सुब्रत

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बासवराज, श्री जी.एस.

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बाबर, श्री गजानन ध.

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराज

मंडल, डॉ. तरूण

मंडल, श्री मंगनी लाल

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

मित्रा, श्री सोमेन

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री पिनाकी

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

*मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

*यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकान्त

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामाशंकर, प्रो.

राय, श्री अर्जुन

*राय, श्री नृपेन्द्र नाथ

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री बिष्णु पद

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, श्री के. चन्द्रशेखर

राव, श्री के. नारायण

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. राजामोहन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लागुरी, श्री यशवंत

लिंगम, श्री पी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विजय शान्ति, श्रीमती एम.

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी

शिवप्रसाद, डॉ. एन

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनुप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री कल्याण

सिंह, श्री गणेश

सिंह,, श्री जसवंत

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हां, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

सुशान्त, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री दीनूभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, शेख सैदुल

हजारी, श्री महेश्वर

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनंत कुमार

मत विभाजन संख्या-2 सायं 06.43 बजे

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन, श्री मोहम्मद

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख

अमलावे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

आधि शंकर, श्री

अरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीश राम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कलमाडी, श्री सुरेश

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

*खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गावित, श्री मणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द्र

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चितन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

*जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जयप्रदा, श्रीमती

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

ठाकोर, श्री जगदीश

डिएस, श्री चार्ल्स

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिंद

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

*पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

'बाबा', श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

भोई, श्री संजय

*मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मणि, श्री जोस के.

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महंत, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, प्रदीप

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मीणा, श्री नमोनारायण

मीणा, श्री रघुवीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजा, श्री ए.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई

रेड्डी, श्री के.आर.जी.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लालू प्रसाद, श्री

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

शेट्टी, श्री राजू

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सत्यनायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इन्दर

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री उमाशंकर

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जगदानंद

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुधाकरण, श्री के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

हेगड़े, श्री के जय प्रकाश

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन, * मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:

पक्ष में : 224

विपक्ष में : 254

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण श्री हसन खान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की विषय-वस्तु प्रो. सौगतराय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में शामिल कर ली गई है। चूंकि प्रो. सौगतराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह सभा पहले ही निर्णय दे चुकी है, अत: मैं श्री हसन खान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान, के लिए नहीं रख रही हूं।

दीर्घाए खोल दी जाएं।

सभा 6 दिसंबर, 2012 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.54 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा गुरूवार, 6 दिसंबर 2012/15 अग्रहायण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान में मतदान किया:

पक्ष में : 224 + सर्वश्री/श्री गोपीनाथ मुंडे, दिनेश चन्द्र यादव और नृपेन्द्र नाथ रॉय = 227

विपक्ष में : 254 + डॉ. मन्दा जगन्नाथ, सर्वश्री/जी हसन खान सदाशिवराव दादोबा मांडलिक और मिशन भाई वी. पटेल = 258

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अर्जुन राम मेघवाल श्री नीरज शेखर	161
2.	श्री के, सुगुमार श्री पी. विश्वनाथन	162
3.	श्री भर्तृहरि महताब श्री सी. शिवासामी	163
4.	श्री लाल जी टन्डन	164
5.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर श्री दुष्यंत सिंह	165
6.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री गजानन ध. बाबर	166
7.	डॉ. रत्ना डे श्री सुशल कुमार सिंह	167
8.	श्री वीरेन्द्र कश्यप श्री वीरेन्द्र कुमार	168
9.	श्री अशोक तंवर श्री एस.आर. जेयदुरई	169
10.	श्री धर्मेन्द्र यादव श्री ए.के.एस. विजयन	170
11.	श्री कामेश्वर बैठा श्री जयंत चौधरी	171
12.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे श्री एस. अलागिरी	172
13.	श्री भूदेव चौधरी श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	173
14.	श्री एस. पक्कीरप्पा श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	174
15.	श्री प्रेमदास श्री मंगनी लाल मंडल	175
16.	श्री रतन सिंह श्री मनसुखभाई डी. वसावा	176
17.	श्री विजय बहादुर सिंह श्री नित्यानंद प्रधान	177
18.	श्री हरिभाऊ जावले श्रीमती कमला देवी पटले	178
19.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री एन.एस.वी. चित्तन	179
20.	श्री एन. कृष्टप्प श्री खगेन दास	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए साई प्रताप	2041, 2045
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	2025, 2069
3.	श्री बसुदेव आचार्य	2031
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2010
5.	श्री आधि शंकर	1884, 1933
6.	श्री आनंदराव अडसुल	1996, 2010

1	2	3
7.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1851, 1962
8.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1904, 2052
9.	श्री हंसराज गं. अहीर	1876
10.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1999
11.	श्री एम. आनंदन	1925
12.	श्री अनंत कुमार	1953, 1968, 2049
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1952, 1980, 2051
14.	श्री सुरेरश अंगड़ी	1925
15.	श्री घनश्याम अनुरागी	1960, 2043
16.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2044
17.	श्री कीर्ति आजाद	1900, 2019
18.	श्री गजानन ध. बाबर	2010
19.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	1977, 2025
20.	श्री रमेश बैस	2038, 2054
21.	श्री कामेश्वर बैठा	1952, 1968
22.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1890, 2060
23.	डॉ. बलीराम	1973, 2019
24.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	1932
25.	श्री अवतार सिंह भडाना	1928
26.	श्री सुदर्शन भगत	1979, 1986, 2025
27.	श्री ताराचन्द्र भगोरा	1898, 2019
28.	श्री संजय भोई	1924, 2029, 2030, 2031
29.	श्री उदयनराजे भोंसले	1953
30.	श्री समीर भुजबल	1870
31.	श्री पी.के. बिजू	1856, 1943
32.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1887, 2010
33.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1985, 2022, 2025, 2038
34.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	2015
35.	श्री हरीश चौधरी	2019, 2027
36.	श्री जयंत चौधरी	1950
37.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	1848, 1972, 2057
38.	श्री संजय सिंह चौहान	2037
39.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	2033
40.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1877, 1892, 2026
41.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2020, 2029, 2032
42.	श्री भूदेव चौधरी	1930
43.	श्री निखिल कुमार चौधरी	2017
44.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1868, 2056
45.	श्री बंस गोपाल चौधरी	2031
46.	श्री भक्त चरण दास	1965, 1994
47.	श्री खगेन दास	2033, 2038
48.	श्री राम सुन्दर दास	2055
49.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1952, 1979, 2027, 2030, 2050

1	2	3
50.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	2034
51.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1945
52.	श्री के.डी. देशमुख	1951
53.	श्रीमती अश्वमेध देवी	1903
54.	श्रीमती रमा देवी	1879, 1918, 2010
55.	श्री के.पी. धनपालन	1922, 1947
56.	श्री संजय धोत्रे	2020
57.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2023
58.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1846, 1943, 2022, 2025, 2060
59.	श्री निशिकांत दुबे	1962, 1995, 2025, 2048
60.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2028
61.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1930, 2006, 2022
62.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1924, 2029, 2030, 2031
63.	श्री गजेनद्र सिंह राजुखेड़ी	2014
64.	श्रीमती मेनका गांधी	1928, 1933, 2010, 2021, 2042
65.	श्री वरुण गांधी	1920
66.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	1938
67.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1899, 1963, 2020
68.	श्री एल. राजगोपाल	2013, 2020, 2025
69.	श्री शिवराम गौडा	1913, 2035
70.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1952, 2045
71.	श्री महेश्वर हजारी	1842, 1843, 2025, 2046, 2053
72.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	2025
73.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1873, 1879, 1963, 1968, 1973
74.	श्री बलीराम जाधव	1983, 2025
75.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	1953, 1956
76.	डॉ. संजय जायसवाल	2003
77.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2019, 2052
78.	श्री बद्रीराम जाखड़	1881
79.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1877, 2043
80.	श्री नवीन जिन्दल	1858, 2065
81.	श्री महेश जोशी	1961, 2046
82.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1952, 1980, 1987
83.	श्री प्रहलाद जोशी	1891
84.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2049
85.	श्री सुरेश कलयाडी	1953
86.	श्री पी. करुणाकरन	2034, 2038, 1932
87.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1972, 2001, 2043, 2055
88.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1979
89.	श्री राम सिंह कस्वां	1909, 1954, 2026

1	2	3
90.	श्री नलिन कुमार कटील	1868, 2035
91.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1942, 2034
92.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1927, 2005
93.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1962, 2025
94.	श्री मधु कोड़ा	1972
95.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2025
96.	श्री एन. कृष्टप्प	2018, 2033
97.	श्री विश्व मोहन कुमार	1954
98.	श्री अजय कुमार	1935
99.	श्री पी. कुमार	1862, 2069
100.	श्री एन पीताम्बर करुप	1851, 1907
101.	श्री यशवंत लागुरी	1859, 1879, 2043, 2066
102.	श्री पी. लिंगम	1952, 1979, 2027, 2030, 2050
103.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1869, 1953
104.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1948
105.	श्री सतपाल महाराज	1989
106.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1886
107.	श्री नरहरि महतो	1861, 1965, 1982, 2068
108.	श्री भर्तृहरि महताब	2019, 2020
109.	श्री प्रदीप माझी	1953, 1974, 2000, 2010, 2031
110.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	1962, 2052
111.	श्री मंगनी लाल मंडल	2026
112.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	2030, 2031, 2032
113.	श्री जोस के. मणि	1905, 1979, 2031, 2041
114.	श्री हरि मांझी	1889, 2038, 2054
115.	श्रीमती इन्ग्रिड मेक्लोड	2012
116.	श्री दत्ता मेघ	1949
117.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1930, 1953
118.	श्री भरत राम मेघवाल	1977, 2025
119.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1962
120.	श्री महाबल मिश्रा	1975
121.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	1940
122.	श्री सोमेन मिश्रा	1883
123.	श्री पी.सी. मोहन	2022, 2025, 2039
124.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1867, 1985, 2021, 2025, 2047
125.	श्री विलास मुत्तेमवार	2021, 2026, 2039
126.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1880, 1968, 2039
127.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1916, 1949, 2024, 2039
128.	श्री नामा नागेश्वर राव	1968, 1993, 2020
129.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	1964

1	2	3
130.	श्री जफर अली नकवी	1978
131.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1846, 1954, 1972, 2018, 2022
132.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1997
133.	श्री संजय निरुपम	1963, 2047
134.	कुमारी मौसम नूर	1968, 2009, 2021
135.	श्री ओ.एस. मणियन	2026, 2048
136.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1847, 1952, 2029, 2040
137.	श्री जगदम्बिका पाल	1944
138.	श्री वैजयंत पांडा	1917
139.	श्री प्रबोध पांडा	2005
140.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2027
141.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1902, 2043
142.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1959
143.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1924, 2029, 2030, 2031, 2032
144.	श्री कमलेश पासवान	2002
145.	श्री देवजी एम. पटेल	1867, 1953, 1968, 2025
146.	श्री आर.के. सिंह पटेल	1971
147.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1850, 2004, 2058
148.	श्री बाल कुमार पटेल	1984
149.	श्री किशनभाई वी. पटेल	1953, 1974, 2000, 2010, 2031
150.	श्री हरिन पाठक	2004, 2025
151.	श्री संजय दिना पाटील	2039
152.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1952, 1959, 2025, 2042
153.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1983, 2028
154.	श्री सी.आर. पाटिल	1894, 2025
155.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1874, 2025
156.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1924
157.	डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1958, 2041
158.	श्रीमती कमला देवी पटले	1854, 1972
159.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1845, 2010, 2022
160.	श्री नित्यानंद प्रधान	2021
161.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	2007, 2009
162.	श्री प्रेमदास	2025
163.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1965, 1966, 1979, 2048, 2054
164.	श्री कबीन्द्र पुरकास्थ	1934
165.	श्री एम.के. राघवन	1947, 1957
166.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2034
167.	श्री अब्दुल रहमान	1863, 2029, 2037, 2045

1	2	3
168.	श्री प्रेम दास राय	1962, 1969
169.	श्री रमाशंकर राजभर	1998, 2039
170.	श्री सी. राजेन्द्रन	1914
171.	श्री एम.बी. राजेश	2011, 2036
172.	श्री पूर्णमासी राम	1985, 2025
173.	श्री रामकिशुन	1927, 1992
174.	श्री कादिर राणा	2025
175.	श्री निलेश नारायण राणे	1855, 2063
176.	श्री रायापति सांबासिवा राव	1897, 1947, 2010, 2030
177.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1915, 1953
178.	श्री रमेश राठौड़	1967, 2018, 2033
179.	श्री रामसिंह राठवा	1888, 1979
180.	डॉ. रत्ना डे	2023
181.	श्री अशोक कुमार रावत	1864, 2025, 2027
182.	श्री विष्णु पद राय	1896
183.	श्री रुद्रमाधव राय	1860, 2017
184.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1910
185.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1901, 2030
186.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	1911
187.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1912, 2022, 2025
188.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1861, 1965, 2068
189.	प्रो. सौगत राय	1863, 1939, 2034, 2035
190.	श्री एस. अलागिरी	2019
191.	श्री एस. सेम्मलई	1920, 1967
192.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2026, 2061
193.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1952
194.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1906, 1949, 2005, 2025, 2030
195.	श्री तकाम संजय	1929
196.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1963, 2008
197.	श्रीमती सुशला सरोज	1842, 2046
198.	श्री तूफानी सरोज	1926
199.	श्री तथागत सत्पथी	1937
200.	श्री हमदुल्लाह सईद	1962, 2039, 2042
201.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1946, 2037
202.	श्री जगदीश शर्मा	2021, 2026, 2039
203.	श्री नीरज शेखर	1931, 1952, 2048
204.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	1981
205.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1875
206.	श्री राजू शेट्टी	1895, 1963
207.	श्री एंटो एंटोनी	1947, 1955, 2040
208.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1871, 1968, 2020
209.	डॉ. भोला सिंह	2016, 2052

1	2	3
210.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1885, 2043
211.	श्री गणेश सिंह	1968, 1970, 2038
212.	श्री इज्यराज सिंह	1943, 2019
213.	श्री जगदानंद सिंह	1941, 2036
214.	श्री महाबली सिंह	2024
215.	श्री मुरारी लाल सिंह	1854
216.	श्री प्रवीण सिंह ऐरन	1882
217.	श्री राधा मोहन	1930, 2039
218.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2038, 2039
219.	श्री राकेश सिंह	1849, 2050, 2059
220.	श्री रतन सिंह	1918, 2019, 2027
221.	श्री सुशील कुमार सिंह	2018, 2033, 2052
222.	श्री उदय सिंह	1872
223.	श्री यशवीर सिंह	1931, 1952, 2048
224.	श्री धनंजय सिंह	1919, 2025, 2048
225.	श्री राधे मोहन सिंह	1936
226.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1952, 1987, 2051
227.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1963, 1991, 2007, 2027
228.	श्री उदय प्रताप सिंह	1923, 1959, 2034, 2043, 2044
229.	डॉ. संजय सिंह	1873, 2019, 2052
230.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1857, 2005, 2017, 2064
231.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1954, 1988, 2025
232.	श्री के. सुधाकरण	2030, 2050
233.	श्री ई.जी. सुगावनम	1841
234.	श्री के. सुगुमार	2031, 2067
235.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1916, 1949, 2024
236.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1893, 1962, 2025
237.	श्री मानिक टैगोर	1878, 1969, 2021
238.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1866
239.	श्री लालाजी टन्डन	1959, 2021
240.	श्री अशोक तंबर	2019, 2024, 2062
241.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1844, 2010, 2014
242.	श्री आर. थामराईसेलवन	1908
243.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2036, 2042
244.	श्री पी.टी. थॉमस	1947, 2025, 2030
245.	श्री मनोहर तिरकी	1861, 1982, 2068
246.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1853
247.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2022
248.	श्री लक्ष्मण टुडु	1865, 2043
249.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1842, 1843, 2046, 2053
250.	श्री हर्श वर्धन	1921, 2053

1	2	3
251.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1879, 1973, 2059
252.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1852, 2019, 2023
253.	श्री सज्जन वर्मा	1976
254.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1842, 1843, 2046, 2053
255.	श्री पी. विश्वनाथन	1925, 2069, 2070
256.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1990
257.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1865, 2010, 2019, 2059
258.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2010
259.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1952
260.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2040
261.	श्री मधु गौड यास्खी	1974, 2010

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	169, 173
नागर विमानन	:	163, 165, 166
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	162, 170, 177, 178, 180
पृथ्वी विज्ञान	:	
विदेश	:	164
मानव संसाधन विकास	:	161, 171, 174, 175, 179
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	168
योजना	:	172
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
अंतरिक्ष	:	
शहरी विकास	:	167, 176

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	62, 77, 78
प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1863, 1919, 1920, 1962, 2048, 2053
नागर विमानन	:	1857, 1860, 1871, 1881, 1883, 1893, 1899, 1905, 1908, 1911, 1924, 1938, 1947, 1958, 1963, 1967,1976, 1996, 2014, 2022, 2026, 2030, 2031, 2036, 2037, 2038, 2040, 2042, 2043, 2045, 2056, 2060
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1846, 1862, 1925, 1937, 1945, 1952, 1968, 1969, 1972, 1973, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2027, 2033, 2052, 2054, 2059, 2067, 2069, 2070

पृथ्वी विज्ञान	:	1994, 1997, 2049, 2061
विदेश	:	1844, 1869, 1878, 1890, 1892, 1898, 1939, 1949, 1956, 1986, 1999, 2005, 2006, 2023, 2024, 2035, 2055, 2068
मानव संसाधन विकास	:	1850, 1852, 1856, 1858, 1859, 1861, 1864, 1866, 1867, 1874, 1876, 1877, 1885, 1887, 1888, 1891, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901, 1904, 1906, 1910, 1912, 1913, 1922, 1928, 1932, 1933, 1940, 1941, 1942, 1944, 1946, 1948, 1953, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1987, 1990, 1992, 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2012, 2015, 2029, 2032, 2034, 2039, 2041, 2044, 2047, 2063, 2064, 2065, 2066
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1902, 1943, 1985, 1991
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1842, 1849, 1855, 1872, 1873, 1879, 1903, 1915, 1917, 1918, 1921, 1930, 1931, 1936, 1951, 1957, 1975, 1979, 2003, 2011, 2017, 2046, 2050, 2051
योजना	:	1841, 1843, 1847, 1851, 1854, 1865, 1868, 1880, 1894, 1914, 1929, 1935, 1950, 1971, 1974, 1980, 1995, 2058
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1848, 1853, 1954, 1989, 2013, 2057
अंतरिक्ष	:	1884, 1955, 1984, 2062
शहरी विकास	:	1845, 1870, 1875, 1882, 1886, 1889, 1907, 1909, 1916, 1923, 1926, 1927, 1934, 1970, 1988, 1993, 2004, 2016, 2025, 2028.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

9 & D

जी.एल.एस.– 48/29/9/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।